

प्रकाशक

मद्रक

राजहंस प्रकाशन

अमरचंद्र

दिल्ली ।

राजहंस प्रेम दिल्ली ।

पहली बार

१७४६

मूल्य साठे सात रुपए

प्राप्त हुआ है प्रकाशित किसी भी अन्य प्रयत्न भाग का किसी भी भाग या
उपभाग के भाग या भाग के लिए मूल्य प्रकाशन का आजा रित्त अनधिकृत है ।

सूची

भाग—१ : व्यक्ति, राजनीति और युद्ध

१. डन्कर्ट के बाद
२. अमेरिका भी युद्ध के चंगुल में
३. स्टालिन और हिटलर—एक पुनरध्ययन
४. मेरी भविष्य-वाणी
५. लिटविनाव और जॉसेफ ई० डेविस
६. ब्रिटिश जनता और चर्चिल का इंग्लैंड
७. भविष्य दर्शन
८. भारत की ओर
९. पूरव और पश्चिम का मेल
१०. भारत की समस्याएँ
११. भारत में अंग्रेजी राज्य
१२. फिलस्तीन में दस शांत दिन

भाग—२ : युद्ध द्वारा शांति की ओर

१३. रुजवेल्ट, गांधी और चांग-काई-शेक
१४. सुरक्षा की खोज
१५. रुस क्या चाहता है ?
१६. क्रांति का क्या हुआ ?
१७. लास्की-शास्त्र
१८. जोसेफ स्टालिन
१९. रुजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन के शांति-प्रयत्न

भाग—३ : दोहरी अस्वीकृति

२०. दोहरी अस्वीकृति
२१. एक भारी सकट
२२. दूसरे महायुद्ध के बाद
२३. अमेरिका और सोवियत रुस
परिशिष्ट

भाग—१
व्यक्ति, राजनीति और युद्ध

एक महान् नैतिक चुनौती

: १ :

"डन्कर्क के बाद

युद्ध लहू से रँगी हुई राजनीति है। इसके आरम्भ होने से पहले धारी-दार पाजामा पहने हुए कूटनीतिज्ञ एक-दूसरे से शब्दों की लड़ाई लड़ते हैं और जब उन्हें सफलता नहीं मिलती तो बरदी पहने हुए सिपाही बम सम्हाल लेते हैं। दूसरा महासमर युद्ध से पहले की ही राजनीति का फल था।

युद्ध ने एक बात जो निश्चित कर दी, वह यह कि जर्मनी, इटली और जापान का इस भूमंडल पर राज नहीं होगा। फिर भी कई दूसरी समस्याएँ ज्यों-की-त्यों रह गई और वे अब या तो राजनीति द्वारा हल की जायँगी या उन पर सैनिक दृष्टिकोण से विचार किया जायगा।

शस्त्रीकरण की बढ़ती हुई भयकरता शांति की कोई गारंटी नहीं है। दूसरा महासमर पहले से ज्यादा लम्बा था और उसमें धन और जन की भी अधिक आहुति चढ़ी। तीसरा महासमर इससे भी बढ़कर होगा। हरेक युद्ध अपने से पहलेवाले युद्ध से ज्यादा मँहगा रहा है, लेकिन इस बात के अच्छी तरह मालूम होने पर भी युद्ध कभी रुका नहीं। उसकी बढ़ती हुई भीषणता के कारण कुछ देशों को लड़ने से बस हिचक भर होती है, जो कि आक्रमणकारी देश के लिए बड़े लाभ की बात है।

साधारण लोगों को युद्ध से इतना अधिक भय लगता है कि जनतंत्री सरकारें शांति की आशा दिलानेवाले हर तिनके का सहारा लेने को खुशी के साथ तैयार हो जाती हैं। तुष्टीकरण वा यह एक महत्वपूर्ण साधन है।

सन् १९३१ और १९४० के बीच सभी बड़े तानाशाहों ने किसी-न-किसी देश पर चढ़ बैठने का अपराध किया। ध्यान रहे कि यह अपराध ताना-

गाहो ने ही किया, किसी जनतंत्री सरकार ने नहीं। आजकल की जनतंत्री सरकारों को अपनी जनता की भावनाओं के साथ चलना पड़ता है, तानाशाहों पर ऐसा कोई बन्धन नहीं।

युद्ध का रुकना तानाशाहों और जनतंत्री सरकारों के भावी सम्बन्ध पर निर्भर है। तानाशाह अपना काम बड़ी फुर्ती के साथ करते हैं क्योंकि उनके निर्णय में किसी नैतिकता या जनमत का अड़गा नहीं रहता। जनतंत्री सरकारें अपना निर्णय देर में करती हैं और जब कई जनतंत्री सरकारें अपनी-अपनी कूटनीति को एक-साथ मिला देती हैं तो या तो वे कोई निर्णय ही नहीं कर पाती या "कुछ न करने" का निर्णय करती हैं। सन् १९३९ से पहले यह बात अकसर हुई।

महाल जर्मन का नहीं है। जिन जनतंत्री सरकारों की शान्ति का सर्वमत्तावादी देशों के हमले में मकड़ पैदा हुआ था और अन्त में जिनकी शान्ति नष्ट हो गई थी उनमें चीन पर जापान के, हव्श, अल्बेनिया और स्पेन पर इटली के और ग्राब्रिया और नेपोल्नोवेकिया पर नाजियों के आक्रमण की रोकने की काफी मे उपाय लाए जा चुके थे। अकेले फ्रांस में इतना बल था कि वह मार्च १९३६ में हिटलर का राइनलैंड का पुनः शस्त्रीकरण करने से रोक देता।

महान् चुनौती

सर्वमत्तावादी तानाशाह यह समझ न सके कि आक्रमण करने और पैर फेंकाने से उनकी अपनी ही जड़ कट जायगी। उद्यम जनतंत्री सरकारों ने अपनी समस्याओं का सामना कर सकने में बड़ी अक्षमता दिखाई। उनके कुछ कूटनीतियों को खतरा नहीं दिखाई दिया किन्तु कुछ का समर्थन, प्रेजिडेंट रूजवेल्ट को—दिखाई दिया। सन् १९३६ के आरम्भ में ही उन्होंने आनेवाले युद्ध की और सार्वजनिक रूप से सचेत किया।

पार्लमेट या मन्त्रिमण्डल की मजबूत सलाहों की ओर बढ़ने की अनिच्छा के कारण बहुतों को कूटनीतिज्ञ चप देते जान थे। मंच पृष्ठ पर तो अविनाश

दूर तक असर रखनेवाला अन्तर्राष्ट्रीय उद्देश्य, अर्थात् शान्ति, दृष्टि से ओझल हो जाता है। इसके अलावा, जब कभी किसी सकट के बादल फट जाते हैं तो कूटनीतिज्ञ और बहुत-से साधारण लोग भी हर्ष मनाने लगते हैं। समस्या हल हुई या नहीं, इसकी उन्हें इतनी चिन्ता नहीं होती जितनी इस बात की, कि चलो इस समय तो तनावतनी कम हुई। एक दिन एकाएक ये ही उलझी हुई समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं।

पहले और दूसरे महासमर के बीच जो समय बीता उसमें घुरी राष्ट्र-समूह से बाहर के किसी भी देश ने लगकर या विशेष रूप से युद्ध रोकने की चेष्टा नहीं की। उलटे राजनीतिज्ञों ने कहा—“हिटलर युद्ध के लिए उतारू है, इस समय हमें उसकी बातें मान लेनी चाहिए, बाद में जब वह जड़ जमाकर बैठ जायगा तो रूस-विरोधी शक्ति के रूप में उसकी मित्रता हमारे लिए बहुमूल्य सिद्ध होगी।” उन्होंने यह भी कहा—“इटली का हव्श पर हमला करना एक जुर्म है, फिर भी यदि हम मुसोलिनी को अधिक न भींचे तो सम्भव है कि वह हिटलर के विरुद्ध हमारा साथ दे।” इसके अलावा भी उन्होंने कहा—“यदि स्पेन वामपक्षी रहा तो उससे सब जगह वामपक्ष को ही प्रोत्साहन मिलेगा। फ्रैंको मुसोलिनी या हिटलर का पिटू है तो होने दो, हम उसे रुपये उधार देकर, उसके साथ दया दिखाकर और उसके मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति बरतकर उसे खरीद सकते हैं।” इस तरह की बातों से तात्कालिक लाभ तो अवश्य हुआ किन्तु ये सिद्धान्त की बातें नहीं थी।

इस प्रकार लटलो-चप्पो करने से हिटलर, हिरोहितो और मुसोलिनी का बिना रक्त बहाये ही विजयी बनने में 'सहायता' मिली, जिसके फलस्वरूप युद्ध अधिक दिनों तक चला और उसमें खून की नदियाँ भी खूब बही। राजनीति केवल युद्ध की सृष्टि ही नहीं कर सकती बल्कि उसे दीर्घकालीन भी बना सकती है। साथ ही साथ वह विजय को निरर्थक भी कर सकती है।

युद्ध से पहले जो राजनीतिक हिचकिचाहट थी वह उसके आरम्भ होजाने पर भी चलती रही। तुष्टीकरण की नीति सक्रामक सिद्ध हुई। जहाँ एक सरकार ने उसे छोड़ा वही दूसरी ने अपना लिया। फ्रांस और ब्रिटेन को छोड़कर घुरी-राष्ट्र-समूह के बाहर ऐसा कोई दूसरा देश नहीं था जिसने अपने पर प्राक्रमण होने से पहले युद्ध की घोषणा की हो। फ्रांस ने ३ सितम्बर, १९३९ को ५ बजे मन्थ्या समय युद्ध घोषित किया, वह भी इसलिए कि उसी दिन सुबह ६ बजे हर्बर्ट स्पेन्स का जहाज फ्रांस की पानी की

बात की राष्ट्रीय भावना देर से किन्तु पर्याप्त मात्रा में पैदा हो चुकी थी कि ब्रिटिश भूमि और जनता पर नाज़ी हथौड़े के गिरने से पहले ही। नेविल चेम्बरलेन की सरकार को, जो फाशिज़्म की कट्टर विरोधी नहीं मालूम पड़ती थी, युद्ध में शामिल होने के लिए विवश किया जाय। इतने पर भी, युद्ध घोषित करने के बाद इंग्लैण्ड और फ्रांस दोनों ही प्रतीक्षा करते रहे। महीनों तक ब्रिटेन की हवाई-सेना ने बमों के होते हुए भी केवल कागज के पर्चे ही गिराये। २ फरवरी, १९४० को 'न्यूयार्क टाइम्स' में युद्ध का जो समाचार छपा उसे दूसरे पृष्ठ के दूसरे कॉलम में सबसे नीचे केवल छः इंच का स्थान मिला और उसका शीर्षक यह था—“पच्छमी मोर्चे पर सर-गरमी बढ़ी।” तीन दिन बाद फिर उसी पत्र में उसी, दूसरे पृष्ठ पर यह सूचना छपी—“एक हल्की सी भिडन्त में फ्रांसीसियों को विजय मिली।” १० फरवरी को एक दूसरे समाचार का शीर्षक यह था—“इंग्लैण्ड के सब से भयंकर हवाई-युद्ध में अंग्रेजों ने जर्मनी के तीन हवाई जहाज गिरा दिये और बीस को तहम-नहम कर डाला।” अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि २१ जनवरी, १९४० को नेविल चेम्बरलेन ने पार्लियामेंट में इस बात की शिकायत की, कि यदि कोई व्यक्ति केवल ब्रिटिश लोक-सभा (हाउस ऑफ कॉमन्स) की बैठमें और समाचारपत्रों में लगी हुई कुछ अधिक मनसनीपूर्ण खबरे ही पढ़े तो वह समझेगा कि ब्रिटेन की सरकार नडाई जालने के लिए बहुत ही कम प्रयत्न कर रही है।

यह एक भूठमूठ की लड़ाई थी। नाज़ियों और बोल्शेविकों ने पोलैंड को रौंद डाला था। उसके बाद जर्मनी की लड़ाई कुछ समय के लिए स्थगित रही और फिर हिटलर स्कैंडिनेविया और पश्चिमी यूरोप की ओर बढ़ा।

सच पूछिये तो उस समय अमरीका युद्ध केवल यूरोप के उत्तरी वर्णवर्ति भाग में रूस और फिनलैण्ड के बीच हो रहा था। ३० नवम्बर, १९३९ को फिनलैण्ड पर रूस का आक्रमण और उसी दिन रात्रि के समय रूसी विमानों द्वारा हेलसिंकी पर बम वर्षा—ये दो ऐसी घटनाएँ थीं जिनमें सारे समाचार में सोवियत रूस के विरुद्ध एक लहर-सी दौड़ गई। प्रेज़िडेंट रूजवेल्ट ने रूस के साथ व्यापार पर नैतिक प्रतिबन्ध लगा दिया। राष्ट्र-संघ (लीग ऑफ नेशन्स) ने रूस को सदस्यता में हटा दिया। रूसी समस्या ने जिसमें चीन, स्पेन, आस्ट्रिया और चेकोस्लोवेकिया पर फासिस्टों द्वारा आक्रमण होनेके समय अपनी आँखें बन्द कर रखी थी रूस के विरुद्ध दृढ़प्रतिज्ञ रखकर काम किया। न्यूयार्क में दिये गए मैनिफेस्टो ने रूजवेल्ट को सहायता देने की अपील की। लॉरेगियन गिरजा ने फरवरी, १९४० में ५ लाख डॉलर एम्बेस्सी बनाने का कार्य आरम्भ किया।

हरवर्ट हूवर ने, जो स्पेन पर फाशिस्ट आक्रमण के समय चुप थे, फिनो को पूर्ण सहायता देने का प्रस्ताव किया।

फिनो ने युद्ध करते हुए अपने शक्तिशाली पड़ोसी को कई बार पीछे हटाया और रूस के अनगिनत नौजवानों का काम तमाम कर दिया। १ फरवरी, १९४० को फिनलैण्ड के प्रेजिडेंट क्योस्टी कैलियो ने रूसियों के बर्बरतापूर्ण और अर्थहीन आक्रमण का अन्त करने के लिए "सम्माननीय सधि" की याचना की। किन्तु इसका उत्तर देते हुए मास्को के पत्र 'प्रवदा' ने लिखा— "फिनलैण्ड के लुटेरों का नाश कर दिया जायगा, हम अपने महान् नेता स्टालिन की अधीनता में काम करते हुए उन पर विजय प्राप्त करेंगे।" स्टालिन के सम्बन्ध में 'प्रवदा' ने लिखा— "इनका हृदय विद्वान्-जैसा है और चेहरा मजदूर-जैसा; देखने में यह सिपाही मालूम पड़ते हैं।" किन्तु 'न्यूयार्क टाइम्स' ने स्टालिन को "पूर्व देश का एक निर्दय तानाशाह" कहकर पुकारा। "स्टालिन बदला लेनेवाला एक क्रूर व्यक्ति है।" वाल्टर लिपमैन ने लिखा और फिनो को सहायता देने की अपील की। १ दिसम्बर, १९३९ को जोसेफ बार्न्स ने 'न्यूयार्क हेरल्ड ट्रिब्यून' में, जिसके कि वह मास्को में प्रतिनिधि रह चुके थे, लिखा— "फिनलैण्ड एक पुरानी राष्ट्रीय परम्परावाला जनतन्त्री देश है, वह उस अर्थ में भी फाशिस्ट नहीं जिस अर्थ में रूसवाले फाशिस्ट शब्द का खीच-तानकर प्रयोग करते हैं।"

फरवरी, १९४० में जब ब्रिटेन में जनता का मत लिया गया तो ७४ प्रतिशत व्यक्तियों ने फिनलैण्ड को सशस्त्र देने और ३३ फीसदी लोगो ने वहाँ सेना भेजने के पक्ष में राय दी।

बहुत-से विद्वानों ने कम्युनिस्ट दल से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि रूस आक्रमणकारी बन गया था। ब्रिटिश ट्रेड यूनियन डेलीगेशन के नेता सर वाल्टर सितरीन ने दस दिन तक फिनलैण्ड के शहरों और युद्ध के मोर्चों की देखभाल करने के बाद हेलिंकी पहुँचकर कहा कि फिनलैण्ड को सामान और शायद योद्धाओं—दोनों की विस्तृत सहायता देने की आवश्यकता है।

सन् १९३६ में सितरीन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने रूसी शासन और घरेलू कार्य-पद्धति की बड़ी कड़ी आलोचना की थी। अब उन्होंने फिनलैण्ड के कारण रूस का विरोध किया। बाद में जब हिटलर के आक्रमण के पश्चात् रूस भी युद्ध-क्षेत्र में उतर आया तो वह रूस के पक्षपाती बन गए। राजनीति में समय की आवश्यकता और देशभक्ति सिद्धान्त से अधिक शक्तिशाली होती है। हिटलर के आक्रमणों, अवार्मिक कार्यों और अत्याचारों के

वात की राष्ट्रीय भावना देर से किन्तु पर्याप्त मात्रा में पैदा हो चकी थी कि ब्रिटिश भूमि और जनता पर नाज़ी हथौड़े के गिरने से पहले ही। नेविल चैम्बरलेन की सरकार को, जो फाशिज़्म की कट्टर विरोधी नहीं मालूम पड़ती थी, युद्ध में शामिल होने के लिए विवश किया जाय। इतने पर भी, युद्ध घोषित करने के बाद इंग्लैण्ड और फ्रांस दोनों ही प्रतीक्षा करते रहे। महीनों तक ब्रिटेन की हवाई-सेना ने बमों के होते हुए भी केवल कागज के पर्वे ही गिराये। २ फरवरी, १९४० को 'न्यूयार्क टाइम्स' में युद्ध का जो समाचार छपा उसे दूसरे पृष्ठ के दूसरे कॉलम में सबसे नीचे केवल छः इंच का स्थान मिला और उसका शीर्षक यह था—“पच्छमी मोर्चे पर सर-गरमी बढी।” तीन दिन बाद फिर उसी पत्र में उसी दूसरे पृष्ठ पर यह सूचना छपी—“एक हल्की सी भिडन्त ने फ्रांसीसियों को विजय मिली।” १० फरवरी को एक दूसरे समाचार का शीर्षक यह था—“इंग्लैण्ड के सब से भयंकर हवाई-युद्ध में अंग्रेजों ने जर्मनी के तीन हवाई जहाज गिरा दिये और बीस को तहस-नहस कर डाला।” अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ३१ जनवरी, १९४० को नेविल चैम्बरलेन ने पार्लामेंट में इस बात की शिकायत की, कि यदि कोई व्यक्ति केवल ब्रिटिश लोक-सभा (हाउस आफ कामन्स) की बहसे और समाचारपत्रों में छपी हुई कुछ अधिक सनसनीपूर्ण खबरे ही पढ़े तो वह समझेगा कि ब्रिटेन की सरकार लडाईं ज़ातने के लिए बहुत ही कम प्रयत्न कर रही है।

यह एक झूठमूठ की लडाईं थी। नाज़ियों और बोलशेविकों ने पोलैंड को रौंद डाला था। उसके बाद जर्मनी की लडाईं कुछ समय के लिए स्थगित रही और फिर हिटलर स्कैंडिनेविया और पश्चिमी यूरोप की ओर बढ़ा।

सच पूछिये तो उस समय असली युद्ध केवल यूरोप के उत्तरी बर्फीले भाग में रूस और फिनलैण्ड के बीच हो रहा था। ३० नवम्बर, १९३९ को फिनलैण्ड पर रूस का आक्रमण और उसी दिन रात्रि के समय रूसी विमानों द्वारा हेलसिंकी पर बम-वर्षा—ये दो ऐसी घटनाएँ थी, जिनसे सारे सप्ताह में सोवियन् रूस के विरुद्ध एक लहर-सी दौड़ गई। प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने रूस के साथ व्यापार पर नैतिक प्रतिबन्ध लगा दिया। राष्ट्र-संघ (लीग ऑफ नेशन्स) ने रूस को सदस्यता से हटा दिया। नसी सस्था ने जिसने चीन, स्पेन, आस्ट्रिया और चेकोस्लोवेकिया पर फाशिस्टों द्वारा आक्रमण होनेके समय अपनी आँखें बन्द कर रखी थी रूस के विरुद्ध दृढ़प्रतिज्ञा रहकर काम किया। न्यूयार्क में विशप मैनिंग ने फिनलैण्ड को सहायता देने की अपील की। लथेरियन गिरजा ने फरवरी, १९४० में ५ लाख डालर एकत्र करने का कार्य आरम्भ किया।

हरवर्ट हूवर ने, जो स्पेन पर फाशिस्ट आक्रमण के समय चुप थे, फिनो को पूर्ण सहायता देने का प्रस्ताव किया।

फिनो ने युद्ध करते हुए अपने शक्तिशाली पड़ोसी को कई बार पीछे हटाया और रूस के अनगिनत नौजवानों का काम तमाम कर दिया। १ फरवरी, १९४० को फिनलैंड के प्रेजिडेंट क्योस्टी कॅल्लियो ने रूसियों के बर्बरतापूर्ण और अर्थहीन आक्रमण का अन्त करने के लिए 'सम्माननीय सधि' की याचना की। किन्तु इसका उत्तर देते हुए मास्को के पत्र 'प्रवदा' ने लिखा—'फिनलैंड के लुटेरो का नाश कर दिया जायगा, हम अपने महान् नेता स्टालिन की अधीनता में काम करते हुए उन पर विजय प्राप्त करेंगे।' स्टालिन के सम्बन्ध में 'प्रवदा' ने लिखा—'इनका हृदय विद्वान्-जैसा है और चेहरा मजदूर-जैसा; देखने में यह सिपाही मालूम पड़ते हैं।' किन्तु 'न्यूयार्क टाइम्स' ने स्टालिन को 'पूर्व देश का एक निर्दय तानाशाह' कहकर पुकारा। 'स्टालिन बदला लेनेवाला एक क्रूर व्यक्ति है।' वाल्टर लिपमैन ने लिखा और फिनो को सहायता देने की अपील की। १ दिसम्बर, १९३९ को जोसेफ बार्न्स ने 'न्यूयार्क हेराल्ड ट्रिब्यून' में, जिसके कि वह मास्को में प्रतिनिधि रह चुके थे, लिखा—'फिनलैंड एक पुरानी राष्ट्रीय परम्परावाला जनतन्त्री देश है, वह उस अर्थ में भी फाशिस्ट नहीं जिस अर्थ में रूसवाले फाशिस्ट शब्द का खीच-तानकर प्रयोग करते हैं।'।

फरवरी, १९४० में जब ब्रिटेन में जनता का मत लिया गया तो ७४ प्रतिशत व्यक्तियों ने फिनलैंड को सस्त्र देने और ३३ फीसदी लोगो ने वहाँ सेना भेजने के पक्ष में राय दी।

बहुत-से विद्वानों ने कम्युनिस्ट दल से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि रूस आक्रमणकारी बन गया था। ब्रिटिश ट्रेड यूनियन डेलीगेशन के नेता सर वाल्टर सिटरीन ने दस दिन तक फिनलैंड के शहरो और युद्ध के मोर्चों की देखभाल करने के बाद हेल्सिंकी पहुँचकर कहा कि फिनलैंड को सामान और शायद योद्धाओं-दोनों की विस्तृत सहायता देने की आवश्यकता है।

सन् १९३६ में सिटरीन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने रूसी शासन और घरेलू कार्य-पद्धति की बड़ी कड़ी आलोचना की थी। अब उन्होंने फिनलैंड के कारण रूस का विरोध किया। बाद में जब हिटलर के आक्रमण के पश्चात् रूस भी युद्ध-क्षेत्र में उतर आया तो वह रूस के पक्षपाती बन गए। राजनीति में समय की आवश्यकता और देशभक्ति सिद्धान्त से अधिक शक्तिशाली होती है। हिटलर के आक्रमणों, अवामिक कार्यों और अत्याचारों के

वावजूद भी ब्रिटेन के बहुत-से प्रसिद्ध और साधारण तुष्टिकर्त्ताओं ने ३ सितम्बर, १९३६ तक हिटलर को "काफी ग्राह्य" ही समझा। उसके बाद युद्ध-कालीन परिस्थिति के कारण उनकी प्रवृत्ति बदल गई और उन्होंने अपने विश्वास नहीं बल्कि सरकार के आदेश के अनुसार कार्य किया।

२७ फरवरी, १९४५ को सर विलियम वेवरिज ने, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक सुरक्षा के पक्षपाती थे, ब्रिटिश लोक-सभा में कहा—“विदेशी मामलों में हमें सिद्धान्त का पालन करना चाहिए और यदि मित्रता और सिद्धान्त दोनों का साथ-साथ ध्यान रखना सम्भव न हो तो हमें (मित्रों को छोड़कर) सिद्धान्त की ही चिन्ता करनी चाहिए, क्योंकि सिद्धान्त कभी बदलते नहीं और मित्र कुछ समय के लिए युक्ति-सगत न होने पर भी बाद में बदलकर युक्तिसगत बन सकते हैं। अवसरवादिता, तुष्टीकरण, स्वार्थपूर्ण नीतियाँ, शक्ति-राजनीति—इन सबमें हमारी आशाओं का हनन होता है।”

फिर भी अधिकतर लोग सिद्धान्त को भूल जाते हैं और यही कारण है कि वे उलझन और प्रचार के शिकार बनते हैं।

विदेश-नीति के मामले में एक साधारण व्यक्ति की तुलना एक ऐसी दुकान से की जा सकती है जहाँ सभी तरह की चीजें पड़ी रहती हैं। सन् १९३७ में एक दिन संध्या समय मुझे न्यूयार्क में निर्धनों की वस्ती में रहनेवालों से बातचीत करने का अवसर मिला। वे समझदार लोग थे और अखबार पढ़ा करते थे। उन्होंने रूसी कमिश्नर मैक्सिम लिटविनाफ की सामूहिक सुरक्षा के लिए अपीलें पढ़ी और वे सामूहिक सुरक्षा के पक्ष में हो गए। उन्होंने प्रधान-मन्त्री चैम्बरलेन के वे भाषण पढ़े जिनमें हिटलर आदि के तुष्टीकरण के लिए क्षमा माँगी गई थी और वे इस बात को अच्छी तरह समझ गए कि जो ब्रिटेन लड़ाई के लिए तैयार नहीं था और केवल शान्ति का आकांक्षी था उसने युद्ध से बचने की चेष्टा क्यों की। उन्होंने हिटलर के भाषण भी पढ़े और अनुभव किया कि उसका यह कहना सत्य है कि जर्मनी में रहने की जगह की तंगी है, जर्मनी को व्यापार के लिए बाज़ार चाहिए और वारसाई में सन्धि करते समय उसके साथ अन्याय हुआ था।

राजनीति की एक बड़ी भारी समस्या यह है कि आजकल के लोग बड़ी आसानी से विदेशी और घरेलू प्रचार के शिकार बन जाते हैं। जनतन्त्री देशों में लोग जो बातें दिन-रात सुनते और पढ़ते हैं उनसे उनका अचम्भा बढ़ता ही चला जाता है। तानाशाही देशों में, जहाँ सरकार सभी समाचारों, भाषणों आदि का सेन्सर करती है, जनता धीरे-धीरे पूर्ण रूप से ऐसी बन जाती है कि

उससे जो कुछ कहा जाता है उसे ही वह मान और ग्रहण कर लेती है।

शासनसंस्थाएँ चाहे वे तानाशाही हो चाहे जनतन्त्री -- युद्ध को जीतने और लोगो को लड़ने में समर्थ बनाने के लिए सब तरह के अस्त्र तैयार करती हैं। कुछ तोपखानो में लोहे और इस्पात के अस्त्रो का निर्माण होता है, तो कुछ में इतिहास को तोड़-मरोड़कर तलवार का रूप दिया जाता है। ऐसा करते समय इतिहास की घटनाएँ विकृत बनाई जाती हैं, यहाँ तक कि अन्त में लोगो के मस्तिष्क तक विकृत हो जाते हैं।

जनता के मस्तिष्क पर सरकार का नियन्त्रण ससार के लिए एक बढ़ता हुआ सकट है। तानाशाही राष्ट्रों में इस नियन्त्रण की प्राप्ति के लिए बड़ी असम्यतापूर्ण युक्तियाँ काम में लाई जाती हैं। वैसे सभी दूसरे देशों में भी सत्य का तोड़ने और उसका गला घोटने के लिए बड़े उत्साह के साथ चेष्टाएँ की जा रही हैं।

“युद्ध इंग्लैण्ड चाहता था,” मार्शल गायरिंग ने २ जनवरी, १९४० को कहा। साथ-ही-साथ उसने यह भी कहा, “जर्मनी के निवासी ‘वृहत्तर जर्मनी’ की स्वतन्त्रता के लिए एक विकट युद्ध में तल्लीन हैं।” इसके अतिरिक्त, नाजी दल के सन् १९४० के कैलेंडर में यह बात दृढ़तापूर्वक कही गई कि आक्रमण का आरम्भ पोलैण्ड ने किया और यहाँ तक झूठ बोला गया कि “जर्मनी की सीमा पर पोलैण्ड ने अपने अनेक आक्रमणों में जिस बल का प्रयोग किया है उसका बल द्वारा उत्तर देने के लिए जर्मनी विवश हो गया है।”

१ जनवरी, १९४० को हिटलर के निजी दैनिक पत्र “वोयलकिशर वीओवाश्टेर” में नाजीवाद के लाभ इस प्रकार गिनाये गये—मजदूरों को अधिकार, मूल्य-नियन्त्रण, माताओं को सहायता, स्वास्थ्य की देखभाल, बच्चों का बीमा, कारखानों में खेलकूद, मनोरंजक यात्राओं द्वारा बलवृद्धि, जर्मन मजदूरों के लिए शास्त्रीय संगीत। उसी पत्र में यह भी लिखा गया—“इन बातों से युद्ध का कारण साफ-साफ समझ में आ जाता है। इंग्लैण्ड और फ्रांस के पूँजीपतियों को इस बात का भय हो गया कि निकट भविष्य में उनके मजदूर भी उनसे ऐसी ही माँगें करेंगे। यह बात उनके लिए असह्य थी, इसलिए इसके अंकुर को नष्ट कर देना आवश्यक था।”

हिटलर के पत्र ने सुर छेड़ा और दूसरे नाजी पत्र तथा रेडियो-आलोचक उसके ताल पर नाच उठे। २ जनवरी, १९४० के “वीओवाश्टेर” में मोटे-मोटे अक्षरों में यह शीर्षक छपा—“ब्रिटिश सकट से यूरोप की मुक्ति।” ४ जनवरी को उसी पत्र ने ‘हमारा साम्यवाद’ नाम से एक लेख छपा। तीन दिन

बाद उसने लिखा —“पिछले एक हजार वर्ष से फ्रांस का उद्देश्य जर्मन-एकता को भग करना रहा है।” ८ जनवरी को छपा—“जर्मनी में बेकागी नहीं है” और ९ जनवरी को प्रथम पृष्ठ पर सब से मोटे अक्षरों में यह शीर्षक दिखाई दिया—“पोलैण्ड के पाशविक हत्यारों ने जर्मनी के सस्त घायल हवावाजों को सताया।” उसी दिन यह भी छपा—“इंग्लैण्ड सिद्धान्त-विहीन पूंजीवाद का गढ़ है।”

हिटलर जर्मन जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था। जनता केवल उसकी झूठी बातें ही सुन सकी। मजदूरों में उसने समाजवाद का विष बोया और सारे देश में इंग्लैण्ड और फ्रांस के विरुद्ध घृणा की आग फैलाई। फ्रांस में उसने ब्रिटेन के विरुद्ध प्रचार किया, ब्रिटेन में फ्रांस के विरुद्ध और अमेरिका में यूरोपियनों के विरुद्ध। अमेरिकावासियों में उसने युद्ध से अलग रहने का भी प्रचार किया।

बदमाश जितना ही बड़ा होता है उतने ही उत्तरदायित्व से हीन उसके तर्क होते हैं। सदा कोई-न-कोई उसका विश्वास कर ही लेता है।

बहुत-से दक्षिणपक्षी फ्रांसीसियों ने हिटलर की चेतावनी सुनी। फ्रांसीसी कम्युनिस्टों के कान में मास्को की आवाज आई, रूसियों ने उन्हें बताया कि यह युद्ध साम्राज्यवादियों का युद्ध है।

फ्रांस को प्रभावान्वित करने और सारे यूरोप में आतंक फैलाने का चाल चलने के बाद नाजियों ने अपनी सेना आगे बढ़ाई और नारवे, डेनमार्क, हालैण्ड तथा बेलजियम को मार गिराया। २१ मई १९४० को नाजी सैन्य-दल बड़ी तेजी के साथ इंग्लिश चैनल की ओर बढ़ा, ब्रिटिश आकाश-सेना ने एकेन पर भीषण बम-वर्षा की, प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने कांग्रेस को अमेरिका के रक्षा-प्रवर्ध को शीघ्र-से-शीघ्र पूर्ण करने का आदेश देते हुए एकता के लिए अपील की और महारानी विल्हेमिना हालैण्ड से भागकर लंदन पहुँची।

१२ मई, १९४० को ‘कम्युनिस्ट सन्डे वर्कर’ नामक पत्र ने एक लम्बी सम्पादकीय टिप्पणी में लिखा—“यह युद्ध हमारा नहीं है, यह दो ठगों का युद्ध है—एक और ब्रिटेन और फ्रांस का दल है और दूसरी ओर हिटलर का। हमें इस युद्ध से अलग रहना चाहिए।” २२ मई को न्यूयार्क में टाइम्स स्ववाचर में युद्ध-विरोधी प्रदर्शन किया गया और कम्युनिस्ट दलवाले जो तख्तियाँ लिये फिर रहे थे उन पर लिखा था—“रूजवेल्ट, डेवी और हूवर ने युद्ध के लिए एक गुट बना लिया है”, “भगवान् हमारे राजा की रक्षा करें”, “अमेरिकन नहा लड़ेंगे” आदि।

दूसरी ओर, सिनेटर जेम्स वर्न्स ने कर्नल चार्ल्स लिडवर्ग की युद्ध से अलग रहने की पराजयसूचक नीति के विरोध में भाषण दिया। वेन्डेल विल्की ने कहा—“हिटलर केवल बल जानता है। जब हम अपने उद्योगों की मशीनें चला देंगे और एक करोड़ आदमियों को काम पर जुटा देंगे तो उसकी आखें खुल जायेंगी।” फ्लोरिडा के सिनेटर पेप्पर ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका के हवाई जहाज यूरोप के जनतंत्री देशों को बेचे जायें।

अमेरिका के लोग बहस करते रहे। उधर नाज़ी सैन्य-दलों के चलने से, जर्मन गोताखोर हवाई जहाजों के शोर से और टैंकों की खड़खड़ाहट से यूरोप कांप उठा।

और फिर डन्कर्क का युद्ध हुआ। २८ मई को बेलजियम के राजा लियोपोल्ड ने अपने सिपाहियों को हथियार डाल देने का आदेश दिया। इससे ब्रिटेन और फ्रांस की सेनाएँ भयानक संकट में फँस गईं। “हमें कठोर समाचारों को सुनने के लिए तैयार हो जाना चाहिए,” विन्स्टन चर्चिल ने पार्लियामेंट में कहा। गहनतम निराशा के समय वह प्रधान मंत्री बनाये गये थे। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सिपाहियों की एक छोटी-सी टुकड़ी समुद्र की ओर पीठ किये डन्कर्क में साहस के साथ लड़ती रही जिससे कि शेष ३॥ लाख ब्रिटिश सैनिक इंग्लैंड लौट जाने की चेष्टा कर सकें। जब कि वे डन्कर्क के तट पर जहाजों की प्रतीक्षा कर रहे थे, जर्मन विमानों ने उनपर घुंआघार गोलें बरसाये। ब्रिटेन से जहाज आये—विध्वंसक यान, छोटी नावे, स्टीमर, केलिपोत, मछली फँसानेवाली बोटें, छोटे-छोटे बच्चों द्वारा रस्सी से खींचकर चलाई जानेवाली नावे—जो भी आ सके, आये। जर्मन-विमानों ने उन पर टूट-टूटकर बम बरसाये। छोटे जहाजों पर चढ़ने के लिए सिपाहियों ने गर्दन-गर्दन तक पानी पार किया। घायलों को लोग हाथों और कंधों पर उठा-उठाकर ले गये। जहाज बोझ से झुक गये। फिर वे ब्रिटिश तट की ओर लपके। जर्मन हवाई-सेना ने उनपर फिर आक्रमण किया। केवल एक दिन में, अर्थात् पहली जून को, ६ जहाज बमों से आहत होकर डूब गये। इनमें से कइयों पर सिपाही खचाखच भरे हुए थे। लोगों ने अपने पास की प्रायः सभी चीजें फेंक दी, किंतु उन्होंने अपने सिरो पर से इस्पात के टोप नहीं हटाने दिये। समुद्र में विस्फोटक सुरंगों और टारपीडो का जाल बिछा हुआ था। अगपताली जहाजों तक पर आकाश से बम गिराये जा रहे थे। जो सैनिक घावों पर फटी और गदी पट्टियाँ बाँधे बुरी दशा में तट पर पहुँचते थे, उन्हें लोग हर्ष और दुःख के मिश्रित आँसू बहाते हुए हाथों हाथ ले जाते थे। इंग्लैंड में खुशी मनाई गई। अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ। जहाज कई बार

आये और कई बार गये और हर उस जहाज को देखकर जो सिपाहियों को लोग लिये कुशलतापूर्वक इंग्लैण्ड पहुँचता था, हर्ष से पागल हो उठते थे। ब्रिटेन ने इस प्रकार बचाये गये अपने सिपाहियों की संख्या गिनी। वही उसकी एकमात्र सेना थी, एक निःशस्त्र सेना—हिटलर के आक्रमण से देश को बचाने की एक मात्र व्यवस्था।

४ जून को चर्चिल ने उत्साह और कृतज्ञता से भरा लोक-सभा में घोषणा की—“एक हजार जहाज ३ लाख २५ हजार सैनिकों को मीत के पजे में छुड़ाकर अपने बतन वापस ले आये हैं।” १ लाख १० हजार फ्रामीसी सैनिक भी बचाकर लाये गये थे। फिर भी चर्चिल ने लोगों को सावधान किया—“यह एक सफलता है, विजय नहीं।” वह जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, उन्हें पता था कि ब्रिटेन को जीवित रखने के लिए अभी लड़ाई लड़नी बाकी है।

इंग्लैण्ड अकेला था, किंतु ४ जून को चर्चिल ने सारे ससार को विश्वास दिलाते हुए लोक-सभा में कहा—“हम न विचलित होंगे, न पैर पीछे हटायेंगे; बल्कि अन्त तक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। हम फ्रांस में लड़ेंगे, सागरों और महासागरों में लड़ेंगे और बढ़ते हुए विश्वास तथा बल के साथ आकाश में भी मोर्चा लेंगे। चाहे कुछ भी हो, हम अपने द्वीप की रक्षा अवश्य करेंगे और कभी घुटने नहीं टेकेंगे। यदि कभी इस द्वीप को या इसके किसी बड़े भाग को दासता और भूख का सामना करना भी पड़ा, जिसकी कि मुझे लेशमात्र भी आशंका नहीं है, तो सात समुद्र-पार हमारा साम्राज्य हमारी जल-सेना की सहायता से उस समय तक सग्राम करता रहेगा जब तक कि नया ससार अपने पूर्ण बल और पौरुष के साथ पुराने ससार की रक्षा और मुक्ति के लिए निकल नहीं पड़ेगा।”

चर्चिल अपने स्वभाव और मानसिक प्रवृत्ति से ही आशावादी थे। उन्हें इस बात का विश्वास था कि किसी-न-किसी दिन अमेरिका युद्ध-क्षेत्र में प्रवेश अवश्य करेगा।

डन्कर्क के पलायन के समय ब्रिटेन की शक्ति अपने न्यूनतम स्तर पर थी, किंतु उस घटना ने राष्ट्रीय पौरुष और आत्मबल के गुप्त स्रोतों को खोलकर विजय का सूत्रपात किया। उसके पश्चात् कई सप्ताह तक ब्रिटिश नर-नारियों ने अपनी-अपनी मशीनों के पास बैठकर इतनी कड़ी मेहनत की कि अंत में वे थककर चूर हो गये। मशीनों पर काम करते-ही-करते उन्होंने भोजन किया, दिन भर काम पर जुटे रहने के पश्चात् रात को वे अपनी बेंचों के पास ही फर्श पर सो रहे और फिर तड़के उठते ही वम और बन्दूक बनाने में लग गये।

प्राण-रक्षा के लिए मनुष्य बहुधा अतिरिक्त श्रम करने को तैयार हो जाता है। यहाँ तो राष्ट्र-का-राष्ट्र जीवित रहने के सकल्प से प्रेरित ही इतना श्रम करने में जुटा हुआ था, जितना साधारणतः मानवी क्षमता से परे है।

इंग्लैंड की रक्षा का श्रेय इंग्लिश चैनल, चर्चिल और ब्रिटिश हवाई-सेना को है। चर्चिल के भाषणों ने जनता में कार्य करने की प्रेरणा भरी। चूँकि आजकल की शासन-संस्थाएँ पहले की शासन-संस्थाओं से अधिक शक्ति-शाली होती हैं, इसलिए उनमें उन महान् पुरुषों की तूती बोलती है जिनके हाथों में अत्यधिक अधिकार होता है और जिनका जनता पर अद्भुत प्रभाव भा होता है। तानाशाही देशों में उन महान् पुरुषों का प्रभाव उनके अधिकार के कारण पड़ता है, किंतु जनतन्त्री राष्ट्रों में उन्हें अपने प्रभाव के कारण अधिकार प्राप्त होता है और वे उस अधिकार का प्रयोग अपने प्रभाव की वृद्धि में करते हैं। चर्चिल ने ब्रिटिश जनता को अपने उच्चतम स्तर तक पहुँचने में सहायता दी।

छोटे-छोटे लोगों ने 'निराशा प्रकट की।' कर्नल चार्ल्स लिडवर्ग ने तो समझलिया कि इंग्लैंड हाथ से निकल गया और उन्होंने इस पर शोक भी प्रकट नहीं किया। वीर मार्शल पेनॉ को, जिनकी आत्मा भयातुर हो गई थी, फ्रांस या इंग्लैंड पर विलकुल भरोसा नहीं था। फिर भी चर्चिल, रूजवेल्ट और चार्ल्स डी गाल को इन पर विश्वास था और उनके साथ बलशाली हृदयवाले छोटे-छोटे लाखों व्यक्ति थे।

डन्कर्क के चार साल बाद, ६ जून, १९४४ को ब्रिटिश सेना अमेरिकन सेना के साथ फ्रांस में फिर उतरी और इस घटना के एक वर्ष पश्चात् ही यूरोप में विजय-दिवस मनाया गया। ये पाँच वर्ष करोड़ों नर-नारियों और बच्चों के लिए रक्त-पात, भूख, ठंड और चिन्ता से भरे हुए वर्ष थे। मनुष्य भी कैसा अद्भुत आविष्कार है! निस्संदेह वह उत्तमतर सौभाग्य का अधिकारी है।

मनुष्य कम-से-कम युद्ध-विहीन मसार का अधिकारी अवश्य है। मैं युद्ध की भयकरता को देख चुका था, इसीलिए प्रतिदिन प्रकाशित होनेवाली युद्ध-विज्ञप्तियों को पढ़ते ही मेरी आँखों के सामने गालियों से क्षत-विक्षत शरीरों या जले हुए टंको और विमानों में झुलसे हुए मनुष्यों के चित्र खिच जाते थे। जब विज्ञप्ति में लिखा होता "दो हवाई जहाज वापस नहीं आ सके" तो मेरे नेत्रों के सामने नाच उठता १२ नवयुवकों की मृत्यु का दृश्य और उनके साथ-साथ १२ माता-पिताओं, १२ परिवारों और अनेक मित्रों का चित्र जो उस विज्ञप्ति को सदा याद रखेगा और जब कभी उन्हें उसकी याद आयगी तभी उनका हृदय शीतल और शिथिल हो बैठने-सा लगेगा। यदि युद्ध वस्तुतः इस योग्य है कि हम

उसके लिए इतनी यातनाओं, इतने कष्टों और इतनी मृत्युओं का भोग भोगें तो निस्संदेह उसका अतः महान् और कल्याणकारी होना चाहिए।

यदि दूसरा महासमर वस्तुतः किसी उद्देश्य से लड़ा गया था तो उसे एक ससारव्यापी गृह-युद्ध का रूप लेना चाहिए था, वह दासता के विरुद्ध और एक ऐसे अखंड भूमण्डल की स्थापना के लिए लड़ा जाना चाहिए था जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान स्वतन्त्रता और न्याय प्राप्त होता। किसी एक देश की भूमि, तेल या व्यापार को छीनकर दूसरे देश को देने के लिए युद्ध करना एक महान् और मूर्खतापूर्ण अपराध है।

अमेरिका भी युद्ध के चंगुल में

विन्स्टन चर्चिल का कोई भी वक्तव्य इतिहासकारों को उतना महत्वपूर्ण नहीं मालूम होगा, जितना कि उनका फ्रांस और इंग्लैंड की शासन-सत्ताओं को एक में मिला देने का १६ जून, १९४० का प्रस्ताव। उस समय फ्रांस का पतन होने ही वाला था। चर्चिल फ्रांस और अपने देश, दोनों की रक्षा करना चाहते थे। उन्होंने प्रस्ताव किया कि ब्रिटेन और फ्रांस इस बात की घोषणा कर दे कि “हमारी सरकारें अलग-अलग न रह कर एक सघ का रूप ले लेगी और फ्रांस के प्रत्येक निवासी को ब्रिटेन की तथा ब्रिटेन के प्रत्येक निवासी को फ्रांस की नागरिकता तत्काल प्राप्त हो जायगी।”

चर्चिल कट्टर राष्ट्रवादी और साम्राज्यवादी थे, फिर भी जीवित रहने की आकांक्षा ने उन्हें सकट के समय विभिन्न राष्ट्रीय सत्ताओं के एकीकरण और अन्तर्राष्ट्रीयता का पक्षपाती बना दिया। उन्होंने यह समझ लिया कि अपने अस्तित्व की रक्षा सबसे अच्छी उस समय हो सकती है जब सार्वभौम सत्ताएँ पृथक्-पृथक् न हो।

वर्षों बाद, यूरोप की विजय से कुछ दिन पहले, जब चर्चिल से पूछा गया कि क्या आप अब भी फ्रांस को ब्रिटेन में मिलाने को तैयार हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया—“नहीं।” पराजय को रोकने के लिए अंतिम प्रयत्न करते समय वह जिस कार्य के लिए तैयार हो गए थे उसीसे वह विजय का आश्वासन मिलते ही मुकर गये। सन् १९४० में सर्वनाश से बचने की व्यावहारिक आवश्यकता का अनुभव करने के कारण वह आदर्शवादी बन गये थे, किंतु सन् १९४४ तक यह आदर्शवाद कपूर की तरह उड़ गया। जब तक स्थिति गम्भीर रही तब तक चर्चिल अच्छे बने रहे।

युद्ध की अमुन्दरता पहले हमसे सुन्दर शांति की एक आदर्शवादी आशा जाग्रत कर देती है और फिर बाद में ऐसा विष उत्पन्न करती है जो उस आदर्श-

वाद को ले बैठता है। दुःख के द्वारा उन्नति की आशा करना एक मृग-मरीचिका है। यदि दुःखभोग से मनुष्य बुद्धिमान बन सके तो इस ससार में इतनी बुद्धिमत्ता व्याप जायगी कि दुःख ही नहीं पायगा।

फ्रांस को बचाना चर्चिल के बस की बात नहीं थी। यदि जून, १९४० में ब्रिटेन या अमेरिका के १० लाख ताजे सिपाही अस्त्र-शस्त्र से पूरी तरह लैस हो नारमैंडी में उतर पड़ते या रूस पूर्व की ओर आक्रमण कर देता, जैसा कि जार ने अगस्त १९१४ में किया था, तो फ्रांस बच जाता और बाद में खून की जो नदियाँ वही वे भी न बहती। किंतु ऐसा नहीं हो सका। नाज़ी सैन्य-दल निर्दयता के साथ आगे बढ़ता रहा, पेरिस ने बिना लड़े ही घुटने टेक दिये और १० जून को इटली भी अखाड़े में उतर आया।

इटली के युवक विदेश-मंत्री काउन्ट चियानो ने, जो मुसोलिनी का दामाद था, अपने देश को युद्ध से अलग रखने की चेष्टा की। बाद में इस अपराध के लिए नाज़ियो ने उसे गोली से उड़ा दिया। मई, १९४० में प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने मुसोलिनी के पास तीन बार निजी सदेश भेजे और उसपर लडाई-भगड़े से दूर रहने का जोर डाला। २४ अप्रैल, १९४० को पोप पायस १२ वे ने मुसोलिनी को एक पत्र लिखकर युद्ध में भाग न लेने की सलाह दी। युद्ध के विरोध में सार्वजनिक प्रदर्शन भी किये गये। किन्तु ये सारी युक्तियाँ बेकार रही, क्योंकि मुसोलिनी मार-घाड़ में हिस्सा बँटाने के लिए इच्छुक थे। उन्हें इस बात का विश्वास था कि जल्दी ही फ्रांस, और कुछ ही सप्ताह में ब्रिटेन भी आत्म-समर्पण कर देगा और तब इटली सरलता से प्राप्त की गई उस विजय के मीठे फल चख सकेगा। किन्तु, कैसी भयंकर भूल की उसने? उसके भाग्य में सन् १९४० में विजयी बनना नहीं, बल्कि सन् १९४५ में हारना और मरना लिखा था।

जनता के अधिकांश दुःख शासन-संस्थाओं की भूलों के ही कारण उत्पन्न होते हैं।

फरवरी १९४० में मुसोलिनी और हिटलर ने ब्रेनर-पास में मिलकर इटली को युद्ध के अखाड़े में उतारने का निश्चय किया था। कर्नल-जनरल गस्टाव जॉर्ड ने, जिसकी मेधा-शक्ति ने दस वर्ष तक जर्मन-सेना का पथप्रदर्शन किया था, जून १९४५ में गिरफ्तार किये जाने पर इस बात का प्रमाण दिया कि जर्मनी के सैनिक अधिकारी इटली के युद्ध में सम्मिलित होने के पक्ष में नहीं थे। फील्ड-मार्शल कीटेल ने भी अपनी गवाही में यही बताया। सच पूछिये तो द इटली तटस्थ बना रहता और मित्र-देश के नाते जर्मनी को जहाज़ों द्वारा

माल भेजता रहता तो वह हिटलर के लिए बड़ा उपयोगी सिद्ध होता और भार न बनता, जैसा कि बाद में वह शीघ्र ही बन गया। किन्तु हिटलर ने, जो राजनीतिज्ञ अधिक था और सैनिक कम, निश्चय ही यह सोचा होगा कि उचित अवसर पर इटली के युद्ध में प्रवेश करने पर फ्रांस के पतन का मार्ग प्रशस्त हो जायगा और ब्रिटेन भी हतोत्साह हो शीघ्र मस्तक झुका देगा। हिटलर को भरोसा था कि ब्रिटेन की प्रतिरोध-शक्ति भग हो जायगी और इटली का युद्ध में आना अंतिम क्रूर प्रहार सिद्ध होगा।

फ्रांस के सन् १९४० के पतन का आरम्भ सन् १९१४ में ही हो चुका था। प्रथम महासमर में उसके अनगिनत नवयुवक काम आये। फ्लैन्डर्स के पोस्तों के खेत स्वस्थ लाल लहू से सिंच गये जिससे तुष्टिकर्त्ताओं की एक फसल-सी खड़ी हो गई। विजय बिलकुल स्पष्ट थी। अमेरिका ने फ्रांस की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं ली और कुछ फ्रांसीसियों ने अनुभव किया कि ब्रिटेन जर्मनी का पक्षपाती हो गया है। उन्होंने कहा कि और नहीं तो कम-से कम युद्ध-क्षतिपूर्ति और रूहर पर अधिकार करने के प्रश्न पर ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी का पक्ष ले रहे हैं। इंग्लैण्ड के प्रति इस अविश्वास से मार्शल पेटाँ की सरकार को २१ जून, १९४० को हिटलर से संधि करने के लिए तैयार हो जाने में बड़ा प्रोत्साहन मिला। कुछ फ्रांसीसियों का यह अनुमान था और कुछ ने अपने पागलपन में यह आशा तक कर ली थी कि ब्रिटेन भी शीघ्र ही घुटने टेक देगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न जल्दी ही हथियार डाल दिये जायँ और तत्परता के लिए नाम कमाया जाय।

फ्रांस को इंग्लैण्ड की प्रतिरोधक-शक्ति के सम्बन्ध में शका थी। जर्मनी और रूस की २३ अगस्त, १९३९ की सन्धि मानो मौत की घंटी थी क्योंकि रूस और अमेरिका के तटस्थ रहते हुए और ब्रिटेन में युद्ध की तैयारी न होने के कारण फ्रांस का विजया बनना असंभव था। ऐसी दशा में फ्रांसीसियों ने सोचा कि एक ऐसे देश के विरुद्ध लड़ने से लाभ ही क्या जो फ्रांस से बड़ा ही नहीं है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली और सैनिक अस्त्र-शस्त्रों में भी अधिक सम्पन्न है। अकेली इस बात से ही फ्रांस के पतन का रहस्य स्पष्ट हो जाता है।

जनरल चार्ल्स डी गाल जानते थे कि फ्रांसीसियों का ससार के अन्य सभी देशों पर मे विश्वास उठ गया है। इसलिए १८ जून, १९४० को लन्दन से अपना पहला प्रसिद्ध भाषण ब्राडकास्ट करते हुए उन्होंने इस प्रश्न का विशेष रूप में उल्लेख किया और कहा—“फ्रांस अकेला नहीं है, उसके पास एक महान् साम्राज्य है। फ्रांस चाहे तो उस ब्रिटिश साम्राज्य के कन्धे से-कन्धा मिला सकता

है, जिसका समुद्रों पर प्रभुत्व है और जो साहस के साथ लड़ता चला जा रहा है। इंग्लैण्ड की तरह वह भी अमेरिका के विशाल औद्योगिक साधनों से लाभ उठा सकता है। .. यह युद्ध एक ससारव्यापी युद्ध है इस. .. ससार में इतने साधन हैं कि उनकी सहायता से एक दिन हम अपने शत्रु को कुचल देंगे। आज दूसरों के यांत्रिक बल ने हमारी चूल अवश्य हिला दी है लेकिन भविष्य में हम इससे भी श्रेष्ठ यांत्रिक बल का प्रयोग कर विजय प्राप्त करेंगे। ससार का भाग्य इसी पर निर्भर है।”

जब रूस और अमेरिका भी युद्ध-क्षेत्र में उतर आये और ब्रिटेन ने अपनी विशाल वैमानिक शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया तो फ्रांस की आशाएँ फिर जाग्रत हो उठी और भीतर-ही-भीतर हिटलर के प्रति विरोध की भावना बढ़ने लगी।

फ्रांस को जितनी कम सहायता बाहर से मिली उतनी ही अल्प उसकी आंतरिक शक्ति भी थी। समाजवादी दल का एक शक्तिशाली भाग सधि का पक्षपाती था और सन् १९३८ में म्यूनिख में किये गये चेकोस्लोवेकिया के विभाजन की प्रशंसा कर चुका था। इसके विपरीत बहुत-से मजदूरों का मत था कि फ्रांस के ऐश्वर्यशाली नेताओं का आचार भ्रष्ट हो गया है, फाशिस्टों से उनकी सहानुभूति है और चेकोस्लोवेकिया और स्पेन को बेचकर उन्होंने फ्रांस के साथ विश्वासघात किया है। अनगिनत फ्रांसीसियों ने अपने कूटनीतिज्ञों और जनरलों के प्रति अविश्वास की भावना प्रकट की। राष्ट्र अपनी सेना की डींगें मार रहा था, किन्तु विशेषज्ञों को पता था कि फ्रांसीसी सेना की यांत्रिक सामग्री कितने पुराने ढंग की है। फ्रांस के पास अच्छे हवाई जहाजों की इतनी ज्यादा कमी थी कि वह जर्मन हवाई-सेना को रोकने में बिल्कुल असमर्थ था। फिर भी फ्रांस के राष्ट्रीय कोष में सोना पड़ा सड़ रहा था। वह अमेरिका से हवाई जहाज खरीदने के काम में लाया जा सकता था। किन्तु अर्थ-मंत्री ने रुपया देना मना कर दिया और लोगों को इस बात की शका हुई कि शायद फ्रांस के उद्योगवाले ही स्वयं आर्डर पूरा करना चाहते हैं। जब युद्ध आरम्भ हुआ तो बेचारे देशभक्त विमान-चालक ठठरी-जैसे हवाई जहाजों को लेकर यह सोचते हुए ऊपर उड़े कि हम आत्म-हत्या करने जा रहे हैं। चार्ल्स डीगाले ने, जो उस समय तक एक कर्नल ही थे, टैंकों के निर्माण पर जोर दिया था, किन्तु मार्च १९४२ में रियॉम के मुकदमे में गवाही देते हुए फ्रांस के भूतपूर्व प्रधान मंत्री दलादिये ने बताया कि स्पेन के गृह-युद्ध में इटली की बस्तरबन्द टुकड़ियों का जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उससे फ्रांसीसी विशेषज्ञों को

इस बात का प्रमाण मिल गया था कि वल्टरवन्द मोटरगाडियो द्वारा युद्ध करने का विचार गलत है। फ्रांसीसी जनरलो को टैकी नहीं, बल्कि मैजीनी लाइन में विश्वास था।

रियोम के ही मुकदमे में गुवला चैम्बर ने जो महासभा के आरम्भ होने के समय फ्रांस के हवाई-मन्त्री थे, कम्युनिस्टो पर इस बात का दोषारोपण किया कि रुस और जर्मनी में सन्धि होने के बाद उन्होंने फ्रांस की हवाई जहाज बनाने वाली फैक्ट्रियो के काम में बाधा डाली। उन्होंने हवाई जहाज के निर्माताओं पर भी विमान-निर्माण-योजना में विलम्ब करने का दोषारोपण किया। दलादिये ने गवाही देते हुए कहा कि निर्माताओं के काम न करने का उद्देश्य प्रमाणित करना था कि हवाई जहाज बनाने वाली फैक्ट्रियो का राष्ट्रीयकरण एक मूर्खता है। जैसा कि पॉलरेनॉ ने अपने सस्मरण में लिखा है, “इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि फ्रांस के पास न टैको की कोई टुकड़ी रही न हवाई जहाजों की”। (पॉलरेनॉ सन् १९४० में मार्च से जून तक फ्रांस के प्रधान मन्त्री थे)।

इन, और अहतो दूसरी बातों से यह सिद्ध हो जाता है कि द्वितीय महा-समर के आरम्भ होने से वर्षों पहले से ही फ्रांस में एक भयंकर गृह-युद्ध चल रहा था, जिसके कारण उसके अनेक खण्ड तो हो ही गये थे, साथ-ही-साथ उसकी शक्ति भी नष्ट हो गई थी और उसका प्रवृत्ति पराजय-सूचक बन गई थी।

फ्रांसीसी अपनी जल-सेना की सहायता से अफ्रीका और एशिया में युद्ध जारी रख सकते थे, किन्तु पेटाँ न तो प्रजातन्त्रवादी थे न फाशिस्ट-विरोधी; इसलिए उन्हें फाशिज्म के विरुद्ध युद्ध करने की कोई आन्तरिक आवश्यकता नहीं थी।

सन् १९४२ में नव वर्ष के अवसर पर ब्राडकास्ट करते हुए पेटाँ ने कहा—“मुझे अपने देश के लिए न मार्क्सवाद की जरूरत है न उदार पूंजीवाद की। रहा केवल फाशिज्म, सो, इस प्रकार के नाजी विचारों वाला नेता नाजियो का विरोध नहीं कर सकता था।

फ्रांस का पतन उसके आन्तरिक दूषण और विदेशी सहायता की कमी के कारण हुआ। उसके घुटने टेक देने से जनतन्त्री शासन-प्रणाली के मौलिक दोष स्पष्ट हो गये और उसका आत्म-समर्पण किसी विशेष जनतन्त्री सरकार का अन्त नहीं बल्कि स्वयं जनतन्त्र के उपहास का आरम्भ माना गया।

इस प्रश्न पर मैंने २२ जून १९४० की शार्लट्सविले में वर्जीनिया विश्वविद्यालय की सार्वजनिक मामलों की सस्था के वार्षिक अधिवेशन में

विचार किया था। तभी हमें फ्रांस के जर्मनी से सधि कर लेने की सूचना मिली थी। उस पर अपने विचार प्रकट करते हुए मैंने कहा—“जनतंत्री सरकारों और जनतंत्र को दफनाकर सारे ससार में नाजी पताका के फहराये जाने में अभी बहुत देर है। फाशिज्म उस समय तक विजयी नहीं हो सकता जब तक कि सारी जनतंत्री सरकारें हरा न दी जाय, ऐसा होने से पहले इंग्लैंड और अमेरिका को पराजित किया जाना अनिवार्य है।”

फ्रांस के पतन की सूचना मिलने पर भी मैं आशावादी ही बना रहा। “अगर जर्मनी इंग्लैंड को फौरन नहीं कुचल सकता” मैंने कहा “तो गतिरोध उत्पन्न हो सकता है और मित्र-राष्ट्रों की विजय निश्चित हो सकती है, क्योंकि यदि जर्मनी इस समय नहीं जीत सकता तो वह बाद में भी नहीं जीत सकेगा और इसके विपरीत, यदि मित्रराष्ट्र इस समय विजय नहीं प्राप्त कर सकते तो बाद में अमेरिका की सहायता से कर सकेंगे।”

सन्धि के लक्ष्य के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करते हुए मैंने लिखा—“जनतंत्र अभी निर्दोष नहीं है, फिर भी जितनी तानाशाहियों से मैं परिचित हूँ उन सबसे वह अच्छा है। किसी भी तानाशाही राज्य में जनता को स्वतंत्रता नहीं मिली। इस ससार का विभाजन सफेद और काले के आधार पर नहीं हुआ है। सफेद कोई भी नहीं, किंतु दुर्भाग्यवश काले बहुत हैं। यदि आप सफेद की ही चिन्ता करेंगे और किसी दूसरे वर्ण का समर्थन नहीं करेंगे तो आपको उसकी प्रतीक्षा में अपने हाथी दाँत के मीनार में कयामत तक बैठना पड़ेगा। हमें तो भूरे रंग के जनतंत्र और काले रंग के एकाधिकारवाद में से किसी एक को चनना है। शांति का सबसे बड़ा लक्ष्य काले का अन्त करना और साथ-ही-साथ भूरे को अधिक सफेद बनाना है।” “मेरी योजना अब भी यही है” उस समय मैंने यह सुझाव रखा था कि “मित्रराष्ट्रों के विजयी होने के बाद यूरोप को एक सघ के रूप में संगठित करना चाहिए। सघ में आर्थिक, राष्ट्रीयता या सकीर्ण राजनैतिक राष्ट्रीयता का कोई स्थान नहीं होता। इतिहास इस बात का सिद्ध कर चुका है कि राष्ट्रों का उद्धार अन्तर्राष्ट्रीयता में है। पुरुष या देश के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा का कोई साधन नहीं।”

मेरे लेख के अन्त में एक छोटा-सा रूपक था, किन्तु समय समाप्त हो जाने के कारण मुझे उसे बिना सुनाये ही छोड़ देना पड़ा। मैंने लिखा था—“‘अ’ नाम के एक युवक व्यक्ति ने अपने रहने के लिए एक सुन्दर और मजबूत मकान बनाया और उसे जनतंत्र कहा। कुछ समय पश्चात् ‘ब’ नाम के एक दूसरे व्यक्ति ने उस मकान के पास वाले दूसरे मकान में आने की अनुमति

मांगी। उसके मालिक ने 'अ' से सलाह ली और उसे बताया कि 'ब' अग्नि द्वारा शकुन बनाने वाला एक प्रसिद्ध व्यक्ति है और आग लगाने के अपराध में दण्ड भी पा चुका है, किन्तु 'अ' ने 'ब' का पक्ष लेते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि यह एक बहुत ही नेक आदमी है।—इस प्रकार 'ब' मुसोलिनी वहाँ आ गया।

“कुछ ही दिनों बाद 'स' नामक एक तीसरा व्यक्ति जनतंत्र के सामने वाले मकान में आकर रहा। यह व्यक्ति बम और दूसरे विस्फोटक पदार्थ बनाने का प्रयोग किया करता था। पड़ोसियों ने 'अ' को सोवधान करते हुए कहा कि जनतंत्र सकट में है। 'अ' इस पर हँसा और बोला कि असल में मैं ही तो उस प्रयोगशाला के लिए रुपए दे रहा हूँ जो 'स' ने मेरे 'जनतंत्र' के सामने बनाई है। एक दिन 'ब' और 'स' 'अ' के पास जनतंत्र में आये। उन्होंने पूछा कि क्या आप हमारे एक साझीदार को कुछ समय के लिए अपनी प्रयोगशाला में ठहरने की अनुमति दे सकते हैं।” 'अ' सहर्ष तैयार हो गया और नये व्यक्ति (फ्रेको) ने उसकी छत पर तम्बू तान दिया। उसने पानी की बड़ी टकी को खाली कर बुरादे से भर दिया और अन्त में जनतंत्र में आग लग गई और 'अ' अपनी स्त्री और बाल-बच्चों के साथ उसी में जलकर राख हो गया।—तो क्या आप कहेंगे कि 'जनतंत्र' एक बुरे ढंग से बनाया गया मकान था? नहीं, आप कहेंगे कि 'अ' मूर्ख था।”

फ्रांस के पतन से अधिकांश अमेरिकनो के हृदय में परिवर्तन हो गया। इनमें अनेक व्यक्ति वे थे जो युद्ध से अलग रहने की पुकार उठाया करते थे। यह लोग साधारणतया विस्तृत महासागरो को अपनी रक्षा का साधन मानते थे और इसीलिए समुद्र पार के भगड़ो में फँसना नहीं चाहते थे। सच पूछिये तो महासागरो से इतना नहीं बनता-विगड़ता था जितना उनके दूसरे तट पर होने वाली घटनाओं से। जब तक कि फ्रांसीसी सेना और ब्रिटिश समुद्री बेड़े में आक्रमणकारी देश को यूरोप के अटलांटिक तट पर पैर जमाने से रोकने की शक्ति थी तब तक निस्संदेह महासागर रक्षावट का काम कर सकता था। किंतु जर्मनों के डियेप कैले और ब्रेस्ट तक पहुँच जाने के कारण इस बात का भय था कि कहीं ऐसा न हो कि अन्त में यही सागर जर्मनों के आने का साधन बन जाय। फ्रांस के पतन के बाद जर्मनी और अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं के बीच का बल ब्रिटेन का समुद्री-बेड़ा ही रह गया था। अतः ब्रिटेन के युद्ध-प्रयत्न में योग देने के लिए अमेरिका के पास यह एक ज़बरदस्त तर्क था।

इसीलिए प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने आज्ञा दी कि अमेरिकन तोपखानों और

कारखानों को सुव्यवस्थित कर ब्रिटिश सेना के लिए हथियार बनाये जाय। विन्स्टन चर्चिल के १४ मई १९४५ के एक वक्तव्य से पता चला कि जून १९४० के वसन्त के आरम्भ होने तक अमेरिका ने दस लाख राइफले और एक हजार तोपे मय बारूद के अटलांटिक के पार भेजी। इनके अलावा हवाई जहाज भी भेजे गये और इस सामान से ब्रिटेन को जर्मन-आक्रमण से अपनी रक्षा करने में बड़ी सहायता मिली। डन्कर्क के पलायन के बाद ब्रिटेन के पास मैना का एक भी डिवीजन ऐसा नहीं रह गया था जो शस्त्र-अस्त्र से लैस हो।

इस संकट के समय प्रेजिडेंट रूजवेल्ट का ध्यान प्रधानतः किस बात पर केन्द्रित था, इसका पता हमें उनके उस पत्र से लगता है जो उन्होंने २० दिसम्बर १९४० को एडमिरल लीही के पास भेजा था और जो बाद में ७ अक्टूबर १९४३ को अमेरिका के स्टेट विभाग द्वारा प्रकाशित हुआ। एडमिरल लीही उस समय विची (फ्रांस) की पेटा सरकार में अमेरिका के राजदूत थे। प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने उन्हें लिखा था—“अमेरिकावासियों की प्रधान दिलचस्पी ब्रिटेन को विजयी देखने की है।” स्पष्टतः अमेरिका अपनी तटस्थता छोड़ चुका था।

पल्लेहार्बर पर जापान द्वारा आक्रमण होने से पहले ही अमेरिका यदि सरकारी रूप में नहीं तो व्यावहारिक रूप में अवश्य ही युद्ध में प्रवेश कर चुका था। ३ सितम्बर १९४० को, जिस दिन युद्ध की पहली वर्ष-गांठ थी, रूजवेल्ट ने घोषणा की कि चर्चिल के साथ एक समझौता हो गया है, जिसके अनुसार अमेरिका ने अपने पचास पुराने विध्वंसक जहाज ब्रिटेन को दे दिये हैं और ब्रिटेन ने बदले में अमेरिका को अन्धमहासागर में सैनिक और समुद्री अड्डे दिये हैं। पूछा जा सकता है कि यदि विध्वंसक जहाज बहुत पुराने हो गये थे तो ब्रिटेन ने उन्हें क्यों मांगा। असलियत यह है कि ये जहाज बड़े अच्छे जगी जहाज थे और युद्ध में उन्होंने सभी जगह बड़ी अच्छी तरह काम दिया। ११ मार्च १९४१ को प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने उधार पट्टे कानून पर हस्ताक्षर किये, जिसके अनुसार दसियों करोड़ों डालर के शस्त्र धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध लड़ने वाले देशों को दिये गये। जैसे ही हिटलर या मुसोलिनी ने किसी नये देश पर आक्रमण किया वैसे ही उसे भी उधार पट्टे की सुविधा प्रदान की गई। ५ अप्रैल १९४१ को अमेरिका ने डेनिस ग्रीनलैंड की रक्षा का भार अपने ऊपर ले लिया। ७ जुलाई १९४१ को अमेरिका ने आइसलैंड पर अधिकार करने में इंग्लैंड का साथ दिया। और वही की ब्रिटिश टुकड़ियों की शक्ति बढ़ाने और उनके बदले अमेरिकनो को लाने का भी उत्तरदायित्व ग्रहण किया। सन्

१९४१ में अमेरिकन जल-सेना अन्वमहासागर में व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा पूर्वक लाने व ले जाने का काम करने लगी और नाजी पनडुब्बियों को ढूँढ-ढूँढकर नष्ट करने में अंग्रेजों के हाथ बटाने लगी। अमेरिका की कूटनीति भी जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध प्रवाहित होने लगी। उदाहरणार्थ अमेरिका के स्टेट विभाग ने थिची की पेटा सरकार को इस बात की बार-बार चेतावनी दी कि वह हिटलर को फ्रांसीसी समुद्री बेड़े का प्रयोग न करने दे। लेकिन अमेरिका में धुरी राष्ट्रों की सैनिक और व्यावसायिक युक्तियों को विफल करने का प्रयत्न किया गया। प्रेजिडेंट रूजवेल्ट, विदेश-मंत्री कार्डेल हल और दूसरे छोटे अफसरों ने अपनी घोषणाओं से बार-बार धुरी राष्ट्रों के विरुद्ध भावना प्रकट कर अपने तटस्थ न रहने का प्रमाण दिया।

पर्ल हार्बर की घटना से कई महीने पहले अमेरिका के सैनिक अधिकारियों ने धुरीराष्ट्रों को हराने में योग देने के सम्बन्ध में एक विस्तृत, व्यावहारिक, व्यापक और काल्पनिक योजना बनाई थी। साथ-ही-साथ रूजवेल्ट ने युद्ध से अलग रहने की माँग करने वाले सिनेटर्स और प्रतिनिधियों से मतभेद होने पर भी अमेरिका की सशस्त्र सेना और दूसरी रक्षात्मक व्यवस्थाओं को दृढ़तर बनाया।

इन युक्तियों को और इंग्लैंड की पूर्ण सहायता देने की योजना को भी अमेरिका की अधिकांश जनता का समर्थन प्राप्त था, फिर भी अमेरिकनों की युद्ध-क्षेत्र में जाने से रोकने की भावना बलवती ही बनी रही और १९४० के अन्त में प्रेजिडेंट रूजवेल्ट और वेन्डल विल्की दोनों ही ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ते हुए अपने-अपने भाषणों में देश को इस बात का आश्वासन दिया कि जब तक अमेरिका पर आक्रमण नहीं होगा, तब तक अमेरिका का एक दब्बा भी समुद्र पार नहीं भेजा जायगा।

७ दिसम्बर १९४१ को जापान ने अमेरिका पर आक्रमण कर इस अडचन को भी दूर कर दिया। सम्भव है कि इतिहास में यह घटना जापान की प्रथम आत्मघातक भूल कही जाय। इसने अमेरिकन धन-जन को नष्ट तो अवश्य किया, किन्तु साथ-ही-साथ स्वयं जापान के लिए मृत्यु को भी निमन्त्रण दिया।

३ सितम्बर १९३९ से, या ठीक-ठीक यों कहिए कि फ्रांस के पतन से, लेकर पर्ल हार्बर के आक्रमण तक अमेरिका में एक कोने से दूसरे कोने तक उन दो दलों में संघर्ष चलता रहा जिनमें से एक युद्ध से अलग रहना चाहता था और दूसरा प्रवेश करने के पक्ष में था।

मैसिकन, नेवरासका, एन्डर्सन, इडियाना, कैंटन, ओहियो और अनेक

दूसरे शहरो की शान्त गलियो में से होकर दोपहर से पहले के शांत वातावरण में कई बार गुजरा हूँ। उद्यान से घिरा हुआ लकड़ी का सफेद मकान, वरामदे में पड़ी हुई झूलदार कुरसिया, छाया देने वाले वृक्ष और खिड़कियों में रखे हुए फूलों के गमले—ये सब चीजें एक सन्तुष्ट, सुखी और आरामदेह जीवन का चित्र खींच देती थी। किन्तु खिड़की में एक झण्डा दिखाई दिया करता था जिस पर एक या दो तारों के सैनिक चिह्न होते थे। कभी-कभी तारों का नीला रंग सुनहला रंग दिखाई देता था जो मृत्यु का सूचक था। मैं बड़ी ही सरलता के साथ कल्पना कर सकता हूँ कि उस मकान में कोई माता या पत्नी बंठी-बंठी डाक से आने वाली किसी दूसरे पत्र की प्रतीक्षा कर रही है या किसी पुराने पत्र को पाँचवीं बार पढ़कर यह सोच रही है—“मेरे पुत्र या पति को इस सुन्दर भूमि को छोड़कर ऐसी जगह क्यों जाना पड़ा जिसके सम्बन्ध में मैंने पहले कभी नहीं सुना था ! वहाँ जाकर उसे क्यों गोली और गोलियों की चोट खाने के लिए मिट्टी में खुला पड़ा रहना पड़ा ? कौन जाने वह मर ही गया हो।” उसकी समझ में ऐन्जियो, वेस्टोन आदि नामों का अर्थ ही क्या था, सिवा इसके कि इनसे उसके हृदय में पीड़ा, आकांक्षा और एकाकीपन जाग्रत हो उठे।

एक बार मैं श्रीमती रुजवेल्ट से मिलने उनके घर न्यूयार्क गया। बात-चीत करने के बाद वह मुझे दरवाजे की ओर ले गई। बाहर वरामदे के फर्श पर दोपहर बाद का अखबार पड़ा हुआ था। उसे उठाकर मैंने श्रीमती रुजवेल्ट को दिया और उसमें हमने गुआडल नहर में जल-सेना के प्रथम बार उतरने का समाचार मोटे-मोटे अक्षरों में मुख्य शीर्षक के रूप में छपा देखा।

“उसमें मेरा भी एक लडका है,” श्रीमती रुजवेल्ट ने कहा। उनका अभिप्राय अपने लडके जेम्स से था। युद्ध के समय राजा से लेकर रक तक सेना में जाने से नहीं बच पाते।

गुआडल नहर, सिसली, ओकीनाव, कैसीना, नारमडी ये सब स्थान अमेरिकावासियों को बहुत दूर और महत्वहीन मालूम पड़ते हैं। फिर भी कितने आश्चर्य की बात है कि वहाँ हजारों अमेरिकन कब्रों में गड़े पड़े हैं और बहुतों की आँखें या हाथ-पैर जाते रहे हैं। यह आश्चर्य की ही बात नहीं, बल्कि पागलपन है। फिर भी इस पागल ससार के युद्ध में अमेरिका को हाथ बँटाना ही था और वह अपने उत्तरदायित्व से किनारा नहीं कर सकता था।

हम एक छोटे-से द्वीप में रहते हैं, जिसका नाम पृथ्वी है। यह आवश्यक नहीं कि किसी एक देश की समस्या से किसी दूसरे देश का सम्बन्ध हो ही, फिर

भी यदि वह समस्या हल नहीं होती तो उसमें सबका संबंध हो ही जाता है ।

कर्नल लिडबर्ग और अमेरिका के प्रमुख व्यक्तियों का यह विश्वास था कि यदि अमेरिका की रक्षा का प्रबन्ध उत्तम रीति से किया जाय तो उस पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता । इसलिए अमेरिका के सैनिक-दृष्टि से शक्ति-शाली रहते हुए उन्हें इस बात की कोई चिन्ता नहीं थी कि किस विदेशी राष्ट्र का पतन हुआ और किसका नहीं । ऐसी दशा में युद्ध में किसी एक देश का पक्ष ग्रहण करना उनकी समझ में अनावश्यक और तटस्थता के विपरीत था । यही कारण था कि युद्ध से अलग रहने के पक्षपातियों ने अमेरिकन कांग्रेस में उधार-पट्टा और ऐसे ही दूसरे कानूनों के विरोध में राय दी ।

कर्नल लिडबर्ग ने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकन आकाश-सेना में दस हजार हवाई-जहाज होने चाहिए । २३ जनवरी १९४१ के उधार-पट्टा बिल पर विचार होते समय उन्होंने प्रतिनिधि सभा की विदेशी मामलों की कमेटी के सामने कहा—“यूरोप के वर्तमान युद्ध का परिणाम चाहे कुछ भी हो, मैं समझता हूँ कि इतने हवाई जहाज अमेरिका की सुरक्षा के लिए काफी होंगे । आकाश-सेना के इस विस्तार के साथ-ही-साथ न्यूफाउन्डलैंड, कनाडा, पश्चिमी इंडीज, दक्षिणी अमेरिका के कुछ हिस्सों, मध्य अमेरिका, गलापैगोस द्वीप, हवाई द्वीप और अलास्का में हवाई अड्डे भी बनाने चाहिए ।”

लेकिन हवाई अड्डे क्यों ? निश्चय ही लिडबर्ग ने सोचा होगा कि इससे दुश्मन को रोकने या डराने का काम लिया जा सकता है । जब हम अमेरिका पर आक्रमण होने की सम्भावना का स्वीकार कर लेते हैं—जैसा कि लिडबर्ग ने अड्डों के लिए जोर देकर किया—तो प्रश्न केवल यह रह जाता है कि सम्भावित शत्रु का सामना किस प्रकार से अच्छी तरह किया जाय । अन्तर्राष्ट्रीय विचार वाले व्यक्तियों का मत था कि शत्रु का सामना उसके समस्त यूरोप और एशिया पर विजय प्राप्त करने के बाद नहीं, बल्कि पहले ही करना चाहिए ।

यदि ब्रिटेन को अमेरिका का माल न मिलता और उसे अमेरिका से भविष्य में भी सहायता मिलने की आशा न होती तो अवश्य ही वह घुटने टक देता । इसलिए उस समय जब कि जर्मनी पर अंग्रेजों द्वारा बमबारी नहीं हो रही थी और अमेरिका ने रूस को उधार-पट्टे की सुविधा दी थी, यदि हिटलर रूस पर आक्रमण कर देता तो निश्चय ही रूस पराजित हो जाता । उस स्थिति में चीन का पतन अवश्यम्भावी हो जाता और जर्मनी, इटली और जापान ये तीनों ही यूरोप, अफ्रीका और एशिया पर अधिकार जमाकर निश्चितता के साथ बैठे रहते, फ्रेंको के स्पेन का सहायता से वे व्यापार और प्रचार के मार्गों द्वारा

लैटिन अमेरिकन में भी घुस जाते ।

इन सम्भावनाओं को दृष्टि में रखते हुए स्वभावतः प्रत्येक अमेरिकन की यह इच्छा हो सकती थी कि उसके देश का कोना-कोना शस्त्र-सज्जित हो जाय, अमेरिका एक दुर्ग बन जाय और सदा सावधान रहे—चाहे इसके लिए उस पर कितना ही जोर क्यों न पड़े ।

फाशिस्टों की सैनिक सफलता से प्रभावित होकर अमेरिका के लोग एकाधिकारवाद के पक्षपाती बन सकते थे । लोग कहते कि देखो हिटलर को कामयाबी ही मिल गई । कुछ लोगो ने तो ऐसा कहा भी ।

अमेरिका को या तो हिटलर, मुसोलिनी और जापान के साथ उनकी शर्तों पर व्यापार करना पड़ता, या निर्वासित होकर रहना पड़ता । इस प्रकार युद्ध से अलग रहने के पक्षपाती अमेरिका को एक सकटजनक अवस्था की ओर ले जाते ।

सौभाग्यवश अधिकांश अमेरिकनो ने घुरीराष्ट्रों के शत्रुओं को सहायता देने के पक्ष में निर्णय किया । यह कहना ज्यादा सही होगा कि अमेरिका के लिए विजयी शत्रु के सामने आकर खड़े होजाने के समय तक प्रतीक्षा करने की अपेक्षा भावी शत्रुओं के साथ दूसरों की भूमि पर दूसरों की ही शस्त्र सेना की सहायता से लड़ना ज्यादा अच्छा था । उधार-पट्टा कानून अमेरिकन लोहा देकर अमेरिकन प्राण बचाने की एक बड़ी चतुराईपूर्ण और ऐतिहासिक युक्ति थी । अंग्रेजों और रूसियों द्वारा अधिक जर्मनों के मारे जाने का मतलब जर्मनों द्वारा कम अमेरिकनो का मारा जाना भी था ।

अमेरिकावासियों ने यह बात समझी और फ्रांस के पतन के बाद से उनकी इंग्लैंड को सहायता देने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती गई । सन् १९४० के वसन्त में “ऐम्पोरिया गजट” के सम्पादक विलियम ऐलेन ह्वाइट ने “मित्र-राष्ट्रों को सहायता देकर अमेरिका की रक्षा करने” की एक समिति बनाई । सैकड़ों अमेरिकन इस समिति में शामिल हुए । २६ मई १९४० को मैंने भी उसमें अपने को शामिल करने के लिए मिस्टर ह्वाइट को तार दिया । उन्होंने मेरे पास कई तार और पत्र भेजे । १३ जून १९४० के पत्र में उन्होंने लिखा—

“मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे हवाई जहाज, बन्दूक और गोला-बारूद यहाँ से काफी बड़ी मात्रा में भेजे जा रहे हैं । हम मित्रराष्ट्रों को युद्ध में डटे रहने में सहायता दे सकते हैं ।” ‘सकते हैं’ शब्द के नीचे उन्होंने लाल स्याही से निशान बना दिया था ।

जनवरी १९४० में श्रीमती वेल्स लैथम ने ब्रिटेन के लिए सामान इकट्ठा करने का आन्दोलन आरम्भ किया और कुछ ही दिनों में इस एजेन्सी द्वारा

न केवल कपडा, चिकित्सा के अस्त्र और दूसरी आवश्यक वस्तुओं का एकत्र किया जाना आरम्भ हो गया, बल्कि उसने अमेरिकन शहरों और गाँवों के हजारों व्यक्तियों में बमों के नीचे अकेले पड़े हुए एक वीर राष्ट्र को सहायता देने और उत्साहित करने का जोश भी भर दिया ।

अमेरिकन जनता केवल अनुकरण नहीं कर रही थी । “जनमत इन्स्टी-ट्यूट” के सचालक विलियम ‘ए’ लिडगेड ने १९४१ में लिखा कि आम जनता अपने राजनीतिक नेताओं से अधिक चुस्त और आगे है । इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि अमेरिकन जनमत ने यह सिद्ध कर दिया है कि—(१) अमेरिकी जनता स्पेन पर से प्रतिबन्ध उठा लेना चाहती थी (२) उसने म्यूनिख के समझौते की निंदा उस समय की थी जब कि फ्रांस और ब्रिटेन के नेता उस समझौते में की गई मूर्खता को समझ भी नहीं पाये थे, (३) उसने कांग्रेस की स्वीकृति से ५ महीने पहले ही तटस्थता-कानून में से शस्त्र-अस्त्र सम्बन्धी प्रतिबन्ध को निकाल देने की राय दी थी, (४) पिछले सात वर्ष अर्थात् नवम्बर १९३५ से ही वह जल, थल और नभ-सेनाओं, विशेषतः हवाई-बेड़े में वृद्धि करने के पक्ष में रही है ।”

श्री लिडगेड ने यह भी लिखा कि सम्भव है कि अभी तक जनता के विचारों की ओर किसी ने पर्याप्त ध्यान ही न दिया हो । बात भी यही थी । कांग्रेस ने शोर मचाने वाले अल्पसंख्यकों की अपेक्षा बहुसंख्यकों की चिन्ता कम की । जैसा कि जनतन्त्र-विरोधी देशों में हुआ करता है ।

फिर भी अमेरिका एक ऐसे युद्ध में विजयी बनने के लिए, जिसका उससे सम्बन्ध तो था, किन्तु जिसमें अभी वह निरत नहीं हुआ था, सघीय शासन-विधान को चलाता रहा ।

सन् १९४४ में एक दिन सन्ध्या समय आन्तरिक मामलों के प्रसिद्ध लेखक जॉन गन्थर के मकान पर कुछ विरोधी सम्वाददाताओं ने हार्पर के प्रेजिडेंट कंस कैंफील्ड, विदेशी मामले (फारेन अफेयर्स) नामक तिमाही पत्र के सम्पादक हैमिल्टन फिश, आर्मस्ट्रोंग, “न्यूयार्क हेरैल्ड ट्रिब्यून” के इरीटावान डोरेन और वैंडल विल्की ने आपस में बैठकर राजनीतिक समस्याओं पर विचार किया और अपने-अपने अनुभव बताये । विल्की ने कहा—“सन् १९४१ में मेरे इंग्लैंड से लौटने के बाद “रीडर्स डाइजैस्ट” के प्रकाशक डीविट वॉलेस ने मुझसे टेलीफोन करके कहा कि मैं फ्रैंडा ऊटले के उस लेख के उत्तर में कुछ लिखूँ जिसमें ब्रिटेन को सहायता देने के विरोध में प्रचार किया गया था । वॉलेस ने मुझे इस काम के लिए पाच हजार डालर देने का प्रलोभन दिया । मैंने उनसे

कहा कि आजकल मैं एक मुकदमे के सिलसिले में फँसा हुआ हूँ और मेरे पास लेख लिखने के लिए समय नहीं है। इस पर वॉलेस ने कहा कि—“बस १५०० शब्दों से काम चल जायगा, हम आपको ६ हजार डालर देंगे।” मैंने उनसे फिर कहा कि “मैं लेख लिखने में असमर्थ हूँ” किन्तु वॉलेस ने हठ करते हुए कहा—“मिस्टर विल्की, मैं आपको इस लेख के लिए ८ हजार डालर दूंगा।

आप जानते हैं कि ८ हजार डालर एक छोटी रकम नहीं है।” विल्की ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए मुसकराहट के साथ कहा—“मैंने लेख लिखन के लिए वचन दे दिया।” अपने सम्बन्ध में इस प्रकार की कहानियाँ कहने में विल्की बड़े निपुण थे।

उस लेख में विल्का ने लिखा—“अमेरिका के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि जनतन्त्री सस्थाएँ किस प्रकार जीवित रहें, किस प्रकार एक ऐसी जीवन-प्रणाली की रक्षा हो जो हमारे लिए इस ससार में अन्य सभी पदार्थों से अधिक महत्त्व रखती है।” हम ब्रिटेन को सहायता इसलिए दे रहे हैं कि जो लड़ाई वह लड़ रहा है वह हमारे लिए बहुत लाभदायक है। हिटलर की नीति, जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक—सभी क्षेत्रों में जनता को शासक का दास बनाये रखना चाहती है, स्वभावतः और स्पष्टतः स्वतन्त्रता के विरुद्ध है।”

स्टालिन और हिटलर—एक पुनरध्ययन

फ्रांस के पतन से अमेरिका इंग्लैंड और युद्ध-दोनों के निकटतर आ गया। उससे रूस का आक्रमण भी जल्दी हुआ। प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने दो साल पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। भूतपूर्व राजदूत जोसेफ ई० डेविस ने अपनी “मास्को यात्रा” (मिशन टू मास्को) नामक रिपोर्ट में लिखा है— “१८ जुलाई १९३९ को मैंने प्रेजिडेंट रूजवेल्ट के साथ व्हाइट हाउस में भोजन किया। उस समय चारों ओर चर्चा फैली हुई थी कि स्टालिन और हिटलर में गुटबन्दी होने वाली है। प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने मुझे बताया कि उन्होंने रूसी राजदूत श्रीमास्की से मास्को के लिए रवाना होते समय कह दिया था कि आप स्टालिन को बता दीजियेगा कि यदि रूस ने हिटलर का साथ दिया तो यह निश्चय है कि फ्रांस पर विजय प्राप्त करने के बाद हिटलर रूस की ओर मुड़ेगा और फिर रूस की वारी आयगी। उन्होंने मुझसे कहा कि यदि हो सके तो मैं ये शब्द स्टालिन और मोलोटोव तक पहुँचा दूँ।”

यहाँ हम एक ऐसी कूटनीतिज्ञता का उदाहरण देखते हैं जिसमें भविष्य की छाया पहले ही देख ली गई थी। रूजवेल्ट भूगोल, हिटलर और युद्ध को समझते थे। फ्रांस को जीतने के बाद और इंग्लैंड के जर्मन-सेना की पहुँच से बाहर होने के कारण हिटलर के सामने रूस पर आक्रमण करने के सिवा और कोई चारा ही नहीं था।

सन् १९४१ में हिटलर ने देखा कि इस समय इंग्लैंड यूरोप पर आक्रमण नहीं कर सकता, लेकिन बाद में अमेरिका की सहायता से कर सकता है। यह सोचकर हिटलर ने रूस पर आक्रमण करने की तिथि निश्चित कर ली। उसने अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से पहले ही रूस को कुचल देना चाहा।

दो बातें हिटलर की शक्ति से बाहर थी, एक तो इंग्लैंड पर आक्रमण

करना और दूसरे अमेरिका की बढ़ती हुई सहायता को देखकर चुप बैठे रहना । वह दो बातें कर सकता था, एक तो इंग्लैंड पर उसके साम्राज्य में से होकर आक्रमण करना या दूसरे रूस पर घावा बोलना । हिटलर ने अनुमान लगाया कि सम्मिलित ब्रिटेन और अमेरिका की तुलना में रूस का पतन अधिक सरल होगा । उसे आशा थी कि चूंकि जर्मनी ने "बोलशेविज्म के भयानक संकट के केन्द्र" रूस पर आक्रमण कर दिया है इसलिए पश्चिम के पूँजीवादी राष्ट्र कृत-ज्ञतावश जर्मनी पर आक्रमण करने का विचार त्याग देंगे ।

घटनाओं ने अक्सर यह सिद्ध किया कि हिटलर के अनुमान गलत थे । हिटलर को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि फ्रांस और इंग्लैंड, पोलैंड के कारण युद्ध नहीं करेंगे । उसने अपने सेनाधिकारियों के सामने एक गुप्त भाषण देते हुए कहा कि फ्रांस और इंग्लैंड बड़े डरपोक हैं । जर्मन-रूसी सन्धि का मुख्य अभिप्राय ही फ्रांस और इंग्लैंड को युद्ध की ओर से हतोत्साह करने का था । इसी बात का समर्थन मास्को के अधिकृत पत्र 'प्रवदा' ने २३ अगस्त १९४० की जर्मन-रूसी सन्धि का प्रथम वार्षिकोत्सव मनाते हुए अपने सम्पादकीय स्तम्भ में किया । उसने लिखा—“रूस और जर्मनी की सन्धि का समाचार साम्राज्य-वादी युद्ध के संयोजकों और प्रेरकों के लिए अन्तिम चेतावनी थी । किन्तु इस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और युद्ध आरम्भ हो गया ।”

न्यूरेमबर्ग में युद्ध-अपराधियों के मुकदमे में जर्मनी में पाये हुए जो सरकारी पत्र पेश किये गये, जिन्हे ७ दिसम्बर १९४५ को अमेरिकन समाचार-पत्रों ने उद्धृत किया, उनसे पता चलता है कि हिटलर ने जर्मन-सेना को पोलैंड पर आक्रमण करने का आदेश रूस से सन्धि करने के एक दिन बाद, अर्थात् २४ अगस्त १९३९ को दिया, जब कि उसे विश्वास हो गया कि इस सन्धि से पश्चिमी देश डर गये हैं और वे युद्ध से अलग रहेगे । -

हिटलर ने एक और भूल की । उसने यह आशा की कि पोलैंड की सैनिक-पराजय के साथ-ही-साथ युद्ध का भी अन्त हो जायगा । सितम्बर और अक्टूबर सन् १९३९ में हिटलर ने फ्रांस और इंग्लैंड से कई बार सन्धि का प्रस्ताव किया । गोयरिंग ने बर्लिन की एक सभा में कहा कि पोलैंड के चार हफ्ते की लड़ाई के बाद हम अब एक सम्मानपूर्ण सन्धि के लिए तैयार हैं ।” पोलैंड को हड़पने के बाद नाज़ी कुछ देर के लिए साँस लेना चाहते थे । बाद में उन्होंने शत्रुओं को भी शिकार बनाया ।

पोलैंड की विजय के बाद रूस ने भी युद्ध को समाप्त करने की चेष्टा की ३० नवम्बर १९४० के 'प्रवदा' में स्टालिन ने लिखा कि इंग्लैंड और फ्रांस

के शासकवर्गों ने जर्मनी के सन्धि-प्रस्ताव और रूस के युद्ध को शीघ्र-से-शीघ्र समाप्त करने के प्रयत्नों को रुखाई के साथ ठुकरा दिया ।

रूसी सरकार ने हिटलर के विरुद्ध युद्ध करना निरर्थक समझा । ६ अक्टूबर १९३९ को रूस के सरकारी समाचार-पत्र 'मास्को इजवेस्टिया' ने लिखा कि हिटलरवाद को नष्ट करने के अभिप्राय से युद्ध आरम्भ करना एक भयकर राजनीतिक मूर्खता करना है ।" इसीलिए रूस के विदेश-मन्त्री मोलोटोव ने फ्रांस और इंग्लैंड को 'आक्रमणकारी' कहकर पुकारा ।

द्वितीय महासमर का उद्गम रूस और जर्मनी का समझौता ही था; लेकिन यह कहना ठीक नहीं कि रूस को किसी बड़े युद्ध की आशका थी । रूसी अधिकारियों ने सोचा कि रूस और जर्मनी में समझौता हो जाने से इंग्लैंड और फ्रांस पोलैंड के सम्बन्ध में वही करने को तैयार हो जायेंगे जो उन्होंने म्यूनिख में चेकोस्लोवेकिया के सम्बन्ध में किया था, और वे लड़ाई से दूर रहेंगे । बोल्शेविक जानते थे कि यदि ब्रिटेन और फ्रांस पोलैंड के आत्म-समर्पण के लिए तैयार नहीं हुए तो हिटलर पोलैंड पर आक्रमण करके उसे कुचल डालेगा और रूस के साथ उसका बटवारा कर लेगा । स्टालिन ने यह भी सोचा कि इसके बाद ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकारों को भूख मारकर जर्मनी के साथ सन्धि करनी पड़ेगी । उसे आशा थी कि इस प्रकार जर्मनी और पश्चिमी देशों में जा शत्रुता उत्पन्न होगी वह रूस की सुरक्षा का साधन बनेगा । यही कारण था कि स्टालिन ने हिटलर के साथ सन्धि कर ली ।

घटनाओं ने सिद्ध किया कि स्टालिन ने भी भूल की । उसने यह नहीं सोचा कि अब लन्दन में, और इसलिए पेरिस में भी, शान्ति-याचकों का राज नहीं है । इंग्लैंड और फ्रांस सधि नहीं करेंगे, फ्रांस का पतन होगा और, जैसी कि प्रेजिडेन्ट रुजवेल्ट ने भविष्य-वाणी की थी, रूस को भी उससे नुकसान उठाना पड़ेगा ।

शासन के अधिकारी और उच्च सरकारी अक्सर भी अक्सर साधारण व्यक्तियों की ही भाँति दुर्लभ नीति का अनुसरण करते हैं । मैं यह बात इसलिए कहता हूँ कि मैं इस प्रकार के अधिकारियों के साथ बैठ चुका हूँ और भावी घटनाओं पर विचार भी कर चुका हूँ । कभी-कभी इन लोगों के अनुमान ठीक होते हैं, किन्तु वे भूलें भी करते हैं, जिसका दड जनता को भुगतना पड़ता है ।

सितम्बर १९३८ की म्यूनिख वार्ता के बाद शत्रु को शान्त रखने की चेष्टा में जो ग्यारह महीने का समय बीता उसमें फ्रांस और इंग्लैंड को युद्ध से बचे रहने में उतनी ही कम सहायता मिली जितनी कि रूस को जर्मनी से सधि

करने के बाद के २२ महीनों में । मान-मनोअन से युद्ध की सम्भावना बढ़ जाती है घटती नहीं ।

यह बात आँकड़ों द्वारा सिद्ध की जा सकती है कि हिटलर को सतुष्ट रखने की चेष्टा में ब्रिटेन और फ्रांस ने न तो इतने शस्त्र बनाये न खरीदे ही कि उनसे चेकोस्लोवेकिया की खोई हुई सेना, शस्त्रों और शस्त्र-फैक्टरियों की क्षति-पूर्ति हो सकती । यह बात कही जा सकती है कि चेम्बरलेन और दलादिये की सतुष्टीकरण की नीति के बावजूद भी ग्रेट-ब्रिटेन विजयी हुआ और फ्रांस मुक्त कर लिया गया । किन्तु सोचना यह है कि इस बात के लिए ब्रिटेन और फ्रांस को कितना अतिरिक्त मूल्य चुकाना पड़ा ।

रूस ने तुष्टीकरण की अवधि में शस्त्र बनाये तो जरूर, लेकिन इतने नहीं कि उनसे एक ओर तो फ्रांस की क्षति-पूर्ति हो जाती और दूसरी ओर जर्मनी और पराजित देशों ने इस बीच जितना शस्त्र बनाया उसकी बराबरी की जाता । यह तो ठीक है कि अन्त में रूस को विजय प्राप्त हुई, किन्तु बताया जाता है कि युद्ध में रूस के दो करोड़ २० लाख नागरिक मारे गये । किमी भी देश ने इस सख्या को डेढ़ करोड़ से कम नहीं कूता है । यह सख्या उन दस लाख स्त्रियों और बच्चों से अलग है, जो घायल, रोग-ग्रस्त या अपंग बन गये । रूस की औद्योगिक और कृषि-सम्बन्धी अपार क्षति भी इसमें शामिल नहीं है । अंतिम विजय का अर्थ यह नहीं है कि जल्दी-से-जल्दी लोगों को सन्तुष्ट करने की चेष्टा की जाय । हो सकता है कि शान्त प्रकृति वाले विजय को सिर्फ एक अखबारी सुर्खी या किसी आपसी बहस में जीतने के लिए तर्क-मात्र समझे, किन्तु सभ्य व्यक्तियों के सामने जो असली सवाल होते हैं, वे ये हैं—विजय के लिए हमें कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी ? अगर कुछ ज्यादा चतुराई के साथ काम किया गया होता तो कम मूल्य देना पड़ता ।

रूस ने अगर कुछ अधिक बुद्धिमत्ता से काम लिया होता तो वह युद्ध से अलग रहता और सन् १९३९ में फिलैंड में फ़ॉसने के बजाय फ्रांस पर सकट आने के समय लड़ता । रूजवेल्ट ने सन् १९४० में समझ लिया कि ब्रिटेन को अधिक-से-अधिक सहायता देने में ही अमेरिका की भलाई है । स्टालिन को भी यह समझ लेना चाहिए था कि रूस की भलाई फ्रांस को अधिक-से-अधिक सहायता देने में है ।

सन् १९४० के वसन्त-काल में यदि रूस ने दूसरा मोर्चा खोल दिया होता तो उससे जर्मनी की सेनाएँ बँट जाती, फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी की आकाश-सेना इतनी तीव्रता से काम नहीं कर सकती और सम्भवतः फ्रांस का पतन भी एक

गया होता, ठीक उसी तरह 'जैसे सन् १९१४ की गरमी में रूस ने जर्मनी पर आक्रमण कर देने से मारन में फ्रांस का सँभलना सम्भव हो गया था। रूस की सहायता के बिना सन् १९१४ में भी फ्रांस का उतनी ही शीघ्रता से पतन हो गया होता जितनी शीघ्रता से १९४० में हुआ।

युद्ध को रोके रखने की यह नीति खतरे से भरी हुई थी। मसलन, सम्भव था कि रूसियों के हस्तक्षेप करने पर भी फ्रांस घुटने टेक देता और उस दशा में हिटलर बालकान देशों को हड़पने के बाद रूस पर टूट पड़ता। फिर भी उसने जो किया वह हमारे सामने है। यदि रूस ने पूर्वी मोर्चे पर युद्ध छेड़ दिया होता तो फ्रांस को बचाने का कम-से-कम अवसर अवश्य मिलता। स्टालिन का सबसे बड़ा दुःसाहस फ्रांस का हर्जाना और फिर यूरोप में हिटलर के साथ अकेले लड़ना था।

स्टालिन ने यह अनुमान लगाने में भूल की कि इंग्लैण्ड और फ्रांस पोलैण्ड पर आक्रमण होने से पहले हिटलर की बातें मान लेंगे। उसने यह अनुमान भी गलत लगाया कि पोलैण्ड के पतन के बाद फ्रांस और इंग्लैण्ड युद्ध से अलग हट जायेंगे। इसके अलावा उसने फ्रांस को सहायता न देने की भी भूल की।

स्टालिन ने हिटलर की युद्ध-नीति के केन्द्रीय तत्त्व को भी समझने में गलती की। इस सम्बन्ध में हमें बड़ा दिलचस्प प्रमाण रूस के भूतपूर्व विदेश-मन्त्री मैक्सिम लिटविनाव से मिलता है जो दूसरे कूटनीतिज्ञों की तुलना में विश्व-स्थिति को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाता था। १३ दिसम्बर १९४१ को उसने वाशिंगटन के सम्वाददाताओं को एक वक्तव्य में बताया—“मेरी सरकार को हिटलर के विश्वासघातपूर्ण विचारों की चेतावनी मिल चुकी थी, किन्तु उसने उस पर अधिक गम्भीरता के साथ विचार नहीं किया। इसका कारण यह नहीं था कि रूस को हिटलर के हस्ताक्षरों की पवित्रता में विश्वास था या वह यह समझता था कि हिटलर जिन सधियों पर हस्ताक्षर कर चुका है और जो पवित्र प्रतिज्ञायें उसने बार-बार दुहराई हैं उन्हें वह भग नहीं करेगा। रूसियों ने सोचा कि अगर पश्चिम में युद्ध समाप्त करने से पहले हिटलर पूरब में हमारे-जैसे शक्तिशाली देश में भिड़ेगा तो यह उसका पागलपन होगा।”

हिटलर ने पागलपन किया ही। लेकिन क्या स्टालिन को यह मालूम नहीं था कि हिटलर के सामने और कोई चारा ही नहीं था? स्टालिन को आशा थी, और इसीलिए विश्वास भी था, कि फ्रांस की लड़ाई के बाद जर्मनी इंग्लैण्ड के मृत्यु-पाश में फँस जायगा और वह उस समय तक नहीं निकल पायगा जब तक कि

दोनों में से एक का पतन न हो जाय। रूस को यह भी आशा थी कि इन दोनों में से जो देश जीतेगा वह इतना थक जायगा कि उसमें रूस को छेड़ने की शक्ति न रह जायगी। स्टालिन को यह बात तो समझ में नहीं आई कि सन् १९४० और ४१ में ब्रिटेन का शक्ति की परीक्षा लेने के बाद और उसे बलवान पाकर हिटलर उधर से अपना पजा ढोला कर देगा और वह रूस की छाती पर चढ़ बैठेगा।

स्टालिन न हिटलर और विश्व-स्थिति दोनों ही को गलत समझा और यही कारण था कि उसने हिटलर के साथ गुटबंदी का।

इस गुटबंदी से और बाद के समझौते से भी दोनों दलों को लाभ की आशा थी, कुछ सच्ची और कुछ भ्रामक। २३ अगस्त १९४० को 'प्रवदा' ने कहा कि इस सन्धि से जर्मनी को पूरव में अखण्ड सुरक्षा की गारंटी मिल गई है।" यह बात सच थी और इसके कारण हिटलर को पश्चिम में विजय-ही-विजय प्राप्त हुई। नाज, चरी, जूट, पेट्रोल आदि अपरिमित मात्रा में सीधे रूस से और रूस के जरिये जापान से जर्मनी आये। १९४० में जर्मनी को सोत लाख टन तेल प्राप्त हुआ।

यूरोप और दूसरे देशों के कम्युनिस्ट-दल एकाएक सुलह, समझौते और युद्ध से अलग रहने के पक्षपाती बन गये। उन्होंने अपना क्रोध जर्मनी के शत्रुओं पर उतारा और स्वयं जर्मनी की ओर से चुप्पी साध ली। समझौते के बाद ऐसा होना अनिवार्य था। रूसी समाचार-पत्रों ने डेन्मार्क और नार्वे पर किये गये हिटलर के आक्रमणों का समर्थन किया। ३० नवम्बर, १९४० के 'प्रवदा' में स्टालिन ने लिखा—“जर्मनी ने फ्रांस और इंग्लैंड पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी पर आक्रमण किया। वर्तमान युद्ध का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है।” चूंकि स्टालिन ने युद्ध का दोषारोपण फ्रांस और इंग्लैंड पर किया, इसलिए यह कैसे हो सकता था कि जनतंत्री राज्यों के कम्युनिस्ट फ्रांस या ब्रिटेन का पक्ष लेते। जर्मनी और रूस में जब तक सन्धि रही तब तक सारे रूस में फाशिस्ट और जर्मन-विरोधी प्रचार रुका रहा। फ्रेडरिक वुल्फ के “प्रोफेसर मेमलौक” जैसे नाजी-विरोधी और आइन्स्टीन के ‘अलकजेण्डर नेवेस्की’ जैसे जर्मन-विरोधी फिल्मों का दिखाया जाना बन्द कर दिया गया। आइन्स्टीन ने वेगनर के “डाइवाक्वुरे” नाम का नाटक खेला और नाज़ी अफसरों ने उससे—एक यहूदी से—हाथ मिलाया और बघाई दी, रूसी खम्भों पर रूस के हथौड़े और हँसिया वाले झंडे के साथ-साथ जर्मनी का स्वस्तिक झंडा फहरा देने के बाद ऐसा होना अनिवार्य था। ९ अक्टूबर, १९४१ को ‘इजवेस्तिया’ ने विरक्तभाव से लिखा—“प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है

कि वह किसी सिद्धान्त के सम्बन्ध में अपने विचार स्वतन्त्रतापूर्वक प्रकट करे और उसे स्वीकार करे या न करे। हिटलरवाद या किसी भी दूसरी राजनीतिक विचार-प्रणाली का सम्मान करना भी सम्भव है और घृणा की दृष्टि से देखना भी। यह सब अपनी-अपनी पसन्द की बात है।” जब स्वयं मास्को में फाशिज्म का विरोध रोक जा रहा था और नाजियों के प्रति सहिष्णुता का प्रचार किया जा रहा था, तो बाहर के कम्युनिस्ट किस प्रकार नाज़ी-विरोधी हो सकते थे! उन दिनों नाज़ीवाद का विरोध करना या युद्ध का समर्थन करना वास्तव में स्टालिन का विरोध करने के समान था। इसलिए जनतन्त्री देशों के कम्युनिस्टों ने रक्षात्मक यत्र तैयार करने वाले कारखानों में हड़ताल की आग फैलाई। अमेरिकन कम्युनिस्ट दल ने ‘जर्मनी के बनाये हुए’ माल पर से बहिष्कार उठा लिया और हिटलर के रूस पर आक्रमण करने के दिन तक वे ह्वाइट हाउस पर धरना देते हुए रूजवेल्ट की नाज़ी-विरोधी नीति के विरुद्ध प्रदर्शन करते रहे। ब्रिटिश कम्युनिस्टों ने तो उन दिनों भी, जब ब्रिटेन पर जर्मनी द्वारा धुआँधार बम बरसाये जा रहे थे, ब्रिटिश प्रयत्नों में बाधा डाली। फ्रांसीसी कम्युनिस्टों ने अपने देश को शीघ्र पराजित होने में यथासाध्य सहायता की। यदि स्टालिन ने रूस की शक्ति को बढ़ाने के लिए अवकाश निकालने के अभिप्राय से हिटलर के साथ समझौता किया था, तो समझ में नहीं आता कि कम्युनिस्टों ने क्यों हिटलर को सहायता दी और जर्मनी के विरुद्ध लड़ने वाले देशों के युद्ध-प्रयत्न में बाधा डालकर रूस को दुर्बल बनाया।

जो रूस किसी समय फाशिज्म का सबसे बड़ा विरोधी और सामूहिक सुरक्षा का पक्षपाती था, उसी ने उस देश में व्यापक सधिकार ली, जहाँ कम्युनिस्टों, यहूदियों और जनतन्त्र के प्रति अनाचार होते थे और जहाँ की फाशिस्ट सरकार जातीयता, लालच और वर्चस्व का भावना से भरी हुई थी। स्वभावतः उसके इस कार्य से, चाहे वह किसी भी प्रलोभन या आकर्षण से प्रेरित क्यों न हुआ हो, सिद्धान्त के उस अपमान और राजनीतिक व्यभिचार के फैलने में सहायता मिली जिसके कारण पेटाँ को शीघ्र ही हिटलर के सामने सिर झुकाना पड़ा और जो अब भी हम में पाया जाता है। रूस और जर्मन की सन्धि ने कितने ही सिद्धान्तहीन कार्यों और विचारों को जन्म दिया। सार्वजनिक मामलों में किसी के शिष्टता से गिरने से हिटलर को अपनी तानाशाही चक्की पीसते रहने के लिए ममाला मिल जाता था और वह अब भी एकाधिकारवादियों के लिए लाभदायक है।

हिटलर को रूस से सन्धि करने से ये लाभ हुए। अब देखना है कि

रूस को क्या लाभ हुआ। रूस को दूसरी की भूमि पर अधिकार प्राप्त हुआ। सबसे पहले उसने पूर्वी पोलैण्ड के उतने भाग पर अधिकार किया जितने के लिए दोनों देशों में आपस में समझौता हुआ था। १४ अक्टूबर १९३९ को रिबनट्राप ने डैनजिग में एक भाषण देते हुए बताया कि पोलैण्ड में युद्ध आरम्भ होने के कुछ ही दिनों बाद "रूसी सेनायें सारे मोर्चों पर आगे बढ़ी और उन्होंने पोलैण्ड पर उस रेखा तक अधिकार कर लिया जो पहले ही रूम के साथ बातचीत करके तै कर ली गई थी।"

मैं रिबनट्राप के शब्दों पर उस समय तक विश्वास करने को तैयार नहीं होता जब तक कि वे वस्तुतः कार्यरूप में परिणत न हो जाय। सत्य यह है कि पोलिश सेना का पीछा करते हुए जर्मन-सैनिक अक्सर निर्धारित सीमा को पार कर जाते थे और जब कभी ऐसा होता था तो रूसी सेना के वहाँ पहुँचते ही जर्मनी के सशस्त्र सैनिक फौरन पीछे हट जाते थे। निश्चय ही जर्मनी के विजयी सैनिक नाजी सरकार से पहले से ही हिदायत पाये बिना ऐसा कदापि न करते।

जब हिटलर ने पोलैण्ड को बहकाने और बिना लड़ें ही हार मानने के लिए विवश करने के अभिप्राय से प्रचार आरम्भ किया तो रूम के विदेश-मंत्री लिटविनाव ने २७ नवम्बर १९३८ का मास्को के पोलिश-राजदूत के सामने पोलैण्ड के साथ की हुई अनाक्रमण-संधि का फिर से समर्थन किया। इसका अभिप्राय पोलैण्ड निवासियों को दृढ़ बने रहने के लिए प्रोत्साहन देना था। २९ जून १९३९ को मोलोटोव ने, जो इस बीच रूस के विदेश-मंत्री बन गये थे, मास्को-स्थित पोलिश-राजदूत को सरकारी रूप से विश्वास दिलाया कि यदि पोलैण्ड पर आक्रमण हुआ तो रूस उसे न केवल आर्थिक सहायता देगा बल्कि पुर-मान्स्क बन्दरगाह के रास्ते रूसी प्रदेश को पार कर सामान मँगाने का भी अधिकार देगा। व्यापार के कमिश्नर मीकोयाँ न जो एक उच्च-पदासीन कम्युनिस्ट थे, पोलिश अधिकारियों को एक बार फिर यही आश्वासन दियो। जब तक कि रूसी सरकार को पश्चिमी देशों के साथ समझौते की सम्भावना दिखाई दी, तब तक उसने पोलैण्ड से होकर रूसी सेना के गुजरने का—सम्भवतः जर्मनों से लड़ने के लिए—प्रश्न नहीं उठाया। जैसा कि सन् १९३८ में म्यूनिख-संकट के समय लिटविनाव ने मुझसे बार-बार कहा था, प्रत्येक रूसी अफसर को यह बात मालूम थी कि पोलैण्ड की कोई भी सरकार रूसी सैनिकों को अपने देश में नहीं घुसने देगी। सन् १९३९ में जब मास्को में रूस, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच समझौते की बातचीत चली तो रूस ने अपनी सेना के पोलैण्ड में प्रवेश करने की बात १५ अगस्त से पहले नहीं उठाई। उस समय तक २३ अगस्त के

रूसी-जर्मन समझौते का मसविदा तैयार हो चुका था और यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि रूस पोलैंड की सहायता नहीं करेगा। यही बात उस समय वार्त्ता को भग करने के लिए कारण बन गई।

स्टालिन जानता था कि सीधे पोलैंड से समझौता करने से या फ्रांस और ब्रिटेन से बातचीत करके पोलैंड का एक टुकड़ा भी नहीं मिल सकेगा। हिटलर से संधि करने से उसे पोलैंड में हिस्सा मिला। यही बात बाल्टिक राज्यों के सम्बन्ध में भी हुई। फ्रांस और इंग्लैंड से बातचीत करते समय रूसी सरकार ने इन राज्यों में अपने लिए विशेष अधिकार माँगे। ब्रिटेन और फ्रांस उन्हें स्वतंत्र राष्ट्र समझते थे और इसीलिए उन्होंने स्टालिन को वहाँ सैनिक अड्डे बनाने का अधिकार नहीं दिया किन्तु हिटलर ने स्टालिन को यह अधिकार दे दिया।

इस प्रकार कार्य करना स्टालिन की विशेषता थी। जब वह अपनी मन-चाही वस्तु को पाने का एक रास्ता बन्द देखता था तो वह कुछ देर के लिए रुक जाता था और फिर चक्कर काटकर उस वस्तु को दूसरे रास्ते से प्राप्त करने का प्रयत्न करता था। यह ढंग वह केवल अपनी घरेलू नीति में ही नहीं बल्कि विदेशी नीति में भी अक्सर काम में लाता था। स्टालिन टेढ़े-तिरछे रास्तों से होकर सीधे आगे बढ़ा करता है। उसने जब देखा कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की नैतिकता रास्ते में रुकावट डाल रही है तो उनके साथ बातचीत बन्द कर दी और हिटलर के साथ सन्धि कर ली, जिसके फलस्वरूप उसे पोलैंड के एक भाग पर अधिकार मिल गया और बाल्टिक के छोटे-छोटे देशों पर अपना संरक्षण स्थापित करने में भी सफलता मिली। बाद में यह सोवियत रूस में अन्तर्हित कर लिया गया।

२२ जून १९४१ को रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए हिटलर ने बताया कि रूसी-जर्मन सन्धि की बातचीत करते समय एक विशेष समझौता उस स्थिति के लिए किया गया था जो ब्रिटेन के भड़काने से पोलैंड के जर्मनी के विरुद्ध शस्त्र उठा लेने पर उत्पन्न होती। यदि पोलैंड लड़ता नहीं तो रूस को उसका एक हिस्सा मिलता और यदि लड़ता, तो विशेष समझौते के अनुसार रूस को बाल्टिक में कुछ अतिरिक्त अधिकार दिये जाते। इस सम्बन्ध में हिटलर ने कहा—“जर्मनी ने मास्को में यह बात गम्भीरतापूर्वक कह दी थी कि एस्थोनिया, लैटविया, फिनलैंड और वेसेरीविया तो जर्मनी के राजनीतिक प्रभाव से बाहर अवश्य हैं किन्तु लिथुएनिया नहीं। जर्मनी इस क्षेत्र को रूस से प्रभावित समझता था।”

अमेरिका के स्टेट विभाग को जो जानकारी प्राप्त है उसमें हिटलर के इस कथन का समर्थन होता है। घटनाये भी यही मिश्र करती है। २८ मित-बर १९३९ को एस्थोनिया ने रूस के प्रभाव में पड़कर उसके साथ पारस्परिक सहायता का समझौता कर लिया और उसे बाल्टिक मागर में जहाज़ी अड्डे भी प्रदान किये। ५ अक्टूबर को लेटविया और १६ अक्टूबर को लिथुवेनिया ने भी रूस के साथ ऐसा ही समझौता किया। ३० नवम्बर को रूस ने फिनलैंड पर आक्रमण कर दिया। लिथुवेनिया पर अधिकार करने के मिवा, जिसको बाद में हिटलर ने मान लिया, रूस ने जो-जो काम किये वे रूस और जर्मनी के अगस्त १९३९ के समझौते के अनुकूल थे और अपने वचनको पूरा करने के लिए हिटलर ने जर्मनी को बाल्टिक देशों से, जहाँ वे कई पीढ़ियों से रहते चले आये थे, वापस आने का आदेश दिया। लाखों जर्मनी ने इस आदेश का पालन किया।

रूसी विस्तार का दूसरा परिच्छेद २७ जून १९४० को आरम्भ हुआ, जब कि रूसी सेनाओं ने रमानिया में प्रवेश किया और बेसेरेविया तथा उत्तरी बुकोविना पर अधिकार कर लिया। २१ जुलाई को रूस ने लिथुवेनिया, लैटविया और एस्थोनिया को पूर्ण रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया। हिटलर ने पहले से ही फ्रांस और बाद में ब्रिटेन को हड़पने की योजना बना रखी थी। इसलिए जर्मन-सेना ने पश्चिम की ओर मुँह रखा और स्टालिन ने छुटकर मौज उड़ाई।

२२ जून, १९४१ को जर्मनी के विदेश-मंत्री रिबनट्राप ने बताया कि रूस का बाल्टिक देशों पर अधिकार करना और उन्हें बोलशेविक रंग में रँगना रूस द्वारा दिये गये आवासनों के विरुद्ध था। मोलोटोव ने भी इसी का समर्थन करते हुए कहा—“रूस की एस्थोनिया, लैटविया और लिथुएनिया के साथ की गई नई संधियों में इस बात का दृढ़ संकल्प किया गया है कि संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राष्ट्रों की सार्वभौम सत्ता नष्ट नहीं होनी चाहिए और दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप न करने के सिद्धान्त का पालन करना चाहिए”। मोलोटोव ने जोर देते हुए यह भी कहा—“बाल्टिक देशों के सोवियतीकरण की चर्चा केवल हमारे पारस्परिक शत्रुओं और रूस के विरुद्ध आग भड़कानेवालों के लिए ही लाभदायक है। ३१ अक्टूबर, १९३९ को दिये गये इस स्पष्ट वक्तव्य ने रूस को २१ जुलाई १९४० को बाल्टिक देशों पर आधिपत्य जमाने और उन्हें सोवियत् रँग में रंगने से रोका नहीं और न मोलोटोव ने ही यह कहना बन्द किया कि रूस हमेशा अपने वचनों का पालन करता है।”

जर्मनी के पोलैण्ड में लड़ने से रूस को पोलैण्ड और बाल्टिक देशों में

लाभ हुआ। इसी तरह उसके पश्चिमी यूरोप पर आक्रमण करने से रूस को रूमानिया और बाल्टिक देशों में हिस्सा मिला। रूस ने युद्ध की तैयारी के लिए समय प्राप्त करने के अभिप्राय से नहीं बल्कि दूसरे देशों पर अधिकार प्राप्त करने की इच्छा से जर्मनी के साथ संधि की। उसने लिटविनाव को पद-च्युत कर और १९३९ में जर्मनी से सन्धि कर साम्राज्य-विस्तार का मार्ग प्रशस्त कर लिया और अब भी वह उसी पथ पर बढ़ता चला जा रहा है।

जून १९३६ में स्टालिन ने कहा था—“हमें दूसरों की एक फुट भी जमीन नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी जमीन का एक इंच भी दूसरों को नहीं लेने देंगे।” रूसी विदेश-नीति का सदा यही मुख्य सिद्धान्त रहा है। ध्यान रहे कि स्टालिन ने यह नहीं कहा कि हमें पूर्वी पोलैण्ड या बाल्टिक-राज्यों या फिनलैण्ड के एक भाग को छोड़कर और किसी देश की एक फुट जमीन भी नहीं चाहिए। उसने कहा कि “हमें किसी भी दूसरे देश की जमीन नहीं चाहिए।” स्टालिन के समर्थकों को यह निश्चय करना होगा कि स्टालिन सचमुच अपनी कही हुई बात पर विश्वास करता था या १९३६ में उसने यह बात केवल इसलिए कही थी कि उस समय उसमें आक्रमण करने की क्षमता नहीं थी और फिर सन् १९३९ में इस सिद्धान्त को इसलिए त्याग दिया कि तब तक दूसरे देशों को हड़पने की उसमें शक्ति आ गई थी।

यद्यपि क्रान्ति की चपेट में पूर्वी पोलैण्ड, बाल्टिक राज्य, फिनलैण्ड और बेसेरेबिया रूस के हाथ से निकल गए फिर भी सन् १९२० के बाद रूस पर कोई आक्रमण नहीं हुआ। सन् १९४१ में उस पर तब आक्रमण हुआ जब वह इन देशों को फिर से जीत चुका था। वह आक्रमण जर्मनी का हुआ था जिसकी सहायता से उसने इन देशों को पुनः प्राप्त किया था।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का यह एक स्वाभाविक नियम है—और शायद आजकल का सबसे महत्त्वपूर्ण नियम है कि विस्तार के साथ विस्तार की भूख बढ़ती जाती है। सन् १९४० को गमियो तक रूस उन सभी स्थानों पर अधिकार कर चुका था जो पहले जार के साम्राज्य के अन्तर्गत थे। इनके अतिरिक्त उसने पूर्वी गैलीशिया और उत्तरी बुकोविना पर भी, जो पहले कभी रूसी आधिपत्य में नहीं थे, कब्जा कर लिया था। फिर भी, रूस के रक्षा-कमिश्नर टिमोशेको ने ७ नवम्बर १९४० को मास्को में कहा—“सोवियत् रूस ने अपनी सीमाएँ बढ़ा ली हैं, लेकिन हम इतने से ही सन्तुष्ट नहीं रह सकते।” स्वभावतः रूस ने बालकान में फैलने की चेष्टा की।

सितम्बर १९४० में फ्रांस हिटलर के काले जूते की एड़ी तले दबा पड़ा

था और ब्रिटेन पर जर्मन हवाई जहाज घुआधार बम बरसा रहे थे। 'यू' वोटो की सरगरी ने अन्धमहासागर में एक भयानक सकट उपस्थित कर दिया था। स्टालिन ने इस अवसर को एक दूसरा महान् प्रयत्न करने के लिए बड़ा उपयुक्त समझा किन्तु जर्मनी पश्चिम में फँसे रहने पर भी पूरव की ओर से मतर्क था। पत्रकार लेलैण्ड स्टो ने, जो नाजियो के कट्टर विरोधी थे, २० सितम्बर, १९४० को बुखारिस्ट से न्यूयार्क को निम्नलिखित तार दिया—“जर्मनी ने रूस के रूमानिया में और अधिक विस्तार करने के आयोजन को सफलता पूर्वक रोक दिया है।.. इसमें सन्देह नहीं कि रूस का बलगेरिया और काले समुद्र-तटवर्ती प्रदेश पर सितम्बर में अधिकार कर लेने की आशा पर तुषारपात होगया है। इसका यह मतलब नहीं है कि 'रूस ने बालकान में विस्तार की आकांक्षाएँ छोड़ दी हैं।' १४ अक्टूबर, १९४० को बुडापेस्ट से भेजे गये एक दूसरे पत्र में स्टो ने अपने उक्त कथन का समर्थन किया। उसने तार देते हुए लिखा—“स्टालिन की लाल सेना अब बालकान से बाहर निकाल दी गई है।”

इस रक्तहीन राजनीतिक युद्ध को जीतने के बाद हिटलर ने रूस के विदेश-मंत्री मोलोटोव को बर्लिन आने का निमन्त्रण दिया। मोलोटोव वहाँ १२ नवम्बर को पहुँचे। उस समय उनका जो चल-चित्र तैयार किया गया उसमें वह अपना टोप उठा-उठाकर रास्ते में हर जर्मन अफसर का अभिवादन करते हुए दिखाये गये। लेकिन उनका चपटा चेहरा गम्भीर मालूम होता था, वह हिटलर के साथ महत्त्वपूर्ण बातचीत करने वाले थे।

उस समय यह चर्चा फैली थी कि हिटलर से बात करते समय मोलोटोव जिस कोच पर बैठे थे उसमें जर्मनी की खुफिया पुलिस ने माइक्रोफोन (ध्वनिविस्तारक यंत्र) लगा दिये थे। कहा जाता है कि बाद में जर्मनों ने यह सिद्ध करने के लिए कि हिटलर ने किस प्रकार रूस के विरुद्ध तुर्की के हितों की रक्षा की—माइक्रोफोन के रिकार्डों को तुर्क और दूसरे अफसरों को सुनाया। यह बात ठीक थी या गलत यह तो नहीं कहा जा सकता, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि नाजियो के लिए ऐसा करना असम्भव नहीं था।

हिटलर और मोलोटोव ने अपनी ऐतिहासिक मुलाकातो में किन-किन विषयों पर बातचीत की, इसके सम्बन्ध में हमें केवल उतना ही मालूम है जितना कि हिटलर और रिवनट्रॉप ने २२ जून १९४१ को बताया। हिटलर ने कहा—“रूस के विदेश-मंत्री ने हमसे संधि के सम्बन्ध में चार बातों का स्पष्टीकरण चाहा। मोलोटोव का पहला प्रश्न यह था—जर्मनी ने रूमानिया को जो गारंटी दी है वह क्या रूस द्वारा रूमानिया पर आक्रमण किये जाने पर रूस के विरुद्ध

भी लागू होगी ? मैंने उत्तर दिया—जर्मनी ने एक आम गारंटी दी है और वह हमारे लिए बिना किसी शर्त के बाध्य है । रूस ने हमें यह कभी नहीं बताया कि बेसेरेविया के अलावा भी उसकी रूमानिया में कोई दिलचस्पी है ।”.....दूसरे शब्दों में यो कहिये कि हिटलर ने मोलोटोव को बताया कि जर्मनी रूस से रूमानिया की रक्षा करेगा ।

हिटलर ने आगे कहा—“मोलोटोव का दूसरा प्रश्न यह था—फिनलैंड एक बार फिर रूस के लिए सकट बन गया है । क्या जर्मनी फिनलैंड को किसी तरह की भी सहायता न देने के लिए तैयार है ?”

मैंने उत्तर दिया—“जर्मनी को अब भी फिनलैंड में किसी प्रकार की राजनीतिक दिलचस्पी नहीं है । फिर भी अल्पसंख्यक फिनिश जनता पर रूस का कोई नया आक्रमण जर्मन सरकार को अब सह्य नहीं होगा, विशेषतः इसलिए कि हम इस बात पर कभी विश्वास नहीं कर सकते कि रूस को फिनलैंड से खतरा हो सकता है ।”

मोलोटोव का तीसरा सवाल यह था—“क्या जर्मनी यह मानने को तैयार है कि रूस बल्गेरिया को सुरक्षा का आश्वासन दे और वहाँ इस कार्य के लिए रूसी सेना भेजे ? इस सम्बन्ध में मोलोटोव यह कहने को तैयार थे कि रूस बल्गेरिया के राजा को गद्दी से उतारना नहीं चाहता ।”

मैंने उत्तर दिया—“बल्गेरिया की सत्ता सार्वभौमिक है और मुझे पता नहीं कि उसने रूस से कभी ऐसे आश्वासन के लिए प्रार्थना की है जैसी रूमानिया ने जर्मनी से की थी ।”

मोलोटोव का चौथा सवाल यह था—“हर हालत में रूस दरें दानियाल से होकर आने-जाने का स्वतन्त्र रास्ता चाहता है और अपनी रक्षा के लिए दानियाल और वॉसफोरस के कई महत्वपूर्ण अड्डों पर अधिकार भी चाहता है । क्या जर्मनी इससे सहमत है ?”

मैंने उत्तर दिया—“जर्मनी मॉनट्रियो संधि में कालेसागर के तटवर्ती राज्यों के अनुकूल परिवर्तन करने को हर समय तैयार है, किन्तु जलडमरूमध्यों के अड्डों पर रूस का अधिकार होने देने के लिए तैयार नहीं ।”

हिटलर का यह बनावटी भोलापन और अपने को फिनलैंड और बालकान देशों का रक्षक सिद्ध करने का प्रयत्न किसी से छिप नहीं सका । बालकान के सम्बन्ध में उसकी अपनी योजनाएँ थी और उसे रूस का हस्तक्षेप बुरा मालूम होता था । फिर भी, दोनों ने बालकान की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया और इसमें सन्देह नहीं कि हिटलर ने मोलोटोव की माँगों की जो रूपरेखा बताई

वह उस नीति से बिलकुल मिलती-जुलती है जो रूस ने अपनी सेना की शानदार जीतो के बाद सन् १९४४ में ग्रहण की।

१६ नवम्बर को मोलोटोव मास्को लौट गया। हिटलर ने फौरन स्लो-वेकिया, हंगरी और रूमानिया के प्रतिनिधियों को बुलाकर घुरी-राष्ट्रों का साथ देने का आदेश दिया और उन्होंने उसकी आज्ञा का पालन किया। जब हंगरी ने ऐसा किया तो रूस की सरकारी तार एजेसी 'टास' ने २२ नवम्बर को घोषणा की कि हंगरी ने मास्को की स्वीकृति लिये बिना ही यह कार्य किया है। 'टास' ने इन शब्दों द्वारा रूस की अस्वीकृति का संकेत किया, किन्तु हिटलर ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वह बालकान की किलेबन्दी करने लगा। इस काम में उसे मुसोलिनी की वाहवाही भी मिली, किन्तु इटली से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई।

बालकान की किलेबन्दी का अभिप्राय क्या था? एक बड़ी घटना घटने वाली थी। इस बार हिटलर ने अपनी तैयारी धीरे-धीरे की। बलगेरिया पर मार्च १९४१ में उसने अधिकार किया। उसी महीने की तीसरी तारीख को रूस ने सरकारी रूप से उसके इस कार्य की निन्दा की। मोलोटोव की बर्लिन-यात्रा के बाद से रूस और जर्मनी का सम्बन्ध स्पष्टतः विगड़ता जा रहा था और अब वह एक संकट की स्थिति में पहुँच गया था।

रूस के प्रवेश-द्वार को चकनाचूर करने से पहले हिटलर बालकान में अपने पीछे के द्वार में ताला डालना चाहता था, किन्तु अभी यूगोस्लेविया और यूनान का सफाया करना बाकी था। यूगोस्लेविया ही जर्मनी के यूनान में घुसने का मार्ग था, जहाँ (जनवरी और फरवरी सन् १९४१ में) महान् मुसोलिनी की सेनाएँ साधारण अस्त्र-शस्त्र से सज्जित यूनानी योद्धाओं द्वारा अपमानित की जा रही थी।

अतः मार्च १९४१ के अन्त में हिटलर ने अपनी 'भीचने और भय दिखाने' का प्रसिद्ध रीति से काम लिया और यूगोस्लेविया की सरकार को घुरीराष्ट्रों का साथ देने के लिए विवश किया। बेलग्रेड के प्रतिगामियों और राजभक्तों ने कोई आपत्ति नहीं की, किन्तु वहाँ की जनता और सैनिक कार्य-कर्त्ता चुप नहीं बैठे। उन्होंने एक साथ मिलकर विप्लव किया और हिटलर के साथ हिटलर की इच्छानुसार सधि करने वाले मन्त्रिमंडल को उखाड़ फेंका। अमेरिका के सरकारी क्षेत्रों में कहा गया कि यह घटना अग्रेजों की प्रेरणा से हुई है। नाज़ियों ने कहा इसमें रूस का हाथ है। रूस और ब्रिटेन दोनों ही यूगोस्लेविया को जर्मनों की आँखों की किरकिरी बना देना चाहते थे। यूगोस्ले-

विया की रक्षा कर अंग्रेज स्वेज और भारत की तथा रूसी मास्को की रक्षा कर रहे थे ।

२७ मार्च को जनरल डूसाँ सिमोविच के नेतृत्व में यूगोस्लोविया में घुरी-राष्ट्र-विरोधी एक नई सरकार बनी और उसने जर्मनी के विरुद्ध लड़ना आरम्भ किया । ५ अप्रैल को रूसी सरकार ने यूगोस्लोविया की इस नई सरकार के साथ मित्रता की संधि की । यह हिटलर का खुल्लम-खुल्ला विरोध था ।

६ अप्रैल को रूस के सैनिक पत्र 'रेड स्टार' ने लिखा कि जर्मनी को यूगोस्लोविया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । साथ-ही-साथ उसने यूगोस्लावों के परम्परागत सैनिक गुणों का भी उल्लेख किया और बताया कि जनरल सर आर्कीवाल्ड वेवेल के नेतृत्व में ब्रिटिश कमान ने यूगोस्लोविया को सहायता देने का गम्भीर प्रबंध कर दिया है ।

रूस की याशा थी कि यूगोस्लोविया और यूनान जर्मनी से डटकर मोर्चा लेंगे और ब्रिटेन उनकी सहायता करेगा ।

बालकान का युद्ध रूस के लिए युद्ध और शान्ति दोनों का कारण बन सकता था । इस बात की सम्भावना थी कि जर्मनी यूगोस्लोविया और यूनान दोनों को कुचलने के बाद उभी दिशा में क्रीट, मिस्र, सीरिया, ईराक और भारत की ओर बढ़ता रहे । बहुत से जर्मन जनरलों ने इस कार्यक्रम का समर्थन किया भी था । उस दशा में रूस के लिए कोई तात्कालिक सकट न होता ।

अप्रैल सन् १९४१ में ईराक में रशीदअली ने अंग्रेजों के विरुद्ध विप्लव किया । उससे अगले महीने में विची (फ्रांस) के अधिकारियों ने जर्मनों को सीरिया में फ्रांसीसी हवाई अड्डों को प्रयोग में लाने की अनुमति दे दी, अलेप्पो का हवाई अड्डा तो बिल्कुल नाज़ियों के लिए ही छोड़ दिया गया । सीरिया से जर्मनों ने रशीदअली को सैनिक सहायता भेजी, उधर उत्तरी अफ्रीका में इटली और जर्मनी का एक संयुक्त सेना अंग्रेजों से जूझ पड़ी ।

अब प्रश्न यह था—क्या हिटलर भारत की ओर बढ़कर जापानियों का नाश देगा ? सीधे ब्रिटिश द्वीप समूह पर आक्रमण करने में असफल होने के कारण सम्भवथा हिटलर ब्रिटिश-साम्राज्य का अंग-भंग करने का प्रयत्न करता । उस समय हिटलर का ध्यान रूसी प्रदेश से बहुत दूर चला जाता ।

रूस की ये आशाएँ निष्फल रही । हिटलर ने अपनी सारी शक्ति यूगो-स्लेविया और यूनान के विरुद्ध केन्द्रित कर दी और अप्रैल का अन्त होते-होते दोनों देश पद-दलित कर दिये गए । उसके बाद शीघ्र ही सारे यूरोप में यह अफ-वाह फैल गई कि जर्मन-सेनाएँ बालकान और फ्रांस से हटाकर रूसी सीमा

की ओर भेजी जा रही है। जर्मन टुकड़िया फिनलैण्ड में दिखाई भी दी।

मास्को में सनसनी फैल गई। स्टालिन ने बड़ी तत्परता और पौरुष के साथ काम किया। ये ही वे गुण हैं जिनसे उन्हें शक्ति और ख्याति मिला है। ६ मई को उन्होंने मोलोटोव को हटा दिया और वह स्वयं सोवियत् सरकार के प्रधान बन गए। उस समय स्टालिन की आयु ६२ वर्ष की थी।

८ मई १९४१ को मैंने अमेरिका के अडर सेक्रेटरी समनर वेल्स को एक पत्र में लिखा, "यदि हिटलर ने रूस पर आक्रमण किया या उस पर युद्ध के सहायताार्थ अधिक सामान देने का दबाव डाला तो उससे यह सिद्ध हो जायगा कि २३ अगस्त सन् १९३९ के समझौते में तुष्टीकरण की जिस नीति का आरम्भ किया गया वह खोखली थी। युद्ध आरम्भ हो जाने पर या घटनाओं द्वारा रूसी कूटनीतिज्ञता की असफलता सिद्ध हो जाने पर स्टालिन की इच्छा सारी शक्ति और अधिकार अपने हाथ में ले लेने की होगी और वह किसी दूसरे के हाथ में शक्ति नहीं रहने देना चाहेंगे।"

सकट के समय सर्वोच्च अधिकार का मोलोटोव जैसी गुड़िया के हाथ में छोड़ देना दुर्बलता का निर्देशक होता। इसीलिए स्टालिन ने रूसी शासन की अध्यक्षता अपने हाथों में ले ली। साथ-ही-साथ, उन्होंने युद्ध के लिए अपनी सेना भी तैयार की। फिर भी उन्होंने हिटलर को एक बार फिर तुष्ट करने और उसकी चेष्टा को ब्रिटिश-अधिकृत पूर्वोक्त देशों की ओर मोड़ने की आशा नहीं छोड़ी थी। एकाएक रूस की नीति बदल गई और वह विरोध की बजाय आज्ञापालन की ओर झुकी। ९ मई को रूसी सरकार ने नार्वे और बेलजियम पर से स्वीकृति वापिस ले ली और उनके मास्को-स्थित कूटनीतिक प्रतिनिधियों के विशेषाधिकार भी रद्द कर दिये। नार्वे और बेलजियम साल भर से हिटलर के आधिपत्य में थे फिर भी रूस उनके राज-दूतों को स्वीकार करता आया था। अब उसने उन्हें अस्वीकार कर दिया और यूगोस्लोविया पर से भी स्वीकृति वापिस ले ली। स्मरण रहे कि उसने एक मास पहले यूगोस्लोविया के साथ मित्रता की संधि की थी। हिटलर को तुष्ट करने के विशेष अभिप्राय से उसने ईराक के ब्रिटिश-विरोधी राजद्रोही रशीदअली की सत्ता स्वीकार कर ली।

स्थिति अब तब पर पहुँचती जा रही थी। लोग रोमाचकारी घटनाओं के समाचार सुनते-सुनते कुन्द हो गये थे। एकाएक और भी बड़ी रोमाचकारी घटना हुई। हिटलर का डिप्टी रूडोल्फ हेस हवाई जहाज में बैठकर स्काटलैण्ड गया और १० मई को एक हवाई छतरी के जरिये हेमिल्टन के ड्यूक की बड़ी

रियामत के पास उतरा। वहाँ के एक आश्चर्य-चकित किसान ने, जो खेत में दोदाता फावड़ा चला रहा था, उमें पकड़ लिया।

कई महीने बाद मैंने लंदन में हेस-रहस्य के सम्बन्ध में ब्रिटेन के विदेश-मंत्रि एन्थेनी ईडेन, गृह-मंत्री हरबर्ट मॉरिसन, डिप्टी प्रधान-मंत्री क्लेमेंट एटली, मजदूर-नेता प्रोफमर हेराल्ड लास्की और कई अन्य व्यक्तियों के साथ बातचीत की। ईडेन में जो बातचीत हुई वह इस प्रकार थी।

ईडेन—“जमन-आक्रमण के सम्बन्ध में हमने रूसियों को तीन सप्ताह पहले ही आगाह कर दिया था।”

मैं—“यह बात उन्हें पहले से ही मालूम होगी। जब हेस स्काटलैंड आया तो अवश्य ही जर्मनी न रूस पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया होगा।”

ईडेन—“क्यों?”

मैं—“हेस १० मई को आया। उस समय तक २२ जून के आक्रमण की तैयारी अवश्य आरम्भ हो गई होगी। कोई भी देश ऐसा आक्रमण छ. हफ्ते की तैयारी के बिना नहीं कर सकता।”

ईडेन—“तो क्या आप समझते हैं कि हेस रूस पर आक्रमण करने के विरुद्ध था?”

मैं—“नहीं, लेकिन वह चाहता था कि ब्रिटेन जर्मनी के साथ लड़ाई बन्द कर दे।”

इसके बाद कुछ देर के लिए निस्तब्धता छाई रही और मैंने अनुभव किया कि मैंने विजय पा ली है।

प्रमाणस्वरूप मैंने जो दावे कही उनसे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई। हेस को रूस पर किये जाने वाले आक्रमण की जानकारी थी। हिटलर की पुस्तक “मीन कैम्फ” (मेरी जीवनी) में जिमके लिखने में हेस ने सहायता दी थी, ब्रिटेन का विरोध नहीं किया गया था। उसमें यूक्रेन को प्राप्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था और ब्रिटेन के साथ ऐसी व्यवस्था करने का उल्लेख किया गया था जिससे जर्मनी उम सम्पन्न क्षेत्र पर अधिकार कर सके। अतः जब जर्मनी रूस पर आक्रमण करने वाला था तो यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि वह ब्रिटेन के साथ कोई-न कोई प्रवन्व करता।

हेस ने सोचा कि जर्मनी के साथ ब्रिटेन की काफी लड़ाई हो ली। किसान सर्वसत्तावादी को यह नहीं मालूम कि जनतात्री देशों में किस प्रकार कार्य होता है। हेस को ब्रिटेन के उन लाडों की याद थी, जो तुष्टीकरण के पक्षपाती थे। और युद्ध से पहले उनके पास गये थे। उसे विश्वास था कि ब्रिटेन में उनका

अब भी प्रभाव है। उसे यह नहीं मालूम था कि ब्रिटेन में जर्मनी को तुष्ट रखने की भावना मर चुका है। उसने साचा कि अग्रजों को रूस के भारी आक्रमण की बात बताकर मैं उनमें तुष्टीकरण की भावना फिर जाग्रत कर सकूंगा, किन्तु उसका यह सोचना गलत निकला। चर्चिल ने उसका बताया हुआ महान् समाचार को स्टालिन तक पहुँचा दिया और हेस ब्रिटेन की एक जेल में पड़ा रहा।

स्टालिन को जर्मन-आक्रमण की निश्चित सूचना केवल चर्चिल के ही तार से नहीं मिली, बल्कि २२ अप्रैल और २१ जून के बीच जर्मन हवाई जहाजों ने रूसी सीमा को १८० बार पार किया। कुछ हवाई जहाज तो फोटो लेते हुए रूस में ४०० मील अन्दर तक घुम गये। यह समाचार मास्को के मवाददाताओं को रूस के विदेशी मामलों के असिस्टेंट कमिशनर सालाभन लाजवस्की ने २८ जून को बताया।

फिर भी नाज़ी-आक्रमण के समय रूस मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध के लिए तैयार नहीं था। पल हार्वर पर जापानी आक्रमण होने से दो दिन पहले मेक्सिम लिटविनाव वाशिगटन में रूसी-राजदूत का अपना नया पद ग्रहण करने के लिए हवाई जहाज द्वारा प्रशान्त महासागर को पार कर जाते हुए होनोलूलू में ठहरे। वहाँ अमेरिकन जल और थल सेनाओं के बड़े-से-बड़े अफसरों ने उनका स्वागत किया। लिटविनाव ने उन्हें रूस पर अकस्मात् किये गए नाज़ी प्रहार की बात बताई और कहा कि एक शान्त देश को इस बात की कल्पना करने का अभ्यास नहीं हो सकता कि उस पर शीघ्र आक्रमण हो सकता है और यही कारण है कि वह अब भी रह जाता है। हो सकता है कि इस समय जापान भी अमेरिका पर आक्रमण करने का आयोजन कर रहा हो और वह होनोलूलू पर प्रहार करे। इसीलिए लिटविनाव ने अमेरिकन अफसरों को दिन-रात सचेत रहने की सलाह दी। रूस के पल हार्वर से उन्हें अकल आ गई थी।

२२ जून १९४४ को सवेरे चार बजे नाज़ियों ने बिना कोई चेतावनी दिये ही रूस पर आक्रमण कर दिया। पहले दिन रूस के एक हजार हवाई-जहाज अधिकतम जमीन पर खड़े-खड़े ही नष्ट हो गये। इस सम्बन्ध में हैरी-हॉपकिन्स ने प्रेजिडेंट रूजवेल्ट के विशेष दूत की हैसियत से रूस की यात्रा करने के बाद दिसम्बर १९४१ के 'अमेरिकन मैगज़ीन' के अंक में लिखा कि हिटलर ने स्टालिन को किसी प्रकार का संकेत दिये बिना ही रूस पर आक्रमण कर दिया। हिटलर ने रूस के सामने कोई माँग उपस्थित नहीं की, क्योंकि ऐसा करना एक चेतावनी समझा जाता। हिटलर रूस से कुछ लेना नहीं चाहता था, वह स्वयं रूस को चाहता था। हॉपकिन्स ने लिखा है कि जर्मन-आक्रमण के

कारण मास्को में हिटलर के विरुद्ध घृणा की ऐसी भावना उत्पन्न हो गई जिसे हिटलर को मृत्यु के अलावा कोई दूसरी वस्तु कम नहीं कर सकती थी। उमके आक्रमण को रूसियों ने एक साभीदार का विश्वाभघात कहकर पुकारा जो एकाएक कुत्ते की तरह पागल हो गया है।

हॉपकिन्स ने अपने लेख में हिटलर के प्रति स्टालिन की निराशा का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया—“स्टालिन ने एक बार मुझसे कहा था कि हम (रूसी) कभी इस आदमी (हिटलर) पर विश्वास करते थे और जर्मनी के साथ सीधा सादा व्यवहार करने के अलावा मेरा और कोई विचार नहीं था। रूसी जर्मनी पर आक्रमण नहीं करते।”

स्टालिन को अन्त तक यह विश्वास रहा कि हिटलर रूस-जर्मन संधि का पालन करेगा और ब्रिटिश साम्राज्य को कुचलने की चेष्टा करेगा। यही कारण था कि उसने हिटलर को बार-बार तुष्ट करने की चेष्टा की। किन्तु उसकी आशाओं के बिल्कुल प्रतिकूल हिटलर ने “मीन कैम्फ” के अनुसार कार्य किया और रूस को कुचलने की चेष्टा की।

: ४ :

मेरी भविष्यवाणी

निकट अतीत की घटनाओं का सिंहावलोकन करने में मुझे अनन्त रोमांच का अनुभव होता है। एक ही प्रकार की घटनाएँ, भिन्न-रूप ग्रहण कर लेती हैं। ८ दिसम्बर १९४१ को पर्ल हार्बर का कुछ और चित्र था, जब कि प्रत्येक अमेरिकन को ऐसा लगता था मानो उसका सिर किसी कठोर पत्थर से टकरा गया है और वह गिर पड़ा है। किन्तु जब हम कुछ वर्ष बाद के पर्ल हार्बर का स्मरण करते हैं तो हमें अपनी वाद की सफलताओं पर अभिमान होने लगता है और हम अपना सिर ऊँचा कर लेते हैं।

आज से कुछ वर्ष पहले मोलोटोव, हिटलर, लिडबर्ग, स्टालिन, हजवेल्ड और हमारे लोगों के भाषणों को पढ़कर कुछ और ही भावना होती थी और अब उन्हीं को पढ़कर कुछ और भावना होती है। अब मैं उन भाषणों को जितनी अच्छी तरह से समझने लगा हूँ उतनी अच्छी तरह से स्वयं उनके देने वाले उन्हें देने समय न समझ पाये होंगे। मेरे सामने कई वर्षों की घटनाएँ हैं, जिनकी वसोती पर उन भाषणों को बस सकता हूँ।

इतिहास हमारे सामने घटनाओं का एक चित्र-सा खींच देता है, किन्तु अर्द्ध शताब्दी पूर्व के इतिहास का सबध ऐसी घटनाओं से होता है जिनका आज भी हमारे जीवन पर असर तो अवश्य होता है, किन्तु जो स्वयं समाप्त हो चुकी है।

उदाहरण के लिए स्पेन के साथ अमेरिका की लड़ाई या प्रेजिडेंट क्लीवलैण्ड के शासन का ले लीजिए। ये अतीत की बातें हैं, हो सकता है कि जो घटनाएँ आज स दो या तीन वर्ष पहले घटी थी वे अब भी अज्ञात हों। मसलन, यूरोप में विजय का दिवस तो मनाया जा चुका है। किंतु अभी यूरोप का युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। हम उसके राजनीतिक परिणाम को नहीं जानते। हिटलर चला गया है, किंतु जर्मनी किस रास्ते जा रहा है? भविष्य अतीत के अर्थ को बदल देगा।

नीति निर्धारित करने वाला कूटनीतिज्ञ अक्सर भविष्य को समझने की अपनी योग्यता पर ही प्रधानतः निर्भर रहता है। वह पहले से ही मान लेता है कि भविष्य में अपेक्षित घटनाएँ होगी और सोचता है कि जो युक्तियाँ मैं कर रहा हूँ वे उन घटनाओं का सामना करने के लिए काफी होगी। वह कहता है कि भविष्य के सम्बन्ध में कोई निश्चय नहीं है, सिवा इसके कि भविष्य स्वयं अनिश्चित है। फिर भी अक्सर भविष्य निश्चित होता है। सन् १९४० में प्रेजिडेंट रूजवेल्ट यह तो नहीं जान सकते थे कि भविष्य में ब्रिटेन के भाग्य में क्या लिखा है, किन्तु उन्हें इस बात को निश्चय था कि अमेरिका की सहायता से ब्रिटेन और साथ-ही-साथ अमेरिका का भी भाग्य उज्ज्वल हो जायगा। ऐसी स्थिति में यदि नीति-निर्माता को जनता का समर्थन प्राप्त हो तो नीति का निर्माण सरल हो जाता है।

अतीत का कुछ-न-कुछ तत्त्व भविष्य में सदा विद्यमान रहता है। इसी तत्त्व के आधार पर भविष्य निश्चय किया जाता है और नीति भी बनाई जाती है। जो भविष्यवाणी केवल कल्पना-मात्र होती है—अधिकांश भविष्यवाणियाँ ऐसी ही होती हैं—वह रचनात्मक नहीं होती और उसका कोई मूल्य नहीं होता। जो भविष्यवाणी कुछ महत्त्व रखती है वह अन्धकार में अज्ञात को टटोलने के लिए ज्ञात का विश्लेषण करती है। अतीत को उपलब्ध घटनाओं को वह शृंखला-बद्ध करती है और ऐसा करने से खोई हुई कड़ी का रूप स्पष्ट हो जाता है। इनका ही नहीं बल्कि बाद में उस कड़ी से सम्पर्क रखने वाली दूसरी कड़ियों को ध्यान पूर्वक देखने से और भी बातों का पता चल जाता है। ससार की सभी राजधानियों में कूटनीतिज्ञ और पत्रकार इसी प्रकार की राजनीतिक भूल-भुलैया के अध्ययन में लगे रहते हैं।

“युद्ध कब समाप्त होगा?” सब लोग यही प्रश्न पूछा करते थे। किंतु इसका उत्तर देने का प्रयत्न कोई ठग या मूर्ख ही कर सकता था। उत्तर देने के लिए बहुत-सी अज्ञात बातों का ध्यान रखना आवश्यक था। अनेक राजनीतिक स्थितियाँ इतनी अस्पष्ट और धुंधली होती हैं कि उनका विश्लेषण करना

और उनके भविष्य को समझना असम्भव हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसी होती है जिनका भविष्य दिखाई दे जाता है।

हम सभी भविष्यवाणी करते हैं, चाहे वह हम तकसीमित हो चाहे दूसरो को सुनाई दे जाय। जो भविष्यवाणी सत्य निकलती है उस पर हम अभिमान करते हैं और जो नहीं निकलती उसे भूल जाना ही ठीक समझते हैं।

सन् १९४१ के आरम्भ में जापान और रूस का रहस्य अमेरिकन प्रेक्षकों के लिये बड़ा दुखदायी बना हुआ था, वाशिंगटन को टोकियो और मास्को का भावी-नीतियों के सम्बन्ध में कुछ संकेत की आवश्यकता थी। अतः अमेरिका ने रूस के साथ अपने सम्बन्ध इस आशा में घनिष्ठतर बनाने की चेष्टा की कि स्टालिन हिटलर से विमुख हो जायगा। चूँकि रूस ने फिनलैंड के शहरों पर बमबारी की थी, इसलिए २ दिसम्बर १९३९ को प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने रूस के साथ व्यापार पर नैतिक प्रतिबंध लगा दिया था। किन्तु लगभग दो साल बाद २९ जनवरी १९४१ को अमेरिका के अन्डर-सेक्रेटरी समनर वेल्स ने राज-दूत कान्स-टैन्टाइन अमानस्की को सूचित किया कि प्रतिबन्ध उठा लिया गया है। देखने में यह एक छोटा-सी बात थी जिससे कुछ थोड़े से अमेरिकन व्यापारियों को रूस के लिए सामान भेजने की छूट मिल गई। किन्तु मुझे ऐसा लगा कि यह काम बड़ा गलत सिद्ध हो सकता है। इसके सम्बन्ध में मैंने जो आलोचनाएँ पढ़ी, उनमें मुझे ऐसा लगा कि इस कार्य के महत्त्व का गलत अनुमान लगाया गया है। उदाहरणार्थ, आर्थर नॉक ने न्यूयार्क टाइम्स के २३ जनवरी १९४१ के अंक में लिखा कि यथार्थवादी लोग इस कार्य का स्वागत करेंगे। इससे इस बात का और भी अधिक प्रमाण मिलता है कि ब्रिटेन को पूर्ण सहायता देने का उत्तरदायित्व ग्रहण करते हुए अमेरिका की सरकार अपने सुदूर पूर्वीय पिछवाड़े और अ-महासागर के सामने के मोर्चे का भी ध्यान रख रही है। इसके विपरीत मुझे ऐसा भान हुआ कि अमेरिका दूर पूर्व में अपनी स्थिति को भयानक संकटों में डाल रहा है। इसलिए मैंने समनर वेल्स को अपने विचार लिखकर भेजने का निश्चय किया। उनसे मैं कभी मिला नहीं था, न उन्हें कभी पत्र ही लिखा था इसलिए समझ नहीं सका कि मेरे लिखने की उन पर क्या प्रतिक्रिया होगी। फिर भी मैंने चूकना ठीक नहीं समझा और उन्हें २४ जनवरी १९४१ को निम्नलिखित पत्र भेजा—

प्रिय मिस्टर वेल्स,

मैं मास्को में १४ वर्ष तक एक अमेरिकन पत्रकार की हैसियत से रह चुका हूँ और मैंने रूस के विदेश सम्बन्धों का इतिहास दो भागों में

लिखा है। इस पत्र में मैं अमेरिकन सरकार के अभी हाल के उस निर्णय पर पर विचार करूँगा जिसके अनुसार अमेरिका से रूस भेजे जाने वाले कुछ पदार्थों पर से प्रतिबन्ध हटाने की घोषणा की गई है।

मैं समझता हूँ कि यह निर्णय एक उगा निर्णय है, विशेषतः इस कारण कि इसका परिणाम अमेरिका के हितों के विपरीत हो सकता है। इससे रूस और जापान के पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठतर होने में बड़ी सरलता पूर्वक सहायता मिल सकती है।

इस निष्कर्ष पर मैं कैसे पहुँचा इसका विवरण नीचे देता हूँ—

रूस की वर्तमान घबराहट और अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयों का कारण यह है कि जहाँ एक ओर उसकी पश्चिमी सीमा पर जर्मनों के दबाव का डर है वहाँ पूर्वी सीमा पर जापान है। रूस में जर्मनी का सामना करने या उसे शत्रु बनाने की शक्ति नहीं है, किन्तु यदि वह जापान को दुर्बल बना सके या उसका ध्यान किसी ओर दिशा में लगा सके तो उसकी स्थिति सुधर जायगी और जर्मनी का भय भी कम हो जायगा।

चीन की सैनिक सहायता कर रूस जापान को दुर्बल बना सकता है। यही उसने किया भी है, किन्तु यह काम मँहगा है। इसलिए रूस पर से जापानी दबाव को कम करने की ज्यादा अच्छी युक्ति यह होगी कि रूस जापान का विस्तार दक्षिण दिशा में स्याम और डच पूर्वी इन्डोनेशिया की ओर लक्षित करने का प्रयत्न करे। इससे जर्मनी का भी हित सिद्ध होगा। चीन में यदि जापान को कोई महान् विजय भी प्राप्त हो जाय तब भी उससे हिटलर को यूरोप में शीघ्र ही सहायता नहीं मिल पायगी, किन्तु यदि चीनी युद्ध समाप्त हो जाय तो उससे अवश्य सहायता मिलेगी, क्योंकि तब जापान अपना ध्यान दक्षिण की ओर केन्द्रित करेगा जहाँ से हमें और ब्रिटेन को महत्वपूर्ण सामान मिलता है। बोल्शेविकों को यह आशा होगी कि दक्षिण सागरों में प्रयत्नशील होने पर जापान अमेरिका या ब्रिटिश साम्राज्य के साथ संघर्ष में फँस जायगा और दुर्बल बन जायगा।

चूँकि हम चीन को सहायता दे रहे हैं, इसलिए जापान के लिए रूस के साथ समझौता करना और भी आवश्यक है। चीन को अमेरिका और रूस की सहायता जापान के सर्वनाश का कारण बन सकती है। यदि रूस चीन की सहायता करना बंद कर दे तो अकेले हमारी सहायता सफल नहीं होगी। इसी प्रकार, अमेरिका और रूस के सम्बन्ध में सुधार होने से रूस और जापान में समझौता होना सरल हो जायगा। यदि जापान को अमेरिका और रूस को मंत्री

का भय होगा तो वह रूस की लल्लो-चप्पो करेगा। यदि हम किसी प्रकार रूस को जर्मनी से अलग कर सकें तो सब बातें ठीक हो जायें। किंतु रूस इतना अरक्षित है और उसे युद्ध के अंतिम परिणाम के सम्बन्ध में इतनी अधिक शंका है कि वह खुल्लम-खुल्ला या क्रियात्मक रूप से हिटलर को विरोध नहीं कर सकता। अतः हमारे रूस के प्रति मित्रता प्रदर्शित करने से जापान डरकर रूस के साथ समझौता कर लेगा।

ग्रीमास्की के लिए, जिन्हें मैं पिछले दस साल से बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, रूसी व्यापार पर से प्रतिबन्ध का हटना एक सम्मान की बात होगी और शायद इसीलिए उन्होंने इस पर इतना जोर दिया। किंतु आपको अवश्य ही याद होगा कि सन् १९३६ की गमियों में रूस ने ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा दी गई प्रत्येक रियायत और मंत्रीपूर्ण सकेत से लाभ उठाकर अपने को हिटलर की दृष्टि में अधिक बहुमूल्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया। रूस और हमारे बीच समझौते के लिए हाल ही में जो कदम उठाया गया है उसके प्रति मेरी सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि उससे लाभ उठाकर रूस जापान पर अपने साथ समझौता करने के लिए दबाव डालेगा, जिससे जापान के आक्रमण का मार्ग दक्षिण की ओर मुड़ जायगा, चीन की स्थिति बिगड़ जायगी, रूसियों को चीन पर प्राधिपत्य जमाने के लिए एक कम्युनिस्ट क्षेत्र मिल जायगा और पोलैण्ड की भाँति चान का विभाजन हो जायगा, यद्यपि उस समय भी स्टालिन हिटलर के चंगुल से मुक्त नहीं हो पायगा।

यह पत्र अब बहुत बड़ा हो गया है और मैं समझता हूँ कि अब मुझे इसे समाप्त कर देना चाहिए। मुझे आशा है कि मैंने अपने विचार ठीक से व्यक्त कर दिये हैं।

मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि मैं आपसे मिलकर इस विषय पर और कई दूसरे प्रश्नों के सम्बन्ध में बातचीत कर सकूँ। मैं यहाँ (वाशिंगटन में) एक व्याख्यान-माला के सम्बन्ध में कुछ दिन ठहरूँगा। यदि इस बीच आपसे मिलने का अवसर मिल सके तो बड़ा अच्छा हो। हमारी आपकी भेंट प्रकाशित या उद्धृत किये जाने के लिए नहीं होगी। दुर्भाग्यवश, मैं केवल ३ फरवरी को सवेरे ६।। से बजे से ११ बजे तक आपसे मिलने का समय निकाल सकूँगा। क्या आप मुझसे उस समय मिल सकते हैं? या यदि आप कहें तो मैं ११ फरवरी को एक भाषण का कार्य-क्रम रोककर वाशिंगटन आ जाऊँ। फिर भी मैं ३ फरवरी ही पसन्द करूँगा। क्या आपको उस दिन मुझसे मिलने में सुविधा होगी?

भवदीय— (हस्ताक्षर) लुई फिशर

मैं कह सकता हूँ कि पत्र में मैंने जो कुछ लिखा वह एक सच्चा भविष्य-वाणी थी। उस समय रूस और जापान में समझौता होने की कोई चर्चा नहीं थी और जापान द्वारा ब्रिटेन और अमेरिका पर आक्रमण हान की सम्भावना भी दूर मालूम होती थी। किंतु १३ अप्रैल १९४१ का रूस और जापान ने एक व्यापक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किये और कम-से-कम ५ वर्ष तक दोनों ने एक-दूसरे में न लड़ने की प्रतिज्ञा की। उसी समय में सिंगापुर, मलाया और हवाई द्वीप पर जापान के आक्रमण आरम्भ हुए।

समनर वेल्स ने ३० जनवरी को उत्तर देते हुए लिखा, “आप अपने पत्र में सुझाई गई किसी भी तिथि पर आकर मुझसे मिल सकते हैं।” मैंने ११ फरवरी को जाना ठीक समझा, क्योंकि मैंने सोचा कि उस दिन समनर वेल्स बातचीत के लिए अधिक समय दे सकेंगे। मैं उनसे विदेश-विभाग में उनके दफ्तर में मिला।

समनर वेल्स का कद लम्बा और शरीर छड़ की तरह सीधा है। उनके कंधे चौड़े हैं, गठन अच्छी है और वह बड़े ही निर्मल वस्त्र पहनते हैं। गिर लम्बा और विशेषता लिये हुए है। आवाज गहरी और भारी है। एक कूट-नीतिज्ञ होने के नाते उनकी सहज गम्भीरता और भी बड़ गई है। साधारण बातचीत करने की क्षमता उनमें बिलकुल नहीं है, किंतु उन्हें विद्वत्ता-पूर्ण सम्भाषण पसन्द है और ऐसे सम्भाषणों के समय किसी समस्या की तह तक पहुँचने की उनकी इच्छा उनके महान् आन्तरिक सयम पर विजय पा लेती है। जब उन्हें यह मालूम हो जाता है कि उनकी बात कोई ठीक से समझ सकता है तो वह बड़ी निष्कपटता के साथ बातचीत करते हैं। उनका मस्तिष्क यत्र के समान अचूक है और उनकी स्मृति दिव्य। अभिमान उनमें तनिक भी नहीं है, यद्यपि उनसे सहानुभूति न रखने वाले व्यक्ति को इसके प्रतिकूल धारणा हो सकती है। अपने लेखों के सम्बन्धमें वह बड़े ही नम्र है।

जब मैं उनसे पहली बार बातचीत करने के लिए उनके दफ्तर में घुसा तो उन्होंने बढकर हाथ मिलाया और मुझसे खिडकी के पास बैठने को कहा। एक लम्बे लहमे के लिए उन्होंने मुझे दृष्टि जमाकर देखा और फिर एक सिगरेट निकालकर उसे एक सोने के डिब्बे पर उछालते हुए कहा—“महाशय फिशर मैंने आपके पत्र को बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा।” इसके बाद वह एकदम मेरे पत्र के मुख्य विषय पर आगये। वहाँ से अपने होटल के कमरे में आकर मैंने उनसे की गई बातचीत ज्यो-की-त्यो लिख डाली। महत्वपूर्ण राज-नीतिक मुलाकातों की एक डायरी बना लेने की मेरी आदत पड़ गई है। प्रायः

मैं उन्हें उसी दिन लिख लेता हूँ और मेरा खयाल है कि मैं उन्हें शब्दशः लिखने में सफल हो जाता हूँ।

वेल्स ने आरम्भ में पूछा—“आपकी राय में दूर पूरब में रूस का लक्ष्य क्या है?”

मुझे अपना उत्तर तैयार करने में थोड़ा समय लगा। मैंने कहा—
“जापान को दुर्बल बनाना।”

“और उसका दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है?”

“चीन पर आधिपत्य करना।”

“क्या आपको विश्वास है कि रूस समस्त चीन पर प्रभुत्व जमाना चाहता है? या वह उसे केवल विभाजित करना चाहता है?”

मुझे इस प्रकार की खली जिरह अच्छी लगी। उनके प्रश्नों से मुझे पता चल जाता था कि उनका अपना क्या विचार है। मैंने सोचा कि बाद में मैं भी उनसे कुछ प्रश्न करने की चेष्टा करूँगा।

मैंने उन्हें बताया कि रूस को पहले अपने निकटवर्ती चीनी कम्युनिस्ट प्रान्तों पर अधिकार करने की आशा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वह चीन के दूसरे भागों पर अपना प्रभाव नहीं चाहता।

“मैं समझता हूँ कि यह ठीक है,” वेल्स ने कहा। उन्होंने रुककर सिगरेट का कण खींचा और फिर कहा—“तो क्या आप समझते हैं कि मध्य पूर्व में रूस का उद्देश्य जापान को अमेरिका से लड़ाना है?”

“हां, जापान को दुर्बल बनाने के लिए,” मैंने उत्तर दिया।

“मैं आपसे सहमत हूँ,” वेल्स ने कहा।

“विदेशी मामलों में रूसियों ने अक्सर दीर्घकालीन दृष्टिकोण से ही काम किया है,” मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा—“लेकिन इस समय मैं उन्हें ऐसा करते नहीं देखता। हिटलर के साथ सन्धि करने के बाद से वे अल्पकालीन पद्धति के अनुसार कार्य कर रहे हैं और अपनी दृष्टि वर्तमान स्थिति के अन्त तक भी नहीं दौड़ा पा रहे हैं।”

इस बीच वेल्स ने एक दूसरी सिगरेट सुलगाई। वह एक के बाद दूसरी सिगरेट पीने के अभ्यस्त मालूम होते थे।

“रूसी व्यापार पर से नैतिक प्रतिबन्ध हटाने के सम्बन्ध में मेरी मुख्य आपत्ति यह है कि रूसी हमारे मंत्रीपूर्ण सकेत से लाभ उठाकर जापान के साथ नम्रभीता करने का प्रयत्न कर सकते हैं,” मैंने उनके सिगरेट सुलगा लेने पर कहा।

वेल्स—“यह तो होना ही है।”

मै—“आपको पता है कि स्टालिन जापान से क्या चाहते हैं ?”

वेल्स—“रूस ने दक्खिनी सखालीन और चीन के उन प्रांतों की मांग की है जिनका उल्लेख आपने अभी किया था।”

मै—“क्या आप समझते हैं कि जापानी रूस के मचूरिया से बाहर रहने के वचन पर विश्वास करेंगे ?”

वेल्स—“जहाँ तक ‘विश्वास’ का सवाल है वह कई बातों पर निर्भर है, जैसे जापान का यह सोचना कि जर्मनी रूस को यूरोप की ओर दबाये रख-कर एशिया में उसकी सरगमियों को रोक सकता है। यह भी बात सही है कि पिछले दो महीनों में रूस ने जितने शस्त्र च्याग-काई-शेक को भेजे हैं उतने उसने पिछले दो साल में किसी समय भी नहीं भेजे।”

मै—“तो क्या आप समझते हैं कि इस प्रकार रूस अपने साथ समझौता करने के लिए जापान पर दबाव डाल रहा है ?”

वेल्स—“मैंने इसका अर्थ यही लगाया है। दक्षिण में विस्तार का काम जापान की जल-सेना को करना होगा। लेकिन वह ऐसा करने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं मालूम होती। फिर भी राजनीतिक दृष्टिकोण से उसकी सेना अधिक शक्तिशाली है।”

मै—“जल-सेना अनिच्छुक क्यों है ?”

वेल्स—“अगर आप मेरी राय साफ-साफ जानना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि जापानी जल-सेना का दक्षिण की ओर विस्तार कर लेने के लिए इच्छुक न होने का मुख्य कारण यह है कि उसके अफसरों को राजनीति का बहुत अच्छा ज्ञान है और वे विश्व-स्थिति को अधिक गम्भीरता के साथ समझ सकते हैं।”

मै—“मैं समझता हूँ कि नीति को निर्धारित करने में आजकल जिस बात का सबसे अधिक महत्त्व है, वह है ‘कार्य करने के लिए अवसर का मिलना।’ स्याम की घटनाओं और हिन्द-चीन में फ्रांसीसियों के पतन में जापान को कार्य करने के लिए अवसर प्रदान किया और जापान के अंतिम निर्णय पर जितना प्रभाव इन अवसरों का पड़ा उतना टोकियो में किये गए किसी विचार-विमर्श या आयोजन का नहीं।”

वेल्स (ज़ोर देते हुए)—“मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।”

इसके पश्चात् हमने चीनी और भारतीय जनता के प्रति अमेरिका

और ब्रिटेन के रुख के सम्बन्ध में बातचीत की। मैंने भारत के राष्ट्रीय नेता जवाहरलाल नेहरू का उल्लेख किया।

वेल्स—“हम पंडित नेहरू को जानते हैं और उनका बड़ा आदर करते हैं। यदि जापान इंग्लैंड और अमेरिका पर आक्रमण कर दे तो नेहरू पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ?”

मैं—“मैं समझता हूँ कि नेहरू जापान का बड़ा विरोध करेंगे। यह उनकी भावुकता-जनित प्रतिक्रिया होगी। जहाँ तक उनकी नीति का प्रश्न है वह तो अंग्रेजों के कार्य पर निर्भर होगी। अंग्रेज अपने घर में तो जनतंत्री बनते हैं लेकिन भारतवर्ष में उन्होंने काफी मूर्खता के साथ काम किया है। भारत में ब्रिटेन की प्रतिक्रिया सबसे बाद में हुई है और मैं समझता हूँ कि अनुदार दल वाले उस पर अंतिम सास तक अधिकार जमाये रखना चाहेंगे।”

वेल्स—“यहाँ के लोगो में भारत के प्रति उदार नीति बरतने की बड़ी प्रबल भावना है। आप नेहरू से अखिरी बार कब मिले थे ?”

मैं—“सितम्बर १९३८ में जिनेवा में और उससे पहले पेरिस और लन्दन में।”

“आपकी समझ में आजकल रूस की स्थिति कैसी है ? उसकी सेना की शक्ति कितनी होगी ?” वेल्स ने मुझसे एकाएक पूछा।

मैं—“रूसी सेना और हवाई वेडे की शक्ति को कम कूटना भूल होगी। फिर भी अगर जर्मन चाहे तो वे यूक्रेन और काकेशिया के भी कुछ हिस्से को जीत सकते हैं।”

वेल्स—“वे ऐसा करना क्यों चाहेंगे ?”

मैं—“अगर हिटलर ब्रिटेन पर आक्रमण नहीं कर सकेगा तो वह यह साच-कर कि लड़ाई लम्बी चलेगी शायद पहले रूस का सफाया करने का निश्चय करेगा।”

वेल्स—“तो क्या उसके कारण जर्मनी को दो मोर्चों पर नहीं लड़ना पड़ेगा ?”

मैं—“नहीं। हिटलर का ख्याल है कि यद्यपि ब्रिटेन पर सफलता पूर्वक आक्रमण नहीं किया जा सकता तथापि ब्रिटेन में कम-से-कम साल भर तक यूरोप पर आक्रमण करने की क्षमता नहीं है। इसके अलावा रूस पर आक्रमण करने में हिटलर का उद्देश्य उसे पीछे ढकेलना होगा ताकि अधिकृत यूरोप पर ब्रिटेन के भावी आक्रमण के समय रूस दूसरा मोर्चा न खोल सके।”

वेल्स—“लेकिन बात यही तो समाप्त नहीं होगी।”

मै—“नहीं, किन्तु उससे हिटलर की कठिनाइया टल सकती है।”

वेल्स—“यदि जर्मनी इंग्लैण्ड पर आक्रमण करने की चेष्टा करे तो क्या उससे रूस को जापान पर अधिक दबाव डालने में सहायता नहीं मिलेगी।”

मै—“उसका उलटा असर भी तो पड़ सकता है क्योंकि अगर हिटलर को ब्रिटेन पर आक्रमण करने में सफलता न मिली तो वह अपनी शक्ति रूस पर केन्द्रित करेगा और उस दशा में जापान की स्थिति अच्छी हो जायगी।”

वेल्स—“यह सब कोरी कल्पना है। अगले कुछ महीनों की घटनाओं से पता चल जायगा।”

मै—“और भी बातें हैं जिन पर विचार करना होगा। जर्मनी की बलगेरिया पर विजय होने से भी रूस दुर्बल हो जायगा और जापान को सहायता मिलेगी।”

वेल्स—“यह ठीक है। मैं समझता हूँ कि रूस जर्मनी को बलगेरिया पर आधिपत्य जमाने से किसी तरह रोकेगा नहीं।”

मै—“यही बात मैं आजकल अपने भाषणों में कह रहा हूँ। किन्तु क्या बलगेरिया से तुर्की का सवाल नहीं उठ खड़ा होता? हो सकता है कि रूस और जर्मनी तुर्की को बाट लेने का निश्चय करे।”

वेल्स—“जर्मनी ने यह प्रस्ताव रूस के सामने पिछले अक्टूबर में ही रखा था।”

मै—“विभाजन की रेखा कहा होगी, यह मैं नहीं कह सकता। असली महत्व का स्थान इस्तम्बूल है, और सवाल यह है कि उसे कौन पायगा।”

वेल्स—“इसका जवाब मैं नहीं दे सकता।”

मै—“मैंने रूस के विदेशी मामलों का एक इतिहास लिखा है।”

वेल्स—“बड़ी अच्छी किताब है।”

मै—“उसमें से मैंने रूस के लन्दन और पेरिस-स्थित भूतपूर्व राज-दूत क्रिश्चियन राकोवस्की द्वारा दी गई कुछ सामग्री निकाल दी थी क्योंकि ऐसा करने से स्टालिन और राकोवस्की के सम्बन्ध के बिगड़ने का भय था। राकोवस्की ने मुझे बताया था कि तुर्की और ईरान में स्टालिन की विशेष दिलचस्पी है। यह बड़े मार्क की बात है कि स्टालिन जैसे बोल्शेविक पर भी विदेश-नीति निर्धारित करते समय अपने जन्म-स्थान जार्जिया के भूगोल का प्रभाव पड़ा था। सन् १९१९ के बाद से सभी बोल्शेविक तुर्की के पक्ष-पाती रहे हैं, क्योंकि कमालपाशा साम्राज्यवाद और पादरियों का विरोधी था। किन्तु जार्जियन बोल्शेविकों के हृदय में सदा शका की भावना बनी रहा,

क्योंकि वे इस बात को भूले नहीं कि मार्च १९२१ में तुर्कों ने जार्जिया के बन्दरगाह वातूम पर कब्जा कर लिया था। यही कारण है कि जार्जिया के कम्युनिस्ट तुर्की सीमा को पीछे ढकेलना चाहते हैं। स्टालिन की उत्तरी ईरान में भी दिलचस्पी रही है जो कि जार्जिया की सीमा पर है।”

वेल्स ने सिर हिलाकर स्वांक्रुति की सूचना दी। मुझे पता नहीं था कि वह मुझसे और कितनी देर बात करेंगे, इसलिए मैंने नैतिक प्रतिबन्ध की चर्चा छेड़ते हुए कहा—“चूँकि स्टालिन के लिए हिटलर से मिलकर काम करना जरूरी है और हमारे मित्रतापूर्ण सकेत से रूस और जापान में समझौता होने में सहायता मिलेगी, इसलिए मेरी समझ में नहीं आता कि प्रतिबन्ध क्यों उठाया जाय ?”

वेल्स—“क्योंकि जुलाई १९४० से पहले छत्तीस महीने तक रूस से बातचीत करना असम्भव था। इसलिए मैं सम्पर्क स्थापित करने में विश्वास करता हूँ और अब भी समझता हूँ कि सम्पर्क वाञ्छनीय है।”

मैं—“मैं समझता हूँ कि आमास्की खुश है, वह एक छोटा आदमी है।”

वेल्स—“हो सकता है कि वह छोटा आदमी हो, लेकिन वह तेज है और उसे मालूम है कि प्रतिबन्ध के हटाने से पदार्थिक वस्तुओं पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।”

मैं—“हाँ, वह बड़ा तेज आदमी है। आगे देखा होगा कि मैंने अपने पत्र में उन चीजों का उल्लेख भी नहीं किया है, जो रूस को नई व्यवस्था के अनुसार प्राप्त होगी। मैं समझता हूँ कि उस कुछ अधिक नहीं मिल पायगा; किन्तु मुझे इस बात का भय है कि वह हमारी मैत्री का प्रयोग जापान पर दबाव डालने में करेगा।”

वेल्स—“आपने पहले कहा था कि अगर जर्मनी इंग्लैंड पर आक्रमण नहीं कर सका तो लडाई लम्बी चलेगी और इंग्लैंड यूरोप पर आक्रमण नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड इटली के रास्ते यूरोप पर चढ़ाई कर सकता है।”

यह सुनकर मैं सीधा बैठ गया। “वेल्स कोई रहस्य तो नहीं बता रहे हैं” मैंने सोचा और उनसे कहा—“हिटलर मुसोलिनी के कंधे से कंधा मिला देगा और आक्रमण का रोकने का प्रयत्न करेगा।

वेल्स—“किन्तु एक पूरे समुद्र-तट की रक्षा करना कठिन काम है।”

वेल्स ने अपना हाथ अपनी कुर्सी के हत्ये पर रखा और मुझसे पूछा—“क्या आप वाशिंगटन बराबर आया करते हैं ?” मैं जाने के लिए उठ खड़ा

हुआ। वेल्स ने मुझसे कहा कि "अगली बार वाशिंगटन आने से पहले आप मुझे पत्र लिख दीजिएगा। मुझे आपसे फिर मिलने में खुशी होगी।"

यह समनर वेल्स से मेरी पहली मुलाकात थी। उसके बाद उनसे कई बार दफ्तर में और दफ्तर से बाहर भी बड़ी लाभदायक और दिलचस्प बातचीत हुई।

जिन दिनों ब्रिटेन यूरोप के साथ युद्ध में उलझा हुआ था, जापान ने दक्षिण की ओर हालैंड और ब्रिटेन के साम्राज्य में बढ़ने का अभूतपूर्व सुअवसर देखा। इसीलिए उसने रूस के साथ समझौता करना चाहा, ताकि उत्तर में वह सुरक्षित रह सके।

जर्मनी जापान को दक्षिण की तरफ मोड़ना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने से ब्रिटेन को कुछ शक्ति और साथ-ही-साथ अमेरिकन सहायता भी यूरोप की ओर से हटाई जा सकती थी। इसीलिए उसने जापान को रूस के साथ समझौता करने में सहायता दी। उसे इस बात की चिन्ता नहीं हुई कि इस कार्य से रूस की स्थिति दृढ़तर बन जायगी। हिटलर ने सोचा कि रूस तो मैं अकेला ही निपट सकता हूँ।

अमेरिका ने रूस से अच्छे संबंध बनाने चाहे, क्योंकि उसे आशा थी कि बाद में रूस घुरीराष्ट्रो के गुट से तोड़ लिया जायगा। इसीलिए उसने रूस व्यापार पर से नैतिक प्रतिबन्ध उठाकर रूस को अपनी सद्भावना का परिचय दिया।

स्टालिन ने अमेरिका की इस सद्भावना से लाभ उठाया। साथ-ही-साथ उसने जापान के उत्तर की ओर बढ़ने की प्रेरणा से और जर्मनी की उत्तर की ओर बढ़ाने की इच्छा से भी लाभ उठाया और जापान के साथ तटस्थता की संधि कर ली। स्टालिन को इस संधि की आवश्यकता थी, क्योंकि जापान के दक्षिणी प्रशान्त में फँस जाने से रूस को केवल एक सक्रिय शत्रु—जर्मनी—का भय रह जाता।

अप्रैल १९४१ में रूस और जापान में जो संधि हुई उसमें दोनों देश की सीमा के संबंध में कुछ समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार रूस जापान को मंचूरिया पर अधिकार करने की छूट दे दी, यद्यपि पहले उस इसका विरोध किया था और बदले में जापान ने बाहरी मंगोलिया पर रूसी संरक्षण स्वीकार कर लिया था। बाहरी मंगोलिया का प्रदेश बड़े ही कूटनीतिक महत्त्व का है। उसे चीनी अपना समझते हैं, किन्तु कितने ही वर्षों से उस पर उनका राज नहीं रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि रूस और जापान जैसे दो

बारूदी साम्राज्यो ने सधि कर चीन के व्यय पर एक-दूसरे के लिए गु जाइश निकालने की चेष्टा की

सधि करने के बाद जब जापान के विदेश-मंत्री मत्सुओका मास्को से लीटे तो स्टालिन उन्हें विदा करने के लिए स्टेशन तक गये। इतिहास में यह पहला उदाहरण था कि स्टालिन ने किसी को स्टेशन पर जाकर विदा किया। स्टालिन के प्रत्येक कार्य की रूपरेखा किसी निश्चित ध्येय को दृष्टि में रखकर पहले से ही तैयार कर ली जाती है। एसोसिएटिड प्रेस के प्रतिनिधि हेनरी कैसीडी ने, जो स्टेशन पर मौजूद थे, बताया है कि स्टालिन ने मत्सुओका का चुम्बन लेकर विदा किया। इसके बाद स्टेशन पर ही स्टालिन की मुलाकात जर्मनी के सैनिक उपाधिधारी कर्नल हैन्स क्रेव्स से हुई। उनसे हाथ मिलाकर स्टालिन ने कहा—“हम मित्र बनकर रहेंगे।”

२६ मार्च १९४१ को समनर वेल्स से जब मेरी दूसरी मुलाकात हुई तो हमने फिर रूस पर जर्मन आक्रमण की सम्भावना पर विचार किया और प्रशान्त महासागर की गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में ध्यानपूर्वक बातचीत की। जब मेरी उनसे १९ मई को बातचीत हुई तो रूस और जापान में सधि हो चुकी थी, हेस हवाई जहाज में बैठकर स्काटलैण्ड पहुँच चुका था और यूरोप की प्रत्येक राजधानी में रूसी सीमा पर दोनों दिशाओं से सैनिक तैयारी के समाचार फैल रहे थे। रूस और जर्मनी में युद्ध छिड़ने के ६ दिन बाद विदेश कार्यालय में मेरी समनर वेल्स से फिर बातचीत हुई। हमने उस समय की परिवर्तित युद्ध-स्थिति के कई पहलुओं का सिंहावलोकन किया। जाने से पहले मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप मेरे ग्रेट ब्रिटेन जाने की व्यवस्था करा दीजिए।

लिटविनाव और जॉसेफ़ ई० डेविस

अक्टूबर १९३६ में जब लंदन में मेरी विन्सटन चर्चिल में बात-चात हुई तो हमने आध घंटे तक इस प्रश्न पर विचार किया कि किस प्रकार रूस को ब्रिटेन के पक्ष में लाया जा सकता है। फिर भी यह काम किमी नाज़ा-विरोधी को नहीं दिया गया। स्वयं हिटलर ने ऐसा कर दिया।

रूस और जर्मनी में लड़ाई छिड़ जाने के कारण स्टालिन और लिटविनाव में शाब्दिक द्वन्द्व आरम्भ हो गया। क्रान्तिवादी अक्सर राजद्रोही और अवज्ञाकारी माना जाता है; किंतु रूसी नागरिक इस समार के सबसे कट्टर राज्यानुयायी माने जाते हैं। तानाशाही देशों में या तो प्रजा को शासक के आदेश की आख बंद करके पालन करना पड़ता है या फिर। वहां कोई शासक सस्या की आलोचना नहीं करता, या यो कहिए कि आलोचक का प्रथम विरोध में ही अन्त कर दिया जाता है। मैक्सिम लिटविनाव इन दोनों नियमों का अपवाद है।

लिटविनाव एक प्रतीक है और स्टालिन उनका महत्त्व जानते हैं। लिटविनाव का नाम सामूहिक सुरक्षा का द्योतक है। वह न तो तुष्टीकरण के पक्षपाती थे, न आक्रमण के। जब रूस को जर्मनी के साथ संधि करने की सभावना दिखाई दी तो उसने लिटविनाव का सामने से हटा दिया। लिटविनाव रूस का सबसे प्रतिभाशाली हिटलर-विरोधी था। बाद में जब हिटलर ने रूस पर आक्रमण किया तो स्टालिन ने लिटविनाव को फिर सामने कर दिया और उनसे अंग्रेज़ों से अपनी सुन्दर अंग्रेज़ी भाषा में रेडियो पर बात-चीत करने के लिए कहा। बाद में स्टालिन ने उन्हें राज-दूत बनाकर वाशि-गटन भेज दिया।

दो वर्ष तक बेकार रहने के बाद एक दिन लिटविनाव मास्को के निकट काठ के एक कमरे में बैठ हुए अपनी पत्नी ईवी के साथ ताश खेल रहे थे कि एकाएक नाज़ियों ने रूस पर आक्रमण कर दिया। जर्मनों के इस निर्दयतापूर्ण आक्रमण के फलस्वरूप पुनः नौकरा पर बुला लिये जाने पर भी लिटविनाव ने अपने को रूस का “अपनी पीठ पर आप कोड़ा मारने” की नीति

से अलग रखा। उन्होंने कभी भी स्टालिन की हिटलर के साथ सधि करने की नीति का समर्थन नहीं किया। सन् १९४१ में जब सर स्टेफर्ड क्रिप्स मास्को में ब्रिटिश राज-दूत के पद पर काम कर रहे थे, लिटविनाव ने उनसे कहा कि जर्मनी के साथ सधि करके हमने अपनी उगली जला ली है। ८ जुलाई १९४१ को मास्को रेडियो पर बोलते हुए लिटविनाव ने बड़ी गूढ़ता के साथ स्टालिन को डाटा और कहा—“हिटलर और उसके पार्टिडुओ के साथ की गई किसी भी सधि, उनके द्वारा दिये गये किसी भी आश्वासन या तटस्थ रहने की घोषणा, या यो कहिए कि उनके साथ किये गये किसी भी प्रकार के सम्बन्ध से इस बात की गारन्टी नहीं मिल सकती कि वे अकस्मात् या अकारण हम पर आक्रमण नहीं करेंगे। विश्व-विजय के अपने स्वप्न को पूरा करने के अभिप्राय से दूसरे देशों पर आक्रमण करने के अपने कुटिल आयोजनों में हिटलर ने सदा फूट डालकर आक्रमण करने की ही नीति का ध्यान रखा है। वह अपने शिकारों को एक साथ मिलकर विरोध करने से रोकने के लिए घृणित-से-घृणित युक्तियाँ प्रयोग में लाता है और इस बात का विशेषरूप से प्रयत्न करता है कि उसे यूरोप के सबसे शक्तिशाली देशों के साथ दो मोर्चों पर न लड़ना पड़े। उसकी चाल हमेशा यह होती है कि अपने शिकारों को पहले से ही ताक लो और परिस्थिति के अनुसार उनमें से एक-एक पर प्रहार करा।”

रूस-सम्बन्धी नीति का यह एक विलकुल सत्य चित्रण है। इसमें इस बात की आलोचना की गई है कि स्टालिन ने हिटलर को, इस नीति को कार्यान्वित करने में, सहायता दी।

लिटविनाव ने अपने भाषण में यह भी कहा कि हिटलर ने पहले पश्चिमा देशों से निबटने का विचार किया ताकि वह रूस पर प्रहार करने के लिए विलकुल स्वतंत्र हो जाय। यह बात उसके प्रतिभाशाली विदेश-मंत्री ने उन कूटनीतिज्ञों के गाल पर चपत लगाने के लिए कही, जो आरोप लगाया करते थे कि स्टालिन ने हिटलर के साथ सधि इस उद्देश्य से की है कि सन् १९३९ में पोलैण्ड को जीतने के बाद जर्मनी रूस पर आक्रमण न करने पाय। लिटविनाव ने कहा कि यह बात गलत है, हिटलर की योजना पहले पश्चिम की ओर बढ़ने की है। यह बात उस समय कुछ लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी जिनमें से रोज़वेल्ट भी एक थे।

फिर भा, जैसा कि लिटविनाव ने बताया, कहीं कोई रुकावट थी। हिटलर को इंग्लिश चैनल पार करने की शिक्षा नहीं मिली थी, वह इंग्लैंड पर

अधिक पसन्द करता है। फिर भी रूसी जीवादी डेविस के विचारों को समाजवाद में नहीं बदल सका। उनकी “मास्को यात्रा” (मिशन टू मास्को) नामक पुस्तक रूस-विरोधी है। उदाहरण के लिए, उसमें डेविस ने एक स्थान पर लिखा है—“सच पूछिए तो रूस की सरकार अकेले एक आदमी स्टालिन में केन्द्रित है, जिन्होंने अपने प्रतिद्वन्द्वियों पर विजय पाई और उनका पूर्ण रूप में अन्त करके सर्वोच्च अधिकारी बन गये।”

एक बार डेविस ने अमेरिका के विदेश विभाग को अपने गुप्त मकेत में तार दिया—“यहाँ भयानक आतंक फैला हुआ है। मास्को में इस बात के अपनेको प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ के निवासियों के पत्येक वर्ग में भय छाया हुआ है। एक भी घर ऐसा नहीं जिसे इस बात का लगातार डर न हो कि कहीं रात के समय (अक्सर एक और तीन बजे के बीच) गुप्त पुलिस आवाज बोल दे। पुलिस जब एक बार किसी को पकड़ लेती है तो उसके बारे में महीनों तक और अक्सर कभी भी, कुछ नहीं पता चलता। यह अक्सर शिकायत की जाती है कि रूस की मजदूर तानाशाही की गुप्त पुलिस उतनी ही निर्दय और निर्भय है जितनी कि पुराने ज़ार के समय में थी।

डेविस ने अपनी पुस्तक में यह भी लिखा है कि साम्यवाद चल नहीं सकता, वह रूस में नहीं चला। सोवियत शासन की निन्दा करते हुए उन्होंने लिखा है कि “यहाँ दल के प्रति कर्त्तव्य की तुलना में व्यक्तिगत वफादारी को महत्त्व नहीं दिया जाता। परिणाम यह होता है कि नेतृत्व के मामले में यहाँ के लोगो को एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो सकता। यह एक गम्भीर और आधारभूत दुर्बलता है। इसके अलावा रूस की आर्थिक व्यवस्था रूसी उद्योग-धंधों पर सरकारी नियंत्रण होने के कारण सफल नहीं हुई है बल्कि इसके बावजूद भी उसे सफलता मिली है।”

तो फिर रूस के कम्युनिस्टों और दल-मित्रों ने डेविस की पुस्तक की इतनी प्रशंसा क्यों की? उस पुस्तक में रूसी सिद्धांतों और प्रणालियों के अस्वीकार किये जाने पर भी उसका रूसियों द्वारा स्वागत किया जाना सोवियत-समर्थक विचारधारा की एक दिलचस्प कुंजी है। उसमें स्टालिन की व्यक्तिगत तानाशाही के बाल की खाल निकाली गई है, किन्तु उसमें स्टालिन और रूस की औद्योगिक सफलताओं की प्रशंसा की गई है और रूस की वैदेशिक नीति का समर्थन भी किया गया है। इसके अलावा स्वयं डेविस ने वाद में मास्को के मुकदमों का समर्थन किया और अपनी पुस्तक का एक ऐसा विकृत फिल्म बनने दिया जिसमें अभियुक्तों का दोष प्रदर्शित करने का

प्रयत्न किया गया है। डेविस के इस काम ने उसे स्टालिन के समर्थकों में प्रिय बना दिया।

मास्को के मुकदमे सन् १९३६, ३७ और ३८ में हुए, वे रूसी इतिहास के सबसे सकटपूर्ण परिच्छेद थे और स्वयं स्टालिन को करतूत थे। इसलिए रूसी सरकार अब भी इस बात की आशा रखती है कि ससार का जन-मत इन मुकदमों को केवल षड्यंत्र मात्र नहीं समझेगा। मास्को के मुकदमों और विरोधी-तत्त्वों के उन्मूलन के सम्बन्ध में बहस-मुवाहसा अब भी होता है।

रूस की गुप्त पुलिस आजकल उच्च श्रेणी के रूसी नेताओं की सावधानी के साथ निगरानी करती है। वह उनकी चाल-ढाल, टेलीफोन, वार्ता और डाक, इन सब पर दृष्टि रखती है। फिर भी मास्को के मुकदमों में सरकारी इस्तगासे की ओर से एक भी प्रमाण पेश नहीं किया जा सका। अभियुक्तों को उनके अपराध-स्वीकार के आधार पर ही दण्ड दिया गया।

मुकदमों की कार्रवाई को, जो अब अंग्रेजी में उपलब्ध है, ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद अभियुक्तों के अपराध-स्वीकार का रहस्य बिलकुल खुल जाता है। उससे पता चलता है कि इस्तगासे और अभियुक्तों में पहले से ही समझौता हो गया था। सफाई पक्ष वालों ने वे ही बयान दिये जो रूसी सरकार ने उनसे देने के लिए कहा। उदाहरणार्थ, बहुत से रूसी नेता स्टालिन के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने अनुभव किया कि स्टालिन रूसी क्रान्ति का सत्यानाश कर रहा है और रूस को आन्तरिक राष्ट्रीय की वजाय राष्ट्रीय और प्रगतिशील की वजाय प्रतिगामी बना रहा है। फिर भी रूसियों की धारणा है कि स्टालिन अदृष्टित है और कोई भूल नहीं कर सकता। चूँकि वह कोई गलती नहीं कर सकता इसलिए लोग उस पर भूल करने का दोषारोपण नहीं कर सकते। मुकदमे में अभियुक्तों का स्वतंत्रता-पूर्वक अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है, फिर भी मास्को-मुकदमे के अभियुक्तों ने स्टालिन के सम्बन्ध में अपने भाव स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त नहीं किये। उन्होंने स्टालिन की कोई निन्दा न कर सरकारी प्रवक्ताओं की भाँति उसकी कीर्ति का गान किया। यदि वे अपने निजी विश्वास के अनुसार अपने भाव प्रकट करते तो वे निश्चय ही स्टालिन को लाञ्छित करते।

अभियुक्तों से अपराध स्वीकार कराने के लिए उन्हें प्रायः महीनो—कभी-कभी दस महीनो—तक रूसी गुप्त पुलिस के कारावास में बंद रखा गया। इस बीच वे अपना अपराध स्वीकार करने से इन्कार करते रहे और जब तक कि उनका आत्म-दल तोड़ न दिया गया तब तक वे टस-से-मस नहीं हुए। अन्त में अभियुक्तों और सरकार में समझौता हुआ—वह यह कि अभियुक्तों को मृत्यु या आजीवन

कारावास का दण्ड दिया जायगा, किन्तु यदि मुकदमे की सुनवाई के समय उनका व्यवहार अच्छा रहेगा तो उनके साथ दया दिखाई जायगी। मेरा अपना विश्वास है कि अभियुक्तों को इस बात का आश्वासन दिया गया कि उनको और उनके परिवार वालों को मारा नहीं जायगा। वे सचमुच छोड़े गये या नहीं, यह मुझे नहीं मालूम; स्वयं अभियुक्तों को इस बात का पक्का भरोसा नहीं था कि रूसी पुलिस अपना वचन पूरा करेगी। फिर भी इतना पता है कि अभियुक्तों के कुछ बच्चे बाद में जीवित रहे। जो कुछ भी हो, जब पता चल जाता है कि बिना हाँ में हाँ मिलाये अपनी और अपने बच्चों की जान नहीं बचेगी तो स्वभावतः लोग उस अवसर से लाभ उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं।

अक्सर पूछा जाता है कि मास्को के अभियुक्तों ने ज़ार के शासन-काल और नाज़ी जर्मनी के अनेक क्रान्तिकारियों की भाँति मर जाना ही क्यों नहीं पसन्द किया। एक बोल्शेविक के लिए ज़ार की पुलिस की अवहेलना करना, उतना कठिन नहीं था जितना कि उस बोल्शेविक सरकार की उपेक्षा करना; जिसकी स्थापना में उसने स्वयं हाथ बटाया था और जिसे वह संसार की अन्य सभी शासन-प्रणालियों से उत्तमतर समझता था, चाहे उसकी नीति के साथ कितना ही मतभेद क्यों न हो। जब वही सरकार उससे एक झूठे अपराध-स्वीकार-पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है तो वह विडचिडा हो जाता है और उसमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने की इच्छा नहीं रह जाती। मास्को-अभियुक्तों द्वारा मृत्यु का आह्वान न किया जाने का एक कारण यह भी था। जहाँ तक और कारणों का प्रश्न है, यह स्मरण रखना चाहिए कि जितने अभियुक्तों ने अपराध स्वीकार किया उनसे अधिक अभियुक्त बिना मुकदमे चलाये ही मार डाले गये। मुकदमों की सुनवाई उन्हीं की हुई जिन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया। ऐसे व्यक्तियों की संख्या ५० प्रतिशत से भी कम थी। हजारों ने अपराध स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और इसीलिए उन्हें मृत्यु-दण्ड भोगना पड़ा।

यह अपराध-स्वीकार रूसी इतिहास को झूठा बना देता है। इसमें वे परम्परागत रूसी इतिहास की प्रत्येक नई पुस्तक और नए रूसी कोषों के प्रत्येक भाग में या तो पहले संस्करणों में प्रकाशित अनेकानेक महत्वपूर्ण और सिद्ध घटनाएँ निकाल दी गई हैं या उनमें अनगिनत मनगढ़न्त घटनाएँ जोड़ दी गई हैं और इस प्रकार रूस का इतिहास असत्य बना दिया गया है। 'असत्यवादिता' सभी डिक्टेटरो का सचित्र अस्त्र है। उसका प्रयोग पुस्तकों में, समाचारपत्रों में, कूटनीतिज्ञता में और मुकदमों में सभी जगह किया जाता है।

नागरिक बोल्शेविक नेताओं पर सार्वजनिक रूप से मुकदमा चलाने के

अलावा ११ जून १९३७ को रूसी सेनापति मार्शल टुखाचेवस्की और सात अन्य मार्शलो तथा जनरलो पर फौजी मुकदमा भी चलाया गया। यह मुकदमा गुप्त रूपसे किया गया और यह मास्को में सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा माना जाता है। किसी भी बाहरी आदमी को मालूम नहीं कि इस मुकदमे में क्या हुआ। उन आठ मार्शलो और जनरलो के मुकदमे की सुनवाई मार्शलो और जनरलो ने ही की। साल भर के भीतर-ही-भीतर स्वयं इन न्यायाधीशों में से अधिकांश मार डाले गये। मुकदमे के सम्बन्ध में जानकारी का पूर्ण अभाव है। हाँ, इतना अवश्य कहा जाता है कि मुकदमा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन रूस में ऐसी बातों का पता चलना टेढ़ी खीर है। हमारी जानकारी तो वन उस संक्षिप्त सरकारी विज्ञप्ति तक सीमित है जो रूसी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई थी और जिसमें बताया गया था कि अभियुक्तों के मुकदमे की सुनवाई हुई, उन्होंने राजद्रोह का अपराध स्वीकार किया और उन्हें मृत्यु का दण्ड दिया गया। मुकदमे के बाद रूसी सेना के हजारों अफसर अपने पद से हटा दिये गये।

२७ जुलाई १९३७ को डेविस ने अमेरिका के विदेश विभाग को तार दिया—“जहाँ तक इन जनरलो के जर्मन सरकार से षडयंत्र करने के कथित अपराध का प्रश्न है, यहाँ के लोग उसे साधारणतः न्याय-सगत मानते हैं। असली बातें अभी उपलब्ध नहीं हुई हैं और इसमें सन्देह है कि वे एक लम्बे अरसे तक उपलब्ध हो सकेंगी। इसलिए यह बताना सम्भव नहीं कि मुकदमे में वस्तुतः क्या हुआ और रूसी सेना के अफसरों का असली अपराध क्या था? राय तो जानी हुई बातों द्वारा निकाले गये निष्कर्ष के ही आधार पर बन सकती है। किन्तु ऐसी बातें मालूम कब हैं?”

‘अमेरिकन मैगज़ीन’ के दिसम्बर १९४१ के अंक में मिस्टर डेविस ने अपनी भूल स्वीकार की और लिखा कि मास्को के मुकदमे का तत्त्व में जाने नहीं पाया। डेविस मुकदमे में गये तो जल्द थे किन्तु अभियुक्तों के अपराध को ठीक-ठीक नहीं समझ सके। डेविस ने अपना अपराध किस आधार पर स्वीकार किया? निश्चय ही उन्हें कोई नया प्रमाण नहीं मिला होगा। किसी ने कोई नया प्रमाण दिया ही नहीं था। न तो सोवियत सरकार ने, न उसके समर्थकों ने ही इस बात का रत्ती भर भी प्रमाण दिया कि रूसी सेना के जनरलों ने, जिनमें से दो यहूदी थे, रूस के विरुद्ध नाज़ी जर्मनों या जापान के षडयंत्र में हाथ बँटाया। प्रमाण तो दूर रहे मुकदमे की प्रारम्भिक बातों तक का पता नहीं। नागरिक नेताओं के अपराध के बारे में भी रूस के किसी सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति ने कोई जानकारी नहीं दी है। मुकदमे के बाद

से अब तक इतने वर्ष बीत गये किंतु रूसी राजधानी मास्को से एक भी बात ऐसी नहीं मालूम हुई जिसमें अभियुक्तों के अपराध का समर्थन किया जा सके। इसका कारण सहज ही समझा जा सकता है।

मास्को के मुकदमे में सफाई पक्ष वालों ने बताया था कि ट्राट्स्की ने हिटलर के डिप्टी रूडाल्फ हेस से स्वयं बातें की थीं और रूसी सरकार के तत्त्वे को उलटने का षड्यंत्र रचा था। हेस के विरुद्ध यह एक बड़ा गम्भीर आरोप है लेकिन समझ में नहीं आता कि यूरेमवर्ग की अदालत में युद्ध-अपराधियों पर चलाए गए मुकदमे में हेस पर और आरोपों के साथ-साथ यह आरोप भी क्यों नहीं लगाया गया। उस मुकदमे में रूस का इस्तगामे का एक सरकारी वकील भी था। उसने हेस से ट्राट्स्की के साथ की गई बातों की वास्तव पृष्ठ ताल्लु क्यों नहीं की? क्या इसका कारण यह था कि उसे पता था कि हेस और ट्राट्स्की में बातचीत हुई ही नहीं?

हिटलर की पराजय के बाद कितने ही गुप्त नाजी दस्तावेज प्रकाशित किये जा चुके हैं। अमेरिकन सरकार ने भी जर्मनी के अनगिनत सरकारी पत्र प्रकाशित किये हैं जिनसे अब तक अज्ञात और अत्यंत गुप्त मामलों पर बड़ा बहुमूल्य प्रकाश पड़ा है। रूसी सेना ने आधे जर्मन पर विजय प्राप्त की। उसने जर्मनी की राजधानी बर्लिन को जीता। किंतु क्यों उसे एक भी ऐसा पत्र नहीं मिला जिससे यह सिद्ध हो सकता कि मार्शल टुखाचेव्स्की और उनके जनरलों ने रूस पर आक्रमण करने के लिए नाजियों के साथ षड्यंत्र किया था, क्या यह एक दिलचस्पी की बात नहीं कि मास्को में अब तक कोई भी ऐसा पत्र प्रकाशित नहीं हुआ, जिससे अभियुक्तों पर लगाये गये आरोप या उनके अपराध-स्वीकार का समर्थन किया जा सके?

तो फिर कौन-सी ऐसी बात थी जिसके कारण डेविस ने 'अमेरिकन मैगजीन' में अपनी भूल स्वीकार की। उनके लिखने के अनुसार इसका कारण रूस में भेदियों का न होना है लेकिन डेविस को इस बात का अधिकार है कि नई घटनाओं के प्रकाश में अपने मन में परिवर्तन करे। किन्तु रूस में भेदियों के न होने से यह बात कैसा सिद्ध होती है कि जो लोग गोली से उड़ाये गये वे भेदिये थे। बहुत-से दूसरे देशों—जनतंत्री और सर्वसत्तावादी—में भी भेदिये नहीं थे। सम्भवतः रूस में भी विरोधियों के उन्मूलन से पहले भेदिये नहीं थे।

कुछ आलोचकों ने कहा कि जर्मनी पर रूस की विजय होने से मास्को के मुकदमे और सैनिक अधिकारियों के उन्मूलन की वाछनीयता सिद्ध होती है। उनका मत था कि चूँकि रूस में विरोधियों का उन्मूलन कर दिया गया है और

रूस नाजियों के विरुद्ध सफलतापूर्वक लड़ा है इसलिए यह सिद्ध होता है कि रूस के जर्मनी के विरुद्ध सफलतापूर्वक लड़ने का कारण यह था कि उसने अपने देश से विरोधियों का उन्मूलन कर दिया था। क्या खूब तर्क है यह। तब तो हम यह भी कह सकते हैं कि रूस में अकाल पड़ा और रूस नाजियों के साथ अच्छी तरह लड़ा, इस लिए रूस का नाजियों के साथ अच्छी तरह लड़ने का कारण अकाल है।

सच बात यह है कि रूस को अपने सैनिक विरोधियों के उन्मूलन के लिए बड़ी भयंकर कीमत अदा करनी पड़ी। छोटे-से फिनलैंड ने रूसी सेना को इतने दिनों तक क्यों रोके रखा? उसने रूसी सेना को इतनी भारी क्षति क्यों पहुँचाई? रूसियों ने सोचा कि वे फिनलैंड को बड़ी आसानी से कुचल डालेंगे। सम्भवतः फासी पर लटकाये गये टुखाचेवस्की ने अपने को इस मृग मराचिका से ग्रसित न होने दिया होना कि फिनलैंड में क्रांति करा देने में उस पर रूसी आक्रमण का मार्ग खुल जायगा।

रूसी सेना ने फिनलैंड में जो दुर्बलता दिखाई उससे हिटलर को रूस पर आक्रमण करने में प्रोत्साहन मिला और उन जनरलों की आपत्ति को भी दवाने में सहायता मिली जो रूस पर आक्रमण करने के विरुद्ध थे। इन जनरलों में फील्ड मार्शल ब्राउखिख भी थे।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि रूसी सेना ने जर्मनों के साथ लड़ने में बड़ी प्रतिभा दिखाई। किन्तु आरम्भ में उसका कार्य अच्छा नहीं था। रूस के बड़े-बड़े प्रदेश हाथ में निकल गये और लाखों रूसी मारे और पकड़े गये और घायल भी हुए। मच पूछिये तो रूस एक प्रकार से बिलकुल हार चुका था। मास्को के रक्षक और वॉलिन के विजेता मार्शल जूकाव ने २४ जून १९४५ को मास्को के रेड स्क्वायर में (जहाँ विजय-प्रदर्शन हुआ था) कहा—“ऐसे कितने ही अवसर आये जब स्थिति निराशाजनक हो गई थी।” ३ महीने बाद २४ अगस्त १९४५ को स्टालिन ने भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने क्रेमलिन (रूसी शासन-भवन) में सैनिक अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा—“सन् १९४१ और ४२ में ऐसे अवसर आये जब कोई आशा नहीं रह गई थी।”

दिसम्बर, १९४७ में नाज़ी नेता मास्को के उपनगर खिम्की तक पहुँच गई, जहाँ से वस द्वारा क्रेमलिन का रास्ता थोड़ी देर का है। स्टालिन-ग्राह तक में स्थिति अनिश्चित ही रही। राजनीतिक आलोचक तो केवल अंतिम विजय पर जोर देते हैं। किन्तु रूसी जनता और सेना को पता है

कि युद्ध इतना सरल नहीं था। रूस को टुखाचेव्स्की आदि के उन्मूलन के बाद सम्भलने में पांच वर्ष लग गये। रूसियों ने इस उन्मूलन का मूल्य लहू द्वारा चुकाया।

रूस के सम्बन्ध में बहुत-कुछ लिखा गया है। रूस की मव में बड़ी विशेषता उसकी जन-संख्या है। वहाँ १६ करोड़ ३० लाख आदमी रहते हैं। सदियों तक बुरी तरह रहते आने के बाद भी उनकी कार्य-क्षमता अपार है। उनका शरीर कठोर होता है और प्रकृति या इतिहास का उन पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ा है। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है और सतानोदयित बड़ी तीव्र गति से होती है। वे किसी बात से हतोत्साहित नहीं होते। युद्ध, रोग, दुर्भिक्ष और अपने नेताओं की भूल के कारण उपस्थित होने वाली स्थिति से वे जल्दी सम्भल जाते हैं। मैं उनके साथ १४ वर्ष तक रह चुका हूँ और उनमें प्रेम करता हूँ। वे नम्र और आज्ञाकारी होते हैं। वे मूल्य भी चुकाते हैं। मुकदमे और सैनिक उन्मूलन का भी उन्होंने मूल्य चुकाया।

मनुष्यों, विशेषतः युवकों, के मानसिक विकास के लिए आज सारे संसार में स्वतंत्रता और सर्वसत्तावाद में जो युद्ध हो रहा है उसका रूम के सैनिक-विरोधियों के उन्मूलन से भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। डेविस ने इस ताना-शाही के उन्मूलन की प्रशंसा कर जनतंत्र का बड़ा अहित किया। कत्लेआम का समर्थन करना सर्वसत्तावाद का प्रचार करना है। यदि वह सफल हो गया तो उसमें जनतंत्र को धक्का लगेगा।

डेविस ने हमें यह नहीं बताया कि मास्को के मुकदमों और सैनिक उन्मूलन के सम्बन्ध में केवल दो ही बातें मानी जा सकती हैं— एक यह कि अभियुक्त निर्दोष थे और दूसरे यह कि वे अपराधी थे। अगर पहली बात सच मानी जाय तो यह कहना पड़ेगा कि सैनिक उन्मूलन राजनीतिक हत्याकाण्ड थे, जिनका आयोजन जान-बूझकर प्रतिद्वन्द्वियों और असुविधाओं से छुटकारा पाने के लिए किया गया था। अगर दूसरी बात मानी जाय तो इसका अर्थ यह है कि रूसी सर्वसत्तावाद के किसी पहलू ने, स्टालिन को छोड़कर, रूसी क्रांति की रचना करने वाले अन्य सभी प्रमुख व्यक्तियों को क्रान्ति और देश के प्रति द्रोही बना दिया था। इन दोनों में से एक बात भी रूसी शासन-प्रणाली के लिए प्रशंसनीय नहीं।

ब्रिटिश जनता और चर्चिल का इंग्लैण्ड

हिटलर के रुस पर आक्रमण करने के दो सप्ताह बाद, जुलाई १९४१ में मैं हवाई जहाज से इंग्लैण्ड गया। हवाई जहाज को न्यूयार्क से बरमुदा पहुँचने में पांच घंटे लगे, बरमुदा से होर्टा तक (जो पुर्तगाल एजोर्स में एक द्वीप है) १४ घंटे और फिर वहाँ से लिस्बन तक ७ घंटे ।

समुद्र से ८ हजार फुट की ऊँचाई पर उड़ना उतना ही आरामदेह, मनोरंजक और आसान होता है जितना कि एक आधुनिक मोटर में चढ़ना। मैंने भोजन में शेरवा मास, सलाद, डबलरोटी, मक्खन, आइसक्रीम और काफी ली और व्यायाम के लिए लम्बे बरामदे में टहलने लगा। एजोर्स को देखकर ऐसा मालूम होता था मानो ईश्वर ने चट्टानों को सागर में अललटप्प बिखेर दिया हो। हवाई जहाज नीचे उतरने लगा। दोनों तरफ पहाड़ थे, जिनकी चोटियाँ बादलों में छिपी हुई थी। विमान ने उनमें से होते हुए नीचे की ओर मोता लगाया। कुछ भट्को के बाद वह पानी पर उतरा और फिर धीरे-धीरे बौंध तक गया। 'आइल डि रे' नाम का एक पुराना जहाज, जो रेड क्रॉस द्वारा भेजा हुआ भोजन अनधिकृत फ़ास ले जा रहा था, लगर पर आकर रुका। जब हम होर्टा के घाट पर जाकर लगे तो एक दूसरे जहाज ने अपना स्वस्तिक का चमकदार लाल और काला झंडा ऊपर उठाया।

जब ग्रीनलैण्ड के आसपास हवा का दबाव कम हो जाता है तो वहाँ पश्चिमी अफ्रीका की हवा खिंचकर आती है और उसके कारण एजोर्स के आसपास का पानी हिल उठता है और ऊपर चढ़ने लगता है। पानी चढ़ने के कारण हमें होर्टा में २४ घंटे की देर होगई। वहाँ हम एक होटल में ठहरे, जिसका सचा लन फूलमर नाम का एक अमेरिकन-दम्पति करता था। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। और मैं अपने हवाई जहाज के कप्तान विन्सटन के साथ शतरंज खेल रहा था। उसी समय किसी ने रेडियो खोल दिया। जिसमें से यह आवाज आई—

“हम ५००० फुट की ऊँचाई पर हैं। आपको कितनी दूर कहा तक दिखाई दे रहा है?”

कप्तान विन्सटन ने खेलना बन्द कर दिया और कहा—“लिम्बन मे हवाई जहाज आरहा है।”

“यहाँ से हम १००० फुट ऊँचे तक देख सकते हैं” होटल के मैनेजर ने आने वाले हवाई जहाज के चालक को उत्तर देते हुए बताया।

“मैं अन्दाजे से ही उतर रहा हूँ” चालक की आवाज आई।

“उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है” कप्तान विन्सटन ने कहा।

एक मिनट बाद चालक ने फिर कहा—“३००० फुट पर उतर आया हूँ।”

“बाध के पास लड़के ऊँची उठ रही है उनका ध्यान रखना। यहाँ बड़े जोरों की वर्षा हो रही है” होटल के मैनेजर ने सावधान करते हुए कहा।

“हरे राम” विन्सटन ने कहा और कापते हुए हाथों से एक सिगरेट सुलगाई।

शका से हृदय धड़कने लगा। हम सब चुप बैठे थे और हवाई जहाज की आवाज सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे, किन्तु कुछ सुनाई नहीं दिया।

“इस समय तूम कहा हो” मैनेजर ने पूछा।

“१००० फुट की निचाई पर, बाँध के पास पहुँच रहा हूँ” चालक ने उत्तर दिया।

“मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बन्दरगाह में कोई जहाज तो नहीं है?” उसने पूछा।

“बन्दरगाह के बीचों बीच ‘आइल डि रे’ खड़ा है, उसका ध्यान रखना। जमीन उस जहाज से पश्चिम की ओर है।”

“अब तूम हमें दिखाई देने लगे” चालक ने बताया।

“बहुत अच्छा” विन्सटन बोला। “लेकिन उतरना बड़ा मुश्किल होगा।”

“ऊँची लहरों का ध्यान रखना” मैनेजर ने फिर सावधान किया।

विन्सटन ने वेचैनी दिखाई।

“उतर गये, धीरे-धीरे बाध की ओर जा रहे हैं” चालक ने बताया।

विन्सटन ने चैन की माम ली और सीटी बजाता हुआ वह शतरज की ओर घूमा। कुछ ही देर बाद चालक ने सूचना दी। “घाट पर पहुँच गये।”

होर्ट और लिस्बन के पुर्तगाल छोटे और दुबले दिखाई देते थे। ऐसा मालूम होता था कि जिन लोगों को अपना साम्राज्य वीर-नाविकों से मिला था

उन्हे अब भर-पेट भोजन नहीं मिलता । जहाजी घाट पर खड़े हुए स्त्री-पुरुष मानो हमसे पूछ रहे थे—“जब यूरोप के सब लोग अमेरिका जाना चाहते हैं तो आप लोग यूरोप क्यों आ रहे हैं ?”

दूसरे महासमर के दिनों में पुर्तगाल, स्वीजरलैंड और स्वीडन—विशेष रूप से पुर्तगाल—अन्तर्राष्ट्रीय भदियों के छत्ते बने हुए थे । लिस्बन से बाहर एस्टोरिल में, जहाँ फ़ैशनेबिल लोगो का आना-जाना लगा रहता था, नाजी अफसर और ब्रिटिश कूटनीतिज्ञ खेल-तमाशो में साथ-साथ बैठते थे, यहूदी शरणगत और जेस्टापो के अत्याचारी पास-पास मेजों पर बैठकर खाना खाते थे, जापानी एजेण्ट, अमेरिकन हवावाज, बेल्जियन उमरा, इटैलियन अफसर और तुर्क व्यापारी जुआघर में नम्रता के साथ एक-दूसरे का रुपया लेने थे । जुआ खेलते समय जापानी सबसे ज्यादा धवराते थे, सफेद रूसी सबसे अधिक गम्भीर रहते थे, नाजी-विरोधी जर्मन सबसे अधिक शान्त रहते थे और नाजी सबसे अधिक हुल्लडबाजी करते थे । अमेरिकन थोड़े-से डालरो से ही जुआ खेलते हैं, वह भी मनोरंजन मात्र के लिए और उसके सबध में अपने घर पत्र लिख सकने के लिए । मैंने देखा कि जब कभी मैं छोटे दाव लगाकर खेला तो नहीं हारा और जब कभी मैंने दाव पर ज्यादा रुपये लगाये तो उसमें उत्तेजना तो अधिक हुई किन्तु जितना मैंने खोया उतना खोना मेरे-जैसे एक स्वतंत्र पत्रकार के लिए कल्याणकर नहीं था ।

हॉलैंड का एक निःशस्त्र नागरिक हवाई जहाज हमें लिस्बन से ब्रिस्टल (इंग्लैंड) छः घण्टे में ले गया । वह फ्रांस के नाजी अधिकृत तट के समानान्तर उड़ता हुआ गया । नाजी जानते थे कि इस प्रकार लोग बराबर इंग्लैंड आते-जाते रहते हैं किन्तु जब तक उन्हें किसी विशेष यात्री को रोकने की आवश्यकता नहीं होती थी तब तक वे किसी को छेड़ते नहीं थे । अंग्रेज भी जर्मनी के नागरिक हवाई जहाजों के साथ ऐसा ही करते थे ।

ब्रिस्टल की जर्मनों की बमबारी से बड़ी क्षति पहुँची थी । टूटे-फूटे मकानों का मलवा ऐसे बिखरा पड़ा था जैसे जानवरों को काटने से उनकी आतडियाँ निकल पड़ती हैं । रेलवे स्टेशन की दीवारे गिर पड़ी थी और छत भी टूट गई थी । फिर भी लोग शान्त थे ।

“गस्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई,” जहाँ हम उतरे वहाँ के कार-पोरल ने पूछा ।

“कुरसी पर बैठ जाइये,” सारजण्ट ने कहा । उस समय हम अपने पानपोट की परीक्षा कराने की प्रतीक्षा में थे ।

“क्या आप चाय पीना पसन्द करेंगे ?” एक अफसर ने पूछा । ऐसा मालूम होता था जैसे कोई एक हफ्ते के लिए अपने देहात की रियासत में आ गया हो । सब लोग भद्रता और सहयोग की भावना दिखा रहे थे ।

स्टेशन का दृश्य देख कर मुझे सन् १९१८ का स्मरण हो आया, जब कि मैं इंग्लैण्ड में एक ब्रिटिश सेना में स्वयंसेवक था । सब जगह बर्दियाँ-ही-बर्दियाँ दिखाई देती थी । औरते तक बर्दियों में थी । यह एक नई बात थी जो कि पहले महासमर में नहीं दिखाई दी थी । सिपाही अपने सामान के मोटे थैलो पर बैठे गाड़ियों की प्रतीक्षा कर रहे थे । गाड़ियाँ खचाखच भरी रहती थी ।

प्लेटफार्म के एक कोने में मैंने दो आदमियों को देखा जो स्पष्टतः बाप और बेटे मालूम होते थे । बाप जो लगभग पैंतालीस वर्ष का था, मेजर का बिल्ला पहने हुए था और उसके रिवनो से मालूम होता था कि वह पहले महासमर का एक पुराना सिपाही है । लड़का जो पच्चीस के आसपास था, शाही आकाश-सेना का नीला बिल्ला पहने हुए था । ब्रिटेन में कहीं भी मुझे पहले की तुलना में अधिक म्लानता नहीं दिखाई दी । वे दोनों आदमी उदास नहीं थे । बाप १९१७ का फ्रास का अपना एक अनुभव सुना रहा था । बीच-बीच में लड़का मुसकरा उठता था । वे ही लोग जिन्होंने २५ वर्ष पहले ‘युद्ध का अन्त’ करने के लिए युद्ध किया था और बाद में शान्तिपूर्वक रहने के लिए लड़के और लड़कियाँ पैदा किये थे, आज अपने लड़के और लड़कियों के कन्धे-से-कन्धा मिलाकर एक दूसरे विश्वव्यापी महासमर में कूद रहे थे ।

एक टैक्सी में चढ़कर हम लदन की उन गलियों में से होकर गये जिनसे मैं अच्छी तरह परिचित था । प्रत्येक गली में बम के निशान बने हुए थे । यह एक आधुनिक युद्ध था, एक ऐसा युद्ध जो नागरिकों से भी लडा जाता है, जो बच्चों के पालनों पर प्रहार करता है, जो भोजन करते समय चार व्यक्तियों के एक पूरे परिवार के प्राण हर लेता है और रसोई में तश्त-रियों को चकनाचूर कर देता है ।

लदन में पहुँचने के थोड़ी देर बाद मैं स्टॉर्म जेम्सन से मिला । वह एक प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका है और मेरी पुरानी मित्र है । मैंने उनसे उनके ८८ वर्षीय बूढ़े बाप के बारे में पूछा । “वह ब्रिटनी में है,” जेम्सन ने उत्तर दिया । ब्रिटनी इंग्लैण्ड के पूर्वी तट पर है । यह वही स्थान है जहाँ नाजी हवाई जहाज उत्तरी सागर को पार कर प्रायः अपने बम गिराया करते थे ।

“वह बम से मारे तो नहीं गये ?” मैंने पूछा ।

“नहीं सिर्फ घर की खिड़कियाँ टूटी हैं” जेम्सन ने जवाब दिया ।

“तो तुम उन्हें किसी भीतरी नगर में अधिक सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं पहुँचा देती” मैंने पूछा ।

“क्या कहा आपने ?” वह जोर से बोली । “वह उनका अपना मकान है । उसी में उनका जन्म हुआ था । क्या आप समझते हैं कि मैं अपना मकान सिर्फ हिटलर के बम के डर से छोड़ दूँगी ।”

कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपने मकान छोड़कर भाग जाते थे, किन्तु स्टार्म जेम्सन में मानो इरलैण्ड की आत्मा दृष्टिगत होती थी । सन् १९४३ में उसकी छोटी बहन एक उस बमबारी में मारी गई थी, जो छोटे-छोटे अरक्षित व्यापार-विहीन कस्बों पर दिन-बहाडे की जाती थी । उन कस्बों में भोली जनता के अलावा और कुछ नहीं होता था जिससे बमबारी की सार्थकता सिद्ध की जा सकती ।

“उसका अभाव मुझे सारे जीवन भर अखरेगा । लडाई के बाद मैं उसके बच्चों को ले आऊँगी और उनका पालन-पोषण करूँगी ।” स्टार्म ने मुझ लिखा ।

एक बार एक शाम की पार्टी में एक महिला ने सिगरेटों के घटियापन पर खेद प्रकट किया । एक दूसरी महिला ने अखबारों को दिये जाने वाले खराब किस्म के कागज का उल्लेख किया । “कपडे भी अब पहले से बहुत खराब आने लगे हैं,” एक मेहमान ने कहा ।

“सभी चीजें पहले से खराब हो गई हैं,” एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, “सिर्फ आदमी पहले से अच्छे हैं ।”

ब्रिटेन के निवासी सचमुच बड़े अद्भुत थे । वे यह अनुभव भी नहीं कर रहे थे कि वे बहादुर बन रहे हैं । मेरे ब्रिटिश प्रकाशक जोनेथन केप ने मुझसे कहा—“किया क्या जाय ? बम गिरने पर या तो हम चिल्लाया या पागल हो जाय या आत्म-हत्या कर ले या फिर धीरतापूर्वक चुपचाप शान्त बैठे रहे ।”

अंग्रेज बड़ी मर्यादा के साथ कार्य कर रहे थे । फिर भी जब मैं थके-मादे और शायद भूखे लंदन-निवासियों को पूर्ण अन्धकार में रास्ता टटोलते अपने घर जाने देखता तो मुझे ऐसा लगता कि यह युद्ध केवल अमानुषिक ही नहीं है बल्कि मानवी मर्यादा के ऊपर एक प्रहार भी है । मनुष्यों के रहने का यह तरीका नहीं होता । युद्ध मनुष्य के अच्छे-से अच्छे गुण को तुरे-से-तुरे कार्य के लिए जाग्रत करता है ।

लन्दन में मैं पार्लमेण्ट के मजदूर-सदस्य जार्ज रसेल स्ट्रास के पास हूँ। उनके साथ एक दूसरे मजदूर-सदस्य अन्थुरिन वेवन भी ठहरे हुए थे। साथ में उनकी पत्नी जेन्नो ली भी थी जो कि स्वयं एक मजदूर-नेत्री हैं। स्ट्रास और वेवन 'ट्रिब्यून' नाम का एक वामपंथी मजदूर साप्ताहिक पत्र प्रकाशित करते थे। उसके लेख भी वे ही लिखा करते थे। एक इतवार को सवेरे गीजेण्ट गली से जाते समय मैंने एक आदमी को टहनते और 'ट्रिब्यून' पढ़ते हुए देखा। मैंने उससे पूछा—“इस अखबार के बारे में आपकी क्या राय है?” मेरी उसकी आध घण्टे तक बात हुई। घर लौटकर मैंने मागी बात स्ट्रास और वेवन को सुनाई। उन्हें मेरी इस अमेरिकन साहसिकता पर बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ वर्ष पहले मुझे ऐसा करने में बड़ा सकोच हुआ करता था। लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग बात करना पसन्द करते हैं और अगर आप उन्हें रोककर कुछ पूछें तो वे बुरा नहीं मानते। ऐसा मैं कई देशों में कर चुका हूँ। सबसे ज्यादा आसानी मुझे उस समय पड़ती है जब मैं किसी के साथ एकदम गम्भीरता से बातें करने लग जाता हूँ, जैसा कि 'ट्रिब्यून' पढ़ने वाले आदमी के साथ हुआ। इसके विपरीत जब मुझे भूमिका-स्वरूप—“बड़ी अच्छी सुबह है,” या “ऐसा मालूम होता है, कि पानी बरसेगा,” आदि कहना पड़ता है तो कभी-कभी मेरी जवान बन्द हो जाती है।

जब कभी मैं किसी देश को समझने की चेष्टा करता हूँ तो जिससे भी मिलता हूँ उससे अक्सर एक ही तरह के सवाल करता हूँ और उसके परिणामस्वरूप उस देश की नब्ज टटोल लेता हूँ, एक प्रकार से वहाँ का जन-मत प्राप्त कर लेता हूँ। मैंने दो सौ आदमियों से पूछा—“मान लीजिये, हिटलर आप से शान्ति का प्रस्ताव करे उस समय आप क्या सोचेंगे?” इस प्रश्न के उत्तर में केवल एक व्यक्ति ने कहा कि इस तरह का प्रस्ताव विचारणीय होगा, शेष सभी लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया, किसी ने अधिक जोश और घृणा के साथ और किसी ने कम।

उस समय तक रूम की विजय नहीं हो रही थी। अमेरिका सहानुभूति दिखा रहा था और सहायता भी दे रहा था, परन्तु युद्ध से बहुत दूर था। हिटलर के किसी समय भी आक्रमण करने का भय था, लेकिन जनता ने एक मत होकर आगे बढ़ने का सकल्प कर लिया था। यह बात नहीं थी कि ६० व्यक्ति पक्ष में हो और ४० विपक्ष में। प्रत्येक व्यक्ति ने शत-प्रतिशत दृढ़ता के साथ निश्चय कर लिया था।

“यहाँ के लोग डिगेंगे नहीं” चर्चिल ने मुझसे कहा था। जनता को

जीत का पूरा-पूरा विश्वास था, इसलिए वह दृढ़प्रतिज्ञ थी ।

इंग्लैण्ड में नाजी बमों के शोरागुल के बीच एक सामजस्य दिखाई देता था, सामजस्य, एकता नहीं । एकता तो सर्वसत्तावाद की परिचायिका होती है । सामजस्य जनतन्त्र में होता है । सामजस्य का अर्थ है भिन्न-भिन्न तत्त्वों का सहयोग । एकता इन सब का बलात् आत्मसमर्पण है । जनतन्त्री देश के विजयी उम्मीदवार को एक वोट से भी विजय प्राप्त करने पर सार्वजनिक समर्थन प्राप्त हो जाता है, किन्तु नाजियों की "एकता" के लिए चुनाव में सत्तानवे प्रतिशत बहुमत की आवश्यकता होती है ।

इंग्लैण्ड में रहते हुए मुझे जो बात सबसे आश्चर्य-जनक मालूम हुई, वह था एक जगह देश-भक्तों द्वारा व्यापक रूप से तोड़-फोड़ । बेवन ने, जो बचपन में कोयले की खान में काम कर चुके थे, बताया कि कोयले की खानों के मालिक अपनी बुरी चट्टानों को खोद रहे थे और अच्छी चट्टानों को युद्ध के बाद लाभ कमाने के लिए बचा कर रख रहे थे । इस बात पर आसानी से विश्वास करना सम्भव नहीं था क्योंकि उसका अर्थ था युद्ध के प्रयत्नों को क्षीण बनाना । मैंने सरकारी खान विभाग के प्रधान अधिकारियों से बातचीत की । उन्होंने भी बेवन की बात का समर्थन किया । फिर भी मुझे इस बात का रीकार्ड रखने में हिचकिचाहट हुई । उन्हीं दिनों व्यापारियों के दैनिक पत्र "आर्थिक समाचार" (फाइनेन्शियल न्यूज) ने लिखा—'यदि कोयले की खानों के मालिकों को अतिरिक्त आय-कर के सम्बन्ध में रियायत दी जाय तो वे अपनी सब से अधिक उत्पादक चट्टानों को काम में लाने के लिए अधिक तत्परता दिखायेंगे ।'

खानों के मालिकों द्वारा खराब चट्टानों के काम में लाये जाने का कारण यह था कि वे जानते थे कि लड़ाई के दिनों में सब चीजें, यहाँ तक कि खराब कोयला भी बिक जाता है । दूसरी बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार उनका प्रायः मारा का-सारा लाभ युद्ध का खर्च चलाने के लिए ले लेती थी । तो फिर वे अपना अच्छा कोयला क्यों खत्म करते ? क्यों न वे उसे शान्तिकाल के लिए संचित करके रखते जबकि उसके अच्छे होने के कारण ग्राहक आकर्षित होते और जो लाभ हाता उसे वे अपने लिए बचा सकते । जो लोग ऐसा कर रहे थे शायद उनका कोई लडका हवाई बेड़े में रहा होगा । राष्ट्र के लिए वे अपने बेटे के प्राण न्योछावर कर देने को तैयार थे, लेकिन अपना अच्छा कोयला नहीं ।

मालिकों और मजदूरों, अमीरों और गरीबों, उच्च-वर्ग के भद्र पुरुषों और निम्न-वर्ग के साधारण व्यक्तियों—सभी ने युद्ध में सहायता दी । हवाई रक्षा का काम करने वालों में ऊँच-नीच का भेदभाव जाता रहा । घरेलू-रक्षा दल

मे जहाँ नागरिकों को आक्रमण रोकने का काम मिलाया जाता था वहाँ दफ्तर का चपरासी अपने अफसर के कंधे से-कंधा मिला कर चलता था। राष्ट्र-रक्षा के कार्य में लगे हुए सभी नागरिकों के लिए ब्रिटेन एक मित्रों का राष्ट्र बन गया था। इसीलिए वहाँ सामाजिक तथा मैत्री और सामाजिक के कारण ही इंग्लैंड सुखी था।

फिर भी कोयले के मालिकों ने अपना खराब कोयला ही बँचा और अफसर—अफसर ही बने रहे। युद्ध के कारण समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों में लोगों का सम्पर्क बढ़ गया। श्रेणीगत भेद-भाव टूटने लगे। जब वर्गों ने किन्हीं का भेद भाव नहीं किया तो भला आदमी ही ऐसा क्यों करते?

फिर भी इस बात को छोड़ कर कि ब्रिटिश सरकार ने युद्ध कालीन उत्पादन में हाथ बटाया और भिन्न-भिन्न नियंत्रण स्थापित किये, किन्तु आर्थिक बल उन्हीं लोगों के हाथों में रहा जिनके हाथों में पहला था।

जब लोग सकल के समय समान स्थल पर आ जाते तो जीवन के सुख-भोग के समय वे असमान रहना नापसंद करते हैं। इंग्लैंड में चर्चिल के ढाँचे में ढले हुए आम लोग हमेशा ही रहेंगे। किन्तु कैसे? घर होंगे या गन्दे भोपड़े? काम होगा या आलस्य? जीवन के आरम्भ से अंत तक सुरक्षा? जिस युद्ध ने वर्तमान में सहयोग को प्रोत्साहन दिया उसी ने अतीत के प्रति विरोध उत्पन्न किया।

एक नवयुवक विमान-चालक ने, जो रात्रि के समय युद्ध करने वाले हवाई जहाजों के एक दल का नेता था, मुझे इंग्लिश चैनल की सैर कराने के बाद अपने नए जहाज का भीतरी हिस्सा दिखाया। फ्यूज के तारों के पास पीले रंग में १५ छोटे-छोटे स्वस्तिक बने हुए थे जिसका अर्थ यह था कि उस समय तक चालक जर्मनी के १२ हवाई जहाज नष्ट कर चुका था। उसने अपने जहाज को वैसे ही थपथपाया जैसे कोई प्यार से अपने घोड़े को थपथपाता है। सहसा वह मुझसे पूछ बैठा—“क्या आप समझते हैं कि यह युद्ध समाप्त हो जाने के बाद हम बेकार हो जायेंगे?” वह चिन्तित उतना नहीं था जितना कि किर्कर्टव्य विमूढ़। युद्ध के समय उसने जिस देश की इतनी सेवा की थी, वह क्या शांति-काल में उसके लिए कोई काम नहीं निकाल सकेगा? उसने यह बात स्वीकार की कि उसे मजदूर दल में दिलचस्पी है।

मजदूर, विरोधी, विद्वान् और मध्यम श्रेणी के लोग जब यह देखते हैं कि उनकी अपनी आर्थिक शक्ति तो अत्यंत सीमित है और जिन लोगों के हाथ में आर्थिक अधिकार हैं वे उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो वे सामाजिक

और आर्थिक उन्नति के लिए शासन-संस्था की ओर आशा की दृष्टि से देखते हैं। सच पूछिये तो आजकल उत्तम जीवन के लिए जो आंदोलन चलते हैं उनका मुख्य उद्देश्य शासन-संस्था को प्रभावित करना और रास्ता दिखाना होता है। यही कारण है कि मजदूरों की इच्छा राजनीति में प्रवेश करने की होती है। अपने चोटों के बल पर करोड़ों मजदूर उन लोगों से जिनके हाथ में आर्थिक अधिकार होता है, राजनीतिक शक्ति छीनने की चेष्टा करते हैं।

अतः जिस युद्ध ने इंग्लैण्ड में सामाजिक सामञ्जस्य उत्पन्न किया उसी ने सामाजिक संघर्ष के भी बीज बोये।

जिन दिनों मैं इंग्लैण्ड में था, समाचार पत्रों ने चर्चिल का एक चित्र छापा जिसमें वह बमबारी से अत्यधिक क्षतिग्रस्त नगर प्लाइमाउथ का निरीक्षण करते दिखाये गये थे। वह एक तंग गली के बीच टहलते हुए जा रहे थे और उनके मुँह के एक कोने में उनका अभिन्न सिगार था। उस दिन उनके चेहरे पर अभूतपूर्व मुसकराहट थी। उनके सामने, उनके ठीक पीछे और उनके दोनों तरफ स्त्री-पुरुष और बच्चे भी टहल रहे थे। जनता आप-से-आप अपने हर्ष का प्रदर्शन कर रही थी। ठीक उनके सिर के ऊपर कुछ लोग कीलों पर से उनका स्वागत कर रहे थे। चर्चिल ने अपना हैट उतार कर बेत पर रख लिया था। और उसे ऊपर उठा कर हिला-हिला कर वह लोगों के स्वागत का उत्तर दे रहे थे। यह एक जनतन्त्र का चित्र था। इधर बहुत वर्षों से एक भी तानाशाह इस प्रकार के अज्ञात और अनगिनत नागरिकों के आकस्मिक प्रदर्शन के बीच घिरा हुआ नहीं देखा गया। भय और पत्थर की दीवारें तानाशाहों को जनता से अलग कर देती हैं। चर्चिल को ब्रिटिश जनता का डर नहीं था, ना ब्रिटिश जनता को चर्चिल से डर था। भय तो तानाशाहों के खड़े होने का चहूँतरा है।

फिर भी चर्चिल आम जनता के आदमी नहीं थे। युद्ध से पहले और सन् १९४१ में मेरे ब्रिटेन जाने पर वहाँ के निवासियों ने मुझसे अक्सर कहा कि पहले और दूसरे महासमरों के बीच ब्रिटेन में जो राजनीतिक दुर्बलता दिखाई दी थी उसका कारण यह था कि पहले महासमर में ब्रिटेन के अनगिनत आदमी मारे गये। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आज के नेता कल खाइयों में मारे गये। यह सत्य का एक लघु अंश मात्र है। 'लंदन इकोनोमिस्ट' ने, जो अर्थ सम्बन्धी एक गंभीर साप्ताहिक पत्र है, गोप वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए सन् १९४२ में लिखा—“यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि इस देश में प्रायः सभी प्रकार के नेता उस वर्ग के हैं जिसमें यहाँ की सम्पूर्ण जन-संस्था

का बीसवां भाग भी सम्मिलित नहीं । इससे भी बड़ी बात यह है कि इन नेताओं का चुनाव उनकी योग्यता के आधार पर नहीं होता ।”

‘इकोनोमिस्ट’ ने यह भी लिखा—“अमेरिका में जहाँ ४ करोड़ ८० लाख व्यक्ति रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों का शासन है, जो २० लाख जनसंख्या वाले देशों में पाये जा सकते हैं, सिवा उन विशेष व्यक्तियों के जिन्होंने अपने पथ की बाधा को नष्ट कर डाला है ।” बाधा किस वस्तु की ? वन और सामाजिक सीमायों की ? “देश की प्रतिभा का यह कोई उपयोगी प्रयोग नहीं माना जा सकता”— ‘इकोनोमिस्ट’ ने निष्कर्ष निकाला । ब्रिटेन में जन-शक्ति की जो कमी है वह अशत मनुष्यों की ही करनी का फल है । यह सत्य है कि सन् १८३५ से १९४५ के बीच के युद्ध-समय १० वर्षों में ब्रिटेन की जनशक्ति का लगातार ह्रास होता रहा । किन्तु इससे तो बचे हुए व्यक्तियों की योग्यता को प्रयोग में लाने की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है और यही कारण है कि सामाजिक भेदभाव को हटाने की मांग की जाती है ।

सन् १९१७ में, रूस में, राजसी और धनी शासकों के छोटे से दल और करोड़ों निर्धनों, मस्त मजदूरों तथा किसानों के विशाल समूह में महान् भेदभाव था । किन्तु यह भेदभाव दुर्बल और कंच की तरह सहज ही टूट सकने वाला था । इसी लिए राइफलों, हथगोलों और शब्दों के थोड़े-से प्रहारों ने ही उसे चकनाचूर कर दिया । रूस एक पिछड़ा हुआ देश था, इसलिए उसके अनुकूल ही वहाँ छोटे-बड़े के बीच की दीवार लकड़ी की बनी हुई थी । अन्य देशों में यह बड़ी मजदूरी के साथ ककरीट और इस्पात से बनाई गई है । इंग्लैंड के विशेषाधिकार-प्राप्त लोग खूब जमे हुए होते हैं और वे देश-सेवा, शिक्षा, शासन-योग्यता, व्यापारिक अनुभव और उद्योग, बैंक तथा व्यापार सम्बन्धी साहसिकता के भी अलकाशों से आभूषित होते हैं । इन विशेष गुणों का देश के आर्थिक जीवन पर बड़ा गहरा असर पड़ता है । वे आसानी से टस-से-मस नहीं किये जा सकते । किन्तु दीवार की दूसरी ओर के ४ करोड़ ६० लाख निवासी जिन्हें वाल्डविन और चैम्बरलेन की मतपट्टीकरण सम्बन्धी भूलों ने शासकों का कम आदर करना सिखा दिया है और जिन्हें युद्ध ने अधिक अपनी आदर करना सिखाया है, ऐसे अधिकारियों की मांग करते हैं जिनसे दीवार के इस ओर रहने वाले २० लाख निवासियों ने उन्हें अब तक बचि़त रखा है ।

ब्रिटेन का शासक वर्ग युद्ध करना जानता था, किन्तु वह युद्ध को रोकने में समर्थ नहीं हो सका था । इसलिए सन् १९४१ में ही लोगो ने कहना आरम्भ कर दिया कि शांति-स्थापना का काम अनुदारदलियों को नहीं सौंपना चाहिए ।

सन् १९४१ में इंग्लैंड से लौटने पर मैंने लिखा—“नाज़ियों के साथ युद्ध करने के प्रश्न पर तो सभी अंग्रेज एक मत हैं, किन्तु उनमें से कुछ थोड़े से लोग तो पुराने ब्रिटेन को, जो उन्हें बड़ा अच्छा लगता था—अक्षुण्ण रखने के लिए लड़ रहे हैं और जोष सब एक नए ब्रिटेन के निर्माण के लिए लड़ रहे हैं। सच पूछिये तो ब्रिटेन इस समय दो लड़ाइयों में सलग्न है—एक हिटलर के नये विधान के विरुद्ध और दूसरी नेविल चैम्बरलेन के पुराने विधान के विरुद्ध।” “और चर्चिल के पुराने विधान के विरुद्ध भी” मुझे यह भी लिखना चाहिए था।

इंग्लैंड के वामपक्षी नाटककार जे० बी० प्रीस्टले ने अपनी “आउट ऑफ दी पीपुल” नामक पुस्तक में लिखा—“आपको इस बात का कोई अधिकार नहीं कि पहले तो आप असली ब्रिटेन को युद्ध में रत कर दें और फिर बाद में घोषणा करें कि आप एक बिल्कुल दूसरे और बहुत कम वास्तविक ब्रिटेन की रक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं।” उसके वाद से प्रीस्टले को रेडियो पर बोलने नहीं दिया गया। यहाँ बात हरल्ड लास्की के साथ हुई। लास्की ने मुझे बताया कि उन्होंने जब चर्चिल से प्रतिवध का कारण पूछा तो उत्तर मिला—“चूँकि आप जिस तरह का ब्रिटेन चाहते हैं वह उस ब्रिटेन से बिल्कुल भिन्न है जो मैं चाहता हूँ।” फिर भी लास्की, प्रीस्टले और दूसरे द्रोहियों ने मेना और हवाई बेड़े के शिबिरो में बातचीत की, लेख और पुस्तकें लिखी और जो बातें वे इंग्लैंड के निवासियों से नहीं कह सकते थे वही उन्होंने रेडियो द्वारा उप-निवेशों के निवासियों से कहा। मुझे भी बी० बी० सी० वालों ने लंदन से ब्रिटिश साम्राज्य और उत्तरी अफ्रीका के निवासियों से रेडियो द्वारा बातचीत करने का तो निमंत्रण दिया, किन्तु अपने देशवासियों से बातचीत करने के लिए नहीं।”

युद्ध के कारण ब्रिटेन की कुछ नागरिक स्वतंत्रताएँ कम अवश्य हो गईं, किन्तु अधिक नहीं। इंग्लैंड स्वतंत्र ही रहा। बाथ के निकट मैं ब्रिटिश आकाश-सेना के एक ग्रुप पर जॉन स्ट्रैची से मिला। स्ट्रैची साम्यवाद के समर्थक रह चुके थे। स्टालिन और हिटलर के समझौते के बाद वह भी अन्य साम्यवादियों की भाँति युद्ध के विरोधी हो गये थे। किन्तु सन् १९४० के दसत में नारवे पर आक्रमण होने से उनके विचार बदल गए। उन्होंने अपना नाम हवाई आक्रमण के समय रक्षा करने वाले वाइंगों में लिखाया और जब श्रीमती मिलर बम के नीचे दबकर मर गई तो उन्होंने उनके लिए वक्त्र भी बोदी। इनके बाद वह हवाई बेड़े में शामिल हो गये और रात्रि के समय लड़नेवाले एक हवाई दल के एडजुटेंट नियुक्त कर दिये गये। उनके सोने के स्वाटर्स में एक पुस्तकालय था, कार्ल मार्क्स, जेनिन और ट्राट्स्की की

अनेक पुस्तकों के अलावा समाजवाद सम्बन्धी उनकी स्वरचित पुस्तकें भा उसमें रहती थी। अधिकारी इस बात को जानते थे फिर भी उन्होंने इसकी चिन्ता नहीं की। अंग्रेज सहिष्णु होते हैं। सहिष्णुता सभ्यता की परिचायक होती है। विचार, वर्ण, जाति, धर्म और राजनीति के भेदभाव के महन किये बिना जनतंत्र एक मजाक भर रह जाता है।

राजनीतिक मतभेदों के होते हुए भी अनुदार और मजदूर दलों के सदस्यों ने युद्ध-कार्य में सयुक्त सरकार के साथ पूरा-पूरा सहयोग किया। यदि कभी मजदूर दल के नेताओं को चर्चिल की नीतियां नापसन्द आती थीं तब भी वे मानते थे चर्चिल की ही बात। मंत्रिमंडल की बैठकों में चर्चिल की ही राय सर्वोपरि रहती थी। मंत्रियों ने मुझे बताया कि चर्चिल मंत्रिमंडल के सदस्यों से अधिक बोलते थे और कभी-कभी इतना बोलते थे जितना कि सब सदस्य मिलकर बोल सकते थे। लोगों को उनकी भाषा के प्रवाह में बड़ा आनन्द आता था। उन्होंने देखा, और मैंने भी चर्चिल के साथ अपनी मुलाकात में यही अनुभव किया, कि उनकी साधारण और बिना तयार की हुई बातचीत के वाक्य भी उतने ही प्राजल और शास्त्रीय होते हैं जितने कि उनके अधिक-से-अधिक सावधानी के साथ तैयार किये गये व्याख्यानों के वाक्य।

चर्चिल युद्ध-काल के एक अनिवार्य नेता थे, क्योंकि उनके पौरुष और भाषणों से जनता में स्फूर्ति भर गई। फिर भी उन्होंने उत्पादन और उससे सम्बन्ध रखने वाली दूसरी समस्याओं पर ठीक ध्यान नहीं दिया। उनका मस्तिष्क अर्थ-शास्त्र के अनुकूल था ही नहीं। यह बात उन्होंने स्वयं कई बार स्वीकार की। उन्हें एडमिरलो और जनरलो के साथ बैठकर नक्शों और ग्लोबों पर विचार करना और रसायन-शास्त्रियों से नये विस्फोटकों के सम्बन्ध में बातचीत करना अधिक प्रिय लगता था।

चर्चिल को भविष्य में भी अधिक दिलचस्पी नहीं थी, यह बात उनके शान्ति सम्बन्धी समस्याओं पर दिये गये सार्वजनिक भाषणों से सिद्ध होती है। वह अतीत के साथ जकड़े हुए थे। वह १९ वीं सदी के व्यक्ति थे और उस पर उनकी अनुरक्ति थी। वह साम्राज्य, सम्राट् और जाति से प्रेम करते थे। उन्होंने इँटे तो अवश्य पायी थी किंतु वह इँट पाथने वालों तक पहुँचने वाला सामाजिक पुल नहीं बना सके। वह राजसी आदमी थे। लायड जार्ज को ब्रिटेन के उच्च-वर्गों, जनरलों और लाडों आदि से घृणा थी और वह उनसे लड़े भी। किंतु चर्चिल ने इन्हें अमर बनाना चाहा। यह एक आश्चर्यजनक बात थी,

क्योंकि वह उनसे श्रेष्ठ थे। इसीलिए वे लोग चर्चिल से डरते थे और सन् १९४० के राष्ट्रीय संकट से पहले, उन्होंने चर्चिल को अधिकार के स्थान पर नहीं पहुँचने दिया। फिर भी चर्चिल ने उनके विशेषाधिकारों और वन की रक्षा करने की चेष्टा की। उनकी आत्मीयता उच्च वर्गों से उतनी नहीं थी जितनी कि १९ वीं शताब्दी के इंग्लैंड से, जिसने कि उन्हें उत्पन्न किया था। उनकी दृष्टि में १९वीं शताब्दी एक अनुपम शताब्दी थी, अग्रेजों की अपना शताब्दी वह नैपोलियनीय फ्रांस के पतन के बाद की और कैसरीय जर्मनी के उत्थान के पहले की शताब्दी थी जब कि चारों तरफ ब्रिटेन का बोल-बासा था। इसी शताब्दी में महारानी विक्टोरिया के अतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ब्रिटेन का पुराना प्रताप ही चर्चिल का ईश्वर था। उनकी समझ में उच्च वर्ग के लोग देश की महानता के परिचायक थे। ऐसा ही भारत था और ऐसा ही था १९वीं शताब्दी के इंग्लैंड का पार्लामेण्टरी जनतन्त्र भी।

चर्चिल ने इंग्लैंड की इसी परम्परागत मर्यादा की रक्षा करने के लिए लड़ाई की। जनतन्त्र और निर्धनता के पारस्परिक विरोध के कारण उन्हें कोई पीडा नहीं होती थी। इंग्लैंड का स्वतन्त्रता और भारत की पराधीनता के पारस्परिक विरोध की भी उन्हें चिंता नहीं थी। जब तक मुसोलिनी ब्रिटेन का शत्रु नहीं बना था तब तक उन्होंने उसकी प्रशंसा करने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। जनरल फ्रैंको के लिए भी उनके हृदय में दया का भाव था। चर्चिल नाजी शासन की बर्बरता को घृणा की दृष्टि से देखते थे। हिटलर उसकी समझ में ब्रिटेन के लिए जर्मन-संकट का प्रतीक था। यह वान उन्हें आरम्भ में ही समझ में आ गई थी और वहीरे ब्रिटेन को उन्होंने चेतावनी भी दे दी थी।

चर्चिल को नता बनने में बड़ा आनन्द आता था। ब्रिटेन के नेतृत्व की वागडोर हाथ में आने ही उनके पाव जम गये। उनका समय बड़े मौज के साथ बीता। वह जानते थे कि लोग मुझे सुनना पसंद करते हैं। मैंने देखा है कि जब कभी लोगो ने लोक-सभा में उनके किसी चुटकुले को पसंद किया तो वह तर्प से किलकारी मार उठे। उनमें अभिनेता के अनेक गुण थे और कुछ-कुछ हास्य की वृत्ति भी। उनमें वचपना भी था और कटनीतिज्ञता भी। उन्हें फोटो खिचवाना बड़ा अच्छा लगता था। वह किसी बड़े रंगमंच का केन्द्रीय आकर्षण बनना भी पसन्द करते थे। कई ऐसे अधिकार-पूर्ण इतिहास लिखने के कारण, वह एक निदहस्त इतिहास-निर्माता बन गये थे। निर्विवाद सर्वश्रेष्ठता और सार्वजनिक चाटुकारिता के फलस्वरूप उनकी शारीरिक

शक्ति बढ़ गई थी ।

चर्चिल को अतीत के रोमाम और वर्तमान की साहसिकता की अनुभूति तो अवश्य हुई, किन्तु वह भविष्य-द्रष्टा नहीं थे । वह राजनीतिक क्षेत्र में एक कवि थे— वायरन के रूप में नैपोलियन । उन्हें वचन और कर्म दोनों में प्रेम था । वर्तमान युग में ऐसे गुणों का समन्वय निम्सदेह दुर्लभ है । यही समन्वय हिटलर में भी था ।

चर्चिल में पाशविक आनन्द की प्रवृत्ति और कितनी हा वामनाएँ भी विद्यमान थी । उनमें आतंरिक प्रेरणा भी थी । जनतंत्री देशों के कुछ नेता अपने देश को अपना अनुकरण करने के लिए तैयार कराने से पहले जनता के परिपक्व मन की प्रतीक्षा करते हैं । प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने कितने ही अवसरों पर ऐसा किया । किन्तु चर्चिल साधे सिर के बल क्रोध पड़ते थे और आगा रखते थे कि इंग्लैंड की जनता उनके पीछे पीछे चली आयेगी । उदाहरणार्थ, किसी भी व्यक्ति को जनमत को अपने सँचे में ढालने में इतनी सफलता नहीं मिली जितनी चर्चिल को रूस पर जर्मन-आक्रमण के दिन, जब कि उन्होंने फौरन माइक्रोफोन उठाकर रूसियों को तात्कालिक सहायता का वचन दिया ।

चर्चिल सब चीजों को विजय से हेय समझते थे । सन् १९१८, १९ और २० में उन्होंने बोलशेविक शासन में हस्तक्षेप करने के अभिप्राय से अंग्रेजों का एक सशस्त्र संगठन तैयार किया था । वह सदा बोलशेविज्म के विरोधी रहे । दिसम्बर १९४१ में उन्होंने ह्वाइट हाउस में भोजन करते समय एक पड़ोसी से कहा कि रूस में भयंकर एकाधिकारवाद है । फिर भी इसकी चिन्ता नहीं की गई, विजय के लिए रूस का सहयोग आवश्यक था । लोग जानते थे कि चर्चिल युद्ध में जीतने के लिए तुले बैठे हैं । दृढ़ प्रतिज्ञता का औरो पर भी प्रभाव पड़ा । उसके कारण विरोधियों को अपना विरोध कोमल बनाना पड़ा । बेवन और लास्की जैसे लोग उन पर बार-बार कटाक्ष करते रहे और चर्चिल भी उन पर उलटकर वार करते रहे । फिर भी मजदूर-दल ने उनका मित्रता पूर्वक समर्थन किया और मन्त्रि-मण्डल के कुछ सदस्यों, मसलन विल्किंसन पर उनका जादू चल गया ।

इस दल के बीच मजदूर-दल के मन्त्री शासन करने का कला सीखते रहे । एक दिन मैं गृह-विभाग में हरवर्ट मॉरिसन के दफ्तर में गया और वहाँ से हम दोनों उनकी कार में बैठकर एक गांव में एलेन विल्किंसन के छोटे से घर में छुट्टी मनाने गये । मॉरिसन ने बताया कि उन्हें पुस्तकें पढ़ने के लिए काफी समय मिल जाता था । किन्तु अपना अधिक-से-अधिक समय वह सर

कारी कागजों विशेषतः विदेश विभाग के पत्र-व्यवहार का अध्ययन करने में लगाते थे, ताकि वह शासन का ढग ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकें। इसमें सन्देह नहीं दूसरे मजदूर मन्त्रियों ने भी अपने पद से इसी प्रकार का लाभ उठाया। पाच वर्ष तक एक ऐसी सरकार में कार्य करने के बाद, जिसने ब्रिटेन को विजय की ओर अग्रसर किया, मजदूर-दल पर शासन करने के अयोग्य होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता था। इसके कारण अनुदार दलियों के हाथ से वह बहाना जाता रहा जिसका उन्होंने पहले के चुनावों में काफी सफलता के साथ मजदूर-दल के विरुद्ध प्रयोग किया था। जुलाई १९४५ में मजदूर दल की जो इतनी गानदार विजय हुई उसका यह भी एक कारण था। 'नेशन' के १६ अगस्त १९४१ अंक में मैंने लिखा था—“मजदूर दल को इस बात का-विश्वास है कि वह उन उच्च और मध्यम वर्गों के लोगों को अपना समर्थक बनाता जा रहा है जिन्होंने कभी उसकी देश-भक्ति और योग्यता में विश्वास नहीं किया।

मॉरिसन ५३ वर्ष के थे। उनकी वृद्धि बड़ी तीक्ष्ण है और उनमें वाक्-धातुरा और सहृदयता भी है। लन्दन के निवासी उनसे परिचित हैं। उनके साथ उन्हें 'अरबर्ट' या 'अर्व' कहकर पुकारते हैं। पहले वह डाक ले जाया करते थे और बाद में टेलीफोन आपरेटर रहे। फिर वह लन्दन कौन्टी कौंसिल के नेता बने और १९४० में चर्चिल मंत्र-मण्डल में गृह-मन्त्री नियुक्त हुए।

एक बार गृह-विभाग में मॉरिसन के वेटिंग रूम में बैठे-बैठे मैंने अंगीठी के सगमरमर के कानिंस पर एक लाल फ्रेम रखा हुआ देखा। वह लगभग पाच इंच चौड़ा और ९ इंच लम्बा था और उसके भीतर सफेद कागज पर मोटे मोटे लाल अक्षरों में 'मृत्यु-दण्ड' लिखा हुआ था। उसी के नीचे कुछ नाम, तारीख आदि अंकित थे। मैंने सोचा कि उसे पास जाकर देखना मेरे लिए ठीक नहीं। किन्तु मैं मॉरिसन के दफ्तर में गया तो उन्होंने अपनी सेक्रेटरी कुमारी मैकडोनेल्ड से कहा—“इतको मृत्यु-दण्ड दिखा दो।” कुमारी मैकडोनेल्ड ने मुझे १२ नामों की एक सूची दिखाई। प्रत्येक नाम के आगे जन्म, दण्ड देने की तारीख, अपील की तारीख और अदालत का नाम भी लिखा हुआ था। पहले दो नाम लाल स्याही से काट दिये गये थे और उनके सामने अखीरी खाने में लिखा हुआ था—“फासी दे दी गई।” मॉरिसन ने कहा—“शुरू-शुरू में जब मेरे मन में यह भावना उठा करती थी कि किसी मनुष्य के जीवन और मरण के बीच मेरे हस्ताक्षरों की ही रुकावट है तो मैंने अपने हस्ताक्षर करने में बड़ी कठिनाई पड़ती थी। किन्तु बाद में मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि कुछ लोगों को मारना, विशेषतः युद्ध-काल में, सरकार के लिए

अनिवार्य होता है और अन्तिम आदेश पर हस्ताक्षर करने में मैं जितनी ही देर करूंगा उतनी ही रातें मैं जागकर बिताऊंगा।”

“केवल हस्ताक्षर ? अपना पूरा नाम भी नहीं लिखना पड़ता ?” मैंने पूछा ।

“गृह-विभाग की परम्परा के अनुसार केवल हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। पूरा नाम लिखने की आवश्यकता नहीं।” मॉरिसन ने उत्तर दिया। सम्राट् द्वारा क्षमा की याचना अस्वीकृत हो जाने पर भी फाँसी देने वाले को मॉरिसन के हस्ताक्षर के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

मॉरिसन एक योद्धा है। वह केवल अपनी बाईं आँख से देखते हैं लेकिन देखते बहुत हैं। जिस निर्धनता के बीच उनका जन्म हुआ था उससे उन्हें घृणा है। वह सरल जीवन बिताते हैं और बनते नहीं। उनके मित्रों का कहना है कि यदि उनमें और अरनेस्ट बेविन में चलती न होती तो वही मजदूर दल के नेता होते। चूँकि ऐसी स्थिति में इन दोनों में से एक भी नेतृत्व नहीं ले सका था, क्लेमेंट एटली दल के नेता बने।

अरनेस्ट बेविन एक लड़ाकू प्रकृति के व्यक्ति हैं। उनका शरीर बलिष्ठ है। वह कठोर और हठी हैं और अमीर-उमराओं की तुलना में खुलम-खुल्ला मजदूरों को ज्यादा अच्छा समझते हैं। चर्चिल के मंत्रि-मण्डल में वह उत्पादन के संयोजक थे और यह बात उनके शत्रु भी मानते हैं कि उन्होंने अपना काम बड़ी योग्यता के साथ किया। मंत्रि-मण्डल में सम्मिलित होने से पहले वह इंग्लैंड के सबसे बड़े मजदूर-संगठन यातायात कर्मचारी संघ (ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन) के नेता थे और उसे उन्होंने अपने फैलाव पजे में दबा रखा था। उनके साथ मेरी जो मुलाकात हुई वह मेरी सबसे असफल मुलाकात थी। मैंने शायद युद्ध से पहले की ब्रिटिश विदेश-नीति की कुछ निंदा करके उनकी गलत रणनीति दी थी। वह देश-भक्त थे और देश की निन्दा सहन नहीं कर सकते थे। मैंने एक घंटे तक इस बात की चेष्टा की कि लड़ने के बजाय वह मुझसे सीधे मुँह बाते करें, किंतु वाद में निराश होकर मैंने यह प्रयत्न छोड़ दिया।

मजदूर-संघों और मजदूर-दल की भिन्न-भिन्न सस्थाओं के कम्युनिस्टों ने अपनी फूट और खिजलाहट पैदा करने वाली चालबाज़ियों से मॉरिसन बेविन और व्यापार बोर्ड के सभापति ह्यू डाल्टन को भो, जिन्हें मैं उनकी विदेशी मामलों में दिलचस्पी के कारण कई वर्ष से जानता था, कम्युनिस्टों का कट्टर विरोधी बना दिया है। किंतु ब्रिटिश मजदूर-दल के नेताओं और दूसरों

कार्यकर्ताओं का साम्यवाद का विरोध मुख्यतः उनके स्वतंत्रता प्रेम के कारण कम हो जाता है। कितने ही मजदूर दली ऐसे हैं जिनका मार्क्स के सिद्धांतों से विरोध है किंतु फिर भी वे समाजवाद में विश्वास करते हैं। वे अपने देश के कुछ प्रधान उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीय-करण चाहते हैं और शासन-संस्था का प्रयोग निर्धन और अरक्षितों के त्राण के लिए करना चाहते हैं। उनके "समाजवाद" को हम दूसरे शब्दों में "मानवीय कल्याण" कह सकते हैं। उनके लिए समाजवाद कोई सिद्धान्त नहीं बल्कि मनुष्य जाति की उन्नति का साधन-मात्र है।

मजदूर-दल वाले समाजवादी जनतंत्री हैं। वे समाजवादी होते हुए भी जनतंत्र में विश्वास करते हैं और इसीलिए उन कम्युनिस्टों से भिन्न हैं जो समाजवादी तो हैं किंतु जनतंत्र में न तो विश्वास करते हैं न उसका अनुकरण ही करते। यही कारण है कि कम्युनिस्ट समाजवादी जनतंत्रियों से घृणा करते हैं और जितना विरोध कम्युनिस्टों और मजदूर-दलीयों में आपस में होता है उतना उनका पूँजीवादियों से भी नहीं होता।

यह बात नहीं कि कम्युनिस्ट अत्यधिक वाम-पक्षी थे। बेवन का दल कम्युनिस्टों को अपने से अधिक दक्षिणपक्षी मानता था। बेवन, रसेल, स्ट्रास और उनके मित्रों को चर्चिल से अनुरक्त नहीं थी। किन्तु कम्युनिस्टों का नारा था—“चर्चिल का अबाधित रूप से समर्थन करो।” लंदन में सूचना विभाग के बाहर मैंने एक खुली सभा में ब्रिटेन के प्रधान कम्युनिस्ट हैरी पोलिट को एक ऐसे झंडे के नीचे खड़े होकर बोलते देखा जिस पर “सरकार को मजबूत बनाओ” लिखा हुआ था। कितने ही उप-चुनावों में कम्युनिस्टों ने मजदूर उम्मीदवारों के विरोध में अनुदारदलियों का समर्थन किया।

ब्रिटिश मजदूर-दल के बुद्धिमान् और प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके वामपक्षी दल में हैं और प्रभाव और शक्ति रखने वाले व्यक्ति दक्षिणपक्षी दल में। वलेमेन्ट एटली मजदूर-दल के “निर्जीव मध्य” माने जा सकते हैं। मजदूर-दल के अधिकांश सदस्य तो उनके दाहिने पक्ष में हैं किन्तु जो लोग उनकी वाई और हैं वे उनके नीचे आग लगा सकते हैं। मैंने एटली को कई बार पार्लमैण्ट में अपने दफ्तर में और लोक-सभा के भोजन-भवन में बैठे हुए देखा था। (एटली को विरोधी दल के नेता होने के कारण सरकार की ओर से एक दफ्तर मिला हुआ था और वेतन भी मिलता था।) गृह-युद्ध के समय हम दोनों स्पेन में थे। सन १९४१ में मैं उनसे नम्बर ११ डाउनिंग स्ट्रीट में मिला। यह जगह चर्चिल के सरकारी निवास-स्थान (१० डाउनिंग स्ट्रीट) के

विलकुल पड़ोस में थी। एटली उन दिनों डिप्टी प्रधान मंत्री थे और प्रधान मंत्री चर्चिल प्रेजिडेंट रुजवेल्ट में मिलने के लिए अन्ध महामागर की एक खाड़ी में गये थे, जहाँ दोनों ने 'आगस्टो' नामक क्रूजर में बैठकर एटलांटिक अधिकारपत्र तैयार किया था। यह नान १४ अगस्त की है। उस दिन सवेरे समाचार पत्रों और रेडियो ने रहस्यपूर्ण ढंग में और बड़ी ही गम्भीरता के साथ घोषणा की थी कि दोपहर बाद एटली एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। उस दिन मैंने रिफार्म क्लब में एक अंग्रेज मित्र के साथ भोजन किया। अनुमान लगाये जा रहे थे कि एटली क्या कहेंगे। कुछ लोगों को आशा थी कि अमेरिका युद्ध में प्रवेश करेगा। अधिकांश लोगों का खयाल था कि रुजवेल्ट और चर्चिल अपने युद्ध-लक्ष्यों की घोषणा करेंगे। भोजन के बाद, एक दुबले-पतले बूढ़े आदमी ने गुशलखाने में कहा—“लोग कहते हैं कि वे यह बताने जा रहे हैं कि हम किसलिए लड़ रहे हैं। यह बात तो हम स्वयं जानते हैं। हम हिटलर को हराना चाहते हैं।” १५ आदमियों का एक दल विलियर्ड के कमरे में रेडियो पर कान लगाये बैठा था। एटली साधारण उत्तेजना-विहीन स्वर में बोले। ब्रिटिश जनता को चर्चिल के प्रतिभाशाली रेडियो-भाषण सुनने की आदत पड़ गई थी। एटली ने एटलांटिक अधिकारपत्र की आठो बातें पढ़ कर सुना दी। उनके बोलना बन्द करते ही लोग उठकर जाने लगे। किसी ने ताला नहीं बजाई, किसी ने आलोचना नहीं की। कोई भी प्रभावित दिखाई नहीं दिया, सभी निराश-से हो गये। लोगों को आशा थी कि अमेरिका ब्रिटेन के कन्धे-से-कन्धा मिलाने के लिए युद्धक्षेत्र में उतर आयगा।

क्लब से मैं ११ उनिंग स्ट्रीट एटली के दफ्तर में गया। वह मेरी और फुर्ती के साथ हिलते हुए आये। मैंने उनसे कहा कि आपका वक्तव्य रेडियो पर विलकुल साफ-साफ सुनाई दिया। इस पर वह हर्षपूर्वक मुसकराये। इस बार वह न तो अपनी चुरट पी रहे थे, न 'अच्छा', 'ठीक' आदि कहकर उदासीनता ही दिखा रहे थे। वह बातचात और टीका-टिप्पणी के लिए इच्छुक मालूम होते थे। हमने ब्रिटेन की गृह और विदेश-नीति के प्रति की जाने वाली अमेरिकन आलोचनाओं के सम्बन्ध में बातचीत की।

एटली जमकर बहस करते हैं। यदि उन्हें कोई बात कहनी होती है तो वह उसपर दृढ़तापूर्वक जमे रहते हैं। दूसरे ऊब उठते हैं, किंतु वह अपने आडम्बरहीन ढंग से बहस करते ही रहते हैं। उनके सम्बन्ध में एलेन विल्किंसन ने कहा है—“मैं उन्हें मजदूर-दल की एक तूफानी बैठक में देख चुका हूँ। वहाँ बड़े-बड़े भावुक वक्ता जोशीले भाषण दे रहे थे। सारे वाता-

वरण में बिजली-सी दौड़ जाती थी, सकट निकट दिखाई देता था और पार्टी खतरे में होती थी। इस पर एटली धीरे से उठते और अपने शान्त तर्कशील स्वर में एक भावुकताशून्य सार्थक भाषण करते... "मैंने देखा है कि ऐसे भाषण के बाद २०० क्रुद्ध व्यक्ति कमरे से बाहर निकल गये और कुछ समय में नहीं आया कि आखिर भगडा हो किस बात पर रहा था।"

एटली में चमत्कार लाना कठिन है। उनके मजदूर दली अनुयायी इस बात की चिन्ता नहीं करते, बल्कि चमत्कार हीन होने के कारण उनके ऊपर और भी अधिक विश्वास करते हैं। ब्रिटेन के मजदूर वर्ग को इस बात का भय है कि उपाधियों, धन और उपाधिवारियों के मिलन-निमग्न ऐसी सूक्ष्म रिश्ते हैं जिनमें उनके नेता ठगे जा सकते हैं। एटली को वे इन सब बातों से बरी समझते हैं। उन्हें वे रैमजे मैकडोनेल्ड से, मजदूर-दली प्रधानमंत्री बनने के बाद १९३१ में अनुदार दल में शामिल हो गये थे, भिन्न समझते हैं।

हैरल्ड लास्की ने, जो ११ डाउनिंग स्ट्रीट में एटली के सलाहकार का काम करते थे, मुझसे यह बात कही—"एक बार मैं ह्वाइट हाउस में रूजवेल्ट से बातें कर रहा था। रूजवेल्ट ने मुझसे पूछा कि क्या आप हमारे लन्दन-स्थित राजदूत विन्घम को पसन्द करते हैं? मैंने उत्तर दिया कि विन्घम से कभी मुलाकात नहीं हुई। इस पर प्रेज़िडेंट रूजवेल्ट को आश्चर्य हुआ। मैंने उन्हें बताया कि विन्घम मजदूर दल के लोगों से ज्यादा नहीं मिलते-जुलते। इंग्लैंड लौटने पर कुछ दिनों बाद मैं अमेरिकन राजदूतालय में भोजन करने के लिए निमन्त्रित किया गया। वहाँ एटली भी थे। वह विन्घम की दाहिनी तरफ बैठे थे। बातचीत धीरे-धीरे चलती रही। विन्घम ने एटली से पूछा कि क्या इधर आपने कोई शिकार किया है? एटली ने उत्तर दिया कि अखीरी शिकार मैंने १९१७ में किया था। इस पर विन्घम ने उत्सुकता पूर्वक पूछा—"शिकार में आपने क्या मारा? 'जर्मनो को', एटली ने धीरे से उत्तर दिया।

एटली द्वारा रेडियो पर एटलांटिक अधिकारपत्र की घोषणा किये जाने के कई दिन बाद मैंने सूचना-मंत्री ब्रैण्डन ब्रेकन से कहा—"क्या आप इस बात से सहमत हैं कि यदि चर्चिल को अपनी ही इच्छा से काम करना होता तो वह एटलांटिक अधिकारपत्र को कभी प्रयोजनीय नहीं समझते? उन पर युद्ध सम्बन्धी उद्देश्यों की घोषणा करने के लिए जनता की ओर से कोई दबाव नहीं था। अतः उन घोषणापत्र की बात निश्चय ही रूजवेल्ट की ओर से आरम्भ की गई होगी, ब्रेकन मुझसे सहमत थे। चर्चिल को ब्रिटिश जनता की नैतिकता उत्तेजित करने के लिए अधिकारपत्र की आवश्यकता नहीं थी किन्तु रूजवेल्ट

को इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई ।

एटलांटिक अधिकारपत्र की दुर्बलता उसकी आधारभूत कल्पना में ही है । उसकी कल्पना शान्ति की स्थापना के लिए किसी बुनियादी सिद्धान्त के रूप में नहीं की गई थी, बल्कि अमेरिका को मनोवैज्ञानिक रूप से युद्ध के लिए तैयार करने के साधन के रूप में । वह शान्ति के लिए प्रचार मात्र था । जब शान्ति-निर्माण का कार्य वस्तुतः आरम्भ हुआ तो शुरू-शुरू में उस अधिकारपत्र की उपेक्षा या अवज्ञा की गई और बाद में वह विलकुल भुला दिया गया ।

ब्रिटेन के विदेश-मन्त्री ऐन्थनी ईडेन का युद्धोत्तर समझौतों और सामाजिक प्रश्नों से चर्चिल की अपेक्षा अधिक सम्बन्ध था । किन्तु यदि उन्हें अमेरिका की दिलचस्पी का पता न लग गया होता तो मन् १९४१ में यह भी शान्ति-समझौते की इतनी अधिक बातें न कर सके होते जितनी कि उन्होंने कीं । ईडेन जानते थे कि अमेरिका के अभी युद्ध में प्रवेश न करने का एक कारण यह था कि ब्रिटेन अभी पिछली ही लड़ाई लड़ रहा था । जो लोग यह समझते थे कि सन् १९१६ की शान्ति निरर्थक सिद्ध हो गई है वे किसी दूसरे युद्ध में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे और आगामी शान्ति के सम्बन्ध में कुछ आश्वासन चाहते थे ।

ईडेन योग्य और मिलनसार व्यक्ति है । उनकी मिलनसारी का परिचय उनके आगे के ६ बड़े-बड़े दावों से मिलता है । चर्चिल के बाद इंग्लैंड में वही सबसे अधिक लोकप्रिय राजनीतिज्ञ थे वेही और चर्चिल के सम्भावित उत्तराधिकारी समझे जाते थे । (उस समय तक किसी ने मजदूर-दल के विजयी होने की कल्पना भी नहीं की थी) (ईडेन का जन्म १२ जून १९९७ को हुआ था) वह चर्चिल से बाद की पीढ़ी के थे । उनका यह सिद्धांत कि सामाजिक सुरक्षा के बिना शान्ति नहीं मिल सकती, २० वीं सदी का सिद्धान्त है ।

ऐन्थनी ईडेन के बड़े भाई जॉन ईडेन प्रथम महासमर के पहले वर्ष में ही युद्ध-मोर्चे पर मारे गये थे । दो साल बाद उनके दूसरे भाई ब्रिटिश जलसेना में काम आये थे । स्वयं ईडेन उस युद्ध में लड़े थे । इन घटनाओं और सेनाओं ने उन्हें नूतन विचार-धारा से सम्बद्ध कर दिया था । उनके बाबा बगाल के गवर्नर थे और उनकी मा का जन्म भारत में हुआ था । उनका परिवार, ख्यातिप्राप्त, सम्पत्तिशाली और अनेक उपाधियों से विभूषित था । जिसकी एक शाखा मेरीलेड और उत्तरी कैरोलीना के उपनिवेश में थी । इन बातों के कारण ईडेन अनुदार दल से सम्बद्ध थे ।

अनुदार दल वाले ईडेन को सम्भवतः उनके अनेक “विचित्र” सामा-

जिक विचारों के कारण, दुर्बल समझते थे। मजदूर दल वाले भी उन्हें ऐसा ही समझते थे, क्योंकि वह अनुदार विचार के थे, यद्यपि उन्हें राजनीति का और अच्छा ज्ञान होना चाहिए था।

ब्रिटेन के किसी अनुदारदली नवयुवक के माने यह नहीं है कि वह अन्य प्रौढ अनुदारदलियों की तुलना में कम अनुदार है। सच पूछिये तो अनुदार पथ के दुर्ग पर २०वीं सदी के निरन्तर प्रहारों के कारण उसके रक्षकों में को दुर्ग की दीवारों को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने की प्रेरणा होती है। वे गड़्हा और भी गहरा कर लेते हैं जिससे कि उनके पैर आसानी से न उखड़ सकें। ब्रैन्डेन ब्रैकन, जो कि सूचना विभाग के मन्त्री थे, युवक अनुदारदलियों में सबसे अधिक सैनिक प्रवृत्ति के थे। वह धनी, भावुक और तीक्ष्ण बुद्धि के थे। उन्हें मैं लडाई के पहले से ही जानता था। युद्ध आरम्भ हो जाने पर सन् १९३९ में जब मैं पहली बार ब्रिटेन गया, तो उन्होंने मुझे चर्चिल से मिलाने में सुविधा प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने कितने ही दूसरे अफसरों से भी मुलाकात कराने में सहायता दी। १८ सितम्बर को उन्होंने मुझे सूचना विभाग के नये और आधुनिक भवन में भोजन के अपने प्राइवेट कमरे में भोजन करने के लिए बुलाया।

मेरे अलावा वहाँ तीन और व्यक्ति थे—ब्रैकन, उपनिवेशों के मन्त्री लार्ड मोइन और डोमीनियन सेक्रेटरी वाइकाउन्ट क्रेनवोर्न। तीनों के तीनों अनुदारदली थे। हम डेढ़ बजे इकट्ठे हुए थे और मैं वहाँ से चार बजे वापस आया। ब्रैकन ने मुझे बताया कि मोइन, जो कि एक शराब बनाने वाले परिवार के थे, युद्ध से पहले ही अवकाश ग्रहण कर चुके थे और अब अपनी रचि के अनुकूल कितने ही सांस्कृतिक कार्यों में लगे हुए थे, जैसे औषधि, पूर्व ऐतिहासिक पशु आदि के अध्ययन में। (वाद में फिलिस्तीन के दो आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी।) क्रेनवोर्न के पिता सेलिसवेरी के अमीर थे और उनका परिवार पुराना प्रभावशाली सेसिल परिवार था।

वातचीत के दौरान मैं किसी ने म्यूनिख के आत्म-समर्पण की चर्चा छेड़ी। ब्रैकन ने कहा—“म्यूनिख की सधि हमारे लिए सर्वनाश सिद्ध हुई। चेकोस्लोव्हेकिया को बचाने के लिए हमें लड़ना चाहिए था।”

“हमारे पास विमानबेधी तोपें नहीं थीं” मोइन ने विरोध करते हुए कहा।

‘वाटर!’ अगर तुम यह जानते कि सितम्बर १९३८ और सितम्बर १९३९ के बीच हमारे यहां हवाई जहाजों और बन्दूकों के उत्पादन की गति

कितनी दयनीय थी तो तुम्हे पता चल जाता कि युद्ध में प्रवेश करने से पहले कभी कोई राष्ट्र युद्ध की तैयारी नहीं करता” ब्रैकेन ने उत्तर दिया।

मैंने कहा कि म्यूनिख के सफ्ट के समय रूस पश्चिमी देशों की ओर में लड़ता। ब्रैकेन मुझसे सहमत थे, उन्होंने कहा—“पेरिस की जीतने में दूणों ने—जर्मनों को वह सदा हूण ही कहा करते थे—चेक-टैको का प्रयोग किया और चेकोस्लोवेकिया के स्कोडा कारखाने के बराबर जर्मनी में कोई दूसरा कारखाना नहीं है।”

“फिर भी”, चश्माधारी अध्ययनशील और खोखले मस्तिष्क वाले क्रैनबोर्न ने कहा, “रूस से सलाह लिये बिना पोलैण्ड का सहायता देने का वचन देना मूर्खता का काम था।”

मैंने कहा कि “वह समस्या हल नहीं हो सकती थी; पोलैण्ड की कोई भी सरकार रूसी सेना को अपने देश में प्रवेश नहीं करने देती।”

“मैं जानता हूँ कि स्पेन के मामले में तुम्हाग मुझसे मतभेद है” ब्रैकेन ने क्रैनबोर्न से कहा। “मैं समझता हूँ कि धार्मिक प्रश्नों के कारण हम वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे। किंतु जब मितम्बर १९३० में नॉयन में ब्रिटिश और फ़ामीसी जल-सेना ने भूमध्यसागर में गश्त लगाने और राज्यानुयायियों के पास शस्त्र ले जाने वाले जहाजों का इटैलियन पनडुब्बियों द्वारा डुबाया जाना रोकने का निश्चय किया तो उन्होंने इस कार्य पर ध्यान के साथ विचार किया।

“चैम्बरलेन की तरह यह कहना कि इंग्लैण्ड जैसी जल-सेना वाला राष्ट्र अपने जहाजों की रक्षा नहीं कर सकता, निस्संदेह एक मूर्खता की बात थी।” क्रैनबोर्न ने बीच में टोकते हुए कहा “हमें मत्तोलिनी और फ़ैको से कह देना चाहिए था कि हम न केवल अपने जहाजों की रक्षा करेंगे बल्कि उन पर आक्रमण करने वाले जहाजों को डुबा भी देंगे, चाहे उसका अर्थ युद्ध ही क्यों न समझा जाय।”

“हमें इटैलियनों को ह्वा देश में ही रोक देना चाहिए था, तो फिर स्पेन की घटना घटती ही नहीं”, ब्रैकेन ने कहा।

“इस बात में मैं तुमसे सहमत हूँ”, क्रैनबोर्न बोले।

मोइन इससे सहमत नहीं थे, वह सदा से ही तुष्टीकरण के पक्षपाती थे। उन लोगों ने मुझसे स्टालिन के बारे में पूछा। मैंने बताया कि स्टालिन निर्दय और अवसरवादी है किन्तु है, एक महान् पुरुष।

“हैरी हॉपकिंस की भी यही रिपोर्ट है”, ब्रैकेन ने कहा।

“क्या स्टालिन प्रभावशाली है”, क्रैनबोर्न ने पूछा।

“नही, देखने में प्रभावशाली नहीं है”, मैंने उत्तर दिया।

मोइन ने मुझसे रूस की त्रासकारी घटनाओं की बात पूछी। मैंने वहाँ की गुप्त पुलिस की कुछ बातें बताईं।

“बुटेनी और वारोशिलाव जैसे जनरलों के बारे में आपका क्या खयाल है ?” ब्रैकेन ने पूछा। “उन्होंने तो अपने काम में बड़ी अयोग्यता दिखाई है।”

“वे राजनैतिक जनरल हैं,” मैंने कहा। सेना-विभाग के दफ्तर का काम ऐसे जनरलों द्वारा होता है जिनके बारे में रूस से बाहर के देशों को कुछ पता नहीं।”

“क्या आप समझते हैं कि टुखाचेवस्की ने सचमुच नाजियों के साथ षड्यन्त्र रचने का अपराध किया था ?” ब्रैकेन ने पूछा।

“मुझे इस पर विश्वास नहीं, क्योंकि मुझे इसका कोई प्रमाण नहीं मिला”, मैंने उत्तर दिया “वहाँ के सिपाही बहादुरी के साथ लड़ते रहे हैं। रूसी सिपाही मदा ही बहादुरी से लड़े हैं, किंतु सेना-विभाग के दफ्तर का काम निम्नकोटि का मालूम पड़ता है।”

“लेनिनग्राड में उनका वानलीव से हमेशा मतभेद रहता है और मैं समझता हूँ कि सैनिक दफ्तर में उससे अच्छा काम करने वाला और कोई नहीं है।”

हमने इस बात पर विचार किया कि जाड़े के दिनों में रूस में जर्मनों के लड़ने की संभावना है या नहीं। मैंने यह मत प्रगट किया कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मौसम या प्रादेशिक कठिनाइयों के कारण रूस में जाड़ों में लड़ाई नहीं हो सकती। हमने तेल, वोल्गा के रक्षा-प्रवध और ऐसे ही ऐसे दूसरे विषयों पर भी विचार किया। मैंने कहा “मैं समझता हूँ कि हिटलर का रूस पर आक्रमण करने का उद्देश्य यह था कि इंग्लैण्ड सधि की याचना करे। वह जानता है कि ब्रिटेन और अमेरिका को व्यापक रूप से युद्ध-सामग्री का उत्पादन आरम्भ करने में अभी एक साल लगेगा। इस एक साल में वह रूस को वृचल डालने और आपके सामने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देने की प्रार्थना रखता है कि आप जीत न सकें और उससे सधि के लिए बातचीत करें।”

“यह बात ठीक है”, ब्रैकेन ने कहा। “हिटलर का समय निर्धारण बिल्कुल ठीक था।”

तीन दजे जर्मनों और मोइन चले गये। ब्रैकेन उनके साथ लिपट तक गये और मुझे रुकने का कह गये। हमने एक घंटे और बातचीत की।

लिपट से लौटकर ब्रैकेन ने मुझसे कहा कि ब्रिटिश सरकार को इस बात की निरन्तर बिता लगी रहती है कि स्टालिन हिटलर से अलग सविन कर ले। ऐसी सभावना पर सारे इंग्लैण्ड में चर्चा चल रही थी। ब्रैकेन ने मुझसे कहा—“युद्ध बंडमिटन के खेल की तरह है, जिसमें चिड़िया कभी डधर और कभी उधर रहती है। पहले पूर्व में पोलैंड में युद्ध हुआ, बाद में पश्चिम में नीदरलैण्ड और फ्रांस में। अब फिर पूर्व में रूस में युद्ध हो रहा है। क्या इसके पश्चात् फिर पश्चिम में होगा ?”

ब्रैकेन सोडा और हिस्की पीने लगे और मुझसे बोले कि रूस को युद्ध में रत रखने के लिए ब्रिटेन को क्या करना चाहिए ? मैंने उत्तर दिया—“रूस को शस्त्र देते रहिए, इस बात की चेष्टा कीजिए कि तुर्की रूस के विरुद्ध जर्मनी के साथ न मिल जाय, स्पेन को नाज़ियो से बचाये रखिए और रूस को इस बात का विश्वास दिला दीजिए कि आप हिटलर का मनागें-बहलायेंगे नहीं। मुझे विश्वास है कि रूस यह सोचता है कि आप चाहते हैं कि रूस और जर्मनी एक दूसरे को मार खाय।”

“लेकिन अब हम कदापि तुष्टीकरण का चेष्टा नहीं करेंगे, हमने बहुत कुछ सीख लिया है,” ब्रैकेन ने कहा।

हमने यूरोप में दूसरा मोर्चा खोलने के प्रश्न पर भी विचार किया। इसके विरुद्ध जितने भी तर्क दिये जा सकते थे, ब्रैकेन ने दिये। ये ही तर्क मैं कौंसिल के लार्ड प्रेजिडेंट सर लार्ड एन्डरसन और मजदूर-मंत्रियों से भी सुन चुका था। ये तर्क विशुद्ध सैनिक तर्क थे। अकेले ब्रिटेन के पास इतने आदमी और अस्त्र-शस्त्र नहीं थे कि वह जर्मनी के अधिकांश सैनिकों के रूसियों के साथ भिड़े रहने पर भी जर्मन-सेना का सामना कर सकता।

“सब कुछ होते हुए भी रूस के साथ हमारे सम्बन्ध पहले से अच्छे होते जा रहे हैं,” ब्रैकेन ने कहा। “शुरू-शुरू में हमारी विलकुल नहीं बनी। क्रिप्स उनके लिए अधिक वाम-पक्षी थे, वे डेवनशायर के ड्यूक या उनके ही जैसे किसी और व्यक्ति को ज्यादा पसन्द करते। किन्तु अब स्टालिन और क्रिप्स की खूब नन रही।” पोलाटाव के सम्बन्ध उतने अच्छे नहीं हैं, किन्तु मोलोटोव व्यक्ति

क्रिप्स के

दन-स्थित

हैनीफैव-

चर्चा की। “आह।

रुजवे

छे मि

ब्रैकेन ने कहा। “वे दो

वश्वा

की

करते

ब्रैकेन ने यह भी बताया कि मैं ब्रिटिश व्याख्यानदाताओं को अमेरिका जाने से रोक रहा हूँ। “हम अमेरिका के लिए युद्ध के जितने निकट आने की आशा कर सकते हैं, वह उतना ही निकट आगया है,” ब्रैकेन ने कहा; “किंतु हमें उससे सैनिकों की आशा नहीं।”

“इसी भरोसे पर तो हिटलर भी कूदता है,” मैंने कहा। “एक ओर तो वह ब्रिटेन से सधि का प्रस्ताव करेगा और दूसरी ओर अमेरिका से कहेगा कि जब तक अमेरिका अपने ५० लाख आदमी लड़ाई में नहीं भोकेगा तब तक ब्रिटेन नहीं जीत सकेगा।”

“यह तो अमेरिका कभी नहीं करेगा,” ब्रैकेन ने कहा।

“तो, आपकी जीत रूस पर निर्भर है,” मैंने कहा।

“इसीलिए तो हमसे जितना भी हो सक रहा है हम रूस की सहायता कर रहे हैं,” ब्रैकेन ने कहा। आरम्भ में स्टालिन ने हमसे प्रतिमास उतने हवाई जहाज माँगे जितने हम साल भर में बना पाते हैं। जब हमने उसका स्वप्न भग किया तो उसने अपनी मांग आधा कर दी। हमारे पास जितना भी है, हम सब उसे दे देंगे, चाहे उसके कारण हम स्वयं सकट में क्यों न पड़ जाय? आप तो जानते ही हैं कि जब क्रिप्स ने स्टालिन को सभावित जर्मन आक्रमण की सूचना दी तो स्टालिन ने उस पर विश्वास करने से इन्कार किया।”

“मैं समझता हूँ कि स्टालिन को यह बात मालूम थी कि जर्मनी आक्रमण करने वाला है,” मैंने कहा “लेकिन उस समय रूस हिटलर के सामने श्रीघे मुँह पड़ा था और अंग्रेजों की इस आशा की पुष्टि नहीं करना चाहता था कि वह शीघ्र ही जर्मनी से लड़ेंगे।”

“तो आप समझते हैं कि स्टालिन को इस बात का पता था,” ब्रैकेन ने कहा। “आप तो जानते ही हैं कि स्टालिन और चर्चिल की खूब बन रही है। मन्त्रिमण्डलों की बैठकों में चर्चिल यह कहकर कि आज चाचा जी के पास से मेरे पास तार आया है खुशी से फूल उठते हैं।”

मैंने पूछा कि क्या ब्रिटेन को रूसी-जर्मन युद्ध में काम आये हुए यशिनियों की ठीक-ठीक संख्या मालूम है। ब्रैकेन ने उत्तर में बताया—“पहले दस सप्ताहों में रूस के तीस लाख और, जर्मनी के बीस लाख आदमी खेत रहे। कैंदियों की नरणा अपेक्षाकृत कम हैं, उन्हें क्वार्टर नहीं दिये जाते। अमेरिकन जनरलों का खयाल है कि जर्मन-सेना अजेय है और रूस हार जायगा। वे मध्य पश्चिम के निवासी हैं और जर्मनों का आदर करते हैं। अगर रूस ने घुटने टेक दिये तो हम सबके लिए बहुत बुरा होगा।”

“केवल इस कारण से कि रूस के पतन से आपके सर्वनाश की सम्भावना है, आपको उसे रोकने के लिए अधिक-से-अधिक धन-जन का व्यय करने के लिए तैयार रहना चाहिए,” मैंने कहा।

“यदि इस कार्य में हमारे एक लाख सैनिक भी मारे जाय तो हमें चिंता नहीं,” ब्रैकेन ने कहा। “लेकिन क्या आपको इस बात का विश्वास है कि हम जो कुछ भी करेंगे उससे एक भी जर्मन-सैनिक पूरब से हटाया जा सकेगा? हिटलर ने फ्रांस और हाल्लैंड में सेनाएँ सुरक्षित कर रखी हैं। हमने यह बात स्टालिन को समझा दी है और वह सतुष्ट है।”

ब्रैकेन को काम करना था, इसलिए मित्रतापूर्वक हाथ मिलाकर हम एक-दूसरे से अलग हो गये।

सन् १९३९ की जर्मन-रूसी संधि और स्टालिन द्वारा सन् १९३५ में आरम्भ किये गये सैनिक विरोधों के उन्मूलन की घटनाओं की चर्चा की भाँति सन् १९३८ की म्यूनिख घटना की चर्चा भी, आजकल जहाँ राजनीतिक प्रवृत्ति वाले लोग इकट्ठे होते हैं, वही छिड़ जाती है। ब्रैकेन के भोजन में म्यूनिख पर वाद-विवाद हुआ। २३ सितम्बर १९४१ को जब मैं लण्डन में चेकोस्लोवेकिया के प्रेजिडेंट एडवर्ड बेनेश से मिला तो उनके मस्तिष्क में भी सबसे अधिक म्यूनिख का ही ध्यान था।

“आप अच्छे तो हैं?” मैंने उनकी लदन-स्थित निर्वासित सरकार के प्रधान कार्यालय में प्रवेश करते हुए पूछा।

“हाँ, अच्छा हूँ,” उन्होंने उत्तर दिया।

“क्यों?” मैंने पूछा।

“पहले मैं नरक में वास कर रहा था,” उन्होंने कहा, “लेकिन तब से अब स्थिति अच्छी है। अब हम युद्ध कर रहे हैं। हमारे लिए तो म्यूनिख के समय ही लड़ना अधिक उचित था। यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि जर्मनी सुडेटनलैंड के मामले पर लड़ हो पड़ता। मुझे रिपोर्ट मिली थी कि वह उस समय तैयार नहीं था। लेकिन अगर वह हम पर आक्रमण करता भी तो हम चार या सम्भवतः छ महीने तक उसे रोके रखते। हमारी सुडेटनलैंड की किलेबन्दियाँ मैजीनो लाइन से ज्यादा अच्छी थीं।

“किंतु क्या आस्ट्रिया की ओर से आपकी सीमा खुली हुई नहीं थी?” मैंने पूछा।

“हाँ, वहाँ हमारी किलेबन्दी ज्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी खासी अच्छी थी,” बेनेश ने उत्तर दिया। “यह तो ठीक है कि प्रेग नष्ट हो जाता,

किन्तु हम भी तो ड्रेसडेन और लिपज़िग को नष्ट कर देते और बर्लिन पर भी बमबारी करते। उसके बदले आज चेकोस्लोवेकिया के स्कोडा और दूसरे कारखानों में इंग्लैंड और रूस के विरुद्ध कार्य हो रहा है। हमारे पास १७०० हवाई जहाज थे जो कि जर्मनी के हवाई जहाजों से किसी भी तरह कम न थे। फ्रांस के पास १५०० हवाई जहाज थे और इंग्लैंड के पास १५०० से २००० तक। यह सभी हवाई जहाज प्रथम कोटि के थे। जर्मनी के पास ३००० विमान थे। चेकोस्लोवेकिया का पतन फ्रांस की नैतिकता और फ्रांस तथा रूस के पारस्परिक सम्बन्ध के लिए भी बुरा था। म्यूनख को घटना मानो यूरोप के लिए एक सर्वनाश थी। हम इस बात के लिए तैयार थे कि पहले बोहीमिय में लड़े और फिर मोरेविया, स्लोवेकिया और रूमेनिया के रास्ते पीछे हटते हुए रूस चले जाय। रूमेनिया से रूसी सीमा की ओर एक रेलवे लाइन भी जाती थी।”

मैने डाक्टर वेनेश से यह लाइन नक्शे में दिखाने को कहा और उन्होंने दिखा दिया।

डाक्टर वेनेश ने फिर कहा—“दिखाने के लिए तो हमने यह लाइन रूमेनिया के लिए उधार बनवाई थी, लेकिन असल में हमने अपने पीछे हटने का रास्ता तैयार कराया था। हमने अपने विमान-चालक भेजकर रूस के ३०० बम-वर्षक हवाई जहाज मंगा लिये थे और हम भी उसी तरह के हवाई जहाज बनाना शुरू करने जा रहे थे। हवाई जहाज हमने रूमेनिया पर उड़ाये। इस मामले में रूमेनिया के राजा कैरोल ने बड़ी मित्रता दिखाई और कहा कि हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं। कैरोल रूमेनिया से होकर रूसी सेना को चेको-स्लोवेकिया आने देते लेकिन पोलैंड ऐसा कभी नहीं करता। फिर भी रूसी सेना पोलैंड को तटस्थ छोड़कर रूमेनिया से होकर हमारे यहाँ आ सकता थी।”

डाक्टर वेनेश ने बातचीत में और भी अधिक दिलचस्पी लेते हुए कहा—“सितम्बर १९३८ में रूसियों ने तीन बार सहायता देने का वचन दिया उस महीने के आरम्भ में हमारे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रूस ने कहा कि अगर फ्रांस सहायता देगा तो वह भी देगा। यह बात असतोष जनक थी, क्योंकि हमें इस बात की आशका थी कि फ्रांस सहायता नहीं देगा। इसलिए हमने रूस को फिर लिखा और उसने हमें सन्नाह दी कि यह मामला हम राष्ट्र-संघ में उठावे। किन्तु मुझे भय था कि राष्ट्र-संघ शायद ब्रिटेन और फ्रांस के दबाव में पहलकर जर्मनी का सामना करने का विरोध करेगा और इस दशा में यदि हम लड़ते तो कहा जाता कि हम संघ के निर्णय के विपरीत काम कर रहे हैं अन्त में रूस

“केवल इस कारण से कि रूस के पतन से आपके सर्वनाश की सम्भावना है, आपको उसे रोकने के लिए अधिक-से-अधिक जन-जन का व्यय करने के लिए तैयार रहना चाहिए,” मैंने कहा ।

“यदि इस कार्य में हमारे एक लाख सैनिक भी मारे जाय तो हमें चिंता नहीं,” ब्रैकेन ने कहा । “लेकिन क्या आपको इस बात का विश्वास है कि हम जो कुछ भी करेंगे उससे एक भी जर्मन-सैनिक पूरव से हटाया जा सकेगा? हिटलर ने फ्रांस और हॉलैंड में सेनाएँ सुरक्षित कर रखी हैं । हमने यह बात स्टालिन को समझा दी है और वह सतुष्ट है ।”

ब्रैकेन को काम करना था, इसलिए मित्रतापूर्वक हाथ मिलाकर हम एक-दूसरे से अलग होगये ।

सन् १९३९ की जर्मन-रूसी संधि और स्टालिन द्वारा सन् १९३५ में आरम्भ किये गये सैनिक विरोधों के उन्मूलन की घटनाओं की चर्चा की भाँति सन् १९३८ की म्यूनिख घटना की चर्चा भी, आजकल जहाँ राजनीतिक प्रवृत्ति वाले लोग इकट्ठे होते हैं, वही छिड़ जाती है । ब्रैकेन के भोज में म्यूनिख पर वाद-विवाद हुआ । २३ सितम्बर १९४१ को जब मैं लण्डन में चेकोस्लोवेकिया के प्रेजिडेंट एडवर्ड बेनेश से मिला तो उनके मस्तिष्क में भी सबसे अधिक म्यूनिख का ही ध्यान था ।

“आप अच्छे तो हैं ?” मैंने उनकी लदन-स्थित निर्वासित सरकार के प्रधान कार्यालय में प्रवेश करते हुए पूछा ।

“हाँ, अच्छा हूँ,” उन्होंने उत्तर दिया ।

“क्यों ?” मैंने पूछा ।

“पहले मैं नरक में वास कर रहा था,” उन्होंने कहा, “लेकिन तब से अब स्थिति अच्छी है । अब हम युद्ध कर रहे हैं । हमारे लिए तो म्यूनिख के समय ही लड़ना अधिक उचित था । यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि जर्मनी सुडेटनलैंड के मामले पर लड़ ही पड़ता । मुझे रिपोर्ट मिली थी कि वह उस समय तैयार नहीं था । लेकिन अगर वह हम पर आक्रमण करता भी तो हम चार या सम्भवतः छ महीने तक उसे रोके रखते । हमारी सुडेटनलैंड की किलेबन्दियाँ मैजीनो लाइन से ज्यादा अच्छी थी ।

“किंतु क्या आस्ट्रिया की ओर से आपकी सीमा खुली हुई नहीं थी ?” मैंने पूछा ।

“हाँ, वहाँ हमारी किलेबन्दी ज्यादा अच्छी नहीं थी, फिर भी ख़ासी अच्छी थी,” बेनेश ने उत्तर दिया । “यह तो ठीक है कि प्रेग नष्ट हो जाता,

किन्तु हम भी तो ड्रेसडेन और लिपज़िग को नष्ट कर देते और बर्लिन पर भी बमबारी करते। उसके बदले आज चेकोस्लोवेकिया के स्कोडा और दूसरे कारखानों में इंग्लैंड और रूस के विरुद्ध कार्य हो रहा है। हमारे पास १७०० हवाई जहाज थे जो कि जर्मनी के हवाई जहाजों से किसी भी तरह कम न थे। फ्रांस के पास १५०० हवाई जहाज थे और इंग्लैंड के पास १५०० से २००० तक। यह सभी हवाई जहाज प्रथम कोटि के थे। जर्मनी के पास ३००० विमान थे। चेकोस्लोवेकिया का पतन फ्रांस की नैतिकता और फ्रांस तथा रूस के पारस्परिक सम्बन्ध के लिए भी बुरा था। म्यूनिख की घटना मानो यूरोप के लिए एक सर्वनाश थी। हम इस बात के लिए तैयार थे कि पहले वोहीमिय में लड़ें और फिर मोरेविया, स्लोवेकिया और रूमेनिया के रास्ते पीछे हटते हुए रूस चले जाय। रूमेनिया से रूसी सीमा की ओर एक रेलवे लाइन भी जाती थी।”

मैंने डाक्टर वेनेश से यह लाइन नक्शों में दिखाने को कहा और उन्होंने दिखा दिया।

डाक्टर वेनेश ने फिर कहा—“दिखाने के लिए तो हमने यह लाइन रूमेनिया के लिए उधार बनवाई थी, लेकिन असल में हमने अपने पीछे हटने का रास्ता तैयार कराया था। हमने अपने विमान-चालक भेजकर रूस के ३०० बम-वर्षक हवाई जहाज मंगा लिये थे और हम भी उसी तरह के हवाई जहाज बनाना शुरू करने जा रहे थे। हवाई जहाज हमने रूमेनिया पर उड़ाये। इस मामले में रूमेनिया के राजा कैरोल ने बड़ी मित्रता दिखाई और कहा कि हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं। कैरोल रूमेनिया से होकर रूसी सेना को चेको-स्लोवेकिया आने देते लेकिन पोलैंड ऐसा कभी नहीं करता। फिर भी रूसी सेना पोलैंड को तटस्थ छोड़कर रूमेनिया से होकर हमारे यहाँ आ सकता थी।”

डाक्टर वेनेश ने बातचीत में और भी अधिक दिलचस्पी लेते हुए कहा—“सितम्बर १९३८ में रूसियों ने तीन बार सहायता देने का वचन दिया उस महीने के आरम्भ में हमारे एक प्रश्न का उत्तर देते हुए रूस ने कहा कि अगर फ्रांस सहायता देगा तो वह भी देगा। यह बात असतोष जनक थी, क्योंकि हमें इस बात की आशंका थी कि फ्रांस सहायता नहीं देगा। इसलिए हमने रूस को फिर लिखा और उसने हमें सलाह दी कि यह मामला हम राष्ट्र-संघ में उठावें। किन्तु मुझे भय था कि राष्ट्र-संघ शायद ब्रिटेन और फ्रांस के दवाव में पड़कर जर्मनी का सामना करने का विरोध करेगा और इस दशा में यदि हम लड़ते तो कहा जाता कि हम संघ के निर्णय के विपरीत काम कर रहे हैं अन्त में रूस

ने हमसे कहा कि हम सब बातों का विचार छोड़कर लड़ने लगे और उसने रुमेनिया से होकर और आकाश-मार्ग से भी सहायता देने का वचन दिया।”

उस भयंकर सितम्बर की याद आते ही वेनेश के मुख की रेखाएँ और भुर्रिया और भा गहरी गड़ गई। ब्रिटेन और फ्रांस की घमकी के कारण वह लड़ाई न करने के लिए रजामन्द हुए थे, किंतु म्यूनिख ने चेकोस्लोवेकिया का गला घोट दिया था। वेनेश को इस बात की पहले से आशंका थी, किंतु वह ब्रिटेन और फ्रांस का विरोध नहीं कर सकते थे। “मैं अपने देश को पूरा स्पेन नहीं बनाना चाहता था,” उन्होंने मुझसे कहा। “अगर हमने रूसी सहायता स्वीकार करके युद्ध आरम्भ कर दिया होता तो मैं बोलशेविक कहलाता।”

वेनेश ने यह सकेत किया कि उनकी सरकार को तुष्टीकरण में विश्वास करने वाली जनतन्त्री सरकारों की ओर से भी विरोध का सामना करना पड़ा था। उन्होंने आह भरते हुए कहा—“यदि लड़ाई ११ महीने बाद आरम्भ न होकर १९३८ में ही शुरू हो गई होती, तो शायद फ्रांस बच जाता। उस समय तक हिटलर की पश्चिमी दीवार तैयार नहीं हुई थी और स्पेन के राज-भक्त तब भी लड़ रहे थे।”

वेनेश मुझसे इस बात में सहमत थे कि सन् १९३८ में ब्रिटेन और फ्रांस का मिलकर हिटलर को तुष्ट करना वैसा ही था जैसा सन् १९३९ में स्टालिन का हिटलर को फुसलाना मनाना। “रूस को फ्रांस की रक्षा करनी चाहिए थी,” वेनेश ने अनिच्छा पूर्वक कहा।

एक दिन शनिवार को दोपहर बाद मैं रेल से ब्रिटेन के हरे-भरे गावों की ओर चल पड़ा और एक छोटे से स्टेशन पर उतर गया। स्टेशन पर प्रथम महासमर के ब्रिटिश प्रधान मंत्री डेविड लायडजार्ज के सेक्रेटरी श्री वाइट ह्वाइट ने मेरा स्वागत किया। वहाँ से घर की ओर जाते समय उन्होंने दो कैंनेडियन सिपाहियों को भी मोटर में चढा लिया था, जिन्होंने कहा कि हमने लड़ाई में नाम लिखवा रखा है, किंतु महीनों तक निष्क्रिय पड़े रहने के कारण ऊब गये हैं। उन्हें यह जानकर बड़ा रोमांच हुआ कि वे लायड जार्ज की मोटर में बैठे हुए थे।

हिटलर से बरखटेसगैडेन में मिलने के बाद लायड जार्ज ने चर्ट में खलिहानों के पास बने हुए अपने मकान की प्रधान बैठक को फिर से बनवाया था और उसमें हिटलर के ‘घोसले’ की तरह एक लम्बी चौड़ी खिड़की लगवा ली थी। घाटी का दृश्य जैसा कि मैंने सन् १९३८ की यात्रा में देखा था उससे कहीं अधिक सुन्दर होगया था। लायड जार्ज के पियानो पर से हिटलर का वह

चित्र, जिस पर हिटलर ने अपने हस्ताक्षर किये थे, हटा लिया गया था। इसी तरह, ब्रिटेन के वाशिंगटन-स्थित भूतपूर्व राजदूत लार्ड लोदियन का चित्र भी, जो पहले लायड जार्ज के सेक्रेटरी रह चुके थे, हटा लिया गया था। फिर भी वहा फ्रेम में जड़े हुए कई चित्र थे, जिनमें से एक वुडरो विलसन का था। इस चित्र पर वुडरो विलसन ने लिखा था “अपने मित्र लायड जार्ज को”। अब भी उनके प्रेम या मित्रता में कोई कमी नहीं आई थी। उनके अतिरिक्त, वहाँ फील्ड मार्शल स्मट्स, फाच, क्लेमेन्सियो, लार्ड बर्केंहेड और लायड जार्ज की माता के भी चित्र थे। एक लम्बी कोच पर साप्ताहिक “न्यू स्टेट्समैन” और “नेशन” की प्रतियाँ, अनेक वामपक्षी परचे, साप्ताहिक “पिकचर पोस्ट” के कितने ही अंक और कई पुस्तकें पड़ी हुई थी।

लायड जार्ज कमरे में कुछ कूदते हुए से आये। किन्तु वह इतने स्त्रस्थ नहीं मालूम पड़ते थे जितना कि मैंने उन्हें १९३८ में देखा था और उनके कोट के कालर पर पड़ने वाले लम्बे रूपहली बाल भी उतने चमकदार नहीं रह गये थे। उन्हें यह बात याद थी कि पिछली मुलाकात में हमने मुख्यतः स्पेन के सम्बन्ध में बातचीत की थी। “अफसोस!” उन्होंने कहा “यदि वहाँ हमने ठीक समय पर सावधानी से काम किया होता तो शायद यह लड़ाई रुक जाती। युद्ध स्पेन में आरम्भ नहीं हुआ। वहाँ से पहले तो हव्वा और मचूरिया में लड़ाई हुई थी, किन्तु तानाशाहों को रोकने के लिए सबसे अच्छा अवसर स्पेन ही में था।” इसके बाद लायड जार्ज फौरन रूस की चर्चा छोड़ बैठे। “स्टालिन मर्झ नहीं करेगा वह जानता है कि इसका परिणाम क्या होगा?” लायड जार्ज ने दृढ़ता के साथ कहा जोर इस बात पर जोर दिया कि रूस पर से जर्मन दबाव कम करने के लिए हमें फ्रांस में दूसरा मोर्चा खोलना चाहिये। मैंने उनसे कहा कि जितने भी मन्त्रियों से मेरी बातचीत हुई है, उन सबको, यहाँ तक कि चर्चिल के दाहिने हाथ सर जॉन एण्डरसन को भी, इस बात का विश्वास है कि ब्रिटेन इस समय दूसरा मार्चा खोलने में समर्थ नहीं है।

“क्यों नहीं?” लायड जार्ज ने तटका से पूछा। “वे कहते हैं कि जहाज काफी नहीं है? वाह, जहाज का क्या बहाना! मार्च १९१८ में जब हमारा फौज फ्रांस में घुसी तो मैंने खाद्य-कन्ट्रोलर को आदेश दिया कि सारे जहाज एटलांटिक से हटाकर उधर ले जाओ। हमने फ्रांस में फौज-पर-फौज उतार-दी और निर्यात सभाल ली। अगर मैं होता तो फ्रांस में एकदम एक या दो लाख सिपाही भेज देता। अगर हमारे पास सम्मान की कमी है तो समझ में नहीं आता कि हम पिछले बारह महीनों से क्या करते रहे हैं। जून १९१५ और जुलाई

१९१६ के बीच मैने १३ लाख सैनिकों को शस्त्र सज्जित करके फ्रांस भेजा था।”

मैने कहा कि यह युद्ध पहले के युद्ध से भिन्न है, कि आज की सेनाओं को टंको जैसे भारी अस्त्र-शस्त्रों और हवाई जहाजों की आवश्यकता है।

“टंक ?” लायड जार्ज ने कहा, “हाँ, इन्हें बनाने के लिए हमारे पास काफी समय था। विन्स्टन मे साहसिकता की भावना नहीं है। पहले महा-समर मे गैलीपोली में उन्हें जो अनुभव हुआ था उसमे उनकी साहसिकता भग हो गई है। विन्स्टन ने यूरोप मे कुछ करना नहीं चाहा। जब जर्मनी ने रूस पर आक्रमण किया तो चर्चिल रूजवेल्ट से मिलने चले गये। उन्होंने अपने को दूर इसलिए रखा कि उन पर कुछ और करने के लिए दबाव न पड़ सके।”

इसी समय नौकरानी जलपान की ट्राली लेकर आई, जिस पर चाय डबलरोटी, मक्खन और शहद रखा हुआ था। लायड जार्ज ने मक्खन निकले हुए दूध का एक गिलास पिया और कहा—“मैं यही पिया करता हूँ।” दूध पीते समय उनका हाथ काँप रहा था। उनकी उम्र ७८ वर्ष की थी और उन्होंने सिगरेट पीना छोड़ दिया था।

मैने एक रिपोर्ट की चर्चा की, जिसमे यह कहा गया था कि सन् १९३७ और १९३८ मे रूजवेल्ट ने विश्व की समस्या को हल करने के लिए हिटलर स्टालिन, मुसोलिनी, चेम्बरलेन और दलादिये को अमेरिका निमन्त्रित करने का विचार किया था।

“तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया ? यह तो एक बड़ा ही अच्छा खयाल था,” लायड जार्ज ने कहा। कुछ क्षण बाद उन्होंने सन्देह की भावना प्रकट करते हुए कहा—“लेकिन नहीं, स्टालिन नहीं आता, वह लिटविनाव को भेज देता और तब हिटलर भी स्वयं न आकर रिबनट्राप को भेजता और सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकलता।”

मैने लायड जार्ज से एटलांटिक अधिकारपत्र के सम्बन्ध में उनका मत पूछा।

“आखिर उस अधिकार-पत्र का मतलब क्या है ? मुक्त व्यापार ?”— लायड जार्ज ने कहा और ‘ख-ख’ की आवाज करते हुए आनन्द के साथ अपना सिर इधर-उधर हिलाया। उन्हें यह विश्वास नहीं था कि एटलांटिक अधिकार-पत्र का अर्थ मुक्त व्यापार है। उन्होंने कहा—“उसमे और निःशस्त्रीकरण की बात भी तो है। वारसाई की सधि में भी यही योजना थी किंतु वह काम नहीं कर सकी। फ्रांसीसियों ने अपने को निःशस्त्र करने से इकार कर दिया। केवल ब्रिटेन और अमेरिकनो ने इसको महत्त्व प्रदान किया।”

लायड जार्ज के पुत्र रिचार्ड, जो पार्लमेण्ट के सदस्य और खाद्य-मंत्री लार्ड वुलटन के सहकारी थे, अपनी लम्बी पत्नी और पुत्र डेविड के साथ चाय पीने आये। लायड जार्ज ने पूछा कि युद्ध में प्रवेश करने के सम्बन्ध में अमेरिकनो की क्या भावना है। साथ-ही-साथ उन्होंने कहा भी—“केवल वही देश, जो सचमुच युद्ध में रत होता है, युद्ध के लिए पूर्ण रूप से उत्पादन करने और उसके श्रम को सहन करने को तैयार हो सकता है।”

“क्या आप समझते हैं कि अमेरिका के युद्ध में प्रवेश करने से पहले हा रूस का पतन हो जायगा,” उन्होंने चिन्ता के साथ पूछा। हमने इस आनुमनिक प्रश्न पर काफी देर तक विचार किया और फिर दूसरा सवाल उठाया—“क्या ब्रिटिश जर्मनी पर बम बरसाकर जीत सकता है?”

“हुँह,” लायड जार्ज ने कहा—“जिस तरह वे अपने हवाई आक्रमणों द्वारा हमें नहीं दबा सकते, उसी तरह हम भी उन पर बम बरसाकर उन्हें नहीं जीत सकते। यह काम बमों से नहीं हो सकता।”

मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा आभास हुआ है कि ब्रिटेन में रूस को सहायता देने की तात्कालिक आवश्यकता को अधिक महत्त्व नहीं दिया जा रहा है।

“मेरी समझ में इसका कारण यह है कि हम पर बमबारी नहीं हो रही है,” लायड जार्ज ने कहा। “लोग गोलाबारी की सीमा से बाहर निकलकर बड़े प्रसन्न होते हैं। सन् १९१८ में जब हमारी सेना फ्रांस में घुसी तो मैं वहाँ बर्लमैन्स्यू से मिलने गया। मेरी उनकी मुलाकात व्यूविले में हुई। यह बात अप्रैल १९१८ की है। जब मैं मोटर पर जा रहा था तो हमारी कुछ रेजीमेण्टे लाइन से बाहर आ रही थी। वे हफ्तों तक खाइयों में पड़े रहे थे और उन्होंने जर्मनों के तमाचे भी खूब खाये थे। वे युद्ध-भूमि से अधिक पीछे नहीं थे, वहाँ बन्दूकों के छूटने की आवाज सुनाई दे रही थी फिर भी उनके चेहरों पर रोशनी थी और वे खुश हो-होकर गा रहे थे।”

मैंने लायड जार्ज से पूछा कि क्या आपकी समझ में इंग्लैण्ड अभी दो माल और डटा रह सकता है “क्यों नहीं?” उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया। जैसा कि आप जानते हैं, मुझे आक्रमण करने में विश्वास नहीं। बहुत कुछ रस पर निर्भर है। उसे घन-जन की भीषण क्षति उठानी पड़ी है। वे आक्रमण नहीं बल्कि प्रत्याक्रमण बरके लड़ते रहे हैं, और इस प्रकार लड़ना हमेंना भेत्ता होता है। जर्मनों ने टैंकों और यन्त्रों का उपयोग किया है, जिनके कारण मनुष्यों की मृत्यु कम होती है। पिछले दिनों में चर्चिल के साथ बंठा-

बैठा प्रथम महासमर की मृत्यु-संख्या पर विचार कर रहा था और हमें यह बात याद थी कि उस समय जब हमें अपने सैनिक मदर मुकाम से जर्मन क्षति के सम्बन्ध में आई हुई सूचना पर गड्ढा होती थी तो हम उन्हें जर्मनों की रिपोर्टों से मिलाने थे और तब पता चलता था कि जर्मनों की रिपोर्टें ज्यादा सही हैं। उदाहरण के लिए, पास चेन्डीकल की लड़ाई में, हेग ने रिपोर्ट दी थी कि जर्मनों के ५८ डिवीजनों का सफाया हो गया है, लेकिन हम जानते थे कि यह रिपोर्ट गलत है और अब हमें मालूम है कि जर्मन-सैनिकों की मृत्यु-संख्या का ज्यादा सच्चा विवरण जर्मन विज्ञापितियों में मिला करता था।—हेग पिछले महासमर में ब्रिटेन के प्रधान सेनापति थे, जिन्हें लायड जार्ज बहुत नापसन्द करते थे।

लायड जार्ज के पुत्र ग्विलिन, जो अब तक विलकुल चुप थे, बोले—जहाँ तक इस युद्ध का प्रश्न है, जर्मनी अपनी यू-बोटों द्वारा हमारे जहाजों के डुबाये जाने के सम्बन्ध में झूठा समाचार दे रहा है।” लायड जार्ज ने यह बात मान ली और यह भी स्वीकार किया कि नाजी अपनी हवाई क्षति को भी कम करके बताते हैं।

इसके बाद वह फिर अमेरिका की बात करने लगे और बोले—“जीत अमेरिका के औद्योगिक उत्पादन पर निर्भर है।” मैंने उन्हें बताया कि वहाँ का उत्पादन लगातार और तेजी के साथ बढ़ रहा है। इसे स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा—“हाँ, लेकिन पिछले महासमर में अमेरिका ने इतना अच्छा काम नहीं किया। अमेरिकन फीजे फ्रांसीसी बन्दूकों इस्तेमाल कर रही थी और कहीं-कहीं तो ब्रिटिश बन्दूकों भी, क्योंकि वह अस्त्र-शस्त्र से पर्याप्त रूप से सज्जित हुए बिना ही यूरोप में आ गई थी।”—मैंने उनसे कहा कि ऐसी बात इस युद्ध में नहीं होगी।

मेरी दृष्टि में लायड जार्ज इतिहास की साकार मूर्ति थे। समस्याओं को समझने की उनमें आश्चर्यजनक क्षमता थी और जितनी विचार-शक्ति उनमें थी उतनी शायद मन्त्रिमण्डल के तीन सदस्यों में एक साथ मिला देने पर भी नहीं हो सकती। हमारी बात कभी अमेरिका और कभी ब्रिटेन पर चलती रही। उन्हें अमेरिका के सम्बन्ध में बातचीत करना ज्यादा अच्छा लगता था और मैं चाहता था कि वह इंग्लैंड की भी बातें करे। अमेरिका की वास्तव बातचीत करते हुए उन्होंने मुझसे उन लोगों के बारे में पूछा जो अमेरिका का युद्ध से अलग रखने के पक्ष में थे।

एक क्षण रुककर मैंने कहा—“आपके मन्त्रिमण्डल से बड़े आदमों

क्यों नहीं है ?”

“तुम्हारे मे क्यों नहीं है ।” उन्होंने तपाक से जवाब दिया । न तो रजिस्ट्रार के ही मन्त्रिमण्डल मे कोई बड़ा आदमी है, न विल्सन के मन्त्रिमण्डल में ही था ।”

“क्या इसका कारण यह है कि चर्चिल को किसी प्रतिद्वन्द्वी को प्रोत्साहन देने मे भय लगता है ।” “मैंने कहा—“सभी बड़े आदमियों को अपने आसपास बड़े आदमियों को रहने देने मे भय लगता है ।”

“नहीं, अगर वह आदमी सचमुच बड़ा है तो उसे भय नहीं लगेगा”, लायड जार्ज ने कहा । मुझे विश्वास है कि उनका सकेत अपने से था ।

“चर्चिल को प्रतिद्वन्द्वियों से डरने की कोई जरूरत नहीं;” लायड जार्ज ने फिर कहा, ‘देश उन्हें चाहता है और केवल उन्हें ही चाहता है ।”

इस बातचीत से उनका ध्यान रूस की ओर खिंच गया । उन्होंने कहा—“रूसी सेना विभाग का काम ठीक चलता नहीं मालूम होता है । बुडेनी एक साहसी घुड़सवार अफसर है ।”

‘बुडेनी सार्जेंट-मेजर है और उन्हें मार्शल की पदवी प्राप्त है,” मैंने कहा । इस पर लायड जार्ज हँसे और उन्होंने मुझसे पूछा कि स्टालिन कैसा आदमी है । कुछ देर बाद वह उठ खड़े हुए और उन्होंने मुझसे अपने मुलावातियों के रजिस्ट्रार मे हस्ताक्षर करने के लिए कहा । मुझसे पहले ब्रिटेन के पीछे पड़े रहनेवाले दो पत्रकारों—माइकल फुड और फ्रैंक ओवेन—के हस्ताक्षर थे । पृष्ठ के सिरे पर रूसी राजदूत ईवान मैस्की और श्रीमती मैस्की के दस्तखत थे ।

ग्विलिम और उनकी पत्नी के साथ मैं कुछ देर खेत में घूमता रहा । हमने कुछ सेब और देर तोड़कर खाये । एक बाटिका के अन्दर हमें लार्ड जयज हरे रंग की ऊनी टोपी पहने चुस्ती के साथ टहलते और अपनी जायदाद निरीक्षण करते हुए मिले । वह एक महान् व्यक्ति मालूम होते थे, जैसे कि वह दस्तुत है ।

मैं मकान के पीछे के लम्बे-चौड़े उद्यान मे बैठकर धूप ले रहा था और रविवार के समाचारपत्र पढ़ रहा था । उस दिन कहीं से टेलीफोन नहीं आया । मेरे मेजबान और लन्दन के दूसरे व्यक्ति गाँव मे छुट्टी मनाने गये थे । घर के अन्दर से दो० टी० सी० द्वारा ब्राडकास्ट किये जाने वाले शास्त्रीय संगीत की ध्वनि आ रही थी । एला अन्दर बैठी हुई सुन रही थी और मैं भी बीच-बीच में गल्लार पटना रोबकर सुनने लगता था । लम्बे-चौड़े मैदान के किनारे-किनारे

रंग-विरंगे सुन्दर फूल उगे हुए थे । उस दिन ७ सितम्बर था । वातावरण शांत और सुखद था । ठीक एक साल पहले ३५० नाजी विमान टेम्स नदी पर उड़ते हुए आये थे और उन्होंने ब्रिटिश आकाश-सेना के परदे को फाड़कर लण्डन पर बमों के रूप में मृत्यु की वर्षा का र्था । उसी दिन जर्मन के एक सी तीन आक्रमण विमान मारकर गिरा लिये गये थे । जर्मनी वाले हमें स्तम्भित रह गये थे । फिर भी लण्डन के आकाश-मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ३१ अक्टूबर तक लड़ाई चलती रही थी । इसके बाद जर्मन हवाई ब्रेडा थककर पीछे हट गया था किंतु बीच-बीच में उसके आक्रमण होते ही रहे । १० मई १९४१ को उसने जो आक्रमण किया वह उसका सबसे भीषण आक्रमण था । नागरिक रक्षा के अधिकारी सर वारेन फिशर ने मुझे बताया कि इस प्रकार के १० आक्रमणों से लण्डन पूरा-का पूरा नष्ट हो सकता था ।

उस भीषण आक्रमण के ६ सप्ताह बाद जर्मन आकाशी-सेना ने अपना ध्यान रूस पर केन्द्रित करना आरम्भ किया । इंग्लैंड में मैं ६ हफ्ते ठहरा । किन्तु इस बीच केवल एक—और वह भी बहुत ही हलका-सा—आक्रमण हुआ । फिर भी रक्षा का कार्य करने वाले लोग सदा सावधान रहे । हजारों रुकावट डालने वाले गुब्बारे जो सामने से देखने में तिमिगल—ह्वेल मछली—जैसे और और पीछे से सेवार-जैसे मालूम देते थे आकाश में ऊँचे उड़ते रहे । वे एक दूसरे से लोहे के लम्बे और मजबूत तारों में बँधे हुए थे और ये तार जमीन पर भारी-भारी ट्रकों में जकड़े हुए थे । ये गुब्बारे सख्या में इतने अधिक थे कि किसी भी आक्रामक विमान को उनके जाल के अंदर प्रवेश करने का साहस नहीं होता था क्योंकि ऐसा करने से उसके तार से कटकर दो टुकड़े हो जाने का डर था । अतः जर्मन-विमानों को विमानवेधी तोपों की पहुँच के भीतर आते ही रुक जाना पड़ता था ।

फिर भी एक विस्तृत लक्ष्य-क्षेत्र बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह सकता । सन् १९४० में एक दिन जर्मनी के तीन बम जमीन के नीचे ४० फीट तक घुस गये, जहाँ सैकड़ों व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए छिपे हुए थे । विक्टोरिया जिले में तो एक बम ने ५८ हजार टेलीफोनो के तार नष्ट-भ्रष्ट कर डाले । जनवरी १९४१ में लन्दन में गैस के प्रधान तार ८ हजार जगहों पर टूट-फूट गए । अक्टूबर १९४० में बमों ने दक्षिणी रेलवे को अस्त-व्यस्त कर दिया था । जर्मन-आक्रमणों के कारण ब्रिटेन के २० लाख मकान पूर्णतः या अंशतः नष्ट-भ्रष्ट हो गये ।

किन्तु यह परिच्छेद अब समाप्त हो चुका था । जब मैंने उस युद्ध-

कालीन शान्त रविवार के दिन 'आवजर्वर' पढ़ना आरम्भ किया तो कुछ मध्यम श्रेणी के ब्रिटिश बम-वर्षक पूर्व की ओर जाते हुए दिखाई दिये और जितनी देर में मैंने अपना भोजन और चार समाचार पत्रों का पढ़ना समाप्त किया उतनी देर में वे जर्मनी और नाजी कृत यूरोप पर बम बरसाकर घड़-घड़ाते हुए वापस आगये। इंग्लैंड ने पाँसा पलट दिया था क्योंकि जर्मनी \ रुस की ओर झुक गया था। यह विराम शांति उस समय तक कायम रही, जब तक कि जर्मनी के नये प्रकार के बमों ने हिटलर के सामने यह स्वप्न एक बार फिर लाकर खड़हर नहीं कर दिया कि इंग्लैंड पर आकाश-मार्ग से आक्रमण करके युद्ध जीता जा सकता है।

सन् १९४१ की गर्मियों में भा, जब जर्मनी के वैमानिक आक्रमण नहीं हो रहे थे, हजारों बूढ़ी औरंग्ते सरकार द्वारा बनाये गये, लंदन के तहखानों में लकड़ी पर सोया करती थी। उन्हें इस बात का बड़ा भय था कि कहीं घर में सोते-साते ही बम न बरस पड़े। जहाँ बमों ने मकानों के ब्लाक के ब्लाक घरायायी कर दिये थे, जैसा कि लन्दन के की ईस्टहैम और दूसरे कारखानों के क्षेत्रों में हुआ था, वहाँ की सारी-की-सारी आवादी तहखानों में सोती ही नहीं बल्कि रहती भी थी। इन तहखानों में पानी के नलों, पाखानों, कैंटीनो, बिजली और रेडियो तन्त्र का प्रबन्ध था लोग पटरियों पर दो-दो या तीन-तीन की पक्ति में सोते थे। बच्चे नीचे की पक्ति में मुलाये जाते थे। सबरे सब बच्चे स्कूल भेज दिये जाते थे और दोपहर बाद वे फिर इन बदबूदार और शोर-गुल से भरी हुई गुफाओं में आ जाते थे जहाँ हमेशा कोई-न-कोई रहता ही था। स्त्रियाँ मुझे यह बताते हुए कि वर्तमान स्थिति में उनका जीवन कितना अनियमित हो गया है, रो पड़ती थी। लन्दनने युद्ध का कीमत न केवल मनुष्यों के प्राणों, टूटे हुए घरों, बम भोजनों, और दूरे कपड़ों से चुकाई, बल्कि उसका प्रभाव जनता की स्नायुओं पर भी पड़ा। और जब असर स्नायु पर पड़ता है तो उसकी पीड़ा धीरे-धीरे मृत्यु तक भुगतनी पड़ती है और अगली पीढ़ी भी उससे दोषित नहीं रह पाती। यार्क, बाथ, राटरडम, शेफील्ड और ब्रिटेन के दूसरे छोटे-छोटे कस्बों में, जहाँ मैं गया स्थिति कुछ अधिक भिन्न होते हुए भी प्रकट होती थी। यूरोप में हालत बहुत बुरी थी।

लड़ाई के बाद का यूरोप भयभीत स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों का यूरोप है। अपने देशों का पुनर्निर्माण इन्हीं स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को करना है। साथ ही साथ, उन्हें अपना भी पुनर्निर्माण करना है और मानवीय भद्रता के प्रति अपने विश्वास को पुनः जाग्रत करना है।

रंग-विरंगे सुन्दर फूल उगे हुए थे । उस दिन ७ सितम्बर था । वातावरण शांत और सुखद था । ठीक एक साल पहले ३५० नाजी विमान टेम्स नदी पर उड़ते हुए आये थे और उन्होंने ब्रिटिश आकाश-सेना के परदे को फाड़कर लण्डन पर बमों के रूप में मृत्यु की वर्षा की थी । उसी दिन जर्मन के एक सी तीन आक्रमण विमान मारकर गिरा लिये गये थे । जर्मनी वाले इसमें स्तम्भित रह गये थे । फिर भी लण्डन के आकाश-मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ३१ अक्टूबर तक लड़ाई चलती रही थी । इसके बाद जर्मन हवाई बेड़ा थककर पीछे हट गया था किंतु बीच-बीच में उसके आक्रमण होते ही रहे । १० मई १९४१ को उसने जो आक्रमण किया वह उसका सबसे भीषण आक्रमण था । नागरिक रक्षा के अधिकारी सर वैंरेन फिगर ने मुझे बताया कि इस प्रकार के १० आक्रमणों से लण्डन पूरा-का पूरा नष्ट हो सकता था ।

उस भीषण आक्रमण के ६ सप्ताह बाद जर्मन आकाशी-सेना ने अपना ध्यान रूस पर केन्द्रित करना आरम्भ किया । इंग्लैंड में मैं ६ हफ्ते ठहरा । किन्तु इस बीच केवल एक—और वह भी बहुत ही हलका-सा—आक्रमण हुआ । फिर भी रक्षा का कार्य करने वाले लोग सदा सावधान रहे । हजारों रुकावट डालने वाले गुब्बारे जो सामने से देखने में तिमिगल—ह्वेल मछली—जैसे और और पीछे से सेवार-जैसे मालूम देते थे आकाश में ऊँचे उड़ते रहे । वे एक दूसरे से लोहे के लम्बे और मजबूत तारों में बँधे हुए थे और ये तार जमीन पर भारी-भारी ट्रकों में जकड़े हुए थे । ये गुब्बारे सख्या में इतने अधिक थे कि किसी भी आक्रामक विमान को उनके जाल के अंदर प्रवेश करने का साहस नहीं होता था क्योंकि ऐसा करने से उसके तार से कटकर दो टुकड़े हो जाने का डर था । अतः जर्मन-विमानों को विमानबेधी तोपों की पहुँच के भीतर आते ही रुक जाना पड़ता था ।

फिर भी एक विस्तृत लक्ष्य-क्षेत्र बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह सकता । सन् १९४० में एक दिन जर्मनी के तीन बम जमीन के नीचे ४० फीट तक घुस गये, जहाँ सैकड़ों व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए छिपे हुए थे । विक्टोरिया जिले में तो एक बम ने ५८ हजार टेलीफोनो के तार नष्ट-भ्रष्ट कर डाले । जनवरी १९४१ में लन्दन में गैस के प्रधान तार ८ हजार जगहों पर टूट-फूट गए । अक्टूबर १९४० में बमों ने दक्षिणी रेलवे को अस्त-व्यस्त कर दिया था । जर्मन-आक्रमणों के कारण ब्रिटेन के २० लाख मकान पूर्णतः या अंशतः नष्ट-भ्रष्ट हो गये ।

किन्तु यह परिच्छेद अब समाप्त हो चुका था । जब मैंने उस युद्ध-

कालीन शान्त रविवार के दिन 'आवजर्वर' पढ़ना आरम्भ किया तो कुछ मध्यम श्रेणी के ब्रिटिश बम-वर्षक पूर्व की ओर जाते हुए दिखाई दिये और जितनी देर में मैंने अपना भोजन और चार समाचार पत्रों का पढ़ना समाप्त किया उतनी देर में वे जर्मनी और नाजी-कृत यूरोप पर बम बरसाकर धड़-धड़ाते हुए वापस आगये। इंग्लैंड ने पाँसा पलट दिया था क्योंकि जर्मनी \ रुस की ओर झुक गया था। यह विराम जाति उस समय तक कायम रही, जब तक कि जर्मनी के नये प्रकार के बमों ने हिटलर के सामने यह स्वप्न एक बार फिर लाकर खड़हर नहीं कर दिया कि इंग्लैंड पर आकाश-मार्ग से आक्रमण करके युद्ध जीता जा सकता है।

सन् १९४१ की गर्मियों में भा, जब जर्मनी के वैमानिक आक्रमण नहीं हो रहे थे, हजारों बूढ़ी और ते सरकार द्वारा बनाये गये, लदन के तहखानों में लकड़ी पर सोया करती थी। उन्हें इस बात का बड़ा भय था कि कहीं घर में सोते-साते ही बम न बरस पड़े। जहाँ बमों ने मकानों के ब्लाक के ब्लाक धराशायी कर दिये थे, जैसा कि लन्दन के की ईस्टहैम और दूसरे कारखानों के क्षेत्रों में हुआ था, वहाँ की सारी-की-सारी आवादी तहखानों में सोती ही नहीं बल्कि रहती भी थी। इन तहखानों में पानी के नल्ले, पाखानों, कैंटीनो, बिजली और रेडियो तक का प्रबन्ध था लोग पटरियों पर दो-दो या तीन-तीन की पवित में सोते थे। बच्चे नीचे की पक्ति में मुलाये जाते थे। सबरे सब बच्चे स्कूल भेज दिये जाते थे और दोपहर बाद वे फिर इन बंदबूदार और शोर-गुल से भरी हुई गुफाओं में आ जाते थे जहाँ हमेशा कोई-न-कोई रहता ही था। स्त्रियाँ मुझे यह बताते हुए कि वर्तमान स्थिति में उनका जीवन कितना अनियमित हो गया है, रो पड़ती थी। लन्दनने युद्ध का कीमत न केवल मनुष्यों के प्राणों, टूटे हुए घरों, बम भोजनों, और बुरे कपड़ों से चुकाई, बल्कि उसका प्रभाव जनता की स्नायुओं पर भी पड़ा। और जब असर स्नायु पर पड़ता है तो उसकी पीड़ा धीरे-धीरे मृत्यु तक भुगतनी पड़ती है और अगली पीढ़ी भी उससे वांचत नहीं रह पाती। यार्क, बाथ, राटरडम, शेफील्ड और ब्रिटेन के दूसरे टोटे-छोटे कस्बों में, जहाँ मैं गया स्थिति कुछ अधिक भिन्न होते हुए भी अच्छी थी। यूरोप में हालत बहुत बुरी थी।

लड़ाई के बाद का यूरोप भयभीत स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों का यूरोप है। अपने देशों का पुनर्निर्माण इन्हीं स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को करना है। साथ ही साथ, उन्हें अपना भी पुनर्निर्माण करना है और मानवीय भद्रता के प्रति अपने विश्वास को पुन जाग्रत करना है।

रंग-विरंगे सुन्दर फूल उगे हुए थे । उस दिन ७ सितम्बर था । वातावरण शांत और सुखद था । ठीक एक साल पहले ३५० नाजी विमान टेम्स नदी पर उड़ते हुए आये थे और उन्होंने ब्रिटिश आकाश-सेना के परदे को फाड़कर लण्डन पर बमों के रूप में मृत्यु की वर्षा की थी । उसी दिन जर्मन के एक सौ तीन आक्रमण विमान मारकर गिरा लिये गये थे । जर्मनी वाले इसमें स्तम्भित रह गये थे । फिर भी लण्डन के आकाश-मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ३१ अक्टूबर तक लड़ाई चलती रही थी । इसके बाद जर्मन हवाई बेड़ा थककर पीछे हट गया था किंतु बीच-बीच में उसके आक्रमण होते ही रहे । १० मई १९४१ को उसने जो आक्रमण किया वह उसका सबसे भीषण आक्रमण था । नागरिक रक्षा के अधिकारी सर वैंरेन फिगर ने मुझे बताया कि इस प्रकार के १० आक्रमणों से लण्डन पूरा-का पूरा नष्ट हो सकता था ।

उस भीषण आक्रमण के ६ सप्ताह बाद जर्मन आकाशी-सेना ने अपना ध्यान रूस पर केन्द्रित करना आरम्भ किया । इंग्लैंड में मैं ६ हफ्ते ठहरा । किन्तु इस बीच केवल एक—और वह भी बहुत ही हलका-सा—आक्रमण हुआ । फिर भी रक्षा का कार्य करने वाले लोग सदा सावधान रहे । हजारों रुकावट डालने वाले गुब्बारे जो सामने से देखने में तिमिगल—ह्वेल मछली—जैसे और और पीछे से सेवार-जैसे मालूम देते थे आकाश में ऊँचे उड़ते रहे । वे एक दूसरे से लोहे के लम्बे और मजबूत तारों में बँधे हुए थे और ये तार ज़मीन पर भारी-भारी टुकों में जकड़े हुए थे । ये गुब्बारे सख्या में इतने अधिक थे कि किसी भी आक्रामक विमान को उनके जाल के अंदर प्रवेश करने का साहस नहीं होता था क्योंकि ऐसा करने से उसके तार से कटकर दो टुकड़े हो जाने का डर था । अतः जर्मन-विमानों को विमानबेधी तोपों की पहुँच के भीतर आते ही रुक जाना पड़ता था ।

फिर भी एक विस्तृत लक्ष्य-क्षेत्र बिलकुल सुरक्षित नहीं रह सकता । सन् १९४० में एक दिन जर्मनी के तीन बम जमीन के नीचे ४० फीट तक घुस गये, जहाँ सैकड़ों व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए छिपे हुए थे । विक्टोरिया जिले में तो एक बम ने ५८ हजार टेलीफोनो के तार नष्ट-भूट कर डाले । जनवरी १९४१ में लन्दन में गैस के प्रधान तार ८ हजार जगहों पर टूट-फूट गए । अक्टूबर १९४० में बमों ने दक्षिणी रेलवे को अस्त-व्यस्त कर दिया था । जर्मन-आक्रमणों के कारण ब्रिटेन के २० लाख मकान पूर्णतः या अंशतः नष्ट-भूट हो गये ।

किन्तु यह परिच्छेद अब समाप्त हो चुका था । जब मैंने उस युद्ध-

कालीन शान्त रविवार के दिन 'आवजर्वर' पढ़ना आरम्भ किया तो कुछ मध्यम श्रेणी के ब्रिटिश बम-वर्षक पूर्व की ओर जाते हुए दिखाई दिये और जितनी देर में मैंने अपना भोजन और चार समाचार पत्रों का पढ़ना समाप्त किया उतनी देर में वे जर्मनी और नाजी-कृत यूरोप पर बम बरसाकर धड़-धड़ाते हुए वापस आगये। इंग्लैण्ड ने पाँसा पलट दिया था क्योंकि जर्मनी रूस की ओर झुक गया था। यह विराम शांति उस समय तक कायम रही, जब तक कि जर्मनी के नये प्रकार के बमों ने हिटलर के सामने यह स्वप्न एक बार फिर लाकर खंडहर नहीं कर दिया कि इंग्लैण्ड पर आकाश-मार्ग से आक्रमण करके युद्ध जीता जा सकता है।

सन् १९४१ की गर्मियों में भा, जब जर्मनी के वैमानिक आक्रमण नहीं हो रहे थे, हजारों बूढ़ी औरतें सरकार द्वारा बनाये गये, लंदन के तहखानों में लकड़ी पर सोया करती थीं। उन्हें इस बात का बड़ा भय था कि कहीं घर में सोते-साते ही बम न बरस पड़े। जहाँ बमों ने मकानों के ब्लाक के ब्लाक धराशायी कर दिये थे, जैसा कि लन्दन के की ईस्टहैम और दूसरे कारखानों के क्षेत्रों में हुआ था, वहाँ की सारी-की-सारी आबादी तहखानों में सोती ही नहीं बल्कि रहती भी थी। इन तहखानों में पानी के नलों, पाखानों, कैंटीनो, बिजली और रेडियो तक का प्रबन्ध था लोग पटरियों पर दो-दो या तीन-तीन की पंक्ति में सोते थे। बच्चे नीचे की पंक्ति में मुलाये जाते थे। सबरे सब बच्चे स्कूल भेज दिये जाते थे और दोपहर बाद वे फिर इन बंदबूदार और शोर-गुल से भरी हुई गुफाओं में आ जाते थे जहाँ हमेशा कोई-न-कोई रहता ही था। स्त्रियाँ मुझे यह बताते हुए कि वर्तमान स्थिति में उनका जीवन कितना अनियमित हो गया है, रो पड़ती थीं। लन्दनने युद्ध का कीमत न केवल मनुष्यों के प्राणों, दूटे हुए घरों, कम भोजनों, और बुरे कपड़ों से चुकाई, बल्कि उसका प्रभाव जनता की स्नायुओं पर भी पड़ा। और जब असर स्नायु पर पड़ता है तो उसकी पीड़ा धीरे-धीरे मृत्यु तक भुगतनी पड़ती है और अगली पीढ़ी भी उससे वांचन नहीं रह पाती। यार्क, वाथ, राटरडम, शेफील्ड और ब्रिटेन के दूसरे छोटे-छोटे कस्बों में, जहाँ मैं गया स्थिति कुछ अधिक भिन्न होते हुए भी अच्छी थी। यूरोप में हालत बहुत बुरी थी।

लंडन के बाद का यूरोप भयभीत स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों का यूरोप है। अपने देशों का पुनर्निर्माण इन्हीं स्त्रियों, पुरुषों और बच्चों को करना है। साधनी नाथ, उन्हें अपना भी पुनर्निर्माण करना है और मानवीय भद्रता के प्रति अपने विश्वास को पुनः जाग्रत करना है।

ब्रिस्टल से मैं हवाई जहाज में लिसव्न गया वहाँ न्यूयार्क जाने वाले हवाई जहाज में स्थान पा जाने के लिए मुझे दो दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैं जानता था कि जाने का प्रबंध दो चार दिनों में हो ही जायगा, फिर भी बड़ा क्रोध आ रहा था। एक ऐसी जगह पर रहने में, जहाँ मैं रहना नहीं चाहता था, बड़ा भार मालूम हो रहा था। वहाँ हजारों शरणार्थ महीनों में प्रतीक्षा कर रहे थे। इनमें से अधिकांश यहूदी थे और उन्हें इस बात का भरोसा नहीं था कि वे कभी वहाँ से निकल भी पायेंगे या नहीं। जैसा कि अमेरिका के विदेशी सम्वाददाता, जे ऐलेन, ने एक बार कहा था, इन शरणार्थों को यह बात मालूम थी कि हिटलर पुर्तगाल पर पलक मारते अधिकार कर सकता है।

एक दिन मैं अमेरिकन आकाश-सेना के कप्तान गेलवॉर्डेन (जो पहले "शिकागो टाइम्स" में थे) "वाशिंगटन" पोस्ट के मालिक यूजान मेयर सैम-हरवर्ट, श्रीमती हरवर्ट और ब्रिटिश राजदूतालय के मैकल-स्टूअर्ट के साथ साड की लड़ाई देखने के लिए एक गाव में गया। स्पेनिश की लड़ाई बड़ी रोमांचकारी होती है और पुर्तगाल साड की लड़ाई नीरस साड से लड़ने वाला व्यक्ति घोंडे पर चढ़कर लड़ता है। स्पेन में तो हर एक सांड मार दिया जाता है, किंतु पुर्तगाल में उसके गिर जाने के बाद कई वीर पुरुष उसके सिर, उसकी पूछ और दूसरे हिस्सों को पकड़कर उसे खींचते हुए ले जाते हैं।

गलियों में हम जो पुर्तगाल मिले वे ब्रिटेन के समर्थक थे। यह बात उनके कोटों में लगे हुए विजय सूचक बटनों से स्पष्ट हो रही थी और उन पर जर्मनों की पराजय की अच्छी प्रतिक्रिया होड़ रही थी। तानाशाही शाला-जार की धार्मिक फासिस्ट सरकार की जमता ब्रिटेन का समर्थन इसलिए करता था कि उसे यह पता था कि पुर्तगाल के प्रति इंग्लैंड का कोई नीचता पूर्ण आयोजन नहीं है। फिर भी उसे इस बात की चिन्ता थी कि यदि यूरोप में फासिस्ट विरोधियों की विजय हो गई तो शायद वह कायम न रह सके। इसलिए इंग्लैंड और जर्मनी दोनों के साथ चाल चलता रहे और दोनों को अपना माल बेचकर पैसा कमाता रहा।

लिसव्न में नाजी पुस्तकें और अंग्रेजी अखबार दोनों ही कोनों की अनेक दुकानों पर बिका करते थे। मैंने जर्मनी के दैनिक और साप्ताहिक पत्रों को पढ़ा उन सबमें यही राग अलापा गया था कि रूस में जर्मनी को बड़ी-कठिनाइयाँ भोगनी पड़ रही हैं, उन्हें कीचड़, गोली मिट्टी की जमीन रेतीला सड़को और यातायात सम्बन्धी दूसरी असुविधाओं का सामना करना पड़

रहा है। सब जगह यही बात स्वीकार की गई थी कि जर्मनी के सैनिक अधिकांशियों ने रूस की शक्ति के सम्बन्ध में जो अनुमान लगाया था, उससे वह अधिक शक्तिशाली है।

गलियो, भोजनालयों और सिनेमा-घरों में मैंने जो पुर्तगाल देखे उनमें स्पेनियाडों की अपेक्षा कम तेज, शक्ति और हास्यवृत्ति थी। किन्तु स्पेनियाडों का तरह वे भी बहुत शोर-गुल करते थे और एक दूसरे की पीठ पर मारते भी थे। वहाँ-पुरुषही-पुरुष दिखाई पड़ते थे। स्त्रियाँ होटलों और विश्रामालयों में बहुत ही कम जाती थी।

भविष्य-दर्शन

“मैं रविवार को सवेरे ९ बजे यूरोप से रवाना हुआ और सोमवार शाम को ३ बजे न्यूयार्क पहुँच गया।” न्यूकासल (पेन्सिलवेनिया) में स्टेट शिक्षक-सम्मेलन का जो अधिवेशन हुआ उसमें लोग हाँफते हुए-से दिखाई दिये। सबके हृदय में यह भावना बैठी हुई थी कि अब युद्ध होने ही वाला है।

२४ अक्टूबर को इन शिक्षकों से मैंने कहा—“मैं यूरोप से युद्ध-स्थिति का विचारपूर्वक अध्ययन करके लौटा हूँ और उसका साराश यह है—ब्रिटेन जीत नहीं सकता। शायद जर्मनी भी नहीं जीत सकता और ब्रिटेन समझौता करके युद्ध समाप्त नहीं करेगा। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? यही कि केवल अमेरिका में ही युद्ध को समाप्त करने की क्षमता है और वह अधिनायकों को हराकर ऐसा कर सकता है। इसलिए यदि हम युद्ध नहीं करेंगे तो लड़ाई लम्बी होती जायगी।” मेरा भाषण एक स्टैनोग्राफर ने लिखा था और उसकी एक प्रति मेरे पास भेज दी थी, जो मेरे पास है।

हमारे यहाँ युद्ध में भाग लेने और न लेने के समर्थकों के बीच जो वादविवाद चल रहा था उसका अन्त जापान ने ही कर डाला। पर्ल हार्बर में जापान न हमें बतला दिया कि ससार में वायुयानों की कमी नहीं और हम बीसवीं सदी में रह रहे हैं।

७ दिसम्बर १९४१ की शाम को मैं आर्थर उपहम पोप से मिला। ये महाशय ईरानी मामलों के विशेषज्ञ हैं और रूस के सम्बन्ध में सम्पादक के नाम पत्र लिखा करते थे। उनके यहाँ गद्देदार कुर्सियों पर बैठकर हमने चाय पी। जब मैं वापस जा रहा था तो वर्दीधारी लिफ्ट चलाने वाले ने कहा—“हवाई द्वीप में जापानियों ने हम पर हमला कर दिया है।” उसी दिन शाम को न्यूयार्क से सिनसिनाटी जाती हुई गाडी में बैठे हुए नागरिक यात्रियों ने रेडियो सुना। उनकी खामोशी से उनके विषाद का पता चल रहा था।

पर्लहार्वर पर आक्रमण कर निस्सन्देह जापान ने एक आत्मघातक भूल की। वह ऐसा करने के लिए क्यों प्रेरित हुआ ? ७ दिसम्बर १९४१ के प्रहार का उद्देश्य निश्चय ही अमेरिकन जल-सेना को बरबाद करने या उसे बुरी तरह से पगु बना देने का था। क्या जापान ने अमेरिका की औद्योगिक क्षमता को सचमुच इतना अल्प समझा था कि उसे यह आशा ही नहीं थी कि हम शीघ्र ही इस हानि को पूरा न कर सकेंगे ? क्या उसने अमेरिका के उत्साह को इतना गिरा हुआ मान लिया था कि हम उस प्रहार को चुपचाप सहन कर लेंगे और आगे कुछ कार्रवाई ही नहीं करेंगे ? क्या वास्तव में टोकियो वाले इतने मूर्ख थे ?

सवाल यह नहीं कि जापानियों ने डच पूर्वी इन्डोनेशिया, मलाया और बर्मा पर आक्रमण क्यों किया ; वहाँ उन्होंने दो ऐसे साम्राज्यों की बहुमूल्य सम्पत्ति को हथियाने का सुअवसर देखा जो यूरोपीय युद्ध के कारण क्षीण बन गए थे। किन्तु साथ-ही-साथ उन्होंने अमेरिका को क्यों लड़ाई में घसीटा ? अपने विरुद्ध बेमतलब अमरीकी सैन्य-शक्ति को जुटाने में क्या बुद्धिमत्ता थी ? टोकियो के सामने दो रास्ते थे, या तो वह उत्तर दिशा में आगे बढ़कर मोवियत् रूस के क्षेत्रों पर अधिकार कर सकता था, या दक्षिण की ओर बढ़ कर ब्रिटेन, हालैंड और फ्रांस की भूमि को हथिया सकता था। जापान के बहुत से राजनीतिक विचारक रूस को ही अपना प्रधान सक्ल मानते थे और वे चाहते थे कि जैसे ही सन् १९४१ के अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर के महीनों में हिटलर मास्को की ओर बढ़े और यूक्रेन के औद्योगिक प्रदेश में प्रवेश करे वैसे ही वह भी साइबेरिया में जा घुसे। यह कार्रवाई जापान की जल-सेना द्वारा की जाती।

उधर जापान की जल-सेना यह कह सकती थी कि दक्षिण की ओर बढ़ने में जापान को जितना कच्चा माल और जन-बल प्राप्त हो सकेगा उतना रूस को अपने दूर पूरब के क्षेत्रों में प्राप्त नहीं है और साथ ही चीन का युद्ध भी समाप्त हो सकेगा।

इसमें यह तो पता लग जाता है कि जापान दक्षिण में हागकाग, मलाया और सिंगापुर की ओर क्यों बढ़ा, किन्तु यह नहीं मालूम हो पाता कि जापान ने अमेरिका को लड़ाई में कूदने के लिए क्यों प्रेरित किया। क्या सहज विजय की आशा से जापान के समुद्री अधिकारियों की दृष्टि धुँधली पड़ गई थी ? यह हो सकता है। उन्मत्त तो आखिर उन्मत्त ही होते हैं क्योंकि वे अपने कार्यों के परिणाम की परवाह नहीं करते। पर्ल हार्वर की भूल पहली भूल नहीं थी। ऐसी

भूले तो शक्ति-उन्मत्त अधिकारी करते ही आये हैं। हो सकता है कि मध्य-कालीन मनोवृत्ति वाले जापानी योद्धा आधुनिक ढंग के शस्त्रों से सुलज्जित होने के कारण पथभ्रष्ट होगये हों।

फिर भी पर्ल हार्बर पर आक्रमण करना जापान के लिए तर्क की दृष्टि से आवश्यक था। यदि जापान को पीछे रहना था तो उसके लिए यह आवश्यक था कि १९४१ के ऐसे अवसर पर जब कि उसके मुद्दूर पूर्व के प्रतिद्वंद्वी और सम्भावित शिकार—ब्रिटेन, हालैंड और रूस—हिटलर के साथ लड़ाई में वुरी तरह उलभं हुऐ थे, गम्भीर क्षति उठा चुके थे, तो वह कहीं-न-कहीं प्रहार करता।

जब फ्रांस हार चुका था और इंग्लैंड के पैर सड़ाखड। रहे थे, तब जून १९४० में जापान के लिए दक्षिण की ओर बढ़ने का अच्छा अवसर होता। तैयार होने के कारण ही जापान सितम्बर १९४० में फ्रांसीसी हिन्द-चीन को हड़पने के अलावा कुछ और नहीं कर सका। रूस दूसरा कारण था। जब कि हिटलर और जगह उलभा हुआ था, तटस्थ रूस यूरोप में जारकालीन प्रदेशों पर अधिकार करने की ओर कदम उठा चुका था। एशिया में कितने ही जारकालीन प्रदेशों पर जापान का अधिकार था। टोकियो ने सोचा कि यदि वह दक्षिण में बढ़ा तो कहीं मास्को उवत प्रदेशों पर भी फिर से अधिकार करने का प्रयत्न न करने लगे। किन्तु अप्रैल १९४१ में रूस और जापान में मवि हो जाने से और उसी वर्ष जून में हिटलर के रूस पर आक्रमण करने से दूर पूरव में रूसी कार्रवाई का भय जाता रहा। इस घटना ने जापान की दिसम्बर १९४१ की महान् कार्रवाई के लिए रास्ता साफ कर दिया।

१९३९, १९४० और १९४१ में जापान और अमेरिका के कूटनीतिक सम्बन्ध लगातार बिगड़ते गये थे। १० जुलाई १९३९ को अमेरिका के विदेश मंत्री श्री कार्डेल हल ने वाशिंगटन में जापानी राजदूत से कहा कि अमेरिका सम्पूर्ण चीन और प्रशान्त सागर के द्वीपों के साथ वह व्यवहार नहीं देखना चाहता जो मचूरिया के साथ हुआ था। इस के साथ-साथ ही अमेरिका ने जापान पर प्रार्थिक दबाव डालना भी शुरू किया और अमरीकी वेडे का बहुत बड़ा भाग प्रशान्त सागर में भेज दिया गया। अगस्त १९४० में हवाई जहाजों के काम आने वाली अमेरिकन गेसोलीन और अनेक प्रकार के मशीनी औजारों का जापान भेजा जाना बन्द कर दिया गया और अगले महीने में लोहे और इसपात के टुकड़े का निर्यात भी बन्द कर दिया गया। २६ जुलाई १९४१ को प्रेजीडेन्ट रूज-वेल्ट ने सरकारी आदेश द्वारा अमेरिका में समस्त जापानी सम्पत्ति को जब्त कर लिया। इससे दो दिन पहले उन्होंने जापान से फ्रांसीसी हिन्द-चीन की

तटस्थता का आदर करने को कहा था। परन्तु जापानी सेनाएँ इस समृद्धिशाली उपनिवेश पर बराबर अधिकार जमाती गईं। १७ अगस्त १९४१ को चर्चिल के साथ एटलांटिक अधिकार पत्र के सम्बन्ध में बातचीत करने के फौरन बाद प्रेज़िडेंट रूजवेल्ट ने वार्शिंगटन स्थित जापानी राजदूत से यह साफ-साफ कह दिया कि यदि जापान ने बल-द्वारा या बल का भय दिखाकर पड़ोसी-देशों पर सैनिक अधिकार जमाने की नीति जारी रखी तो अमेरिका उचित अधिकारों और स्वत्वों की रक्षा के लिए तत्काल ही आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जायगा ।

वह तारीख शायद सबसे ज्यादा सगीन थी। जापान का जहाजी बेड़ा डच और ब्रिटिश साम्राज्यों के बड़े-बड़े नये प्रदेशों को हड़पने को तैयार बैठा था। हिन्द-चीन पर जापानी अधिकार का रूजवेल्ट की सरकार ने जो जबर-दस्त विरोध किया था उससे जापान समझ गया था कि यदि उसने किसी और देश पर विशेष रूप से बर्मा, सुमात्रा और मलाया सरीखे कच्चे माल के भण्डार और सैनिक महत्व के प्रदेशों पर आक्रमण किया तो उसकी अमेरिका में बड़ी गम्भीर प्रतिक्रिया होगी। अमेरिका का रुख दिन-पर-दिन अधिक लड़ाकू होता जा रहा था।

प्रेज़िडेंट रूजवेल्ट को आशा थी कि वह बातचीत द्वारा आक्रमण रोक सकेंगे। यह प्रयास प्रशंसनीय था। किन्तु उस समय अमेरिका के समुद्री बेड़े और थल-सेना में जो कमजोरियाँ थी, उनको ध्यान में रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि प्रेज़िडेंट रूजवेल्ट ने आवश्यकता से अधिक कूटनीतिज्ञता दिखलाई। जो कुछ भी हो, इसका निर्णय तो इतिहास ही करेगा कि अमेरिका को दो-चार महीने पहले युद्ध में डालने के लिए पर्ल हार्बर का सकट मोल लेना उचित था अथवा नहीं। जापान के लिए यह सम्भव नहीं था कि वह अपनी विस्तार-नीति का तिलाजलि दिये बिना और अन्त में, चीन में प्राप्त किये गये सारे प्रदेशों को त्यागे बिना रूजवेल्ट की माँगों को पूरा करता। जापानी साम्राज्य-वादी अपने-आपको ऐसे शान्तिपूर्ण कार्य करते देखने की कल्पना नहीं कर सकते थे। सन् १९४१ में उन्होंने इंग्लैण्ड के ही सदृश एक महान् साम्राज्य स्थापित करने का बड़ा अच्छा अवसर देखा। उनका विश्वास था कि बृहत्तर एशिया की चहारदीवारी में वे अजेय होंगे।

अतः जापान ने अमेरिका पर अचानक प्रहार कर उसकी जलसेना को पगु बर्बाद करने का निश्चय किया और उस समय की प्रतीक्षा करना ठीक नहीं समझा जब अमेरिका की सेनाएँ पहले से अधिक मस्त्र-सज्जित होकर स्वयं

युद्ध में प्रवेश करती। सन् १९४१ की गर्मियों में वाशिंगटन में जो बातचीत चली थी उससे जापान को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था कि अमेरिका का युद्ध में प्रवेश करना अनिवार्य है। जापान चाहता था कि उस अवसर पर अमेरिका को किसी भयानक विपत्ति का सामना करना पड़े। इसीलिए उसने पर्ल बन्दरगाह पर अचानक आक्रमण किया।

एक महान् साम्राज्य को जीतने और बनाये रखने की लालसा से जापान ने बर्मा और (शायद) भारत, टिमोर और (शायद) आस्ट्रेलिया फिलीपाइन, चेक और ग्वाम को घेरकर एक वृहद् वृत्त बनाने का आयोजन किया। जापान की आशा थी कि इन दूरस्थ छावनियों से महायत्ना पाकर और उनके द्वारा रक्षित रहकर वह लम्बे-से-लम्बे घेरे का सामना कर सकेगा। उसे यह बात सूझी ही नहीं कि अमेरिका उस वृत्त को पहली ग्वाडलकनाल के निकट काटेगा, और फिर लेटे में उसे भग करता हुआ अन्त में ओकिनावा में वह वृत्त के केन्द्र में जा घुसेगा और साथ-ही-साथ जापान पर भी उस समय तक बम, परमाणु-बम और गोले बरसाता रहेगा जब तक कि सम्राट् हिरोहितो हार मानकर आत्म-समर्पण न कर दे।

जापान ने रूस पर हिटलर के आक्रमण का अर्थ यही निकाला होगा कि हिटलर ने इंग्लैंड पर आक्रमण करने और उसे हराने में अपनी असमर्थता स्वीकार कर ली है। रूस पर आक्रमण करके हिटलर ने लडाई में अडगा लगाना चाहा था। उसने सोचा कि रूस पर अधिकार करने के बाद जर्मनी हराया नहीं जा सकेगा। उधर जापान के युद्ध में आजाने से ब्रिटिश और अमरीकी सेनाएँ यूरोप और एशिया में बट जायगी; जिससे जर्मनी का न हारना और भी निश्चित हो जायगा। इसके अलावा उसने सोचा कि अपराजित जर्मनी ब्रिटेन और अमेरिका की इतना अधिक सेनाएँ अपने में उलझाये रखेगा कि वे जापान को कुचलने में समर्थ नहीं हो पायेंगे। अतः जर्मन-युद्ध के अनिश्चित काल तक रुके रहने का अर्थ यह था कि जापान का युद्ध भी अनिश्चित काल तक रुका रहता।

रूस, यूरोप और प्रशान्त के क्षेत्रों पर घुरी राष्ट्रों का आधिपत्य होजाने से ब्रिटेन और अमेरिका की विजय रुक जाती। घुरी राष्ट्र समझते थे कि इन परिस्थितियों में बुरे-से-बुरा यही हो सकता है कि दोनों बराबर रहे। सम्भव है कि कुछ नाजियों और जापानियों ने अन्त में विजयी बनने के स्वप्न भी देखे हों।

घुरी देशों के इन अनुमानों में रूस और अमेरिका की शक्ति वास्तविकता से कम आकी गई।

इंग्लैण्ड से वापस आने के बाद के महीनों में दिये गये अपने भाषणों में मैंने बराबर औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, रूस को अधिक सहायता देने और शान्ति की रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। तब से मैं शान्ति पर ही जोर देता आया हूँ। यद्यपि मुझे युद्ध से घृणा है, फिर भी मैं युद्ध के पक्ष में था, क्योंकि मैं वास्तविक शान्ति चाहता हूँ और जानता हूँ कि जब तक शक्ति-गाली आक्रमणकारी देश कमजोर और छोटे देशों को अपना शिकार बनाते रहेगे तब तक ससार को वास्तविक शान्ति नसीब न होगी।

१९४२ के वसन्त में अमेरिका के पश्चिमी भागों का दौरा करते हुए मैंने जापानी हवाई आक्रमण के सम्बन्ध में बहुत लोगों में दयनीय घबराहट देखी। कुछ लोगों की मांग यह थी कि हमारी सेनाएं अमेरिका की रक्षा के लिए अमेरिका में ही रहनी चाहिए। धनी लोग सानफ्रांसिस्को, सीटल आदि नगरों को छोड़कर अरिजोना और नेवडा आदि सुरक्षित स्थानों में जा रहे थे। मैंने अपने श्रोताओं से कहा कि केवल ५ सेंट में मैं युद्ध-काल के लिए शत्रु-बम से मृत्यु अथवा हानि के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति का भारी रकम के लिए बीमा करा सकता हूँ।

सानफ्रांसिस्को के पत्रों ने मेरे १२ फरवरी को दिये गये एक भाषण का निम्नलिखित उद्धरण छापा था—“युद्ध के अन्तिम परिणाम (विजय) के सम्बन्ध में मैं आशावादी हूँ, किन्तु मुझे यह महसूस नहीं होता कि हम अभी युद्ध कर रहे हैं। युद्ध के लिए अभी सैनिकों और कारखानों का ही सगठन हुआ है, नागरिकों का नहीं। नागरिकों को चाहिए कि वे सरकार के ऐसा करने से पहले ही स्वयमेव अपने रहन-सहन के मान को घटा दें।”

यूरोप में पड़ी हुई पुरानी आदत के अनुसार मैंने जहाँ भी सम्भव हुआ कारखानों का निरीक्षण किया। सीटल में मैंने एक वायुयान बनाने के कारखाने में पूरा एक दिन लगाया। टकोमा और पोर्टलैंड में मैंने जहाज-निर्माण के केन्द्रों को देखा। मैंने जो कुछ देखा वह उत्साह-वर्द्धक था। ७ मार्च १९४२ का मैंने “नेशन” पत्र में निम्नलिखित सम्वाद भेजा : “एक ही महीने में एक बहुत बड़े कारखाने में, जो शायद युद्ध का सबसे अधिक प्रभावशाली आधुनिक-शस्त्र तैयार कर रहा है, उत्पादन में ७० प्रतिशत की वृद्धि हुई है।” यह संकेत, जो उस समय आवश्यकतानुसार गोपनीय रखना पड़ा था, बोइंग प्लानिंग फोर्ट्रेस पैक्टरों की ओर था।

मैंने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा था—“पल हार्वर ने लोगों में जोश भर दिया है। कारखानों के कर्मचारी युद्ध-सम्बन्धी दैनिक विज्ञप्तियों को पढ़ने

के कारण यह संभव गये हैं कि हर रोज वे जो काम करते हैं उसका प्रभाव युद्ध के मोर्चे पर पड़ता है।”

अलग-अलग काम करने वाले गोला-बारूद के कारखानों के व्यवस्थापकों की भी यही प्रतिक्रिया थी। जब मैंने उनमें पूछा कि आपकी क्या शिकायत है तो उन्होंने उत्तर दिया—“कागज, वाशिंगटन जानकारी चाहता है, स्टेट भी यही जानकारी चाहती है, हल्के पैदल वाले और अविश्वसनीय बातें जानना चाहते हैं, फिर वाशिंगटन का कोई और विभाग उन्हीं आकड़ों के लिए तार भेजता है जो उसके पास वाले विभाग ने पहले ही इकट्ठे कर लिये हैं। यह सब अनवरत रूप से चलता रहता है।”

एक कारखाने में एक अफसर ने एक वनती हुई इमारत की ओर इशारा किया। वह बोला—“इसमें कई सौ पहलवान काम करेंगे और दफ्तरों की विलम्बकारी आदत से युद्ध लड़ेंगे।” मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे मैं यह निश्चित रूप से पता लगा सकता कि यह शिकायत ठीक थी या नहीं। किन्तु इसमें संदेह नहीं कि केन्द्रीय और स्थानीय दफ्तरों में ऐसे अनेक बातूनी और सवाल-जवाब करने वाले लोग थे जिनसे कारखाने वालों में क्रोध उत्पन्न होता था और उत्पादन-कार्य में रुकावट भी पड़ती थी।

“अनुपस्थिति” सारे राष्ट्र के लिए सिर दर्द बन गई थी और इसके कारण कारखानेदारों को श्रमजीवियों की मार-घाट का अवसर भी अच्छा प्राप्त हुआ था। मैंने भिन्न-भिन्न औद्योगिक केन्द्रों से कुछ आकड़े इकट्ठे किये थे। अनुपस्थित रहने वालों में अधिकतर बच्चों की माताएँ थीं। रक्षा सम्बन्धी काम करने वाले बहुत से लोग दूर के प्रान्तों से आये हुए थे। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाता तो माँ के काम पर चले जाने पर उसकी देख-रेख करने के लिए दादी, मौसी, भतीजी आदि कोई भी नहीं थी। जिनके पास रहने का स्थान नहीं था वे लोग स्वयं एक समस्या बन गये थे। घर, खाने-पीने की वस्तुओं एवं फर्नीचर आदि की खोज में मजदूर अक्सर काम से गैरहाजिर रहते थे। अनुपस्थिति का एक कारण मजदूर लोगों का एकाएक सम्पन्न हो जाना भी था, जिसके फलस्वरूप मदिरा-पान और फिजूलखर्ची फैल गई और युद्ध-कालीन विषमताओं से आचरण में भी शिथिलता आ गई। बड़े शहरों की सड़कों पर प्रातःकाल विखरी हुई ह्विस्की की खाली बोतलों को देखकर यह पता चल जाता था कि उस दिन-युद्ध संधी कारखानों में बहुत से लोग अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहने वाले व्यक्ति जान-बूझकर हानि पहुँचाना चाहते थे सो तो नहीं; वस्तुतः उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी। एक कारखाने में मजदूरानियों के

बच्चो के लिए शिशु-केन्द्र खोलते ही अनुपस्थिति बहुत कम हो गई थी ।

सब लोगो का ध्यान ऊँचे वेतनो पर था । मैने सैनिको और धनी नागरिको को कहते सुना : “यदि युद्ध-क्षेत्रमे लडने वाला व्यक्ति २१ डालर प्रति मास के पीछे २४ घटे का नौकर बनकर अपने जीवन के लिए खतरा मोल लेता है, तो कारखानो मे काम करने वालो को ४० या ५० डालर प्रति सप्ताह क्यो दिये जाय । मशीनो की खड-खडाहट और तेज टाचों के प्रकाश के बीच मैने युद्ध का कार्य करने वाले मजदूरो से यह प्रश्न किया—पतलून पहने और लिप-स्टिक लगाये हुए एक सुन्दर लड़की ने उत्तर देते हुए कहा—“अगर हमारा मालिक लाखो कमाता है और सरकार द्वारा मुनाफाखोर घोषित किये जाने का खतरा उठाता है, ताँ मै भी इतनी अच्छी मजदूरी को क्यो न लूँ कि बढे हुए नये दामो पर अपनी आवश्यकता की चीजे आसानी से खरीद सकूँ ?” बोझ उठाने की मशीन पर काम करने वाले एक व्यक्ति ने कहा —“जब मालिक २१ डालर मासिक लेगा तो मै भी इतना ही लूँगा” पास ही से एक और कारीगर ने चिल्लाकर कहा “मै छुट्टी के दिनों की तनखाह छोड दूँ तो क्या वह मैकार्थर के सिपाहियो के पल्ले पडेगी ? नही, वह तो कम्पनी के मालिको की ही जेबो मे जायगी ।” लडाई के दिनों मे अमेरिका के लोगो मे त्याग की दृष्टि से समानता नही थी ।

अमेरिका के पश्चिमी भाग के हुल्लडवाजो की खूब वन आई थी । उनमे से बहुतो का खयाल था कि वे श्रीमती रूजवेल्ट पर आक्षेप करके या अमेरिका मे पैदा हुए जापानियो के अमरीकी बच्चो को देशनिकाला देकर युद्ध जीत लेंगे । मेरी उन स्त्रियो से बातचीत हुई जिन्हे आशका थी कि ट्रक चलानेवाले जापानी किसान मज्जियो मे विष मिला देगे । मुझे बताया गया कि तटवर्ती क्षेत्रो से जापानियो को हटा देना चाहिये, क्योकि इस बात का भय था कि हवाई आक्रमण से क्रुद्ध होकर अमेरिकावासी कही उन्हे मार न डालें । सनसनी फैलाने वाले अखबारो ने पुकार उठाई कि सारे जापानी नजरबन्द कर दिये जाय । एक्के-दुवके हमलो की सख्या भी बढनी गई । कोई क्राइस्ट-जैसा व्यक्ति कैलिफोर्निया मे कह सकता था—“पहला पत्थर उसी को फेकने दो जिसने अपने माता-पिता को चुन लिया है ।”

कैलिफोर्निया मेलोग मुझे बडे निरुत्साह-दिखाई दिये । “दूर पूरव के विशेषज्ञो” ने भविष्यवाणी की थी कि हम “जापानियो को तीन सप्ताह में मार गिरायेगे ।” जब नागरिको को पता लग गया कि यह भविष्यवाणी कितनी मूर्खतापूर्ण थी तो उनमें हास्यास्पद आत्मभिमान के बदले अनावश्यक निराशावाद

की भावना जाग उठी ।

फिर भी, उत्पादन लगातार बढ़ रहा था । मैंने ३ मार्च को मिल्वौकी में एक भाषण देते हुए कहा —“अमेरिका की मोटर अब चलने लगी है ।” मैंने इस बात का विस्तारपूर्वक उल्लेख किया कि हम जिस शान्ति की स्थापना करेंगे वह “प्रतिकारात्मक होगी दण्डात्मक नहीं ।” मैंने आगे चलकर यह भी कहा “सच्चा जनतंत्र ही शान्ति का एकमात्र मार्ग है, किंतु इसका आज तक किसी भी महान् युद्ध के बाद प्रयोग नहीं किया गया ।

११ मार्च, १९४२ को सेंट पाल के एक डिस्पैच में मेरे भाषण का निम्नलिखित उद्धरण दिया गया—“यह जान लेने पर कि मैं इंग्लैंड को पराजित नहीं कर सकता; हिटलर ने इंग्लैंड पर विजय पाने के बदले रूस पर आक्रमण करना ठीक समझा ...। यह अब मित्रराष्ट्रों का काम है कि वे रूस को युद्ध में लगाये रखे । इच्छा से या अनिच्छा से अब स्टालिन इस युद्ध में ‘फरिस्ते’ की ओर से लड़ रहा है और अगर ‘फरिस्ते’ जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वे युद्ध में कूद पड़े और रूस की सहायता करें । रूस को सहायता, अधिक सहायता की आवश्यकता होगी ।”

१५ मार्च को मैंने लूइसविले (केटकी) में एक सार्वजनिक सभा में कहा था—“रूस इस युद्ध का मुख्य आधार है और भारत शान्ति का प्रतीक है ।” मैंने यह भी कहा कि यद्यपि इस समय लाल-सेना ने हिटलर को रोक लिया है फिर भी उसमें अभी लड़ने की पर्याप्त शक्ति शेष है ।

इस बीच दूर पूरब में जापानी तेजी से आगे बढ़ रहे थे । इस पर अपना मत प्रकट करते हुए मैंने कहा—“बर्मा और मलाया के हमारे हाथों से निकल जाने का एक कारण तो अस्त्र-शस्त्रकी कमी थी और दूसरा अंगरेजों की साम्राज्यवाद सम्बन्धी प्रतिगामी विचार-धारा । ब्रिटेन की कमजोरी का कारण यह है कि बौद्धिक दृष्टि से ब्रिटिश सरकार आधुनिक समय से एक पीढ़ी पीछे है । चर्चिल के व्यक्तित्व में सभी शताब्दियों का सम्मिश्रण विद्यमान है सिवा बीसवीं सदी के ।” मैंने अमेरिकन सरकार से आग्रह किया कि वह भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने में सहायता दे । कारण, “हो सकता है हम युद्ध तो जीत लें, किंतु शान्ति हमारे हाथ से निकल जाय । मैं इस बात को उठती हुई सभ्यता के लिए एक लाछन समझता हूँ कि प्रत्येक देश में लोगो को शान्ति के प्रति सन्देह है और उन्हें आशंका है कि शान्ति चिरस्थायी नहीं होगा । वर्साई की सन्धि में उन बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को नहीं सुलझाया गया जिनके कारण युद्ध उत्पन्न हुआ था । इसी

प्रकार की सन्धि हम अब भी स्थापित कर सकते हैं, किन्तु यदि हम ऐसा करेंगे तो, हमें एक और युद्ध लड़ना पड़ेगा।”

रूसी सेना उस समय जर्मनी द्वारा हड़पी गई रूसी भूमि का पाँचवाँ भाग ही मुक्त कर पाई थी। फिर भी अमेरिका में रूस के प्रति भय की भावना बढ़ती जा रही थी। न्यूयार्क के पी० एम० नामक पत्र ने मुझसे “क्या अमेरिका के लिए विजयी रूस स डरने का कोई कारण हो सकता है” शीर्षक लेख लिखने को कहा। उस लेख का परिचय कराते हुए फ्रीडम हाऊस के सभापति हर्बर्ट आगर ने लिखा था—“कुछ अमेरिकन यह गुप्त रूप से चाहते हैं कि रूस हार जाय, या, कम-से-कम, रूसी-जर्मन मोर्च पर युद्ध लम्बा पड़ जाय।”

मैंने “पी० एम०” के २७ अप्रैल १९४२ वाले अंक में लिखा “विजयी रूस से अमेरिका को क्या डर हो सकता है? कम्युनिस्ट-क्रान्ति का? यह खयाल हास्यास्पद है। अमेरिका के कम्युनिस्ट मुठ्ठी भर हैं और घृणा की दृष्टि से देखे जाते हैं। जब उन्होंने प्रजातन्त्री स्पेन के सहायतार्थ कुछ किया था तब उनका प्रभाव पड़ा था, या अब जब वे पूँजीवादी अमेरिका की रक्षा और रूस को सहायता पहुँचाने के लिए प्रयास करते हैं तो उनका थोड़ा-बहुत प्रभाव दिखाई देता है। किन्तु यदि वे अमेरिकन सरकार को उलटने का प्रयत्न करें तो वे एक रेजिमेंट भी नहीं जुटा पायेंगे”। यदि क्रान्ति का भय नहीं तो क्या रूस द्वारा आक्रमण का भय है? क्या विजय प्राप्त करने के बाद रूस अमेरिका पर आक्रमण कर सकता है? यह एक मज्जाक की-सी बात मालूम देती है..। रूस के प्रति भय की भावना उभारने के बजाय, हमें इस बात पर जोर देना चाहिए कि हिटलर को (और इसलिए जापान को भी) पराजित करने में अभी तक सबसे अधिक सहायता रूस ने दी है। हमारा ध्येय रूस को अधिक मजबूत बनाना होना चाहिए।”

मैंने इस लेख के अंत में दो शब्द चेतावनी के रूप में भी लिखे, किन्तु “पी० एम०” ने उसे छपा नहीं। उसने मेरा केवल यह वाक्य प्रकाशित किया—“बहुत कुछ इस बात पर निर्भर होगा कि युद्ध समाप्त होने पर हमारी और रूस की कैसी मनोदशा है।” इसके बाद के जो तीन वाक्य निकाल दिये गये थे वे ये थे—“अगर हम साम्राज्य स्थापित करना या दूसरे देशों को हड़पना या गाने सभार में एक मात्र एंग्लो-अमेरिकन नेतृत्व का ही झंडा फहराना चाहेंगे तो हमारे देश हमारा उतना ही विरोध करेंगे जितना शायद हम रूस का करें यदि उसका प्दोत्तर नीति दूसरे देशों को हड़पने की हो। रूस अपनी नीमाग्रो

के भीतर बलात् दूसरे राष्ट्रों को खपाकर अपने को सुरक्षित नहीं समझ सकता, ठीक वैसे ही जैसे हम ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी साम्राज्यों का सिरदम मोन लेकर अपने को सुरक्षित नहीं समझ सकते। ऐसी कार्रवाई का परिणाम अधिक कष्ट और अधिक युद्ध ही हो सकता है।”

पता नहीं, ये पवित्रता किसने निकाली। मूर्ख लोग समझते हैं कि किसी समस्या को हल करने का तरीका उसे छिपाना और उसकी अवहेलना करना है। असल में वाशिंगटन के उच्चाधिकारियों में रूस की युद्धोत्तर नीति के सम्बन्ध में चिंता दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही थी। ह्वाइट हाउस को पता लगा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री ईडन से बातचीत के दौरान में स्टालिन ने यह घोषणा की कि वह बाल्टिक राष्ट्रों और पूर्वी पोलैण्ड को रूस में मिलाना चाहते हैं। अमेरिका के लंदन-स्थित राजदूत जॉन जी० विनेट ने, जिनसे इंग्लैंड में मेरी कई बार घनिष्ठता के साथ बातचीत हुई, मुझे २५ अप्रैल को न्यूयार्क के रुजवेल्ट होटल के अपने कमरे में बिलकुल गुप्त रूप से बताया कि हम कर्जन लाइन तक की समस्त पोलिश भूमि को अपने में मिला लेगा, किन्तु रुजवेल्ट युद्ध-काल में इस प्रकार के सीमा-परिवर्तन नहीं चाहते। इस का मतलब यह था कि अमेरिका रूस की विस्तार-नीति का विरोध करने को तैयार था? मित्र-राष्ट्र, जो युद्ध में विजय के लिए एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, युद्ध के बाद लाभ उठाने के लिए चालें चल रहे थे।

आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की अन्तर्राष्ट्रीय विषयो की परिषद् (रायल इस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स) में मैंने १९४१ में अपने इंग्लैंड-प्रवास के समय एक भाषण दिया था। उस समय पेरिस-शान्ति-सम्मेलन के एक सुयोग्य इतिहासज्ञ ने मुझसे कहा था—“युद्ध के बाद इंग्लैंड अमेरिका का छोटा सा भीदार बन जायगा, किन्तु मुझे इसकी चिन्ता नहीं।” रायल इस्टीट्यूट में काम करने वाले उनके दो सहयोगी भी उनमें सहमत थे। उनमें से एक ने कहा—“अमेरिका और रूस के बीच ब्रिटेन मध्यस्थ का काम करेगा।” दूसरे ने राय दी कि शायद अनुदारदल वाला ब्रिटेन राष्ट्रवादी रूस से गठबन्धन कर ले, जिसके परिणाम-स्वरूप यूरोप दो हिस्सों में बँट जायगा। इस पर इतिहासज्ञ ने कहा—“किन्तु यूरोप में रूस के साथ हम अकेले शायद सुखी न रहे।”

जब मैंने अमेरिका के विदेश विभाग के एक अधिकारी से इस बातचीत का उल्लेख किया तो उसने इतना ही कहा—“युद्ध के बाद अमेरिका रूस से कम शक्तिशाली नहीं होगा।” १९४२ में मित्र-राष्ट्रों की विजय आरम्भ तो नहीं हुई थी किन्तु अमेरिका की बढ़ती हुई शक्ति और रूस की दूसरे देशों को

हटने की प्रत्यक्ष लालसा के कारण तीन महान् राष्ट्रों में युद्धोत्तर दलबन्दी की सम्भावना पर अच्छे खासे वादविवाद होने लगे थे ।

अमेरिका और पेटा-कालीन फ्रांस का सबध भी काफी वादविवाद का विषय बन गया था । मैंने वाशिंगटन में एक कूटनीतिज्ञ से कहा—“देश भर का भ्रमण करने से मुझे पता चला है कि हमारे नवयुवक खूशी-खुशी सेना में भरती हो रहे हैं, वे अच्छा काम करेंगे । किन्तु प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, इसीलिए उनमें उत्साह नहीं है । उनमें से बहुत ही कम इस बात को जानते हैं कि यह सहाई क्यों लड़ी जा रही है । लोगों की समझ में नहीं आता कि हिटलर को सहयोग देने वाला विची (फ्रांस) सरकार से हमारी मित्रता क्यों है ? ‘हम क्यों लड़ रहे हैं’ यह प्रश्न प्रायः सभी जगह पूछा जाता है । यदि हम फ्रांस की विची सरकार से नाता तोड़ ले और फ्रांस, स्पेन तथा भारत के प्रति स्पष्ट रूप से फाशिस्ट-विरोधी नीति ग्रहण करें, तो हमारे उद्देश्य स्पष्ट हो जायेंगे और जन-साधारण को विश्वास हो जायगा कि रूजवेल्ट और नॉचिल ने ऐटलांटिक अधि-कार-पत्र में जो कुछ लिखा है वही उनका करने का इरादा भी है ।”

अमेरिका के शासनाधिकारी यह जानते थे कि अमेरिका की फ्रांस सबध नीति से जनता चिढ़ी हुई है । प्रवक्ता यह स्वीकार करते थे कि अब फ्रांसीसी समूही वेडे जर्मनी के हाथों में पड़ने का खतरा नहीं रहा । पहले वे इसी वेडे के भविष्य के सबध में चिन्ता प्रकट कर विची सरकार के प्रति अपनी नीति का समर्थन करते थे । “किन्तु मान लीजिये हम फ्रांस की भूमि से आक्रमण करना चाहते हैं और वहाँ हमारे एजेंटों के महत्त्वपूर्ण सम्पर्क हैं, तब क्या हमें उन सम्पर्कों को नष्ट होने देना चाहिए ?” यह बात रूजवेल्ट के एक सलाहकार ने मुझसे वाशिंगटन में सन् १९४२ के वसन्त-काल में पूछी ।

राजदूत विनेट ने मुझे बताया कि ब्रिटिश सरकार को, जिसका फ्रांस की पेटा-सरकार से कोई सबध नहीं था, यह आशा थी कि हम फ्रांस से अपने सबध बनाये रखेंगे ।

किसी भी देश के विदेश विभाग की मनोवृत्ति का पता इस बात से लगता है कि उसके अधिकारियों को यह खयाल बना रहता है कि वे दूसरे देशों के साथ सबध बनाये रखने और सुधारने और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के “कारदार” में लगे हुए हैं । (ऐसा ही मैंने उन्हें कई बार कहते सुना है) यही कारण है कि जब किसी देश से सबध-विच्छेद का प्रस्ताव आता है तो कूटनीतिज्ञ उसका तीव्रता से विरोध करते हैं और उस समय वे सिद्धान्तों की चिन्ता नहीं करते और न यही ध्यान रखते हैं कि उसका जनता की नैतिकता

पर क्या प्रभाव पड़ेगा ।

पर्ल हार्बर के धक्के से धीरे-धीरे सम्भलते हुए अमेरिका के विचारणीय व्यक्तियों ने सन १९४२ में यह सोचना आरंभ किया कि आखिर यह युद्ध लड़ा किसलिए जा रहा है । जापान, जर्मनी और इटली को पराजित करने के लिए ? निश्चय ही । किंतु, क्या इतना ही काफी है ? विजय के बाद क्या होगा ?

अमेरिका की सबसे बड़ी अदालत के सहकारी न्यायाधीश, फेलिक्स फ्रैंकफर्टर के सामने मैंने अमेरिकन जनमत के मन्त्र में अपनी राय मन्त्र में इस प्रकार प्रकट की—“देश युद्ध का अर्थ समझने के लिए अटकलें लगा रहा है । अन्त में अमेरिका को आदर्शवादी शान्ति और साम्राज्यवाद में किस एक बात को अपनाना पड़ेगा । जब जनता को हमारी महान् शक्ति का पता चल जायगा तो सम्भव है वह नवीन प्रदेशों पर अधिकार करना चाहे । रूस की विस्तार नीति के कारण मुझे एक चिन्ता यह भी है कि कहीं ऐसा न हो कि हम भी उसी मार्ग का अनुसरण करने की ठान बैठें । दूसरा रास्ता यह है कि हम प्रभाव के सभी केन्द्रों, साम्राज्यों और उच्च व्यापारिक मूल्यों के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से फाशिस्ट विरोधी नीति ग्रहण करें और एटलांटिक अधिकार-पत्र का ईमानदारी के साथ पालन करें । यही कारण है कि फाशिस्ट समर्थक विचार सरकार से हमारा सम्बन्ध बनाये रखना लोगों को अखरता है और उन्हें भारत से दिलचस्पी होती है ।” (इस पर जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने क्या कहा यह बतलाने की मुझे स्वतन्त्रता नहीं ।)

उन दिनों भारत के समाचार पहले पृष्ठ पर छपा करते थे । जापान बर्मा में प्रवेश कर चुका था । जर्मनों के तुर्की पर आक्रमण करने व मिस्र को जीतलेने की भी सम्भावना थी । युद्ध को जीतने का घुरीराष्ट्रों के लिए एक ही तरीका था और वह यह कि एशिया में किसी स्थान पर सम्भवतः भारत में जर्मन और जापानी सेनाएँ एक दूसरे से आ मिलें । भारत में राजनीतिक आन्दोलन जोरो पर था । प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने युद्ध के भूतपूर्व सहकारी मंत्री कर्नल लुई जॉनसन को अपने विशेष दूत के रूप में नई दिल्ली भेजा था । ब्रिटिश सरकार ने भी सर स्टैफर्ड क्रिप्स को, जो पहले मास्को में ब्रिटिश राज-दूत थे और अब ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में हैं, लिखित प्रस्ताव देकर भारत भेजा था । भारत के सभी दलों ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया था । अब क्या होगा ? क्या जापान भारत पर आक्रमण करेगा ? क्या हिटलर निकट पूरव में घुस पड़ेगा ?

बृहस्पतिवार २२ अप्रैल को मैंने श्री समनर वेल्स से कहा कि मैं भारत जाना चाहता हूँ । उन्होंने अपने पैड पर पेंसिल से कुछ लिखा और ठीक एक सप्ताह बाद मुझे न्यूयार्क में टेलीफोन द्वारा बताया—“अगर आप तीन दिन के भीतर-भीतर टीका आदि लगवाकर अपनी तैयारी कर ले तो रविवार को न्यूयार्क से जानेवाले वायुयान में आपको जगह मिल सकती है ।” मैंने इस पर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और पासपोर्ट माँगा । उन्होंने पासपोर्ट उसी शाम को डाक द्वारा भेजने का वादा किया, जो अगले दिन सवेरे मुझे मिल गया । मैं व्यर्थ के सवाल, आवेदन-पत्रों और दफतरो की झिंक-झिंक से बच गया । मैंने तुरन्त ही हैजे, टाईफाइड, पीतज्वर, चेचक आदि के टीके लगवा लिये, और सोमवार ३ मई को हवाई जहाज से रवाना हो गया । (उसी दिन मेरे दोनों बेटों का जन्मदिन था ।) मैंने बहुत प्रमोद और मनोरंजन की आशा की थी, किंतु मेरे पास जितना समय था उसको दृष्टि में रखते हुए मेरी आशाएँ कम पूरी हुई ।

भारत की ओर

वायुयान में ५० व्यक्ति थे । इनमें कुछ तो अमेरिका के इंजीनियर थे, जो भारत में अवरोध के उत्पादन को बढ़ाने जा रहे थे—जिसकी अमेरिका को युद्ध-कार्य के लिए आवश्यकता थी । इनके अलावा अमेरिकन अफसर थे जो चीन में चीनी हवाई-सेना को संगठित करने जा रहे थे, और कुछ अमेरिका के विदेश विभाग के कार्यकर्ता थे, जो मुहर बन्द डाक के थैले लिये हुए थे, जिनसे वे कभी जुदा नहीं होते थे । हमारे साथ एक अमेरिकन दम्पति भी था जो तीन साल पीत-ज्वर से युद्ध करने ब्रिटिश पूर्वी अफ्रीका जा रहे थे । उसी विमान में एक पोलिश कूटनीतिज्ञ भी विराजमान थे जो मिस्र और रूस के रास्ते चीन जा रहे थे । म्यामी में हमारे साथ कई लैटिन-अमेरिकन और अमेरिकन सैनिकों का एक दल भी आ मिला जो अफ्रीका गोल्ड कोस्ट पर स्थित अमेरिकन सैनिकों के लिए खजाची का काम करने जा रहा था ।

अगले दिन सवेरे हमारा हवाई जहाज सान जवान (पोर्टो रीको) पर उतरा । मैंने टापू के गवर्नर रेक्सफर्ड जी० टगवेल को टेलीफोन किया जिनसे मैं पहले मास्को में मिला था । वह मेरे पास आये और हवाई जहाज के रवाना होने तक लगभग एक घंटा हम बातचीत करते रहे । प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने निजी परीक्षणों की धुन में ही घिबत्सघ में से टगवेल को पोर्टो रीको का गवर्नर 'नेशन' के प्रबन्ध सम्पादक अन्रंस्ट ग्रूनिंग को अलास्का का गवर्नर और "न्यूरिपब्लिक" के एक सम्पादक राबर्ट मार्स लोवेट को वर्जिन टापुओं का गवर्नर नियुक्त किया होगा । शायद इसके उत्तर में रूजवेल्ट मुझसे कहते—“जो काम दूसरे करते हैं उसकी तो टीका टिप्पणी कर दी । अब आप स्वयं उस काम को कीजिये और देखिये कि वह आपको कितना पसन्द आता है ।” मैं जानता हूँ ग्रूनिंग को अपना काम बहुत पसन्द था । सम्पादन या सिद्धांत निर्धारण का कार्य करने की बजाय व्यावहारिक शासन कार्य करने के कारण टगवेल, ग्रूनिंग और लोवेट की उदार विचार-धारा में कोई परिवर्तन नहीं आया और वे अनुदारदलो नहीं बने । वास्तव

राजनीति से सम्बन्ध रखने वाले दुराचारों के ज्ञान से और उन दूषित प्रभावों का पता होने के कारण जो राजनीतिज्ञों पर प्रायः डाले जाते हैं, शासनसत्ता के प्रति उनका आलोचनापूर्ण दृष्टिकोण परिपुष्ट होगया।

जब हमारा हवाई जहाज सुरिनम के ऊपर उड़ रहा था तो हम पीकर खेल रहे थे और उस डच उपनिवेश की रक्षा करने वाले अमेरिकन सिपाहियों के बारे में बातें कर रहे थे। सुरिनम में ऐसे घने जंगल हैं जिनके बीच से होकर गुजरना सम्भव नहीं। किन्तु ऊपर से ऐसा जान पड़ता था मानो सुरिनम सैंकड़ों मील लम्बा, साफ-सुथरा सुरक्षित जंगल है जिसमें कहीं-कहीं भरने के किनारे फूस की भोपड़ियाँ बनी हुई हैं और कहीं-कहीं एक लाल छत के मकान के चारों तरफ, जो शायद एक जागीर है, बहुत-सी भोपड़ियों का एक घेरा-सा बना हुआ है। वायुयान पर एक ब्राजीलियन भी था जिसने अमेरिकन हवाई सेना के लिए अड़ों की खोज में सारा दक्षिणी अमेरिका छान रखा था और जिस प्रदेश के ऊपर से हम जा रहे थे वह उसके जलथल के एक एक भाग से परिचित था। उसने बताया कि वास्तव में जंगल बहुत साफ है। उसमें घास फूस कम है और जंगल जानवर बहुत कम हैं। चीते, जगौर, प्यूमा, जंगली बिल्लियाँ आदि तो इक्के-दुक्के हैं; किन्तु जंगली पक्षी और छोटे-बड़े साप अनगिनत हैं। यहाँ के बन्दर इतने छोटे होते हैं कि आसानी से आदमी की हथेली पर बैठ सकते हैं। बड़े-से-बड़े बन्दर दो फिट ऊँचे होते हैं।

हमारे अगले पड़ाव बेलम (ब्राजील) का रास्ता अभी ४५ मिनट का शेष रह गया था कि हवाई जहाज की चार मोटरों में से एक बंद होगई। हवाई जहाज के तीन पक्षों को स्थिर देखकर हमें बड़ी चिंता हुई किन्तु यात्रियों में से एक व्यक्ति, जो हवाई जहाज की मरम्मत आदि करता था, बोला कि यदि हवाई जहाज के दो ही मोटर काम करते हों तब भी वह ठीक से उतर सकता है। हूप पारा नदी पर उतरे। उस समय वर्षा हो रही थी। गरम देशों की सन्ध्याकालीन अधियारी में चालक का पथ-प्रदर्शन करने के लिए हवाई जहाज में जो सर्चलाइट लगा हुआ था उसके प्रकाश में वर्षा की धाराएँ चांदी जैसी रंग दिखाई देती थी।

बेलम में हम पांच दिन ठहरे। इस बीच में मोटर की मरम्मत भी हो गई। बेलम पारा राज्य की राजधानी है। वह भूमध्य रेखा से १०० मील दक्षिण की ओर स्थित है, किन्तु मई में भी वहाँ गरमी न थी। रातें सुखद और ठीकी थी और सोते समय चादर तथा कम्बल ओढ़ना पड़ता था। वहाँ सवेरे गरमी बढ़ने से पहले ही बादल छा जाते हैं और सूर्य को ढक लेते हैं। प्रायः दिन भर

हवा मन्द-मन्द चलती रहती है। दोपहर समाप्त होते-होते वर्षा का भय होने लगता है। जितने दिन हम वहां रहे हर रोज़ वर्षा हुई। इस पर जब मैंने पूछा कि क्या यह बरसात का मौसम है तो मुझे बताया गया कि "नहीं, बरसात तो जनवरा में आरम्भ होता है"। वह तो ख़ुश्की का मौसम था।

जिन कीड़ो-मकोड़ो को मैं अमज़ोनिया से अभिन्न समझता था वे वहां देखने में नहीं आये। बेलम में मुझे एक मच्छर भी दिखाई नहीं दिया। चिडिया-घर में मैंने चींटियों को खाने वाले जानवर देखे पर चिडियाँ और मक्खियां वहां उतनी ही कम दिखाई दी जिनकी अमेरिका के शहरों में दिखाई देती हैं। वहां के पार्कों में उड़ने वाले और रेंगने वाले कोड़े भी नहीं थे।

जिस बात से मुझे सबसे अधिक आश्चर्य हुआ वह थी वहां की प्राचीन और गौरवपूर्ण सभ्यता। अज्ञानवश मैं समझा करता था कि वहां की बस्ती में बड़ी गरमी होगी और बामो के सहारे खड़ी फूँफू की भोपड़िया-ही-भोपड़िया होगी। पारा की नींव फ्रांसिस्को काल्डीरो काम्टीलो ब्राको नामक पुर्तगाल नाविक ने सन १६१५ में बड़े दिन से एक दिन पहले रखी थी। (यह बात मुझे एक गाइड बुक से मालूम हुई जिसमें शहर का पूरा विवरण दिया हुआ था।) वहां एक बड़ा गिरजाघर है। पत्थर के कई छोटे-छोटे गिरजाघर हैं और बहुत से स्कूल तथा सार्वजनिक भवन। इसकी चौड़ी सड़कों पर काटे हुए गोल पत्थर बिछे हैं और पगडंडिया सीमेंट की बनाई हैं। नगर में टूँलिया और बसे भी चलती हैं। ज्यादातर सड़कों के दोनों तरफ घने वृक्ष हैं जिनकी ऊपर की पत्तियां एक दूसरे से मिल जाती हैं और उनके कारण छाया रहती है। वहां पीछे इतनी जल्दी और आसानी से उगते हैं कि वृक्षों की छाल से ही कोपले फूट पड़ती हैं।

हमबोल्ट, अगासीज और मार्टीन्स आदि प्रसिद्ध पर्यटकों ने अमेजन क्षेत्र में बेलम को ही अपने पर्यटन और ढूँढ-खोज के लिए केन्द्र बनाया था। बेलम आजकल फोर्ड के रबड़ के बगीचों के लिए बन्दरगाह का काम करता है। ये बगीचे पारा नदी से ऊपर की ओर छः सौ मील दूरी पर हैं। अमेरिका के वाइस-कौंसल, हार्ट के कथनानुसार इन बगीचों में काम करने वाले अमेरिकन मज़दूरों को बगीचों व जंगलों के बीच रहते हुए भी घर के सारे सुख उपलब्ध हैं।

अमेज़ोनिया किमी समय रबड़ की जननी थी। किन्तु वहां रबड़ की खेती की ओर से बड़ी लापरवाही दिखाई गई। ब्राजीलियों का कथन है कि रबड़ के बीज के निर्यात पर कड़ा सरकारा प्रतिबन्ध होने पर भी "एक साहसी अंग्रेज" वहां से ७०,००० बीज ले भागा। ये बीज सबसे पहले लंदन के क्यू गार्डन में बोये गये और वहां से उखाड़कर पोषे मलाया, सुमात्रा, जावा, लंका आदि

रधानो में व्यावसायिक दृष्टि से लमाये गये । आज अमेरिकन पूजीपतियों की सहायता से ब्राजील रबड के ससार में फिर पाँव जमाने की चेष्टा कर रहा है ।

हुजे और पैरा-टाइफाइड के जो टीके मुझे लगवाने रह गये थे उन्हें लगाने के लिए डा० आरलेण्डो लीमा आये । “निकर पहने हुए ये कौन आदमी है”, उन्होंने मनोरजन के भाव से पूछा । डाक्टर बढिया सफेद सूट और नेक-टाई आदि पहने हुए थे । वह उत्तरी अमेरिका के रहने वालो की त्रिचित्र सम-भते थे । बेलम में मैं निकर पहने हुए था और न्यूयार्क में डा० लीमा ने मुझे आस्तीन ऊपर चढाए हुए और जाकट उतारकर कन्धो पर रखे ले जाते हुए देखा था । पहले दिन शाम को मैं होटल के खाने के कमरे में बिना जाकट के चला गया । हैड वेटर ने, जो सफेद और काला सूट पहने हुए था, नम्रता-पूर्वक यह कहकर कि हम खाली कमीज पहने हुए लोगो के लिए खाना नहीं परसते, मुझे वापस लौटा दिया । सभी लैटिन अमेरिकनो की भाँति ब्राजील-निवासी भी पोशाक आदि पर बहुत ध्यान देते हैं ।

डा० लीमा ने बताया कि वह रियो डि जैनरो के मेडिकल कॉलिज में पढे थे और उच्च-शिक्षा उन्होंने १९०८ में जर्मनी में पाई थी । “आप इतने वृद्ध तो नहीं दिखाई देते”, मैंने कहा ।

“मैं ५७ वर्ष का हूँ” उन्होंने कहा । उनके बाल घने और काल थे । जब मैंने ध्यानपूर्वक देखा कि उनका एक-भी बाल पका नहीं था तो उन्होंने कहा— “यह स्वाभाविक ही है क्योंकि मैं भूरी जाति का हूँ । मैं अशत भारतीय हूँ,” उन्होंने गर्व से कहा, “हम रक्त का सम्मिश्रण करते हैं, यह अच्छा होता है ।” वहाँ गलियो में हटिशयो जैसी मुखाकृति वाले श्वेत वर्ण के लोग और चीनियो-जैसी आँवो के भूरे चेहरे वाले लोंग आमतौर पर दिखाई देते हैं । पुर्तगाल के आरम्भिक अधिवासी ब्राजील में उस समय आये थे जब पुर्तगाल भी दूर पूरब के श्रवण में व्यस्त था । बेलम में लम्बे आदमी प्रायः नहीं मिलते, ऐसे ही भूरे बालो वाली स्त्रियाँ भी वहाँ कम हैं । स्त्रियाँ यहाँ हैट नहीं पहनती ।

बेलम के भूमध्य रेखा के निकट होने से मुझे रूस की याद आ गई । इसका एकमात्र कारण यह था कि मुझे प्रेजिडेंट गट्टूनियो वर्गास का फोटो प्रत्येक स्थान पर टँगा हुआ मिला । साथमें अधिक वह फोटो दिखाई दिया जिसमें वर्गास और रुजवेल्ट ह्वाइट हाउस में इकट्ठे भोजन कर रहे थे । अमेरिका से अच्छा सम्बन्ध होने के कारण मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और प्रायः लैटिन अमेरिका के डिक्टेटरो की रयाति को अमेरिकन पूँजी और व्यापार के कारण चार चाँद लगे हैं । वित्तु इस बात से रियो डि जैनरो से

दक्षिण में रहने वालों के बीच अमेरिकनो की लोकप्रियता बढ़ी नहीं।

दक्षिण अमेरिका के जिन फाशिस्ट डिक्टेटरो ने युद्ध जीतने में सहायता की उनका तो अमेरिकन सरकार ने समर्थन किया किंतु जिन फाशिस्ट डिक्टेटरो ने युद्ध में सहायता नहीं की उनका उसने विरोध किया। इसमें लैटिन की फाशिस्ट विरोधी शक्तियों की यह धारणा नहीं हुई कि उत्तरी अमेरिका अधिनायकवाद का विरोधी है।

हमारा मरम्मत किया हुआ वायुयान बेलम से नेटाल पहुँचा जो कि ब्राजील से अफ्रीका जाने का निकटतम हवाई अड्डा है। वहाँ से १४ घंटे की साधारण उड़ान के बाद हम अधमहामागर को पार कर लैंगोस (नाइजीरिया) जा पहुँचे। इस ब्रिटिश उपनिवेश की आबादी २,१०,००,००० है। इन लोगों के बारे में हम लोग बहुत ही कम सोचते हैं। ये लोग तीन विभिन्न जातियों के हैं और अलग-अलग भाषाएँ बोलते हैं। हवाई अड्डे के पास एक कैटीन था जिसमें केवल गरम लेमोनेड मिलता था। इसमें तीनों जातियों का एक-एक बैरा था। ये एक दूसरे से टूटी-फूटी अंग्रेजी में बात करते थे। लैंगोस से अंग्रेजी के कई पत्र निकलते हैं जिनमें एक समाजवादी दैनिक भी है। वहाँ मैं एक स्कूल में गया जिसका संचालन मिशनरी करते थे। उसमें पाँच-छः साल की गहरे चॉकलेटी रंग की लड़कियाँ, जिनके तार-जैसे बाल बीसियों कड़ी चोटियों में गुथे हुए सूर्य की किरणों की तरह सीधे खड़े थे, अपनी भाषा में यह वाक्य पढ़ना सीख रही थी, “क्राइस्ट समुद्र की सतह पर चलता था।” वे मुझे स्वच्छ और आश्चर्य-चकित-सी दीख पड़ी।

लैंगोस में हम अमेरिका के फेरी कमान के सुपुर्द कर दिये गये जिसने हम में से कुछ को दो घंटे सात मिनट में ५४० मील पार कर कानो के उत्तर में पहुँचा दिया गया। कानो एक मुस्लिम राज्य की राजधानी है। यहाँ के अमीर को अंग्रेजों से सहायता के रूप में एक मोटी रकम मिलती है और इसके बदले वह अंग्रेजों की इच्छानुसार काम करता है और ऐसा ही अपनी प्रजा से भी कराता है। यहाँ के लोग अरबों से मिलते-जुलते हैं, और मैंने ऊबड़-खाबड़ अरबी में उनसे कुछ बातें की।

कानो में हम ब्रिटिश वारकों में सोये और अगले दिन सबेरे ५ बजे एक नये अमेरिकन अड्डे से मँडगुरी के लिए रवाना होगये। वहाँ हम सात बजे एक और नये अमेरिकन हवाई अड्डे पर जा उतरे। यहाँ हम लोग, एक भयंकर आधी में घिर गये और हमारे लिए आगे चलना असम्भव होगया। एक अफसर ने बताया कि हमें सारा दिन और सारी रात मँडगुरी में ही बितानी होगी।

अफ्रीका के ऐसे बियावान जंगल में २४ घंटे गुजारने के विचार से मुझे प्रसन्नता नहीं हुई। किन्तु विरोध करना निरर्थक था। हम एक ढीली-ढाली बस में बैठ गये जो गहरे गड़्ढों वाली सड़क पर से हिलती-हिलाती चलने लगी। जब कभी यह बाबा आदम के समय की बस किसी बँलगाड़ी को जाने को जगह देने के लिए रुकती तो अमेरिका के १६-२० वर्षीय नीजवान उडाको में से कोई एक, जिसे अभी कॉलेज या विश्वविद्यालय से निकले दो-तीन महीने हुए थे, चिल्ला उठता, “जर्सी सिटी, अब आगे टाइम्स स्क्वेयर आयागा” या “अब सब लोग यूनियन स्टेशन पर पहुँचकर रहेंगे।” उन युवकों ने स्वीकार किया कि उन्हें घर की याद सता रही है।

हव्शी स्त्री-पुरुष, जो करीब-करीब बिलकुल नग्न थे, कितु सिर पर भूस के लम्बे-चोड़े हँट ओढ़े हुए थे, झुलसती धूप में रई के खेतों में काम कर रहे थे। हर वस्तु निम्न कोटि की और पुराने जमाने की जान पड़ती थी। वायुयान ने हमें बाबा आदम के युग में ले जा पटका था।

फेरी कमान के मेहमानों के रूप में हम लोग कमान के कैम्प में ठहरे। कैम्प की सारी भोपड़िया नई थी और लकड़ी की बनी हुई थी। उनकी हरेक खिडकी में इकहरी जाली और हरेक दरवाजे पर दुहरी जाली लगी हुई थी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग खाट थी जिस पर मच्छर-दानी टँगी हुई थी। हर कमरे के साथ गुशलखाना था जिसमें ठंडे और गरम पानी के फव्वारे, अमेरिकन साबुन की बड़ी-बड़ी टिकियाँ, आधुनिक श्रृंगार की सामग्री, बिजली के उतरते के लिए प्लग, बिजली की रोशनी, एक बड़ा रिफ्रिजरेटर था, जिसमें उबले हुए बरफ के समान ठंडे पानी की भूरी बोतलें भरी थी। जैसे ही बोतल खाली होती थी वैसे ही एक हव्शी बैरा उसे भर देता था।

घटी बजने पर हम लोग खाना खाने गये। हमारे हटते ही नौकरों ने कमरों में सब और पिलट छिड़कना शुरू किया ताकि अगर कोई मक्खी या मच्छर अन्दर आया हो तो मर जाय। खाने के कमरे में अघेरा-मा कर दिया गया था और वहाँ बिजली के पखे चल रहे थे। एक भी मक्खी कहीं नहीं थी। स्यानीय दैरे, जो शायद उन्ही दिनों जंगली क्षेत्रों से लाये गये थे, सफेद सूट पहने हुए थे और उनके हाथों पर सफेद सूती दस्ताने चढ़े हुए थे। वे नग्न पाँव खामोशी से घाते-जाते थे और उन्होंने भोजन की टाइप की हुई एक सूची लोगों में बाँटी।

अगले दिन मवेरे उसी भोजनालय में मेजों पर सफेद मेजपोश और नैपकिन रखे हुए थे। “कान फ्लेक चाहिए या आटे का दलिया”, एक अमेरिकन हव्शी दैरे ने पूछा। मेरी दूसरी प्लेट अड़ो की थी। इसके बाद गेहूँ

के केक और मक्खन और साथ में मुरव्रा आया; और अन्त में मलाई और चीनी वाली स्वादिष्ट काफी आई। ये सब पदार्थ मंडुगुरी-जंसी उजाड़ भूमि में मिले। युद्ध जीतने के लिए अगर अमेरिकन नवयुवकों को घर से दूर जाना पड़ा, तो उन्हें अफ्रीका के जंगलों तक में इतना अधिक घर-वा-मा आनन्द मिला जितना कोई भी हितेच्छु सरकार किसी के लिए जुटा सकती है। नाई-जीरिया से लेकर भारत तक सब फेरी कमानों का यही हाल था।

जब कि जर्मनी और इटली दक्षिणी यूरोप, भूमध्यसागर और उत्तरी अफ्रीका के बहुत से भागों पर अधिकार किये हुए थे और प्रशान्त के द्वीपों और मलाया तथा बर्मा पर जापान का नियंत्रण था, हमारे लिए अमेरिका और इंग्लैंड से एक ही सुरक्षित हवाई रास्ता था—वह था मिन, तुर्की और रूस से होकर ईरान हिन्दुस्तान और वहाँ से चीन।

इस रास्ते से उड़ने वाले हवाई जहाज सेना के जहाज थे और उनमें सुख-सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं थी। यात्री अलुमिनियम की गहरी सीटों पर बैठते थे और वायुयान की हिलती हुई 'दीवाल' से पीठ लगा लेते थे। अगर इस तरह बैठा-बैठा कोई थक जाता था तो वह नीचे फर्श पर बैठ सकता था, या सामान रखने की जगह पर जा सकता था जहाँ बन्दूकों आदि युद्ध-सामग्री पड़ी होती थी। मंडुगुरी से फ्रांसीसी अफ्रीका में लेकर चंड तक और वहाँ से झुल-सते हुए सूडान में खारतूम तक हम रेतीले मरुस्थल और रेत की ऊँची चट्टानों के ऊपर से उड़े। हमारा वायुयान ऊपर तक रबड़ के छोटे-छोटे टायरों के बक्सों से भरा था। इस तरह के टायर हवाई जहाजों के पीछे के पहियों में लगे रहते हैं। ये टायर उबार-पट्टा व्यवस्था के अन्तर्गत अमेरिका से रूस जा रहे थे। कुछ बक्स रास्ते में ही खुल गये और हमें फुदकते हुए फर्श पर टायरों के अन्दर बैठकर बड़ा आनन्द आया। मैं भारत के सम्बन्ध में गुस्टर और विट की लिखी हुई एक पुस्तक पढ़ता रहा।

खारतूम से काहिरा मैं एक दूसरे वायुयान से गया, जिसके चालक सान एजलो (टेक्सास) निवासी टी० एफ० कालिन्स और पेसिल्वेनिया निवासी रेमण्ड वाइज (जूनियर) थे। उन्होंने कहा कि हम पूरे ६०० मील की यात्रा बिना कही रुके एक उड़ान में पूरी कर लेंगे। यह बड़ी अच्छी बात थी क्योंकि भूमि पर उतरने का मतलब विलम्ब और भयानक गर्मी का सामना करना ही था। उड़ने से पहले वाइज ने कहा—“काहिरा के आधे रास्ते में हमें वादी हाल्फा में ठहरना है। वहाँ अस्पताल में एक अमेरिकन सैनिक है जिसके पैसे खतम हो गये हैं; हम उसके लिए १५० डालर ले जा रहे हैं।” वादी हाल्फा

रेगिस्तान के बीच में है। वहाँ खजूर के वृक्षों का एक छोटा-सा झुण्ड और कुछ भोपड़ियाँ हैं। वहाँ सिर्फ एक अमेरिकन था जो अपने घर से ११००० मील दूर बंठा हुआ था। हमने उसके लिए बहुत-सी पत्रिकाओं का भी बडल बाँधकर तैयार कर लिया।

काहिरा में सभी सभ्य सामग्रियाँ उपलब्ध थीं। हमें अपनी यात्रा में एक बढ़िया हाटल का कमरा, ठंडे पेय, स्नान के लिए टब, स्वादिष्ट भोजन और घूमने के लिए टैक्सी मिली। हमने विदेशी सम्वाद-दाताओं और कूट-नातिज्ञों से भेंट भी की। उन दिनों अलेग्जेंडर कर्क, जिनसे मेरा परिचय पहले राम में और फिर मास्को में हुआ था, मिश्र में अमेरिकन राजदूत था। नाज़ी जनरल रोमेल से काहिरा भयभीत था। ब्रिटिश सैनिकों में वीरता तो थी किन्तु वे कमजोर थे। कर्क के मस्तिष्क में एक बात जमी हुई थी।

अमेरिका को इटली पर अवश्य हमला करना चाहिए। कर्क को खयाल था कि ऐसा करने से मिश्र और स्वेज नहर की रक्षा हो जायगी और सारे यूरोपीय युद्ध का पासा पलट जायगा। कर्क बहुत ही धनवान हैं और जो उन्हें नहीं जानते वे उनकी गणना आसानी से अमेरिका के राजसी कूटनीतिज्ञों में कर सकते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मेहमानदारों की खूब गान के साथ खातिरदारी करने में उन्हें मज़ा आता है। किन्तु उनकी बुद्धि बड़ी बुझाग्र है और वह अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति को खूब समझते हैं। उनमें बड-प्पन का अह्वार दिखाई देता है और कभी-कभी वह बनते भी बड़े हैं। किन्तु दारतव में उनमें यह भाव है नहीं। वह तो केवल उन सिद्धान्तों के लिए लड़ते हैं जिनमें उनका विश्वास है। वह बराबर आग्रह करते रहे कि हमें रूमानिया के तेल-क्षेत्रों पर बम-वर्षा करनी चाहिए।

प्रसिद्ध शैफर्ड्स होटल में पहुँचने पर मेरी अपने पुराने मित्र मारिस हिट्स से टक्कर होगई, जो तभी-तभी मास्को से आये थे। उसके बाद हमारी भेंट कर्नल लुई जॉनसन से हुई, जिन्हें प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने अपने विशेष दूत के रूप में भारत भेजा था। उनके साथ इडियानापोलिस के एक उद्योगपति कर्नल आर्थर डब्ल्यू० हेरिंगटन भी थे जो निकट पूरव में दीर्घ काल तक काम कर चुकने के कारण उस प्रदेश से अच्छी तरह परिचित थे। जॉनसन ने हेरिंगटन का सहायना से भारतीय स्थिति का अध्ययन किया था और मार्च तथा अप्रैल १९४२ में त्रिप्स-योजना सबधी बातचीत की निकट में समाक्षा की थी। मैं जॉनसन से उन दिनों मिला था जब वह अमेरिका में युद्ध के उपमन्त्री थे। इस पद पर वह १९४० तक रहे। मुझे आशा थी कि भारत में उनकी सहायना

से मुझे लोगो के साथ सम्पर्क स्थापित करने और जानकारी हासिल करने में सुविधा मिलेगी। किन्तु भारत के मौसम और जलवायु के कारण वह अस्वस्थ हो गये थे और इलाज के लिए अमेरिका वापस जा रहे थे। मुझे उनकी बातों से पता लगा कि भारत के अनुभवों ने उन्हें इस बात का विश्वास दिला दिया है कि भारत के शासन में परिवर्तन होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय नेता जवाहरलाल नेहरू के सम्बन्ध में उन्होंने बड़े उत्साह और आदर की भावना से बातचीत की।

पूरब जाने वाले वायुयान के लिए मुझे काहिरा में चार दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैं होटल के बारजे में एक अमेरिकन पत्रकार के साथ बैठ जाया करता था और हम आपस में बातें किया करते थे। “आपको मालूम है कि यहाँ फरवरी में क्या हुआ था,” उसने पूछा। मैंने कहा—“नहीं।” रहस्यमय ढंग से और बहुत-सी इधर-उधर की बातों के बाद उसने चुपके से मेरे कान में कुछ कहा। अलैगज़ेडर कर्क ने मुझसे कहा कि काहिरा की फरवरी की घटनाओं का मुझे पता लगाना चाहिए। मेरे द्वारा पूछने पर उन्होंने कुछ बातें बतलाई और फिर विषय बदल दिया। इस प्रकार असंगत बातों को जोड़कर मैं एक कहानी बनाने लगा। इस सम्बन्ध में काहिरा से कोई व्यक्ति कुछ नहीं लिख सकता था क्योंकि ब्रिटिश सेंसर इस सिलसिले में विशेषरूप से कड़ा था। मेरा इस बारे में कुछ लिखने का इरादा नहीं था, किन्तु मुझे उत्सुकता थी और मैं बातें जानना चाहता था। इसलिए मैंने ब्रिटिश राजदूत सर माइल्स लैम्पसन से, जो थूलथुले शरीर के एक हँसमुख व्यक्ति थे, मिलने का समय नियत किया। हमने चर्चा तो अनेक विषयों की की किन्तु गहराई के साथ किसी पर बातचीत नहीं की। अन्त में मैंने कहा:— “फरवरी की घटनाओं के सम्बन्ध में मुझे इतनी काफी जानकारी हो गई है कि मैं उसके बारे में इस विश्वास के साथ बातचीत कर सकता हूँ कि मैं जो कुछ जानता हूँ वह बिल्कुल ग़लत नहीं है। फिर भी मेरी जानकारी के कुछ अंश ग़लत और अपर्याप्त अवश्य होंगे।” लैम्पसन ने कहा कि तुम जो कुछ जानते हो वह बताओ। मैंने बता दिया और उसने उस पर टीका-टिप्पणी की। घटनाएँ ये थी—फरवरी, १९४२ में ब्रिटिश सरकार और मिस्र के शाह फारूक के आपसी सम्बन्ध बहुत अधिक बिगड़ गये थे। शाह को कोई मुश्किल से ही युद्ध और अंग्रेजों का समर्थक कह सकता था। सम्भवतः धुरीराष्ट्रों के प्रति उनके मन में कुछ सहानुभूति भी थी। इसका कारण यह नहीं था कि शाह को इटैलियनो अथवा जर्मनों से प्रेम था, बल्कि उन्होंने शायद यह सोचा हो कि

अगर अग्रेज हार जायेंगे तो मिस्र को और भी अधिक स्वतंत्रता मिल जायगी । जब ब्रिटिश सरकार ने यह माँग की कि काहिरा-स्थित विची-मन्त्री से गोपनीय सदेज भेजने की सुविधाये वापस ले ली जाय तो मामला एकदम बहुत गंभीर हो गया । यह सन्देह किया जाता था कि विची-मन्त्री ब्रिटिश सैनिक गतिविधि के बारे में पेता की सरकार को गोपनीय सूचनाएँ भेजते हैं । स्वभावतः ये बातें पेता सरकार से जर्मनों को मालूम हो जाती थी । शाह ने विची-मन्त्री से इन सुविधाओं को वापस लेने से इकार कर दिया था । इसलिए सर माइल्स लैम्पसन और ले० जनरल राबर्ट जी० स्टोन ने शाह से भेट करने की आज्ञा माँगी । नियत दिन को ब्रिटिश टैंको और सैनिकों ने शाह के महल को घेर लिया । तब लैम्पसन और स्टोन शाह के कमरे में घुसे । प्रत्येक व्यक्ति सौजन्य और जिष्टाचार के साथ बातें कर रहा था । अग्रेजों ने सुझाव पेश किया कि शाह महोदय के लिए हवाई अड्डे पर एक वायुयान तैयार है जो उन्हें बहुत दूर एक ऐसे स्थान पर ले जा सकता है जहाँ वह चिर-काल तक रह सकेंगे— किंतु ये सब बातें तब होती जब वह विची के राजदूत के सम्बन्ध में एक आज्ञा जारी करने को तैयार न होते और अपना प्रधान-मन्त्री न बदलते । शाह ने ये बातें रवीकार कर ली ।

नाजियों ने काहिरा पर बम नहीं बरसाये । मिस्री लोग पहले जैसी चहल-पहल के साथ जीवन-यापन करते रहे । युद्ध से उन्होंने खूब लाभ उठाया ।

२१ मई १९४२ को मैं काहिरा से चल पड़ा । मेरा हवाई जहाज स्वेज नहर और दक्षिणी फिलस्तीन के राफा प्रदेश के ऊपर से उड़ा जहाँ पर मैं १९१९ में ब्रिटिश सैनिक के रूप में कई महीने रह चुका था । इसके बाद वह हवाई जहाज गाजा, जो अब युद्ध के कारण बहुत फँस गया है, हरे समुद्र के तट पर स्थित सफेद यहूदी नगर तेल-अबीव और जूडिया की खुश्क पहाड़ियों के ऊपर उड़ता हुआ बगदाद के पास हवानिण पहुँचा । इस यात्रा में हमें ४॥ घंटे लगे । ईराकी सिपाहियों ने हमें हवाई अड्डे के पास वह पहाड़ी दिखाई जिस पर १९४१ में रशीदअली की विद्रोही सेना ने अग्रेजों से लड़ते समय मोर्चा जगाया था ।

भोजनालय में खाना खाने के बाद दो घंटे में हम बमरा जा पहुँचे । यहाँ यूफ्रेटीज और टाइग्रिस नदियाँ मिलकर शत-अल अरब नामक नदी बन जाती है, जो होटल के बाहर बागों के साथ-साथ धीरे-धीरे बहती है । होटल एयर-कंडीशंड है । पन्ने एक मिनिट के लिए भी बन्द नहीं हुए । सोते समय मैंने कोई चादर नहीं ओढ़ी और सारी रात पसीना पोछता रहा । बमरा की

तुलना में अफ्रीका ठण्डा है ।

वसरा के पास उधार-पट्टे का सामान लाने ले जाने के लिए एक हथियार का हवाई अड्डा था । यहाँ हवाई जहाज और रबड़ के टायर अड्डे पर उतार दिये गये । वहाँ से हम शरजा चले गये, जो अरब के स्वतंत्र प्रदेश ओमन में है । यहाँ कहीं जंगल है, कहीं पहाड़ और कहीं समुद्र । शरजा में हम ब्रिटिश हवाई कम्पनी के होटल में सोये । अगले दिन प्रातः छः बजे ७४० मील दूर प्रायः सारे रास्ते समुद्र के ऊपर से उड़कर हम भारत के पूर्वी द्वार कराची में पहुँच गये । हम एक अमेरिकन हवाई अड्डे पर उतरे, वहाँ के सभी कर्मचारी अमेरिकन थे । यह अड्डा अमेरिका के बड़े हवाई अड्डों जैसा ही था, जहाँ अमेरिकनो की बेतकल्लुफी से वित्त प्रमन्न हा गया । किसी ने मुझसे पास-पोस्ट तक के लिए नहीं पूछा । मैंने वहाँ के इंचार्ज कर्नल मेसन से पूछा—“नई दिल्ली के लिए जहाज अब कब दिलवाइयेगा ।” “तीस मिनट में” उन्होंने उत्तर दिया । मैंने कैदीन से सीले विस्कुटो का एक डिब्बा खरीदा और हवाई जहाज पर जा चढ़ा । २३ मई की शाम को मैं अपने निश्चित स्थान भारत की राजधानी नई दिल्ली में जा पहुँचा ।

पूरब और पश्चिम का मेल

पूरब में एक ओर तो हाथी पर चढ़ने वाले महाराजों की चमक-दमक है और दूसरी ओर किसान की भोषड़ी की जघन्य दरिद्रता, एक ओर गैरी का शिकार, तो दूसरी ओर रोटो के लिए दौड़-धूप, एक ओर आकर्षक रंगों के वस्त्र और दूसरी ओर जीवन का फीकापन। पूरब एक रहस्य है, एक महान् पड़्यत्र, एक रोमांस, एक भयानक भुखमरी—असह्य जीवन-भार और असामयिक मृत्यु। पूरब में प्रकृति की रहस्यपूर्ण सुन्दरता और जीवन की स्पष्ट गुरुपता दोनों ही का समान रूप से दिग्दर्शन होता है।

पश्चिम जीवन का सुख लेता है और पूरब जीवन का अर्थ समझने के लिए भटकता फिरता है। पश्चिम की गति उन्मादपूर्ण है। पूरब धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता है। पश्चिम नवीन की खोज में प्रयत्नशील है और पुरातन को श्रृंगार का हेतु मात्र मानता है। पूरब पुरातन से अभिन्न है पश्चिम पढता अधिक है और सोचता कम है। पूरब पढता कम है और चिन्तन को आदर्श अवस्था मानता है।

पश्चिम में जीवन का ताल-स्वर मशीनों में मिलता है, पूरब में मानव में। पश्चिम को धन, अधिकार, बल और सौन्दर्य की लालसा है। पूरब इनके आगे श्रुति है पर आदर निर्बलता, सादगी, विनय और आत्मसमय का करता है।

पूरब पश्चिम से भिन्न है। किन्तु यह अन्तर देश का है या काल का? क्या यह इसलिए है कि एशिया बीसवीं नहीं बल्कि १४ वीं शताब्दी में रहता है। जब यूरोप १४ वीं शताब्दी में था तो वह आज के यूरोप की अपेक्षा आज के एशिया से अधिक मिलता-जुलता था।

एशिया पश्चिम से सैकड़ों वर्ष पूरब की ओर है।

एशिया की समस्या यह है कि वर्तमान में किस प्रकार रहना आरम्भ किया जाय।

भारत की समस्या बीसवीं शताब्दी के समकक्ष होना है।

भारत का सघर्ष पूरव और पश्चिम का सघर्ष नहीं है बल्कि १७वीं और २०वीं शताब्दियों का सघर्ष है ।

मै न्यूयार्क से मई १९४२ में चला था और गमियों भर भारत में ही रहा । किन्तु मोटर में तीन मील यात्रा करने या तीन मिनट की सैर भर में मुझे तीन शताब्दियाँ पीछे “ब्रिटेन में बनी” दुनिया की याद आ जाती थी । भारत में पश्चिम को लाने वाले पुर्तगाल, फ्रांसीसी और अंग्रेज थे । वे भारत में हैं, किन्तु भारत के नहीं हैं । जो कुछ अंग्रेज लाये भारतीयों ने उसे स्वीकार किया, किन्तु उन्होंने अंग्रेजों को स्वीकार नहीं किया । और न ही अंग्रेजों ने हिन्दुस्तानियों को स्वीकार किया । कवि रुडयार्ड किपलिंग की डम पवित्र का अर्थ “पूरव पूरव है और पश्चिम पश्चिम, और दोनों कभी नहीं मिलेंगे” यह है कि अंग्रेज और हिन्दुस्तानी कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्वामी और नौकर कभी नहीं मिलते ।

कराची के अमेरिकन हवाई अड्डे पर, जहाँ मैंने भारत में प्रवेश किया, मुझे कोई हिन्दुस्तानी या अंग्रेज दिखाई नहीं दिया । नई दिल्ली के हवाई अड्डे पर भी मुझे कोई हिन्दुस्तानी नजर नहीं आया । नई दिल्ली की सड़कों पर और इम्पीरियल होटल में कुछ हिन्दुस्तानी थे । परन्तु नई दिल्ली भारत का इंग्लैण्ड है—सरकारी अफसरों के लिए एक अंग्रेजी शहर । भारत में पहुँचने पर पहले दिन भारत को देखे बिना सोने को जी नहीं चाहता था । इसलिए मैंने होटल के खजाची से डालरों के बदले में रुपये देने के लिए कहा ताकि मैं उन्हें लेकर पुरानी दिल्ली जा सकूँ । “इस काम को करने में मुझे घटो लगेगा” खजाची बोला, “और मैनेजर की आज्ञा लेनी होगी ।” मैनेजर अंग्रेज था । उसने मुझे चेतावनी देते हुए कहा—“बेहतर हो अगर आप रात को पुरानी दिल्ली न जाय । वहाँ कोई भी किसी समय आपकी पीठ में छुरा धोप सकता है ।” फिर भी उसने मुझे ४० रुपये दे दिये और मैं मोटर में बैठकर पुरानी दिल्ली चल दिया । रास्ते में मैंने गायों और बैलों को सड़कों पर सोते देखा और अर्धनग्न, क्षीणशरीर व्यक्तियों को फुटपाथों पर पड़े देखा । मैं अकेला एक मनोरंजन-गृह में जा बैठा और वहाँ भारी कपड़ों से लदी एक लड़की का नृत्य देखने लगा । उसके बाद मैं सही-सलामत होटल वापस आ गया । मुझे ऐसा अनुभव हुआ मानो मैं गरमी, गंदगी, गर्द और पिछड़ेपन से साक्षात्कार करके लौटा हूँ ।

हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में जो बातें मुझे सब से ज्यादा याद हैं, वे हैं, वे व्यक्ति जिनसे मैं मिला और वे समस्याएँ जिनका मैंने अध्ययन किया । हिंदू-

स्तान में बान करने का एक ही विषय है—स्वयं हिन्दुस्तान । अक्सर मैंने अमेरिका, रूस और युद्ध की बात छेड़नी चाही, किन्तु मैं असफल रहा । हिन्दुस्तान की समस्याएँ इतनी दुखदायी और आवश्यक हैं कि सारा ध्यान उन्हीं की ओर केन्द्रित रहता है । हिन्दुस्तान बीमार है और ऐसा मालूम होता है कि उसके दिल या पेट में कोई रोग है । यह रोग तभी भुलाया जा सकता है जब वह दूर हो जाय ।

भारत दो भागों में विभाजित है । एक ओर तो करोड़ों का वह जन-समूह है जो जारिरीक रूप से दुर्बल और आर्थिक तथा शैक्षिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए वह अपने आप को निराशा की भावना से ऊपर नहीं उठा सकता । दूसरे दल में वे छोटी के लाखों आदमी हैं जो राष्ट्रीय-दरिद्रता, प्रतिकूल जलवायु और उस हीनता की भावना पर काबू पाने के लिए सतत सग्राम में व्यस्त हैं, जो एक विदेशी स्वामी की दासता में रहने के कारण उनके मस्तिष्क में सदा बनी रहती है ।

भारत जैसे पिछड़े हुए देश को सफलता की सीढ़ियों पर अधिकार करने और फिर उस अधिकार को बनाये रखने के लिए जो घोर सग्राम करना पड़ा है, और अतीत में देश की जो कठोर स्थिति रही है, उससे धन, प्रतिष्ठा और मान की प्राप्ति के हेतु प्रतियोगिता तीव्र बन गई है । प्रतियोगियों में असाधारण जोश और वेग होते हैं । उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि समय हाथ से निकला जा रहा है । असफलता का भय उनमें अपूर्व शक्ति और अत्यधिक कटुता पैदा कर देता है । असफलता प्रतिशोध की भावना को जन्म देती है । यह सब होते हुए भी वे व्यक्ति निजी व्यवहार में स्वच्छन्द होकर दार्शनिकों की भाँति बातें करते हैं । घनिष्ट सम्बन्ध रखने वाले मामलों पर भी वे बिना किसी आडम्बर के और बड़ी स्पष्टवादिता से बातें करते हैं । निराशा और असफलता की बातें मैंने गरीबों, आदर्शवादी विद्यार्थियों, करोड़पतियों, हिन्दू उच्चाधिकारियों, परिश्रमी व्यापारियों—सभी के मुँह से सुनीं ये लोग निराशा का कारण ब्रिटिश राज्य को ही समझते थे । किन्तु मैंने देखा कि जातीय भेदभाव और आर्थिक उन्नति के लिए अवसर की कमी भी इस निराशा का एक कारण है । निस्सन्देह भारतवासियों की आशाएँ भग्न होगई हैं; यही कारण है कि उनका सामूहिक व्यपहार मुझे कम असाधारण नहीं लगा । भारतीय राजनीति में कोई रोग फैल गया है और उसे एक डॉक्टर की आवश्यकता है ।

गांधीजी के इनने अधिक अनुयायी होने का कारण यह बताया जाता है कि वे एक निपुण राजनीतिज्ञ हैं । लोगों में

इस बात पर अक्मर वहस होनी है कि वह संत है अथवा राजनीतिक नेता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह भारत के डॉक्टर है।

यह बात मुझसे जवाहरलाल नेहरू ने कही जब नई दिल्ली पहुँचने के अगले दिन ही मैं उनसे मिला। भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के नेतृत्व के मामले में जवाहरलाल नेहरू गांधीजी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। गांधीजी ने भारतीयों की आत्म सम्मान की भावना को जाग्रत करने में सफलता प्राप्त की है और यही वह रज्जु है जो नेहरू और गांधी को एक सूत्र में बाँधती है। वास्तव में ये दोनों व्यक्ति एक-दूसरे से भिन्न हैं। नेहरू तो एक प्रकार के पश्चिम हैं जो पूर्व में काम कर रहा है। १९४१ में उनकी अवस्था ५२ वर्ष की थी। अब तक उनके जीवन के लगभग १० साल हिन्दुस्तान की जेलों में कटे हैं। कुछ साल वह हैरो और केम्ब्रिज में रहे। अंग्रेजी स्कूलों की नेहरू पर छाप लगी है। ऐसे ही आधुनिक ससार का भी उन पर गहरा प्रभाव है। नेहरू का रोम-रोम देश के यत्रहीन पिछड़ेपन का विरोध करता है। उधर गांधी को इन्हीं बातों में आनन्द आता है।

वेश-भूषा, खान-पान, धार्मिक दृष्टिकोण तथा जीवन-दर्शन की दृष्टि से गांधीजी प्राचीन भारत के प्रतिनिधि हैं। किन्तु इस प्राचीनता में नेहरू केवल इतना विश्वास रखते हैं, जितने से वह भारतवासियों के लिए ग्राह्य बने रहें और उन्हें उनमें परिवर्तन करने का अवसर मिले।

मैं नेहरू को जेनीवा, पेरिस और लन्दन में यूरोपियन वेशभूषा में देख चुका था। अब मैंने उन्हें सफेद खादी का चुस्त पाजामा पहने देखा, जो टखनों तक आता था, उस पर उन्होंने कुरता पहन रखा था जो घुटनों को छूता था और कुरते के ऊपर एक हलके नारंगी रंग की वास्कर थी। वह नगे पाँव थे किन्तु जिस सोफे पर हम बैठे थे उसके पास ही उनके काले चमड़े के बूट पड़े थे। उन्होंने मेरा परिचय अपनी चचेरी बहन से कराया, जिनके यहाँ वह ठहरे हुए थे। वह एक आई. सी. एस. अफसर की पत्नी है। उन्होंने सफेद साड़ी पहन रखी थी और उनके माथे पर लाल चमकदार बिन्दी लगी हुई थी। बिन्दी उनके सुझाग की निशानी थी। उन्होंने हमें सन्तरो का रस पिलाया।

थोड़ी-थोड़ी देर के बाद बाहर लटकी हुई खस की टट्टी पर पानी छिड़के जाने का शब्द सुनाई पड़ता था। टट्टी से छनकर आने वाली गरम हवा को पानी ठंडा कर देता था और बाहर आकाश तक छाई हुई धूल अन्दर नहीं आ पाती थी। मकान कुछ नीचा था, किन्तु उसकी बनावट और सजावट यूरोपियन ढंग की थी, सिवा उन आभूषणों के जो पूर्वी ढंग के थे और अत्यन्त

सुन्दर लगते थे ।

नेहरू ने एक लम्बी नली में डालकर कई सिगरटे पी । वह बहुत हसते रहे जिससे उनके सफेद सुन्दर दाँत दिखाई देते रहे । उनका रंग रेत की तरह भूरा है । वह गजे हैं और उनके कानों पर सफेद बालों के गुच्छे हैं, पर हैं वह अत्यन्त सुन्दर ।

एक प्रश्न के उत्तर में नेहरू ने स्वीकार किया कि अंग्रेजों ने भारत को शान्ति और सुव्यवस्था दी है । “परन्तु उन्होंने हमें कमजोर और पथभ्रष्ट भी कर दिया है” उन्होंने कहा—“भारतीय गौरव और राष्ट्रीय भावना का फिर जो उत्थान हुआ है वह तो पिछले २२ या २३ वर्षों से ही हुआ है, जब से गांधी जी ने (‘जी’, शब्द का प्रयोग आदर के लिए किया जाता है) अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन आरम्भ किया । इससे पहले अगर एक पुलिस का सिपाही किसी किसान को मार बैठता था तो और लाग भाग खड़े होते थे । अब वे ही लोग किसान की रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं । हिन्दुस्तानियों में अब साहस का संचार हो चुका है । यह केवल राजनीतिक हथियार ही नहीं है, हमने इसके द्वारा माल-गुजारी को भी बढ़ने से रोका है ।”

गांधी ने भारतीयों में अंग्रेजों के विरोध की भावना को जन्म दिया है; वह उनके प्रतीक हैं । दुबले-पतले लंगोटी और चप्पल पहने हुए गाँधी ब्रिटिश सरकार के नियमों की अवहेलना कर पैदल समुद्र की ओर चल देते हैं । लाखों हिन्दुस्तानी उनके पीछे हो लेते हैं और इस प्रकार वह यात्रा तीर्थ-यात्रा बन जाती है । इस यात्रा में युवकों का आदर्शवाद दिखाई देता है और साथ-ही-साथ एक नेताहीन राष्ट्र की किसी के नेतृत्व में कार्य करने की आकांक्षा भी फूटी पड़ती है । “डाडी मार्च” द्वारा भारतवासियों को एक नेता के पद-चिन्हों पर चलने के अवसर की भानक मिलती है और गांधी की कृपा से उनके अनुयायियों को उन विदेशियों के सामने खड़े होने में अभिमान होता है जो उनके घर पर अपना आधिपत्य जमाये हुए हैं ।

गांधी का वाइसराय के संग मरमर के महल की सीढ़ियों पर चढ़ना हिन्दुस्तानियों के हृदयों को विशेष महत्त्व की भावना से ओत-प्रोत कर देता है । गांधी अनशन करते हैं, साम्राज्य वाप उठता है । गांधी का एक असहयोग आन्दोलन हिंसात्मक हो जाता है । उसका पश्चात्ताप करने के लिए गांधी द्रत करते हैं । हिंसा बन्द हो जाती है । अधिकार के ताम्रनाम के बिना ही—क्योंकि गांधी न तो किसी को दण्ड दे सकते हैं न पारितोषिक—गांधी जनता पर निर्भर रहते हैं । गांधी का कहना है कि बदलों से बल की धारा बहेगी ।

अबलो की कीर्ति ही गांधीका बल है। हजारों लोग उन्हें वापू कहते और समझते हैं। वह अपने हस्ताक्षर में 'वापू' लिखते हैं। एक पत्र में उन्होंने मेरे पास भी 'वापू' ही लिखकर भेजा है।

गांधी भारत की निराशा को दूर करने की प्रतिरोधक श्रौषधि है। जब से उन्होंने भारतीयों का नेतृत्व ग्रहण किया तब से भारतवासी अपने मस्तक ऊँचा उठाकर चलना सीख गये हैं। नेहरू उनके आभारी हैं। नेहरू अभिमानी, भावुक और तूफानी प्रकृति के व्यक्ति हैं। "हमें उपनिवेश-पन नहीं चाहिए," उन्होंने एक बार कहा था। "आस्ट्रेलिया या कनाडा की तरह भारत इंग्लैंड की पुत्री नहीं है। भारत तो स्वयं माता है। भारत शताब्दियों तक एक सभ्य देश रहा है। अंग्रेज हमें ब्रिटिश सामन्यतन्त्र में सम्मिलित होने को कहते हैं, जिसके कुछ राष्ट्र (उदाहरणार्थ दक्षिणी अफ्रीका) भारतीय प्रवासियों से भेदभाव करते हैं। इससे अच्छा तो यह होगा कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय संघ में सम्मिलित हों, जिसमें केवल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के अलावा चीन, अमेरिका, रूस और सारी मानव-जाति शामिल होगी।

मैंने नेहरूजी को गांधीजी के बारे में बात करने के लिए प्रेरित किया वह बोले— "गांधी भारत के राष्ट्रीय नेता हैं। किंतु उनका सन्देश समस्त विश्व के लिए है। वह भारतीय हैं। किंतु उनकी आध्यात्मिकता सार्वभौमिक है।"

"गांधी में डिक्टेटर का भी पुट है" मुसकराहट के साथ नेहरू ने स्वीकार किया। किंतु उन्होंने कहा, "बाध्य करने की जितनी शक्ति गांधी के एक उपवास में है उतनी हिटलर के आतंक में नहीं। गांधी को हड़तालों में विश्वास नहीं। पंच द्वारा निर्णय को वह अधिक अच्छा समझते हैं। इसके बावजूद भी जब एक बार कपड़ा-मिलों के कुछ मजदूरों ने हड़ताल कर दी तो मिल-मालिकों को समझौता करने को बाध्य करने के लिए गांधी ने उपवास आरम्भ कर दिया और मालिकों ने फौरन समझौता कर लिया। कौन-सा ऐसा हिंदुस्तानी है जो गांधी के जीवन को सकट में डालने या एक दिन के लिए भी उनका कष्ट बढ़ाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले सकता है?"

सेवाग्राम में मैं महात्मा गांधी के साथ एक सप्ताह तक रहा। सेवाग्राम भारत के मध्य में एक गांव है। जिस सप्ताह में मैं वहाँ था उसके पहले तीन दिन नेहरू भी वही थे।

मैं एक कच्ची झोपड़ी में रहा जिसकी छत फूस की थी। मैं मूज की चारपाई पर खुले मैदान में सोया और मैंने वही खाया जो गांधी खाते थे—सब्जियों के उबले हुए पत्ते और आलू, कच्ची प्याज और गाय का दूध, आम,

ग्रहद और विस्कुट । हर रोज यही चीजे बनती थी । दो दिन तक तो मैं ठीक रहा किंतु जब तीसरे दिन भी ये ही चीजे खाईं तो मैंने कहा— “धन्यवाद, मैं नहीं लूंगा ।” गांधी, जो खाद्य-सम्बन्धी समस्याओं में बहुत रुचि रखते हैं और वाते समय मुझे ध्यानपूर्वक देखते थे, बोले, “आपको सज्जियाँ पसन्द नहीं ।”

“मुझे इन सज्जियों का स्वाद अच्छा नहीं लगता ।” मैंने उत्तर दिया ।

इन पर उन्होंने कहा, “आपको इसमें नमक और नींबू खूब मिलाना चाहिए ।”

“तो दूसरे जव्दो में आप चाहते हैं कि मैं स्वाद को मार डालूँ” मैंने हँसकर कहा ।

“नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप स्वाद को और अच्छा बनाये” गांधी ने कहा ।

आप तो इतने अहिंसक हैं कि आप स्वाद को भी मारना नहीं चाहते,” मैंने कहा ।

नि मन्देह गांधी शान्तिवादी हैं । किंतु उनसे मैंने जो बातें की और उनके जीवन का जो मैंने अध्ययन किया उससे मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि उनका शान्तिवाद राजनीतिक है धार्मिक नहीं । वह सम्पूर्ण शान्तिवादी नहीं है । वह युद्ध का विरोध इसलिए करते हैं कि ऐसे युद्ध में उन्हें विश्वास नहीं जिसका अवलम्बन आधुनिक राष्ट्र-विजय और आधिपत्य के लिए है । यदि उनमें सामर्थ्य होती तो वह द्वितीय विश्वयुद्ध को रोक देते, क्योंकि उन्हें इस बात में विश्वास नहीं था कि किसी भी देश की सरकार में इतनी योग्यता है कि वह विजय द्वारा मानवता का उद्धार कर सके ।

यदि आप निकट से देखें तो आपको मालूम होगा कि गांधी की अहिंसा और शान्तिवाद एक ही नहीं है । गांधी की अहिंसा का अर्थ लड़ने से इकार करना नहीं है । यह वह अस्त्र है जिससे गांधी लड़ते हैं । उपवास भी उनके लिए अस्त्र ही है । भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के पास एक यही अस्त्र है । गंगा के पास कोई शस्त्र नहीं है ।

गांधी ने मुझे बताया कि अहिंसात्मक प्रतिरोध को उन्होंने किन परिस्थितियों में अपनाया । सारी घटना मूल-रूप से भारतीय हैं । गांधी ने कहा—“आरम्भ १९१९ में हुआ । मैं लग्नज में कांग्रेस-दल के लिए कार्य कर रहा था । एक विमान मेरे पास आया । दूसरे किसानों की तरह वह भी गरीब और दुर्बल था । मैंने ही उसने कहा— ‘मेरा नाम राजकुमार शुक्ल है । मैं चम्पारन का रहने वाला हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरे जिले में चले ।’ उसने अपने जिले के

किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया और मुझसे प्रार्थना की कि मैं उसके साथ चलूँ। चम्पारन लखनऊ से कई सौ मील दूर है, किन्तु उसने बराबर इस तरह आग्रह के साथ कहा कि मैंने जाने का वादा कर लिया।”

गांधी तत्काल ही नहीं जासके। इसलिए वह किसान देश भर के दौरे में हफ्तों उनके साथ रहा। आखिरकार १९१७ में वह उन्हें साथ लेकर कनकते से चम्पारन जाने वाली गाड़ी में बैठ ही गया।

गांधी का विचार चम्पारन के किसानों से उनकी अवस्था के बारे में पूछ-ताछ करने का था। “कितु”, बात को जारी रखते हुए गांधी ने कहा, प्रश्न के दूसरे पहलू का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं अग्रेज कमिश्नर से भी मिलना चाहता था। जब मैं कमिश्नर के पास गया तो उसने मुझे घंटा बताई और तत्काल ही जिले से बाहर चले जाने की सलाह दी। मैंने यह सलाह स्वीकार नहीं की और हाथी की पीठ पर चढ़कर मैं देहात की अवस्था का पता लगाने के लिए एक गाँव की ओर चल दिया।

“रास्ते में एक पुलिस का प्यादा मेरे पास पहुँचा और उसने चम्पारन से बाहर चले जाने का आदेश दिया। पुलिस वाले को साथ लेकर मैं अपने ठहरने की जगह गया और वहाँ पहली बार मैंने सविनय अवज्ञा का आश्रय लिया। मैंने जिले से बाहर जाने से इकार कर दिया। उस घर के चारों तरफ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ को नियंत्रण में रखने में मैंने पुलिस के साथ सहयोग किया।

“फिर मुकदमे के लिए मैं कचहरी पहुँचाया गया। सरकारा वकील ने न्यायाधीश से मुकदमा स्थगित करने की प्रार्थना की, परन्तु मैंने आग्रह किया कि मुकदमा चलना चाहिए। मैं कचहरी में यह घोषणा करना चाहता था कि चम्पारन छोड़ने के आदेश की अवज्ञा मैंने जान बूझकर की है। मैंने न्यायाधीश से कहा कि मैं चम्पारन में किसानों की अवस्था के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने आया था और मुझे अग्रेजी कानून की अवहेलना इसलिए करनी पड़ी कि मैं एक उच्चतर कानून के आदेशानुसार काम कर रहा था। वह कानून मेरी आत्मा का आदेश था।

“अग्रेजों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा का यह मेरा पहला कार्य था। इसके द्वारा मैं यह सिद्धान्त स्थापित करना चाहता था कि किसी भी अग्रेज को इस बात का अधिकार नहीं कि अगर मैं अपने देश के किसी भी भाग में शान्तिपूर्ण उद्देश्य लेकर जाऊँ तो वह मुझे वहाँ से निकल जाने के लिए कहे। मैंने अपने आपको दोषी स्वीकार किया।”

सरकारी अधिकारियों ने गांधी से अनुनय-विनय किया कि आप अपना दोष स्वीकार न करें। वे उन्हें अपराधी ठहराना नहीं चाहते थे। किन्तु गांधी ने ऐसा करने से इकार कर दिया। अन्त में सरकार के सामने और कोई चारा नहीं था सिवा इसके कि वह मुकदमे को बरखास्त कर गांधी को मनचाहा कार्य करने दे।

“सविनय अवज्ञा का विजय हुई” गांधी ने कहा। १९१७ के उस दिन से गांधी ने सविनय अवज्ञा प्रणाली के दोषों को दूर करके उसमें अनेक सुधार किये हैं। स्वतंत्रता की माग करने वाले प्रदर्शकों की भीड़ पर पुलिस लाठी-चाज करती है। प्रदर्शक सड़क पर लेट जाते हैं और बराबर पिटते जाते हैं। कुछ देर बाद यह कार्य इतना जघन्य हो जाता है कि अंग्रेज अधिकारियों को पुलिस हटा लेनी पड़ती है। हिन्दुस्तानी विदेशी कपड़ा खरीदना बंद कर देते हैं। वे टैक्स देने में भी इकार कर देते हैं। वे सड़कों पर लम्बे लेटकर अंग्रेज अफसरों की मोटर गाड़ियों को रोक लेते हैं।

गांधी ने बहुत चतुराई से हिन्दुस्तानियों की निष्क्रियता तथा उदासीनता को एक युद्ध के अरत्र का रूप दे दिया है। अंग्रेज शासकों द्वारा सिखाई गई दिनभरा अव अंग्रेजों के ही विरुद्ध प्रयुक्त होती है केवल साहस इसमें जोड़ दिया गया है। गांधी की यही देन है।

एक बार मैंने गांधी से कहा कि इंग्लैंड लोकतन्त्रवादी देश है। किन्तु उन्होंने आग्रहपूर्वक उत्तर दिया कि यह सम्भव नहीं कि घर में तो इंग्लैंड जनतन्त्री हो और बाहर साम्राज्यवादी। वास्तव में साम्राज्यवाद जनतन्त्र का दिलकुल उल्टा है। केवल इसलिए कि हममें शारीरिक शक्ति तो है लेकिन हमें दूसरों पर राज करने का अधिकार नहीं दिया गया। अगर हम किसी देश को दूत यिनो तब दासता में जकड़े रखे तो निश्चय ही हमारा यह कार्य जनतन्त्री सिद्धान्तों के प्रतिकूल ही होगा। साम्राज्यवाद का अर्थ अनधिकृत बलात्कार है। इस सीमित परिधि के भीतर रहते हुए अंग्रेज भारत में अनेक जनतन्त्री नियमोपनियमों का प्रतिपादन करते हैं। किसी भी यूरोपीय तानाशाही देश में गांधी जैसे व्यक्ति को रातों-रात इस प्रकार ठिकाने लगा दिया जाय कि अगले दिन सड़े उनका कुछ पता ही न चले। नाज़ी जर्मनी जैसे देश में सामूहिक सविनय अवज्ञा की कल्पना भी नहीं की जा सकती और न ही सोवियत रूस में अहिंसक असहयोग सम्भव है। किन्तु गांधी जानते हैं कि जब तक भारत, इंग्लैंड और अमेरिका में जनमत पर कोई प्रतिबन्ध नहीं तब तक अंग्रेज उन्हें न तो ठिकाने लगाएंगे, न लगा सकते हैं। इन देशों में मत-प्रदर्शन की जो स्वतन्त्रता है उसी के

कारण गांधी भारत की आजादी के लिए अपने अहिंसक आंदोलन का युद्ध आरम्भ कर सके ।

गांधी के माथ एक सप्ताह अतिथि के रूप में रहकर मैं निरन्तर सोचता रहा कि इनकी शक्ति का रहस्य क्या है । कांग्रेस दल, जिसका ये बोर नेहरू नेतृत्व करते हैं, एक बड़ी ही ढीली-ढाली संस्था है । जिसके सदस्य चार आना वापिक चन्दा देते हैं; किन्तु ऐसा करने मात्र में वे किसी विशेष अनुशासन या कार्यप्रणाली से बंध नहीं जाते । गांधी के पास न धन है, न मर्ति और न संगठन-कार्य का कोई अमंत्र है । फिर भी उनमें ऐसे करोड़ों भारतीयों की श्रद्धा है जिन्होंने उन्हें कभी देखा भी नहीं । इनमें से बहुत से व्यक्ति उनके आह्वान पर भारी बलिदान कर सकते हैं, अपने प्राण और स्वतंत्रता को भी सड़क में डाल सकते हैं । जब वह अनगन करते हैं तो अमर्य्य व्यक्ति उत्कण्ठापूर्वक उनकी शय्या की ओर निहारते हैं । यह सब क्यों ?

इसका आशिक कारण धार्मिक है । भारत एक बड़ा ही धर्म-प्रधान देश है और हिन्दुओं की, जो गांधी के सबसे अधिक अनुयायी हैं, ईश्वर के सम्बन्ध में एक विचित्र भावना है । हिन्दू-धर्म एक व्यापक धर्म है । इसमें बौद्ध मत, ईसाई-मत और मूर्ति-पूजा—इन तीनों मतों के गुण हैं । गांधी पक्कै हिन्दू हैं, किन्तु वह कुरान से परिचित हैं और इस्लाम के कुछ सिद्धान्तों में विश्वास रखते हैं । गांधी के मिट्टी के बगले में एक ही सजावट का उपकरण है—महात्मा ईसाका चौखटे में जड़ा हुआ एक छपा चित्र, जिसके नीचे लिखा है—“वही हमारी शान्ति है ।” “मे क्राइस्ट का अनुयायी हूँ,” गांधी ने मुझसे कहा । हिन्दू धर्म सब धार्मिक सिद्धान्तों को खपा लेता है और किसी का उन्मूलन नहीं करता । इसलिए हिन्दू मत का कोई कट्टर अथवा आधारभूत सिद्धान्त नहीं है, इसके सभी आधारभूत सिद्धान्त परिवर्तनशील हैं, जिसका अर्थ यह है कि वास्तव में वे अनिवार्य सिद्धान्त नहीं हैं ।

हिन्दू धर्म इतना विशाल है कि इसमें नास्तिकता, अद्वैतवाद और मूर्तिपूजा तीनों के लिए स्थान है । हिन्दू मूर्तियों के आगे नृत्य और प्रार्थना करते हैं । किन्तु जब मैंने कुछ हिन्दुओं से पूछा कि क्या आप मूर्ति में विश्वास करते हैं, तो वे बोले—“नहीं हमारा विश्वास तो एक ईश्वर में है ।” नेहरू ने कहा—“यदि नियागरा जल-प्रपात भारत में होता तो वह भी एक देवता ही माना जाता । अमर्य्य हिन्दू गांधी को ईश्वर का अवतार मानते हैं । एक हिन्दू पूंजीपति से मेरी बात हुई । उनका कांग्रेस-दल में प्रेम नहीं और न उनका राजनीति से कुछ सम्बन्ध है, फिर भी दृढ़तापूर्वक उन्होंने मुझसे कहा—

गांधी जैसे महापुरुष हजार साल में एक बार ही जन्म लेते हैं, उनके स्वागत के लिए स्वर्ग के द्वार खले हैं।

किन्तु क्या कारण है कि गांधी की ही इतनी प्रतिष्ठा मिली और क्या कारण है कि मुसलमान और अहिन्दू भी उन्हें अपना नेता समझते हैं? सेवा-ग्राम-वास के छठे दिन मैंने यह प्रश्न गांधी के प्राइवेट सेक्रेटरी महादेव देसाई से किया, जो अब स्वर्ग सिंघार चुके हैं; और जिन्होंने १० वर्ष से अधिक गांधी की सेवा की थी। मैंने कहा—“इन दिनों मैं बराबर गांधी की अनन्त प्रभावशीलता के मूल कारण को समझने की चेष्टा करता रहा हूँ। अस्थायी-रूप से मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि इस प्रभाव का मुख्य कारण गांधी की लगन या राग है।”

“यह बात ठीक है” देसाई ने उत्तर दिया।

“मगर इस रोग का मूल कारण क्या है” मैंने पूछा।

वह बोले—“इसका मूल कारण उन सब रोगों का शमन करना है जो साम हट्टी के बने होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति में विद्यमान है।”

“आपका मतलब काम से है?” मैंने पूछा।

“काम, क्रोध और मोह”, देसाई ने गिनाते हुए उत्तर दिया। “गांधी अपनी गलती आप जान सकते हैं। वह अपने आपको दण्ड दे सकते हैं और दूसरों के दोषों को भी अपने ऊपर ले सकते हैं। वह पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में हैं। इसी के कारण उन में असाधारण शक्ति और राग का संचार होता है।”

राग सभी महापुरुषों का एक आवश्यक अंग है। वह सत् और असत् दोनों ही हो सकता है। हिटलर में भी यह प्रचुर मात्रा में था। राग बौद्धिक विषय-सम्बन्धी और नैतिक तीनों प्रकार का हो सकता है, किन्तु महापुरुष में यह होता है अवश्य।

इस प्रकार गांधी की महत्ता के रहस्य को समझने की चेष्टा करते समय मैंने स्वयं गांधी से पूछने का निश्चय किया। मैं उनके साथ सवेरे-शाम घूमता आया करता था। एक दिन शाम को मैंने उनसे कहा—“मैं आप से एक प्रश्न करने जा रहा हूँ जो व्यक्तिगत नहीं बल्कि राजनीतिक है। इतने लोगों पर अपने प्रभाव का कारण आप क्या समझते हैं?”

गांधी ने उत्तर दिया—“मैं सोचता हूँ कि मेरे प्रभाव का कारण यह है कि मैं सत्य का अनुयायी हूँ। सत्य ही मेरा ध्येय है। किन्तु सत्य केवल सत्य ही नहीं होता, इसका वास्तविक अर्थ दैनिक जीवन में व्यावहारिक

रूप से सत्य का अनुसरण करना है।” मेरे खयाल से उनका सकेत सात्विक जीवन की ओर था। यदि वह चाहे तो लोग उन्हें सभी कुछ दे सकते हैं, किंतु कुछ विशेष अवसरो को छोड़कर उनका भोजन, उनके वस्त्र और उनका घर ठीक उसी तरह का होता है जैसा हिंदुस्तान के ९० प्रतिशत लोगो अर्थात् किसानो का। कुछ लोग समझते हैं कि राजनीतिक प्रभाव डालने के लिए यह एक ढोंग है। चूँकि उन्हें इस प्रकार रहने की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह सब जान-बूझकर किया गया है। सभी त्याग ऐसे ही किये जाते हैं। गांधी इसी ससार में रहते हैं। ३० करोड़ से अधिक हिंदुस्तानी भी उसी ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वे गांधी में अपना प्रतिबिम्ब देखते हैं। गांधी के रहन-सहन के तरीके से उन्हें अपने को गांधी में मिलाने को सहायता मिलती है।

मैंने इस विषय पर और भी बातें की। घूमते-घूमते मैंने फिर पूछा—“क्या यह सत्य नहीं है कि जब आप स्वतन्त्रता का समर्थन करते हैं तो अनेक भारतीयों की हृदय-तन्त्री के तार भ्रूत हो उठते हैं। जिस प्रकार एक गायक अपने श्रोताओं को मोहित करने के लिए प्रयत्न करता है उसी प्रकार आप भी एक ऐसा स्वर निकालते हैं जिसे भारतवासी सुनने को तत्पर रहते हैं। मैंने देखा है कि जनता प्रायः, उन्हीं स्वरों का सबसे अधिक स्वागत करती है जिन्हें वह कई बार सुन चुकी है और जो उसे भाते हैं। क्या इसका यही कारण नहीं कि आप जो कुछ कहते और करते हैं वह वही है जो जनता चाहती है कि आप कहे और करे।”

गांधी ने कहा—“हां, हो सकता है कि यह बात ऐसी ही हो।”

गांधी की प्रभावशीलता एक जटिल तत्त्व है जिसके कई कारण हैं। एक कारण यह है कि भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम के नायक के रूप में गांधी ठीक समय पर अवतरित हुए हैं। एक नेता की हैसियत से उनका असली रूप १९१९ में प्रकट हुआ जब ससार के अनेक पराधीन देशों में, जिनमें भारत भी एक था, राष्ट्रीयता की लहर-सी फैल गई थी। प्रथम विश्व-युद्ध में इतने युवकों की आहुति के बाद भी स्वतन्त्रता की ओर नगण्य प्रगति होने के कारण सारे भारत पर निराशा के बादल छाये हुए थे। गांधी का उदय मानो देश की आवश्यकता और प्रार्थना का ही परिणाम था।

१९४२ की गर्मियों में हिंदुस्तान में एक बार फिर घोर निराशा छाई हुई थी। मार्च के महीने में सर स्टैफर्ड क्रिप्स चर्चिल सरकार के कुछ लिखित प्रस्ताव लेकर भारत आये थे। इन प्रस्तावों में भारत के शासन-विधान में कुछ

युद्ध-कानीन और कुछ युद्धोत्तर व्यवस्था की गई थी। विभिन्न कारणों से सभी भारतीय दलों ने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। क्रिप्स-मिशन की असफलता की प्रतिक्रिया-स्वरूप भारत में उत्साहहीनता और सकट दिखाई दे रहा था।

स्वभावतः गांधी कभी हतोत्साह नहीं होते। वह एक योद्धा है। निराशा के शिकार तो प्रायः अकर्मण्य ही होते हैं, कर्मठ लोग तो निराशा के मूल कारणों से जूझने में व्यस्त रहते हैं, वे निराशा के आगे झुकते नहीं। १९४२ में, जब मैं गांधी से मिला, तो ७३ वर्ष के होते हुए भी वह आशावादी, उत्साहपूर्ण और प्रसन्नवदन थे। अतीत में उनकी रुचि नहीं थी। लायड जार्ज की भांति अतीत की सस्मृतियाँ उनके मस्तिष्क में कभी नहीं उमड़ती थीं। वह भविष्य की ओर ही देखते ही थे। उनके जीवन का ध्येय, भारत की स्वतन्त्रता, अभी पूर्ण नहीं हुआ था।

भारत को स्वाधीनता प्रदान करने में क्रिप्स-मिशन की असफलता के कारण गांधी में कुछ करने की प्रेरणा उत्पन्न हुई। इष्ट-फल की प्राप्ति के लिए गांधी कर्म को साधन मानते हैं और प्रतिकार रूप में कर्म को स्वयं साध्य भी मानते हैं। उन्होंने एक बार मुझसे कहा—“चीन को अमेरिका और इंग्लैंड से कहना चाहिये कि हम अपनी स्वतन्त्रता की लड़ाई को आपकी सहायता के बिना स्वयं ही लड़ेंगे। स्वतन्त्रता में उसी को मानता हूँ। यह बुद्धिमत्ता है। औरों पर निर्भर रहकर जो स्वतन्त्रता प्राप्त की जाय वह वास्तव में स्वतन्त्रता नहीं होती। जिस साधन के द्वारा साध्य उपलब्ध किया जाय वह साधन भी उपलब्धि का आवश्यक अंग होता है। वास्तविक जन-तन्त्र में ऐसा ही होना चाहिए। स्टालिन के रूस में अच्छा और बुरा—दोनों ही—शिखर से आरम्भ होता है। सभी निर्णय चोटी के तानाशाही नेता करते हैं और फिर ये निर्णय ग्राम लोगों तक पहुँचाये जाते हैं, जो अधी आज्ञाकारिता के अभ्यस्त होने के कारण इन्हे मशीन की भाँति ग्रहण कर लेते हैं। एक ऐसी शासन-प्रणाली में जहाँ साध्य की वाछनीयता के कारण साधन भी वाछनीय मान लिया जाता है, साधन का कोई शैक्षिक और नैतिक महत्त्व नहीं रह जाता और उसके परिणाम स्वरूप सिडीपन और राजनीतिक अनैतिकता उत्पन्न होती है।

गांधी अपने-आपको जनतन्त्र का रक्षक घोषित नहीं करते, फिर भी यह हृदय से जनतन्त्रवादी है, क्योंकि वह साधनों के सम्बन्ध में बड़े सतर्क रहते हैं। किसी बात को वह छिनाकर नहीं रखते; अपने अनुयायियों से उनका ध्यान निरन्तर होता है, और वह ऐसे कार्यक्रम में विश्वास रखते हैं जिसे

नेता और अनुयायी दोनों एक साथ करे। वास्तव में गांधी का आदर्श यह मालूम होता है कि राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न स्वर-तालों के समन्वय से स्वयं ही एक मधुर स्वर निकले। उदाहरणार्थ, वह भारतीय राष्ट्रवादियों को आतंक या गुप्त कार्रवाई में भाग लेने का अनुमति नहीं देते। देश-व्यापी सविनय अवज्ञा आन्दोलन आरम्भ करने से पहले वह इसकी सूचना अंग्रेज अधिकारियों को दे देते हैं। जब आन्दोलन शुरू होता है तो कांग्रेस दल के नेता सार्वजनिक स्थानों में खड़े होकर अहिंसक असहयोग करने की इच्छा प्रकट करते हुए पुलिस को अपने को गिरफ्तार कराने के लिए आमंत्रित करते हैं, अंग्रेज तुरन्त ही उन सबको, जिनकी सत्याग्रहारी में होती है, पकड़कर जेल में ठूँस देते हैं। इसके बाद जनता चाहे वह कांग्रेस की सदस्य हो या न हो उस नेतृत्वहीन आन्दोलन में भाग लेने लगती है और अपने गाँवों और कस्बों में असहयोग आरम्भ कर देती है। वह कर देना बन्द कर देती है। यह सब उस समय तक चलता रहता है जब तक या तो आन्दोलन स्वयं क्षीण नहीं हो जाता या गांधी यह समझकर कि उनके उद्देश्य की पूर्ति अथवा आंशिक पूर्ति हो चुकी है या यह देखकर कि आन्दोलन असफल रहा है, उसे वापस नहीं ले लेते।

क्रिप्स मिशन की असफलता के परिणाम स्वरूप गांधी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन का निश्चय किया। आन्दोलन ९ अगस्त १९४२ को गांधी जी, नेहरू और हजारी दूसरे लोगों की गिरफ्तारी से आरम्भ हुआ। नेहरू १९४५ में छोड़ दिये गये।

जिन दिनों मैं गांधी के पास था उनके मस्तिष्क में आगामी आन्दोलन की रूपरेखा निर्धारित हो रही थी इसका बीजारोपण एक दिन आप-ही-आप मई के महीने में हुआ जब कि गांधी ने साप्ताहिक मीन धारण कर रखा था। उन्होंने मन में सोचा—“अंग्रेजों का चला जाना चाहिए” इस पर विचार कर लेने के बाद उन्होंने एक लेख लिखा और जो कोई भी सुनने को तैयार होता उससे वह इसकी चर्चा करते। उन्होंने मुझसे भी चर्चा की और बताया कि इस सविनय अवज्ञा आन्दोलन का उद्देश्य अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से चले जाने के लिए बाध्य करना है।

प्रतिदिन शाम को गांधी मुझसे एक घंटे बात किया करते थे। ठीक एक घंटे के बाद वह धोती के भीतर से अपनी निकल की बड़ी घड़ी निकालते और हसकर कहते “अब” जिसके सुनते ही मैं उठकर चल देता था। समय के वह बहुत पावन्द है।

तीसरे दिन मैं उनकी कुटिया के कच्चे फर्श पर पतले तख्तियों के पाम

बैठा था। हम उनके “भारत छोड़ो” प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे। मैंने कहा— “मेरा त्याग है कि अंग्रेजों के लिए भारत को पूर्ण रूप से छोड़कर चला जाना सम्भव नहीं होगा। इसका अर्थ तो भारत को जापान के हाथों में सौंपना होगा। इंग्लैंड इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होगा और न अमेरिका ही इसे पसन्द करेगा। यदि आप यह चाहते हैं कि अंग्रेज बोरिया-बदना बाधकर यहाँ से चले जाय तो आप निश्चय ही एक असम्भव बात की माग कर रहे हैं। यह तो वृक्ष के सामने भूकने के समान होगा। निश्चय ही आपका यह मतलब नहीं कि वे अपना सेनाये भी यहाँ से हटा लें।

गांधी की बुद्धि बड़ी कुशाल और प्रतिभाशाली है। किन्तु इस बार वह कम से-कम दो मिनट तक खामोश रहे, जिससे जान पड़ता था कि वह कुछ सोच रहे हैं। आखिर वह बोले “आप ठीक कहते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका तथा अन्य देश भी अपनी सेनाये यहाँ रख सकते हैं और भारत की भूमि का सैनिक कार्रवाई अड्डे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि जापान युद्ध में विजयी हो। मैं धुरी राष्ट्रों को विजयी देखना नहीं चाहता। किन्तु मेरा विश्वास है कि जब तक हिन्दुस्तानी स्वतंत्र नहीं हो जाते तब तक अंग्रेज जीत नहीं सकते। ब्रिटन कमजोर है और भारत पर राज्य करते हुए नैतिक दृष्टि से तो वह और भी अक्षणीय है। मैं इंग्लैंड का अपमान करना नहीं चाहता।”

तत्पश्चात् गांधी के लखपति मित्र जी० डी० बिड़ला ने, जो वस्त्र-व्यवसाय के राजा हैं, मुझे बताया कि उनके पास महात्मा गांधी का पत्र आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझसे बातचीत करने से इस विषय पर उनका मत बदल गया है। यही बात गांधी ने राजगोपालाचार्य से भी कही और राजगोपालाचार्य ने मुझे बताया। किन्तु गांधी के कई घनिष्ठ साथियों ने उनकी मौलिक याजना में इस सशोधन को पसन्द नहीं किया और शब्दों में उनके सामने अपना विरोध प्रकट भी किया।

“मैं समझीता-प्रेमी व्यक्ति हूँ, क्योंकि मुझे यह कभी निश्चय नहीं होता कि मैं ठीक रास्ते पर हूँ”, एक दिन गांधी ने मुझसे कहा। इस आश्चर्यजनक जटिल परिपक्व व्यक्तित्व का यह भी एक पहलू है। आगे चलकर उन्होंने कहा, “किन्तु इस समय मुझे सबसे अधिक चिन्ता अनिवार्य भविष्य की है।” यह उनके व्यक्तित्व का हमरा पहलू है। उन्होंने आयोजित सविनय अवज्ञा आन्दोलन को लागू करने से इन्कार कर दिया।

शुद्ध समाप्त होने तक आप इसे क्यों नहीं स्थगित कर देते ?”

“मैं नहीं हूँ।” “क्योंकि मैं तत्काल ही काम करना चाहता हूँ और लड़ाई के

रहते हुए देश के लिए अपने आपको उपयोगी बनाना चाहता हूँ," उन्होंने उत्तर दिया। मेरा ख्याल है कि उन्हें अपनी वृद्धावस्था का भी ध्यान था। हो सकता है भारत की स्वतंत्रता के लिए यह उनके जीवन का अंतिम काम हो। फिर भी उन्होंने कहा, "अपने प्रेज़िडेंट (रूजवेल्ट) से कह देना कि मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे इस कार्य को करने से विमुख कर सके।" यह उनके व्यक्तित्व का तीसरा पहलू है। एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ होने के कारण वह जानते थे कि यदि रूजवेल्ट उन्हें यह विश्वास दिला सके कि युद्ध में विघ्न न पड़ने देने के विचार से आन्दोलन स्थगित कर देना चाहिए, तो वाद में उनके लिए भारत का स्वाधीनता के मामले में हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जायगा।

शुरू में नेहरू गांधी की १९४२ की सविनय अवज्ञा की योजना के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उन्हें आशा थी कि भारत के शासन में परिवर्तन करने के लिए अमेरिका अपने प्रभाव का प्रयोग करेगा। वह अन्तर्राष्ट्रवादी और फाशिस्ट-विरोधी है। युद्ध से पहले भी वह फाशिस्ट अत्याचार और आक्रमण के घोर शत्रु थे। नेहरू को भय था कि यदि भारत में अंग्रेजी सरकार के कार्य में सार्वजनिक रूप से बाधा डाली गई तो उससे युद्ध कार्य में कठिनाई पैदा होगी। गांधी का दृष्टिकोण भारतीय था। स्वतंत्र राष्ट्र के अधिकारों से वंचित रहने के कारण बहुत से हिन्दुस्तानियों का दृष्टिकोण अपने देश पर ही केन्द्रित हो गया है, मुझ से एक बम्बई की महिला ने कहा—यह तो वही हुआ कि कोई आदमी जबरदस्ती हमारे घर में घुस आये और फिर बाहर निकलने से इकार करे। भारतवासी अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए इतने व्यग्र हैं कि प्रायः उन्हें और कुछ दिखाई ही नहीं देता। नेहरू तथा उनके कुछ साथी विश्वव्यापी दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं, किन्तु १९४२ में वे अपनी बात नहीं मनवा सके। गांधी ने नेहरू को सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समर्थन के लिए मना लिया।

इस जोश और अधीरता के होते हुए भी, गांधी बड़े सहिष्णु और परिपक्व हैं; नेहरू ऐसे नहीं। दो कारणों से वह अंग्रेज साम्राज्यवादियों को नापसन्द करते हैं। एक तो इसलिए कि वे (अंग्रेज) साम्राज्यवादी हैं और दूसरे इसलिए कि वे प्रतिगामी हैं। ४५ करोड़ चीनियों और विश्व की प्रगति पर साम्राज्यवाद का जो दूषित प्रभाव पड़ा है उसे वह भूलते नहीं। वह जानते हैं कि साम्राज्यवाद के कारण युद्ध निरर्थक हो जायगा और शांति भी नष्ट हो जायगी।

जब तक कि द्वितीय विश्व युद्ध में सभी पुराने साम्राज्यवाद धरा-
नहीं हो जाते। तब तक शांति से हमारे साम्राज्यवाद के उठ खड़े होने

की सम्भावना थी। यही भारत में मेरी दिलचस्पी का कारण था। भारत की स्वतंत्रता में मेरी रुचि इसलिए थी कि मैं उसे स्वतंत्र और श्रेष्ठतर ससार का प्रवेश-मार्ग समझता था। नेहरू के राष्ट्रवाद में यह अन्तर्राष्ट्रवाद निहित है, किन्तु गांधी को, नेहरू को यह विश्वास दिलाने में कठिनाई नहीं पड़ी कि जब तक अंग्रेजों को बाध्य नहीं किया जायगा तब तक वे भारत से कभी नहीं जायेंगे। अपने मित्र क्रिप्स के भारत में रहते समय और भारत से जाने के बाद के व्यवहार से नेहरू बहुत ही क्षुब्ध थे। अवज्ञा आन्दोलन का आश्रय लेने में उन्हें यदि सकोच था तो केवल इसलिए कि वह फाशिस्टों की विजय नहीं चाहते थे। किन्तु उनके पास गांधी की इस दलील का कोई उत्तर नहीं था कि यदि देश में एक ऐसी सार्वजनिक क्रान्ति हो सकी जिसके कारण अंग्रेज हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वराज्य देने को बाध्य हो जाय तो केवल भारत ही नहीं बल्कि चीन और सारे ससार में फाशिस्ट-विरोधी भावना प्रबल रूप से जाग्रत हो उठेगी और उसके फलस्वरूप मित्रराष्ट्रों की विजय शीघ्र हो सकेगी।

जून १९४२ में मैंने नेहरू को बम्बई की एक सार्वजनिक सभा में कहते सुना—“मैं स्वयं हाथ में तलवार लेकर जापान से लड़ूंगा; किन्तु मैं ऐसा खतर्क होकर ही कर सकता हूँ।”

इसलिए सिद्धान्त रूप से गांधी और नेहरू सहमत थे। युद्ध-काल में यदि भारत स्वाधीन हो जाता तो घुरी देशों के लोगों से हिन्दुस्तानी कह सकते—यद्यपि तुम्हारी पराजय हांगी फिर भी तुम्हारे लिए श्रेष्ठतर जगत् के द्वार खुल जायेंगे। इसी प्रकार वे घुरी-विरोधी राष्ट्रों से यह कह सकते—विजय के फलस्वरूप शांति और मानव-समाज की उन्नति होगी।

उस समय यदि अवज्ञा आन्दोलन के सम्बन्ध में नेहरू के मन में कोई शका रही होगी तो उसे गांधी के आग्रह ने दूर कर दिया होगा। गांधी स्वाधीनता आन्दोलन की सबसे मूल्यवान् विभूति है। वही वह पूजा है जिसके नेहरू उत्तराधिकारी बनेंगे। एक ऐसे युद्ध के समर्थन के प्रश्न को लेकर जो देश में लोकप्रिय नहीं समझा जाता था और जिसके सम्बन्ध में स्वयं उनका शपना मत निश्चित नहीं था, नेहरू कैसे अपने आप को इस उत्तराधिकार से दक्षित कर सकते थे।

सेवाग्राम में जब गांधी और नेहरू इस विषय पर बातचीत कर रहे थे तो नेहरू बहुत ही दुखी जान पड़ते थे। परन्तु जब वह एक बार गांधी के पक्ष में खड़े गये तो स्वयं गांधी से भी अधिक अदम्य होगये। जब मैं सेवाग्राम से लौटने लगा तो गांधी और उनके सेक्रेटरी, देसाई ने मुझसे कहा कि मैं वाइसराय

के सामने गांधी को बुलाकर बातचीत करने का प्रस्ताव रखू। गांधी को तब भा दुखदायी अवज्ञा आन्दोलन के रुकने की आशा थी। किन्तु बाद में जब बम्बई में मने नेहरू से पूछा कि क्या आप समझते हैं कि गांधी का वाइसराय से बातचीत करना ठीक होगा तो उन्होंने क्रोधपूर्वक कहा—“नहीं, व वाइसराय से क्यों मिले ?” अब नेहरू अपना निश्चय कर चुके थे।

गांधी में कटुता नहीं है। अंग्रेज नेहरू से बात करने की अपेक्षा उन्हें बात करना अधिक अच्छा समझते हैं। मैं हिन्दुस्तान में जितने भी अंग्रेज उच्चाधिकारियों से मिला नेहरू के बारे में सभी ने नाक-भी मिकोटकर बात की किन्तु गांधी के बारे में नहीं। गांधी को न समझने पर भी अंग्रेज यह समझ सकते हैं कि वह इस प्रकार व्यवहार क्यों करते हैं। किन्तु उनकी समझ में नहीं आता कि नेहरू, जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है और जो ऊंचे घराने में जन्मे हैं, उनका क्यों विरोध करते हैं। नेहरू से वे अधिक नाराज इसलिए हैं कि वे समझते हैं कि कहीं तो नेहरू को हमारा साथ देना चाहिए और कहीं का हमारा इतना कड़ा विरोध करते हैं।

नेहरू की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है और वह एक सुन्दर लेखक है। साफ सुथरे, सत्यवादी, आत्मालोचक और नम्र है। मर्यादा और क्रोध उनके प्रमुख गुण हैं। आधुनिक जीवन में मानव पर जो अपमान लादे जाते हैं, उनके प्रति उनका रोम-रोम विद्रोह करता है।

अपने जीवन का प्रथम भाग नेहरू ने एक महान् व्यक्ति की प्रतिच्छाया में व्यतीत किया है। वह महान् व्यक्ति उनके पिता स्वर्गीय प० मोतीलाल नेहरू थे। अपने जीवन का दूसरा भाग नेहरू ने एक दूसरे महान् व्यक्ति की प्रतिच्छाया में बिताया है। वह दूसरा व्यक्ति है मोहनदास कर्मचन्द गांधी। जब तक वह इस प्रतिच्छाया से मुक्त नहीं होंगे तब तक उनकी अपनी महानता पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगी।

इतिहास ने नेहरू को एक विशेष कार्य सुपुर्द किया है। भारतीय स्वाधीनता का आन्दोलन स्वतंत्र और एकान्त बनने की एक आदि-प्रेरणा है। साथ-ही-साथ वह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए भी एक सघर्ष है। नेहरू का कर्तव्य देश को आर्थिक अभावों और भय से मुक्त करना है। वे इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं।

भारत की समस्याएं

भारत में सात दिन रह चुकने के बाद (ये सब दिन नई दिल्ली ही में कटे) मैंने अनुभव किया कि बड़ी-से-बड़ी दूरी जो मैंने पैदल तय की थी वह घी टैंकी से मकान के दरवाजे तक का रास्ता। चुनाचे मैंने घूमने का निश्चय किया। मैं मूरज के डूबने की प्रतीक्षा करने लगा। किन्तु मकानों और फर्शों में इतनी गरमी निकल रही थी और हवा भी अभी इतनी गरम थी कि मैं मुश्किल से चल पाया और सड़क पार कर कनाॅट सर्कस के बड़े पार्क में जा बैठा। खड़े होकर मैंने चारों ओर देखा, थोड़ा-सा चला और फिर बैठ गया। गरमी के कारण घूमना मुश्किल था।

पार्क में एक जगह साफ और चमकदार आँखों वाले भूरे रंग के १२ लडके हाकी के बल्ले लिये घास पर बैठे थे। वे सम्भवतः अपने खेल के बारे में कोई सभा कर रहे थे। इधर-उधर लडके हवाई हमलों से रक्षा के लिए खोदी गई खाइयों के अन्दर-बाहर दौड़ रहे थे। बड़े लोग छोटी-छोटी सूखी घास पर बैठे थे। कभी-कभी हरी, गुलाबी और टमाटर के रंग की चमकती हुई साटी की झलक भी दिखाई दे जाती थी।

पार्क के किनारे-किनारे जो पगडंडी बनी थी उस पर लकड़ी की एक उंची प्याऊ थी जिसमें दो बड़े मटके रखे थे। इनके पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह एक काँसे के लोटे से पानी निकालकर पीने आने वाले व्यक्तियों के घुल्लू में डाल देता था। मैं प्याऊ को देख रहा था। सफेद सूट पहने एक और आदमी भी उधर ही देख रहा था। वह हँसा और मेरी ओर सकेत भेजते उसने मुझे भी पानी पीने को कहा। मैं उसके पास गया। उसने अग्रजी में मुझे बताया कि वह एक डॉक्टर है। वह प्याऊ उसी की दिशाई हुई थी। रात्रियों को चारों ओर मील भर तक बड़ी पीने का पानी नहीं मिलना था, इसलिए उसने वह प्याऊ लगवाई थी। इसी प्रकार वह और उसके पाँच मित्र कनाॅट सर्कस में पानी पिलाने का प्रदग्ध प्रतिवर्ष करते थे। प्रत्येक

व्यक्ति को ५०) मामिक खर्चा पड़ता था और प्याऊ गरमियों में पाँच छ. महीने रहती थी। डॉक्टर ने बताया कि नई दिल्ली में भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा बिठाई गई इस प्रकार की बीसियों प्याऊ हैं। उसने यह भी कहा, कल वर्क मिल सकेगी और एक नली भी आ जायगी और फिर मटको को ऊपर से ढाप दिया जायगा। जितनी देर हम बातें करते रहे लोग बराबर पानी पीने आते रहे।

“पानी का प्रबन्ध अधिकारी क्यों नहीं करते” मैंने पूछा।

उसने जवाब दिया—‘यह तो मैं आपसे पूछता हूँ। हम कई बार सरकार के पास आवेदन-पत्र भेज चुके हैं, किन्तु वह कहते हैं कि पार्क में पाइप या फव्वारे लगाने से पार्क की शोभा जाती रहेगी। ये प्याऊ हम अधिकारियों की आज्ञा के बगैर बिठाते हैं और उन्होंने हमसे ऐसा न करने के लिए कह रखा है। हमें इस कार्य के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है’। उम आदमी ने बताया कि वह कांग्रेस-दल का सदस्य है और क्षत्रिय है, जिसकी गणना ब्राह्मणों के बाद होती है। “लेकिन आज हमारे पास शस्त्र नहीं है और हम लड़ नहीं सकते”, उसने कहा।

अमेरिकन हवाई सेना के कप्तान कुलर और मैं होटल की दूसरी मजिल से झुककर बाहर देख रहे थे। अमेरिकन सेनाओं के लिए बनाये जाने वाले मकानों आदि की चिनाई में काम करने वाले भारतीय मजदूर और मजदूरनियाँ पुरानी दिल्ली अपने घरों को वापस जा रहे थे। पुरुष प्रायः नगें थे और केवल एक लँगोटी बाँधे हुए थे, किन्तु स्त्रियाँ जिप्सियो (खानाबदोशों) की तरह रंग-बिरंगे लँहगे पहने हुए थीं। बहुत-सी स्त्रियो ने गोद में बच्चे ले रखे थे। भुल-सती हुई धूप में १० या १२ घंटे काम करके अब ये लोग चार या पाँच मील पदल-पुरानी दिल्ली में अपने-अपने घरों को जा रहे थे। वे सब दीनता के क्षीण प्रतीक जान पड़ते थे।

“कितना भयानक दृश्य है।” मैंने कप्तान से कहा।

‘यह गुलामी है, गुलामी’ कप्तान ने उत्तर दिया। वह दक्षिण करो-लिना का रहने वाला था।

कुछ दिन बाद मैंने वाइसराय की कार्यकारिणी के एक अग्रेज सदस्य से खाने पर पूछा कि नई दिल्ली में इतनी बसे क्यों नहीं हैं जिस पर चढ़कर ये लोग घर जा सकें ?

“ये लोग बसों का किराया नहीं दे सकते।” अग्रेज सदस्य ने उत्तर

हैदराबाद में जब मैं रेलगाड़ी में सवार हुआ तो मेरे डिब्बे में एक हिंदुस्तानी भी था। हैदराबाद शहर हैदराबाद रियासत की राजधानी है। इस रियासत पर निजाम राज्य करता है, जो ससार का सबसे धनी आदमी माना जाता है। मेरे डिब्बे में जो आदमी बैठा था वह हिंदुस्तानी मुसलमान था और भारतीय हवाई सेना में अफसर था। वह अपने स्क्वाड्रन के लिए एक नया वायुयान लेने पूना जा रहा था। वह जापानियों के विरुद्ध बर्मा में लड़ चुका था। यद्यपि वह स्वेच्छा से भरती होकर अंग्रेजों के साथ तीन वर्ष तक सेना में काम कर चुका था, फिर भी अंग्रेजों की जैसी निन्दा उसने की ऐसी मैंने किसी और भारतीय के मुख से नहीं सुनी। खिड़की की ओर उ गली करते हुए वह बोला—“इन आदमियों की तरफ देखिये। इन्हें जानवरों की तरह जिदगी बितानी पड़ती है।” हम गाँवों में से होकर गुजर रहे थे, जहाँ लोग बास या गारे या दजूर की जान्वाओं से बनी हुई भोंपड़ियों में रहते थे। बड़े-बड़े लड़के तब दिलकुल नगे थे। स्त्रियाँ चियड़े पहने थी और पुरुष लंगोटी। “अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान का जोषण किया है” वह अफसर बोला “जब तक मैंने जॉन गन्धर की पुस्तक ‘इन्साइड एशिया’ नहीं पढ़ी थी तब तक मुझे इसकी अधिक जानकारी नहीं थी। अंग्रेज हमें जान-बूझकर अज्ञानी और गरीब बनाकर रखते हैं और हमारे देश के विकास को रोकते हैं।”

हिन्दुस्तान में दो-चार दिन रहने के बाद ही पता चल जाता है कि यहाँ भयानक दरिद्रता है और सभी वर्गों और दलों के लोग हृदय से अंग्रेजों के विरोधी हैं।

दाइसराय की कार्यकारिणी के सदस्य, सर फीरोज खा नून ने एक दिन मुझे कहा—“अंग्रेज एशिया और अफ्रीका में कहीं भी स्थानीय लोगों को मित्र नहीं बना सके और न उनके रहन-सहन में आधुनिक सुधार कर सके। न्यूयार्क की तो बात दूर है, लन्दन और पेरिस में भी हम आज जो कुछ देखते हैं वह सब पिछले १५० वर्षों में ही जुटाया गया है। किन्तु हिन्दुस्तान में १५० वर्ष में प्रायः कुछ भी नहीं बदला; चारों ओर वही दारुण दरिद्रता और फटे चियड़े दिखाई देते हैं। हाँ, यह बात ठाक है कि यद्यपि हिन्दुस्तानी अधिक नहीं खाते फिर भी मरते कम हैं क्योंकि अंग्रेजों ने स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्थाएँ कर दी हैं।” नून मुसलमान जमींदार है। वह अंग्रेजों से सहयोग करते हैं और गांधी-विरोधी हैं।

“हिन्दुस्तान के अंग्रेजों में दहा साम्राजिक अहंकार है और वे हमारा शक्तिशाली जोषण करते हैं।” यह मुझसे दाइसराय की कार्यकारिणी के सप्लाई

सदस्य, सर हामी मोदी ने कहा । मोदी एक लखपति पारसी है ।

स्वयं लार्ड लिनलिथगो ने मुझे कहा था—“हिन्दुस्तान इतना इंग्लैण्ड-विरोधी कभी नहीं रहा है जितना आज है ।”

भारतीय पत्रकार-संघ ने मुझे बम्बई में अपनी एक सभा में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया । यह तय पाया कि भाषण देने की वजाय में प्रश्नों के उत्तर दूंगा । एक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैंने युद्ध-प्रयत्नों के समर्थन पर जोर दिया और यह बताने का प्रयत्न किया कि यदि फाशिस्टों की विजय होगई तो भारत पर और हम सब पर क्या बीतेगी ।

“भारत के लिए जापानी फाशिस्टवाद और अग्रेजी फाशिस्टवाद में कोई अन्तर नहीं है” पत्रकार बोला ।

मैंने कहा—“देखिये, इंग्लैण्ड फाशिस्ट नहीं है । इंग्लैण्ड बहुत ही जन-तंत्रवादी है और कई राजनीतिक मामलों में तो वह अमेरिका से भी अधिक जनतंत्री है । मैं जानता हूँ कि कभी-कभी भारत में अग्रेज दमन के जो कार्य करते हैं उन्हें आप पसन्द नहीं करते । किन्तु मैं जब से इस देश में आया हूँ हर चार-पाँच आदमियों में से एक ने मुझे बताया है कि वह जेल हो आया है । मैं रूस और जर्मनी में सालों रहा हूँ । उन देशों में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दे जो जेल होकर आया हो । वहाँ ता जो एक बार जेल में जाता है वह जेल का ही हो रहता है और बहुत-से तो वहाँ गोली से उड़ा दिये गये हैं ।”

एक दूसरा भारतीय पत्रकार बोला—“अग्रेज उसे गोली से नहीं मारते, वे हमें हलाल करते हैं ।”

मैंने उससे इस बात का अभिप्राय पूछा । उसने कहा—“हिन्दुस्तान में औसत आयु २७ वर्ष की है ।” यही अक वाद में मैंने सरकारी अक-संग्रह में भी देखा । इंग्लैण्ड में औसत आयु ६० और अमेरिका में ६३ वर्ष की है ।

तीसरे पत्रकार ने बताया कि “भारत में जन्म लेने वाले बच्चों में से ४५ प्रतिशत ५ वर्ष के होने से पहले ही मर जाते हैं ।” यह भी जन-संख्या-की पुस्तक में लिखा हुआ है ।

बम्बई की मजदूर-वस्तियों और थाना जिले में, जो बम्बई से अधिक दूर नहीं हैं, मैंने जैसी भयंकर दग्धता देखी वैसी न तो १९२० से बाद के रूस और पोलैंड में देखी न १९३० के बाद-स्पेन के भूखे-नगरे देहातों में । पर्लबक का कहना है हिन्दुस्तानी किमान चीनी किमान से भी अधिक गरीब है । मिलों में काम करने वाले मजदूर किसानों से नाम मात्र के लिए अच्छे हैं । “लंदन इकानोमिस्ट” के अनुसार जितने में “हिन्दुस्तानी मजदूर साल भर तक गुज़र करते हैं,

उतना तो अंग्रेज मजदूर केवल सिगरेट तम्बाकू में फूँक डालता है ।” सन् १९३१ की जन-संख्या संबंधी पुस्तक की भूमिका में ब्रिटिश जन-संख्या विभाग के प्रमुख अफसर, श्री जे० एच० हटन ने लिखा है कि बम्बई में “२, ५६, ३७९ लोग एक कमरे में ६-६ या ९-९ के हिसाब से रहते हैं..... बम्बई के अधिकांश निवासियों को प्रति व्यक्ति ६ वर्ग फुट के हिसाब से रहने का स्थान मिल पाता है ।” तब के बाद से बम्बई की आवादी और भी अधिक हो गई है ।

यह बात अक्षरशः सत्य है कि भारत के कई करोड़ निवासी हमेशा भूखे रहते हैं । निरन्तर कष्ट देने वाली इस स्थायी भूख के कारण केवल शरीर की जाति ही क्षीण नहीं होता—मस्तिष्क भी पेट में उतर आता है । हिन्दुस्तानी ग्रामीण यह नहीं जानते थे कि युद्ध में कौन किसके साथ लड़ रहा है और अंग्रेज किसकी ओर से युद्ध कर रहे हैं । जब मैंने उनसे पूछा कि लडाई के बारे में तुम्हारा क्या खयाल है, तो उन्होंने जवाब दिया—“हम भूखे हैं ।” इसी तरह जब मैंने पूछा कि अंग्रेजों की तरफ से तुम्हारा क्या खयाल है, तब भी उन्होंने यही उत्तर दिया—“हम भूखे हैं ।”

भारतीय राजनीति की रूपरेखा पेट में तैयार की जाती है ।

भारत की वर्तमान दशा के कारण भारत के इने-गिने शिक्षित और राजनीतिक लोगों में अंग्रेजों के प्रति शत्रुता के भाव पैदा होगये हैं ।

जब मैं वैभवशाली देशी नरेशों और लखपती व्यवसायियों से मिला तो मैंने भर्त्सना की कि आप लोग अपनी जनता के दुःख-निवारण में अधिक सहायता क्यों नहीं देते ? वे इस दिशा में अधिक प्रयत्न कर सकते हैं और उनमें से इस-ऐसा करते भी हैं । किन्तु चालीस करोड़ लोगों को तिल भर भी ऊपर उठाना एक महान् कार्य है और इस कार्य को कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता । भारत में अकेले ब्रिटेन में सम्भवतः इस समस्या को हल करने की क्षमता नहीं है । इसके लिए उस तरह के अन्तर्राष्ट्रीय साधनों को जुटाने की आवश्यकता है जिनके फलस्वरूप परमाणु बम बनाया जा सका और घुरी राष्ट्र हराये जा सके ।

भारत की आवादी ५० लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से बढ़ रही है । श्री हटन ने १९३१ की सरकारी जन-संख्या-पुस्तक में लिखा था—“इंग्लैंड में जाति जितने घनी हैं उतनी ही कम उनमें जन्म संख्या पाई जाती है ।” उनका मत है कि भारत, चीन और रूस में अधिक जन्म संख्या का यह भी कारण है कि शहर गिन लिखा जाय कि धार्मिक या राजनीतिक कारणों से सरकार हस्त-क्षेप करेगी तो इस दशा में सन्तति-निग्रह की सफलता एक सीमा तक सिद्धा,

ट्रेनिंग और ऐसे साजो-सामान पर निर्भर होगी जो एक औसत दर्जे के भारतीय के लिए महंगा पड़ेगा। इसलिए भारत में जन्म-संख्या घटाने के लिए उत्तमतर आर्थिक अवस्था की सबसे पहले जरूरत है। यह भी ठीक है कि जन्म-संख्या में कमी होने से रहन-सहन की अवस्था में सुधार होगा, किन्तु जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है। आर्थिक दशा को सुधारने से पहले सन्तति-निग्रह पर जोर देना बिल्कुल उलटी बात होगी।

सरकारी जन-संख्या-विवरण के अनुसार भारत की आबादी १९३१ में ३३,८०,००,००० थी और १९४१ में ३८,५०,००,००० थी, अर्थात् १० साल में जन-संख्या में ५ करोड़ की वृद्धि हुई। यही भारत की सबसे बड़ी समस्या है।

सोवियत रूस में, अपूर्व औद्योगिक प्रसार के दिनों में, जब पचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत बड़े-बड़े कारखानों और महान् नगरों का आविर्भाव हो रहा था, उपयोगी धन्वों में हर साल दस लाख आदमी खप जाते थे। किन्तु भारत में जहाँ प्रति वर्ष ५० लाख नये पेट उत्पन्न होते हैं, पिछले बीसियों सालों से बहुत हा कम औद्योगिक उन्नति हुई है। सन् १९२२ में प्रकाशित एक सरकारी अंग्रेजी पुस्तक में इंडियन मेडिकल सर्विस के डाइरेक्टर जनरल मेजर-जनरल सर जॉन मिगाव ने लिखा था—“यह स्पष्ट है कि जीवन की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है उससे कहीं अधिक वृद्धि आबादी में हो रही है। अतः स्थिति में यदि कोई मौलिक परिवर्तन न हुआ तो अधिक जीवन का मौजूदा मान जो पहले से ही बहुत नीचा है, अनिवार्य रूप से और भी नीचा होता जायगा। एक सीमा तक भविष्य निश्चय ही अन्धकार पूर्ण है।” वाद की घटनाओं ने मिगाव की शोकपूर्ण भविष्य वाणी की पुष्टि की। हिन्दुस्तान में रहन-सहन का मान बराबर घटता जा रहा है।

द्वितीय विश्वयुद्ध के दिनों में भारत के इसपात और अस्त्र-शस्त्र के उत्पादन में वृद्धि हुई, किन्तु समग्र औद्योगिक उत्पादन में कमी हुई।

भारत में मैंने ऐसे कई ब्रिटिश कागजात और सरकारी वक्तव्य प्राप्त किये थे (वे प्रकाशित भी किये जा चुके हैं) जिनसे यह सिद्ध होता है कि भारत के औद्योगिक विस्तार में ब्रिटिश सरकार ने बाधाये डाली हैं। हिन्दुस्तान से न्यूयार्क आते हुए मैं जब फिलस्तीन में ठहरा तो मैंने यह बात अपने मित्रों से कही। उन्होंने बताया कि फिलस्तीन में भी अंग्रेजों की यही नीति है और साम्राज्यवादियों की तो सभी जगह यही नीति है उपनिवेशों को कच्चे माल या आधे तैयार किये हुए माल के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाय। “फार्चून” पत्रिका के सम्पादक स्वर्गीय रेमंड लेस्ली वूएल ने लिखा था—“अमेरिका की क्रान्ति मुख्यतः व्यापार-

वृत्ति के प्रति और जहाजरानी, चीनी स्टाम्प आदि कानूनों में निहित शोषण के प्रति विद्रोह था। ब्रिटेन ने उपनिवेशों को उस समय तक व्यापार, उत्पादन और भूमि तक में विस्तार करने का अधिकार नहीं दिया जब तक कि उससे ब्रिटेन के व्यापारियों को प्रत्यक्ष लाभ न हो।” सन् १७७६ की अनुदार मनोवृत्ति आज भी जोरों पर है। साम्राज्यवाद उतना ही बदलता है जितना उसे बाध्य होकर बदलना पड़ता है। आर्थिक उन्नति में वह बाधक होता है।

भारत, चीन (जो नाम मात्र के लिए स्वतंत्र होते हुए भी अभी अर्ध-शोपनिवेशिक अवस्था में है) एशिया और अफ्रीका के अन्य शोपनिवेशिक देश और लैटिन अमेरिका के भी बहुत से भाग आर्थिक दृष्टि से मरुभूमि के समान हैं। इस मरुभूमि में १५ खरब प्राणी निवास करते हैं। उन्हें खाने और पहनने की बहुत कम मिलता है और रक्षा के लिए स्थान भी कम मिलता है। उत्पादन और उपभोग दोनों ही का स्तर इतना नीचा है कि लज्जा आती है। इन देशों में समस्त ससार की तीन चौथाई जनता निवास करती है और वह शेष चौथे भाग को भी नीचे की ओर घसीटती है।

पूरब के पिछड़े रहने के कारण पश्चिमी ससार को आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक क्षति उठानी पड़ती है। निर्धन, रोगी और अपराधी चाहे किसी भी समाज के हो वे सबके लिए भार-समान ही होते हैं। ससार आखिर एक ही जाति तो है।

यह एक पागलपन की-सी बात मालूम पड़ती है कि जिस ससार में उत्पादन की इतनी शक्ति हो जितनी कि उसने युद्ध के दिनों में दिग्विधौ, करोड़ों पुरुष, स्त्रियाँ और बच्चे बेकार, भूखे, नग्न और अरक्षित रहे। यह सब पागलपन ही नहीं घोर अपराध है, ईसाइयत और जनतंत्र के सिद्धान्तों के विलकुल विपरीत है।

वर्तमान युग की महान् चुनौती यह है कि जिस प्रकार आजकल हम रह रहे हैं और जिस प्रकार हम मशीनी और टेक्निकल प्रगति का पूरा लाभ उठाने के दावद रह सकते हैं, उन दोनों में साम्य स्थापित करें। पृथ्वी के गर्भ में असीम सम्पत्ति छिपी पड़ी है और यदि हमें अधिक सम्पत्ति की आवश्यकता होगी तो हमारी निर्माण-शक्ति का जादू उसे समुद्र के जल, समुद्र के घाम-प्लव, बोयले की राख और रेत में पैदा कर देगा। परमाणु का विस्फोट हमारे सामने अक्षयनीन सम्पत्ति उपस्थित कर देगा। इस सम्पत्ति को उपभोग के योग्य बनाने के लिए हमारे पास असीम जन-शक्ति है जो प्रत्येक नई मशीन के साथ बढ़ती जाती है। जन-शक्ति, सृष्टि-शक्ति और भौतिक सम्पत्ति के इन अक्षय

भण्डार के रहते हुए वह सभ्यता, जो दरिद्रता, रुग्णता और निरक्षरता को सहन करती है, हास्यास्पद प्रतीत होती है।

वास्तव में दोष गताब्दियों की दीर्घायु का है। शताब्दियां बीत जाती हैं किन्तु उनकी विचार-धाराएँ, उनके राजनीतिक, और आर्थिक रूप तथा उनके नैतिक मान-बाद में भी हमें परेशान करते रहते हैं। विज्ञान के द्वारा हमें इक्की-सवीं शताब्दी का भी पूर्वाभास हो गया है। विज्ञान ने बाहुल्य और स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसी के द्वारा मानव को पृथ्वी की आकर्षण शक्ति और शून्य के बन्धनों से मुक्त होने की आशा है। किन्तु राजनीति अब भी उसी दकियानूसी काल में फँसी है, जब न भाप के इंजन थे न विजनी थी और न हवाई जहाज थे। राजनीति मध्ययुग के पक में उलझी हुई है और हमने मानव को भय और अभाव की रस्सी में जकड़ रखा है। राजनीतिज्ञ अब भी भौगोलिक सीमाओं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और साम्राज्यगत आधिपत्य के आवार पर शांति-संधियां करते हैं।

या तो राजनीति विज्ञान को ले बैठेगी या विज्ञान, जिसकी शक्तियों पर घगठित मानव का नियंत्रण नहीं है, भूमंडल की धज्जियाँ उड़ा देगा।

जीवन से भारतीयों को जो कुछ मिल सकता है और जो वास्तव में मिल रहा है उन दोनों के बीच इतना अखरने वाला और उन्माद-प्रेरक अंतर है कि इसी से भारत के नैराश्य, असन्तोष और क्षोभ का पता चल जाता है। भारत भूमण्डल का पंचमाश है। गत ५० वर्षों में एशिया की जन-संख्या दुगुनी होगई है। आज एशिया जाग्रत अवस्था में है। उसे स्वाधीनता, सुरक्षा, समृद्धि और गौरव की चाह है। आर्थिक या राजनीतिक दृष्टि से यह ससार उस समय तक निष्कलेश नहीं हो सकता जब तक कि एशिया और दूसरे भूखंडों के खरबों जीव उस सुख-सुविधा में हिस्सा नहीं लेते जो उन्हें मनुष्य द्वारा खड़ी की गई पुराने ढंग की बाधाओं के हटते ही प्राप्त हो सकती है।

भारत की सभी समस्याएँ—राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक—भारत की करुण दरिद्रता और अवरुद्ध आर्थिक गति की काली पृष्ठभूमि में ही समझी जा सकती हैं। उदाहरणार्थ, हिन्दू-मुस्लिम समस्या पर भारत के व्यावसायिक पिछड़ेपन का विचित्र किन्तु गहरा प्रभाव है। भारतीय शहरों में रोजगार बहुत ही सीमित है जिसके फलस्वरूप सरकारी नौकरियाँ ही भारतीयों का मुख्य व्यवसाय बन गया है। इनके लिए प्रतिस्पर्धा बड़ी तीव्र रहती है और बहुत से हिन्दुस्तानी इनमें खप भी जाते हैं, क्योंकि अंग्रेजों को शहरी रयों की बहुत बड़ी संख्या में आवश्यकता रहती है। भारत में ब्रिटिश

जासक बड़े कमाल के साथ शासन करते हैं। उनकी शासन-संस्था तो कही दिखाई देती ही नहीं। वाइसराय के गोपनीय सेक्रेटरी सर जॉन थॉर्न ने, जिनके साथ मैं एक बार खाने पर मिला था और जिनसे मैंने कुछ आँकड़े मागे थे, मुझे १३ जुलाई १९४२ को लिखा कि इंडियन सिविल सर्विस में ५७३ अंग्रेज हैं और इंडियन पुलिस में ३८६ बड़े और लगभग ४५० छोटे अंग्रेज अफसर हैं। माराज निकालते हुए सर जॉन ने लिखा—“इसलिए यह कहना ठीक होगा कि कुल मिलाकर भारत पर शासन करने वाले अंग्रेजों की संख्या १४०० है।” यह तो ठीक है कि ब्रिटिश शक्ति का प्रतिनिधित्व ब्रिटिश जल और थल सेनाओं और अप्रत्यक्ष रूप से, व्यापारी वर्ग में भी है किन्तु शासन के वास्तविक यंत्रको चलाने वाले अंग्रेजों की संख्या १४०० ही है, शेष सब हिन्दुस्तानी हैं।

आई० सी० एस० और शासन-सम्बन्धी दूसरी नौकरियों में ऐसे हजारों हिन्दुस्तानी भरती किये जाते हैं जिन्हें इन नौकरियों का काम विशेष रूप से सिखाया गया होता है। ये लोग सभी सम्प्रदायों और वर्गों के होते हैं किन्तु हिन्दू इनमें सबसे अधिक होते हैं। ग्राम तौर पर भारत में इसका कारण यह बताया जाता है कि हिन्दू अधिक शिक्षित और बुद्धिमान होते हैं। मेरे खयाल में बात कुछ और है। जब अंग्रेज भारत में आये तो उन्होंने मुसलमान शासकों को पद-च्युत किया। सन् १८५७ के विप्लव के बाद तो विशेष रूप से अंग्रेज मुसलमानों से, जिन्होंने विप्लव में प्रमुख भाग लिया था, सशक रहने लगे। इसलिए मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने से हतोत्साह किया जाता था। इसके अलावा चूँकि कुरान के अनुसार सूद खाना वर्जित है, इसलिए और अन्य कारणों से भी मुसलमानों ने लेन-देन, उद्योग-धंधे और बड़े व्यापार हिन्दुओं के हाथों में छोड़ दिये। परिणाम यह हुआ कि मुसलमान या तो बड़े जमींदार बने रहे या छोटे किसान। शहरों में रहने वाले मध्यम-वर्ग के मुसलमानों की संख्या नहीं के बराबर थी।

शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के हिन्दुओं और धनी हिन्दू और पारसी व्यवसायियों ने यह महसूस किया कि अंग्रेज हमारे आर्थिक विकास में तो रोड़े अटकते ही हैं साथ-ही-साथ सामाजिक व्यवहार में भी वे हमारा अपमान करते हैं। अतः वे भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन करने वाली संस्था कांग्रेस में प्रधान कार्यकर्ता और प्रतिपालक बन गये। कांग्रेस ने हिन्दू और मुस्लिम दोनों वर्गों की सहानुभूति भी प्राप्त कर ली।

जबकि मध्यम और उच्च वर्ग के हिन्दू अंग्रेजों के विरोधी थे, इसलिए बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में अंग्रेजों ने मुसलमानों की लालो-चप्पो करनी शुरू की।

हिन्दू पूजीपति राष्ट्रीय स्वाधीनता चाहते हैं ताकि वे साम्राज्यवाद का प्रतिस्पर्धा और हस्तक्षेप से बचे रहकर फल-फूल सकें। दूसरी ओर मुस्लिम जमींदारों को भय है कि अगर स्वतंत्रता प्राप्त करते ही हिन्दुओं ने जमींदारी प्रथा में संशोधन कर दिया तो उनकी सम्पत्ति और आय सकट में पड़ जायगी। इसलिए उच्चवर्गीय मुसलमानों के हृदय में स्वतंत्रता के लिए स्थान नहीं है। श्री मुहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग में अधिकतर उच्चवर्ग के मुसलमान ही हैं।

मुसलमानों में भी एक मध्यम वर्ग की स्थापना करने के अभिप्राय से सरकारी नौकरियों का एक अंश मुसलमानों के लिए सुरक्षित कर दिया गया, चाहे वे इन नौकरियों के लिए हिन्दू उम्मीदवारों की अपेक्षा कम योग्य ही क्यों न हों। सन् १९०६ में अंग्रेजों ने जाति या धर्म के आधार पर पृथक्-निर्वाचन-पद्धति स्थापित की जो अब भी जारी है। इसके अनुसार सार्वजनिक चुनाव आदि में हिन्दू केवल हिन्दू के लिए और मुसलमान केवल मुसलमान के लिए मत दे सकते हैं। इस प्रकार मुस्लिम राजनीतिज्ञों की आकांक्षाओं को प्रोत्साहन मिला, मुसलमानों में एकता का सूत्रपात हुआ और साम्प्रदायिक भेद-भाव दृढ़ होते गये।

शहरों में पुराने मध्यम वर्ग के हिन्दुओं के मुकाबले में एक नये मध्यम वर्ग के मुसलमान खड़े होगये। मुसलमानों का राजनीतिक समर्थन प्राप्त करने के लिए अंग्रेज उन्हें प्रोत्साहन देने लगे। इसके कारण हिन्दू अंग्रेजों का और भी अधिक विरोध करने लगे और हिन्दू-मुसलमानों का पारस्परिक वैमनस्य बढ़ गया।

भारत में मैं जिस किसी से भी मिला—इनमें भारत के वाइसराय, सर आर्चिबाल्ड वेवल, अनेक सर्वोच्च अंग्रेज अधिकारी, जिन्ना, गांधी, कांग्रेस के मुसलमान राष्ट्रपति आज़ाद भी सम्मिलित हैं—सभी ने इस बात की पुष्टि की कि देहात में हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच में संघर्ष नहीं के बराबर है, और भारत का ९० प्रतिशत भाग देहातों में है। हिन्दू-मुस्लिम समस्या मनुष्य द्वारा बनाई गई एक शहरी समस्या है। इससे केवल यही पता लगता है कि शहरों में रोजगार की कमी है।

जिन्ना ने मुझे बताया कि भारत के ७५ प्रतिशत मुसलमान पहले हिन्दू थे, जिन्हें सैंकड़ों साल हुए मुगल विजेताओं ने मुसलमान बना लिया था। नेहरू ने ऐसे मुसलमानों की संख्या ९५ प्रतिशत बताई थी। कुछ भी हो, अधिकांश हिन्दुओं और मुसलमानों का जातीय स्रोत एक ही है। रंग-रूप और भाषा की दृष्टि से एक बंगाली मुसलमान और बंगाली हिन्दू में कोई अन्तर नहीं। जाति-शास्त्र दृष्टि से सोवियत रूस, स्विट्ज़रलैंड और सम्भवतः अमेरिका की अपेक्षा

भी भारत कही अधिक एकजातीय है ।

भारतीय जीवन में धर्म को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । यद्यपि हिन्दू गाय की पूजा करते हैं और मुसलमान इसे खाते हैं, फिर भी, देहातो में साम्प्रदायिक वैमनस्य नगण्य-सा ही है । इसकी प्रधानता तो शहरों में ही दिखाई देती है । जहरों में हिन्दुओं के खान-पान-सम्बन्धी प्रतिबन्धों के कारण और विवाह से पहले और बाद के रीति-रिवाजों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला भेद-भाव अधिक प्रतिद्वन्द्विता के कारण और भी बढ़ जाता है । यदि जीवन में प्रवेश करने वाले नवयुवकों के सामने औद्योगिक नौकरियों की वैकल्पिक सूची उपस्थित हो तो राजनीतिक स्थानों के लिए प्रतियोगिता इतनी तीव्र न रहे ।

नये मध्यम वर्ग के मुसलमानों और पुराने मध्यमवर्ग के हिन्दुओं के बीच बढ़ती हुई प्रतिद्वन्द्विता ने मुस्लिम राजनीतिज्ञों के लिए नये अवसर प्रस्तुत कर दिये । तब मुहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस-दल से त्याग-पत्र दे दिया और वह मुस्लिम लीग के नेता हो गये । कांग्रेस में सभी धर्मों के लोग शामिल हैं इसलिए भारतवर्ष का वही एकमात्र महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है । अन्य दल—हिन्दू सभा और मुस्लिम लीग आदि—साम्प्रदायिक दल हैं । केवल उनके उद्देश्य राजनीतिक हैं ।

सन् १९४२ में मुस्लिम लीग के प्रायः सभी सदस्य जमींदार थे । ज्यों-ज्यों शहरों में हिन्दुओं और मुसलमानों में तनातनी बढ़ती गई, और ज्यों-ज्यों अंग्रेजों की सहायता से जिन्ना ने मुसलमानों को अधिक नौकरियाँ दिलाने की अपनी योग्यता प्रमाणित की, त्यों-त्यों सामाजिक दवाव और स्वार्थ ने पेशेवर और दीर्घक मुसलमानों को कांग्रेस में शामिल होने से रोका । किन्तु लीग के जागीरदारों से भी उनका सहयोग सम्भव न था । मुस्लिम काश्तकारों के लिए भी यह सम्भव नहीं था कि वे जमींदारों के प्रति अपनी शत्रुता को भूल जाते और लीग से सहानुभूति प्रकट करते ।

चूँकि मुसलमानों में एक ही धर्म होते हुए भी वर्गीय सघर्ष मिटा नहीं इसलिए जिन्ना को किसी ऐसी व्यक्ति का आवश्यकता थी जिससे मुसलमान काश्तकारों व जमींदारों और नये मध्यमवर्ग के बीच की खाई भरी जा सके । यह व्यक्ति उन्हें राष्ट्रीयता में मिल गई । सन् १९४० में पहली बार जिन्ना ने घोषित किया कि हिन्दुस्तान के मुसलमान एक राष्ट्र हैं और उन्होंने उनके लिए एक राष्ट्रीय प्रदेश की मांग प्रस्तुत की । वह इसे 'पाकिस्तान' कहते हैं और उनकी योजना के अनुसार इसमें मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत सिंध, पंजाब, बिहार, अफगानिस्तान, सीमाप्रान्त, खानाबाद और दक्कन शामिल हैं ।

धर्म और राष्ट्रीयता मिलकर एक शक्तिशाली संयोग बन जाते हैं और इन्हीं से जिन्ना को अधिक सार्वजनिक समर्थन प्राप्त हुआ है। मार्च १९४७ की क्रिप्स-योजना, जिसमें सिद्धान्त रूप से पाकिस्तान के औचित्य को स्वीकार कर लिया गया था, जिन्ना के लिए मुंहमागी मुराद थी।

भारत के ९,२०,००,००० मुसलमानों में जिन्ना सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। वह समुद्र के किनारे बम्बई में एक महान् और भव्य भवन में रहते हैं, जिसका छज्जा सगमरमर का है। जिन्ना लम्बे, बहुत ही दुबले, सुन्दर मुख वाले किंतु भद्दे दागदार दाँतों वाले व्यक्ति हैं। जब मैं उनसे पहली बार मिला तो वह शेरवानी, चुस्त पाजामा और बिना भोजे के काले चमड़े के पम्प नू पहने हुए थे। ऐनक का शीशा धागे से बँधा लटक रहा था। हिन्दुस्तानी समझते हैं कि वह योग्य हैं और पथ-भ्रष्ट नहीं किये जा सकते।

उनकी दलील यह थी—मुसलमान स्थायी रूप से अल्पसंख्यक नहीं रहना चाहते। वे आत्म-निर्णय की स्वतंत्रता चाहते हैं। यह ठीक है कि अवि-काश मुसलमान पहले हिन्दू थे, किन्तु इस्लाम तो एक व्यावहारिक जीवन-शैली है। आप देख सकते हैं मुस्लिम वेश-भूषा, भवन-निर्माण-कला, भोजन तथा भाषा में हिन्दुओं से भिन्न हैं। मुस्लिम भारत को हिन्दू भारत से अलग कर देना चाहिए और उसे एक स्वतंत्र राज्य अथवा पाकिस्तान का रूप दे देना चाहिए।

इस पर मैंने कहा कि सभ्य मानव का तो यह कर्तव्य है कि वह वर्तमान के भेद-भाव को दूर करे न कि उन्हें तीव्र बनावे। वह बोले, “मैं यथार्थवादी हूँ। मेरा काम तो जो स्थिति है उससे निपटना है न कि उससे, जो होनी चाहिए।”

जिन्ना ने स्वीकार किया कि अंग्रेज की नीति सम्प्रदायों में भेद-भाव बनाये रखने की है ताकि वे सहज ही भारत में अपना आधिपत्य कायम रख सकें। “अंग्रेजों ने भारतीय शिक्षा और आर्थिक व्यवस्था को बहुत क्षति पहुँचाई है,” उन्होंने कहा।

तीन दिन बाद जब मैं फिर जिन्ना से भेंट करने गया तो उन्होंने कहा कि क्रिप्स-प्रस्तावों में पाकिस्तान के सिद्धान्त मान लिये गए हैं, यद्यपि व्यवहार में “केवल सिंध असेम्बली ही इसके पक्ष में मत दे सकती है। सीमा-प्रान्त पर कांग्रेस का अधिकार है। पंजाब असेम्बली भी शायद पाकिस्तान के पक्ष में मत देने से इकार कर दे। अतः यद्यपि सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है तथापि इसकी विधि मान्य नहीं है।”

इनके उत्तर में मैंने कहा — “दूसरे शब्दों में यों कहिये कि अंग्रेज ने आपको पाकिस्तान नहीं दिया और बहुत से मुसलमान भी इसके विरुद्ध हैं। अब आप चाहते हैं कि गांधी जी आपको पाकिस्तान दे दें।”

“गांधी तो इसके लिए पहले ही वचन दे चुके हैं”, उन्होंने कहा। “वह कह चुके हैं कि यदि मुसलमान अलग होना चाहते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यदि पाकिस्तान के प्रश्न पर हिन्दू और मुसलमान सहमत हो जाय तो हमें यह मिल जायगा। हम एक दूसरे के पड़ोसी होंगे। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दोनों ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल में स्वाधीनता-प्राप्त उपनिवेश होंगे।”

जिन्ना व्यापक इस्लाम के समर्थक हैं—जिसका अभिप्राय मोरक्को से चीन तक इस्लामी साम्राज्य स्थापित करना है। उनका खयाल है कि अगर फिनलैंड में यहूदियों की प्रधानता रही तो इससे उनकी योजना में बाधा पड़ती है।

नेहरू और गांधी के सम्बन्ध में जिन्ना ने विस्तारपूर्वक और उग्रता से बातें कीं। “नेहरू ने होमरूल सोसायटी में मेरे नीचे काम किया है” उन्होंने अपने गम्भीर वक्तव्य बताते हुए कहा—“गांधी भी मेरे नीचे काम कर चुके हैं। मेरा उद्देश्य हिन्दू और मुसलमानों में एकता स्थापित करना था। सार्वजनिक जीवन में मैंने १९०६ में पदार्पण किया। मैं भी कांग्रेस में था। जब मुस्लिम लीग संगठित हुई तो मैंने कांग्रेस पर इस बात का जोर डाला कि वह लीग को भारतीय ग्यतवना की उपलब्धि में सहायक मानकर उसका स्वागत करे। सन् १९१५ में मैंने लीग और कांग्रेस को बम्बई में एक ही समय अपने अधिवेशन बुलाने पर तैयार किया ताकि दोनों संस्थाएँ एकता के सूत्र में बद्ध दिखाई दें। इस प्रकार की एकता में सकट देख अंग्रेजों ने खुले अधिवेशन को बलपूर्वक भग्न कर दिया, किन्तु घन्द कमरे में संयुक्त अधिवेशन बराबर होता रहा। सन् १९१६ में फिर मैंने दोनों संस्थाओं के अधिवेशन लखनऊ में इकट्ठे बुलवाये। वहाँ हमने हिन्दू-मुस्लिम सहयोग के लिए लखनऊ-पैक्ट तैयार किया। सन् १९२० तक, जब कि गांधी प्रकाश में आये, प्रतिवर्ष इसी प्रकार अधिवेशन होते रहे। इसी वर्ष से स्थिति बिगड़नी शुरू हो गई। लंदन में गोलमेज कांग्रेस में अक्सर पर मूले इस बात का पूर्ण विश्वास हो गया कि एकता की योजना निरर्थक है। गांधी एकता नहीं चाहते थे। मुझे बड़ी निराशा हुई और मैं अस्वीकार ही में रहने का निश्चय किया। मैं भारत में अपनी मिलिक्यन देवने के लिए नहीं गया। यह कार्य मैंने एक दलाल के द्वारा किया। इंग्लैंड में मैं १९२६ तक रहा। मैंने प्रिवी काउंसिल में वकालत प्रारम्भ की और मुझे

उसमे आशातीत सफलता मिली। मेरा भारत लौटने का इरादा नहीं था। किन्तु प्रति वर्ष मुझे मित्र मिलते थे और भारतीय स्थिति से अवगत कराते हुए कहते थे कि आप वहाँ चलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अन्त में मैंने भारत आना स्वीकार किया। ये सब बातें मैंने आपको यह सिद्ध करने के लिए बताई हैं कि गांधी स्वतंत्रता नहीं चाहते। वह नहीं चाहते कि अंग्रेज भारत छोड़ जाय। वह तो हिन्दू-राज स्थापित करना चाहते हैं। सर्वप्रथम वह हिन्दू हैं।”

मैं जब ताजमहल होटल में अपने कमरे में वापस आया तो मैंने मार्च १९४० के लाहौर अधिवेशन में प्रधान पद से दिया गया जिन्ना का अभिभाषण पढ़ा। इसमें उन्होंने कहा था, “मेरी समझ में बुद्धिमानी इसी में है कि कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति का अत्यधिक विश्वास न करे।”

मैंने जिन्ना के अन्य भाषण भी पढ़े और उनका मासिक पत्र, “डान” देखा। वह अपने विरोधियों पर मिट्टी उछालते हैं और निरर्थक वादविवाद करते हैं। वह विरले ही कोई बड़ी या नई बात करते हैं। वह कोई आगे का रास्ता नहीं सुझाते; वह स्वयं दुबले-पतले हैं और उनकी बातें भी दुबली-पतली होती हैं। वह एक ही राग अलापते हैं—मुसलमान पाकिस्तान चाहते हैं। किन्तु वह पाकिस्तान को मुसलमानों की पुनर्जागृति के रूप में व्यक्त नहीं करते। संस्कृति और भाव के क्षेत्र में उनका पाकिस्तान कोई नया पग नहीं है। वह यह तक ठीक-ठीक नहीं कहते कि पाकिस्तान क्या है और कहा स्थापित होगा। वह सौदा पटाते हैं और कहते हैं—जब तक आप मेरी आधी बात मानने का वचन नहीं देंगे तब तक मैं आपको पाकिस्तान का विस्तृत विवरण नहीं दूंगा। वह राजनीतिज्ञ नहीं, एक राजनीतिक व्यापारी हैं। बात-बात में वह “वैधानिक और कानून की दृष्टि से” कहते हैं, और उसी से उनका परिचय मिलता है। उनमें पटुता है, किन्तु विस्तार नहीं।

मैं जिन्ना के साथ ५ घंटे रहा। इस बीच प्रायः वही मुझसे बात करते रहे। वह मुझे विश्वास दिलाने का प्रयत्न कर रहे थे। जब मैं उनसे कोई प्रश्न करता था तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था मानो मैंने ग्रामोफोन के किसी रिकार्ड पर सूई चढ़ा दी हो। वह जो कुछ कहते थे मैं पहले भी सुन चुका था या लोग के प्रकाशित साहित्य में पढ़ सकता था। जब मैं गांधी से कुछ पूछता तो ऐसा जान पड़ता था कि मैं एक मौलिक और रचनात्मक कार्य कर रहा हूँ। मैं उनके मनोभावों को प्रकट होते सुन और देख सकता था। किन्तु जब जिन्ना बात करते थे तो मुझे ग्रामोफोन की सूई की घिस-घिस की-सी ही आवाज आती सुनाई देती थी। जिन्ना ने मिर्बा निष्कर्षों के मुझे और कुछ नहीं दिया। गांधी

किन्ती भी निष्कर्ष की ओर बढ़ते थे तो वह मुझे भी उसका निरीक्षण करने देते थे। गांधी से भेंट करना एक सनसनीपूर्ण तथा बौद्धिक अनुभव है। जिन्ना की मुलाकात नीरस होती है चाहे वह कितनी ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो -

जिन्ना मुसलमानों के नेता नहीं, उनके वकील है। उनका पक्ष बार-बार और अच्छी तरह से पेश करते हैं। किन्तु उनकी बातों से मुस्लिम जनता के अपार धन और सहृदयता का लेश मात्र भी पता नहीं चलता। मुसलमान आकर्षक होते हैं, बहुत-सी बातों में तो बुद्धिमान हिन्दुओं से भी अधिक आकर्षक होते हैं। उनमें जोश है, जीवन के प्रति प्रेम है, सज्जीत हैं, कविता है। किन्तु जिन्ना ने दाते करते समय किसी को इन बातों का ख्याल तक नहीं आसकता है।

नई दिल्ली में महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी के घर पर, जो 'हिन्दु-स्तान टाइम्स' के सम्पादक हैं, मैं एक और मुसलमान से मिला। वे खान अब्दुल-गफार खाँ थे, जो व्यापक रूप से "सीमा प्रान्तीय गांधी" के नाम से पुकारे जाते हैं। वह सीमा-प्रान्त के मुसलमानों के नेता हैं। जिन्ना का विरोध करते हैं और गांधी का समर्थन। सीमा-प्रान्त के किसानों में कांग्रेस के जो असह्य अनुगामी हैं उन्हें इन्होंने ही संगठित किया है। शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से वह उन लोगों में से हैं जिन्होंने भारत में मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया। वह ६ फुट से अधिक लम्बे हैं, उनका शरीर बलवान है तथा सिर गज्जत और दिलकुल अड़े जैसा। उनके सिर और दाढ़ी पर भूरे-काले बालों की पूँटियाँ हैं। वह आयु में ६० वर्ष से अधिक हैं किन्तु उनकी काली चमकदार गौर चूभने वाली आँखों से यह मालूम होता है कि वह अभी ३० वर्ष के ही हैं। मिलने वाले पर उनकी मुखाकृति का जो प्रभाव पड़ता है उससे दसगुना उनसे बातचीत करने से पड़ता है। उनके बोलने से पहले ही मैंने उनकी शक्ति को महसूस कर लिया। उनका घर पेशावर जिले के एक गाँव में है जहाँ वह किसानों की तरह रहते हैं। अपने पिता के समान वह भी धनी थे किन्तु उन्होंने अपनी सम्पत्ति को त्याग दिया। उन्होंने नीले भूरे रंग का लम्बा ढीला कुरता और चौड़ी मोहरी की सलवार पहन रखी थी जो सीमा-प्रान्त के उनके स्व-जातीय पठानों का खास पहरावा है। हाथ से बुने हुए इन कपड़ों का रंग उड़-सा गद्दा या और गर्दन के पास उनके कुरते पर एक पैदन्द भी लगा हुआ था। उनके हाथ लम्बे और करीब-कराव सफेद हैं और उनके पैरों की बनावट बड़ी सुन्दर है। मुझसे हाथ मिलाने के बाद उन्होंने अपने हाथ को दिल पर रख लिया।

मैंने उनसे पूछा कि जिन्ना के पाकिस्तान के द्वारे में आवजी क्या राय

है। उन्होंने जवाब दिया, “मैं तो इसकी वास्तविकता का अन्दाजा उन लोगों को देखकर लगाता हूँ जो मेरे प्रातः में इसके समर्थक हैं। वहाँ इसका समर्थन धनी खान, पैसे वाले नवाब और प्रतिगामी मुल्ला करते हैं। पाकिस्तान उन लोगों के हाथ मजबूत करेगा जो हमारे किसानों का शोषण करते हैं।”

“क्या पाकिस्तान इस्लाम से मजबूत होगा”, मैंने पूछा।

उन्होंने क्रोध से कहा—“जिन्ना एक बुरे मुसलमान हैं। वह पैगम्बर के सच्चे अनुयायी नहीं हैं।”

“क्या आप धर्मनिष्ठ हैं?” मैंने पूछा। “हाँ, मैं मस्जिद में पाँच बार नमाज पढ़ता हूँ, मैं खुदा के एक सच्चे खिदमतगार की जिदगी बिताता हूँ। सीमा-प्रातः में हमारा आन्दोलन खुदाई खिदमतगार के नाम से प्रसिद्ध है। कभी-कभी इसे लाल कुर्ती वालों का आन्दोलन भी कह देते हैं, किन्तु लाल रंग की विचार-धारा से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। हम व्यापक शिक्षा और उच्च आदर्शों के प्रतिपादक हैं। तीन वर्ष हुए जब मैंने अधिक स्कूल स्थापित करने का मुझसे प्रस्तुत किया था तो अंग्रेजों ने मुझे जेल में डाल दिया और मुल्लाओं ने मेरा विरोध किया।”

उन्होंने मुझसे अंग्रेजी में बात की और चुन-चुनकर प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया। मैंने सोचा—“हिन्दुस्तान के दूर-दराज पर्वतीय प्रान्त के रहने वाले इस व्यक्ति से मिलना और तत्काल ही उससे सम्बन्ध स्थापित करना कितना रोमांचकारी है।”

यदि गांधी का भारत की मिट्टी और रेत से नाता है तो गणफारखा का भारत की चट्टानों और पर्वतीय जल-प्रपातों से सम्बन्ध है।

एक बार उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि मैं हिन्दुस्तान और अफगानिस्तान के बीच के कबायली प्रदेश में चलूँगा एवं लडाकू तथा उपद्रवी अफ्रीदियों और वजीरो को इस बात के लिए प्रेरित करूँगा कि वे अंग्रेजों से और आपस में लड़ना-भिडना बन्द कर दें। उन्हें आशा थी कि वह इन लोगों को गांधी के अहिंसावाद की ओर ला सकेंगे। किन्तु अंग्रेजों को इस बात का डर था कि कहीं अफ्रीदियों में इनका प्रभाव न हो जाय, इसलिए उन्होंने गणफारखा को उस क्षेत्र में जाने की आज्ञा नहीं दी।

“मेरे प्रान्त के आदिमियों का गांधी में विश्वास है क्योंकि गांधी हिन्दुस्तान की आजादी चाहते हैं” गणफारखा ने कहा।

जिन्ना मुसलमान शांति-कारों को बतलाने का प्रयत्न करते हैं कि वे केवल मुसलमान हैं और उन्हें एक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिए।

गणकारवा, नेहरू और दूसरे कांग्रेसी नेता मुसलमान किसानों से कहते हैं कि वे अधिक दृष्टि से किसान, धार्मिक दृष्टि से मुसलमान और राजनीतिक दृष्टि से हिन्दुस्तानी हैं, हिटलर ने जर्मनों से कहा था कि वे केवल जर्मन हैं। उन्ने आशा थी कि राष्ट्रवाद के उन्माद में मजदूर अपने वर्गीय शत्रुओं को भूल जायेंगे और केवल जातीय शत्रुओं—जर्मनों के यहूदियों और शेष सभी ससार में घृणा करेंगे। जिन्ना का धर्ममूलक जातिवाद भी उससे कम खतरनाक नहीं।

कुछ समय तक तो अंग्रेज जिन्ना की खुशामद करते रहे और उनके हाथ मजबूत करते रहे क्योंकि वे गांधीजी के स्वाधीनता आन्दोलन के मुकाबले में कोई और दल खड़ा करना चाहते थे। अपने साम्राज्य पर से एक गकट गालने के लिए अंग्रेज सारे एशिया के लिए खतरा खड़ा करने को तैयार थे।

गांधी कहते हैं कि भारत को हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में विभाजित करना एक कलक है। दूसरे शब्दों में इसे मूर्खता कहना चाहिए। ईराक और ईरान के ही समान पाकिस्तान भी एक दयनीय देश होगा, यद्यपि उनसे जरा दया होगा। दो हिन्दुस्तान सारे ससार के लिए सिर दर्द बन जायेंगे। विभाजन और संघर्ष के कारण भारत कमजोर हो जायगा और वह चीन तथा यूरोप के छोटे राष्ट्रों की ही भाँति बड़े राष्ट्रों के पड़ोसी और कुचालों का शिकार बनकर रह जायगा।

रवतत्र सघीय भारत में हिन्दु-मुस्लिम समस्या को हल करने के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक होंगी—

प्रान्तों के लिए व्यापक स्वाधीनता, और हिन्दू-बहुमत प्रान्तों में मुस्लिम अल्पमतों के लिए और मुस्लिम बहुमत प्रान्तों में हिन्दू अल्पमतों के हितों की रक्षा की कानूनी गारंटी।

धार्मिक आधार पर स्थापित पृथक् निर्वाचन पद्धति का उन्मूलन तथा राजनीति से धर्म को अलग कर देने का दृढ़ प्रयास।

भारतीय सेना और स्कूलों में धार्मिक पृथक्ता और भोजन-सम्बन्धी गैर-भाव अन्तर्-भिन्न हो रहे हैं। कितने ही भारतीय विद्यार्थियों ने मुझे बताया कि राजबंदा के तदुद्भव अपने माता-पिताओं की अपेक्षा धार्मिक और जातीय अन्तर्-भाव से अधिक महत्व मानते हैं। १९३१ की जन-संख्या-पुस्तक के अनुसार राजबंदा रूप से यह कहा जा सकता है कि हिन्दुओं और मुसलमानों के मिल-जुलकर रहने में कोई इन्तर बाधा नहीं जान पड़ती। तजौर और म्दुरा में तो

ऐसे हिन्दुओं के मन्दिर हैं जिनके कुलक्रमानुसार द्रष्टी मुसलमान हैं।" १९३१ के एक जन-सत्याग्रह सुपरिन्टेन्डेंट ने लिखा है—“अंग्रेजी पढ़े लिखें आम लोग धर्म की आर से पूर्णतः उदासीन और अव्यवस्थित में रहते हैं।”

जहाँ धार्मिक सुरक्षा और धर्म-मूलक राजनीति होगी, वहाँ निश्चय ही दरिद्रता, अनक्षरता और प्रान्तीयता का वास भी होगा। अगर शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय और लोग सम्मान हो जाय तो शहरों की हिन्दू-मुस्लिम तनावपूर्णता काफूर हो जाय। हिन्दुस्तान में रहन-सहन का मान ऊँचा करने और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने के हेतु औद्योगिक और कृषि-सम्बन्धी क्रांति परम आवश्यक है। आर्थिक प्रगति से सांस्कृतिक जागृति बढ़ेगी और दोनों मिलकर आजकल के कठोर साम्प्रदायिक और जातीय विभाजनों को निश्चय ही नष्ट कर देंगे।

मतभेदों के प्रति असहिष्णुता एक पुराना रोग है और इससे वे देश भी अछूते नहीं जो आज अपनी सभ्यता के बारे में सबसे अधिक घमण्ड के साथ बोलते हैं। भारत में तो अभी इस समस्या पर प्रहार किया जाना भी ठीक से आरम्भ नहीं हुआ। भारत में अनिवार्य शिक्षा का अभाव है, जिसके द्वारा देश-व्यापी सामान्य भाषा का सहज ही प्रचार हो सकता है। हरिजनों और अछूतों के बच्चे (जिनके सम्बन्ध में यह खयाल किया जाता है कि उनका साया भी सवर्ण हिन्दू को अपवित्र कर देगा) जब हिन्दुओं, सिखों, ईसाइयों, मुसलमानों और अंग्रेजों के बच्चों के साथ बैठेंगे तो यह प्रमाणित हो जायगा कि हमारे अखण्ड ब्रह्म और प्रतिबन्ध मूर्खतापूर्ण हैं। इसी प्रकार आर्थिक व्यवस्थाओं के विस्तार से और रोजगार में वृद्धि हो जाने से उन गलतफहमियों और दीवारों के नष्ट होने में सहायता मिलेगी जो भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों और धर्मों के बीच खड़ी हैं। आज अछूत या “दलित जातियाँ” शहरों में केवल मेहतरों का काम, सड़कों आदि की सफाई और चमड़े का काम करती हैं जिसे सवर्ण हिन्दू गन्दा काम समझते हैं। आजकल जब कि रोजगार की भारी कमी है, प्रत्येक जाति या सम्प्रदाय इस बात का प्रयत्न करता है कि वह अपने पेशे को एकाधिकार के रूप में ग्रहण करे। इसीलिए अछूतों को अधिक लाभदायक और कम गंदे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता।

हिन्दुओं की वर्ण-व्यवस्था एक प्राचीन व्यवस्था है। आधुनिक काल में इसका अर्थ भारत की आर्थिक व्यवस्था और शिक्षा को सदा के लिए अग्रगतिशील रखना है।

मुझे भारत में जो सबसे कटु व्यक्ति मिला वह सबसे प्रसिद्ध अछूत हैं—

डॉक्टर भीमराव जी अम्बेदकर। उनके पिता और दादा वर्षों अंग्रेजी-सेना में रहे और इस अमाधारण परिस्थिति के कारण ही अम्बेदकर भारत में शिक्षा प्राप्त कर सके। बाद में महाराजा बडोदा द्वारा दी गई छात्रवृत्ति की सहायता से उन्होंने कोनम्बिया विश्वविद्यालय (न्यूयार्क) से एम० ए० और पी० एच० डी० की उपाधियां प्राप्त कीं। वह जर्मनी में बौन विश्वविद्यालय तथा लंदन विश्वविद्यालय में भी पढ़े। वह एक ख्यातनामा लेखक, वकील और अर्थ-शास्त्री हैं। उनका शरीर गठा हुआ है और उनकी आत्म-शक्ति सुदृढ़ है। वह बहुत ही "टेढ़े" हैं और इतने ही भावुकताहीन और बौद्धिक हैं, जितने बहुत से हिन्दू दार्शनिक और अबौद्धिक हैं। वह हिन्दुओं से घृणा करते हैं, और इसका कारण भी है। भारत के पाँच या सात करोड़ अछूतों के प्रति जैसा धृष्ट व्यवहार होता है वैसा इस ससार में कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के प्रति नहीं करता। मैं समझता हूँ कि हिन्दुओं के इस खयाल ने कि अछूत का दूर का सम्पर्क भी उन्हें भ्रष्ट कर देगा, हिन्दुओं को स्वयं भ्रष्ट कर डाला है। ऐसे वर्तमानपूर्ण विचारों से धर्म कलंकित हो जाता है।

गांधी वचन और कर्म द्वारा अछूतों के उत्थान का प्रयत्न करते रहे हैं। वह अछूतों के हाथों का तैयार किया हुआ भोजन करते हैं और अछूत उनके गाँव में उनके बहुत ही निकट रहते हैं। इसीलिए अछूतों में गांधी के बहुत अनुयायी हैं और सम्भवतः वे गांधी को अम्बेदकर की अपेक्षा अधिक जानते हैं।

अम्बेदकर गांधी के विरोधी और पाकिस्तान के समर्थक हैं। हिन्दु-स्तान में मैं जितने आदिमियों से मिला उनमें से एक भी अंग्रेजों का इतना दया समर्थक नहीं जितना कि अम्बेदकर। अगस्त १९३० में अम्बेदकर ने हरिजनों के सम्मेलन में कहा था—“मुझे भय है कि अंग्रेजों द्वारा हमारी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्दशा के प्रचारित किये जाने का कारण यह नहीं है कि अंग्रेज हमारी इस दुर्दशा का निराकरण करना चाहते हैं बल्कि यह कि ऐसा करने से उन्हें हिन्दुस्तानी राजनीतिक प्रगति रोकने का बहाना मिल जाता है।” अम्बेदकर का मतानुसार कि सर्वत्र हिन्दुओं और हरिजनों के बीच शत्रुता होने के कारण अंग्रेजों को भारत में जमे रहने के लिए एक और दलील मिल गई है। फिर भी सन् १९४२ में अम्बेदकर ने वाइसराय की कार्यकारिणी का सदस्य बनना स्वीकार किया और इस प्रकार वह अंग्रेजों के सहयोगी बन गये। दण्ड देने वाले हिन्दुओं के प्रति अम्बेदकर का विद्वेष इतना अधिक है कि जो चीज हिन्दू अस्वीकार करते हैं उसका वह स्वागत करते हैं और जिस बात को हिन्दू कहते हैं उसे वह

अस्वीकार करते हैं। अम्बेदकर मे हमे परम्परागत अन्याय और कष्ट की गूँज सुनाई देती है जिसके फलस्वरूप अधिक से-अधिक विचारवान व्यक्ति में भी विचारहीन आवेग उत्पन्न हो जाते हैं।

मेने अस्पृश्यता के बारे मे एक कट्टरपन्थी हिन्दू से बात की। वह भारतीय सघ न्यायालय के सदस्य सर एस० वरदाचार्य थे, जिनके नाम मुझे भारत के न्यायाधीश सर मारिस ग्वायर ने पत्र दिया था। सर मारिस से परिचय प्राप्त करने के लिए मैं अपने साथ फेलिक्स फ्रैंकफर्टर का पत्र लाया था। सर मारिस ग्वायर के अनुसार "नई दिल्ली मे अकेले वरदाचार्य ही एक-मात्र राजनीतिक दार्शनिक थे।"

मेरी टैक्सी जब वरदाचार्य के बगले पर पहुँची तो वह भारतीय न्यायाधीश प्रवेश-द्वार पर मुझसे मिलने आये। वह बिना कालर की सफेद कमीज पहने हुए थे जिसके सारे बटन सोने के थे। चूड़ीदार पाजामा पहने हुए थे। पाँव नंगे थे—न जूते न मोज़े। सिर के मध्य मे चोटी के लम्बे बालों की उन्होंने गाँठ बाँध रखी थी। बाकी बाल काटकर छोटे कर दिये गये थे। इनके कारण देखने मे वह चीनी जान पड़ते थे। ललाट के बीचो बीच एक लाल रंग का पतला-सा तिलक लगा था। कनपटियो से नाक तक दो सफेद धारिया कहीं-कहीं से खिंची हुई थीं, जो बीच से टूटी हुई थी। इन तिलकों को देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ी। वह लगभग ६० वर्ष के थे और बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, यद्यपि वह कभी भारत से बाहर नहीं गये थे।

उन्होंने कहा:—"भारत एक महान् देश है; इसके कुछ निवासी अब भी वृक्षों पर रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन पर ऑक्सफोर्ड की शिक्षा और सभ्यता की छाप लगी है। यहाँ भिन्न-भिन्न जातियाँ और धर्म हैं जिन्हे एकता के सूत्र में बाँधने की आवश्यकता है; किन्तु अंग्रेजों ने जो एकता हमे दी है वह शासन सम्बन्धी ही है। वह शिखर से आरम्भ होती है और वहीं समाप्त हो जाती है। हमारे देश में उन्नति भी हुई है, किन्तु यह औरो ने अपने लाभ के लिए की है और इससे हमे जो लाभ हुआ है वह नाममात्र है। उदाहरणार्थ, हमारी शिक्षा साहित्य-प्रधान रही है, क्योंकि पहले ईस्ट इंडिया कम्पनी को और बाद में ब्रिटिश सरकार का दफ्तरो मे काम करने के लिए बलकों की आवश्यकता थी। परन्तु, जब इन पढ़े-लिखे आदमियों मे से वे लोग, जिन्हे नौकरियाँ नहीं मिलती, राजनीति मे पदार्पण करके सरकार को तंग करते हैं, तो अंग्रेज यह नहीं समझते कि इसका दायित्व स्वयं उन्ही पर है।"

मेरे कुछ कहे बिना ही वह धारा-प्रवाह बोलते रहे— "हिन्दुस्तान में

ग्रिग्रेजो का रैन-ब्रेरा-सा है। जब वे यहाँ उद्योग स्थापित करते हैं तो उन्हें भारत के हिंदो की नही बल्कि अपने हिंदो की चिन्ता रहती है। हमारे शासको के जीवन में भारत एक घटना मात्र है। वाइसराय की तरह वे यहाँ पाँच, दस या बीस वर्ष ठहरते हैं और खूब मौज उड़ाते हैं। यही कारण है कि भारत पिछड़ा हुआ है और आधुनिक ससार के अन्य राष्ट्रों के बीच उसका कोई स्थान नहीं।”

माधे के तिलक के सम्बन्ध में मेरी उत्सुकता कम नहीं हुई थी। मैंने पूछा कि ‘ये क्या है?’ उन्होंने जवाब दिया :—‘मैं ब्राह्मण हूँ। हिन्दू एक सामूहिक जन्म है। कुछ हिन्दू त्रिदेव के तीन स्वरूपों में से किसी एक के विशेष भवन होते हैं। उन स्वरूपों में से एक विष्णु है, दूसरे शिव। इनमें से मेरे दण्डदेव विष्णु हैं और विष्णु के सभी अनुयायियों को ऐसा तिलक धारण करना चाहिए।”

“हमेजा?”

“हाँ” उन्होंने उत्तर दिया, “किन्तु दुर्भाग्य से बहुतों को इसमें लज्जा आती है।”

मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अस्पृश्यता में विश्वास करते हैं।

“सवाल अस्पृश्यता में ‘विश्वास’ करने का नहीं है,” बरदाचार्य ने निन्दा-भाव से कहा। “इसके आदि कारण को समझना आवश्यक है। यदि आप आत्मा के आवागमन में विश्वास करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि यदि किसी आत्मा ने एक जन्म में कुकर्म किये हैं तो दूसरे जन्म में उसका हरिजन के घर में जन्म हो सकता है।”

मैंने कहा—“यह बात असम्भ्यता की सूचक है कि किसी शरीर को उसकी पूर्व जन्म की आत्मा द्वारा किये गये ऐसे कुकर्म के लिए दण्ड दिया जाय जिसका उत्तरदायी वर्तमान शरीर नहीं है।”

“आप सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं,” उन्होंने प्रतिवाद करते हुए कहा। “यदि एक हरिजन लंदन में उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत वापस आवे तो उसे आत्मिक अयोग्यता के अतिरिक्त और किसी अयोग्यता का बण्ड सहन नहीं करना पड़ेगा।”

‘फिर भी’ मैंने कहा “उनमें से अधिकांश इतने गरीब हैं कि वे लंदन जाने ही क्षम्य नहीं कर सकते।”

एतदन्ते—‘रेल्गाडी में आप नहीं जान सकते कि कौन हरिजन हैं और कौन नहीं। सामाजिक जीवन में अस्पृश्यता का प्रभाव स्वतः शिथिल

होता रहता है।"

कट्टर हिन्दू होते हुए भी वरदाचार्य ने अस्पृश्यता का समर्थन न करके वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में मेरी शकाओं का समाधान करने की चेष्टा ही की। अन्य दूसरे हिन्दुस्तानियों ने भी मुझे बताया कि शहरी जीवन में सबों और हरिजनों के बीच का भेद-भाव कम हो जाता है।

एक और कृत्रिम विभाग ऐसा है जिसके कारण भारत की एकता का ह्रास हुआ है। वह है देशी रियासतें, जिन पर महाराजा राज्य करते हैं। चालीस करोड़ हिन्दुस्तानियों में से लगभग एक चौथाई इन रियासतों में रहते हैं, जिन पर प्रत्यक्ष रूप से तो भारतीय नरेशों का किन्तु अप्रत्यक्ष रूप में अंग्रेजों का राज्य है। विस्तार में ये रियासतें एक दूसरे से भिन्न हैं—एक और तो हैदराबाद है जिसकी आबादी १,७०,००,००० है और दूसरी और छोटे-छोटे घटक हैं जिनकी जन-संख्या मुश्किल से दो चार सौ ही है। रियासतें देश भर में अनियमित रूप में इधर-उधर बिखरी हुई हैं। इनके निवासी भी भारत के अन्य भागों की तरह, विभिन्न जातियों और धर्मों के हैं।

सन् १९४२ में नरेन्द्र-मण्डल के चांसलर बीकानेर नरेश थे। एक दिन बम्बई में जब मैं अपने होटल के कमरे में बैठा था, तो मेरे पास उनके सेक्रेटरी का फोन आया कि महाराजा साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने भेट के लिए प्रार्थना नहीं की थी। इसलिए मैं हैरान था कि वह मुझसे क्या बातें करना चाहते हैं। तभी-तभी मैं गाँधी जी के साथ एक सप्ताह रहकर लौटा था। बीकानेर नरेश यह जानना चाहते थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के सम्बन्ध में गाँधी का क्या आयोजन है? क्या उन्हें वाइसराय और गांधी के बीच मध्यस्थता करने का काम नहीं सौंपा गया था?

जैसे ही मैं महाराजा के बम्बई-स्थित महल की डघोड़ी में पहुँचा वैसे ही सफेद वरदी पहने हुए भूरे रंग के दरबान एकदम सीधे खड़े होगये। एक सेक्रेटरी तुरन्त ही मुझे महाराजा के गोल कमरे में ले गया। महाराजा वहाँ खड़े थे। वह अत्यंत ओजस्वी प्रतीत होते थे, उनका सिर विशेष रूप से सुन्दर था। वह सफेद सूट और हलके पीले रंग की कमीज पहने हुए थे। गला ऊपर से खुला था। भीतर से हलके पीले रंग का बनियान भी दिखाई देता था। उनकी घनी मूँछें अर्धपकी और उमठी हुई थी। उनकी घनी भीहें प्रायः बिल्कुल काली थीं, किन्तु उनके सुन्दर सिर के बाल पूर्णतः सफेद थे। उनके कानों पर लम्बे-लम्बे काले बाल खड़े थे।

महाराजा की आवाज़ कुछ भारी सी थी। उन्होंने बताया कि मैं

टम्बई गले के आपरेशन के लिए आये थे। “कोई ऐसी गम्भीर बात नहीं,” वह बोले, “गले के अन्दर एक नस फूल गई है; इसे काट दिया जायगा और फिर सब ठीक हो जायगा।” (गले के फोड़े के कारण ही कुछ मास बाद उनकी मृत्यु हो गई)। वह विशुद्ध अंग्रेजी बोलते थे और उनका उच्चारण भी अंग्रेजी ढंग का था।

महाराजा का पहला प्रश्न यह था — “कहिये, महात्माजी ने आपसे क्या कहा?”

सात दिन की बात को मैंने या सक्षेप में बताया — “गांधी अधीर हैं और परिवर्तन चाहते हैं। मुझे तो ऐसा जान पड़ा है कि भारत अंग्रेजों का दरा कट्टर विरोधी है।”

महाराजा ने कहा — “ब्रिटिश भारत तो पूर्ण रूप से अंग्रेजों का विरोधी है। आम तौर से यह कहा जा सकता है कि अंग्रेज अपने को हिन्दुस्तानियों में दिलकुल अलग रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि यहाँ ऐसे कई बलब हैं जिनमें हिन्दुस्तानी शामिल नहीं हो सकते। ‘याच बलब’ ही उन में से एक हैं। इन बलब वालों ने मुझसे एक बार कहा — “अगर श्रीमन्त चाहे तो हमें शामिल हो सकते हैं।” मैंने जवाब दिया — “नहीं, धन्यवाद, मैं बकिंगहम पैलेस में आपके सम्राट् के साथ भोजन कर चुका हूँ और मुझे आपके बदल की आवश्यकता नहीं।”

“क्या आप का खयाल है कि अंग्रेज यहाँ सदा के लिए ठहर सकते हैं?” मैंने पूछा।

महाराजा बोले — “ब्रिटेन ने रियासतों को कई वचन दे रखे हैं और वह उन्हें तोड़ नहीं सकता।”

मैंने महाराजा से कहा — “अभी-अभी जब मैं हैदराबाद में था तो मैंने एक सदा संधियों के विवरण पढ़े जो १७ वीं शताब्दी से लेकर अब तक अंग्रेजों और हैदराबाद की रियासतों के साथ की है। मेरा विचार है कि सदा संधियाँ ब्रिटिश सरकार द्वारा रियासतों पर लादी गई हैं और अब अंग्रेज कहता बना रहे हैं कि वे इन्हें तोड़ नहीं सकते।”

श्रीमान्-नरेश हँस कर बोले — “ठीक है, मैंसूर कोई महत्त्वपूर्ण रियासत नहीं है। रहा हैदराबाद, सो उसकी बात अलग है। क्योंकि वहाँ एक मुसलमान शासक हिन्दू बहुमत पर राज करता है। आपको अपनी सधि दिखा दें। उन्होंने घड़ी दवाई और नारंगी रंग का पगोट बाँधे हुए आदमी के रूप में। उसके महाराजा ने प्राइवेट सेक्रेटरी को भेजने को कहा। एक

मिनट बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया । अपने को बोलने से बचाये रखने के लिए महाराजा ने सीटी बजाई और सेक्रेटरी अन्दर आ गया । महाराजा ने उस से अंग्रेजी में बात की । सेक्रेटरी उसी समय चला गया और थोड़ी देर बाद ही दोनों तरफ से छपा हुआ एक कागज लेकर वापस आगया । महाराजा ने वह कागज मुझे दे दिया । महाराजा चुपचाप बैठे रहे और मैं उसे धीरे-धीरे पढ़ने लगा ।

उसे पढ़ चुकने के बाद मैंने कहा—“इस संधि में दो महत्त्वपूर्ण शब्द हैं—“अधीन और सहयोग” । “आप अधीन हैं और अंग्रेजों से सहयोग करना आपके लिए आवश्यक है ।”

संधि पर ६ मार्च, १९१८ दिल्ली की तारीख पड़ी थी । धारा ३ में लिखा था :

“महाराजा सूरतसिंह और उनके उत्तराधिकारी अधीन सहयोग के आधार पर ब्रिटिश सरकार से व्यवहार करेंगे और उसकी उच्च सत्ता को स्वीकार करेंगे और किसी अन्य सरदार या रियासत से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखेंगे ।”

“ठीक है,” महाराजा ने कहा “फिर भी यह एक अच्छी संधि है ।” उन्होंने भारी लाल पेसिल उठाई और धारा १ पर निशान लगाते हुए कहा , “यह अच्छी धारा है” । इसी प्रकार धारा २ और ९ पर लगाते हुए उन्हें अच्छा बताया । धारा १ में मैत्री-सम्बन्धों की भूमिका है । संक्षेप में, धारा २ में लिखा है—“ब्रिटिश सरकार बीकानेर राज्य और उसकी सीमाओं की सुरक्षा करने का वचन देती है ।” सम्पूर्ण धारा ६ इस प्रकार है—“महाराजा और उनके उत्तराधिकारी अपने प्रदेश के एकाधिकारी शासक होंगे और उनकी भूमि में अंग्रेजी सत्ताधिकार लागू नहीं किये जायग ।”

महाराजा ने कहा—“हमने इस संधि की शर्तों को अक्षरशः पूरा किया है और ब्रिटिश सरकार को सैनिक सहायता दी है । सम्राट् के लिए मैं स्वयं रणभूमि में लड़ा हूँ ।”

मैंने कहा—“गांधी ने मुझे बताया था कि यदि अंग्रेज शासन-सत्ता भारतीयों को सौंपना स्वीकार कर लें तो तत्काल ही एक अस्थायी सरकार स्थापित कर दी जायगी, जिसमें मुसलमानों, नरेशों और हिन्दुओं के प्रतिनिधि होंगे ।”

“ऐसी सरकार से भी हम उसी सुरक्षा की आशा करेंगे जो इस सम हमें ब्रिटिश सरकार से मिलती है” महाराजा ने उत्तर दिया ।

मैंने पूछा—“किन्तु क्या आप समझते हैं कि इस प्रकार की दो भिन्न-भिन्न शासन प्रणालियों का साथ-साथ जीवित रहना सम्भव है ?”

“क्यों नहीं ?” उन्होंने चकित होकर पूछा । मैंने कहा—“राष्ट्रीय सरकार व्यापक मताधिकार आरम्भ करेगी और अन्य जनतंत्री सुधार भी करेगा ।”

इस पर वह बोले—“मैं एक स्वतंत्र शासक हूँ । किन्तु मेरी प्रजा ब्रिटिश शासन की प्रजा से अधिक सुखी है । आप एक बार वीकानेर अवश्य आये । हिन्दुस्तान के कई सर्वोत्तम अस्पताल वीकानेर में हैं । उनमें से एक अस्पताल एक जर्मन यहूदी शरणार्थी के अधीन है । हमारी रियासत में सुन्दर सड़के और स्कूल हैं । मैं अपनी प्रजा से अच्छा व्यवहार करता हूँ । हाँ, वे लोग ब्रिटिश भारत के लोगों की अपेक्षा पिछड़े हुए अवश्य हैं और जनतंत्र के लिए परिपक्व नहीं हैं ।” मैंने पूछा—“क्या आपके यहाँ भी हिन्दू-मुस्लिम उपद्रव होते हैं ?”

“सदियों से हमारे यहाँ कभी उपद्रव नहीं हुए,” वह बोले “किन्तु अब यह रोग ब्रिटिश भारत से रियासतों में भी आ रहा है । हमारी रियासत के उत्तरी भाग में मुल्ला लोग आगये हैं । जो हमारे मुसलमानों को बहकाते हैं कि उन्हें हिन्दुओं से कोई वारंता नहीं रखना चाहिए । मैं आपसे स्पष्ट शब्दों में बात कर रहा हूँ और मेरा विश्वास है कि जब भी कभी उपद्रव होता है तो उसे आरम्भ करने वाला प्रायः मुसलमान होता है । जिन्ना साहब गन्दे और गहित व्यक्ति हैं । मैं आपको उनके निजी जीवन के बारे में कुछ बातें बताऊँगा । जब वह युवक थे तो उनका एक पारसी के घर में आना-जाना शुरू हो गया । उनका नाम ठीक से याद नहीं, लेकिन सर पेटीट था । उनके घर में जिन्ना का पूरा धर्म समान आदर होता था । उन्होंने उस पारसी की पुत्री में प्रेम करना आरम्भ किया और उससे विवाह कर लिया । अब आप स्वयं देखिये कि जब किसी घराने में पुत्र की भाँति आपसे व्यवहार किया जाय तो क्या आपको उसी घर की लड़की से प्रेम करने लगना शोभा देगा ? यह विवाह सुखद नहीं था । उस लड़की ने शब्द अपने पिता को छोड़ दिया है और एक पारसी से विवाह कर लिया है जो हाल ही में ईसाई हो गया है । जीवन की यही विडम्बना है ।”

मैंने महाराजा से जिन्ना के पाकिस्तान के बारे में पूछा । समस्या का हिन्दू-मुस्लिम विवेचन करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान व्यावहारिक योजना नहीं है और मुसलमान वास्तव में इसे नहीं चाहते । उन्होंने अपना मत प्रकट करते हुए यह भी कहा—“पाकिस्तान से हिन्दुस्तान का विभाजन हो जाएगा ।”

यह सारा भगड़ा आगाखा की गलती से शुरू हुआ था, जो ब्रिटिश वाइसराय लार्ड मिंटो से मिलने वाले मुस्लिम शिष्टमण्डल के नेता थे। [यह भेंट १ अक्टूबर १९०६ में हुई थी] आगाखा ने आग्रह किया था कि भारत में धार्मिक आचार पर पृथक् निर्वाचन-पद्धति चालू की जाय।”

मेने पूछा—“मगर अंग्रेजों ने यह प्रार्थना क्यों स्वीकार कर ली ?”

महाराजा बोले— “शिष्टमण्डल की भेंट को सरकार की ही प्रेरणा से किया गया एक कार्य कहा गया है। अंग्रेज ही ऐसा चाहते थे। साम्राज्य में अक्सर ऐसी ही कूटनीतिज्ञता से काम लिया जाता है। ‘दो दलों को परस्पर लडाकर उन पर शासन करो।’”

मुलाकात करते मुझे एक घटा हो चुका था। महाराजा ने घटी वजाई और सेक्रेटरी से मेरे लिए बीकानेर-सम्बन्धी पुस्तक लाने को कहा। जब हम पुस्तक की प्रतीक्षा कर रहे थे, महाराजा बोले— “बातचीत बड़ी अच्छी रही, मुझे खुशी है कि आपने आने का कष्ट किया। किन्तु वास्तव में, मैं “लाइफ एड टाइम” वाले बिल फिशर की प्रतीक्षा में था। उनसे मैं कई बार पहले मिल चुका हूँ।” इस पर हम दोनों खूब खिलखिलाकर हँसे। यह महाराजा के सेक्रेटरी की गलती थी।

“आइये ज़रा वर्षा ऋतु का दृश्य देखें” महाराजा ने कहा। समुद्र के ऊपर आकाश में काले-काले बादल छाये हुए थे। वह मुझे अपने उद्यान के लम्बे-चौड़े लॉन में ले गये जहाँ बहुत बड़ा नीला कालीन बिछा था। कालीन के बीच में बेत की कुरसियाँ रखी थी। उद्यान के अन्त में एक दीवार थी। नीचे चट्टानी समुद्र-तट था। समुद्र की ऊँची-ऊँची लहरे दीवार से टकरा रही थी और उसके छोटे हमारी ओर आ रहे थे। काले बादलों में गड़गड़ाहट हो रही थी। वर्षा होने ही वाली थी। महाराजा ने दो महिलाओं से मेरा परिचय कराया, जो दीवार के पास खड़ी थी। वहाँ से हम सब प्रकृति का वह खेल देखते रहे। एक महिला तो भारतीय डाक्टर थी और बीकानेर के एक अस्पताल में काम करती थी; और दूसरी हंगेरियन यहूदिन थी। उनके बाल सफ़ेद थे और वह महाराजा के तीन सुन्दर पोतों की ‘गवर्नेस’ थी, जिन्होंने उसी समय बाबा के स्वागत के लिए एक खिड़की से अपने चमकते हुए आकर्षक चेहरे बाहर निकाले थे।

महाराजा ने मुझे जो पुस्तक दी उसका नाम था—“बीकानेर की प्रगति के चार दशक”। यह बीकानेर दरबार का सरकारी प्रकाशन था और सन् १९३७ में प्रकाशित हुआ था। बीकानेर का क्षेत्रफल २३,३१७ वर्ग मील है,

द्विजयम और हार्लैण्ड के सम्मिलित क्षेत्रफल से कुछ ही छोटा । बाकानेर में कोई नदी नहीं है । सन् १९०१ में वहाँ की जन-संख्या ५,८४,७५५ थी और १९३१ में ९,३६,२१८ हो गई । बाकानेर नगर (राजधानी) की जन-संख्या ८४,९२७ है । रियासत में हिन्दुओं की संख्या ७,२५,०८४, मुसलमानों की १,४१,५७८, सिखों की ४०,४६९ और जैनियों की २८,७३३ है । रियासत की मृत्तम दृष्टी आवश्यकता पानी है । वहाँ की खेती वर्षा पर निर्भर है, जो कभी नहीं भी होती । वहाँ कई भयंकर अकाल पड़ चुके हैं ।

बाकानेर के महाराजा ने ४४ वर्ष शासन किया । वर्माई की शान्ति-संधि पर उनके भी हस्ताक्षर हैं । मध्य-कालीन भारत की वे एक विभूति थे ।

नरेण जानते हैं कि आजकल ममार में और भारत में एक नई हवा चल रही है । प्रसिद्ध कवयित्री और रवतत्रता की अधिक समर्थक श्रीमती मरोजिनी गांधी ने मुझे बताया कि कई भारतीय नरेण गोपनीय रूप से कांग्रेस-दल के सम्पर्क में हैं । नरेण्ड मण्डल के एक नेक्रेटरी ने मुझसे कहा—“रियासतें भारत के लिए ‘अरगटर’ सिद्ध नहीं होगी”, अर्थात् वे इंग्लैण्ड को स्वतंत्र भारत में घुसना नहीं समझेंगी । नरेण अब धीरे धीरे अपने आपको इस परिवर्तन के अनुकूल बना रहे हैं । उदारतम नरेणों में इन्दौर के महाराजा हैं ।

एक दिन अमरीका सेना के जनरल ऐडलर मिश्र के लिए इन्दौर के महाराजा के महल पर पहुँचे । कुछ दिन बाद, ३० मई १९४२ को महाराजा-पत्नी ने महाराजा इन्दौर द्वारा लिखित प्रेजिडेंट राजपेक्ट के नाम पर “गुला पत्र” प्रकाशित किया । इस पत्र में महाराजा ने राजपेक्ट में भारत और ब्रिटेन के भगने में बीच-बचाव करने का कहा था । उन्होंने लिखा था—“भारत विभाजित और असन्तुष्ट है ।”

महाराजा ने यह भी लिखा था—“नरेण तो मैं केवल अपने जन्म के गयोग से हैं । जहाँ तक मेरे निजी विश्वास का प्रश्न है मैं अन्तर्राष्ट्रीय और अन्तर्गत समर्थक हूँ ।”

ऐसा पत्र लिखने के लिए वाशिंगटन ने दुर्लभ ही महाराजा इन्दौर को मान-सम्मान दत्तार । उनके द्वारा किये गये वागों में एक यह भी था कि उन्होंने भारत की राष्ट्रीय संसदीय विधान दल स्वीकार कर लिया था ।

भारत की रियासतें मध्यकालीन विश्वास-कार के सदृश हैं । अन्तः-क्षेत्र के लिये रहने के लिए मित्रित्व के अभाव में इन इन्डिपेंडन्सी सन्देशों के प्रकाश के लिए बाध्य हैं । फिर उन्हें १९ वीं शताब्दी की प्रतीति है और वे १९ वीं शताब्दी की प्रतीति के लिये बाध्य हैं ।

भारतीय रियासतों की हम साम्राज्यवाद की सब से अधिक विचक्षण युक्ति कह सकते हैं। इन रियासतों का वास्तविक उद्देश्य क्या है; इस सम्बन्ध में मेरे पास अंग्रेज अधिकारियों द्वारा घोषित की गई कम-से-कम ६ विभिन्न नीतियों के वक्तव्य हैं। उनमें से मैं दो को यहाँ उद्धृत करता हूँ। प्रोफेसर रशब्रुक विलियम्स ने, जिन्होंने प्रायः अंग्रेजों और नरेशों के बीच सरकारा शृंखला का काम किया है, २८ मई १९३० के “ईर्वनिंग स्टैंडर्ड” नामक लंदन के पत्र में लिखा था—“ब्रिटिश भारत के अन्दर-बाहर फली हुई ये सामंत रियासतें सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी उपयोगी हैं। इन्हें हम सदिग्ध भूमि में फैलाये गये मंत्रीपूर्ण दुर्गों का जाल कह सकते हैं। इन स्वामीभक्त रियासतों के कारण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध साधारण विद्रोह का सफल होना बहुत कठिन होगा।”

भारत के वाइसराय, लार्ड कैनिंग ने ३० अप्रैल १८६० को कहा था—“सर जॉन मॅल्कम बहुत पहले ही कह चुके हैं कि यदि हम सारे भारत को अंग्रेजी जिलों में ही बांट देंगे, तो इस बात की सम्भावना नहीं कि हमारा साम्राज्य ५० वर्ष से अधिक तक चल सकेगा। किन्तु यदि हम बहुत-सी रियासतें कायम कर दें, उन्हें राजनीतिक अधिकार से वंचित रखें और उनसे केवल शाही अस्त्र के तौर पर काम लें, तो हम भारत में तब तक रह सकेंगे जब तक हमारी जलसेना का प्रभुत्व अक्षुण्ण रहेगा। इस सम्मति के आधारभूत सत्य में मुझे बिलकुल सन्देह नहीं और हाल ही की घटनाओं ने यह विषय हमारे लिए इतना विचारणीय बना दिया है जितना पहले कभी नहीं था।” “हाल की घटनाओं” का अभिप्राय १८५७ के विप्लव से था।

इंग्लैंड के विकसित जनतंत्र का ज्ञान रखने वाले न्याय-प्रिय व्यक्तियों के लिए यह विश्वास करना निस्सन्देह बड़ा कठिन है कि उपनिवेशों पर अपना अधिकार बनाये रखने के लिए अंग्रेज अनेक सम्भावनाओं को उठाकर ताक पर रख देते हैं और जनता के धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मतभेदों को उत्तेजित कर उनसे लाभ उठाते हैं। किन्तु थल और जल सेनाओं तथा एक छोटे शासन-यंत्र द्वारा ४० करोड़ आदिमियों पर राज्य करना आसान काम नहीं। हिन्दुस्तानियों में आत्म-प्रतिपादन की उठती हुई भावना के कारण यह काम और भी कठिन है। इसलिए जहाँ से भी सम्भव होता है अंग्रेजों को हिन्दुस्तानियों का समर्थन प्राप्त करना ही पड़ता है। यह समर्थन उन्हें कठपुतली महाराजाओं से मिलता है। युद्ध के दिनों में यह समर्थन उन्हें कम्युनिस्टों से भी मिला, जो सरकार से आर्थिक सहायता लेते थे और जिनका दल भारत

भारतीय रियासतो की हम साम्राज्यवाद की सब से अधिक विचक्षण युक्ति कह सकते हैं। इन रियासतो का वास्तविक उद्देश्य क्या है; इस सम्बन्ध में मेरे पास अंग्रेज अधिकारियों द्वारा घोषित की गई कम-से-कम ६ विभिन्न नीतियों के वक्तव्य हैं। उनमें से मैं दो को यहाँ उद्धृत करता हूँ। प्रोफेसर रशब्रुक विलियम्स ने, जिन्होंने प्रायः अंग्रेजों और नरेशों के बीच सरकारा शृंखला का काम किया है, २८ मई १९३० के “ईवनिंग स्टैंडर्ड” नामक लंदन के पत्र में लिखा था—“ब्रिटिश भारत के अन्दर-बाहर फली हुई ये सामंत रियासते सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी उपयोगी हैं। इन्हें हम सदिग्व भूमि में फैलाये गये मैत्रीपूर्ण दुर्गों का जाल कह सकते हैं। इन स्वामीभक्त रियासतों के कारण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध साधारण विद्रोह का सफल होना बहुत कठिन होगा।”

भारत के वाइसराय, लार्ड कैनिंग ने ३० अप्रैल १८६० को कहा था—“सर जॉन मेलकम बहुत पहले ही कह चुके हैं कि यदि हम सारे भारत को अंग्रेजी जिलों में ही बांट देंगे, तो इस बात की सम्भावना नहीं कि हमारा साम्राज्य ५० वर्ष से अधिक तक चल सकेगा। किन्तु यदि हम बहुत-सी रियासतें कायम कर दें, उन्हें राजनीतिक अधिकार से वंचित रखें और उनसे केवल शाही अस्त्र के तौर पर काम लें, तो हम भारत में तब तक रह सकेंगे जब तक हमारी जलसेना का प्रभुत्व अक्षुण्ण रहेगा। इस सम्मति के आधारभूत सत्य में मुझे बिल्कुल सन्देह नहीं और हाल ही की घटनाओं ने यह विषय हमारे लिए इतना विचारणीय बना दिया है जितना पहले कभी नहीं था।” “हाल की घटनाओं” का अभिप्राय १८५७ के विप्लव से था।

इंग्लैण्ड के विकसित जनतंत्र का ज्ञान रखने वाले न्याय-प्रिय व्यक्तियों के लिए यह विश्वास करना निस्सन्देह बड़ा कठिन है कि उपनिवेशों पर अपना अधिकार बनाये रखने के लिए अंग्रेज अनेक सद्भावनाओं को उठाकर ताक पर रख देते हैं और जनता के धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मतभेदों को उत्तेजित कर उनसे लाभ उठाते हैं। किन्तु यल और जल सेनाओं तथा एक छोटे शासन-यंत्र द्वारा ४० करोड़ आदमियों पर राज्य करना आसान काम नहीं। हिन्दुस्तानियों में आत्म-प्रतिपादन की उठती हुई भावना के कारण यह काम और भी कठिन है। इसलिए जहाँ से भी सम्भव होता है अंग्रेजों को हिन्दुस्तानियों का समर्थन प्राप्त करना ही पड़ता है। यह समर्थन उन्हें कठ-पुतली महाराजाओं से मिलता है। युद्ध के दिनों में यह समर्थन उन्हें कम्पुनिस्टों से भी मिला, जो सरकार से आर्थिक सहायता लेते थे और जिनका दल भारत

का एक मात्र यद्ध-समर्थक दल था। अपनी स्थिति दृढ़ बनाने के लिए वे हिन्दू-मुस्लिम और हिन्दू-हरिजन भेद-भावों से लाभ उठाते हैं। वे शासन कर रहे हैं क्योंकि वे हिन्दुस्तानियों में फूट डाल सकते हैं। यदि ४० करोड़ हिन्दुस्तानी सुनहाल हो, शिक्षित हो और एकता के सूत्र में बँधे हो तो उन्हें शीघ्र ही ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त होने के साधन मालूम हो जाय। यही कारण है कि भारत में अंग्रेजों का प्रधान लक्ष्य यह कभी नहीं रहा कि देश सम्पन्न बने, सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नति करे, अथवा एकता के सूत्र में बँधे।

निश्चय ही अंग्रेजों ने भारत में रेलें, सिंचाई की प्रणालियाँ, बिजली, स्वास्थ्य-व्यवस्था इत्यादि जारी की हैं। आखिर यह बीसवाँ सदी है। फिर भी मध्य-कालीन सदियों का वातावरण सम्भवतः चौदहवीं शताब्दी तक सुरक्षित रखा गया है और आगे बढ़ने की गति को मन्दतम रखने की चेष्टा की जा रही है।

नये युग का आह्वान ही भारत के विद्रोह का कारण है।

यह कोई नहीं कहता कि स्वाधीनता से भारत की सब समस्याएँ हल हो जायगी। उससे तो नई समस्याएँ पैदा होंगी। स्वतंत्रता तो केवल समस्याओं के समाधान का द्वार खोल देती है।

स्वाधीनता के समय कैसी परिस्थितियाँ हागी इसकी जानकारी पराधीनता-कालीन परिस्थितियों में नहीं होती। मनुष्य में जो कुछ भी अच्छा है या हो सकता है वह पराधीनता और स्वाधीनता के अन्तर में निहित है। स्वाधीनता की उपादेयता को स्वाधीन रहकर ही जाना जा सकता है।

: ११ :

भारत में अंग्रेजी राज्य

प्रायः सभी भारतीयों की शिकायत थी कि वे हतोत्साह हैं। अंग्रेजों का कहना था कि हिन्दुस्तानी उदार नहीं हैं। अंग्रेजों को यह दुःख है कि भारत में उनके कार्यों को सराहा नहीं जाता। अनेक अंग्रेज अफसरों की यह दृढ़ धारणा है कि उन्होंने भारत की विशेष सेवा की है। परन्तु वे यह भी जानते हैं कि भारतीयों का इसके बारे में भिन्न मत है।

उन अंग्रेज परिवारों के सदस्यों ने, जिनके पूर्वज कई पीढ़ियों से भारत सरकार की सेवा करते आये हैं, मुझे बताया कि अब भारत सरकार की नौकरी में न उन्हें कोई सतोष अथवा प्रसन्नता प्रतीत होती है और न इसका भविष्य ही उन्हें उज्ज्वल दिखाई देता है। भारत के प्रतिकूल जलवायु में वर्षों कठोर श्रम करने के बाद जब अंग्रेज अफसर इंग्लैंड लौटता है तो वह स्वदेश में अपने को परदेशी-सा पाता है। और इस कठोर सेवा का पारिश्रमिक उसे मिलता है, अपने प्रति भारतीयों का बढ़ता हुआ द्वेष। भारत में अंग्रेज एक वैमनस्य के समुद्र के बीच अपने निजी छोटे से टापू में रह रहे हैं। उन्हें ऐश्वर्य और प्रभुता तो प्राप्त है, परन्तु वास्तविक सतोष एवं प्रसन्नता उन्हें नहीं मिल सकी।

अंग्रेजों का भारतीयों के साथ व्यवहार समानता का नहीं है। भारत सरकार के एक उच्च-पदाधिकारी अंग्रेज ने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया, जिस पर तीन मुस्लिम भी आमन्त्रित थे। वह रह-रहकर अपने भारतीय अतिथियों को कहता—“मि० फिशर को ज़रा बताइये कि भारत की क्या दुर्दशा होगी यदि अंग्रेज आज भारत छोड़ दें। तब तो इन्हें हिन्दू-मुस्लिम समस्या के बारे में तो बताये”। तुरन्त मुझे घड़ा-घड़ाया उत्तर मिलता। भारत में प्रलय आजाएगी। हिन्दू-मुसलमान एक दूसरे का गला काट डालेंगे। उसी दिन उनमें से एक सज्जन मुझे एकांत में फिर मिले। उन्होंने कहा—“मैं आपका दुबारा केवल यह बताने के लिए मिला हूँ कि जो कुछ भी मैंने उस अंग्रेज अफसर के खाने

वर कहा था, उसमें मेरा स्वयं विश्वास नहीं है। ऐसे हिन्दुस्तानी अंग्रेजों का अपने ऊपर आधिपत्य तो स्वीकार करते हैं, परन्तु वे उन्हें अपने से श्रेष्ठतर मानने से इन्कार करते हैं। अंग्रेज इसे खूब समझते हैं, इसीलिए उन्हें अब हिन्दु-मान में रहना नहीं भाता।”

गांधी की घास-फूस की कुटिया में तीन हफ्ते रहकर मैं हैदराबाद के रेजीडेंट सर क्लाड गिडनी का मेहमान बना। एक सुन्दर पार्क में स्थित एक प्रासाद के दो कमरों में मैं ठहराया गया। लश्करी सफेद वरदी, रंगीन पेट्टी और सुन्दर मूँठ वाली कटार से लैस, नंगे पैर, गम्भीर दरवान मेरी सेवा में सदा हाज़िर रहता। वह इतना खामोश रहता कि मुझे उसकी मौजूदगी का भी कई बार पता न चलता। प्रातः सवेरे, ज्योंही मेरी आख खुलती, कहवा और फलों की छोटी हाज़िरी वह मेरे सामने ला रखता। मेरे गुसल और कपड़ों की धुलाई का प्रबन्ध भी वही करता।

खाने के वक्त का काला सूट मैं नई दिल्ली में ही रख आया था। क्योंकि मेरे विचार से भारत की गरमियों में उसकी आवश्यकता न थी। हा, एक टाई मैं जरूर लाया था, परन्तु वह सूटकेस में पड़ी रहती। हैदराबाद में पहली ही शाम को रेजीडेंट ने कॉकटेल और भोज का आयोजन किया। कॉक-टेल पार्टी के बाद सर क्लाड रात के खाने की पोशाक पहनने के लिए मुझ से विदा हुए और मैं तथा लेडी गिडनी अकेले रह गये। अतिथि के मनोरंजनार्थ और बातचीत चलाने के लिए लेडी गिडनी ने अपनी बाबत मुझे सुनाना शुरू किया। वह सार दिन सार्वजनिक कार्यों—विशेष कर ब्रिटिश मंत्रियों का महासभायें कायों में व्यस्त रहती थी। साथ ही उन्हें भारतीयों को भी भोज देने पड़ते थे। वे कहने लगी, भारतीयों को भी भोज देना जरा नाजुस मानता है। यदि कोई हिन्दुस्तानी किसी अंग्रेज के लंच (दिन का खाना) पर बुलाया जाय, तो अपने समुदाय में उसकी प्रतिष्ठा बढ जाती है। डिनर (रात का खाना) पर बुलाये जाने पर तो उसकी शान दुगुनी हो जाती है। अंग्रेज मेहमानों को प्वाणेत में दिये गए भोज में शामिल होने से तो हिन्दुस्तानी महानय की प्रशंसा प्रतिष्ठा में ही वृद्धि होती है वरन् उनके निजी व्यवहार में भी उन्नति की सम्भावना हो जाता है। हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि अपने पुराने परिचित भारतीयों को समय-समय पर खाने पर बुलाने रहें। नहीं तो हमारे पुराने अन्तर्गतता सम्बन्ध जाता है जिस के परिणामस्वरूप उन व्यक्ति की प्वाणेत में अन्तरे जा होती है।

जिन देश में महानय ने की दावत का इन्तजाम किया है...

सम्राट् अथवा वाइसराय पद, पदवी, नौकरी, जागीर, अथवा अन्य कृपायें करके अपने पिट्ठुओं तथा जी-हुजूरों का बहुत बड़ा वर्ग बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस तरह अंग्रेजों के कृपापात्र बनने की होड़ उनमें सघर्ष और फूट का बीज भी बो देती है। परन्तु राजनीतिक चेतना युक्त, स्वाभिमानी-भारतीयों में इन जी-हुजूरों के प्रति केवल घृणा ही उत्पन्न होती है और ब्रिटिश सरकार के प्रति उनका अविश्वास और भी गहरा हो जाता है।

एक दोपहर, रेजीडेंट गिडनी के यहाँ नवाब कमालयार जग खाने पर बुलाये गए। नवाब साहब देखते ही बनते थे। भद-भद मोटा शरीर, चमकीला भूरा चेहरा, सफेद पोशाक और सिर पर बड़ी हैदरावादी पगड़ी। नवाब साहब कहने लगे—मेरी जागीर ३१७ वर्ग मील है और इसमें लगभग पीने दो करोड़ मनुष्य रहते हैं। हैदरावाद राज्य के लगभग ८० फीसदी निवासी राज्य से असंतुष्ट हैं। भला, हमें अरक्षित छोड़कर अंग्रेज भारत से कैसे कूच कर सकते हैं ?

ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में अत्यंत प्रतिक्रियागामी शक्तियों से अपना नाता जोड़ रखा है। मैंने सर आर्चिबाल्ड (अब लार्ड और वाइसराय) वेवल से पूछा : पर्ल हार्बर के पश्चात्, प्रशांत क्षेत्र में अंग्रेजों की हार-पर-हार का क्या कारण था। “उन प्रदेशों में रहकर, जहाँ सदियों से सिवाय टीन की खान तथा रबड़ के बागीचों की देख-रेख के कोई काम ही न था, हम सुस्त और निकम्मे हो गए थे,” उन्होंने उत्तर दिया।

वेवल सभ्य, सुसंस्कृत एवं सच्चे व्यक्ति हैं। उनसे मेरी पहली मुलाकात नई दिल्ली में उन्हीं के घर पर दिन के खाने के व्रक्त हुई थी। बहुत देर तक बातचीत के बाद, वह मुझे नाचे छोड़ने आये। सीढियों में मैंने कहा—“आप बहुत थके जान पड़ते हैं।” तीन साल से हार की लड़ाइयाँ लड़ते-लड़ते मैं थक गया हूँ” उन्होंने स्वीकार किया। फिर कहा, “रोमेल बहुत बड़ा सेना-नायक है। मैंने उसका मुकाबला किया है। मैं उसके गुणों को खूब जानता हूँ।” मैं वेवल से चार बार मिला, और वह हर मुलाकात में रोमेल का जिक्र छोड़ देते थे।

वेवल की चाल को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, मानो मनुष्य की टांगों के बल टैंक चल रहा हो। उनका चेहरा सिकुड़ा हुआ-सा लगता है जिस पर गहरी रेखाओं की स्पष्ट छाप है। उनकी बाईं आँख मुदी हुई और ज्योति-विहीन है। उनके सिर के बाल घने और भूरे हैं। उनकी खाँकी वरदी के बाईं

और छाता पर फीजी रिबन की पाच कतारें भला लगती है। तीस साल हुए जब वे भारत में मामूनी लेफ्टिनेंट की हैसियत से आये थे। १९४१ में भारतीय प्रधान मन्त्रिण बनकर वे भारत वापिस आये। इससे पहले, वे कई देशों में घूम आये थे। वह रूस भी दो बार हो आये थे। पहली बार प्रथम युद्ध से पहले एक वर्ष वे वहाँ रहे थे और दूसरी बार उसी युद्ध के दौरान में ६ मास तक वे रुम में रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि रूसी बलिष्ठ और वीर्यवान जाति है, और प्रथम विश्व-युद्ध में, जारशाही के मातहत भी लड़कर, उन्होंने गण्टमैन का परिचय दिया था। वेबल १९३६ में श्वेत रूस में लालफौज की गतिविधि के प्रदर्शन के समय आमंत्रित थे और उन्होंने युद्ध-विभाग को अपनी गिर्फाट में बनाया था कि मार्शल टुखाचेवस्की की कमान में लाल फौज शीघ्र ही पकड़ जायगी।

एक बार मैं वेबल के साथ उनके भवन के बाग में टहल रहा था। वह आगम में थे। मृत्सा उनकी पुरानी स्मृतियाँ जाग उठी और वे प्रथम युद्ध में बाकिंगिया के अपने सम्मरण मुझे सुनाने लगे। उन्हें कई रूसी मुहावरे याद हो आये। उन्होंने जात्रिया प्रदेश की एक वीर-कविता के सहसा कुछ टप्पे गुनगुनाने शुरू कर दिये।

वेबल का आदर्श वीर जनरल एलनवाई है, जो प्रथम युद्ध में उनके बग़ावत थे। जिन दिनों में हिन्दुस्तान में था, वेबल एलनवाई की जीवन-कथा का दूसरा भाग सम्पादन करने में जुटे हुए थे। उन्हें यह शिकायत थी कि उन दिनों उन्हें दिग्गजों का अवकाश बहुत थोड़ा मिलता था। वे भी लेखकों की बमजारी का शिकार हो गए। उनमें रहा न गया और झूठ से दरार में से अपनी रत्न-नीपि निजाल उन्होंने मुझ से पूछा—आप इसे पढ़ना चाहेंगे? मैं इस अवसर पर पुस्तक का प्रथम भाग पढ़ने के लिए घर ले गया। मैंने उसे चाब से पढ़ा। उनमें एक पात्र वेनस ऐरिफ का चरित्र-चित्रण पढ़ने से यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि जहाँ ब्रिटिश सेना को एक बड़ा सेनानी प्राप्त हुआ, वहाँ अंग्रेजी भावित्व ने एक सना हुआ लेखक खो दिया। उन पुस्तक में एलनवाई के मार्च १९०० में ब्रिटिश सरकार के साथ हुए संधि की बड़ी ही रोचक और विपक्षी दृष्टि-दृष्टि की गई है। उन दिनों एलनवाई मिल में हाई कमिश्नर थे। वे मिल में ब्रिटिश सरकार उद्योग के पक्ष में थे और ब्रिटिश सरकार विपक्ष में थी। एलनवाई अपने पक्ष की उन्नतता को पक्ष में रखते थे। प्रधान मन्त्री, लार्ड मिलनर, लार्ड बर्क और लार्ड रॉबर्ट्स एलनवाई का विरोध कर रहे थे।

कहते हैं, सबसे अधिक और कटु विरोध उनका चर्चिल ने किया।

अतः मे एलनवाइ ने घमकी दी कि वे इस्तीफा देकर ब्रिटिश जनमत से इस प्रश्न का निर्णय करायेगे। उन दिनों एलनवाइ की गुड्डी स्वदेश में बहुत चढ़ी हुई थी। फिलस्तीन और सीरिया में उनकी शानदार जीतो ने वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध में शत्रु (तुर्कों) को प्रबल आघात पहुंचाया था, जिसके कारण विजय बहुत निकट आ गई थी। ब्रिटिश सरकार ने, खुले आम में जीत के डर से, चुपचाप एलनवाइ की बात मान ली।

ब्रिटिश मंत्रि-मंडल के साथ हुए एलनवाइ के इस सघर्ष का हाल पढ़ते समय मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि यदि कभी वेवल को भी ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा, तो वे निश्चय ही अपने हीरो एलनवाइ का अनुकरण करेंगे।

वह हस्तलिपि लौटाते समय मैंने वेवल को एक पत्र में कहा—“मेरे विचार में चर्चिल, लायडजार्ज, कर्जन आदि ने मित्र की स्वतंत्रता का विरोध करते हुए ऐसी ही दलीले दी होगी, जैसी कि आजकल भारत की आज़ादी के विरोध में मैंने सुनी है। परंतु एलनवाइ अपनी बात पर अड़े रहे और अतः मैं उनकी जीत हुई। आप ठीक कहते हैं, एलनवाइ सच्चे थे और ब्रिटिश मंत्रि मंडल का पक्ष गलत था। प्रायः सरकारें भूल में होती ही हैं। समस्त यूरोप का १९१९-१९३९ तक का इतिहास गलत नीतियों का इतिहास है। ब्रिटिश मंत्रि मंडल की हाल का भारत सबन्धी कार्रवाई उनकी बुद्धिमत्ता की सूचक नहीं है।”

वाद में जब वेवल को मैं फिर मिला तो मैंने एलनवाइ के सघर्ष का इतना अच्छा और रोचक वर्णन देने के लिए उन्हें बधाई दी। वेवल बोले—वास्तव में यह राजनीतिक जीत एलनवाइ की सेनानी विजयों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी।

दूसरे दिन दुपहर में वेवल को फिर मिला और हम सूर्यास्त तक बात चीत करते रहे। हम एक ही डेस्क पर बैठे थे। मैंने उनकी मेज के एक खाने में छोटी काली जिल्द वाली बाइबल का एक प्रति देखी। वेवल ने मुझे मैथ्यू आर्नल्ड कवि की कविता भी सुनाई। उन्होंने एक कविताओं का संग्रह स्वयं भी प्रकाशित किया है। साथ ही वह ब्लाटिंग पर लाल पेंसिल से गोल चक्र बनाते रहे। फिर वह कहने लगे : “साम्राज्य ने हमें बोदा और सुस्त बना दिया है। इस युद्ध में ब्रिटेन को उपनिवेशों से बहुत कम सहायता मिली है, भारत में सैनिक या तो धन के लालच के भरती हो रहे हैं, या फिर अपनी प्राचीन परम्परा के कारण।”

केवल में दार्शनिक, ऐतिहासिक एवं कलाकार का विचित्र सामंजस्य पाया जाता है। वे निश्चय ही फाडलो में दबे रहने वाले नौकरशाही के पुतले मात्र नहीं हैं। लिनलिथगो १९४२ में रात में देर तक बैठे भारत के प्रत्येक जिज्ञे की रिपोर्ट पढ़ते रहते थे। वे भारत को दूरबीन की बजाय खुरदबीन से देखकर मन्तोष कर लेते थे।

लार्ड लिनलिथगो ने ४ जुलाई को अमेरिकन स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वाइमराय-भवन में एक भोज दिया। उस में भारतीय स्वतंत्रता के विरुद्ध अनेक दलीले मेरे सुनने में आईं। जनरल विटरटन, जो वर्मा में सर हेरेल्ड अलेक्जेंडर के नीचे चीफ-आव स्टाफ रह चुके थे, मुझ से बोले—परंतु, स्वतंत्र भारत अपनी रक्षा कैसे करेगा ?

“क्या स्वतंत्र इंग्लैंड अपनी रक्षा कर सकता है ?” मैंने प्रत्युत्तर में कहा।

यदि केवल उन देशों को स्वतंत्र होने का अधिकार है जो अकेले अपनी रक्षा करने में समर्थ हैं, तो शायद ही कोई देश स्वतंत्रता का अधिकारी हो। ग्रीस, डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस आदि अनेक देश तो निश्चय ही स्वतंत्रता के अधिकारी रहेंगे। वास्तव में इस समय हमको एक ऐसे व्यक्ति मन्तव्य प्रत्युत्तर में सगठन की आवश्यकता है जो एक स्वतंत्र भारत, आजाद इंग्लैंड आदि देशों के साथ एक स्वतंत्र राष्ट्रों की रक्षा करने में समर्थ हो सके। पञ्च अरि और अवन राष्ट्र समाज के लिए कई बार अधिक मानसिक प्रयास हो रहे हैं और विजेता अथवा गुडे की बजाय वे संरक्षण के अधिक अधिकारी रहे हैं।

उसी दिन शाम को लिनलिथगो की सुंदर पत्नी ने मुझे बान्सीन के लिए बुलाया। उन्होंने भोजन का जिक्र छोड़ कर बान्सीन बोलना शुरू किया। उस शाम गर्मी का तापमान ११० था और हमारे शरीरों में पसीना चूर रहा था—यह थोड़ी ही दूर में हम राजनीति में प्रवेश कर गए। बादस्तेन ने कहा—दूर क्या दिव्यनीति वास्तव में स्व-शासन के योग्य है ?

‘आज तो आपका यह प्रश्न विचित्र-सा लग रहा है’ मैंने उत्तर दिया। ‘मार्च १७७६ में ब्रिटिश टारियो ने वही प्रश्न अमेरिका के १३ उपनिवेशों के सम्मुख में किया था।’

भारत में भगते बह रहे हैं कि ब्रिटेन भारत छोड़ रहा है। बादस्तेन ने वास्तव में वास्तव के गृह-सदस्य सर रेजीनल्ड मैक्डोवेल ने मुझे अपने घर पर बुलाया। उन्होंने कहा—‘ब्रिटेन भारत पर हमला करने का प्रयत्न कर रहा है।’ मैं विचार में पड़ने के दो साल बाद ब्रिटेन भारत छोड़ देगा, मुझे निश्चय

समय नहीं घोषित किया है। मेरे विचार में यही हमारी भूल है।

“आप अच्छी तरह समझते होंगे,” एक बार मैंने जनरल वेवल से कहा, “भारत का वर्तमान राज्य ५ या १० वर्ष से अधिक नहीं रह सकता।”

“विलकुल ठीक” वेवल ने जोरदार समर्थन किया। जब मैं वाइसराय से पुनः मिला तो वे मुझ से बोले “हम भारत में अधिक देर न ठहरेंगे। कांग्रेस इस पर विश्वास नहीं करती है।” कांग्रेस और बहुत से हिन्दुस्तानियों के अविश्वास का कारण यह था कि यद्यपि अंग्रेज भारत छोड़ने की घोषणा तो करते हैं, लेकिन वे अपनी दलीले ठहरने के पक्ष में ही देते हैं।

जहां तक मुझे स्मरण है शायद ही भारत में किसी अंग्रेज अफसर ने अथवा इंग्लैंड में अनुदार दल के व्यक्ति ने भारत की स्वतंत्रता का समर्थन किया हो। बात इसके विपरीत ही हुई है। भारत से बाहर अमेरिका में अंग्रेजों ने लाखों रुपये भारतीय स्वतंत्रता के विरुद्ध आंदोलन करने में खर्च किये हैं। इसीलिए भारतीयों को अंग्रेजों के वचन पर विश्वास नहीं रहा।

भारतीय अंग्रेजों का परंपरा अविश्वास भारत की वर्तमान स्थिति का आधार-भूत सत्य है। सर रेजीनॉल्ड डॉरमन स्मिथ सन् १९४२ में बर्मा के गवर्नर थे जब कि वह देश जापानियों के हाथ चला गया। “एशियाटिक रिव्यू क्वार्टरला” के जनवरी १९४४ के अंक में एक लेख द्वारा उन्होंने पूर्वी एशिया में ब्रिटेन के पतन के कारणों पर प्रकाश डाला है। वे लिखते हैं—“पूर्वी एशिया में न हमारे वचन और न ही हमारी मशाओ पर अब किसी को विश्वास रहा है, यह मैं निश्चय से कह सकता हूँ। इसका कारण स्पष्ट है। हमने बर्मा आदि देशों को राजनीतिक प्रस्तावों और वादों के सहारे इतना देर तक रखा है कि अब ये देश राजनीतिक सुभावों और गुरों के नाम से चिढ़ते हैं, और वे इन्हें हमारी आना-कानी का लक्षण मानते हैं। हमारे राजनीतिक गुर अथवा उनके हल हमारे शत्रु व मित्र दोनों को अचम्भे में डालने वाले होते हैं, क्योंकि उनका अर्थ लगाना मुश्किल नहीं है।

बर्मा को आजाद करने का हमने वचन दे दिया है। फिर भी सर हेरल्ड अलक्जेंडर ने, जो जापान के अधिकार में उतने समय तक बर्मा में ब्रिटिश सेनापति थे, ३१ मई सन् १९४२ को नई दिल्ली में एक सम्मेलन में कहा—“हमें बर्मा वापिस लेना होगा। यह देश तो ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग है।”

बर्मा स्वतंत्र होगा—बर्मा ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग रहेगा। इन दोनों में से हम किस बात को मानें? सर रेजीनॉल्ड इन दोनों विकल्पों में उलझे हुए हैं, वे लिखते हैं— ब्रिटेन बर्मा को पूर्ण-स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए

वचन-वद्ध है। अतः हमारा ध्येयवर्मा में ऐसी नीति वर्तना होना चाहिये, जिसके कारण वर्मा साम्राज्य से निकलना ही न चाहे।

‘स्वतंत्रता’ शब्द की व्याख्या करके सर रेजीनॉल्ड लिखते हैं— हमें स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ समझने चाहिए। मुझे भय है कि हम कहीं भूल न जाय कि विभिन्न लोग स्वतंत्रता का तात्पर्य भिन्न समझते हैं। क्या ही अच्छा हो यदि हम भी बर्मियों को माफ-साफ बतादे कि स्वतंत्रता का अर्थ हम क्या लगाते हैं ?

मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के अन्तःकोप में स्वतंत्रता का अर्थ साम्राज्यान्तर्गत रखना ही है।

सर स्टैफर्ड क्रिप्पन भारत आये और चर्चिल सरकार की ओर से उन्होंने भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य का प्रस्ताव रखा। भारतीय उपनिवेश, यदि चाहे, तो उसका सबसे पहला काम अपने-आपको ब्रिटिश-साम्राज्य से बाहर निकालना हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। यह मार्च १९४२ की बात है। परन्तु नवम्बर १९४२ में चर्चिल ने कहा “मेरे साम्राट् का प्रधान नवी इस लिए नहीं हुआ है कि मेरे अधिकार-काल में ब्रिटिश-साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो जाय।” प्रकट है, उनका सकेत भारत की ओर था। चुनाव, जब पण्डित भारद्वाज निकलने की बात करने लगे, तो भारतीयों का उनके प्रति मरदेखा भाविक था।

चीनियों की एक प्रसिद्ध लोकोक्ति है—समृद्धि की ओर और तमस से पुकारना बुद्धिमानी का प्रथम लक्षण है।

जार्जिया कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और आयरलैंड ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रहने हुए भी स्वायत्त हैं। यह विशेष विस्मयकृत तथ्यान्त पर दिया है। आयरलैंड युद्ध में शामिल नहीं हुआ। दूसरे चार उपनिवेश स्पेञ्चा से ब्रिटिश साम्राज्य के साथ अपने-अपने निष्कर्ष निकालने की योजना में धनु से निर्यते। बीसवीं सदी का यह एक राजनैतिक चमत्कार है।

परन्तु भारत का एंग्लोइड के प्रति दूसरा ही रव है। अंग्रेजों के भारतीयों के बावण भारतीयों को उनसे लड़ने का प्रेरण नहीं है। अंग्रेज इसे प्रवृत्ति कहेंगे। ब्रिटिश राज्य के इतिहास में भारतीयों ने इन्हीं-उन्हीं दिनों साम्राज्य विच्छेद करने की प्रकट इच्छा व्यक्त कर दी है।

इसके अतिरिक्त कुछ यह भी बात है कि इन्दिया में ही केवल भारत में ही प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी गई है। और यह अनुभव, निश्चित है। अब के अंग्रेज

श्वेतांग महाप्रभुओं का भार उठाते-उठाते थक गई है। वे गोरी जातियों के विज्ञान, शिल्प और भौतिक उन्नति के आगे सिर झुकाती है। परन्तु अंग्रेजों की राजनीति एवं सार्वजनिक नैतिकता के लिए उनके दिल में तनिक भी श्रद्धा नहीं है। वे अंग्रेजों का सैनिक योग्यता की कायल है, परन्तु उनका गानि स्थापन सम्बन्धी योग्यता में उन्हें विश्वास नहीं है।

पश्चिम का आदमी अब एशिया में केवल मित्र बनकर रह सकता है। वह अब एशिया में शासन नहीं कर सकेगा। चीन और भारत, जो गायद ही पहले एक-दूसरे के परिचित रहे हों, अब घनिष्ठ पड़ोसी बन रहे हैं। आगामी ५० वर्षों में एशिया का मरदार चीन या भारत होगा। रंगीन जातियों की सख्या अरबों से ऊपर है। “एशिया एशियावासियों के लिए” यह नारा साम्राज्यवादी जापान ने अपनी स्वार्थ-मिद्धि के लिए प्रचारित किया था। यदि एशियावासियों ने गोरे-साम्राज्यों का अंत करने के लिए इस नारे का आश्रय लिया, तब तो स्थिति भयंकर हो जायगी।

पूर्व का प्रेम पश्चिम के प्रति विपरीतानुपात से उनना ही कम है जितना पश्चिम ने पूर्व के साथ अधिक अत्याचार किया है।

गोरा अपने प्रभुत्व का इतना आदा हांगया है कि उसे यह खयाल ही नहीं होता कि उसका आधिपत्य दूसरों को अखरता है।

अंग्रेज कहते हैं— भारतीय स्वराज्य के अयोग्य हैं। भारतीय कहते हैं— अंग्रेज ससार पर शासन के अयोग्य हैं। तनिक दो विश्व-युद्धों और उनके परिणामों—अशांति, उच्छृंखलता, अव्यवस्था, दुख और तानाशाहों की ताण्डवता का मुलाहजा कीजिये।

भारतीयों का कहना है कि ब्रिटेन भारत पर शासन करने के अयोग्य है। इंग्लैंड भारत में डंडे के बल से शांति तो कायम रख सकता है, परन्तु भारतवासियों के लिए भोजन, वस्त्र, मकान एवं अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने में असमर्थ है। बार-बार पड़ने वाले अकाल अंग्रेजों की शासन-सम्बन्धी अयोग्यता के प्रमाण हैं। १९४३ के बंगाल दुर्भिक्ष ने भारतीयों को विशेषतः क्षुब्ध किया। उस अन्न-संकट में करीब ३० लाख मनुष्य मौत के शिकार हो गये। किसी का भी अंदाज १० लाख मौतों से कम नहीं है। भारत में प्रति वर्ष १२॥ करोड़ आदमी मलेरिया के शिकार होते हैं। अन्य कारणों से एक लाख मौतें हो जाती हैं। ये अंग्रेजों की शासन-सम्बन्धी योग्यता के प्रमाण नहीं हैं। १९४१ की जन-संख्या के अनुसार भारत में कुल १३१ प्रतिशत साक्षर हैं, जब कि ‘साक्षरता’ से तात्पर्य केवल मामूली पढ़ लेने की योग्यता मात्र है। यह

भा न्यासन का प्रमाण नहीं है। औद्योगिक निश्चलता, अन्यायपूर्ण जमींदारों, अत्याचार और चिरकाल तक विदेशी सत्ता के अधिकार में रहने के कारण नैतिक ह्रास (हम भारत में विजेता के रूप में हैं, ऐसा मुझे लाडें लिनलियगो न कहा था) से भारतीय अत्यधिक क्षुब्ध और अंग्रेजों के प्रति अत्यन्त असहिष्णु (कभी-कभी तो अकारण ही) हो गये हैं। भारतीय स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है।

भारत में आज अनेक सफल, प्रतिभाशाली और अनुभवी शासक, औद्योगिक महाजन, अथवास्त्री, समाजशास्त्री न्यायविचारद, शिक्षक एवं राजनीतिज्ञ मौजूद हैं। सर स्टैफर्ड क्रिप्स का कहना है कि वाइसराय का विश्वास है कि भारतीय अपने राज्य की बागडोर संभालने योग्य हैं। "न्याय और अधि-
कारक सिद्धान्त पर", सर स्टैफर्ड ने पार्लियामेंट में अक्टूबर १९३९ का दिये
भाषण में कहा—“इस बात में कोई भी इकार न करेगा कि आज भारत
स्वराज्य का पूर्ण रूप में अधिकारी है। जब वाइसराय स्वयं इस बात को मानते
थे, हम भारतीयों की स्वराज्य की मांग को स्वीकार न करने का हमारे पास
किया इसका अर्थ यह है कि हम न्याय और औचित्य के अपने सिद्धान्तों को भूल
कर और भारत पर अपना एकाधिकार कायम रखकर, उनका मोर्चा नारो
करना चाहते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय अर्थतन्त्र का विकास अर्थतन्त्र की प्रगति की माँगों को भारत में आवश्यकता नहीं है। प्रगति को बढ़ावा देने के लिए।

[illegible][illegible]

1941 12 10 1942 1 10 1942 2 10 1942 3 10 1942 4 10 1942 5 10 1942 6 10 1942 7 10 1942 8 10 1942 9 10 1942 10 10 1942 11 10 1942 12 10 1943 1 10 1943 2 10 1943 3 10 1943 4 10 1943 5 10 1943 6 10 1943 7 10 1943 8 10 1943 9 10 1943 10 10 1943 11 10 1943 12 10 1944 1 10 1944 2 10 1944 3 10 1944 4 10 1944 5 10 1944 6 10 1944 7 10 1944 8 10 1944 9 10 1944 10 10 1944 11 10 1944 12 10 1945 1 10 1945 2 10 1945 3 10 1945 4 10 1945 5 10 1945 6 10 1945 7 10 1945 8 10 1945 9 10 1945 10 10 1945 11 10 1945 12 10 1946 1 10 1946 2 10 1946 3 10 1946 4 10 1946 5 10 1946 6 10 1946 7 10 1946 8 10 1946 9 10 1946 10 10 1946 11 10 1946 12 10 1947 1 10 1947 2 10 1947 3 10 1947 4 10 1947 5 10 1947 6 10 1947 7 10 1947 8 10 1947 9 10 1947 10 10 1947 11 10 1947 12 10 1948 1 10 1948 2 10 1948 3 10 1948 4 10 1948 5 10 1948 6 10 1948 7 10 1948 8 10 1948 9 10 1948 10 10 1948 11 10 1948 12 10 1949 1 10 1949 2 10 1949 3 10 1949 4 10 1949 5 10 1949 6 10 1949 7 10 1949 8 10 1949 9 10 1949 10 10 1949 11 10 1949 12 10 1950 1 10 1950 2 10 1950 3 10 1950 4 10 1950 5 10 1950 6 10 1950 7 10 1950 8 10 1950 9 10 1950 10 10 1950 11 10 1950 12 10 1951 1 10 1951 2 10 1951 3 10 1951 4 10 1951 5 10 1951 6 10 1951 7 10 1951 8 10 1951 9 10 1951 10 10 1951 11 10 1951 12 10 1952 1 10 1952 2 10 1952 3 10 1952 4 10 1952 5 10 1952 6 10 1952 7 10 1952 8 10 1952 9 10 1952 10 10 1952 11 10 1952 12 10 1953 1 10 1953 2 10 1953 3 10 1953 4 10 1953 5 10 1953 6 10 1953 7 10 1953 8 10 1953 9 10 1953 10 10 1953 11 10 1953 12 10 1954 1 10 1954 2 10 1954 3 10 1954 4 10 1954 5 10 1954 6 10 1954 7 10 1954 8 10 1954 9 10 1954 10 10 1954 11 10 1954 12 10 1955 1 10 1955 2 10 1955 3 10 1955 4 10 1955 5 10 1955 6 10 1955 7 10 1955 8 10 1955 9 10 1955 10 10 1955 11 10 1955 12 10 1956 1 10 1956 2 10 1956 3 10 1956 4 10 1956 5 10 1956 6 10 1956 7 10 1956 8 10 1956 9 10 1956 10 10 1956 11 10 1956 12 10 1957 1 10 1957 2 10 1957 3 10 1957 4 10 1957 5 10 1957 6 10 1957 7 10 1957 8 10 1957 9 10 1957 10 10 1957 11 10 1957 12 10 1958 1 10 1958 2 10 1958 3 10 1958 4 10 1958 5 10 1958 6 10 1958 7 10 1958 8 10 1958 9 10 1958 10 10 1958 11 10 1958 12 10 1959 1 10 1959 2 10 1959 3 10 1959 4 10 1959 5 10 1959 6 10 1959 7 10 1959 8 10 1959 9 10 1959 10 10 1959 11 10 1959 12 10 1960 1 10 1960 2 10 1960 3 10 1960 4 10 1960 5 10 1960 6 10 1960 7 10 1960 8 10 1960 9 10 1960 10 10 1960 11 10 1960 12 10 1961 1 10 1961 2 10 1961 3 10 1961 4 10 1961 5 10 1961 6 10 1961 7 10 1961 8 10 1961 9 10 1961 10 10 1961 11 10 1961 12 10 1962 1 10 1962 2 10 1962 3 10 1962 4 10 1962 5 10 1962 6 10 1962 7 10 1962 8 10 1962 9 10 1962 10 10 1962 11 10 1962 12 10 1963 1 10 1963 2 10 1963 3 10 1963 4 10 1963 5 10 1963 6 10 1963 7 10 1963 8 10 1963 9 10 1963 10 10 1963 11 10 1963 12 10 1964 1 10 1964 2 10 1964 3 10 1964 4 10 1964 5 10 1964 6 10 1964 7 10 1964 8 10 1964 9 10 1964 10 10 1964 11 10 1964 12 10 1965 1 10 1965 2 10 1965 3 10 1965 4 10 1965 5 10 1965 6 10 1965 7 10 1965 8 10 1965 9 10 1965 10 10 1965 11 10 1965 12 10 1966 1 10 1966 2 10 1966 3 10 1966 4 10 1966 5 10 1966 6 10 1966 7 10 1966 8 10 1966 9 10 1966 10 10 1966 11 10 1966 12 10 1967 1 10 1967 2 10 1967 3 10 1967 4 10 1967 5 10 1967 6 10 1967 7 10 1967 8 10 1967 9 10 1967 10 10 1967 11 10 1967 12 10 1968 1 10 1968 2 10 1968 3 10 1968 4 10 1968 5 10 1968 6 10 1968 7 10 1968 8 10 1968 9 10 1968 10 10 1968 11 10 1968 12 10 1969 1 10 1969 2 10 1969 3 10 1969 4 10 1969 5 10 1969 6 10 1969 7 10 1969 8 10 1969 9 10 1969 10 10 1969 11 10 1969 12 10 1970 1 10 1970 2 10 1970 3 10 1970 4 10 1970 5 10 1970 6 10 1970 7 10 1970 8 10 1970 9 10 1970 10 10 1970 11 10 1970 12 10 1971 1 10 1971 2 10 1971 3 10 1971 4 10 1971 5 10 1971 6 10 1971 7 10 1971 8 10 1971 9 10 1971 10 10 1971 11 10 1971 12 10 1972 1 10 1972 2 10 1972 3 10 1972 4 10 1972 5 10 1972 6 10 1972 7 10 1972 8 10 1972 9 10 1972 10 10 1972 11 10 1972 12 10 1973 1 10 1973 2 10 1973 3 10 1973 4 10 1973 5 10 1973 6 10 1973 7 10 1973 8 10 1973 9 10 1973 10 10 1973 11 10 1973 12 10 1974 1 10 1974 2 10 1974 3 10 1974 4 10 1974 5 10 1974 6 10 1974 7 10 1974 8 10 1974 9 10 1974 10 10 1974 11 10 1974 12 10 1975 1 10 1975 2 10 1975

श्वेतांग महाप्रभुओं का भार उठाते-उठाते थक गई है। वे गोरी जातियों के विज्ञान, शिल्प और भौतिक उन्नति के आगे सिर झुकाती हैं। परन्तु अंग्रेजों की राजनीति एवं सार्वजनिक नैतिकता के लिए उनके दिल में ननिक भी श्रद्धा नहीं है। वे अंग्रेजों का सैनिक योग्यता की कायल हैं, परन्तु उनका शान्ति स्थापन सम्बन्धी योग्यता में उन्हें विश्वास नहीं है।

पश्चिम का आदमी अब एशिया में केवल मित्र बनकर रह सकता है। वह अब एशिया में शासन नहीं कर सकेगा। चीन और भारत, जो शायद ही पहले एक-दूसरे के परिचित रहे हों, अब घनिष्ठ पड़ोसी बन रहे हैं। आगामी ५० वर्षों में एशिया का मरदार चीन या भारत होगा। रंगीन जातियों की मख्या अरबों से ऊपर है। “एशिया एशियावासियों के लिए” यह नारा साम्राज्यवादी जापान ने अपनी स्वार्थ-मिद्धि के लिए प्रचारित किया था। यदि एशियावासियों ने गोरे-साम्राज्यों का अंत करने के लिए इस नारे का आश्रय लिया, तब तो स्थिति भयंकर हो जायेगी।

पूर्व का प्रेम पश्चिम के प्रति विपरीतानुपात से उतना ही कम है जितना पश्चिम ने पूर्व के साथ अधिक अत्याचार किया है।

गोरा अपने प्रभुत्व का इतना आदा होगा है कि उसे यह खयाल ही नहीं होता कि उसका आधिपत्य दूसरों को अखरता है।

अंग्रेज कहते हैं— भारतीय स्वराज्य के अयोग्य हैं। भारतीय कहते हैं— अंग्रेजों सत्ता पर शासन के अयोग्य हैं। तनिक दो विश्व-युद्धों और उनके परिणामों—अशांति, उच्छृंखलता, अव्यवस्था, दुख और तानाशाहों की ताण्डवता का मुलाहजा कीजिये।

भारतीयों का कहना है कि ब्रिटेन भारत पर शासन करने के अयोग्य है। इंग्लैंड भारत में डंडे के बल से शांति तो कायम रख सकता है, परन्तु भारतवासियों के लिए भोजन, वस्त्र, मकान एवं अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने में असमर्थ है। बार-बार पड़ने वाले अकाल अंग्रेजों की शासन-सम्बन्धी अयोग्यता के प्रमाण हैं। १९४३ के बंगाल दुर्भिक्ष ने भारतीयों को विशेषतः क्षुब्ध किया। उस अन्न-संकट में करीब ३० लाख मनुष्य मौत के शिकार होगये। किसी का भी अदालत १० लाख मौतों से कम नहीं है। भारत में प्रति वर्ष १२॥ करोड़ आदमी मलेरिया के शिकार होते हैं। अन्य कारणों से एक लाख मौतें हो जाती हैं। ये अंग्रेजों की शासन-सम्बन्धी योग्यता के प्रमाण नहीं हैं। १९४१ की जन-संख्या के अनुसार भारत में कुल १३^१/_२ प्रतिशत साक्षर हैं, जब कि ‘साक्षरता’ से तात्पर्य केवल मामूली पढ़ लेने की योग्यता मात्र है। यदि

भी सुशासन का प्रमाण नहीं है। औद्योगिक निश्चलता, अन्यायपूर्ण जमींदारी व्यवस्था और चिरकाल तक विदेशी सत्ता के अधिकार में रहने के कारण नैतिक ह्रास (हम भारत में विजेता के रूप में हैं, ऐसा मुझे लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था) से भारतीय अत्यधिक क्षुब्ध और अंग्रेजों के प्रति अत्यन्त असहिष्णु (कभी-कभी तो अकारण ही) होगये हैं। भारतीय स्थिति का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है।

भारत में आज अनेक सफल, प्रतिभाशाली और अनुभवी शासक, औद्योगिक महाजन, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, न्यायविशारद, शिक्षक एवं राजनीतिज्ञ मौजूद हैं। सर स्टैफर्ड क्रिप्स का कहना है कि वाइसरॉय का विश्वास है कि भारतीय अपने राज्य की बागडोर सभाने योग्य हैं। “न्याय और अधिकार के सिद्धान्त पर”, सर स्टैफर्ड ने पार्लियामेंट में अक्टूबर १९३९ को दिये भाषण में कहा—“इस बात से कोई भी इकार न करेगा कि आज भारत स्वराज्य का पूर्ण रूप से अधिकारी है। जब वाइसरॉय स्वयं इस बात को मानते तो, है भारतीयों की स्वराज्य की मांग को स्वीकार न करने का हमारे पास भिन्न इसके क्या उत्तर है कि हम न्याय और औचित्य के अपने सिद्धान्तों को भूल कर और भारत पर अपना एकाधिकार कायम रखकर, उसका शोषण जारी रखना चाहते हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय अपने देश का शासन सभाल सकते हैं। अंग्रेजों की भारत में आवश्यकता नहीं है। अंग्रेज इसे खूब जानते हैं।

यदि इंग्लैंड को आर्थिक कारणों से भारत की आवश्यकता है, तो ब्रिटिश प्रजाजन खुशी से स्वतंत्र भारत के साथ व्यापार करे, वहाँ पूजी लगाये, वहाँ ‘रोजगार-धंधा’ करे। इंग्लैंड के लाभदायक आर्थिक संवर्धन अर्जन्टीना आदि कई देशों से है, जो कि साम्राज्य के अन्तर्गत नहीं हैं। परंतु भारत पर राजनीतिक अधिकार होने के कारण अंग्रेजों को कोई असाधारण लाभ है, जो कि भारत तथा कई और देशों के हितों के प्रतिकूल है। व्यापारिक अथवा आर्थिक दृष्टि से भारत का द्वार दूसरे देशों के लिए बंद है और इस द्वार की कुजी अंग्रेजों के पास है। कभी-कभी उन्हें प्रतिद्वन्द्वियों के लिए भी किवाड़ खोलने पड़ते हैं। किन्तु इंग्लैंड भारत का द्वार अपने लाभ के लिए ही खोलता है।

सत्तार में प्रथम श्रेणी का राष्ट्र बना रहने के लिए क्या इंग्लैंड के लिए भारत पर सत्ता जमाये रखना आवश्यक है? यदि आवश्यक है भी, तो इंग्लैंड को महान् राष्ट्र बनाये रखने के लिए भारत क्यों गुलाम रहे?

“प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए इंग्लैंड ने भारत में से लाखों

जवानों की भरती की, जो बड़ी बहादुरी से लड़े और विजय-प्राप्ति में विशेष सहायक हुए।" इस तर्क के अनुसार तो भारत को सदा ही गुनाम रहना चाहिए और इसी तरह जापान भी चीन पर अपना कब्जा न्यायपूर्ण बता सकता था। साथ ही टोकियो के लिए अपार जन-शक्ति का भंडार खुल जाता, वशतकि समस्त चीन जापान द्वारा अधिकृत हो जाता।

“यदि भारत इंग्लैंड के अधीन न होता, तो चीन की तरह वह भी जापान का उपनिवेश बन जाता।” परन्तु इस तर्क का उत्तर यह है कि चान और भारत को सबल और सपन्न राष्ट्र बनाया जाय, ताकि ये दोनों देश आक्रमण को रोक सकें। यदि इंग्लैंड के अधीन रहकर ही भारत की रक्षा हो सकती है, तो यह आवश्यक है कि फ्रांस, स्पेन, इटली, बल्गेरिया आदि सब छोटे राष्ट्र दो या तीन बड़ी शक्तियों के अधीन कर दिये जाय। शायद कुछ काल बाद किसी को यह प्रतीत होने लगे कि इंग्लैंड भी अपनी रक्षा आप नहीं कर सकता और वह प्रस्ताव रख दे कि इंग्लैंड अमेरिका अथवा रूस के अधीन हो जाय। तो फिर किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की क्या आवश्यकता है, जो निर्वल राष्ट्रों की रक्षा कर विश्व-शांति की व्यवस्था करे।

साम्राज्यवाद और अन्तर्राष्ट्रवाद दोनों परस्पर विरोधी हैं। साम्राज्य का आधार पशु-बल है, अतः यह अनैतिक है। इंग्लैंड को भारत पर राज्य करने का क्या अधिकार है? साम्राज्यवाद प्रतिद्वन्द्वी क्षेत्रों को जन्म देता है।

प्रारम्भ में और किन्हीं क्षेत्रों में साम्राज्यशाही से वर्जित जातियों को कुछ लाभ पहुँचता है; परन्तु अंत में इससे आर्थिक, आध्यात्मिक तथा राजनीतिक क्षति ही पहुँचती है। पाश्चात्य आधिपत्य से जो लाभ हुए हैं, उन्हीं के कारण एशियावासी उस आधिपत्य का अब अन्त करने पर उतारू हैं। और उधर साम्राज्यवादी राष्ट्र स्वार्थवश अभी एशिया से ही चिपटे हुए हैं। उपनिवेशों के हित उनके लिए गौण हैं।

“भारत के हाथ से निकल जाने पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का ह्रास हो जायगा” १२ दिसम्बर १९३० को चर्चिल ने यह घोषणा की थी। मार्च १९३१ को चर्चिल ने ब्रिटिश दृष्टिकोण को समक्ष रखते हुए फिर कहा— “भारत का हमारे हाथ से निकल जाना हमारे लिए घातक मिट्ट होगा। यह उस प्रक्रिया का सूत्रपात करेगा जो हमें छोटी ताकत बनाकर रहेगी।”

“छोटी ताकत” यह १९ वीं सदी की विचारधारा की उपज है। सरकार और मानवी-श्रम का ध्येय व्यक्तिगत सुख की वृद्धि करना है। आमतौर पर, शांति-काल में डेनमार्क, स्वीडन अथवा स्विट्ज़रलैंड का निवासी औसतन

एक सामान्य अंग्रेज से कहीं अधिक सुखी है। यदि वह एक छोटे राष्ट्र का सदस्य है, तो इससे क्या ? मैं अब तक यह नहीं समझ सका हूँ कि धरती के किसी और टुकड़े पर अधिकार प्राप्त करने का व्यक्ति के कल्याण से क्या सम्बन्ध है। अन्य देशों पर ऐसे अधिकार गत वर्षों में युद्ध के ही कारण सिद्ध हुए हैं।

यह कहा जा सकता है कि बड़े राष्ट्र के नागरिकों को युद्ध-काल में अधिक लाभ रहता है। यह भी सन्दिग्ध है। यह बात तो परिस्थितियों पर आश्रित है। फ्रांस, इटली, जापान, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन ने, जिन्हें १९३९ में बड़े राष्ट्रों में गिना जाता था—गत युद्ध में छोटे राष्ट्रों से अधिक ही क्षति उठाई है और यदि अब कहीं तीसरा विश्व-युद्ध हुआ, जिसमें समुद्र पार अणुबम फेंके गये तथा कहीं न रुकने वाले पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले विशाल वायु-यानों द्वारा बम-वर्षा की गई, तो क्या छोटे राष्ट्र, क्या बड़े—सब देशों के नर-नारी और बच्चे नारकीय वेदना भोगेंगे।

भारतीय स्वतंत्रता ब्रिटेन को २० वीं सदी के अनुरूप आर्थिक एवं राजनीतिक परिवर्तन करने पर बाध्य करेगी। अमेरिकी उद्योग २० वीं सदी के अनुरूप है, इसलिए उसे उपनिवेशों की आवश्यकता नहीं। ससार को उन वस्तुओं की आवश्यकता है, जिनका निर्यात अमेरिका आसानी से कर सकता है। आज अमेरिका में बने कल-कारखानों में काम आने वाले मशीनों, पुरजों तथा सामूहिक उत्पादन की ससार को बड़ी आवश्यकता है, इंग्लैंड में औद्योगिक विकास पहले आरम्भ हुआ था। यद्यपि इंग्लैंड उतने ही अच्छे और आधुनिक यंत्र बना सकता है तथापि इंग्लैंड की औद्योगिक प्रणाली में बहुत-सी दक्षियानूसी बातें हैं। जिस देश ने बड़ पैमाने पर औद्योगीकरण करने का निश्चय कर लिया हो, उसे इंग्लैंड से थोड़ी बहुत मशीनरी तो प्राप्त हो सकती है, परन्तु उसे अधिक साजो-सामान तो अमेरिका से ही प्राप्त करना लाभदायक रहेगा। अतः भारत के औद्योगीकरण में इंग्लैंड की अपेक्षा अमेरिका अधिक दिलचस्पी लेगा। यदि इंग्लैंड का उद्योग बिल्कुल आधुनिक होता तो बात और थी किन्तु जब तक ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था में १९ वीं सदी का पुट है, तब तक वह भारत के लिए बीसवीं सदी के अनुकूल निर्माण-कार्य में सहायक नहीं हो सकता।

औद्योगिक दृष्टि से बीसवीं सदी में पदार्पण किए हुए ब्रिटेन को चाहिये था कि वह कपड़ा तथा अन्य उपभोग का वस्तुओं की अपेक्षा कल-पुरजों बनाने पर जोर देता और तब वह भारत की स्वतन्त्रता और औद्योगीकरण का पक्ष लेता। इस प्रकार जब स्वतंत्र भारत में उद्योगोन्नति होगी, तब भारत में व्यापार करने

के लिए इंग्लैंड को अमेरिका आदि अग्रगामी देशों से मुकाबला करना होगा। यदि ४० करोड़ भारतीय वर्तमान पशु-जीवन से तनिक ऊँचे उठ जाय और इनके जीवन-यापन का स्तर ऊँचा हो जाय, तो उपभोग की वस्तुओं की माग इतनी बढ़ जायगी कि उसे पूरा करने के लिए इंग्लैंड, अमेरिका और कई अन्य देश भी उत्पादन-कार्य में सलग्न हो जायेंगे। किसानों ने एक बार विनोदार्थ कहा था—“यदि प्रत्येक चीनी पतलून पहनने लग जाय, तो अमेरिका में ५ वर्ष के लिए प्रत्येक आदमी को काम मिल जायगा। यदि प्रत्येक चीनी, भारतीय, यूनानी एवं पेरूवासी के लिए पर्याप्त भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, तथा रोगोपचार की व्यवस्था की जाय, तो ससार की सामूहिक आय में वृद्धि हो जायगी तथा बेरोजगारी घटगी और विश्व में सुख तथा शांति का वृद्धि होगी।

भारत और चीन, यूनान और पेरू अथवा ट्यूनेशिया अपने जीवन के स्तर को ऊँचा करने के लिए साधन कहाँ से जुटाएँगे? वे इस अंश में अमेरिका का अनुकरण करेंगे। जल, भूमि, वायु और अपनी जन-शक्ति से वे सहायता लेंगे।

भारत की स्वतंत्रता नये इंग्लैंड के प्रादुर्भाव पर निर्भर है। यह राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं पर लागू होती है। मृत भूतकाल में इंग्लैंड को अपने विस्तृत साम्राज्य के कारण अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में महत्त्व मिलता रहा है। पर अब समय बदल रहा है, क्योंकि वायुयान-युग में नौसेना का महत्त्व घट गया है तथा रूस और अमेरिका का औद्योगिक बल एवं राजनीतिक महत्त्व बढ़ रहा है।

शक्ति-मूलक राजनीति अनैतिक है और प्रायः युद्धगामी है। जो राष्ट्र देश जीतने की आशा रखता हो, वह भले ही उक्त राजनीति का आश्रय ले परंतु इंग्लैंड क्यों यह खेल खेले, जब उसे विजय प्राप्त ही नहीं हो सकती? इंग्लैंड और रूस में तनातनी हो जाने पर, आशंक स्वतंत्रता-प्राप्त क्रुद्ध-भारत निश्चय ही रूस का पक्ष लेगा। पूर्णतया स्वतंत्र भारत इंग्लैंड का पक्ष लेगा। क्योंकि इंग्लैंड के हार जाने पर रूसी आक्रमण का उसे भय रहेगा।

भारत पर आधिपत्य रखने की अपेक्षा अणु-शक्ति को उत्पन्न करने की क्षमता इंग्लैंड को अधिक सामरिक शक्ति प्रदान करेगी। अणु-युग में साम्राज्यवाद निरी मूर्खता है।

इंग्लैंड के सामने दो विकल्प हैं, या तो वह लड़खड़ाते हुए साम्राज्य के ढाँचे को पकड़े बैठा रहे, या फिर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राष्ट्रों की मैत्री प्राप्त

करे। दूसरे शब्दों में उसे साम्राज्य-गत अरक्षा अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा सुरक्षा—इनमें से एक का चुनाव करना होगा।

साम्राज्य विस्तार की होड़ में इंग्लैंड फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल से इस लिए जीत गया कि वह इन देशों से अधिक संगठित और प्रगतिशील था। साम्राज्यों के परस्पर भावी-सघर्ष में इंग्लैंड हार जायगा, क्योंकि अब वह निर्बल है।

ब्रिटिश-साम्राज्य तो अब केवल अमेरिका सहायता से ही कायम रह सकता है। पर क्या यह वाछनीय है? एक लड़खड़ाते और पतनोन्मुख साम्राज्य को बचाने का अर्थ इंग्लैंड और भारत में जीर्ण-शीर्ण-राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था के कायम रखने में सहायक होना होगा। इससे इंग्लैंड, भारत और अमेरिका तीनों देशों की प्रगति में अड़चन पड़ेगी।

इंग्लैंड के लिए इस समय सबसे अच्छा रास्ता साम्राज्यवाद को त्याग कर अन्तर्राष्ट्रीयता को अपनाना है। यह काम अकेले इंग्लैंड के बस का नहीं है। इस ओर स्वयं प्रयास करके वह ससार को अन्तर्राष्ट्रीयता की ओर ले जाने में सहायक मात्र हो सकता है।

ब्रिटेन के आर्थिक एवं राजनीतिक संगठन को २० वीं सदी के अनुरूप पुनर्गठित करने का दायित्व इतिहास ने मजदूर सरकार को सौंपा है। अब यह प्रत्यक्ष है कि अंग्रेजों ने दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने चर्चिल की सहायता से हिटलर को परास्त किया और फिर नये युग में पदार्पण करने के लिए उन्होंने चर्चिल को भी हरा दिया। इस शुभ-कार्य में इंग्लैंड की जो कुछ सहायता अमेरिका करेगा, उसकी व्याज-समेत अदायगी विश्व-शान्ति और समृद्धि के रूप में उसे वापस मिलेगी।

भारत की स्वतन्त्रता का पक्ष मैंने इंग्लैंड के प्रति कोई दुर्भावना से प्रेरित हाकर नहीं लिया है। शायद ब्रिटेन सबसे अधिक सभ्य, सजग एवं लोक-तंत्री राष्ट्र है। इंग्लैंड भारत एवं विश्व के कल्याण से प्रेरित हुआ। मैं भारत की स्वतन्त्रता के लिए आग्रह करता हूँ।

यद्यपि मैं भारतीय स्वतन्त्रता का समर्थक हूँ तथापि मैं राष्ट्रीयता अथवा राष्ट्रीय पृथक्ता का विशेष पक्षपाती नहीं हूँ। अत्यधिक स्वदेश में ही केन्द्रित होने के कारण मैंने भारतीयों की आलाचना की है। सकीर्ण राष्ट्रीयता एक राग है। राष्ट्रीयता प्रायः पृथक्ता रखती है। अतः यह विश्व-व्यापी अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में रोड़े अटकती है।

कोई पूछ सकता है— यदि बाद में उसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में शामिल

ही होना है तो फिर भारत को एक राष्ट्र का रूप क्यों दें ? इसका उत्तर यह है कि अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग में लोकतन्त्री राष्ट्रों की अपेक्षा साम्राज्यवाद अधिक रोड़े अटकता है ।

लोकतन्त्र विभिन्नता में पनपता है । अपनी विभिन्नता के कारण भारत संभवतः राष्ट्रीयता के खतरो से बच सके । अधिनायकवाद मतभेद सहन नहीं कर सकता और उन्हें समाप्त कर देता है । इसे एकरूपता चाहिए । लोक-तन्त्र-वाद उस इन्द्र-धनुष के समान है जिसके सात रंग मिलकर प्रकाश पैदा करते हैं । स्वतन्त्र भारत शायद सच्चा लोकतन्त्री राष्ट्र बन सके, जो साम्राज्य-वादी एवं शक्ति-प्रिय राष्ट्रों के साथ एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण में सहयोग देगा जो मनुष्य-मात्र का शान्ति एवं सद्बुद्धि की ओर अग्रसर करेगा ।

संसार के सब महाद्वीपों के करोड़ों मनुष्य भारतीय स्वतन्त्रता को उस आगामी नई दुनिया का प्रतीक मानते हैं, जिसका निर्माण इस व्यवस्था संसार की नींव पर होगा । आधुनिक वर्चस्वता ने १९३९ से १९४५ तक वर्तमान सभ्यता के भवन को तोड़ा-फोड़ा ही है ।

: १२ :

फिलस्तीन में दस शांत दिन

मुझे यह खयाल भी न था कि मैं कभी बिलोचिस्तान में अपने को पाऊंगा। यह प्रदेश मेरे लिए केवल एक नाम और नक्शे पर बिन्दुमात्र था। खानगी के दिन हमारा हवाई जहाज वहां उतरा। उसके बाद मैं अरब और ईराक पहुंचा। मुझे न्यूयार्क जाने की जल्दी थी और आशा थी कि मार्ग में कहीं अधिक ठहरना न पड़ेगा।

प्रोग्राम के मुताबिक हमें मध्याह्न का भोजन कालिया में करना था, जो कि 'डेड सी' (समुद्र) के किनारे है और पृथ्वी पर सबसे नीचा स्थान है। यहां पर रासायनिक कारखाने भी हैं। इसलिए बसरा से मैंने यहूशलम के अग्रेजी भाषा के दैनिक "पैलिस्टाइन पोस्ट" के एडिटर मि० गरशन एग्रोस्की को तार देकर कालिया में खाने पर आमंत्रित किया। हम दोनों का लडकपन एक साथ फिलेडल्फिया में व्यतीत हुआ था। मैंने उन्हें सुझाया कि वे अन्य मित्रों को भी अपने साथ खाने पर बुला सकने हैं।

गरशन यहूदियों के मिशन पर दक्षिण अफ्रीका आया था। उसकी स्त्रा एथिल भी कालिया पहुंच गई। उसके साथ उसकी अभिन्न मित्र ईडाव्नूम डेविडोविज थी, जो कि मेरी जन्म-भूमि फिलेडल्फिया की रहने वाली थी।

उन्होंने मेरा भावी कार्य क्रम पूछा। हरे पाना में डोलने हुए समुद्री वायुयान की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा—अफमोस हैं, मुझे जल्दी अमेरिका लौटना है। आशा है पांच दिन में मैं न्यूयार्क पहुंच जाऊंगा। एथिल आग्रह करने लगी कि मैं यहूशलम ज़रूर जाऊ। मैंने कहा, यह असंभव है। यदि जहाज पर मैंने प्राथमिकता से लाभ न उठाया तो शायद मुझे कई सप्ताह तक यात्रा सम्बन्धी प्राथमिकता न मिल सके। आध घंटे तक जहाज जायगा और मैं चल दूंगा।

मेरे मित्र तर्क और विनय से काम लेने लगे। पर मैं टस्-से-मस न हुआ। फिर न जाने कैसे एकदम मेरे विचारों ने पलटा खाया। और मैंने

अपने मन में कहा—“क्यों नहीं ठहर ही जाऊँ ?” और एकदम लापरवाही से मैंने अपना सामान जहाज से उतार लिया और मोटर में बैठ कर यरूशलम चल दिया। यरूशलम ससार के नगरों में बड़ा अद्भुत और सुंदर शहर है। मां में हमने अग्रेजों को सुरंग बनाते और बोगियों से मोर्चे बनाते देखा। नाजी जनरल रोमेल काहिरा से केवल ३ घंटे के सफर की दूरी पर था और स्वेज नहर पर उसके आक्रमण का खतरा था। भय था कि यदि उसने मोर्चे तोड़ डाले तो थोड़े ही दिनों में वह फिलस्तीन भी पहुच जायगा।

१९१९, २० और १९३४ की भांति मैं फिर माउंट स्कोपस पर चढ़ा, जेतून के कुज में घूमा, बायोडोलोरोसा नदी की सैर की, भयङ्कर ‘वेलिंग-वाल’ के सामने खड़ा रहा और उमर की मसजिद की सराहना की। इनमें से कई दृश्यों का उल्लेख बाइबिल में है। यरूशलम का प्रत्येक पुराना टूटा-फूटा पत्थर प्राचीन इतिहास का सूचक है। अब पुराने यरूशलम के साथ नया यरूशलम—साफ, स्वच्छ और आरामदेह—भी बन गया है। नया यरूशलम उन यहूदियों ने बनाया है जो गत ५० वर्षों से फिलस्तीन में यहूदी राष्ट्रीय-वाम बनाने के हेतु आये हैं। यहूदियों का अपने निर्माण-कार्य पर गर्व है। उत्तर में गैलिली और इस्त्रैलन की घाटी में दौरा करने का मुझे निमंत्रण मिला। यहाँ पर इन यहूदियों ने बड़े-बड़े फार्म और कृषक-वस्तिया बसाई हैं।

पोलैंड के ‘घेरो’ में से, रूस, रumanिया और अन्य देशों से आये हुए तथा फिलस्तीन में जन्मे-पले यहूदियों ने अपने पुरुषार्थ द्वारा बजर, पथरीले तथा कीचड़ में भरे मलेरिया प्रदेश को हरे-भरे फलों से लदे बागों में परिवर्तित कर दिया है। इन बागों में हजारों आदमा समान-आधार पर और सामूहिक ढंग से खेती करते हैं।

इन प्रदेशों को मैंने नहीं देखा, क्योंकि एक तो मुझे इनकी सफलता के बारे में पहले से ही बहुत-कुछ पता था; दूसरे मैं भारत की यात्रा से थका हुआ और वहाँ के संस्मरणों से लदा हुआ था। इसके अनावा, मुझे फिलस्तीन की मुख्य राजनीतिक समस्या अरब-यहूदा-परस्पर-संबन्ध में अधिक दिलचस्पी थी।

अरब उन दिनों अग्रेजों पर हुई रोमेल की विजय से प्रसन्न थे। अरबी गाव, झड़े, और ध्वजारें फहराकर रोमेल के स्वागत की तैयारी में थे। नाजी और अरब मिलकर यहूदियों के विरुद्ध प्रबल मोर्चा बना सकते थे। जब मैंने अपने कई अमेरिकन यहूदियों को, जिनके पास पासपोर्ट और जाने के लिए साधन भी थे, यह राय दी कि युद्ध की समाप्ति तक वे अमेरिका जाकर रहे, तो उन्होंने मुझे पागल समझा। वे भागने को सैयार न थे। यदि रोमेल

फिलस्तीन में आ घुसा और उससे उत्तेजना पाकर अरबों ने यहूदियों की मार-काट आरम्भ कर दी, तो वे फिलस्तीन के ५ लाख यहूदियों के साथ कन्वे-से-कन्वा भिड़ाकर अरबों का मुकाबला करेंगे। यहूदियों के अनेक अर्ध-सैनिक और सशस्त्र सगठन अरबों से जूझने को तैयार थे। अनेक यहूदी नवयुवक ब्रिटिश फौज में भरती होगये थे और मिस्र, लीबिया तथा इटली के मोर्चों पर भी लड़ चुके थे। अरब अग्रेजों के विरोधी थे और उन्होंने घुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध अग्रेजों को सहायता देने से इकार कर दिया था।

यहूदी दृढ-संकल्प थे और किसी प्रकार भी उन्हें घबराया हुआ अथवा हतोत्साह नहीं कहा जा सकता था। टेलावीव में, जो प्रशान्त-समुद्र के तट पर एक नया यहूदी शहर बसा हुआ है, मैं डेविडोविज परिवार में ठहरा। हैरी एस० डेविडोविज, जो पहले फिलेडल्फिया और क्लीव लैंड में कानूनी विशेषज्ञ था, अब नकली दात बनाने का व्यवसाय करता था। उसने शेक्स-पीयर का हिब्रू में अनुवाद किया था। उन्नीस वर्ष की उनकी बड़ी पुत्री सूजान डेविडोविज हुलाह झील के किनारे एक नये कृषि-फार्म पर काम करती थी। यह क्षेत्र मलेरिया का घर था। उसका परिवार धनी था और यह कार्य वह केवल यहूदी जाति की रचनात्मक निष्काम-सेवा के भाव से कर रही थी। उस अस्वास्थ्यकर और पिछड़े प्रदेश के पुनरुद्धार कार्य में लगे हुए हजारों युवक और युवतियों का स्वास्थ्य सदा के लिए गिर चुका था।

सूजान वहा के अपने साथियों को छोड़कर शायद ही कभी अपने घर का सुख भोगने के लिए टेलावीव जाती हो।

एक दिन दोपहर के भोजन के पश्चात् हैरी डेविडोविज और मैंने अरब-यहूदी समस्या पर विचार किया। सूजान पौन घंटे तक हमारे पास बैठी हमारी बातें सुनती रही। अचानक, बिना किसी प्रसंग के वह बोल उठी 'हमारे फार्म में एक नई आलू छाटने की मशीन आई है।'

उसका यह असगत वाक्य मेरे लिए अरब-यहूदी समस्या पर यहूदियों के रुख का द्योतक था। अरबों की हिंसा और ध्वंसात्मक प्रणाली का उत्तर यहूदी रचनात्मक कार्यों द्वारा दे रहे थे। वे ईंट-पर-ईंट रखने, शहर और वस्तिया आवाद करने तथा नई आलू छाटने का मशीनें मगाने में व्यस्त थे।

यहूदी आन्दोलन का उद्देश्य एक यहूदी राष्ट्र अथवा राष्ट्रीय समूह कायम करना है। इसलिए फिलस्तीन में यहूदी जाति को बहुसंख्यक बनाना उनका लक्ष्य है। इस समय फिलस्तीन में लगभग ५ लाख यहूदी और १० लाख अरब आवाद हैं। विशेषज्ञों का मत है कि यदि इस देश में सिचाई, विजली

और उद्योग का विस्तार हो जाय तो यहाँ कई लाख मनुष्य सुख और समृद्धि का जीवन व्यतीत कर सकते हैं।

एक यहूदी गीत के वाक्य हैं—“ऐ यरूशलम ! यदि मैं तुझे भूल जाऊ तो मेरा दाहिना हाथ चतुराई भूल जाय, मेरी जीभ मेरे तालू में चिपक जाय।” सदियों से तितर-बितर किये जाने पर भी यहूदियों के दिलों में फिलस्तीन के लिए एक हूक उठती है। वर्म-परायण यहूदी तो फिलस्तीन के साथ विशेष धार्मिक सम्बन्ध मानते हैं। कई अधार्मिक यहूदियों के लिए यरूशलम स्वयं एक धार्मिक-आस्था का विषय है। यहूदी आंदोलन के पीछे उनके पूर्वजों की स्मृति और प्यार छिपा है। यरूशलम उस जाति का मूल स्थान है जो सदियों में दूसरे देशों में रहकर विदेशी वातावरण और रहन-सहन को अपनाते के लिए बाध्य रही है, किंतु अपनी राष्ट्रीय सरकार के नीचे रहकर अपना स्वाभाविक जीवन व्यतीत करने में असमर्थ रही है। ऐतिहासिक घटना-क्रम यहूदियों को फिलस्तीन के साथ प्रेम-सूत्र में बांधे हुए है। लाखों यहूदी, जिन्होंने फिलस्तीन कभी देखा नहीं है और न कभी वहाँ की आशा हाँ रखते हैं, यहूदी राष्ट्रीय पुनरुत्थान का सुनहला स्वप्न देख रहे हैं।

यह एक आवेग है इसलिए इसकी व्याख्या करना अनावश्यक है। फिले-डेल्फिया में रहते हुए अपनी युवावस्था में मैं भी इस आवेग से ओत-प्रोत था। मैं ब्रिटिश सेना की यहूदी बटालियन में भरती होकर १९१८ में फिलस्तीन गया और वहाँ १९२० तक रहा था। अब वह आवेग मेरे अन्दर नहीं है। यह आवेग फिलस्तीन में ही मेरे अन्दर ठंडा पड़ गया था। यूरोप में १९२१ से १९३८ तक रहने के कारण यहूदी-आंदोलन में मेरी रुचि न रही। मेरा ध्यान अन्य महान् सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं में लग गया। अपनी दुःखप्रद स्थिति में यहूदियों की अत्यधिक एकाग्रता का कारण मैं खूब समझता हूँ। इस प्रश्न की अवहेलना नहीं की जा सकती; परन्तु निर्रे राष्ट्रीय आंदोलन से मैं अधिक प्रभावित नहीं होता हूँ जब तक कि उसका उद्देश्य भारतीय अथवा इटालियन राष्ट्रीय आंदोलन की तरह साम्राज्यवाद का अन्त करना न हो। यहूदी आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जिसका ब्रिटिश साम्राज्यवाद से गठबन्धन है।

राष्ट्रीय प्रश्नों का हल अन्ततः विश्व-समस्याओं के हल पर ही निर्भर है ऐसी मुझे आशा है। मैं जानता हूँ, यहूदी यही उत्तर देंगे कि हम अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मैं उनसे सहमत हूँ और इसलिए मैं किसी भी प्रकार से, उनके आंदोलन में दखल नहीं देता। उनके आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के

लिए सैद्धान्तिक सहमति और साहस का आवश्यकता है और इन दोनों का मुझमें अभाव है ।

मे १९३४ मे एक मास फिलस्तीन मे रहा था और १९४२ मे १० दिन शाति से मैने वहा गुजारे थे, परन्तु फिलस्तीन के लिए मेरा पुराना प्रेम फिर न उमडा । इसके अलावा, मेरा विश्वास है कि कोई भी जाति निश्चय ही यहू-दियो जैसी अल्प-जाति अपनी समस्याओं का हल अन्य जातियाँ एव राष्ट्रों से अलग रहकर नहीं ढूँढ सकती । कितने ही ऐसे राष्ट्र हैं जिनका पतन अपनी सामाओं के अन्दर हो गया ?

फिलस्तीन सुन्दर देश है और बहुत से यहूदी यहा लाभकारी और सतुष्ट जीवन व्यतात कर रहे हैं । उनके आत्म-सतोष का कारण है रचनात्मक कार्य करने और देश मे अपनी जडे मजबूत करने की अनुभूति । वे निर्माणकार्य मे जुटे हुए हैं । घर, फार्म, कारखाने, सडके, अस्पताल, स्कूल आदि बनाने मे सलग्न हैं । इसके अतिरिक्त वे राष्ट्रीय ज्ञान निर्माण करने मे लगे हुए हैं । उनका त्याग भी महान् है । फिलस्तीन यहूदियों के खून से सना और उनके आदर्शवाद मे रगा हुआ है । उनमे भी स्वार्थी, शोषक और गैर-जिम्मेदार वर्ग है, परन्तु वह अल्पमख्या मे है । प्रायः उच्च लक्ष्य मनुष्यों को महान् बना देता है । फिलस्तीन मे किसी भी देखन वाले को यह आभास होगा कि वहा की सामूहिक सफलता व्यक्तिगत सफलताओं के योग की अपेक्षा अधिक महत्त्व रखती है । यह आधिब्य सम्भवतः वहा चीज है जिसे हम सभ्यता कहते हैं— सभ्यता का अर्थ सामूहिक आधार पर रहना है ।

अर्जन्टाइना, यूरेन, क्रीमिया आदि देशो मे यहूदियों को बसाने के सगठित प्रयास न्यूनाधिक मात्रा मे सफल हुए हैं । फिलस्तीन मे यहूदियों का बसाना आर्थिक हानि से इसलिए अधिक सफल हुआ कि ससार भर के यहूदियों ने करोडो रुपये फिलस्तीन के नव-निर्माण मे लगा दिये । यहूदियों ने फिलस्तीन पर धन और प्रेम दोनों न्यूँछावर किये । फिलस्तीन की आर्थिक नींव उस सम्पत्ति द्वारा खडी की गई है जो ससार भर के यहूदियों के दान द्वारा प्राप्त हुई है । अतः फिलस्तीन के यहूदियों की आर्थिक व्यवस्था के महत्त्व की अभी परीक्षा होनी है ।

यहूदा आदर्श के प्रति श्रद्धा के अतिरिक्त, यूरोप के यहूदी, यदि उन्हें मौका मिले तो, शायद वे अमेरिका मे जाकर बसना चाहे । सम्भव है कुछ फिलस्तीन के यहूदी भी अमेरिका मे जाकर बसना चाहे । अमेरिका ने, जिसके निवासी, थोडे से आदिम निवासियों (Red Indians) के निवा,

प्रवासियों और शरणार्थियों की सतान है, मृष्टी-भर नये आगन्तुकों को छोड़कर अपने द्वार सबके लिए बंद कर रखे हैं। यद्यपि अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनेडा, रूस, अर्जेंटीना और ब्राजिल में आजादी कम है, फिर भी ये देश यहूदी-प्रवासियों को शरण देना नहीं चाहते। हा, उनके लिए रह गया छोटा-सा फिलस्तीन।

हिटलर द्वारा अधिकृत यूरोप में यहूदियों की जो दुर्दशा हुई उसका पूरा विवरण देने के लिए शब्द अपर्याप्त है। द्वितीय युद्ध के दौरान में यूरोप के ७० लाख यहूदी मौत के घाट उतार दिये गए। ये बमों से या लडाई में नहीं मरे, यद्यपि इनके कारण भी बहुत से हताहत हुए, इनकी तो जान-बूझकर निर्मम हत्या की गई। "चलो! इनको गैस चेंबर में फेंक दो। इनको बिजली की भट्टी में स्वाहा कर दो। इनको आधा-भूखा रखकर काम में खूब जुटाओ और जब ये अशक्त हो जाय तो उन्हें भी भट्टी में स्वाहा कर दो।" इस तरह ५० लाख यहूदी बहुत सफाई से मार डाले गये। नाज़ियो ने नाज़ी-जर्मन-विरोधियों को मारने में मध्यकालीन बर्बरता से काम लिया। यहूदियों को उन्होंने आधुनिक रासायनिक अस्त्रों से मारा।

तो क्या आश्चर्य, यदि यहूदी लोग हिटलर द्वारा विभाजित-यूरोप में रहने को राजी नहीं हैं। हिटलर से पहले भी यहूदियों को यूरोप के कई देशों में अपमान जनक भेद-भाव सहन करने पड़ने थे। एक भाग सोवियट रूस ही ऐसा देश था जहाँ सरकार की सामाजिक नीति के कारण जानिय अत्याचार अथवा यहूदियों का विरोध सरकारी अथवा गैर-सरकारी तौर पर बिलकुल बंद था। यूरोप तथा ससार के देशों में यहूदियों को सामाजिक समानता प्राप्त नहीं थी और उन्हें कई असुविधाएँ सहनी पड़ती थीं।

अमेरिका में यहूदियों को पूर्ण कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है। उनमें असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति भी हैं, सफल व्यापारी भी हैं, अपराधी भी हैं और असफल व्यक्ति भी हैं। कानूनन अमेरिका में यहूदी और गैर यहूदी का कोई भेद नहीं है। परन्तु व्यक्तिगत रूप में अमेरिकावासी और अमेरिका के अन्य वर्ग यह भेद-भाव करते अवश्य हैं। अमेरिका में लाखों ऐसे ईसाई हैं जो यहूदियों के साथ व्यक्तिगत सबंध रखने में सकोच करते हैं या सबंध रखते हैं। वहाँ ऐसे होटल भी हैं जहाँ केवल ईसाइयों ही के लिए हैं। यह ईसाई धर्म के अनुकूल नहीं है।

यहूदियों से सबंध के सकोच का आधार रंग, रूप, सभ्यता, शिक्षा, योग्यता, शिष्टता, धन, मिलनसारी आदि नहीं हैं। जीवन के प्रत्येक स्तर पर,

ईसाई यहूदियों को अपने समान पाएंगे। तो क्या केवल धर्म-भेद ने ही यह खाई पैदा कर दी है? यहूदियों के प्रति घृणा इतनी बढ़ गई है कि ईसाई बाइबिल में दिये हुए यहूदी नामों को भी पसंद नहीं करते। आज कितने ईसाई हैं जिनके काम अब्राहम १लकन की तरह है? अथवा आइजक न्यूटन की तरह या जेकब ऐंस्टर की तरह अथवा बैजमिन फ्रैंकलिन की तरह है। ईसाई लोग अब बाइबिल के नामों को यहूदी समझकर घृणा करते हैं और यहूदी भी स्वयं ऐंग्लो-सेवसन और फ्रांसीसी नाम पसन्द करने लगे हैं।

हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा अभिशाप आधुनिक मनुष्य का अपने वास्तविक स्वरूप से दूर हटने की प्रवृत्ति है। यह यहूदी-विरोधी भावना बहुत-से यहूदियों की इस प्रवृत्ति की पुष्टि करती है, और वे विकृत रूप से आत्म-चेतन हो जाते हैं।

वे ऐसा मानने लग गए हैं कि किसी यहूदी को न तो सर्वोच्च न्यायालय का जज और न उग्रवादी अथवा समाचार-पत्र प्रकाशक बनना चाहिए। ईसाई भद्र लोगों द्वारा लगाये हुए प्रतिबन्धों के परिणाम स्वरूप यहूदी स्वयं अपने आपको क्लृप्त समझने लगे हैं।

बहुत से यहूदी इस बात की आवश्यकता अनुभव करने लग गये हैं कि ससार में एक ऐसा भी स्थान होना चाहिए जहाँ सच्चे मानों में यहूदी-यहूदी बन कर रह सकें। कई यहूदियों का मत है कि यहूदीपन का 'एक मात्र आधार धर्म है। यह धारणा हास्यास्पद है। अमेरिका के बहुत से यहूदी धर्म-निष्ठ नहीं हैं। परन्तु फिर भी उनमें यहूदीपन की भावना मौजूद है। वे सामान्य रवत तथा संस्कृति के सम्बन्ध को अनुभव करते हैं अथवा यहूदी-विरोध उनके यहूदीपन को और भी कट्टर कर देता है।

वे यहूदी भी, जो यहूदी-राष्ट्र के पृथक् निर्माण का विरोध करते हैं, और यहूदी-आंदोलन को केवल धार्मिक मानते हैं, अस्त यूरोपीय यहूदियों के लिए किसी-न किसी सुवन्द-आश्रय की आवश्यकता पर जोर देते हैं और अमेरिका के बाद फिलस्तीन को ही वे उपयुक्त देश मानते हैं। कुछ साल पहले, जो अपने-आपको यहूदी-विरोधी मानते थे, आज वे भी इस आंदोलन के पक्ष में हैं। वह इस आंदोलन के राजनीतिक पहलू का विरोध भले ही करते हों। बेधर अस्त यहूदियों द्वारा किसी नये देश में बसने की आवश्यकता को अस्वीकार नहीं कर सकते।

यदि हमारी दुनिया भली होती तो यहूदियों को फिलस्तीन जाने की कोई आवश्यकता न होती और शायद बहुत थोड़े ही बढ़ा जाना पसन्द करते।

वे जर्मनी, पोलैंड, रूमानिया आदि किसी भी देश में रह सकते थे। इस समय तो यहूदियों की प्रबल इच्छा उस यूरोप को छोड़ देने की है जहाँ हिटलर की वर्चस्वता का ताड़व होना रहा है। यूद्धोत्तर-काल में भी राष्ट्रीय भावना प्रबल रहेगी; इसलिए यहूदी-विरोधी भावना भी घटने की आशा नहीं है। सशस्त्र हिटलर को परास्त करना आसान था, परन्तु उस विषय का शमन करना कठिन है जिससे उसने एक महाद्वीप को ही नहीं बल्कि उससे भी अधिक व्यापक क्षेत्र को विभक्त कर दिया था। यहूदी-आंदोलन की यहूदियों और गैर-यहूदियों द्वारा स्वीकृति युद्धोत्तर सप्ताह और विश्व-शांति की कड़ो आलोचना है।

यदि कोई तनिक सोचे कि विज्ञान, कला-कौशल, शिक्षा एवं राजनीति को यहूदियों की कितनी बड़ी देन है तो उसे आश्चर्य होगा कि क्यों बहुत से देश यहूदियों को आश्रय देने को तैयार नहीं हैं? क्या यह इसलिए है कि जो देश स्वयं प्रतिद्वन्द्विता पर पनपे हैं, अब वे स्वयं प्रतिस्पर्द्धा से घबरा उठे हैं। शायद हिटलर की पराजय का यही कारण था कि उनमें जर्मन-यहूदी वैज्ञानिकों को मरवा डाला, यातनायें दीं अथवा निर्वासित कर दिया। ब्रिटेन और अमेरिका की सरकारों ने उन वैज्ञानिकों को शरण देकर उनसे युद्ध-कार्य में सहायता लेकर बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। फिर भी शांति-काल में इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि होजाने से बेरोजगारी फैलने की आशंका बढ़ जाती है। जब अमेरिकी-वासियों को अपने देश के भविष्य में विश्वास था तो उनके देश के दरवाजे सबके लिए खुले थे। अमेरिकी आज भी पूर्णतया उन्नत नहीं है। और असीम सम्भावनाओं का प्रदेश है।

अरब भी यहूदी-प्रवास का विरोध कर रहे हैं। जब मैं यरूशलेम में ठहरा हुआ था, मैं नित्य प्रति डा० जूडा एल० मैगनस के साथ सैर के लिए जाता और बातचीत किया करता था। डा० मैगनस यहूदी-विश्व-विद्यालय के वाइस चांसलर थे। पहले वह न्यूयार्क में कानूनी विशेषज्ञ थे और २० वर्ष से अब फिलस्तीन में निवास करते हैं। इनके द्वारा मैं प्रमुख अरब राजनीतिज्ञों से मिला।

डा० मैगनस एक तरह के यहूदी गांधी हैं। गहरी धार्मिक भावना और सामाजिक दृष्टिकोण रखने वाले उन्नत डाक्टर के निरंतर चिन्तनीय विषय—भगवान् और जन साधारण हैं। उनमें हठीलेपन और परिपक्वता का विचित्र-संमिश्रण है। उन्हें इस बात का विश्वास रहता है कि वे ठीक हैं। अधिकतर यहूदी सोचते हैं कि वे गलत हैं। वास्तव में वहाँ के कुछ यहूदी उन्हें नापसन्द भी करने हैं। क्योंकि वे अवश्य ही अरबों के साथ सुलह-सफाई कर लेंगे और उन्हें सीमित यहूदी प्रवास के लिए राजी करने की चेष्टा करेंगे।

फिलस्तीन भर में मैगनस ही सभवतः एक मात्र ऐसा प्रमुख यहूदी है जिसका अरबों से मेल-जोल है। यहूदी और अरबों की दुनिया अलग-अलग है। उनमें परस्पर घृणा और द्वेष बहुत है। द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने से पहले १९३६ से १९३९ तक फिलस्तीन गृह-युद्ध में फसा था। अरब यहूदियों पर छिपकर छापा मारते थे और दोनों पक्षों के आदमी हताहत होते थे। मैगनस सहयोग और रियायतों द्वारा इस स्थिति में सुधार करना चाहते हैं किंतु उनके विरोधी कहते हैं कि देश में पहले वे यहूदी बहुमत पैदा कर लें और उसके बाद ही अरबों से बात-चीत चलायेंगे। उनका विचार था कि रियायत देना कमजोरी समझा जायगा और परिणाम कुछ न निकलेगा।

डा० मैगनस के साथ मैं श्रीना अब्दुल हादी से मिला। यरूशलम के मुफती हज-अमीन-अलहुसैनी के अग्रेजों की तिगरानी से हिटलर को मिलने के लिए भाग जाने पर वह फिलस्तीन के सबसे प्रमुख अरब होगये। मैं डा० खालिदी तथा अन्य अरब नेताओं से भी मिला। बाद में इन सबसे मैं पुनः एक अरब सज्जन के घर पर भी मिला।

इन अरब राजनीतिज्ञों ने स्वीकार किया कि फिलस्तीन के गावों में प्रवासी अरब रोमेल के स्वागत की प्रतीक्षा में थे। उनका कहना था कि यहूदियों ने फिलस्तीन को किसी प्रकार भी समृद्ध नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने फिलस्तीन में केवल अपने आपको ही अमीर बनाया। और वे सब प्रवास के लिए यहूदियों के यरूशलम में आने का, उनके हाथ ज़मीन बेचने अथवा फिलस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना का घोर विरोध कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यहूदी अपना बहुमन बढ़ाकर वहाँ अपना राज्य कायम करने का विचार छोड़ दें, तो वे यहूदियों के फिलस्तीन में प्रवास के लिए आने पर इतनी आपत्ति नहीं करेंगे।

अरब अपने विरोध में दृढ़ और अडिग हैं। फिलस्तीन के अरबों का यहूदी व्यवसाय से लाभ ही हुआ है। आप किमी अरब ग्राम में जायें तो आपको पता लगेगा कि अपनी भूमि यहूदियों को अत्यधिक मूल्य पर बेचने के कारण अरब कितने समृद्धिशीली होगए हैं। यहूदियों के ससर्ग से अरबों का जीवन, स्वास्थ्य और शिक्षा का मान भी काफी ऊँचा हो गया है। यदि अरबों को कोई उत्तेजित न करे तो, (यद्यपि वे इस समय यहूदियों के आने पर खीझते हैं) सभव है कुछ काल बाद वे अपना विरोध स्वयं ही समाप्त कर दें। विरोध करने की प्रेरणा अरबों को फिलस्तीन के बाहर से मिलती है।

मध्य-पूर्व के अरबों में आज राष्ट्रीयता की लहर जोर पकड़ रही है।

राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद की उपज है। यहूदी आंदोलन का ब्रिटिश साम्राज्य के साथ गठ-बन्धन होने के कारण अरबों में राष्ट्रीय भावना और भी जोर पकड़ गई है। ईराक, सीरिया, लेबनान, ट्रान्सजोर्डनिया, साउदा अरब, मिन्न फिलस्तीन और उत्तरी अफ्रीका के अरब नेता अरब एकता का सुखद स्वप्न देख रहे हैं। उनकी हार्दिक इच्छा एक ऐसे सघ की स्थापना की है जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में शक्ति और प्रभाव रखता हो। यद्यपि अरब एक ही जाति के हैं, और अधिकतर उनमें इस्लाम धर्मानुयायी हैं (थोड़े से अरब ईसाई भी हैं) फिर भी आज तक उनमें एकता का अभाव रहा है। उनमें एकता न होने के कई कारण हैं। अतः वह परस्पर मेल-मिलाप के आधार की खोज में हैं। यह आधार अब उन्हें यहूदी विरोधी आन्दोलन में मिल गया है। हिटलर ने यहूदियों को आग में भोँककर जर्मन राष्ट्रीयता की ज्वाला प्रज्वलित की। अब यहूदियों की महत्वाकांक्षाओं के खडहर पर अरब अपने साम्राज्य का निर्माण करना चाहते हैं।

मध्य-पूर्व स्थित अंग्रेज अधिकारी पहले नीति निर्धारित कर लेते हैं और बाद में ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेते हैं। कई बार इन दोनों की नीतियों में परस्पर विरोध रहता है। उदाहरण के लिए फिलस्तीन में अंग्रेजी सरकार का एक विभाग अरबों की शस्त्रों से सहायता करता रहा और दूसरा विभाग यहूदियों के पक्ष में था।

साधारण तौर पर यह कहा जा सकता है कि अंग्रेजी सरकार अरबों की ही पीठ ठोकती रही है और उन्हीं की सहायता से अरब लीग की स्थापना हुई है। शायद उसने ऐसा यह समझ कर किया हो कि अरबों का राष्ट्रीयता की ओर झुकाव अब रोके न सकेगा। या फिर यह विचार रहा हो कि यदि अरबों की सहायता अंग्रेजों ने न की तो रूस, अमेरिका अथवा फ्रांस उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा अरबों ने हिंसात्मक कार्यवाही की घमकी भी दी थी और अंग्रेज शक्ति हो उठे थे। इंग्लैंड भारत के ९ करोड़ २० लाख मुसलमानों की भावनाओं का भी खयाल रखता है।

अंग्रेजों का महान् भूतन पूर्ण नहीं तो कम से-कम अनिश्चिन् रह देखकर तथा बाहर के अरबों से उन्नेजना पाकर पवित्र भूमि फिलस्तीन के अरबों की यहूदी-विरोधी आग भभक उठा। गृह-युद्ध का ज्वालामुखी फिलस्तीन की भूमि के नीचे सदा धधकता रहता है, और कई बार फूटकर ऊपर भी आ जाता है। यहूदी भी वीर लड़ाके हैं, और जुडया और जेरुसलीम में उन्होंने अरबों को कई बार लड़ाई में हराया भी है। टैनहार्ड और क-फार गिलिडी के प्रदेश में मैंने स्वयं यहूदी वस्तियों की रक्षा में भाग लिया है। रात को पहरा देते हुए हम जोर्डन नदी

के बहने की आवाज सुन सकते थे, जो ज्ञान प्रदेश से तीव्र गति के साथ बहती हुई आती है। तब से ज्यो-ज्यो यहूदियों का आतंक और शस्त्रास्त्र बढ़े हैं, त्यो-त्यो फिलस्तीन में भगड़े भी बढ़े हैं।

जिन यहूदियों से मैंने १९४२ में बातचीत की, फिलस्तीन के सम्बन्ध में उनकी राय थी कि अपने वचनों को कार्यान्वित करने के सिवा ब्रिटेन के पास कोई और चारा ही नहीं है। तब तक अपने मिशन में अडिग रहने का उनका विचार था। यदि इन दोनों जातियों को ट्रेड यूनियनों, व्यापारी सघों द्वारा और निकट संपर्क में लाने का प्रयत्न किया जाता या ये दोनों जातियाँ मिल कर साम्राज्यवाद ही का मुकाबला करती तो १९२० में भी उन दोनों के बीच सुलह-सफाई-कराई जा सकती थी। परन्तु यह नहीं होना था। जैसे मजदूर दल के यहूदी सदस्य और यहूदी एजेन्सी के अधिकारी मोशेशरतक ने यरूशलम में मुझे १९३४ में बताया था—“हम पहले राष्ट्रवादी, और पीछे समाजवादी हैं।” यहूदी उतने ही उग्र राष्ट्रवादी थे जितने कि अरब। उनके बीच की खाई को पाटना मँगनस के लिए भी संभव न था। और अब तो इस कार्य में अत्यधिक विलंब हो गया है।

फिलस्तीन में मेरे शांतिके १० दिन बड़ी अशांति से गुजरे। संभव है कि फिलस्तीन यहूदी-बहुमत का राष्ट्र बन जाने पर भी यहूदियों की समस्या का हल न निकाले। फिलस्तीन का कल्याण तो इसके यहूदी, ईसाई, और मुस्लिम सभी संप्रदायों का सम्मिलित राष्ट्र बन जाने में है। यह लक्ष्य दुःसाध्य है। इस आदर्श की प्राप्ति तो बड़े और संपन्न राष्ट्रों को भी नहीं हुई है।

खैर! फिलस्तीन १९४२ में हमले से तो बच गया था। जब १९४२ में मैं फिलस्तीन से काहिरा पहुँचा, तो वहाँ का वातावरण बड़ा उत्तेजित था। जनरल रोमेल का आतंक वहाँ अभी छाया हुआ था। समस्त मित्रराष्ट्र चौकन्ने थे और विजय अनिश्चित थी। अंग्रेज, पोलैंड निवासियों की सहायता से, शत्रु से जूझ रहे थे। परन्तु उन्हें और सहायता की आवश्यकता थी। “सन् १९४२ की गरमियों में जब मार्शल रोमेल ने लीबिया के मोर्चे पर ब्रिटेन की टैंक सेना को भारी क्षति पहुँचाई थी, तो जनरल मारशल (अमेरिकन चीफ-आव-स्टाफ) ने फोरन मध्यम श्रेणी के सब टैंक शिक्षा-सवधी आवश्यकताओं की भी परवाह न कर के मित्र के मोर्चे पर भिजवा दिये। इस आपत्ति का सामना करने का यही एकमात्र साधन था।

“हमारा एक सशस्त्र डिवीजन शिक्षा के लिए उत्तरी आयरलैंड जाने को बदरगाह में पड़ा हुआ था। इस डिवीजन के हथियार भी ले लिये

गए और उन्हें दूसरे टेक न मिलने तक वही रोक लिया गया। संकट पूर्ण घड़ी टल गई। अब हमें पता लगा कि मार्शल का अनुमान कितना ठीक था। हिटलर का इरादा मिस्र पर अधिकार करके निकट पूर्व में घुसने का था। यदि वह सफल हो जाता तो युद्ध का चित्र ही बदल जाता।”

ये शब्द युद्ध-मंत्री स्टिमसन ने अपने विदाई भाषण में १९ सितंबर १९४५ को कहे थे।

आल आलमीन और स्वेज नहर के बीच का छोटा-सा रेतीला प्रदेश रोमेल न जीत सका। फलस्वरूप फिलिस्तीन शत्रु-अधिकृत प्रदेश बनने से बच गया और हिटलर की फौजे आगे बढ़कर हिंदुस्तान में जापानी फौजों से मिल करने से रोक दी गई। यदि ऐसा हो जाता तो धुरी राष्ट्र या तो युद्ध में अर्नि शिचतता उत्पन्न करने में सफल होते या युद्ध को ७ साल तक घसीटकर ले जाते।

जिस दिन रोमेल ब्रिटिश टैंकों को नष्ट-भ्रष्ट कर रहा था, उस दिन मैं काहिरा में ही था। उस शाम प्रेस सम्मेलन में हर एक के चेहरे पर व्याकुलता झलक रही थी “कैसी भयंकर स्थिति है,” एक अंग्रेज पत्रकार ने कहा; परंतु मार्शल ने रोमेल को पीट ही दिया।

वायुयान द्वारा मैं न्यूयार्क में ५ अगस्त को पहुंचा। मिस्र का युद्ध अभी जोरो पर था। भारत में अशांति की लहर दौड़ रही थी। गांधी जी और नेहरू राष्ट्र-व्यापार सवितय अवज्ञा आंदोलन का डका बजाने ही वाले थे। उन्होंने ८ अगस्त को आंदोलन शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें तुरंत कैद कर लिया। फलतः ५ अगस्त के दिन प्रत्येक की आख भारत पर लगी थी। ला-गाडिया हवाई अड्डे पर बहुत-से सवाददाता मुझे मिले और भारतीय संकट के विषय में मुझ से पूछने लगे। दूसरे रोज प्रातः काल ‘न्यूयार्क टाइम्स’ ने तीन कालमी लवा मेरा फोटो छपा जिसका शीर्षक था—“गांधीजी के साथ भोज।” उतना ही स्थान उमने आलोचना को दिया। तत्पश्चात् मेरा फोटो और मेरे वक्तव्य का सारांश अमेरिका के अनेक अखबारों में छपा। यदि मैं फिलिस्तीन में न रुक जाता और भारत की स्थिति बिगड़ने से पहले १० दिन आगे ही घर पहुंच जाता तो अमेरिका में मेरी वापिसी की सूचना केवल इस प्रकार छाती—“हवाई जहाज से जो सज्जन उतरे, उनमें लई फिशर भी था।”

भाग—२

युद्ध द्वारा शांति की ओर

: १३ :

रूजवेल्ट, गांधी और चांग काई-शेक

भारत की स्थिति से चिंतित होकर जनरल स्मो चांग काई-शेक ने २५ जुलाई १९४२ को प्रेजिडेंट रूजवेल्ट के पाम १५०० शब्दों का एक गुप्त तार भेजा। यह तार रूजवेल्ट को २६ जुलाई को मिला और उन्होंने उसका उत्तर लगभग ३५० शब्दों में ८ अगस्त को दिया। ११ अगस्त को चांग ने एक छोटा-सा सदेश फिर भेजा, जिसका उत्तर रूजवेल्ट ने अगले ही दिन दिया।

ये तार, जिनसे पता चलता है कि दो शासन-संस्थाओं के अध्यक्ष किस प्रकार एक दूसरे से पत्र-व्यवहार करते हैं, न तो कभी छपे न अमेरिकन—चीना सरकारों के कुछ उच्च-अधिकारियों को छोड़कर किसी को इनके सम्बन्ध में काई जानकारी ही हुई।

चांग ने लिखा था—“भारत का स्थिति बड़ी ही गम्भीर और सकटपूर्ण हो गई है। सच पूछिये तो यही वह सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व है जिसके आधार पर समुक्त राष्ट्रों के युद्ध—विशेषतः पूरव के युद्ध—का परिणाम आका जा सकता है।” चांग चाहते थे कि रूजवेल्ट इस सम्बन्ध में कुछ करे, इसीलिए उन्होंने लिखा—“इस युद्ध में बल के विरुद्ध न्याय का जो संघर्ष हो रहा है उसका नेतृत्व आपके देश के हाथों में है और आप द्वारा प्रकट किये गये मत पर ब्रिटेन में सदा ही गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है। इसके अलावा, भारतीय जनता इस बात की बहुत दिनों से आशा करती रही है कि आप भी इस युद्ध में सक्रिय भाग लेंगे और न्याय तथा समानाधिकार का पक्ष ग्रहण करेंगे।”

चांग को भारत में उत्पात की आशंका थी। वह जानते थे कि गांधी और नेहरू सारे भारतवर्ष में सत्याग्रह-आन्दोलन आरम्भ करने वाले हैं। यही कारण था कि उन्होंने प्रेजिडेंट रूजवेल्ट को लिखा कि “गांधी और नेहरू को अपना योजना पर पुनः विचार करने के लिए प्रेरित करने का एक मात्र उपाय

यह है कि संयुक्त राष्ट्र—विशेषतः अमेरिका, जिसे वे श्लाघा की दृष्टि से देखते हैं—आगे बढ़कर बीच बचाव करे और उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए उन्हें सान्त्वना दे। इससे भारतीयों में अपनी आनुपातिक महत्ता के प्रति पुनः जागरूकता उत्पन्न हो जायगी और उन्हें इस बात का दृढ़तर विश्वास हो जायगा कि इस ससार से न्याय अभी मिटा नहीं है। स्थिति के एक बार सुधार जाने पर उसे स्थायी बनाना असम्भव नहीं होगा और भारतवासी, जो कि अमेरिका के प्रति उसके उपकारों के लिए कृतज्ञ होंगे, स्वेच्छा से युद्ध में भाग लेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संयुक्त राष्ट्र-समूह के अन्य-देशों के प्रति भी निराश भारतीय जनता की वही भावना हागी जो ब्रिटेन के प्रति है और ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना ससार के लिए सबसे बड़ी दुखान्तक दुर्घटना होगी, जिसमें अकेले ब्रिटेन का ही नहीं, बल्कि औरों का भी नुकसान होगा।”

“जहाँ तक ब्रिटेन का सवाल है,” चांग ने लिखा, “वह एक महान् देश है और पिछले कुछ वर्षों से वह अपने उपनिवेशों में प्रगतिशील नीति का अनुकरण करता रहा है। इधर, दूसरी ओर, भारत एक निर्बल देश है और आज-कल जो अभूतपूर्व विस्तृत युद्ध हो रहा है उसके कारण स्वभावतः किसी समस्या को साधारण युक्ति से हल करना सम्भव नहीं है।”

चांग कार्डि-शेक ने प्रेजिडेंट रूजवेल्ट को चेतावनी दी कि संकट का सामना करने की ब्रिटिश चेष्टाएँ दुवारी तलवार के समान होंगी। “यदि इन युक्तियों द्वारा सत्याग्रह-आंदोलन का दमन करने में सफलता भी मिली तब भी”, चांग ने लिखा, “संयुक्त राष्ट्रों को इतनी आत्मिक क्षति पहुँचेगी जितनी किसी युद्ध को हारने से भी नहीं पहुँच सकती। ऐसी स्थिति ब्रिटिश-हितों के लिए विशेष रूप से घातक सिद्ध होगी।”

“इसलिए, भारत को पूर्ण स्वाधीनता दे देना ही ब्रिटेन के लिए सबसे अधिक बुद्धिमानी और प्रगतिशीलता का रास्ता होगा,” चांग कार्डि-शेक ने सलाह देते हुए लिखा। उन्होंने यह भी लिखा—“संयुक्त राष्ट्रों के युद्ध-उद्देश्यों और समान हितों का दृष्टि में रखते हुए मेरा चुप बैठे रहना असम्भव है।” चीन की पुरानी कहावत है—“अच्छी दवा, चाहे वह कड़वी ही क्यों न हो, रोग को दूर कर देती है”—सहृदयतापूर्ण सलाह, चाहे वह कटु ही क्यों न हो, हमारा पथ-प्रदर्शन करती है। मुझे हार्दिक विश्वास है कि मेरी इस पक्षपात-रहित सलाह को, चाहे वह कितनी ही कड़वी क्यों न हो, ब्रिटेन उदारतापूर्वक और दृढ़ता के साथ स्वीकार करेगा।”

अन्त में चांग कार्डि-शेक ने लिखा—“मैं अपने इस विचार को बरा-

बर दुहराना पसंद करूँगा। मेरी एकमात्र भावना यही है कि भारतीय स्थिति के सम्बन्ध में शुद्ध नीति का अनुकरण करने में और उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होने में संयुक्त राष्ट्रों को विलम्ब नहीं करना चाहिए ताकि उसके कारण हमारी युद्ध स्थिति को कोई गम्भीर आघात न पहुँचे। मुझे पूर्ण आशा है कि इस सम्बन्ध में आप अपने स्वस्थ विचारों से अवगत करेंगे।”

रुजवेल्ट ने अपने उत्तर में लिखा—“भारतीय स्थिति के सबंध में आपने जो संदेश भेजा है उस पर मैं अधिक-से-अधिक गम्भीरता के साथ विचार करता रहा हूँ। मैं आपके इस विचार से पूर्णतः सहमत हूँ कि समान विजय के लिए भारतीय स्थिति को स्थिर बनाना चाहिए और सम्मिलित प्रयत्न में भारत का भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए।”

“किन्तु” प्रेजिडेंट रुजवेल्ट ने अपनी कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए लिखा—“मेरा खयाल है कि आप स्वयं इस बात को समझते होंगे कि इस सुझाव में, कि मैं ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता दोनों ही को ‘एक न्यायोचित और सतोषजनक हल’ निकालने की सलाह दूँ, कितनी कठिनाइयाँ हैं। ब्रिटिश सरकार का विश्वास है कि क्रिप्स-योजना में भारत के लिए जिन सुधारों की व्यवस्था की गई थी, वे उचित थी। साथ-ही-साथ, उनका यह भी खयाल है कि इस अवसर पर किसी दूसरे देश के सुझाव उपस्थित करने से भारत की वर्तमान एकमात्र शासन-सत्ता के अधिकार को आघात पहुँचेगा और उनके फलस्वरूप वही सकट और उपस्थित होगा जिसके दूर होने की आपको और मुझे दोनों को अभी आशा है।”

अन्त में प्रेजिडेंट रुजवेल्ट ने लिखा—“वर्तमान स्थिति में मैं अपने और आपके लिए यही अच्छा समझता हूँ कि हम अभी उस काम को करें जिसे करने के लिए आपने मन्त्रों से कहा है।”

इस तार के वाशिंगटन से रवाना होने के अगले ही दिन गांधी, नेहरू, कांग्रेस के अध्यक्ष मोलाना अबुलकलाम आजाद और उनके हजारों अनुयायी भारत में गिरफ्तार किये जाकर जेलों में डाल दिये गए। बाद में भारत के अग्रज प्रधान न्यायाधीश सर मारिस ग्वायर ने इस सम्बन्ध में अपना निर्णय देते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रीय कार्यकर्त्तियों को गैर-कानूनी ढंग से एक तथ्यहीन कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। इस पर वाइसराय ने अगस्त १९४२ की गिरफ्तारियों को कानूनी ठहराने के लिए २८ सितम्बर १९४३ को एक नया अधिनियम घोषित किया।

गिरफ्तारियों के कारण सारे भारतवर्ष में क्रोध की एक लहर-सा दीड़

गई और सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़ी तीव्र गति से बढ़ा। साथ-ही-साथ इस आंदोलन ने फौरन ही हिमात्मक रूप भी ग्रहण कर लिया।

गिरफ्तारियों के दो दिन बाद चांग कार्डि-शेफ ने फिर प्रेजिडेंट रूजवेल्ट को तार दिया। उन्होंने लिखा—“मुझे विश्वास है कि मेरी तरह आपको भी भारतीय कांग्रेस की कार्यकारिणा के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण—जिनमें गांधी और नेहरू भी शामिल हैं—चिन्ता उत्पन्न हुई होगी।” यद्यपि रूजवेल्ट भारत के मामले में हस्तक्षेप करने से हिचक रहे थे, फिर भी चांग कार्डि-शेफ ने उन पर फिर एक बार इसी बात के लिए जोर डाला। उन्होंने लिखा—“चाहे कुछ भी हो, संयुक्त राष्ट्रों को अपने कार्यों से सारे सत्तार के सामने यह बान सिद्ध कर देनी चाहिए कि वे सभी देशों को समान रूप से स्वतंत्रता और न्याय दिलाने के अपने सिद्धान्तों का ईमानदारी से पालन करते हैं। मैं आपसे हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि अटलांटिक अधिकार-पत्र के रक्षिता की हैमियत से आप भारत और सारे नमर के सामने आई हुई समस्या को हल करने के लिए कुछ कारगर युक्तिवा करे। आपकी नीति से हम सबका, जो आक्रमणकारियों के पाशविक बल का इतने दिनों से और साहस के साथ सामना करते आये हैं, पथ-प्रदर्शन हागा। आशा है आप शीघ्र ही उत्तर देंगे।”

इसके बाद घटनाएँ बड़े तीव्र वेग से घटी। चुगकिंग से सन्देश चलने के अगले ही दिन रूजवेल्ट ने चांग कार्डि-शेफ को निम्नलिखित उत्तर भेजा—“मुझे शायद यह बात दुहराने की आवश्यकता नहीं कि अपनी दीर्घकालीन नीति के अनुसार और विशेष रूप से अटलांटिक अधिकार-पत्र में लिखी गई बाराओ के फलस्वरूप मेरी सरकार को उन सभी देशों की स्वतंत्रता की चिन्ता है, जो स्वतंत्र होने के अभिलाषी हैं। अमेरिकन सरकार के प्रवक्ता इस नीति का समर्थन बराबर करते आये हैं। फिलीपाइन जैसे देशों में तो इस नीति को व्यावहारिक रूप दे दिया गया है।

“यह स्पष्ट है”, प्रेजिडेंट रूजवेल्ट ने आगे चलकर लिखा—“कि इस समय ब्रिटिश सरकार और श्री गांधी तथा उनके अनुयायियों के बीच जो आंतरिक झगड़ा चल रहा है, उसमें कितात्मक रूप से भाग न लेते हुए भी आपने और मैंने गम्भीर मतभेद प्रगट करने और झगड़े को शान्ति पूर्वक तै कराने की जो चेष्टाएँ की हैं वे अब तक विफल रही हैं।”

“हमें इस मामले में भारत की सहायता चाहिए”, रूजवेल्ट ने लिखा, “और मैं चाहता हूँ कि श्री गांधी इस तात्कालिक आवश्यकता को और भी स्पष्ट रूप से समझे और यह ध्यान में रखे कि भारतवर्ष के लिए जो घटना सबसे

बुरी हो सकती है, वह है घुरी-राष्ट्रो की विजय ।”

“आज मैंने ‘प्रशान्त कौंसिल’ में, जिसमें श्री सुग (चीन के विदेश-मन्त्री डाक्टर टी० वी० सुग) भी है, कहा था कि मुझे और आपको यह बात ब्रिटिश सरकार और श्री गांधी तथा उनके अनुयायियों को स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए कि हमें अभी अंग्रेजों या भारतीय कांग्रेस दल पर दबाव डालने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, किन्तु हम दोनों के मित्र हैं और यदि वे हमारी सहायता चाहेंगे तो हम सहर्ष देंगे ।”

प्रेजिडेंट रुज्वेल्ट ने अपने सदेश के अन्त में लिखा— “ मैं समझता हूँ कि वर्तमान स्थिति में मेरे और आपके लिए भारत को सबसे अच्छी सहायता देने का एक मात्र तरीका यही है कि कोई खुली अपील या घोषणा न करके अभी हम उसे केवल इतना बता दें कि मित्र की हैसियत से हम सदा उसकी सहायता की अपील पर ध्यान देने को तैयार हैं, बशर्ते कि यह अपील दोनों पक्षों की ओर से आये ।”

रुज्वेल्ट इस बात को पहले से ही जानते थे कि ब्रिटिश सरकार अमेरिका या किसी दूसरे देश से सहायता की अपील कभी नहीं करेगी । इसलिए कहा जा सकता है कि रुज्वेल्ट ने भारतीय मामले में हस्तक्षेप करने की चांग काई-शेक की आवश्यक अपील ठुकरा दी । वह जानते थे कि भारतीय समस्या के कारण विजय प्राप्त करने में देर लगेगी । किन्तु उन्होंने एक कूट-नीतिज्ञ की भाँति अपने परम्परागत दिग्वावे का पालन किया और कहा कि मैं हस्तक्षेप उसी समय करूँगा जब दोनों दल मुझसे ऐसा करने के लिए कहेंगे । दूसरे शब्दों में यों कहिये कि उन्होंने हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया ।

प्रेजिडेंट रुज्वेल्ट अपने इस कार्य द्वारा उपनिवेशों पर साम्राज्यवादी देशों के प्राइवेट मालिकाना अधिकार का समर्थन कर रहे थे । एक उपनिवेश में भाग धक्क रही थी और उससे बाहर वालों को भी खतरा था, किन्तु उपनिवेश के स्वामी ने आग बुझानेवाले को अन्दर आने की अनुमति नहीं दी, इसलिए वह चुपचाप वापस लौट गया ।

जब साम्राज्यवादी स्वामी अपने हठ पर अड जाता है और संयुक्त राष्ट्र अपने को इस मामले से अलग रखते हैं तो स्वतंत्रता की आकांक्षा रखने वाले उपनिवेश के सामने हिंसा के प्रयोग के अतिरिक्त और रास्ता ही कौन-सा रह जाता है ? जुलाई-अगस्त १९४२ में रुज्वेल्ट और चांग काई-शेक में जो पत्र-व्यवहार हुआ उसका भारत और एशिया की जनता को कुछ पता नहीं चला । फिर भी वे जानते थे कि कोई भी बड़ा राष्ट्र एशिया के स्वतंत्रता चाहने वाले

देशों की सहायता करने को तैयार नहीं। यह बात उनके हृदय में अच्छी तरह से बैठ गई थी।

जब राजनीति का संचालन वर्तमान की सुविधाओं की दृष्टि में रखकर किया जाता है तो प्रायः भविष्य के लिए आपदाएँ उठ खड़ी होती हैं। सन् १९४२ की समस्याओं के हल न होने से सन् १९४५ और ४६ की समस्याएँ और भी गम्भीर बन गईं।

समनर वेन्स ने, जो सन् १९४२ में विदेश-उपमन्त्री के पद पर होने के कारण प्रेजिडेंट रूजवेल्ट के विचारों से परिचित थे, "न्यूयार्क हेरल्ड ट्रिब्यून" के ८ अगस्त १९४५ के अंक में बताया—“प्रेजिडेंट रूजवेल्ट को इस बात का विश्वास था कि भारत को स्वतंत्रता मिल जाने से दूर पूरब की नियंत्रित उन्नति में बड़ी सहायता मिल सकती है। उन्हें यह भी विश्वास था कि इसी प्रकार की स्वतन्त्र युक्तियों से और भून करते हुए भी चेष्टा करते रहने की पूर्विय कार्य प्रणाली द्वारा अन्त में भारतवासी अपने लिए उस स्वराज्य की स्थापना कर लेंगे जो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और विचार-धारा के अनुकूल होगा। किंतु चर्चिल ने रूजवेल्ट के इस विचार का विरोध किया। यद्यपि प्रेजिडेंट रूजवेल्ट के मंत्री-पूर्ण सुझाव, युद्ध की बड़ी ही सकटपूर्ण स्थिति में उपस्थित किये गये थे, फिर भी वे न केवल निष्फल रहे बल्कि ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री ने उनके प्रति बड़ा क्रोध भी प्रकट किया।”

चर्चिल के विचारों को बदलना आसान काम नहीं था। रूजवेल्ट ने उनके साथ कई बार भारत की समस्याओं पर विचार करना चाहा, किंतु वह इस बात को अधिक आगे नहीं बढ़ा सके। इसके विपरीत उनके ऐसा करने से चर्चिल के हृदय में रोष की भावना उत्पन्न हुई, जिसे चर्चिल ठीक से छिपा भी नहीं सके।

प्रधान मन्त्री नेविल चैम्बरलेन के तुष्टीकरण के समर्थक होने का मुख्य कारण यह था कि उन्हें इस बात का भय था कि युद्ध के फलस्वरूप जो अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन होंगे उनसे धन, विशेषाधिकार और जाति की चिंता करने वाला ब्रिटेन नष्ट होजायगा। किंतु चर्चिल को विश्वास था कि इंग्लैंड युद्ध कर सकता है, उसे जीत भी सकता है और फिर भी वही पुराना-का-पुराना इंग्लैंड बना रह सकता है। चर्चिल के पुराने इंग्लैंड में भारत भी शामिल था और उनसे भारत को छोड़ देने के लिए कहने का मतलब यह था कि उनसे उसी वस्तु को छोड़ देने के लिए कहा जाय जिसके लिए वह युद्ध कर रहे थे।

किंतु अमेरिका के लिए, जो संयुक्त राष्ट्रों में सबसे शक्तिशाली था, चर्चिल

की बात को स्वीकार करना या भारत सम्बन्धी कार्रवाई में विलम्ब करना ऐसा ही था जैसे भारत पर फेंके गए एक देर से फटने वाले बम को अहानिकर बनाए बिना ही उसके विस्फोट को स्थगित कर देना । इसका मतलब यह था कि युद्धोत्तर साम्राज्यवाद की सम्पूर्ण दुःखद समस्या युद्ध के बाद शांति के रचयिताओं के हाथों में चली जाती । इस समस्या को लड़ाई के दिनों में ही हल करना अधिक सुगम होता जब कि अमेरिका और दूसरे देशों का जाग्रत जनमन विजय को शीघ्र प्राप्त करने के प्रयत्न में सहायता देता और साथ-ही-साथ इस भूमण्डल को औपनिवेशिक शासन के रोग से मुक्त कर देता ।

एक अमेरिकन दूतावास के प्रधान अधिकारी ने १२ सितम्बर १९४२ के अपने एक हस्तलिखित पत्र में ठीक इसके अनुकूल मत प्रकट किया । उन्होंने संक्षेप में मुझे लिखा—“मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मेरा मस्तिष्क केवल वर्तमान की ही बातें सोचता है और ये बातें मुख्यतः इस सम्बन्ध में हैं कि हम किस प्रकार अपने शत्रुओं को अधिक-से-अधिक संख्या में मार सकते हैं और किस प्रकार कम-से-कम समय में उनका अधिक-से-अधिक साजो-सामान नष्ट कर सकते हैं । यही कारण है कि मुझे अतीत या भविष्य पर विचार करने का समय नहीं मिलता और न मुझे उन लोगों को रोके रखने का ही धैर्य है जो हमारे लिए आगे चलकर तो बहुमूल्य और रचनात्मक सिद्ध हो सकते हैं, किंतु जिनसे इस समय युद्ध की प्रगति में बाधा पड़ने की आशंका है । मेरा यह सीमित दृष्टि-कोण गांधी और उनके कार्यों पर लागू होता है या नहीं; यह तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना मैं अवश्य जानता हूँ कि हम सारे काम नहीं कर सकते, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम अपना सारा ध्यान उस शक्ति के प्रयोग में लगावें जिससे हमें शीघ्र-से-शीघ्र विजय मिल सकती है । अतीत की बुराइयों को दूर करने और भविष्य को उत्तम बनाने के काम में हम अपनी बुद्धि वाद में लगा सकते हैं । क्या मेरी यह बात आपको बुरी मालूम होती है ?

यह बात मुझे बुरी नहीं लगी, किंतु मैं उससे स्तम्भित अवश्य हुआ, कारण, यह विचार-धारा वाशिंगटन के एक बड़े दल की विचार-धारा थी, जिसके नेता हेंरी हॉपकिंस थे । इस दल का मुख्य सिद्धान्त था—पहले लड़ाई को जीतो और शान्ति की चिन्ता न करो । किन्तु घबराहट की बात तो यह है कि शांति रुकी नहीं । शान्ति का निर्माण न करते हुए भी हमने उसका निर्माण कर दिया । हमारे न करने पर भी दूसरों ने उसका निर्माण कर दिया ।

आजकल की कठिनाइयों का कारण यह है कि युद्ध के समय, जब दल और प्रभाव पराकाष्ठा पर था, हमने स्थिति को अपने कब्जे में नहीं किया ।

३० अगस्त १९४४ को जब मेरी वेन्डेल विलकी से — उनके अस्पताल जाने से ठीक एक सप्ताह पहले — मुलाकात हुई (बाद में उसी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई) तो उन्होंने मुझसे कहा — “सन् १९४३ के वसन्त काल में ही हमने शान्ति को खोना आरम्भ कर दिया था। जब मैं सारेममार का पर्यटन कर सन् १९४२ में लौटा तो प्रेजिडेंट रूजवेल्ट से मिला और उन पर हवाई जहाज से मास्को जाकर स्टालिन से मिलने के लिए जोर डाला। मैंने उनसे कहा कि स्टालिन रूस से बाहर नहीं निकलेंगे किन्तु आप अमेरिका के प्रेजिडेंट होने हुए भी अगर उनसे मिलने जाय तो आपकी मर्यादा को कोई आघात नहीं पहुँचेगा क्योंकि हम बलवान हैं और बलवानों को ऐसे काम करने का गुजायश रहती है। वही समय था जबकि हम रूस के शक्तिशाली और शान्ति के लिए वहमी बनने से पहले स्थिति में परिवर्तन कर लेते। बलवान अक्सर वहमी होते हैं।”

विलकी ने एक क्षण के लिए खिडकी से बाहर देखा। न्यूयार्क का बन्दरगाह, पूरा-पूरा दिखाई दे रहा था। फिर वह मेरी ओर घूमे और पिछली बात का सिलसिला पकड़ते हुए बोले — “मैंने तो गार्डनर काउलिज से जो मेरे साथ पर्यटन पर गये थे और सरकार की ओर से कार्य कर रहे थे, एक स्मरण-पत्र भी बनवाया जिसमें प्रेजिडेंट रूजवेल्ट के स्टालिन से मिलने जाने के मुख्य उद्देश्य लिखे गये। मैंने एक लिखित स्मरण-पत्र उपस्थित करना चाहा था क्योंकि जब १९४१ में मैं इंग्लैण्ड से लौटा था तब भी मैंने प्रेजिडेंट से ऐसा ही प्रस्ताव किया था और कहा था कि आप जाकर चर्चिल से मिलिये और शान्ति की रूपरेखा निश्चित कीजिये। उस समय भी भारत, चीन और अनेक दमरे देशों के लिए कुछ-न-कुछ अवश्य किया जा सकता था। किन्तु अब ।” कहते कहते विलकी एकाएक रुक गये। शान्ति हाथ से निकलती जा रही थी क्योंकि हमने पहले के सुप्रवमरों को ठुकरा दिया था।

किमी भी राष्ट्र के लिए यह उचित नहीं कि वह अपनी शक्ति-वृद्धि के लिए अपने अधिकार की बन्दूक किमी दूसरे देश के कन्धे पर रखकर चलावे। अच्छाई इसी में है कि वह अपनी शक्ति को स्वतंत्रता और भद्र मानवा आचार की नींव पर खड़ी की जाने वाली शान्ति की स्थापना में लगावे।

चूँकि समनर वेल्स के कथनानुसार प्रेजिडेंट रूजवेल्ट को इस बात का विश्वास था कि भारत के स्वतन्त्र हो जाने से दूर पूरब में नियंत्रित उन्नति में सहायता मिलेगी, इसलिए उन्हें चाहिए था कि वह भारतीय समस्या को हल करने पर जोर देते। यदि ब्रिटिश साम्राज्य के अन्त को ही शान्ति-

स्थापना की पहली आधार-शिला मान लिया जाता तो रूसी साम्राज्यवाद की गति को रोकना और साथ ही साथ अमेरिकन साम्राज्यवाद की ओर भी लोगों के झुकाव को रोकना अधिक सरल हो जाता।

चर्चिल से तीन फुट की दूरी पर बैठने से उनका क्रोध बड़ा कष्टदायक मालम होता था। भविष्य का रोप तो और भी अधिक कष्टकर होगा।

चर्चिल ने चांग कार्डि शेक और रुज्वेल्ट दोनों को धता बताई। चांग कार्डि-शेक ने सीधे ब्रिटिश सरकार से भारत के सम्बन्ध में कुछ करने के लिए अपील का। इसके उत्तर में चर्चिल की सरकार ने कहा कि अगर चीन भारत के मामले में दखल देना बन्द नहीं करेगा तो चीन और ब्रिटन की पारस्परिक मैत्री में सकट उत्पन्न हो जायगा। उसका उल्लेख करते हुए फिलीपाइन के अध्यक्ष मैन्युअल क्वीज़ॉन ने सितम्बर १९४२ में वाशिंगटन के शोरहम होटल में मुँहसे कहा—‘अगर ऐमरी (भारत-मंत्री लियोपोल्ड एस० एमरी) ने ऐसी बात मेरे दूत से कही होती और यदि मेरे देश में डेढ़ करोड़ की बजाय चालीस करोड़ जनता होनी तो मैं कह देता कि अच्छी बात है, मेरी और आपकी मित्रता का कोई मूल्य नहीं रहा और फिर मैं जापानियों से बातचीत शुरू कर देता।’

क्वीज़ॉन ने जोर जोर से पढ़कर मुँह से तार सुनाये जो उन्होंने गांधी और नेहरू को ७ अगस्त को भेजे थे और जिन में उन्होंने प्रार्थना की थी कि वे ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे संयुक्त राष्ट्रों की विजय को धक्का पहुँचने की सम्भावना हो। क्वीज़ॉन ने ये तार प्रेजिडेंट रुज्वेल्ट को दिखा दिये थे और उन्होंने इन तारों को पास भी कर दिया था। किंतु ये तार गांधी और नेहरू को नहीं दिये गये। १८ सितम्बर को क्वीज़ॉन को वाशिंगटन-स्थित ब्रिटिश राजदूत लार्ड हैलीफैक्स का पत्र मिला कि भारत के वाइसराय लार्ड लिनलिथगो ने तारों को गांधी और नेहरू के पास भेजने से इन्कार कर दिया है।

सितम्बर १९४२ में व्हाइट हाल में प्रशांत वॉसिल की जब सभा हुई तो क्वीज़ॉन ने भारत की समस्या का प्रश्न उठाया और अमेरिका द्वारा हस्त-क्षेप किये जाने की वाछनीयता के पक्ष में अनेक तर्क भी दिये। प्रेजिडेंट रुज्वेल्ट, जो वीमिल का सभापतित्व कर रहे थे, बोले कि भारत के सम्बन्ध में मेरी जानकारी बहुत ही थोड़ी है, किंतु अघिकांश अमेरिकन भारत के स्वतंत्र किये जाने के पक्ष में हैं और ब्रिटेन तथा भारतवर्ष के लिए यह अपेक्षित है कि वे आपस में बातचीत कर समझौता करें। उस सभा में लार्ड हैलीफैक्स भी उप-

स्थित थे। उन्होंने कहा कि अब से पहले भारतवर्ष में फिर से नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता है और ब्रिटेन इसे स्थापित करेगा। इसके बाद क्वीजॉन ने चीनी राजदूत डाक्टर सुग की ओर घूमते हुए उनकी सम्मति पूछी ! सुग ने उत्तर दिया कि “भारत, अमेरिका और इंग्लैंड की ईमानदारी की कसौटी है।”

भारत में ब्रिटेन की नीति केवल नियंत्रण की पुनः स्थापना करने की है, यह बात लार्ड हैलीफैक्स ने मुझसे २८ अगस्त को कही। वह बोले—“अगर मैं भारत का वाइसराय होता—मुझे खुशी है कि मैं नहीं हूँ—तो मैं प्रबुद्ध कांग्रेस से कदापि समझौते की कोई बातचीत नहीं करता। भारत के लाखों निवासी अज्ञानी और अशिक्षित भेड़ के समान हैं और अगर आपको ऐसे आश्रमियों पर शासन करना है तो आपको यह बात प्रमाणित करनी होगी कि आप शासन कर सकते हैं।”

यही मनोवृत्ति थी जिसके कारण चर्चिल और हैलीफैक्स से भारत के सम्बन्ध में रूजवेल्ट को मुह की खानी पड़ी और रूजवेल्ट ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया।

महात्मा गांधी ने प्रेजिडेंट रूजवेल्ट को देने के लिए मुझे एक निजी पत्र दिया था। वह पत्र आवश्यक था और यदि रूजवेल्ट ने उसके अनुसार कार्य किया होता तो भारत की बहुत-कुछ परेशानियाँ कम हो गई होती। मैं चाहता था कि वह पत्र प्रेजिडेंट रूजवेल्ट के पास जल्दी-से-जल्दी पहुँचे, इसलिए मैंने उसे भारत-स्थित अमेरिकन हवाई बेड़े के जनरल ग्रूबर को दे दिया, जो विशेष अनुमति से हवाई जहाज द्वारा सीधे वाशिंगटन जा रहे थे और जिन्होंने मुझसे कहा कि—वह प्रेजिडेंट रूजवेल्ट से मिलेंगे। वह पत्र, जिसे महात्मा गांधी ने सेवाग्राम में १ जुलाई को लिखा था, इस प्रकार था—

“प्रिय मित्र !

मैं दो बार आपके महान् देश में आता-आता रह गया। सौभाग्यवश मेरे वहाँ कितने ही मित्र हैं, कुछ परिचित कुछ अपरिचित। मेरे देश के कितने ही निवासी अमेरिका में उच्च-शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं। मुझे यह मालूम है कि अनेक भारतवासियों ने वहाँ शरण भी ली है। थोरो और इमर्सन के लेखों से मैंने बहुत लाभ उठाया है। ये सब बातें मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि मेरा आपके देश से कितना सम्बन्ध है। ब्रिटेन के सम्बन्ध में मुझे इससे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं कि यद्यपि मैं ब्रिटिश शासन को सख्त नापसन्द करता हूँ तब भी इंग्लैंड में मेरे अनेक मित्र हैं, जिनसे मैं

अपने देशवासियों के समान ही प्रेम करता हूँ। मैंने अपनी कानूनी शिक्षा वही पाई थी। इसलिए आपके देश और ग्रेट ब्रिटेन के प्रति मेरे हृदय में सद्भावना-ही-सद्भावना है। अतः आपको मेरे इस कथन पर विश्वास करना चाहिए कि मैंने मैत्रीपूर्ण भावनाओं से ही प्रेरित होकर यह प्रस्ताव किया है कि अंग्रेज भारतवासियों की इच्छा की चिन्ता न करते हुए और बिना किसी सकोच के फौरन भारत पर से अपना शासन हटा ले। मैं चाहता हूँ कि इस समय ब्रिटेन के प्रति भारत में जो दुरी भावनाएं फैली हुई हैं, उन्हें मैं, चाहे उनके विरोध में कुछ ही क्यों न कहा जाय, सद्भावना में परिणत कर दूँ और इस तरह लाखों भारतवासियों को वर्तमान युद्ध में अपना यथोचित भाग लेने के लिए प्रेरित करूँ।

जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत विचारों का प्रश्न है, वे बिलकुल स्पष्ट हैं। मैं सभी प्रकार के युद्ध से घृणा करता हूँ। इसलिए अपने देशवासियों को प्रेरित कर सका तो निस्संदेह वे सम्मानपूर्ण शान्ति को प्राप्त करने में बड़ी ही उपयोगी और निर्णायक सहायता देंगे। किन्तु मैं जानता हूँ कि हममें सभी लोगों को अहिंसा में पूर्ण विश्वास नहीं है। विदेशी शासन में रहते हुए हम इस युद्ध में दासता के अतिरिक्त और कोई दूसरी उपयोगी सहायता नहीं कर सकते।

भारतीय कांग्रेस की नीति, जो अधिकतम मेरे ही निर्देश से कार्य करती है, ब्रिटेन को आघात न पहुँचाने की ही रही है, किन्तु साथ-ही-साथ वह अपन लिए, जो कि निस्संदेह भारत की सबसे बड़ी और पुरानी राजनीतिक समस्या है, सम्मान-पूर्वक कार्य करने की स्वतंत्रता चाहती है। क्रिप्स-योजना द्वारा प्रकट की गई ब्रिटिश नीति ने, जिसे भारत के सभी दलों ने अस्वीकार कर दिया, हमारी आँखें खोल दी हैं और उसी के कारण मुझे यह प्रस्ताव करना पड़ा है। मैं ममकता हूँ कि मेरे प्रस्ताव का पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाना ही एक-मात्र ऐसा उपाय है जिससे ब्रिटेन की रक्षा हो सकती है। मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि जब तक भारत और अफ्रीका का ब्रिटेन द्वारा शोषण होता है और स्वयं अमेरिका में हट्टियों की समस्या विराजमान है तब तक मित्रराष्ट्रों का यह कहना कि हम इस सप्ताह को व्यक्तियों और जनतंत्र की स्वतंत्रता के लिए सुरक्षित बनाने जा रहे हैं, खोखला मालूम देता है। मैंने अपने प्रस्ताव में कोई जटिलता न आने देने के विचार से अपने को भारत तक ही सीमित रखा है। यदि भारत स्वतंत्र हो जाता है तो और देश भी, यदि साथ-ही-साथ नहीं तो उसके शीघ्र ही बाद, आजाद हो जायेंगे।

अपने प्रस्ताव को सर्वमान्य बनाने के अनिश्चित से मैंने यह सुझाव रखा है कि अगर मित्रराष्ट्र जल्द ही समझे तो वे अपने खर्च पर भारत में फौज रख

सकते हैं। किंतु यह फौज भारत की आन्तरिक शान्ति की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि जापानी आक्रमण को रोकने और चीन को रक्षा करने के लिए रखी जायगी। जहाँ तक भारतवर्ष का सवाल है, उसे उतना ही स्वतंत्र हो जाना चाहिए जितने ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका है। युद्ध-काल में मित्र राष्ट्रीय-मेनाए स्वतंत्र भारतीय सरकार के साथ समझौता करके भारत में रहेगी। इस स्वतंत्र सरकार का निर्माण भारत की जनता करेगी और उसके निर्माण में कोई भी ब्राह्मरी देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करेगा।

- यह पत्र मे इस प्रस्ताव के प्रति आपकी सक्रिय महानभूति प्राप्त करने के अभिप्राय से लिख रहा हूँ, मुझे आशा है कि प्रस्ताव आपको पसन्द आएगा।

यह पत्र आपके पास श्री लुई फिशर ले जा रहे हैं। यदि पत्र में मैं कोई बात स्पष्ट न कर पाया हूँ तो आप मुझे लिख भेजिये और मैं फौरन उसका स्पष्टीकरण कर दूँगा।

अन्त में मैं यह आशा करता हूँ कि आप इस पत्र का एक बलात् हस्तक्षेप समझकर रुष्ट नहीं होंगे, बल्कि इसे मित्रराष्ट्रों के एक मित्र और हितैषी की प्रार्थना समझेंगे।

सस्नेह आपका,

(हस्ताक्षर) एम के गांधी।"

भारत से लौटते समय मियामी पहुँचने पर मैंने प्रेजिडेंट रूजवेल्ट से तार द्वारा मिलने की अनुमति माँगी। दो दिन बाद मुझे प्रेजिडेंट के सेक्रेटरी एम० एम० मैकिनटायर के हस्ताक्षर से एक तार मिला, जिसमें लिखा था कि काम की अधिकता के कारण हमने सेक्रेटरी हल से आपसे मिलने के लिए कहा है।

वाद में मुझे प्रेजिडेंट रूजवेल्ट का ११ अगस्त १९४५ का पत्र मिला, जिसमें लिखा था—

"प्रिय श्री फिशर,

मैं अपने को स्थिति के बहुत निवट सम्पर्क में रखने का प्रयत्न कर रहा हूँ। कितने ही साधनों द्वारा मुझे प्रतिदिन ताजों से ताजों समाचार मिलते रहते हैं।

आपका सुहृद्

(हस्ताक्षर) फ्रैंक्लिन डी० रूजवेल्ट

मुझे प्रेजिडेंट से न मिल सवने का अफसोस रहा और मैंने सोचा कि अगर मैं पत्र की जनरल गूवर के हाथ न भेजकर अपने साथ लाता तो प्रेजिडेंट

से मिलने की अधिक सम्भावना हो सकती थी ।

१२ अगस्त को प्रेजिडेंट के घनिष्ठ सम्पर्क में रहने वाले एक व्यक्ति ने मुझे निमंत्रित किया और कहा—“फैकलिन ने मुझसे कहा है कि मैं आपसे मिलूँ और आपकी बातें उन्हें जाकर बताऊँ ।”

जब मैं भारत से न्यूयार्क लौटा तो श्रीमती वलेयर वूथ ल्यूस ने टेलीफोन करके मुझे पूछा कि क्या मैंने वेण्डेल विलकी से मुलाकात की है । मैंने कहा कि नहीं और श्रीमती ल्यूस ने विलकी के साथ मेरी मुलाकात तैयार करा दी । उनसे मिलने के लिए मैं उनके दफ्तर १५ ब्राड स्ट्रीट, गया । मेरे प्रवेश करने पर वह उठे नहीं और अपने पैर उन्होंने डेस्क पर रहने दिये । उन्होंने बताया कि वह बहुत थक गये थे । अमेरिका की इंडिया लीग के सभापति श्री जे० जे० सिंह ने बताया कि उनसे भी विलकी इसी ढंग से मिले थे । यह बात मुझे पसन्द आई । मैं उनकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ ।

विलकी ने कहा कि वह मेरे भारत-सम्बन्धी विचारों से सहमत हैं । उनका खयाल था कि भारत के विषय में उनके विचार उस भावी अवसर के लिए लिखकर रख लिये जाने चाहिए जब स्थिति बदल जायगी और हम अपने युद्ध-सम्बन्धी उद्देश्यों का शान्ति-सम्बन्धी व्यावहारिक अस्त्र के रूप में प्रयोग करेंगे । उन्होंने मुझे बताया कि अपने भू-पर्यटन के समय उन्होंने भारत जाना चाहा था और अपनी यह इच्छा प्रेजिडेंट रूजवेल्ट के सामने प्रकट भी की थी किन्तु प्रेजिडेंट का मत था कि उन दिनों किसी अमेरिकन का भारत जाना ठीक नहीं, इसलिए विलकी को चाहिए कि वह अपनी यात्रा पूरब, रूस और चीन तक ही नामित रखे ।

प्रेजिडेंट के एक गैर-सरकारी सलाहकार ने, जिनसे मैं कभी-कभी वार्शिंगटन में मिला करता था, मेरे भारत से लौटने पर एक मित्र द्वारा मेरे पास कहला भेजा कि प्रेजिडेंट मुझसे नहीं मिलना चाहते ।

उस समय अमेरिका की नीति यह थी कि भारत के मामले में ब्रिटेन को परेशान न किया जाय । यह एक सुविधाजनक नीति है । भगडे में न पटना अवसर सुविधाजनक होता है; किन्तु ऐसा करना महंगा पड़ सकता है ।

२७ अगस्त, १९४२ को दिन में १२।। बजे मैं विदेश-मन्त्री वार्डेल हल से मिला । उन्होंने मुझसे भारत के सम्बन्ध में पूछा और फिर टीका करते हुए कहा—“मुश्किल यह है कि जब दूसरा पक्ष टस-से-मस नहीं होता तो हम कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं ? यह तो वही बात हुई कि कोई बाहरी देश हमें मुनरो सिद्धान्त को कार्यान्वित करने की रीति बताने की चेष्टा करे ।”

मैंने कहा कि अगर इंग्लैंड ने एक लैटिन अमेरिकन राष्ट्र की आक्रमण से रक्षा करने का कुछ भार अपने कंधों पर ले रखा है और अगर उस राष्ट्र को सारा यूरोप मित्रराष्ट्रों की ईमानदारी की कसौटी समझता है तो उसके मामले में बोलने का इंग्लैंड को अवश्य अधिकार होगा।

हल ने कहा कि उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलनों और नई सरकारों को नियमित स्वीकार करने के सम्बन्ध में सदा अनुकूल दृष्टिकोण रखा है। उन्होंने कहा—“जब मैं नौजवान था तो मैंने वयूवा की आजादी के लिए लड़ाई लड़ने के वास्ते एक रेजिमेन्ट संगठित की थी। सन् १९३३ में मैंने अनेक वादाओं की अवहेलना करते हुए सोवियत रूस को नियमित मानने के लिए आवाज उठाई थी। लैटिन अमेरिका में हमने अच्छे पड़ोसियों की तरह रहने की नीति ग्रहण कर रखी है। चीन के लिए मैंने समान अधिकार का समर्थन किया है, किन्तु जहां तक भारत का प्रश्न है, यद्यपि प्रेजिडेंट किसी भी अवसर को हाथ से निकलने नहीं दे रहे हैं, फिर भी जब तक ब्रिटेन टस-से-मस न हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि दूसरा आदमी जमीन में अपनी एडी गड़ाकर खड़ा हो जाय और कहे कि मैं तो यही खड़ा रहूंगा चाहे बाकी सब चीज टुकड़े-टुकड़े क्यों न हो जाय।” यह बात कार्डेल हल ने कई तरह से दुहराई।

१२ बजकर ४० मिनट पर श्री हल के सेक्रेटरी ने भीतर आकर कहा “अब आप भोजन कर लीजिये।” शीघ्र ही वह एक ट्रे लाया जिसमें भुना हुआ ठंडा गो-मांस, एक सलाद, एक गिलास टमाटर का रस, एक गिलास दूध, एक गिलास पानी और एक प्याला चाय थी। इन्हे खा-पीकर हल ने कहा—“अच्छा, अब मुझे जाना चाहिए। आज मैं न्यूज़ीलैंड के प्रधान मंत्री फ्रेजर को खाने पर बुला रहा हूँ।”

एक समान शत्रु से लड़ाई लड़ने के लिए कई राष्ट्र सम्मिलित हो जाते हैं। वे अपनी सेनाओं, अपने अस्त्र-शस्त्रों और अपने साजो-समान को समन्वित कर लेते हैं। उनके लड़के रणभूमि में साथ-साथ मौत के शिकार बनते हैं। किन्तु जब शान्ति-स्थापना का समय आता है तो वे अलग अलग रास्ते पर चलने लगते हैं, अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं और किसी व्यक्ति को अपनी सार्वभौम सत्ता में हस्तक्षेप नहीं करने देते। जब तक यह बात बन्द न होगी तब तक शान्ति के लिए किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की चर्चा करना निरर्थक है।

भारत में ब्रिटेन की सार्वभौम सत्ता है, क्योंकि उसमें इसकी शक्ति है।

यदि भारतवासियों में अंग्रेजों को निकाल बाहर करने की शक्ति आ जाय तो सार्व-भौम सत्ता उनकी हो जाय। रूस ने बाल्टिक देशों और पूर्वी पोलैंड को जीत लिया और उन्हें अपनी सार्वभौम सत्ता में मिला लिया, क्योंकि वह उनसे अधिक शक्तिशाली था और बाहरी हस्तक्षेप सहन नहीं करता था। यह अवैध बन है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के दृष्टिकोण से मानव-समाज अब भी मध्य-कालीन परिस्थिति में है, जब कि सड़कों पर लुटेरों का राज रहता था और वे कमजोरों से कर लिया करते थे।

यदि शान्ति का नवशा शक्तिशाली अराजकता द्वारा तैयार किया जाता है और जब उस पर अराजकता फैलाने वाली सरकारों का अधिकार होता है तो शान्ति के लिए स्थापित की गई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था पगु बन जाती है।

उस फाशिज्म के साथ युद्ध करते समय, जिसे सिद्धान्त विहीन या अवैध बल कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्रों ने किस प्रकार एक ऐसी शान्ति की स्थापना की जिसमें सिद्धान्त-विहीन और अवैध शक्ति निहित है ?

अमेरिका किधर जा रहा है ? ससार किधर जा रहा है ? क्या एक और युद्ध—एक परमाणु-युद्ध—का होना अनिवार्य है ?

सुरक्षा की खोज

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की रूप-रेखा इस बात पर निर्भर होती है कि सत्रसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र और उससे दूसरे नम्बर पर आने वाले देश के पारस्परिक सम्बन्ध कैसे हैं ? नैपोलियन के युग में, यूरोप की राजनीति ब्रिटेन और फ़्रान्स की शत्रुता के घूरे के चारो तरफ घूमती रही। बीसवीं शताब्दी के पहले ४० वर्षों में—सन् १९१९ से १९३५ तक के उस काल को छोड़कर जब जर्मनी कमजोर था—यूरोपीय राजनीति की कुजी ब्रिटेन और जर्मनी की शत्रुता थी। आज यूरोप का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र रूस है और इंग्लैंड उससे दूसरे नम्बर पर है। यही कारण है कि आजकल यूरोप के सारे मामले इन दो देशों के पारस्परिक सम्बन्ध पर आश्रित हैं।

कई शताब्दियों तक ससार की अविकाश शक्ति यूरोप और उसके समुद्र पार साम्राज्य के हाथों में थी। इसीलिए उन दिनों यूरोप के विदेशी मामले अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के पर्यायवाची माने जाते थे।

शक्ति का मुख्य केन्द्र अब यूरोप में नहीं रह गया। अमेरिका और रूस में (जिसका एक बहुत बड़ा भाग यूरोप से बाहर है) शक्ति के बड़े-बड़े केन्द्र स्थापित हो गए हैं। इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में उस सम्बन्ध का प्रतिबिम्ब दिखाई दे रहा है जो इस समय ससार के सबसे अधिक शक्तिशाली देश अमेरिका और उससे बाद के नम्बर पर आने वाले देश रूस के बीच है।

यूरोप के प्रागण में रूस को ब्रिटेन की शक्ति का सामना करना है और ससार के क्षेत्र में अमेरिका की शक्ति का। इस स्थिति के कारण अमेरिका और ब्रिटेन में एक-दूसरे के प्रति दितचस्पी पैदा हो गई है किन्तु समय-समय पर महत्वपूर्ण समस्याओं पर मतभेद होना असम्भव नहीं।

तीन बड़े राष्ट्रों ने मिलकर लड़ाई जीती। आपस के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भदों के होते हुए भी उन्होंने एक-दूसरे की रक्षा में सह्यता की। भौगोलिक दृष्टि से रूस और अमेरिका एक-दूसरे से बहुत दूर हैं—

उनमें कोई व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विता नहीं है। फिर संघर्ष और तनातनी क्यों ?

जर्मनी से इंग्लैंड को सकुट था और यदि इंग्लैंड ने हाथ-पैर ढाल दिये होते तो उससे अमेरिका को भी सकुट उत्पन्न हो जाता। बाद में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया। इससे तीनों देश मिल गए।

जर्मन-शक्ति नष्ट हो चुकी है। जापानी शक्ति का भी अंत हो चुका है। इटैलियन शक्ति भी स्वाहा हो चुकी है। ऐसी कौन-सी वस्तु रह गई है जो तीनों राष्ट्रों को एक में बांधे रखे ?

क्या एक नये युद्ध का भय उन्हें एक-दूसरे से मिलाये नहीं रख सकता ? बड़ा युद्ध इन तीनों बड़े राष्ट्रों द्वारा ही लड़ा जा सकता है इसलिए यदि वे मिलकर रहे तो युद्ध असम्भव हो जाय।

इस साधारण बुद्धि की बान का राष्ट्रों की स्वाभाविक कूटनीतिज्ञता से विरोध है। राष्ट्रों का एक-दूसरे से स्पर्धा करना प्राकृतिक होता है। परस्पर सहयोग के समय भी उनमें प्रतिद्वन्द्विता की भावना रहती है। द्वितीय महा-समर में वे लगातार एक-दूसरे से स्पर्धा करते रहे।

शान्ति उसी समय स्थापित हो सकती है जब राष्ट्र अपने आत्म-बल का प्रयोग कर पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता की जन्मजात भावना को बिलकुल मिटा दें और उसकी सहायता से भावी परमाणु युद्ध के नाश से बचें। आत्म हत्या और स्वरक्षा की परस्पर-विरोधी भावनाओं के संघर्ष स्वरूप राष्ट्रों का जो रूप निकलेगा उसी के द्वारा मानव-समाज के भाग्य का निर्णय होगा।

राष्ट्रों की प्रतिद्वन्द्विता किस प्रकार कम हो सकता है ? कुछ लोग इसे तीन या पांच बड़े राष्ट्रों में संधि या मित्रता करके और साथ ही-साथ संयुक्त राष्ट्रीय संघ जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना द्वारा दूर करना चाहेंगे। ऐसी स्थिति में जब राष्ट्र एक-दूसरे से सहमत होना चाहेंगे तब तो होंगे, नहीं तो उन्हें एक दूसरे से मतभेद प्रकट करने और लड़ने की स्वतंत्रता रहेगी।

चूँकि यह व्यवस्था सतोषजनक नहीं है, इसीलिए बहुत से लोग—जिनकी संख्या दिन-पर-दिन बढ़ती जा रही है—कहते हैं कि राष्ट्रों की प्रतिद्वन्द्विता और लड़ाई उसी समय बंद हो सकती है जब वे अपनी-अपनी सर्वप्रथम सत्ता को त्याग दें और एक उच्च अन्तर्राष्ट्रीय सरकार की अधीनता में रहे जो उन्हें एक-दूसरे से सहमत रहने के लिए बाध्य करेगी।

अमेरिकन राष्ट्र एक दूसरे से युद्ध करने की बात कभी नहीं सोचते। वे एक-दूसरे से युद्ध नहीं कर सकते। मघीय सरकार उन्हें ऐसा करने से रोक देगी। तार सारे सत्तार के लिए एक संघीय सरकार की स्थापना हो जाय तो

युद्ध हो ही नहीं सकता ।

अमेरिकन राष्ट्रों को सार्वभौम सत्ता प्राप्त है, फिर भी कुछ अशो म उन्होंने अपने को वॉशिंगटन की अधीनता में छोड़ रखा है और इसका उन्हें उचित बदला मिलता है । कुछ कानून तो वे अपने लिए स्वयं बनाते हैं और कुछ अपने सहयोग से दूसरों द्वारा बनाये गए कानूनों को स्वीकार कर लेते हैं । विश्व की सघीय सरकार भी इसी रीति से कार्य कर सकती है । शान्ति का रास्ता यही है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सरकार बनेगी अवश्य, प्रश्न केवल यह है कि उसको स्थापना हम स्वयं पहले से ही कर लेते हैं, मानव-समाज परमाणु-युद्ध करता है और उसके फलस्वरूप एक ऐसी विजयिनी शक्ति का प्रादुर्भाव होता है जो सारे समार की सत्ता अपने हाथों में ले लेगी और सब राष्ट्रों की सरकार बन बैठेगी । यह विजयिनी शक्ति रूस के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकती ।

मनुष्य स्वेच्छा से स्थापित की हुई अन्तर्राष्ट्रीय सरकार पसन्द करता है । हमारे पूर्वजों के समय में शासन-सत्ता नगरों के अधिकार में थी । वेल-गाड़ियों और घोड़ों के युग में देश ने सरकार का रूप ग्रहण किया था । भाप और बिजली के युग में यह स्थान राष्ट्र को मिला था और अब हवाई जहाज तथा परमाणु-शक्ति के युग में शासन सत्ता एक अन्तर्राष्ट्रीय सत्ता के हाथों में होगी ।

फिर भी युद्ध-काल में हमारे सामने ऐसे कितने ही प्रस्ताव आये जिनका उद्देश्य ससार का पुराने ढंग की इकाइयों, साम्राज्यों, गुटवदियों आदि में बाँट देने का था । इन सभी योजनाओं को उद्देश्य राष्ट्रीयता का प्रचार करना था ।

सन् १९४३ में गुटवदियों के प्रस्तावों की एक आधी-सी आई । न्यूयार्क के गवर्नर थामस डेवा ने और क्लेयर बूथ ल्यूस ने ब्रिटेन और अमेरिका की गुटबंदी पर जोर डाला । अर्ल ब्राउडर ने, जो उन दिनों अमेरिकन कम्युनिस्टों के नेता थे, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस की गुटबंदी का सलाह दी । वाल्टर लिपमेन और दूसरे लोगों ने प्रस्ताव किया कि युद्ध के बाद शान्ति कायम रखने की एकमात्र युक्ति ब्रिटेन, रूस, अमेरिका और चीन की गुटबंदी होगी ।

एक लेख में मैंने लिखा — “ये सुभाष-हानिप्रद हैं, क्योंकि गुटबंदी से ससार या अमेरिका को युद्ध से अलग रहने में सहायता नहीं मिलेगी । फिर भी बड़ी-बड़ी ग्राहक-संख्या वाले पत्र समय की ही गति में गति मिलाना पसन्द करते हैं, उन्हें आगे बढ़कर बात सोचने में हिचक होती है । आजकल गुटबंदी को लोग लड़खड़ाती हुई शान्ति का लक्षण समझते हैं । सन् १९४३ और १९४४ में

गुटबंदियों की एक चलन-सी चल गई थी। इसीलिए उन दिनों जनता से न तो गुटबंदियों के विरुद्ध कुछ कहा जा सकता था न अन्तर्राष्ट्रीयता के लिए ही अपील की जा सकता थी। मेरा लेख अन्ततः तिमाही 'वरजीनिया रिव्यू' के वसन्त, १९४४ के अंक में प्रकाशित हुआ।

संयुक्त राष्ट्रीय अधिकार-पत्र के सम्बन्ध में डम्बरटन ओक के प्रस्तावों को पढ़ते ही मैंने उनके अधूरेपन पर प्रकाश डालते हुए सितम्बर १९४४ में 'नेशन' नामक पत्र में एक लेख लिखा। मैंने विशेष रूप से विशेष मताधिकार की उस धारा की निन्दा की जिससे पाँच बड़े राष्ट्रों में से प्रत्येक को इस बात का अधिकार है कि वह संयुक्त राष्ट्रों को किसी आक्रमणकारी के विरुद्ध कार्य करने से रोक दे, चाहे वह स्वयं ही आक्रमणकारी क्यों न हो। वाद में मैंने सानफ्रांसिस्को के अधिकार-पत्र में उल्लिखित बड़े राष्ट्रों के विशेष मताधिकार पर भी आपत्ति उठाई और कुछ सशोधन पेश किया। इस बात के लिए 'सन्डे रिव्यू ऑफ लिटरेचर' के सम्पादक नारमैन कजिन्स ने एक सम्पादकीय टिप्पणी में मेरी आलोचना की और मुझे सम्पूर्णतावादी (परफेक्शनिस्ट) कहकर मेरे प्रति घृणा प्रगट की। वाद में सत्तार पर परमाणु बम गिरा और नारमैन कजिन्स ने अपने पत्र में सानफ्रांसिस्को अधिकार-पत्र की बुराईयों पर एक लम्बा वक्तव्य छापा। इस पर मेरे और नारमैन के बीच एक बड़ा मनोरंजक पत्र व्यवहार हुआ।

जो विचार समय से तीन या छ महीने पहले व्यक्त किये जाते हैं वे अनेक अमेरिकन पत्रकारों को बाधक प्रतीत होते हैं। वे घटनाओं से आगे बड़े रहना चाहते हैं, जिसका मतलब यह होता है कि वे घटनाओं से पीछे रह जाते हैं और वाद में घटना घटने पर उनके पाठक आश्चर्य-चकित रह जाते हैं। विशेष रूप से युद्ध के दिनों में यदि कोई व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में बिना सेसर किया हुआ सत्य कहना चाहता है तो वह ऐसा केवल रंगमंचों पर या पुस्तकों में कर सकता है। अन्य स्थानों पर तो पब्लिक को, जॉन फॉर्स्टर डूलस के शब्दों में "युद्ध का पाचनशील मीठा शर्वत" पीने को मिलता था।

सन् १९४४ में चार्ल्सटन (पश्चिमी वर्जीनिया) के एक छोटे-से भोजन में मेरी राय न्यूयार्क के एक ऐसे पत्रकार के सम्बन्ध में पूछी गई जो सभी विषयों पर लेख लिखता करता था। मैंने कहा—“उसे अधिक जानकारी नहीं है। वह भस्तिष्क को भोजन प्रदान करने के बदले उसमें केवल गुदगुदी पैदा करता है।”

इस पर प्रश्नकर्ता ने कहा— फिशर साहब, ऐसी बातें न कहिये,

उसे पढ़कर मुझे बड़ा आनन्द आता है ।”

युद्ध-काल में अधिकांश लोगो के लिखने और सम्पादन करने का उद्देश्य यही था । विजय के लिए जनता अमीम त्याग कर रही थी और वह इस बात की सात्वना चाहती थी कि सब बात ठीक चल रही है । सत्य से मिलती-जुलती कोई भी गम्भीर बात उसे अच्छी नहीं लगती थी । जिन लाखों अमेरिकनो के पेट ‘पाचनशील मोठे शर्बतो’ के अभ्यस्त हो चुके हैं उन भी अधिक ठोस और स्वस्थकर भोजन पचाने की सामर्थ्य नहीं है ।

शान्ति सम्बन्धी समस्याओं पर अमेरिका के युद्धकालीन साहित्य को फिर से पढ़ने में बड़ा दुःख होता है । उसमें हमें यह शिक्षा मिलता है कि पत्र में छपने वाली बातों का अक्सर उन घटनाओं से कोई सम्बन्ध नहीं होता जिनके द्वारा उस समय अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की रूप-रेखा साचे में ढलनी है । यह बात सन् १९४३ और, ४४ में की गई गुटबन्दियों पर विशेष रूप से लागू होती है ।

मैंने गुटबन्दियों का विरोध इतिहास और समाचार पत्रों में छपे हुए सत्य के आधार पर किया था । तबमाही “वरजीनिया” वाले अपने लेख में मैंने लिखा था — “धुरी राष्ट्र का विरोध करने वाले चार बड़े देश अब ऐसे मोर्चे सभाल रहे हैं, जहाँ से वे युद्ध के बाद एक-दूसरे से सघर्ष कर सकें । आने वाली शान्ति का यह कालारूप है । इससे सन् १९३९ से पहले वाली अराजकता के फलने का भय है ।

“इसके अलावा, देश अनिश्चित है । पहले विश्व-युद्ध में जर्मनी के मित्र इटली ने जर्मनी को छोड़ा दिया और वह हमारे पक्ष में आ मिला । जापान भी हमारे ही पक्ष में था । इस युद्ध में इन दोनों देशों ने हमारा विरोध किया है ।

“सन् १९०४-५ में रूस और जापान में लड़ाई हुई थी । सन् १९१४-१९१७ के युद्ध में वे एक दूसरे के मित्र थे । सन् १९१८ और १९२२ के बीच उनमें फिर लड़ाई हुई । सन् १९३८-३९ में उन्होंने एक-दूसरे के साथ डटकर युद्ध किया । आज वे फिर मित्र बन गए हैं, यद्यपि उनके युद्ध-सहकारी एक-दूसरे के विरुद्ध हैं ।

“सन् १९१४-१८ के बीच जर्मनी से लड़ते हुए ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के सिपाहियों ने कितने ही रण-क्षेत्रों में भाई-भाई की तरह खून बहाया था । कुछ ही वर्षों में ब्रिटेन की नीति जर्मनी से भी अधिक फ्रांस-विरोधी हो गई ।

“मित्रता-पूर्ण संधियों को शक्ति की तुला में तोलकर देखा गया है और उनमें कमियाँ पाई गई हैं । इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्रत्येक

सतुलन-गुट की स्थापना ने एक दूसरे शक्ति-सतुलन-गुट का उत्पत्ति के रणा दी है और अन्त में दोनों गुटों में युद्ध होगया है। सन् १९१८ में और फ्रांस ने विजय प्राप्त की थी और जर्मनी के मानो प्राण निकल रहे न्तु यूरोप की पारस्परिक शत्रुताओं के कारण और हवाई जहाज के नाविक युद्ध-अस्त्र के रूप में प्रकट हो जाने से नाजी जर्मनी को फिर से करने का अवसर मिला। इसी प्रकार नई वैज्ञानिक युक्ति या रासायनिक के आविष्कार से शक्ति-सतुलन-गुट में फिर परिवर्तन आ सकता है और समय भय या आजा या द्वेष के कारण अजेय दिखाई देने वाली गुटबन्दी हो सकती है और इसको निबंल बना सकती है ताकि उससे किसी दूसरे देश राष्ट्र-समूह को युद्ध-मार्ग ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन मिले।

“इसलिए वर्तमान स्थिति को कायम रखने के लिए गुटबन्दी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि युद्ध के कारणों को दूर करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय की आवश्यकता है।”

जो लोग अखबारों को पढ़ना जानते थे उन्हें अखबारों के पृष्ठों में तीन राष्ट्रों के युद्धोत्तर संघर्ष का अपशकुन स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकता था, इस सप्ताह में राजनीतिक मूर्ख भरे पड़े हैं। युद्ध के नाद और काल्प-विचारों का भनभनाहट में भावी विपदाओं की घरघराहट सुनाई नहीं दे दक्षिण अफ्रीका के प्रधान मन्त्री फील्डमार्शल जान क्रिश्चियन स्मट्स १ नवम्बर १९४३ को ब्रिटिश लोकसभा में एक ऐसा वक्तव्य दिया था उन्होंने स्वयं “विस्फोटक” कहकर पुकारा था। उनकी बातें विलकुल सही थी, फिर भी वे इतनी महत्त्वपूर्ण थी कि उन पर खूब चर्चा हुई, वे तोड़ी-गई और ब्रिटिश सरकार ने उनके समस्त भाषण को प्रकाशित दिया।

स्मट्स ने घोषणा की कि युद्ध के बाद इस सप्ताह पर त्रिशक्ति का प्रसार होगा। इनमें से ब्रिटेन “निर्धन और यूरोप में पक्षित” होगा, रूस में “सर्वशक्तिमान” होगा और अमेरिका के पास तो “अपार धन, बल साधन है ही।” यह असमानता स्मट्स को खटकती थी। वह चाहते थे कि दोनों राष्ट्र हर दृष्टि से शक्ति और प्रभाव में बराबर रहे। “मेरे असमान दोषदारी पसन्द नहीं करूँगा,” उन्होंने कहा था।

स्मट्स की त्रिशक्ति के समान अधिकार की इच्छा एक प्रकारसे शक्ति-मान की इच्छा है। किंतु यह कैसे सम्भव हो सकता है कि एक राष्ट्र जो दो राष्ट्रों से कमजोर और अतमान है, उनके साथ समानता प्राप्त कर

ले ? स्पष्टतः वह ऐसा या तो शेष दो राष्ट्रों को क्षति पहुँचा कर, कर सकता है—जो कि मुश्किल है—या छोटे छोटे देशों और उपनिवेशों के कन्धों से बन्दूक चला कर। स्मट्स दूसरा बात चाहते थे। अपने भाषण में उन्होंने दो रास्ते बताये—पहला यह कि ग्रेट ब्रिटेन अपने साम्राज्य को अपने साथ और भी घनिष्ठता के साथ जकड़े रखे और दूसरा यह कि वह पश्चिमी यूरोप के छोटे-छोटे देशों का एक महान् यूरोपियन राष्ट्र स्थापित करे।

अपने इस भाषण में स्मट्स ने उन मूर्खों को उत्तर दिया है जो कहते हैं कि हाथी और गिलहरीया मिलकर शान्ति की स्थापना नहीं कर सकती; बड़े और छोटे राष्ट्र एक साथ बैठकर शान्ति का मसविदा नहीं तैयार कर सकते ; यह काम तो हाथियों पर ही छोड़ देना चाहिए। किंतु कौन नई तो यह है कि सभी हाथी बराबर नहीं हैं। स्मट्स ने अपने भाषण द्वारा प्रकट किया कि एक हाथी इंग्लैंड को इस बात का भय है कि वह कहीं गिलहरी न समझा जाय और इसलिए वह अपने को शेष दो हाथियों के बराबर शक्तिशाली बना लेना चाहता है। दो हाथियों में सामंजस्य होना उतना ही भ्रामक है, जितना हाथी और गिलहरी में सामंजस्य होना। निस्सन्देह यदि हाथी गिलहरी पर अधिकार करने की चेष्टा करे तो न तो हाथी और गिलहरी में प्रेम उत्पन्न होगा, और न हाथियों में ही परस्पर सामंजस्य स्थापित होगा।

इस सम्बन्ध में ब्रिटेन की नीति विदेश-मंत्री एन्थनी ईडेन द्वारा ब्रिटिश लोकसभा में २८ सितम्बर १९४४ को स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई थी। उन्होंने बिना किसी हिचक के कहा था—“यदि हम अपने साम्राज्य और पश्चिमी यूरोप के पड़ोसियों की ओर से भी बोले तो दूसरे बड़े राष्ट्रों पर हमारी अधिक धाक जमेगी। मेरी समझ में यही वह सिद्धान्त है जिसके आधार पर हमें भवन-निर्माण करने की चेष्टा करनी चाहिए और सच पूछिये तो यही वह कार्य है जिसमें हम लोग इस समय लगे हुए हैं।” ईडेन के इस वक्तव्य से रहस्य पर से परदा उठ जाता है। उन्होंने यह कहकर कि इससे दूसरे राष्ट्रों पर हमारा अधिक धाक जमेगी स्वीकार कर लिया है कि तीनों राष्ट्रों में पारस्परिक प्रतिद्वन्द्विता है।

एकता की शाब्दिक ओट में शत्रुता चलती रही। किन्तु इस ओट के पीछे जाकर देखने के प्रयत्न को लोग निराशावाद कहकर उपेक्षित करते रहे। यह निराशावाद तो अवश्य था, किंतु था सत्य। दूसरे शब्दों में यो कहिये कि वह रचनात्मक निराशावाद था। उसकी उपेक्षा करके समस्याएँ हल नहीं होती। सत्य को ढका देना या विकृत करना सर्व-सत्तावादियों के लिए तो एक सामान्य

बात है, किंतु जनतंत्री देशों के लिए खतरे से खाली नहीं ।

दिसम्बर १९४३ के बाद जब कि मुझे न्यू यार्क के ब्रिटिश सूचना कार्यालय से मार्शल स्मट्स के भाषण का पूरा विवरण मिला, तो मैंने जितने भी भाषण दिये उनमें प्रत्येक में मैंने स्मट्स का भाषण विस्तार के साथ उद्धृत किया और बताया कि किस प्रकार रूसी प्रभाव के अन्तर्गत एक पूर्वी गुट की स्थापना हो रही है और साथ-ही-साथ ब्रिटिश प्रभाव के अन्तर्गत भी एक पश्चिमी गुट बनाने का अयोजन हो रहा है ।

मैं इस प्रकार की गुटबंदियों और प्रभाव-क्षेत्रों की स्थापना के विरुद्ध हूँ, क्योंकि न तो वे व्यावहारिक होते हैं और न उनमें कोई नैतिक सिद्धान्त ही होता है । गुटबंदियाँ दुर्बल राष्ट्रों को दास बना लेती हैं । उनसे युद्ध रुक नहीं सकता, वे सुरक्षा के लिए हमारी उग्र और आशाहीन खोज का एक अश मात्र हैं । राष्ट्रीय सुरक्षा नाम की कोई वस्तु नहीं । सुरक्षा या तो सबके लिए होनी है या किसी के लिए नहीं । यह बात ६ अगस्त, १९४५ से पहले, जब हिरोशिमा पर परमाणु बम का अवतरण हुआ था, बिलकुल स्पष्ट हो गई थी और अब तो वह बिलकुल अखण्डनीय है ।

रूस को अपनी सुरक्षा के लिए पोलैण्ड या बालकान देशों या आयरलैंड की उत्तनी ही कम जरूरत है जितनी अमेरिका को फिनोपेन या ओकीनावा या सैयान की, और ब्रिटेन को भारत और सिंगापुर की । हो सकता है कि ओकीनावा पर अमेरिकनो का अधिकार होने के कारण, कुछ परिस्थितियों में फिर से सिर उठानेवाले सेनावादी जापान के कुछ काल के लिए आक्रमण रुक जायें, किंतु आज से दस वर्षों बाद अमेरिका को अजन्टाइना, तुर्की, स्पेन, रूस, फ्रांस, सभी जगहों से परमाणु बम के आक्रमण का खतरा हो सकता है । ऐसे आक्रमणों से अमेरिका किस प्रकार अपनी रक्षा कर सकता है ? यह तो सम्भव है कि अमेरिकन अधिकारी अमेरिका पर आघात कर सकने वाले सभी राष्ट्रों के पास के अड्डों पर अधिकार कर लें या उन्हें उधार पट्टे पर ले लें, किन्तु मसाले भर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर अधिकार कर वे स्वभावतः विश्व के कोने कोने में अपने प्रति रोष और शत्रुता उत्पन्न कर देंगे और उनकी सुरक्षा बढ़ नहीं पाएगी । आजबल के परमाणु बम के युग में किसी समय भी और ससार के किसी कोने से भी आक्रमण हो सकता है । इस युग में अपने को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका को न केवल प्रशान्त के शत्रुओं पर, बल्कि सारे भूमण्डल के देशों पर अधिकार करना होगा । किंतु सब की इच्छा से स्थापित की गई अन्तर्राष्ट्रीय शासन-संस्था इससे अधिक अच्छी होगी ।

किसी आक्रमणकारी देश को जीतने या किसी शान्त देश पर शत्रुता जमाने के लिए थल, जल और नभ-सेनाएं अब भी काम में आ सकती हैं। किंतु शक्तिशाली से शक्तिशाली सेना भी बेतार के तांगे द्वारा संचालित हवाई जहाजों को नहीं रोक सकती। परमाणु शक्ति से प्रेरित हो वे हजारों मील की दूरी पार कर बीगो की तरह हम पर आक्रमण कर सकते हैं।

प्रिन्सटन में भौतिक विज्ञान विभाग के चेयरमैन, प्रोफेसर हैनरी डिब्लू स्मिथ ने, जिन्होंने परमाणु-बम के निर्माण का सरकारी इतिहास लिखा था, १३ मार्च, १९४६ को कहा—“वैज्ञानिकों ने अब यह अनुमान लगाया है कि न्यूयार्क नगर पर एक परमाणु बम के गिरने से तीन लाख से लेकर दस लाख तक कुछ सेकंडों के भीतर ही भीतर मृत्यु हो सकती है।”

प्रोफेसर जे० राबर्ट आपेनहोर ने, जो लास अलामास (न्यू मेक्सिको) में, जहाँ पहले परमाणु बम का परीक्षा रूप में प्रयोग किया गया था, परमाणु बम कार्यालय के संचालक थे, सिनेट की एक कमेटी के सामने बताया कि परमाणु बम के प्रथम आक्रमण में ४ करोड़ अमेरिकन मारे जा सकते हैं।

ब्रिगेडियर जनरल थामस एफ० फरेल ने, जिन्होंने लास अलामास (न्यू मेक्सिको) में प्रयुक्त किये गये प्रथम परमाणु बम और जापान पर गिराये गये दो अन्य परमाणु बमों के टुकड़ों को एकत्र किया था और जिन्हें अब पता चल गया है कि ये छोटे-अपूर्ण बम भी कितने विनाशक थे, १९ अक्टूबर, १९४५ को कहा—“यदि नियंत्रण नहीं रखा गया तो परमाणु बम का इतना अधिक विकास हो सकता है कि उससे सारे ससार की जनता नष्ट हो जाय।”

अतः सुरक्षा की बात केवल मूर्ख करते हैं।

जब पखदार बम और हवाई जहाज अप्राम्य गति से चलते हुए दूरी की बाधाएँ मिटा देते हैं तो ससार के किसी भी कोने में सुरक्षा कहाँ ? रूस की सुरक्षा कहाँ ? अमेरिका की सुरक्षा कहाँ ?

द्वितीय विश्व-युद्ध का एक कारण यह था कि कुछ राष्ट्रों ने सारे ससार को युद्ध से अलग रखने की बजाय केवल अपने को अलग रखना चाहा। सन् १९४१ से पहले तुष्टीकरण में विश्वास करनेवाले प्रत्येक देश का लक्ष्य यही था कि वह युद्ध से दूर रहे और अपनी शान्ति तथा सुरक्षा की पहरेदारी करे, इससे युद्ध का रास्ता साफ हो गया और हिटलर, हिरोहिरो तथा मुमोलिनी को यह विश्वास करने के लिए प्रोत्साहन मिला कि वे अपने शिकारों को एक-एक कर मार सकते हैं। उन्हें सफलता करीब-करीब मिल भी गई। कोई एक देश, चाहे वह कौसी भी व्यवस्था क्यों न करे, अपने को परमाणुबम के आक्रमण

से बचाने की सम्भावना को बढ़ा नहीं सकता। वह केवल अपनी प्रत्याक्रमण की शक्ति को बढ़ा सकता है। जो देश सैनिक दृष्टि से शक्तिशाली है उन्हें अपनी शक्ति से केवल एक लाभ होगा। वह यह कि स्वयं नष्ट होते समय वे दूसरों को भी नष्ट कर देंगे। किंतु कोई परमाणु-युद्ध को नहीं जीत सकता। क्या कोई सानफ्रान्सिस्को के भूचाल पर विजय पा सका ?

परमाणुबम के इतने भयकर होने पर भी उससे युद्ध की सम्भावना के घटने की नहीं, बल्कि बढ़ने की ही आशा है। आक्रमणकारियों के लिए परमाणु शास्त्र सबसे बड़े प्रोत्साहन का काम करेंगे। हिटलर की आशा थी कि वह अपने यात्रिक शस्त्रों और हवाई जहाजों से शत्रु को हराने में बड़ी शीघ्रता से सफलता प्राप्त कर लेगा। इसी तरह एक नया आक्रमणकारी अपने विरोधी देश से दुर्बल होते हुए भी इस बात का आयोजन करेगा कि वह परमाणु शस्त्रों को एकत्र कर एक बारगी ही अपने शत्रु पर बरसा दे और उसे जीत ले। यदि कभी परमाणु युद्ध होगा तो वह पर्ल-वन्दरगाह की घटना से भी अधिक आकस्मिक होगा और उसका उद्देश्य केवल आधी जलसेना को डुबाना ही नहीं बल्कि आधे राष्ट्र को नष्ट कर देना होगा। परमाणु शक्ति से आक्रमण करने वाला देश अपने पहले आक्रमण में ही शत्रु को इतना पगु बना देना चाहेगा कि वह उलट कर सफलता पूर्वक प्रत्याक्रमण ही न कर सके। ऐसे सवर्ष में जो देश पहले आक्रमण कर देगा उसका पत्ला बहुत ज्यादा भारी रहेगा।

“जिन परमाणुबमों ने जापान के दो नगरों को मटियामेट कर दिया वे उन बमों की तुलना में, जो आगामी दस या बीस वर्षों में तैयार होंगे, केवल पटाखों के सदृश्य थे।” यह बात शीकागो विश्वविद्यालय के तीन परमाणु शास्त्रियों ने ६ नवम्बर, १९४५ को बताई। चूँकि मनुष्य की कल्पना शक्ति सीमित है इसलिए हमलोग परमाणुबम के सम्बन्ध में जो अनुमान लगा रहे हैं, वह शायद सत्य से अधिक नहीं बल्कि कम है।

परमाणुबम ने एक ऐसा युग उत्पन्न कर दिया है जिसमें सुरक्षा की कोई सम्भावना ही नहीं। अब तो मनुष्य को केवल दो बातों में से एक को पसन्द करना है—विश्वव्यापी अरक्षा या विश्वव्यापी शांति।

तो फिर १९५६ या १९६० में अमेरिका या रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा का क्या शेष रह जायगा ? पूर्वी या मध्य यूरोप में रूस रक्षा का जो दुर्ग खड़ा करना चाहता है वह अमेरिका या ब्रिटेन के परमाणु शक्ति से चलने वाले हवाई जहाजों को आक्रमण करने से नहीं रोक सकेगा। यदि हम यूरोप या एशिया में विस्तार करेगा तो उसका एकमात्र परिणाम यह होगा कि हमारे देश भयभीत

और शक्ति हो जायगे और रूस की अरक्षितता और भी बढ़ जायगी । इसी प्रकार अमेरिकन या ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से रूस की घबराहट बढ़ेगी और अन्य देशों में भी तनातनी की वृद्धि होगी ।

यदि बड़े देश अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा यह होगा कि वे छोटे-छोटे देशों और कमजोर उपनिवेशों पर से अपना हाथ हटा लें । रूस का इंग्लैंड या अमेरिका से सम्बन्ध कैसा है इसका अनुमान लगाने में हमें उनके पारस्परिक सम्बन्ध से उतनी सहायता नहीं मिल सकती जितनी इस बात से कि उनका भूमण्डल के कमजोर देशों से कैसा सम्बन्ध है ।

हिटलर ने १९३९ में ग्रेट ब्रिटेन पर आक्रमण न करके पोलैंड पर किया और उससे द्वितीय विश्व-युद्ध का सूत्रपात हुआ । आक्रमण न करने वाले बड़े देशों ने नाजियों के कुछ आक्रमणकारी कार्यों को सहन कर लिया और उनके कुछ कार्यों में सुविधा प्रदान की । किन्तु अन्त में वह समय आया जब इंग्लैंड को कहना पड़ा—“बस, इतना ही; इससे आगे नहीं । अगर इस रेखा में आगे बढ़ें तो लड़ाई हो जायगी ।” हिटलर उस रेखा का पार कर पोलैंड में घुस गया और इसके फलस्वरूप जर्मनी नष्ट हो गया ।

शान्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा बड़े राष्ट्रों का विस्तार है । उनमें से कोई एक राष्ट्र उस हद तक बढ़ता चला जाता है जिसे दूसरा राष्ट्र अपना रक्षा की सीमा समझता है ।

सन् १९४५ के अन्त में रूस का आधे यूरोप, मंचूरिया और उत्तरी ईरान पर सफल नियन्त्रण था । फिर भी ७ फरवरी, १९४६ को मास्को की सर्वोच्च राजनीतिक सभा के सदस्य लाजार कागनोविच ने कहा—“हमारे देश पर अब भी पूँजी-पतियों का घेरा है इसलिए सतोष की कोई गुंजाइश नहीं । हमें इस घेरे को ढीला करना चाहिए”—अतः रूस ने तुर्की की मांग की और तेहरान में ईराक़ा सरकार पर आधिपत्य जमाने की चेष्टा की । नए प्रदेशों पर अधिकार करने के बाद बोलशेविकों को प्राप्त नए प्रदेशों को सुरक्षित बनाने के लिए दूसरे नए प्रदेशों की आवश्यकता होगी और फिर उनकी रक्षा के लिए तीसरे नए प्रदेशों की । आखिर, इस कड़ी का कहीं अन्त भी होगा ? क्या इस प्रकार अपने लाभ के लिए दूसरे देशों को हडपने का चेष्टा करने से दूसरे देशों का शक्ति होना और प्रत्याक्रमण करना अनिवार्य नहीं है !

वर्तमान युग में राष्ट्रीय सुरक्षा की खोज करते-करते हम अरक्षा के पास पहुँच जाते हैं और यदि वह खोज और आगे बढ़ाई जाती है तो युद्ध हो जाता है ।

बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को जितनी ही अधिक संख्या में निगलते हैं उतने ही अधिक छोटे राष्ट्र एक-दूसरे के निकट आ जाते हैं। अन्त में वह भी समय आयगा जब उनकी सीमाएँ एक-दूसरे को छूने लगेंगी और उनके बीच कोई दीवार खड़ी नहीं रह जायगी। इसलिए किस आधार पर हम सोच सकते हैं कि जिस शत्रुता से प्रेरित होकर ये देश अपना-अपना अधिकार-क्षेत्र अलग स्थापित करते हैं, वही शत्रुता उनका उस सकीर्ण बाधा के सामने जाकर खड़े होने पर समाप्त हो जायगी, जो उनके पूर्ण और शक्ति क्षेत्रों को एक-दूसरे से अलग करती है ? ऐसा सोचने के लिए हमारे पास कोई आधार नहीं।

परमाणु-युग के वर्तमान युग में शान्ति इस बात पर निर्भर है कि तीनों बड़े राष्ट्र छोटे देशों का आदर करें और उपनिवेशों को आजाद कर दें। इसका परिणाम यह होगा कि न तो तीनों बड़े राष्ट्रों के सामने लूटने-खसोटने के लिए कोई वस्तु होगी न वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे। उस समय हम परमाणु-युग को गैर कानूनी घोषित कर सकेंगे। सारे ससार के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय शासन-संस्था स्थापित कर सकेंगे और शान्ति से रह सकेंगे। राष्ट्रीय सार्वभौम सत्ता की उसा हद तक महत्ता है जिस हद तक उससे किसी दूसरे देश की राष्ट्रीय सार्वभौम सत्ता का दमन करने का काम लिया जाय। किंतु यदि किसी राष्ट्र की सार्वभौम सत्ता में हस्तक्षेप ही नहीं किया जायगा तो उसे सार्वभौम सत्ता की जरूरत ही क्या रह जायगी। सार्वभौम सत्ता के अन्त का अर्थ है राष्ट्रीय सरकार की स्थापना।

न्यूयार्क की रियासत कनेक्टिकट की सार्वभौम सत्ता में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, यही कारण है कि वे दोनों एक संधि के मदस्य बनने से इकार नहीं करते। हाँ संधीय सरकार अवश्य ही प्रत्येक रियासत की सार्वभौम सत्ता में हस्तक्षेप कर सकती है और इस दिशा में आवश्यक परिवर्तन दसियों वर्षों तक चलते रहते हैं। किन्तु इन परिवर्तनों के कारण अब कोई देश संधि में अलग होने की चेष्टा नहीं करता।

सार्वभौम सत्ता से अरक्षा उत्पन्न होती है।

३१ अक्टूबर १९४५ को अमेरिका के विदेश-मंत्री वॉर्न ने "न्यूयार्क हेरल्ड ट्रिब्यून" के कार्यालय में कहा था—“हम केन्द्रीय और पूर्वी यूरोप के अपने पड़ोसियों के साथ अधिक घनिष्ठ सम्पर्क और मैत्री स्थापित करने का जो प्रयत्न कर रहा है उसके प्रति हमने विरोध नहीं बल्कि सहानुभूति प्रगट की है। हमें यह अच्छी तरह से मालूम है कि इन देशों में उसे अपनी सुरक्षा की विशेष रूप से चिंता है।” इन शब्दों द्वारा वॉर्न ने स्वीकार किया है कि

आधे यूरोप पर रूस का प्रभाव है किन्तु यह एक निरर्थक बात है। रूस अपना रक्षा किससे करना चाहता है ? अमेरिका और इंग्लैंड से ? तो क्या अमेरिका के विदेश-मंत्री रूस पर इस बात का जोर डालते हैं कि वह अमेरिका से अपना रक्षा करे ? क्या दूसरे शब्दों में वह स्वीकार करते हैं कि रूस को अमेरिका से खतरा है ? या ब्रिटेन से खतरा है ? ब्रिटेन अमेरिका की सहायता के बिना रूस से नहीं लड़ेगा। या, जर्मनी से खतरा है ? जर्मनी अब रूस के लिए खतरा नहीं रह गया और यदि इंग्लैंड और अमेरिका रूस की सुरक्षा चाहते हैं तो वह कभी भविष्य में भी रूस के लिए खतरा नहीं बन पायगा। जर्मनी का पुनर्निर्माण ता उसी समय सम्भव है जब अमेरिका और ब्रिटेन उसका रूस के विरुद्ध प्रयोग करने के लिए उसे सहायता दे। किन्तु यदि श्री वर्न्स को रूस की रक्षा की इतनी चिन्ता है तो वह उक्त कार्य के लिए जर्मनी का पुनरुत्थान नहीं करेंगे।

अतः श्री वर्न्स के शब्दों में कोई विश्वास की भावना उत्पन्न नहीं हुई। बल्कि, उन्होंने अपने भाषण के दूसरे अंशों में पूर्वी यूरोप में जनतन्त्र कायम करने की बात कही, जिसका अभिप्राय यह था कि अमेरिका और ब्रिटेन रूस-प्रभावित क्षेत्रों पर से रूसी अकुश को ढीला करना चाहते हैं। कूटनीतिज्ञों की बातों का जो अर्थ ऊपर से होता है असली मतलब अक्सर उसका उलटा होता है।

जब कि पूर्वी यूरोप के देशों में एक ऐसी सरकार का रहना आवश्यक है जिसका रूस से मित्रता-पूर्ण सम्बन्ध हो, तो फिर वह देश स्वतन्त्र कैसे हो सकता है ? मान लीजिए कि इस देश के निवासी कोई ऐसी सरकार पसन्द करते हैं जिसे रूस अपने लिए मैत्रीपूर्ण नहीं समझता। ऐसी दशा में सम्भवतः रूस उसे अपने विशेष मताधिकार से रद्द कर देगा और किसी दूसरी सरकार की सहायता के लिए जोर देगा। इसी तरह मान लीजिए कि इस देश का विदेश-मंत्री ऐसा है जिसे रूसी मित्र नहीं मानते। मैं समझता हूँ कि निश्चय ही उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। और मान लीजिए कि वह देश कोई ऐसा कर या कानून बनाता है जो रूस को विरोधात्मक प्रतीत होता है तो अवश्य ही उस कर या कानून को रद्द करना पड़ेगा। तो फिर उस देश की स्वतन्त्रता ही क्या रही ? वह किस प्रकार जनतन्त्रवादी हो सकता है ? उसके मामले में तो रूस दखल देता रहेगा और उसका दैनिक जीवन तक रूस के ही आदेशानुसार संचालित होगा। अनिवार्य मित्रता दासता का ही दूसरा नाम है। बलात मित्रता करने की बात आजकल के कूटनीतिज्ञों ने साम्राज्यवाद पर परदा डालने के लिए गढ़ी है। जो लोग इसका समर्थन करते हैं वे बड़े राष्ट्रों के अधिकारों के पक्षपाती हैं।

रक्षात्मक घेरे, प्रभाव-क्षेत्र और साम्राज्य की बातें परमाणु-युग से पहले के युग की बातें हैं। इसी प्रकार सुरक्षा की बात भी उसी काल की बात है। फिर भी मानवता इस अप्राप्य सुरक्षा की प्राप्ति के लिए सम्भवतः सदा खरबों रुपए और लाखों प्राण निछावर करने को तैयार रहेगी। यदि ससार के सभी देश मिलकर एक सघ की स्थापना कर ले तो सुरक्षा की प्राप्ति में धन भी अधिक न लगे और प्राणों की भी अधिक आहुति न चढ़ानी पड़े।

मैं जानता हूँ कि इस प्रयत्न के फल-स्वरूप क्या-क्या समस्याएँ खड़ी हो सकती हैं। किंतु यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें परमाणु-युद्ध का सामना करना पड़ेगा, जिसमें २० करोड़ जीव स्वाहा हो सकते हैं।

रूस और ससार के शेष राष्ट्रों का पारस्परिक सम्बन्ध क्या हो, यही अन्तर्राष्ट्रीय सस्था की केन्द्रीय समस्या है।

रूस क्या चाहता है ?

वैदेशिक नीति के शीशे में घरेलू नीति और स्थिति का प्रतिबिम्ब दिखाई देता है, किंतु रूस अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि की पहुँच से बाहर है। जैसा कि चर्चिल ने सन् १९३९ में कहा था, वह "रहस्य की गंध में छिपी हुई एक पहेली है।" इसीलिए जब रूसी वैदेशिक नीति की व्याख्या करने का प्रश्न उठता है तो बोलने और लिखने वाले आलोचक उम सत्य के बदले, जो उन्हें प्राप्त नहीं होता या जिसका वे सामना नहीं करना चाहते, 'तर्क' से काम लेते हैं। वे कहते हैं कि—“रूस एक विशाल देश है—इसलिए स्पष्टतः उसे और साम्राज्य की आवश्यकता नहीं।” किंतु वे भूल जाते हैं कि बड़ा होते हुए भी रूस ने सन् १९३९ और १९४० में बाल्टिक राज्यों और फिनलैंड, पोलैंड तथा बालकान के प्रदेशों को हाथियाया, सन् १९४५ में चेकोस्लाव्स्कीया, जर्मनी और जापान के प्रदेशों पर हाथ मारा और सन् १९४६ में तुर्की तथा भूमध्य सागर के अड्डों की माग की। आलोचक कहते हैं कि रूस अब अपना सारा ध्यान युद्धोत्तर-निर्माण पर लगा रहा है और उसे विदेशों में विस्तार की इच्छा नहीं। वे भूल जाते हैं कि ये विदेश रूसी पुनर्निर्माण के लिए सामान और यंत्र के बड़े उपयोगी साधन बन सकते हैं।

रूसी वैदेशिक नीति का प्रथम उद्देश्य है रूस और यूक्रेन की राष्ट्रीयता का स्थापना और स्लाव जाति की रक्षा। कभी पहले रूस में अंतर्राष्ट्रीयता का बोल वाला था। बोल्शेविक्म ने बताया था कि व्यक्ति के जीवन में असली महत्व की बात उसकी आर्थिक और सामाजिक मर्यादा है न कि सिर का रूप, या चमड़े का रंग, या जन्म-स्थान। उदाहरणार्थ, सोवियत् पथ में इस बात पर जोर दिया गया था कि यूक्रेन के मजदूर यूक्रेनियन पूजीवादियों को अपेक्षा इटैलियन या चीनी मजदूरों के अधिक निकट है। रूसी शिक्षा का उद्देश्य यूक्रेनी मजदूरों को राष्ट्रीय न बनाकर अन्तर्राष्ट्रीय बनाना था। मैं अपने मे और अमेरिका के एक फाशिस्टवादी में उतनी समानता नहीं पाता जितनी कि अपने में और स्पेन

के एक फाशिस्ट-विरोधी या भारत के एक समाज-सुधारक में ।

जब रूस की घरेलू नीति अन्तर्राष्ट्रीयता की थी तो उसकी वैदेशिक नीति भी स्वभावतः ऐसी ही थी और रूस के भूतपूर्व विदेश मंत्री लिटविनाव सदा सामूहिक रक्षा के लिए अपील किया करते थे ।

सन् १९३५ तक रूसी विचार-धारा में जातीय या राष्ट्रीय श्रेष्ठता का कोई स्थान नहीं था । किन्तु उसके बाद एक नया प्रवाह—रूसी राष्ट्रियता का—वहा । मैंने अपनी “मनुष्य और राजनीति” (मैन एण्ड पालिटिक्स) नामक पुस्तक में, जो सन् १९४१ में प्रकाशित हुई थी, रूसी राष्ट्रवाद के विकास पर प्रकाश डाला था । उसके बाद से रूसी सरकार ने न केवल पूरे उत्साह और बल के साथ रूसी राष्ट्रवाद का ही भरण-पोषण किया है, बल्कि यूक्रेनी राष्ट्रवाद और स्लाव की जातीयता की भावना का भी समर्थन दिया है । जातीयता की यह भावना साम्यवाद, समाजवाद, बोन्शेविज्म और सोवियत् रूस की पूर्वकालीन लेनिनवादी प्रवृत्तियों के बुनियादी तत्त्वों के बिल्कुल विपरीत है । यह एक प्रति-गामी प्रवृत्ति है ।

२४ मई सन् १९४५ को स्टालिन ने क्रेमलिन के एक भोजन में कहा—
‘सबसे पहले मैं रूसी जनता के रवारथ्य के नाम पर शराब पीता हूँ क्योंकि सोवियत् संघ के अन्तर्गत वही सबसे श्रेष्ठ राष्ट्र है और इस युद्ध में उसने सोवियत् संघ के सभी राष्ट्रों में प्रमुख बहलाने की ख्याति प्राप्त की है । पी० डब्ल्यू० एन० लारेन्सन, जो मास्को में “न्यूयार्क टाइम्स” के सम्वाददाता थे, अभी कुछ ही दिन हुए “टाइम्स” में लिखा था कि इस वस्तव्य से यहूदियों में खलबली मच गई ।

आज से ८ या १० साल पहले भोजन के समय इस प्रकार के वस्तव्य असम्भव थे । उन दिनों किसी जाति को सोवियत् रूस का मुख्य राष्ट्र कहना बोल-शविक सिद्धान्तों के प्रतिकूल माना जाता था । सभी राष्ट्र बराबर थे, न कोई प्रमुख धान कोई गौण । जब इनमें से एक प्रमुख बन जाता है तभी शेष गौण ।

“रूस” शब्द का प्रयोग तो सुविधा मात्र के लिए किया जाता है । “रूस” का अर्थ रूस से नहीं बल्कि सोवियत् संघ से है । रूसी तो सोवियत् संघ के केवल ५४ प्रतिशत अंग हैं । शेष व्यक्ति कालमक, बुरियात, तुर्कमान, जाज़ियन गारमेनियन, ओस्सेटियन आदि लगभग १२० जातियों के हैं । बोलशविक इस बात की धीम हाँका करते थे कि वे इन जातियों में भेद-भाव नहीं करते, जाति किसी को ऊँचा नहीं उठाती । किसी भी राष्ट्र का विशेष स्थान नहीं ।

किन्तु अब रूसी राष्ट्र सोवियत् संघ का प्रमुख राष्ट्र है ।

६ नवम्बर १९४५ को रूस के विदेश-मंत्री मोलोटोव ने कहा—‘रूस

पर आक्रमण करके हिटलर ने केवल हमारी भूमि पर अधिकार करना नहीं चाहा था, बल्कि हिटलरवादियों ने घोषणा की कि उनका उद्देश्य रूसी जनता और साधारणतः समस्त स्लाव जाति का अन्त कर देने का है।" यदि यही बात मोलोटोव को ऐसी ही परिस्थितियों में दस वर्ष पहले कहनी होती तो वह कहते कि जर्मनी ने बोलशेविक क्रांति और साम्यवाद को कुचलना चाहा था।

बोलशेविक क्रांति में यही सबसे बड़ा परिवर्तन है। उससे सोवियत शासन-प्रणाली की सारी रूपरेखा ही बदल गई है। इस समय रूसी राष्ट्रवाद से स्लाव जातिवाद की ओर और स्लाव जातिवाद से साम्राज्यवाद का स्वाभाविक प्रवाह चल रहा है।

जब रूस में अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना थी तो बोलशेविक जाति को श्रेणी से उच्च समझने वाले उन नाजियों से बिल्कुल भिन्न थे जो जातीयता को इसलिए प्रोत्साहन देते थे कि उससे राष्ट्रीयता का उन्माद पैदा हो जाय और श्रेणी-युद्ध समाप्त हो जाय। राष्ट्रीयता के उन्माद ने हिटलर के आक्रमण रूपी इजिन में कोयले का काम किया। उसने कहना शुरू किया कि वरसाई की संधि में जर्मनी का अग्र-भग कर दिया गया था। बाद में उसने आस्ट्रियन और चेकोस्लोवाक प्रदेशों की मांग की, जो असल में जर्मनी के नहीं थे, किंतु जिनके निवासी जर्मन थे। इनके बाद वह उन प्रदेशों को जीतने बढ़ा जिनके निवासी भी जर्मन नहीं थे।

शक्तिमान् राष्ट्रवाद को भोजन की आवश्यकता होती है और वह भोजन है "भूमि"।

वह कौन-सी वस्तु थी जिसने स्टालिन को रूसी और यूक्रेनी राष्ट्रवाद तथा स्लाव जातिवाद का विकास करने के लिए प्रेरित किया? सोवियत शासन-सत्ता ने सदा ही रूसी और यूक्रेनी राष्ट्रवाद के विरुद्ध युद्ध किया था। यूक्रेन के कितने ही राष्ट्रवादियों को निकाल बाहर करने में खून की नदियाँ बहाई गई थी। इनमें से कुछ कम्युनिस्ट भी थे। इस शताब्दी के दूसरे और तीसरे शतकों के रूसी समाचारपत्रों में इस घटना का उल्लेख मिलता है जिससे पता चलता है कि २ करोड़ ८० लाख सोवियत यूक्रेनियों में राष्ट्रीयता की कितनी प्रबल भावना थी। आर्थिक कठिनाइयों और यूक्रेन के १९३२-३३ के दुर्भिक्ष की नीव मास्को निवासियों के द्वार पर पड़ी थी और उससे राष्ट्रवाद की भावना को बड़ा पोषण मिला था। यूक्रेनी राष्ट्रवाद को कुचलने में सफल न हो सकने के कारण स्टालिन ने उसके प्रति मित्रता प्रकट की। वह यूक्रेनियन राष्ट्र में एक सुनहरा युग लाना चाहते हैं। अब पोलैंड,

चेकोस्लोवेकिया और रूमानिया में यूक्रेनी नहीं रहेंगे। अब स्टालिन उन सबको सोवियत् भूदे के नीचे एकता के सूत्र में बाँध देंगे। एक यही बात ऐसी है जिसे हम स्टालिन द्वारा चेकोस्लोवेकिया के कारपेथो-रूस या कारपेथो-यूक्रेन के प्रदेशों पर अधिकार किये जाने का कारण मान सकते हैं। रूस के सरकारी सूत्रों का कहना है कि इन क्षेत्रों में ७ लाख २५ हजार व्यक्ति रहते हैं, जिनमें से ६५ प्रतिशत यूक्रेनी हैं। ज़ार के समय में ये क्षेत्र रूस के अन्तर्गत नहीं थे। चेकोस्लोवेकिया ने कभी सोवियत् रूस के विरुद्ध किसी प्रकार के वैर की भावना या आक्रमण की इच्छा नहीं रखी। इसके विपरीत उसने सदा ही रूस से मित्रता रखनी चाही। कोई भी देश कारपेथियन पहाड़ों को पार कर रूस पर आक्रमण नहीं कर सकता था। फिर भी सन् १९४३ में मास्को ने कारपेथो-रूस का प्रश्न उठाया। चेकोस्लोवेकिया के अध्यक्ष बेनेश जब वॉशिंगटन में ब्लेयर भवन में ठहरे हुए थे तो मैं उनसे १७ मई १९४३ को मिला। उन्होंने मुझे बताया कि वह रूसियों को कारपेथियनों के छोटे पिछड़े हुए प्रदेश पर अधिकार न करने के लिए प्रेरित करने में सफल हो गए हैं। बेनेश ने स्टालिन की महती आकांक्षाओं को पूर्ण रूप से समझने में भूल की। २९ जून १९४५ को रूस ने कारपेथो-रूस पर अधिकार कर लिया।

यूक्रेनियों को स्टालिन ने कुछ हिस्सा पोलैण्ड का, कुछ चेकोस्लोवेकिया का और कुछ रूमानिया का दिया और इस प्रकार उनकी स्वामी-भक्ति प्राप्त करने की आशा की। महान् रूसियों को उन्होंने वाल्टिकराज्य, फिनलैण्ड का कुछ भाग और शक्तिशाली रूस का विस्तृत भूखण्ड दिया। काकेशिया में अजरबैजानियों को वह ईरान का निकटवर्ती प्रदेश अजरबैजान देना चाहते हैं। और आर्मेनियनों के लिए वह पास का तुर्क प्रान्त मागना चाहते हैं।

रूस का विस्तार केवल स्लाव-प्रधान क्षेत्रों में ही सीमित नहीं है। किन्तु रूप की नीति है कि यूरोप के स्लाव भागों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाय। जब सोवियत् सब का दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रीय था तो उसका नारा था—“सारे ससार के मजदूरों, एक में मिल जाओ।” अब वह स्लावों को भी एकता के सूत्र में बाँधना चाहता है। दूसरे विश्व-युद्ध के दिनों में मास्को में कितना ही स्लाव कांग्रेसों के अधिवेशन हुए, जिनमें अनेक देशों ने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। किन्तु युद्ध-काल में मजदूर कांग्रेस या ट्रेड यूनियन कांग्रेस वीं कोई भी बैठक मास्को में नहीं हुई। स्लाव कांग्रेसों में इस बात पर जोर दिया गया कि रूस और पूर्वी यूरोप के स्लाव देशों का पारस्परिक सम्बन्ध बना चाहिए और इस प्रकार रूस की उस पूर्वी गृहयुद्ध के निर्माण का

पूर्वाभास मिला जिसके कारण गेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के साथ रूस के सम्बन्ध में गड़बड़ी पैदा हो गई है। किंतु स्टालिन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी मित्र या शत्रु को क्रुद्ध करने या आवश्यकता पड़ने पर, नष्ट तक कर देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाते।

रूसी अधिकारी उन राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे रहे थे जो क्रांति के बाद भी कुछ व्यक्तियों में शेष रह गई थीं। साथ-ही-साथ वे क्रांतिकाल में मृत-प्राय पड़े हुए राष्ट्रीय भावों को जाग्रत कर सोवियत सघ की नई पीढ़ी के लोगों के मस्तिष्क और हृदय में घुसने की चेष्टा कर रहे थे। सोवियत सघ में अब अधिकतः इसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें पहले कभी राष्ट्रवाद का ज्ञान नहीं था और जो अन्तर्राष्ट्रीयता के ही वातावरण में पाले-पोसे गए थे।

राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण पदार्थिक आवश्यकताओं की अपूर्ति की ओर से ध्यान हट जाता है।

पंचवर्षीय योजना के दिनों में रूसियों ने कितने ही नए शहर और बड़े-बड़े औद्योगिक कारखाने बनाये, जिनके उत्पादन से नाज़ियों को हराने में सहायता मिला। बहापरहथियार बनाने वाली मशीनों का एक उद्योग खड़ा कर दिया गया है, विद्युत्-शक्ति का एक जाल-सा फैला दिया गया है, लोहे और इस्पात के नए-नए कारखाने खोले गए हैं, अल्युमिनियम का भी एक उद्योग आरम्भ हो गया है, यातायात के साधनों में सुधार किया गया है, वातु और खनिज सम्बन्धी छट-पुट साधनों के आविष्कार किये गये हैं और उनका प्रयोग भी किया जा रहा है और हजारों स्त्री-पुरुषों को विशेष यांत्रिक शिक्षा दी जा रही है। इन बातों के फलस्वरूप भावी उन्नति के लिए एक व्यावसायिक अड्डा-सा स्थापित हो गया है। इनके अलावा कृषि-कार्य को सामूहिक रूप प्रदान किया गया है। जब से यूरोप के नौकरी पेशा करने वाले किसान बने। तब के बाद से यह कृषि-सम्बन्धी पहला सुधार है।

किन्तु इन महान् ऐतिहासिक परिवर्तनों से अभी रूस के व्यक्तिगत निवासियों को कोई ठोस लाभ नहीं हुआ है। वहाँ की जनता का जीवन-मान पूर्विय यूरोपियन आदर्श की अपेक्षा अब भी नीचे गिरा हुआ है। सोवियत नागरिकों को अपनी मेहनत के अनुकूल मजदूरी नहीं मिलेगी। उनकी मेहनत और मजदूरी में जो अन्तर है उससे हमें नये उद्योगों, शस्त्रों के निर्माण और सरकारी नौकरियों पर खर्च किये जाने वाले धन का आभास मिलता है। किसी-न-किसी को तो कीमत देनी ही पड़ती है। यह कीमत जनता देती है और जनता ही दुःख भी उठाती है।

रूसी प्रचारक इस स्थिति को स्वीकार करते हैं, किंतु उनका कहना है कि इससे राष्ट्र को लाभ हो रहा है, इससे राष्ट्र के लोगो में अभिमान की भावना जाग्रत हुई है। किन्तु रूसी सरकार यह नहीं समझता कि बोलशेविक क्रान्ति या सोवियत् शासन प्रणाली के प्रति अभिमान उत्पन्न होने से दिन-प्रति-दिन होने वाले खर्चों के औचित्य का समर्थन किया जा सकता है। यह सोचकर कि क्रान्ति का उत्साह ठंडा पड़ गया है, जनता को राष्ट्रवाद के रूप में एक नई प्रेरणा दी गई। जब एक बार यह प्रेरणा दे दी गई तो उसका पोषण करना आवश्यक था। रूसी विस्तार का यह सबसे पहला लक्ष्य है।

अब जब कि युद्ध जीता जा चुका है, रूस के सामने अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और अपने भग्न भवनो को फिर से बनाने का अभूतपूर्व कार्य है। रूस के अधिक-से-अधिक भीतरी भाग में घुस चुकने पर जर्मन-सेना के अधिकार में जितनी रूसी भूमि थी वह जर्मनी के वर्गक्षेत्र से तिगुनी बड़ी थी। वह भूमि सोवियत् संघ की सबसे अधिक धन-धान्यपूर्ण और उन्नत भूमि थी। लाखों जर्मन और रूसी सैनिकों के पदाक्रमण के बाद भी जो वस्तुएँ नष्ट होकर धूल नहीं बन गई थी, उन्हें नाजियो ने जान-बूझकर नष्ट कर डाला। जो वस्तु थोड़े ही दिन पहले अत्यधिक व्यय से बनाई जाती है उसे फिर से बनाना एक कठिन कार्य है। आजकल एक बार फिर रूसी नागरिकों को कम भोजन, कम कपड़ा और कम स्थान से सतुष्ट रहकर और अधिक मेहनत करके अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का मूल्य चुकाना पड़ रहा है।

सन् १९१६ के बाद से रूसी जितना श्रम करते आये हैं उसे बाहर-वाले बहुत ही कम समझ सकते हैं। पिछले ३० वर्षों से बहुत ही कम व्यक्तियों के जीवन में ऐसे क्षण आये होंगे जिन्हें उन्होंने साधारण सुख-चैन से बिताया हो। कुछ गिने-चुने लोगो को छोड़कर शेष सभी लोगो का जीवन लगातार कार्य या त्याग से भरा रहा। लोगो को खाना कम मिला और अन्न के लिए लम्बी लाइनों में खड़ा रहना पड़ा। अब, जब कि वह क्रान्तिपूर्ण युग बीत चुका है और रक्तपातपूर्ण युद्ध भी समाप्त हो गया है, सोवियत् जनता को एक बार फिर खोज उठाना है और आर्थिक दृष्टि से अपने देश को स्वावलम्बी बनाना है। स्वभावतः सोवियत् सरकार पुनर्निर्माण की अवधि को छोटा करना चाहती है और जनता पर उसके मूल्य का भार कम-से-कम डालना चाहती है। कैसे ? केन्द्रीय और पूर्वी यूरोप और मध्य-पूर्व की आर्थिक व्यवस्था को रूस की आर्थिक व्यवस्था में मिलाकर, ताकि उनके प्रौद्योगिक प्रबन्ध, कच्चे

पूर्वाभास मिला जिसके कारण गेट ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका के साथ रूस के सम्बन्ध में गड़बड़ी पैदा हो गई है। किंतु स्टालिन अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी मित्र या शत्रु को क्रुद्ध करने या आवश्यकता पड़ने पर, नष्ट कर देने में हिचकिचाहट नहीं दिखाते।

रूसी अधिकारी उन राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन दे रहे थे जो क्रांति के बाद भी कुछ व्यक्तियों में शेष रह गई थी। साथ-ही-साथ वे क्रांतिकाल में मृत-प्राय पड़े हुए राष्ट्रीय भावों को जाग्रत कर सोवियत सघ की नई पीढ़ी के लोगों के मस्तिष्क और हृदय में घुसने की चेष्टा कर रहे थे। सोवियत सघ में अब अधिकतर इसी पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें पहले कभी राष्ट्रवाद का ज्ञान नहीं था और जो अन्तर्राष्ट्रीयता के ही वातावरण में पाले-पोसे गए थे।

राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण पदार्थिक आवश्यकताओं की अपूर्ति की ओर से ध्यान हट जाता है।

पंचवर्षीय योजना के दिनों में रूसियों ने कितने ही नए शहर और बड़े-बड़े औद्योगिक कारखाने बनाये, जिनके उत्पादन से नाज़ियों को हराने में सहायता मिला। वहाँ पर हथियार बनाने वाली मशीनों का एक उद्योग खड़ा कर दिया गया है, विद्युत्-शक्ति का एक जाल-सा फैला दिया गया है, लोहे और इस्पात के नए-नए कारखाने खोले गए हैं, अल्यूमिनियम का भी एक उद्योग आरम्भ हो गया है, यातायात के साधनों में सुधार किया गया है, वातु और खनिज सम्बन्धी छट-पुट साधनों के आविष्कार किये गये हैं और उनका प्रयोग भी किया जा रहा है और हजारों स्त्री-पुरुषों को विशेष यांत्रिक शिक्षा दी जा रही है। इन बातों के फलस्वरूप भावी उन्नति के लिए एक व्यावसायिक अड्डा-सा स्थापित हो गया है। इनके अलावा कृषि-कार्य को सामूहिक रूप प्रदान किया गया है। जब से यूरोप के नौकरी पेशा करने वाले किसान बने। तब के बाद से यह कृषि-सम्बन्धी पहला सुधार है।

किन्तु इन महान् ऐतिहासिक परिवर्तनों से अभी रूस के व्यक्तिगत निवासियों को कोई ठोस लाभ नहीं हुआ है। वहाँ की जनता का जीवन-मान पूर्वोक्त यूरोपियन आदर्श की अपेक्षा अब भी नीचे गिरा हुआ है। सोवियत नागरिकों को अपनी मेहनत के अनुकूल मजदूरी नहीं मिलेगी। उनकी मेहनत और मजदूरी में जो अन्तर है उससे हमें नये उद्योगों, शस्त्रों के निर्माण और सरकारी नौकरियों पर खर्च किये जाने वाले धन का आभास मिलता है। किसी-न-किसी को तो कीमत देनी ही पड़ती है। यह कीमत जनता देती है और जनता ही दुःख भी उठाती है।

रूसी प्रचारक इस स्थिति को स्वीकार करते हैं, किंतु उनका कहना है कि इससे राष्ट्र को लाभ हो रहा है, इससे राष्ट्र के लोगो में अभिमान की भावना जाग्रत हुई है। किन्तु रूसी सरकार यह नहीं समझता कि बोलशेविक क्रान्ति या सोवियत् शासन प्रणाली के प्रति अभिमान उत्पन्न होने से दिन-प्रति-दिन होने वाले खर्चों के औचित्य का समर्थन किया जा सकता है। यह सोचकर कि क्रान्ति का उत्साह ठंडा पड़ गया है, जनता को राष्ट्रवाद के रूप में एक नई प्रेरणा दी गई। जब एक बार यह प्रेरणा दे दी गई तो उसका पोषण करना आवश्यक था। रूसी विस्तार का यह सबसे पहला लक्ष्य है।

अब जब कि युद्ध जीता जा चुका है, रूस के सामने अपने देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और अपने भग्न भवनो को फिर से बनाने का अभूतपूर्व कार्य है। रूस के अधिक-से-अधिक भीतरी भाग में घुस चुकने पर जर्मन-सेना के अधिकार में जितनी रूसी भूमि थी वह जर्मनी के वर्गक्षेत्र से तिगुनी बड़ी थी। वह भूमि सोवियत् संघ की सबसे अधिक धन-धान्यपूर्ण और उन्नत भूमि थी। लाखों जर्मन और रूसी सैनिकों के पदाक्रमण के बाद भी जो वस्तुएँ नष्ट होकर धूल नहीं बन गई थी, उन्हें नाजियो ने जान-बूझकर नष्ट कर डाला। जो वस्तु थोड़े ही दिन पहले अत्यधिक व्यय से बनाई जाती है उसे फिर से बनाना एक कठिन कार्य है। आजकल एक बार फिर रूसी नागरिकों को कम भोजन, कम कपड़ा और कम स्थान से सतुष्ट रहकर और अधिक मेहनत करके अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य का मूल्य चुकाना पड़ रहा है।

सन् १९१६ के बाद से रूसी जितना श्रम करते आये हैं उसे बाहर-वाले बहुत ही कम समझ सकते हैं। पिछले ३० वर्षों से बहुत ही कम व्यक्तियों के जीवन में ऐसे क्षण आये होंगे जिन्हें उन्होंने साधारण सुख-चैन से बिताया हो। कुछ गिने-चुने लोगो को छोड़कर शेष सभी लोगो का जीवन लगातार कार्य या त्याग से भरा रहा। लोगो को खाना कम मिला और अन्न के लिए लम्बी लाइनों में खड़ा रहना पड़ा। अब, जब कि वह क्रान्तिपूर्ण युग बीत चुका है और रक्तपातपूर्ण युद्ध भी समाप्त हो गया है, सोवियत् जनता को एक बार फिर बोझ उठाना है और आर्थिक दृष्टि से अपने देश को स्वावलम्बी बनाना है। स्वभावतः सोवियत् सरकार पुनः निर्माण की अवधि को छोटा करना चाहती है और जनता पर उसके मूल्य का भार कम-से-कम डालना चाहती है। कैसे ? केन्द्रीय और पूर्वी यूरोप और मचूरिया की आर्थिक व्यवस्था को रूस की आर्थिक व्यवस्था में मिलाकर; ताकि उनके औद्योगिक प्रबन्ध, कच्चे

माल और मानवी साधनों से रूसी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यही कारण है कि रूस आस्ट्रिया और रूमानिया के तेल पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है और साथ-ही-साथ हंगरी के व्यवसाय और कृषि, चेकोस्लोवेकिया की फैक्टरियो, यूगोस्लाविया की खानों और यूरोप के रूस-प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले १५ करोड़ प्राणियों के आर्थिक जीवन पर भी अधिकार प्राप्त करना चाहता है। सोवियत् वैदेशिक नीति का यह दूसरा उद्देश्य है।

तीसरा उद्देश्य अवसर है। जर्मनी और इटली के हार जाने से और फ्रांस की दुर्बलता के कारण एशिया में, विशेष रूप से चीन में, शक्ति का एक बहुत बड़ा शून्य पैदा हो गया है। प्रकृति की भांति अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति भी शून्य पसंद नहीं करती। इसीलिए तीनों बड़े राष्ट्रों में से प्रत्येक या तो इस शून्य के अधिक-से-अधिक भाग पर अधिकार करना चाहता है या कम-से-कम शेष दो को इस पर अधिकार करने से रोकना चाहता है। यही तीनों बड़े राष्ट्रों की लड़ाई की जड़ है। एक दूसरे के प्रति उलहना देने से यह लड़ाई रुक नहीं सकता। आज अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के आगन में एक ऐसा पुरस्कार पड़ा दिखाई दे रहा है जो पिछले दसियों सालों से राष्ट्रों को लुभानेवाले सभी पुरस्कारों से बहुमूल्य है। अतः आश्चर्य ही क्या यदि प्रतिस्पर्द्धा अधिक हो।

तीनों पराजित महान् राष्ट्रों—जर्मनी, जापान और इटली—के समाप्त हो जाने से तीनों विजयी महान् राष्ट्रों—रूस, अमेरिका और ब्रिटेन—को विस्तार का अद्वितीय मार्ग मिल गया है। दुर्बल राष्ट्रों की क्लान्ति और निस्सहायता के कारण हड़पने और प्रभुता प्राप्त करने की प्रवृत्ति और भी बढ़ गई है।

रूसियों, उनके विदेशी साथियों और अनेक अमेरिकनों और अंग्रेजों ने भी, जो शक्ति-संतुलन द्वारा शान्ति स्थापित करने में विश्वास रखते हैं, मूलतः आशा की थी कि द्वितीय विश्व-युद्ध में लूटी गई सम्पत्ति तीनों बड़े राष्ट्रों में मित्रता-पूर्वक बाँट दी जायगी, तीनों का प्रभाव-क्षेत्र अलग-अलग निर्धारित कर दिया जायगा और उनमें कोई झगड़े की बात नहीं रह जायगी। उन्होंने यह भी आशा की थी कि लूटी हुई सम्पत्ति के इस विभाजन के आधार पर एक ऐसा युद्धोत्तर समझौता होगा जिसे अक्षुण्ण रखने में तीनों बड़े राष्ट्रों को दिल-चस्पी होगी।

किन्तु घटनाओं ने बिल्कुल ही भिन्न रूप धारण किया। स्टालिन ने यूरोप में झाँककर देखा कि किसी में उसे राकने की सामर्थ्य नहीं। इसलिए उसने अपने अक में बहुत से छोटे-छोटे देश बाँध लिये। अब ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका यह महसूस कर रहे हैं कि रूस ने यूरोपीय शून्य का अधिकांश भाग

हडप लिया है और उसे अपने बिच्छुओं से भर दिया है। इसी प्रकार रूस अनुभव कर रहा है कि अमेरिका ने एशियाई शून्य के अधिकांश पर अधिकार कर लिया है। फिर भी अमेरिका को रूस के चीन विषयक और प्रशान्त के थल और जल क्षेत्रों से सम्बन्ध रखने वाले आयोजनों पर शक है। शून्य में समानता कायम रखना मुश्किल है, किंतु चूंकि शक्ति का सतुलन असम्भव है इसलिए प्रत्येक राष्ट्र अधिक-से-अधिक शक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करता है।

निश्चय ही तीनों बड़े राष्ट्र अपने-अपने मत-भेदों को भिटाने और सहन करने की चेष्टा करते रहेंगे। वे युद्ध नहीं चाहते। वे मोल-भाव करके समझौता कर लेंगे। विश्व-शान्ति के लिए यह एक बड़ा ही सकटपूर्ण आधार है।

इंग्लैंड, जो कि तीनों में सबसे कमजोर है, अपने अधिकार अलग बनाये रखना चाहता है। उसे रूसी आक्रमण का भय है अमेरिका और रूस एशिया में अधिकार प्राप्त करने के लिए एक-दूसरे के साथ स्पर्धा कर रहे हैं।

अवसर ने रूसी सरकार के दरवाजे को थपथपाया। यह अवसर रूसी शक्ति को बढ़ाने का था, प्रलोभन रोका नहीं जा सकता था।

रूस वहां कर रहा है जो अतीत में दूसरे राष्ट्रों ने किया था। अन्तर्राष्ट्रीयतावादी लेनिन ने सन् १९२१ में पोलैंड को इतनी भूमि दे दी जितनी उसने मांगी नहीं थी। उन्होंने सहर्ष फिनलैंड और तीन बाल्टिक राज्यों की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। उन्होंने अफगानिस्तान को भूमि के कुछ टुकड़े दिये और चीन से अपने अधिकार और सम्पत्तियां हटा लीं। ज़ारों ने ईरान से जा तेल और दूसरी सुविधाएँ ली थी उन्हें लेनिन ने ईरान को वापस कर दिया। उन्होंने तुर्की से मित्रता की। उन्हें स्लावो का कोई समूह बनाने में दिलचस्पी नहीं थी। वह एक क्रांति की रचना कर रहे थे, साम्राज्य का निर्माण नहीं। लेकिन अब लोग रूस में लेनिन को भूलते जा रहे हैं।

नापने के लिए एक निश्चित नाप का होना आवश्यक है। रेखा, क्षेत्र, वजन और गरमी-सरदी का मान वैज्ञानिकों द्वारा निश्चित किया जाता है। अपना नैतिक और राजनीतिक मान प्रत्येक व्यक्ति स्वयं निश्चित करता है। यह काम वह अपनी व्यक्तिगत, धार्मिक और आध्यात्मिक प्रकृतियों के अनुसार करता है। उच्चता का आदर्श वह या तो ईश्वर को मानता है या सिद्धान्तों को। किन्तु यदि उसका उच्चता का आदर्श कोई ज़िम्मीदार या सरकार होता है तो उसकी तोल गड़बड़ा जाती है या दूसरे शब्दों में यो कहिये कि घटनाओं और विचारों के सम्बन्ध में उसका निर्णय विकृत बन जाता है, क्योंकि सभी स्त्री-पुरुष अपने सिद्धान्तों और आध्यात्मिक विचारों से डिगते रहते हैं। कोई भी

राजनीतिक शास्त्र, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं, जिससे चूक न हो। अतः जब एक कम्युनिस्ट यह कहता है कि सोवियत् सरकार कभी गलती नहीं करती, या स्टालिन सदा ही ठीक काम करता है और वह इसी मान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु को आंकता है तो निश्चय ही वह सीधे ढग से देख या साच नहीं सकता, वह नाप नहीं सकता। सभी देश, सभी सरकारें, सभी नेता गम्भीर भूले करते हैं। इसका प्रमाण हमें हर सुबह समाचारपत्रों में मिलता है।

सन् १९४५ में अर्जन्टाइना सयुक्त राष्ट्रों में सम्मिलित किया गया तो सोवियत् सरकार और उसके विदेशी समर्थकों ने इस कार्य की निन्दा की। उन्होंने कहा कि फाशिस्ट शासन-संस्थाओं से कोई सम्बन्ध नहीं होना चाहिए। किंतु जब जून, १९४६ में सोवियत् सरकार ने पेरन की तानाशाही को स्वीकार किया और उसके साथ कूटनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध भी स्थापित किया तो किसी भी कम्युनिस्ट ने सोवियत् सरकार की बुराई नहीं की। उनके पास नापने-तोलने का कोई निश्चित मान नहीं है। यही अवसरवादिता कहलाती है। इसका मतलब यह है कि सोवियत् सरकार जो कुछ भी करती है, ठीक ही करती है, चाहे हिटलर के साथ गुटबन्दी हो, चाहे पेरन के साथ समझौता, चाहे सैनिक कार्रवाई हो, चाहे आतंक-प्रसार। नाप-तोल के ऐसे मानों के रहते हुए निर्णयों के निरर्थक बन जाने की सम्भावना रहती है।

: १६ :

क्रान्ति का क्या हुआ ?

क्रान्ति बीते कल की चिन्ता नहीं करती। वह तो और वर्तमान कार्यों की उपेक्षा कर आगामी कल की ओर प्रभावित होती है। क्रान्ति एक 'नया आरम्भ' है। अतीत का विरोध ही उसका मूल-तत्त्व है। बोलशेविक क्रान्ति परम्परागत काली जारशाही पर आक्रमण थी। यही उसका औचित्य था, यही उसकी प्रेरणा थी और यही उसका कार्य था।

कार्ल मार्क्स और पीटर महान् के सिद्धान्तों के बीच जो सघर्ष चलता रहा है वही बोलशेविक क्रान्ति है। वह रूस के अतीत और कम्युनिस्टवादी भविष्य का पारस्परिक संग्राम है। इस सघर्ष में नये को पुराने के विरोध का सामना करना पड़ा। कभी मार्क्स की जीत रही तो फिर कभी पीटर की विजय हुई और मार्क्स उसका बन्दी बन गया। किंतु महत्त्वपूर्ण मामले में पीटर और मार्क्स दोनों एक दूसरे से सहमत थे, दोनों तानाशाही के समर्थक थे। इधर कुछ दिनों में तो वे उस राक्षस का आकार ग्रहण करते आ रहे हैं, जिसका शरीर एक होता है किन्तु जिसके कन्धे पर दो भिन्न-भिन्न सिर होते हैं। कुछ लोग मार्क्स को देखते हैं, कुछ पीटर को। इससे भ्रान्ति पैदा हो जाती है।

सोवियत् रूस न तो शुद्ध रूप से मार्क्सवादी है न शुद्ध रूप से पीटर का अनुगामी। दोनों के मिश्रण ने एक विलकुल ही भिन्न वस्तु उत्पन्न कर दी है, जो अभूतपूर्व होती हुई भी विलकुल स्पष्ट है।

सोवियत् रूस में दुर्भाग्यवश लोकमत अक्सर घटनाओं से बहुत पिछड़ा हुआ है, यहां तक कि १० वर्ष तक पिछड़ा हुआ रहा है। सन् १९२९ के आस-पास मास्को के विदेशी सवाददाताओं ने, जिनमें एक में भी था, यह रिपोर्टें देनी आरम्भ कीं। कि रूस उद्योगों का निर्माण कर रहा है और शक्तिशाली बन रहा है। इसे लोगो ने प्रचार कहकर टाल दिया। कभी कभी प्रचार वह सत्य होता है जो हमारे उसे ग्रहण करने के लिए तैयार होने से काफी पहले ही कह दिया जाता है। जब सम्वाददाताओं ने समय से दस साल पहले लिखा कि रूस बल-

वान बनता जा रहा है तो लोगो ने उसे प्रचार कहकर पुकारा । किंतु जब यही बात दस साल देर करने के बाद राजदूत जोसेफ ई० डेविस ने अपनी "मास्को यात्रा" (मिशन टू मास्को) नामक पुस्तक में लिखी तो उनकी पुस्तक हाथो-हाथ बिकने लगी ।

आज भी हम उन महान् घटनाओं के समझ सकने में ८ या १० वर्ष पीछे हैं जो इस समय सोवियत् रूस के भीतर घट कर रही हैं और जिनसे उसकी शासन-प्रणाली का रूप ही बदलता जा रहा है ।

शासन-संस्थाएँ नेता और पार्टियाँ अक्सर बदलती रहती हैं । नैपोलियन ने अपना जीवन एक क्रान्तिकारी सैनिक-योद्धा के रूप में आरम्भ किया बाद में वह बादशाह बन गया । मुसोलिनी पहले-पहल एक वामपक्षी समाजवादी था । बाद में वह राष्ट्रवादी बन गया और ऐसा कर उसने फाशिस्टवाद की ओर एक कदम उठाया । शासन संस्था रूपी हवाई जहाज के चालक अक्सर अपने सिद्धान्तों को उठाकर फेंक देते हैं ताकि दूसरे बाँध के लिए स्थान खाली हो जाय । फिर भी वे अपने सिद्धान्तों का नाममात्र के लिए राग जरूर अलापते रहते हैं ।

किसी देश की असलियत उसके सरकारी वक्तव्यों में दिखाई नहीं देती । एक बार कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जहाँ एक गृहस्थिनी दुकानदार की बातों में विश्वास न कर मुर्गी के बच्चों को स्वयं परीक्षा करके देखती है, वहाँ इतिहासकार और पत्रकार सरकार की बातें सत्य मान लेते हैं । यदि मार्क्स को आधुनिक पत्रकारों की सलाह देनी होती तो वह कहते कि सरकार द्वारा दिये जाने वाले 'मुर्गी के बच्चों' को सोच-समझ कर लो ।

रूस के नेताओं और उसका अधिकांश भूमि तक बाहर वालों की पहुँच नहीं होती । फिर भी उसमें हमें जो रहस्य दिखाई देता है उसका कारण अज्ञान नहीं बल्कि भविष्य को समझ सकने की असमर्थता है । यह नहीं कि हम नहीं जानते कि रूस क्या है बल्कि यह कि हमें पता नहीं कि रूस क्या करेगा । उसके रहस्यमय होने का यही कारण है । सभी तानाशाही देश रहस्यमय होते हैं क्योंकि तानाशाही को रोकने वाला कोई लोकमत नहीं होता और किसी स्वतंत्र समाचार पत्र में उसकी पोल नहीं खोली जाती ।

रूस कोई रहस्य नहीं है । यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी के साथ उसकी नीति की व्याख्या करना चाहे तो उसे रूसी पुस्तकों आदि में इसके लिए सब आवश्यक सामग्री मिल सकती है । इसके अलावा हम सोवियत् सरकार के भिन्न-भिन्न कार्यों से भी उसके सम्बन्ध में निष्कर्ष निकाल सकते हैं ।

सोवियत् रूस के सम्बन्ध में सभी बुनियादी बातें उपलब्ध हैं और आसानी

से समझी जा सकती है ।

रूस में सारी पूंजी सरकार की होती है । सोवियत् का कोई भी निवासी न जमीन खरीद सकता, न बेच सकता, न रख ही सकता है । वहाँ सब ज़मीन सरकार की है । किसी रूसी किसान के पास न अपना घोड़ा होता है, न बैल, न हल, न ट्रैक्टर । ये उत्पादन के साधन पूंजी हैं, इसीलिए उन पर सरकार का अधिकार होता है । देश की सभी फैक्ट्रियों, रेल की सड़को, तेल के खेतों, खानों, सार्वजनिक उपयोग के साधनों, समाचारपत्रों, छापेखानों, फुटकर और थोक बिक्री की दुकानों, सौन्दर्य-सामग्री की दुकानों, नाइयों की दुकानों, होटलों, भोजनालयों, हवाईजहाज़ों और यातायात के साधनों पर सरकार का अधिकार है और वही इतका संचालन करती है । सारांश यह कि वे सब रूसी पदार्थ, जिनसे धन कमाया जा सकता है, सरकारी नियंत्रण में हैं ।

लोग व्यक्तिगत रूप से घड़ी, सूट, पुस्तकालय, घर, गरमी के दिनों के लिए बगला और मोटर भी रख सकते हैं । यद्यपि रूस इतना निर्धन है कि वहाँ शायद २०० से अधिक व्यक्तियों के पास निजी मोटरे नहीं हैं । किन्तु अगर कोई मोटर को टैक्सी की तरह इस्तेमाल करे यानी उससे रुपया कमाये तो वह पूंजी बन जाती है और रूसी जनता को पूंजी रखने का कानूनी अधिकार नहीं । वहाँ के नागरिक अपने या परिवार के लिए धन या व्यक्तिगत सम्पत्ति रख सकते हैं किन्तु उसका वे पूंजी के रूप में उपयोग नहीं कर सकते ।

रूस की सरकार रूस का एकमात्र पूंजीपति है । आज रूस में हमेशा से ज्यादा सामूहिकता है और उड़ती नज़र डालने वाले प्रेक्षक चाहे कुछ भी कहे, रूस में पूंजी पर से सरकारी अधिकार के हटने की कोई प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती ।

प्राइवेट पूंजीवाद के विरोधी प्राइवेट पूंजीवाद में अनेक बुराईयाँ बताते हैं और उनका कहना ठीक भी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्राइवेट पूंजीवाद के समाप्त हो जाने पर कोई नई बुराई पैदा ही नहीं हो सकती ।

सोवियत् बुराईयों का एक कारण उसका कार्य-प्रलोभन है । बोलशेविक कितने ही निरर्थक प्रलोभन उत्पन्न करते रहते हैं, जैसे राष्ट्र की सेवा और किमी हित के लिए मर मिटना । निस्सन्देह इन बातों का प्रभाव पड़ता है । इसके अलावा रूसी पदक, प्रचार और पुरस्कारों का प्रलोभन देकर नागरिकों को कार्य करने के लिए उत्साहित करते हैं । किन्तु रूस में तीन प्रलोभन मुख्य हैं और वे सभी व्यावहारिक हैं । ये हैं—वेतन, विशेष अधिकार और शक्ति ।

सोवियत् सरकार हमेशा भिन्न-भिन्न प्रकार के कामों के लिए भिन्न-

भिन्न पारिश्रमिक देता रहा है। यदि किसी व्यक्ति में अधिक योग्यता होती है या वह काम को अधिक अच्छी तरह से सीखे हुए होता है या उसमें कोई विशेष प्रतिभा होती है तो उसे इसका विशेष पुरस्कार मिलता है। किंतु इधर कुछ सालों से सबसे अधिक और सबसे कम वेतन पानेवाले व्यक्तियों में अंतर बढ़ गया है। १८ मार्च १९४६ को अमेरिकन समाचार पत्रों में प्रकाशित एक रिपोर्ट में, जो रूस गये हुए एक प्रतिनिधि-मण्डल ने भी और जो पूरी तरह से रूस के पक्ष में है, बताया गया है कि वहाँ के मजदूरों को एक प्रति-रूपक फैक्टरी में तीन सौ से लेकर तीन हजार रूबल तक मिलते हैं।

आजकल रूस में रुपए के प्रलोभन पर अधिक-से-अधिक जोर दिया जा रहा है। कुछ नगण्य उदाहरणों को छोड़कर, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों और किसानों को काम के हिसाब से वेतन मिलता है। कारखानों के मैनेजर और खानों के डाइरेक्टर मरकाही कारोबार के उत्पादन में जितनी वृद्धि करते हैं उसके लिए उन्हें उसी हिमाय से प्रतिशत बोनस मिलता है। युद्ध के दिनों में हवाई छतरी से उतरने वाले एक रूसी सैनिक को हर बार युद्ध के लिए कूदने पर एक महीने की अलग तनख्वाह मिलती थी। किसी उच्च-सैनिक अधिकारी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को सरकार से बड़ा जबरदस्त भत्ता मिलता है। उदाहरण के लिए २७ फरवरी १९४२ को मेजर जनरल लेवाशेव के परिवार को और १२ मार्च १९४२ को वाइस कमिश्नर कार्टूरोव के परिवार को बीस-बास रूबलों की रकम में मजूर की गई और इसके अलावा मृत अफसर की पत्नी को पाँच सौ रूबल और उसके प्रत्येक बच्चे को तीन सौ रूबल की माहवारी पेशन दी गई (यह स्मरण रखने योग्य बात है कि रूस के एक साधारण मजदूर को फी महीने पाँच सौ रूबल मिलते हैं।) यह दो फुटकर उदाहरण हैं जो रूस के दैनिक समाचार पत्रों से ले लिये गए हैं। “प्रवदा” के ११ अप्रैल सन् १९४२ के अंक में छपे हुए समाचारों के अनुसार एक लाख से दो लाख रूबल तक के ‘स्टालिन-पुरस्कार’ कितने ही वैज्ञानिकों को दिये गये। इसी प्रकार अगले दिन के “प्रवदा” में यह समाचार छपा कि कितने ही कलाकार और लेखकों को पचास हजार से लेकर एक लाख रूबलों के पुरस्कार दिये गए।

आर्थिक पुरस्कार को यह असमानता पारिश्रमिक रूप में दी जाने वाली अन्य विशेष सुविधाओं के कारण और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। इन विशेष सुविधाओं में अच्छे मकान, अच्छे कमरे, गरमी के दिनों के लिए विनोद-गृह, अच्छे अस्पतालों में पहुँच, रेलगाड़ियों में मुफ्त यात्रा, मोटरों इत्यादि

का प्रयोग आदि शामिल हैं। एक देश में जहाँ ऐश्वर्य के साधन दुर्लभ हैं, रहने के लिए कमरे का या चढ़ने के लिए मोटर का मिलना या किसी अच्छे कम भीड़-भाड़ वाले अस्पताल में चिकित्सा पा सकना निस्संदेह विशेष महत्व की बात होती है।

अमीर और गरीब में जितना भेद सोवियत रूस में है, उतना पूँजीवादी देशों में भी नहीं। स्टालिन को साधारण वेतन मिलता है और वह शायद कभी रुपया छूने भी नहीं, फिर भी एक मनुष्य को जितने भी पदार्थों की आवश्यकता हो सकती है वे सब उन्हें उपलब्ध हैं। स्टालिन उतने ही सुख से रहते हैं जितने सुख से रुजवेल्ट रहते थे। इसके विपरीत एक रूसी मजदूर को एक अमेरिकन मजदूर की तुलना में बहुत ही कम सांसारिक सुविधाएँ प्राप्त हैं।

सोवियत जनता के जीवन-मान की यह असमानता कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह पूर्व आयोजित है। १९ वीं शताब्दी के दूसरे शतक के मध्य में रूसी लेखकों ने समानता को बोरजुओं की सकीर्णता और जनतंत्री मूर्खता कह कर हंसी उड़ानी आरम्भ की। उसके बाद से जीवन मान की असमानता का सरकार ने जान बूझ करके विकास किया है। इसका उद्देश्य केवल औद्योगिक और कृषि सम्बन्धी उत्पादन को बढ़ाना ही नहीं बल्कि रूस में एक विशेष अधिकार--विशेष व्यक्तियों की श्रेणी स्थापित करना है। यह श्रेणी अब सोवियत रूस में विद्यमान है।

रूस में जीवन-मान के निम्न होने के कारण और उसे उठाने में कठिनाई देखकर स्टालिन ने जान-बूझ कर शिष्ट जनो की एक नई श्रेणी बनाई। जब सभी व्यक्ति सतुष्ट किये जा सकते हैं तो इस बात की आवश्यकता नहीं कि कोई किसी अल्पसंख्यक उच्चश्रेणी के लिए विशेष रूप से कष्ट करें, किंतु जहाँ जनता को इतनी सुविधाएँ नहीं दी जा सकती कि वह सतुष्ट रह सके वहाँ नानाशाहों को अपने समर्थन के लिए एक उच्च वर्ग की आवश्यकता होती है। रूस में इस उच्च-वर्ग में सैनिक अफसर, गुप्त पुलिस के प्रधान अधिकारी, औद्योगिक मैनेजर, (अपेक्षाकृत कम संख्या में) चतुर और अधिक वेतन पाने वाले मजदूर, इंजीनियर और वैज्ञानिक शामिल हैं। इनके अलावा इस वर्ग में उच्चतम सरकारी अफसर, कम्युनिस्ट दल के कार्यकर्ता और वे कलाकार और लेखक भी शामिल हैं जो सरकार और प्रचार का काम करते हैं। कुल मिलाकर इस वर्ग में ४० लाख व्यक्ति और उनके अनगिनत आश्रित हैं। यूरो-पियन जीवन-मान की कसौटी पर कसे जाने पर भी उनका जीवन यापन सतोषजनक है और साधारण नागरिकों से तो वे कई गुने अच्छे हैं ही।

एक राष्ट्र का जीवन-मान कितने ही तत्त्वों के जटिल मिश्रण से तैयार होता है। अन्न, कपड़ा, और घर इनमें मुख्य हैं। स्थायी नौकरी का होना भी जरूरी है। रूस के जो नागरिक स्वस्थ होते हैं, उनके मस्तिष्क में कोई विकार नहीं होता और राजनीतिक दृष्टि से जो आज्ञाकारी होते हैं, उन्हें सरकार की ओर से यह आश्वासन प्राप्त होता है कि वे कभी बेकार नहीं रहेंगे। यह एक बहुत बड़े लाभ की बात है।

पहले मैं सोचा करता था कि रूस में बेकारी की अनुपस्थिति समाजवाद या लाभ न लेने की प्रवृत्ति के कारण है। किंतु आज मेरा ऐसा विश्वास नहीं। सन् १९२२ और १९२४ के बीच प्रजातंत्री जर्मनी में भी बेकारी बिल्कुल नहीं थी। नाजियों के समय में भी इस शताब्दी के तीसरे शतक में जर्मनी में बेकारी नहीं थी। इसी तरह लगभग समस्त युद्ध में अमेरिका, इंग्लैंड और नाजी जर्मनी में बेकारी नहीं थी।

रूस, जर्मनी और दूसरे रण-रत राष्ट्रों में जितने दिनों बेकारी न रही उतने दिनों नीचे लिखी दो बातें उनमें समान-रूप में उपस्थित थी—(१) निर्यात या बड़े उद्योगों के विस्तार या युद्ध के लिए अधिक उत्पादन और (२) उपभोक्ताओं के लिए सामान की कमी। इन दोनों बातों के परिणामस्वरूप मूल्यों में वृद्धि हो गई।

सन् १९२४ में जब मार्क का सिक्का स्थिर बना तो जर्मनी में बेकारी फिर दिखाई देने लगी। इसीलिए सन् १९२४ और १९२८ के बीच जब रूबल का सिक्का स्थायी रहा तो रूस में भी बेकारी रही और सरकार ने नौकरी दिलाने वाली संस्थाएँ स्थापित की। किंतु सन् १९२८ में पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप रूस में उत्साहपूर्ण औद्योगिक निर्माण का एक नया युग आरम्भ हुआ। रूबल का मूल्य घट गया और सन् १९३१ तक मूल्यों की वृद्धि पूरे जोर पर पहुँच गई। अन्न और उपभोक्ताओं के काम में आने वाले दूसरे सामान बहुत दुर्लभ हो गए और बेकारी दूर हो गई।

मेरा कहने का यह अभिप्राय नहीं कि दुर्भिक्ष और मूल्यारोहण के समय ही बेकारी दूर हो सकती है। किंतु अब तक ऐसा हुआ है कि जहाँ जहाँ भी उक्त परिस्थितियाँ प्रस्तुत रही हैं वही-वही बेकारी भी नहीं रही है।

जब पैदा की जाने वाली सभी वस्तुओं के खरीदार होते हैं तो स्वभावतः बेकारी दूर हो जाती है। बेकारी का न होना और उत्पादित पदार्थों का पूर्ण वितरण साथ-साथ चलता है। सैद्धान्तिक दृष्टि से, समाजवादी देश में पदार्थों का सदा ही पूर्ण वितरण होना चाहिए। किंतु देखा यह गया है कि

पूर्ण वितरण उसी समय सम्भव हो सका जब वितरण के लिए पदार्थों की कमी थी, जैसे, प्रजातन्त्र-कालीन जर्मनी में या सन् १९३१ के बाद के सोवियत रूस में या युद्ध-रत देशों में। प्रश्न यह है—क्या बहुलता के युग में भी पूर्ण वितरण सम्भव होगा ? रूस से इसका कोई उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि क्रान्ति के बाद से रूस में कभी अन्न, कपड़े या मकानों का बाहुल्य नहीं रहा। बोलशेविक क्रान्ति दुर्लभता के ही युग में हुई।

तो फिर क्या कारण है कि युद्ध में रूसी इतनी अच्छी तरह से लड़े ? क्या इससे यह सिद्ध नहीं होता कि वे सतुष्ट थे ?

विन्सटन चर्चिल के निर्देश में अग्रेज बड़ी बहादुरी के साथ लड़े और उन्होंने शत्रु का विरोध बड़ी कुशलता के साथ किया। किन्तु बाद में उन्होंने चर्चिल को पदच्युत कर दिया। रूसी जनता भी स्टालिन के लिए उतनी ही लड़ी जितनी ब्रिटिश जनता चर्चिल के लिए या अमेरिकन जनता रूजवेल्ट के लिए। युद्ध कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है। भारतीय सेना ने युद्ध में इतना जो श्रम किया वह इसलिए नहीं कि उसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद से प्रेम था।

जटिल, दार्शनिक, भावुकता-पूर्ण और व्यावहारिक प्रेरणाओं के कारण मनुष्य युद्ध करने और मरने को तैयार हो जाता है। स्पेन के गृह-युद्ध में अन्तर्राष्ट्रीय ब्रिगेड के अलावा, जिसमें मैंने भी नाम लिखवाया था, फ्रेको के मूर ही सबसे अच्छे सैनिक थे। राज-भक्तों की ओर से लड़ने वाले रूसी टैंक-संचालक मुझ से कहा करते थे कि जब वे अपने गराजों में लौटते थे तो उन्हें अपने टैंकों के दातेदार पहियों में उन मोरक्कन सिपाहियों का मास लिपटा मिलता था जो इतनी अभूतपूर्व और अतिशय शक्तिशाली यांत्रिक शक्ति का सामना करते हुए भी पैर पीछे हटाना नहीं जानते थे। फिर भी मूरों को यह पता नहीं था कि युद्ध क्यों हो रहा है ? यह एक बड़ा ही दुर्लभ दृष्टान्त है जिसमें हमें वीरता और निमित्त में कोई तारतम्य नहीं मिलता। बात यह है कि सिपाहियों के युद्ध में वीरता दिखाने से यह न समझ लेना चाहिए कि वे युद्ध पसन्द करते हैं या उन लोगों का समर्थन करते हैं जिन्होंने उन्हें लड़ने के लिए भेजा है।

जितने अच्छे सेना के अफसर होते हैं उतनी ही अच्छी वह सेना होती है। रूसी सेना के अफसर अच्छे थे। इसके अलावा, रूसी सदा ही अपने आक्रमणकारियों के साथ वीरतापूर्वक लड़े हैं। वे नेपोलियन से लड़े और उन्होंने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। रूसी सेना में उस समय भी आजकल की तरह अधिकांश लोग किसान थे और १९ वीं शताब्दी के दूसरे शतक के किसान दास थे। फिर भी उन्होंने अपने को एक क्रूर जार के युद्ध में मरने दिया। प्रथम विश्व-युद्ध

मे भी रूसियों ने खूब अच्छी तरह लड़ाई लड़ी। यद्यपि उस समय उनके पास साजो-सामान को बहुत कमी थी। अक्सर एक रूसी सिपाही को इस बात की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी कि उसका साथी मरे तो उसे उसकी राईफल मिले। फिर भी रूसियों ने कैसर के पूर्वो मोर्चे को मास्को, पीट्रोग्राड, वोल्गा और काकेशिया से बहुत दूर रखा।

रूसी सिपाहियों को पता था कि सन् १९१८, १९१९ और १९२० में जब उन पर विदेशियों का प्रभुत्व था तो उन पर क्या बीती थी। उनमें से बहुतों ने जनता, कस्बों और गांवों पर क्रूर नाज़ियों के अत्याचार होते देखे थे। रूसी जनता किसी विदेशी विजेता द्वारा शासित होना नहीं चाहती थी। बहुत से लोगो, विशेषतः अफ़सरो को क्रांति से लाभ पहुंचा था। शिक्षा और नौकरी सम्बन्धी अधिक विस्तृत सुविधाओं, देशव्यापी स्वास्थ्य-योजनाओं, पेन्शनो, वार्षिक छुट्टियों और दूसरी सामाजिक सुविधाओं के कारण रूसी जनता की अपनी सरकार के प्रति राजभक्ति दृढतर हो गई थी। जातीय भेदभाव न होने के कारण और अल्पसङ्ख्यकों को भी सांस्कृतिक स्वतन्त्रता मिलने के कारण सरकार के प्रति व्यक्ति की आस्था बढ गई थी। अत्याचार, अत्यधिक श्रम और बलिदान के बावजूद भी अधिकांश जनता ने युद्ध के समय अपने देश का समर्थन किया।

रूसी सेना के कुछ सिपाही फौज को छोड़कर चले गये और उन्होंने अपना शेष जीवन विदेशों में बिताना ज्यादा अच्छा समझा। रूस के कुछ सेनापतियों तक ने सेना को छोड़ दिया और वे नाज़ियों की ओर से लड़े। जहाँ तक मैं जानता हूँ, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या यूरोप के किसी भी अन्य देश में आपको ऐसे एक भी जनरल या उच्च सेनाधिकारी का उदाहरण नहीं मिलेगा जो अपने ही देश के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गया हो। किन्तु मेजर जनरल एन्ड्री ए. ब्लासोव, जिन्होंने सन् १९४१ में मास्को की रक्षा में इतना यश कमाया था, जिन्हें २ जनवरी १९४२ को रूस का उच्च सैनिक सम्मान मिला था, जिन्हें मास्को के 'प्रवदा' पत्र ने अपने ६ जनवरी १९४२ के अंक में "एक विशिष्ट रूसी जनरल" कह कर पुकारा था और जिन्हें सन् १९४२ में नाज़ियों ने गिरफ्तार कर लिया था, हिटलर के हाथ के बिलीने बन गये और उन्होंने रूसियों से लड़ने के लिए जर्मनी-स्थित रूसी कैदियों की एक सेना तैयार की। किन्तु ब्लासोव और उनके ही जैसे कुछ अन्य लोग नियम के अपवाद माने जा सकते हैं, साधारणतः रूसी सेना अपने देश के लिए बड़ी आज्ञाकारिता और योग्यता के साथ लड़ी। रूस के नागरिक

भी अधिकतः देशभक्त थे ।

तानाशाही देश जनता से बलात् आज्ञा-पालन कराने के लिए गुप्त पुलिस और आतंक उत्पन्न करने वाले अन्य शस्त्रों का प्रयोग करते हैं । इसके अलावा जनता की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए वे प्रचार और शिक्षा के अपने एकाधिकार का प्रयोग करते हैं और उन्हें प्रायः सफलता भी मिली है । जनतन्त्री देशों तक में, जहाँ जनता न्याय की माँग कर सकती है और किसी मामले के दोनों पक्ष के वादविवाद सुन सकती है, सरकार के सामने व्यक्ति लाचार ही बना रहता है । तानाशाही देशों में कुछ इने-गिने साहसी व्यक्ति ही अपनी विचार-स्वतन्त्रता या विचार-क्षमता पर किये गए सरकारी प्रहार का विरोध कर सकते हैं । ऐसे देशों में जनता अपने मालिकों का जो समर्थन करती है, उसके आधार पर बड़े-बड़े निष्कर्ष निकाल कर जनतन्त्री प्रेक्षक अक्सर अपने को धोखा देते हैं । स्वयं तानाशाह कभी ऐसे समर्थन से छले नहीं जाते । यदि वे छले जा सकते तो वे गुप्त पुलिस, कान्सेंट्रेशन कैंम्पो, इकतर्फा चुनावों आदि की व्यवस्था तोड़ देने, देश में कहीं, गाँव, रंगी, लिखी और चित्रित की जाने वाली सभी बातों पर से सेंसर उठा लेते, विरोधियों का सफाया न करते, जनता के मस्तिष्क को जीतने या पगु बनाने के अभिप्राय से निरन्तर किया जाने वाला कर्कश सरकारी आंदोलन बढ़ कर देते, नेताओं से जनता को अलग रखने वाली गोपनीयता की दीवार तोड़ देते और निजी सुरक्षा के लिए इतने विस्तृत प्रबन्ध न करते ।

यह अक्सर कहा जाता है कि रूसी सरकार विदेशियों से सशक्त रहती है । यह बात केवल अशतः सत्य है । असलीयत यह है कि रूसी सरकार स्वयं अपने नागरिकों से, यहाँ तक कि अपने उच्च-से-उच्च अफसरों की ओर से भी शक्ति रहती है । यदि यह बात न होती तो वह विदेशी पत्रों को अपने देश में आने से क्यों रोकती ? इस शताब्दी के दूसरे शतक में जर्मनी और ब्रिटेन के पूँजीवादी समाचारपत्र मास्को के स्टोरो और सारे रूस में अनेक स्थानों पर बिकते थे । वोरजुओ के दैनिक पत्र 'बर्लिन टैगेलैट' को मैं यूक्रेन और काकेशस में हमेशा रेलवे स्टेशनों से खरीदा करता था । लेकिन कई साल हुए विदेशी अखबारों का इस तरह बिकना बंद कर दिया गया । अब तो केवल विशेष पुस्तकालयों में, जहाँ विदेशी पत्र भँगाये जाते हैं, कुछ चुने हुए लोग ही इन अखबारों को देख सकते हैं । किसी भी व्यक्ति को ट्रांस्की, बुखारिन या किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति की पुस्तक खरीदने या उधार मागने का अधिकार नहीं, जिसने कभी स्टालिन का विरोध किया हो । क्या कारण है कि रूस के लेखकों, वैज्ञा-

निको और औद्योगिको को सरकारी काम के अलावा और किसी काम से विदेश जाने की इतनी कम अनुमति मिलती है और वह भी विशेष सावधानी करने के बाद ? क्या कारण है कि रूसी सरकार रूसियों को देश से बाहर जाने में रोकती है और शरणार्थियों को देश के भीतर नहीं आने देती ? क्या कारण है कि कुछ थोड़े-से चूने हुए लोगों को ही रूस में विदेशियों से मिलने की अनुमति मिलती है ? क्या रूसी सरकार को इस बात का भय है कि विदेशी लोग हमो जनता को बिगाड़ देंगे ? क्या उसे विदेशियों में इतना कम विश्वास है ? वह क्यों नहीं आशा रखती कि उसकी जनता विदेशियों का मत-परिवर्तन कर लेगी ?

६ जून १९४५ को ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य कमांडर किंग-हान ने ब्रिटिश सरकार से पूछा कि रूस के कितने रेडियो-ब्राडकास्ट प्रति सप्ताह अंग्रेजी में रूस से ब्रिटेन आते हैं और ब्रिटेन के कितने ब्राडकास्ट रूसी भाषा में ब्रिटेन से रूस भेजे जाते हैं । श्री लायड ने सरकारी सूचना विभाग की ओर से उत्तर देते हुए ब्रिटिश लोक-सभा में बताया—“रूस से प्रति सप्ताह ५३ रेडियो ब्राडकास्ट अंग्रेजी में ब्रिटेन आते हैं किन्तु ब्रिटिश रेडियो-स्टेशन बी०बी०सी० से एक भी ब्राडकास्ट रूसी भाषा में रूस नहीं भेजा जाता ।”

बी० बी० सी० से सभी भाषाओं में सभी देशों के लिए ब्राडकास्ट किये जाते हैं । किन्तु रूस के लिए कोई ब्राडकास्ट इसलिए नहीं किया गया कि रूसी सरकार अपनी जनता को विदेशी रेडियो सुनने देना नहीं चाहती थी । कुछ उच्च सैनिक और राजनीतिक नेताओं को छोड़कर रूस में किसी व्यक्ति को ऐसे रेडियो रखने की अनुमति नहीं थी जिससे रूस से बाहर के स्टेशनों के प्रोग्राम सुने जा सकें । इसके अलावा रूस के रेडियो स्टेशन बी० बी० सी० के ब्राडकास्टों को अपने यहां से पुन ब्राडकास्ट करने को तैयार नहीं थे । ब्रिटिश जनता तो प्रति सप्ताह रूस के ५३ ब्राडकास्ट सुन सकती है किन्तु स्टालिन को अपनी जनता पर इतना भी विश्वास नहीं कि वह उसे एक भी ब्रिटिश ब्राडकास्ट सुनने दे ।

रूसी सरकार अपने यहां इस मान्यता को यथासाध्य बहुत ही कम प्रचलित होने देना चाहती है कि विदेशी सरकारों में सोवियत संघ के प्रति मित्रता की भावना है । रूस में, अमेरिका और ब्रिटेन की युद्धकालीन उधारपट्टा व्यवस्था की विशेष चर्चा न किये जाने का एक कारण यह भी है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि यदि विदेशी सरकारें रूस से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखती हैं तो क्या कारण है कि उनसे सम्पर्क नहीं बढ़ाया जाता । रूस में यह तनातनी

या शका की भावना क्यों ?

तानाशाही एक दुर्बल ढंग की शासन-व्यवस्था है। यह जानते हुए भी कि वर्तमान शासन सस्थाएँ इतनी शक्तिशाली होती हैं कि साधारण जाति-काल में जन-काति उन्हें भग नहीं कर सकती तानाशाही शासकों में एक घबराहट-सी रहती है। तानाशाहों को जनता से उस समय तक किसी प्रकार का भय नहीं होता जब तक कि उन्हें पद-च्युत करने की इच्छा रखने वाले कोई दूसरे विरोधी नेता न हों। यही कारण है कि स्टालिन को सब से अधिक परेशानी नेतृत्व की समस्या के कारण रहती है। विरोधियों का अन्त करने के बाद ही उन्हें वर्तमान एकाधिकार का पद प्राप्त हुआ है और वह ऐसे प्रतिद्वन्द्वियों को जिनसे उन्हें अपने हराये जाने या काम में बाधा पड़ने का भय है, लगातार सफाया करते जा रहे हैं। साथ-ही-साथ वह अपने नीचे काम करने वाले व्यक्तियों की आज्ञाकारिता और स्वामि-भक्ति प्राप्त करने की युक्तियों को भी अधिक-से-अधिक पूर्ण बनाने की चेष्टा करते रहे हैं।

रूस जैसे देश में, जहाँ शतको से जनता को कठोर जीवन का सामना करना पड़ रहा है और अभी कई वर्षों तक ऐसी ही परिस्थिति रहने की सम्भावना है, वहाँ यदि विशेष सुविधाओं और भावी प्रलोभनों में फँसाकर उच्च वर्ग के मैन-जरो, फौज, गुप्त पुलिस और दास वृत्ति वाले विद्वानों को सरकारी दफन में बाँधा और सतुष्ट रखा जा सके तो उससे आत्म-विश्वास-विहीन सर्व मत्ताधारी शासक को बड़ी सान्त्वना और सहायता मिल सकती है।

सार्वजनिक कठिनाइयों से प्रभावित न होने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी पहुँच से बाहर रहना। रूस की उच्चवर्गीय जाति को जो विशेषाधिकार और ऐश्वर्य के साधन उपलब्ध हैं उनसे दो मन्तव्य पूरे होते हैं—एक, यह कि वह साधारण जनता से दूर रहती है और दूसरे यह कि वह सामाजिक व्यवस्था में जकड़ दी जाती है।

जीवन का मान उच्च रहने से जनतंत्र को प्रोत्साहन मिलता है। उसके निम्न रहने से अल्पजनीय शासन, उच्च वर्गों की राजसत्ता और तानाशाही को प्रोत्साहन मिलता रहा है। लैटिन अमेरिका, एशिया और यूरोप आज ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं। रूस भी इसका एक उदाहरण है।

रूस में उच्च-वर्गों की नई राजसत्ता का जन्म कैसे हुआ, यह बात वहाँ की सैनिक जाति के प्रादुर्भाव से जानी जा सकती है। प्रत्येक सेना में अफसरों का होना अनिवार्य है और रूसी सेना में भी सदा अफसर रहे हैं। सन् १९३५ तक रूसी सेना के अधिकारियों और अन्य कार्यकर्ताओं में जितना कम भेदभाव

या उतना शायद किसी भी अन्य देश की सेना में नहीं था। किंतु उसके बाद एक बड़ा ही व्यापक परिवर्तन आरम्भ हुआ।

पहले रूस के सेनाधिकारियों की श्रेणी का पता उनके काम से लगता था और वे वैंटेिलियन कमांडर या रेजिमेंट के कमांडर आदि कहलाते थे। किंतु सितम्बर १९३५ में रूसी सेनाधिकारियों को पदवियाँ प्रदान कर दी गईं, जैसे लेफ्टिनेण्ट, कप्तान, मेजर, और कर्नल। ध्यान रहे कि उन्हें जनरल की उपाधि नहीं दी गई। देखने में यह बात सीधी-सादी मालूम देती है। जिस दिन इस नई प्रणाली की घोषणा की गई उसी दिन मेरी रूस के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी लेखक सर्जेंट ट्रेटियाकोव से लम्बी चौड़ी बहस हुई। ट्रेटियाकोव ने इस परिवर्तन का समर्थन तो अवश्य किया किंतु वह उसकी व्याख्या नहीं कर पाये। इस सम्बन्ध में जो सरकारी घोषणा की गई वह बिल्कुल अपर्याप्त थी, उसमें परिवर्तन का कोई कारण नहीं बताया गया था। एक आज्ञाकारी नागरिक की भाँति ट्रेटियाकोव ने एक ऐसी बात यत्नवत् स्वीकार कर ली जिसे वह समझते भी नहीं थे। (ध्यान रहे कि बाद में विरोधियों के सफाये के सिलसिले में वह गोली से उड़ा दिये गये।) उपाधि-दान का जो सबसे अच्छा कारण वह बता सके वह यह था कि अन्य देशों में ऐसा ही होता है।

“किंतु अन्य देशों में तो यह बात सन् १९१८ के बाद से ही है। आपके देश में एकाएक पूँजीवादी देशों की नकल करने की ज़रूरत क्यों आ पड़ी?” मैंने मास्को में होटेल मीट्रोपोल के चौड़े चबूतरे पर इधर-उधर घूमते हुए कहा।

मैंने यह बात स्वीकार की कि अफ़सरो की उपाधियों, विशेषतः कर्नल की उपाधि, का रूस में एक विशेष अर्थ था। उनसे ज़ारशाही यानी पुराने राजतन्त्री रूस का बोध होता था जब कि सैनिक अधिकारियों को साधारण सिपाही का स्वामी बनने का अधिकार था।

“वर्तमान रूस की सेना में यह बात कदापि नहीं हो पायगी”, ट्रेटियाकोव ने जोर देते हुए कहा।

उन्हे यह बात नहीं मालूम थी कि कोई बात छोटे से रूप में आरम्भ होकर किस प्रकार बड़ी-से-बड़ी सीमा तक बढ़ सकती है।

७ मई १९४० को सोवियत अधिकारियों ने जनरल और एडमिरल की पदवियाँ आरम्भ की। स्टालिन किसी काम को थोड़ा-थोड़ा करके करने में बड़े निपुण हैं। वह अपनी नीति को टुकड़े-टुकड़े करके कार्यान्वित करते हैं। सन् १९३५ में कर्नल की श्रेणी तक की उपाधियाँ दी गईं। इसके बाद जनता की

अरुचि को नष्ट करने का अवसर दिया गया और फिर सन् १९४० में जनरल और कर्नल की उपाधियां प्रदान की गईं ।

२१ जुलाई १९४० को एक नये आदेश के अनुसार जनरलों द्वारा युद्ध-क्षेत्र में प्रयोग किये जाने के लिए एक भडकीली वरदी निश्चित कर दी गई, जिसमें सोने के बटनो, गगाजमुनी लेंस और कन्धों के फीतो की व्यवस्था की गई ।

१० अगस्त १९४० को नौ-सेना के कमिश्नर निकोलाई कुजनेटसाव ने, जिनसे स्पेन में सन् १९३६ में मेरा खूब अच्छी तरह परिचय था और जिन्हें मैं एक सीधा-सादा गैर-रस्मी ढंग का जनतंत्रवादी समझता था, आदेश दिया कि भविष्य में नाविक अपनी सेना के उच्च अफसरों से सीधे बातचीत न करे बल्कि अपने ऊपर के निम्न श्रेणी के अफसर से ही सम्बन्ध रखे । उस दिन से परम्परागत सहकारिता और समानता की भावना रूसी सेना से निकल गई । ड्यूटी के समय या परेड के बाद भी अफसरों और नाविकों के बीच एक नई कठोरता दिखाई देने लगी । स्वेच्छिक जनतंत्र अनुशासन की भावना जाती रही ।

१२ अक्टूबर १९४० को रक्षा-कमिश्नर टिमोशेको ने अनुशासन सबधी एक नये कानून की घोषणा की । यह एक दिलचस्प बात है कि मास्को के प्रमुख दैनिक पत्रों 'प्रवदा' या 'इजवेस्टिया' ने इस कानून को नहीं छपा । किन्तु चार दिन बाद लेफ्टिनेण्ट जनरल कुरद्यूमोव ने 'प्रवदा' में इस पर टीका-टिप्पणी की । उन्होंने लिखा—“इस कानून के अनुसार निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को अपने कमांडरो का निर्विरोध आज्ञा-पालन करना होगा । कमांडरो का आदेश ही उनके लिए कानून होगा । चाहे कोई भी कठिनाई, परेशानी और दुर्भाग्य की बात क्यों न हो, उसके कारण कमांडर के आदेश की अवज्ञा नहीं की जा सकेगी । जान-बूझकर अनुशासन भंग करने वालों के प्रति कमांडरो को कठोर-से-कठोर कार्य करने में, यहां तक कि शस्त्रों का प्रयोग करने में भी हिचकना नहीं चाहिए । ऐसे कार्यों के परिणाम का उत्तरदायित्व कमांडर पर नहीं होगा ।” अनुशासन को कार्यान्वित कराने के लिए रूसी सेना के कमांडर शारीरिक दण्ड दे सकते हैं और अपराधी को गोली तक से उड़ा सकते हैं ।

१६ अक्टूबर १९४० के 'प्रवदा' में जनरल कुरद्यूमोव ने लिखा—“कमांडर को उदार बनने या सैनिक नियमों की अवज्ञा की दयालुतापूर्वक अपेक्षा करने का कोई अधिकार नहीं । अधीनस्थ कर्मचारियों के सम्बन्ध में

अशुद्ध जनतंत्रवाद की भावना को पूरे उत्साह के साथ उखाड़ फेंकना होगा ।”

इस अशुद्ध जनतंत्र को ही लोग सदा शुद्ध जनतंत्र समझते आये थे । बोलशेविकों और उनके प्रशंसकों ने, जिनमें मैं भी शामिल था, इसे बोलशेविक क्रान्ति की एक सबसे अद्भुत सफलता कहकर डींग हाकी थी । वस्तुतः वह थी भी ऐसी ही, किंतु क्रान्ति ने जारशाही अतीत के सामने मिर झुका दिया ।

७ जनवरी १९४३ को सोने और चांदी के तांगे से कड़ा हुआ कच्चा-भरण भी रूसी अफसरों की वर्दी का एक अंग बना दिया गया । इस सम्बन्ध में रूसी सेना के दैनिक पत्र ‘रेड स्टार’ ने लिखा—“हम लोग, जो रूस की सैनिक कीर्ति के सच्चे उत्तराधिकारी हैं, अपने पूर्वजों के शस्त्रागार से उन सभी उत्तमोत्तम पदार्थों को ग्रहण करते हैं जिनसे सैनिक भावना में वृद्धि हुई थी और अनुशासन शक्तिशाली बना था ।”

फरवरी १९३१ में स्टालिन ने अपने एक भाषण में रूस की सैनिक कीर्ति की खिल्ली उड़ाई । उन्होंने कहा कि पुराने रूस के इतिहास में पता चलता है कि हमारा देश अपने पिछड़ेपन के कारण सदा ही पराजित होता रहा है । हमें मंगोल खानों ने हराया, तुर्क गवर्नरों ने हराया, स्वीडिश किसानों ने हराया, पोलिश और लियुएनियन जमींदारों ने हराया, अंग्रेज और फ्रांसीसी पूँजीपतियों ने हराया और जापानी अमीरों ने भी हराया ।”

फिर भी १२ साल बाद जारशाही रूस की ‘पराजय’ और ‘विवशता’ कीर्ति बन गई । तानाशाहों के हाथ में इतिहास एक खिलौना होता है ।

६ जून १९४३ को साइरस शल्जवर्गर ने मास्को से ‘न्यूयार्क टाइम्स’ में निम्नलिखित सदेश भेजा—“अफसरों से अब यह आशा नहीं की जाती कि वे रेलवे स्टेशनों के निकटवर्ती स्थानों को छोड़कर और कहीं पार्सल या अस-बाब लेकर चलेंगे । उनसे अधिक-से-अधिक अपने बाये हाथ में एक छोटा-सा साफ-सुथरा बडल लेकर चलने की आशा रखी जाती है ।” किपलिंग के भारत में भी अफसर बडल लेकर चलने से बचते थे ।

शल्जवर्गर ने यह भी लिखा—“गाड़ियों आदि में बड़े अफसरों के खड़े रहते हुए छोटे अफसरों को बैठने की अनुमति नहीं । बैठने के लिए उन्हें अपने बड़े अफसरों से अनुमति लेनी चाहिए । प्लैटून कमांडर की श्रेणी से ऊपर वाले सभी अफसरों के लिए अरदलियों की व्यवस्था की गई है । यह बात सरकारी रूप से बताई गई है कि सबसे पहले पीटर महान् ने अरदलियों की आवश्यकता का अनुभव किया था । इन अरदलियों का मुख्य कार्य अफसरों के निजी मामलों—भोजन, वस्त्र आदि—का ध्यान रखना था ।”

इसके बाद इस नीति के कुफल दिखाई दिये । २४ जुलाई १९४३ को एक सरकारी आज्ञा में बताया गया कि अफसरो को तरक्की देने के लिए युद्ध-क्षेत्र में वीरता दिखाना अनिवार्य गुण नहीं माना जायगा । अब के बाद से तरक्कियाँ सैनिक स्कूलों के विशारदों को ही दी जायगी ।

सन् १९४३ में सोवियत् सरकार ने काउंट सुवोरोव के नाम पर सुवोराव स्कूल खोले, जिनमें भरती होकर लड़के सैनिक नेता का जीवन आरम्भ कर सकते थे । काउंट सुवोरोव एक जारकालीन फील्ड-मार्शल थे । उनका जन्म सन् १७२९ में हुआ था और मृत्यु सन् १८०० में हुई । ७ नवम्बर १९४३ के 'न्यूयार्क टाइम्स' में राल्फ पार्कर ने लिखा—“ये स्कूल जारकालीन सैनिक शिक्षालयों, स्कूलों की प्रणाली पर स्थापित किये गये हैं । इनमें मुख्यतः युद्ध में काम आये अफसरो के लड़के ही पढ़ेंगे ।” ध्यान रहे मृत अफसरो के लड़के, मृत सिपाहियों के लड़के नहीं । जातीय भेद-भाव का प्रचार ऐसी ही बातों से होता है । ७ नवम्बर १९४५ को सोवियत् इतिहास में पहली बार सुवोरोव स्कूल के लड़के जिनकी औसत आयु १२ वर्ष की थी, सेना के साथ परेड करते हुए लाल चौराहे से गुजरे ।

मॉरिस हिन्डस ने, कालनीन नगर के पास एक सुवोरोव स्कूल का निरीक्षण करने के बाद “हैरल्ड ट्रिब्यून” के १६ मई १९४३ के अंक में लिखा—“इस स्कूल में नागरिक और ग्रामीण नृत्य को भी उतनी ही प्रधानता दी जाती है जितनी खेल-कूद को ।” इसी तरह रैल्फ पार्कर ने भी अपने लेख में बताया, “रूसी सेना के दैनिक ‘रेड प्लॉट’ ने अभी हाल ही में यह सलाह दी थी कि रूसी जल-सेना के भावी अफसर नृत्य की भी शिक्षा ग्रहण करें । भविष्य में वे रूसी शिक्षित वर्ग के सर्वोत्तम व्यक्तियों के प्रतिनिधि बनेंगे । इसलिए उन्हें समाज का आचार-व्यवहार सीखना चाहिए । किन्तु कैसा समाज ?”

रैल्फ पार्कर ने अपने लेख में आगे बताया—“जैसा कि ‘रेड स्टार’ ने हाल में ही लिखा था, सोवियत् अफसरो को पुरानी परम्पराओं में बहुत-सी ऐसी बातें दिखाई देती हैं जिनसे उन्हें रूसी सैनिक-बल के उद्गम और विकास का स्पष्ट ज्ञान होता जा रहा है । रूसियों को अब यह बात याद आ रही है कि पीटर के जमाने में अफसरो में अपने सच्चे सम्मान की भावना जाग्रत हो गई थी । वर्तमान रूस पर जितना प्रभाव पीटर का है उतना लेनिन को छोड़कर किसी भी दूसरे पूर्वकालीन रूसी का नहीं ।” तो इसका अभिप्राय यह है कि कम्युनिस्ट रूस सत्य सम्मान की भावना पीटर महान् से ग्रहण कर रहा है, जिन्होंने रूस पर सन् १६६४ से सन् १७७५ तक राज्य किया और अपने

नगरो और महलो को बनवाने में लाखों कृषक दासों को मार डाला ।

१६ सितम्बर, १९४५ को ट्रुस एटकिन्सन ने मास्को से 'न्यूयार्क टाइम्स' को निम्न लिखित तार दिया—“रूसी सेना के क्लव अब केवल अफ़सरो के प्रयोग में आ सकेंगे । पहले सेना के सभी लोगों को इन क्लवों को प्रयोग में लाने का अधिकार था ।” ये क्लव, जिनमें से अधिकांश बड़े ही सुन्दर बने हुए हैं और ठाठदार मेज कुरसी आदि से सुशोभित हैं, रूस के अनेक नगरों में स्थित हैं और पहले इनमें अफ़सरो के अलावा दूसरे कर्मचारी भी जा सकते थे । किंतु सेना के साधारण कर्मचारी, जन्हें अच्छा अन्न-वस्त्र नसीब नहीं होता, निम्न कोटि के “मजदूर” समझे जाते हैं और उन्हें अब क्लवों में जाने का अधिकार नहीं ।

‘रेड स्टार’ का कहना है—“कम्युनिस्ट पार्टी और रूसी सरकार जनरलों और दूसरे अफ़सरो के जीवन-मान को उच्च बनाने की लगातार चेष्टा कर रही हैं ।”

उस गोल कमरे का विवरण देते हुए जिसमें अमेरिका और रूस में शतरज का मैच हो रहा था, ‘इजवेस्तिया’ ने अपने २ जून १९४५ के अंक में लिखा—“दर्शकों में बहुत-से अफ़सर भी थे ।” इजवेस्तिया ने प्राइवेट व्यक्तियों का कोई उल्लेख नहीं किया । दस साल पहले किसी रूसी पत्र में इस प्रकार की बातों के छपने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी । यह बात एकदम बोलशेविक-विरोधी मानी जाती । यह है भी बोलशेविक-विरोधी ।

मेजर-जनरल जॉन आर डीन ने, जो युद्ध-काल में दो वर्ष तक मास्को में अमेरिकन सैनिक मिशन के प्रधान की हैसियत से रहे, नवम्बर १९४५ में मास्को से लौटने से कुछ ही दिन बाद न्यूयार्क की एक सभा में कहा—“अफ़सरो और दूसरे सैनिक कर्मचारियों में जितना अन्तर रूसी सेना में है उतना सप्ताह के किसी भी दूसरे देश की सेना में नहीं ।”

रूस के इंजीनियरों, कम्युनिस्टों, दली नेताओं, उच्च सरकारी अफ़सरो, और मिल मालिकों का आर्थिक जीवन-मान साधारण जनता के आर्थिक जीवन-मान से बहुत ज्यादा ऊँचा है । ‘लाइफ’ (जीवन) नामक पत्र में जान हेरसी ने निकालाई पुजीरेव से अपनी मुलाकात का वृत्तान्त छापा है । पुजीरेव लेनिनग्राड की पुटिलोव इस्पात कारखाने के मैनेजर थे और एक चार कमरे वाले मकान में रहते थे । उनका मकान एक घनी आबादी वाले शहर में था, जहाँ चार-चार प्राणियों के कितने ही परिवार एक एक कमरे में गुजारा कर रहे थे । उनके पास निजी इस्तेमाल के लिए एक मोटर, एक शोफर, एक हवाई जहाज, एक

जल-विहार नौका, एक ग्रामीण घर, दो नौकर, और बहुत मात्रा में भोजन और शराब थी। थियेट्रो में उनके लिए सबसे अच्छी सीटें रिजर्व हुआ करती थी।

सन् १९३२ में मैं पुटोलोव कारखाने में एक सप्ताह रहा और सन् १९-३६ तक अक्सर गर्मियों के दिनों में वहाँ चला जाया करता था, ताकि वहाँ के होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कर सकूँ। मैं उसके डाइरेक्टरो, इंजीनियरो, दलीय अफसरों और मजदूरों से परिचित था। सन् १९४४ में जब रूसियों और नाजियों में भयंकर युद्ध हो रहा था, श्री पुजीरेव जिस ऐश्वर्य के साथ रह रहे थे उसका सादृश्य शांति-काल में भी नहीं मिलता।

पूँजीवाद के कारण निर्धनता के पार्श्व में ही अतिव्ययता का जन्म होता है। रूस में तो उच्च और निम्न वर्गों का बड़ा हुआ महान् अन्तर और भी अधिक असंगत है क्योंकि वहाँ उच्च वर्गों से आशा की जाती है कि वे निम्न वर्गों के सहकारी और सेवक की हैसियत से काम करेंगे। समानता असम्भव या अवाछनीय हो सकती है, किन्तु जब बोलशेविज्म से उत्पन्न शासन-संस्था धनी और गरीब में बढ़ते हुए अन्तर को प्रोत्साहन देती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो क्रांति-तत्त्व का आधार ही जाता रहा।

फिर भी सोवियत् सभ में सर्वोच्च और निम्नतम आर्थिक स्तर में जो महान् अन्तर है वह उस खाई की तुलना में कुछ भी नहीं जो वहाँ के राजनीतिक शक्ति-सम्पन्न तानाशाही को राजनीतिक शक्तिविहीन व्यक्ति से अलग करती है। सोवियत् सभ में शासन का अधिकार जितना अधिक केन्द्रित है उतना सत्तार के किसी भी अन्य देश में नहीं।

निरंकुश शासन परोपकारी बन सकता है। वह जनता के लिए और जनता का हो सकता है किन्तु जनता द्वारा चलाया नहीं जा सकता। जनतन्त्र ही एक ऐसा शासन है जिसका संचालन जनता कर सकती है। वह समाजवाद निरर्थक है जिसके अधीन रहकर जनता शासन-निर्देश में सक्रिय भाग न ले सके। लेनिन ने कहा था—“प्रत्येक रसोइये में शासन-संस्था को संचालित करने की योग्यता होनी चाहिए।”

प्रत्येक रसोइये, प्रत्येक खान-मजदूर, प्रत्येक गाड़ीवान और प्रत्येक किसान को बोलशेविक क्रान्ति के फलस्वरूप एक उच्चता की भावना का अनुभव हुआ, क्योंकि उसने समझा कि बोलशेविक सरकार उसकी अपनी सरकार है और वह उसके प्रबन्ध में सहायता दे सकता है। शासनिक कार्य का अधिकार रखने वाली रूसी म्यूनिसिपलिटियो या कौंसिलों की कल्पना इस

आधार पर की गई थी कि इनके द्वारा शासन-संस्था में जनता का व्यापक प्रवेश कराया जा सकेगा। क्रांति के लिए जितना व्यापक उत्साह इन कौन्सिलों द्वारा उत्पन्न हुआ उतना जमींदारी प्रथा नष्ट करने से नहीं। स्वभावतः जनता को यह बात मालूम थी कि उस सबसे बड़ा लाभ उन पदार्थों का नहीं है जो सरकार उसे देती है बल्कि इस बात का कि उसका सरकार के ऊपर नियंत्रण है और इसलिए सरकार उससे अपने उपहारों को वापिस नहीं ले सकती।

सन् १९२३ में मैं मास्को के पास एक छोटे में कस्बे में गया। वहाँ मैं कुछ समय के लिए एक बड़े स्थानीय जज के घर ठहरा। मैंने उनकी पत्नी से, जिन्हे बोल्शेविकों में सहानुभूति नहीं थी, पूछा कि बोल्शेविक क्रांति के कारण संसार में क्या परिवर्तन हुआ है।

“लोग बातें अधिक करने लगे हैं”, उन्होंने घृणा के भाव में कहा।

यह क्रांति की प्रधान सफलता थी। लोग अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में बातचीत करते थे, क्योंकि उन्हें ख्याल था कि उनके विचारों का भी कुछ मूल्य है।

भावनाओं का एकीकरण क्रांति का मूल आयोजन था। अतीत का नाश उनका कारण बना। आशा ने उसे शक्तिशाली बनाया। मैं समझता हूँ कि उसकी उत्पत्ति मुख्यतः व्यक्ति के समाज में समा जाने की अनुभूति के कारण हुई। जिसके फलस्वरूप वह समाज का एक अंग बना और अपने से ऊपर उठ गया।

फिर भी सन् १९१७ के बाद कुछ ही दिनों के भीतर-भीतर इस की कौंसिल आदि अपने यहाँ उन कम्युनिस्टों की अधीनता में पूर्ण रूप से आगई जो मास्को और प्रान्तीय राजधानियों के आदेशानुसार कार्य कर रहे थे। आज ये संस्थाएँ क्रेमलिन (रूसी शासन-संस्था) की खडकी की मुहर मात्र हैं और अब मनुष्य के जीवन में उनकी वास्तविकता नहीं रह गई। उनके चुनाव बड़े ही व्यस्त ढंग से होते हैं जिसमें कम्युनिस्टों का कभी विरोध नहीं किया जाता।

जो दशा इन संस्थाओं की हुई वही कुछ दिनों बाद कम्युनिस्टों की भी हुई। क्रांति के प्रारम्भिक काल में कम्युनिस्ट दल में कम्युनिस्टों को व्यापक आज़ादी प्राप्त थी। सन् १९१८ के आरम्भ में जब कैसरीय जर्मनी और नई बोल्शेविक सरकार में ब्रेस्ट-लिटोवस्क में बातचीत आरम्भ हुई तो सोवियत सरकार बड़ी कमजोर थी। खतरा भीतर से भी था और बाहर से तो जर्मनी रूस पर आक्रमण करने को तैयार बैठा ही हुआ था। फिर भी, उस जीवन और मरण के संघर्ष में कम्युनिस्ट नेताओं के एक दल ने, जिनमें रेडेक,

कोलोनवाई और ओसिंग्की भी थे, मास्को में 'कम्युनिस्ट' नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया। इस पत्र का उद्देश्य लेनिन द्वारा साम्राज्यवादी जर्मनी के प्रति दिखाई जाने वाली शान्ति-नीति को पराजित करना था।

बाद में कम्युनिस्ट-कान्फ़ेसो में लेनिन का बुखारिन और दूसरे कम्युनिस्टों से भीषण वाक्-युद्ध होने लगा। किंतु सैद्धान्तिक रूप से बुखारिन को पराजित करने के बाद भी लेनिन उनके गले में प्यार से अपनी बाहे डाल लेते थे और उन्हें बुखाश्का कहकर पुकारते थे। क्रांति से पहले सैद्धान्तिक मामलों पर लेनिन और ट्राट्स्की की भी कई बार लड़ाई हुई, किंतु क्रांति के बाद उन दोनों ने बड़े घनिष्ठ सहयोग के साथ काम किया।

लेनिन ने कम्युनिस्ट-विरोधियों से बहस-मुवाहसा किया और उन्हें हरा दिया। लेनिन में कुछ ऐसे निजी गुण थे जिनके कारण वह अपने से कुछ बातों में मतभेद रखने वाले लोगों के साथ भी काम कर सकते थे। स्टालिन वादविवाद में ट्राट्स्की या जिनोवीव को हरा नहीं सकते थे। किंतु वह उन्हें गिरफ्तार कर सकते थे।

सन् १९१७ में लेकर १९२६ तक रूस की गुप्त पुलिस का मुख्य काम क्रांति के विरोधियों का अन्त करना था। सन् १९२० में रूसी गुप्त पुलिस ने स्टालिन के आदेशानुसार एक ऐसा कार्य आरम्भ किया जो बोलशेविक इतिहास में अभूतपूर्व था। उसने कम्युनिस्टों का अन्त करना आरम्भ किया। जब जनवरी १९२८ में पुलिस गुप्तचर ट्राट्स्की को उसके मास्को-स्थित घर से उठाकर सीढ़ी से नीचे ले गये तो उस पर किसी ने स्टालिन द्वारा शासित कम्युनिस्ट दल के साथ राजनीतिक और सैद्धान्तिक मतभेद प्रकट करने के अलावा और कोई अपराध नहीं लगाया। सरकारी दबाव के साधन द्वारा इस प्रकार किसी दलीय झगड़े में हस्तक्षेप करने का यह पहला ही उदाहरण था। लेकिन उसके बाद यह एक साधारण प्रथा बन गई है। अब कम्युनिस्ट दल में वाद-विवाद निरर्थक समझा जाने लगा है। स्टालिन के रूस में पुलिस गुप्तचर का रिवाज ही सिद्धान्त सम्बन्धी निर्णायक तर्क है।

किसी समय, ट्राट्स्की, कमेंनेव और जिनोवीव जैसे कम्युनिस्ट विरोधियों को अपना मत सार्वजनिक रूप से व्यक्त करने की अनुमति थी। सोवियत नेताओं और नीतियों के विरोध में वे पुस्तकें या लेख लिख सकते थे। कम्युनिस्ट दल की कांग्रेसों और कान्फ़ेसों के अवसरों पर कम्युनिस्ट दल के मुख-पत्र 'प्रवरा' में "वाद विवाद" का एक विशेष पृष्ठ छपता था, जिसमें विरोधी दल वाले अपना मत प्रकट कर सकते थे। अब तो कम्युनिस्ट दल के किसी भी

सदस्य को इतना साहस नहीं कि वह अपने को विरोधी घोषित करे और सरकारी नीति की आलोचना करने का अधिकार माँगे ।

कम्युनिस्ट दल में लाखों सदस्य हैं । इनकी सन्ध्या और भी बढ़ सकती है किन्तु दल की सदस्यता सीमित है । पद और श्रेणी तो इस दल की सभी बड़ी मशीन में पहियों के निष्क्रिय दातों के समान हैं । स्टालिन अपनी पार्टी को कुछ बताना या उससे सलाह लेना भी पसन्द नहीं करते । सन् १९१८ से १९२५ तक युद्ध और उपद्रव के बावजूद भी पार्टी की कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होता था । उसके बाद स्टालिन तानाशाह बने । पार्टी कांग्रेस का अधिवेशन सन् १९२६ में दो साल के विश्राम के बाद हुआ । १६ वां अधिवेशन १९३० में, १७ वां १९३४ में और १८ वां १९३९ में हुआ ।

सफाये के कारण सोवियत् कम्युनिस्ट दल की प्रेरणा और मर्यादा मारी गई । लोगों ने सोचा कि जब श्रेष्ठतम कम्युनिस्ट भी “फाशिस्ट” और “विदेशी शक्तियों के एजेंट” बन सकते थे तो यह बात कैसे कही जा सकती है कि जिन लोगों का सफाया नहीं किया गया उनमें भी उतनी ही गदगी नहीं है ? सच पूछिये तो जिन लोगों ने सफाया किया था उनमें से कितनों पर एक साल बाद ही मुकद्दमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा दी गई ।

कम्युनिस्ट दल अब तानाशाह का आपसे-आप चलनेवाला हथियार बन गया है ।

पहले सोवियत् मजदूर सघों में भी स्वतंत्रता पूर्वक वाद विवाद हुआ करते थे । हर साल भिन्न-भिन्न उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के सघों की सभाएँ हुआ करती थी और उनका बड़ा प्रचार किया जाता था । किन्तु सोवियत् मजदूर सघ की बैठक हुए अब पन्द्रह साल हो गए ।

हर साल जनवरी के महीने में कारखानों और दफ्तरों के मजदूर-सघों के सदस्य प्रबधकों से बातचीत करते थे और मोलभाव के एक सामूहिक समझौते पर खुल्लम-खुल्ला विचार करते थे । यह समझौता अगली जनवरी तक चालू रहता था, जब कि उस पर फिर से विचार होता था । सन् १९३१ में मजदूरों को नौकरी देने का अधिकार केवल प्रबधकों के हाथ में रह गया । जनवरी १९३३ में बहुत ही कम समझौतों पर पुनः हस्ताक्षर किये गये । जनवरी १९३४ में इनकी सख्या और भी घट गई और घटते-घटते जनवरी १९३६ में विलकुल शून्य रह गई । सन् १९३६ के आरम्भ में अब तक सोवियत् रूस में एक बार भी सामूहिक मोलभाव नहीं हुआ । नौकरशाही मजदूर सघ सरकार का काम चलाते रहते हैं । यह नौकरशाही विदेशी मजदूर-सघों के ग्रान्दोलनो

में भी काम कर सकती है ।

कम्युनिस्टो, मजदूर-सघो और सोवियत् सरकार के मित्रों की स्वतंत्रता के दमन का विदेशी खतरे से कोई सम्बन्ध नहीं । सन् १९१८ में जब कि रूसी सरकार शक्ति-हीन थी, लोगो को जितनी आजादी थी, उतनी अब उसके एक महान् राष्ट्र बन जाने पर नहीं रह गई है ।

रूसी शासन के अज्ञानी समर्थको को यह कहने की आदत पड़ गई है कि सन् १९३५ से १९३८ के सफायो और मुकदमो में स्टालिन ने 'घर के भेदियो' का अन्त कर दिया । कहा जाता है कि इन्ही सफायो के कारण युद्ध के दिनों में रूस के प्रयत्नों में कोई बाधा नहीं पड़ी । मैं पूछता हूँ कि जब शासन-संस्था के शत्रु देश से निर्मूल कर दिये गए हैं तो फिर क्या कारण है कि जनता को अब भी नागरिक अधिकार नहीं दिये जाते ? क्यों नहीं सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान् गुप्त पुलिस अपना खेल समाप्त करती ?

मैं समझता हूँ कि रूस की स्थानीय कौंसिलो, कम्युनिस्ट पार्टी, मजदूर-सघो की स्वतंत्रता का कुचला जाना तानाशाही का परिणाम है । (यही बात फाशिस्ट इटली और नाजी जर्मनी में भी हुई ।)

रूस की राजनीतिक प्रणाली पहले चौड़े आधार वाली स्तूप-समूह के समान थी । सबसे चौड़ी और सबसे नीचे की सतह पर छोटी-छोटा सभाएँ थी, उनके ऊपर मजदूर-सघ, उनके ऊपर कुछ अधिक सकीर्ण कम्युनिस्ट पार्टी, उनके ऊपर पार्टी का नेता और सबसे ऊपर देश का नेता था । धीरे-धीरे स्टालिन ने इस स्तूप-समूह को उलट दिया और उसे उसकी नोक पर खड़ा कर दिया । अधिक चौड़ी सतहों में पहले जितने भी राजनीतिक अधिकार थे वे नीचे लुढ़क पड़े और बहकर शिखर यानी तानाशाह के साथ जा मिले । जब स्थानीय संस्थाओं, मजदूर-सघो, कम्युनिस्ट पार्टी, और पार्टी-नेता के अधिकार ही जाते रहे तो उनकी शक्ति, उनकी प्रेरणा, और उनका विश्वास भी नष्ट हो गया । वे एक भयभीत यात्रिक मनुष्य की भाँति काम करने लगे ।

यह एक बड़े मार्क की बात है कि स्टालिन के रूस में कोई महान् वक्ता नहीं हुआ । कम्युनिस्ट दल में कितने ही प्रसिद्ध वक्ता थे; किंतु अब वे भर चुके हैं और रूस को नये वक्ताओं की आवश्यकता नहीं । अब रूस में राजनीतिक-वादविवाद नहीं होते । सभी राजनीतिक मामले कम्युनिस्ट दल की रसोई में किराये के बावचियों द्वारा पका लिये जाते हैं और वक्ताओं को दे दिये जाते हैं । कोई भी इनसे इधर-उधर नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसा करना खतरनाक सिद्ध हो सकता है ।

जिन रूसी नागरिकों में बौद्धिक और राजनीतिक सामर्थ्य होती है वे अपने कन्वों पर "सामाजिक बोझ" भी उठा लेते हैं। वे निरक्षरता को दूर करते हैं, एशियाई स्त्रियों से पर्दा छोड़ने के लिए कहते हैं, लड़के-लड़कियों को स्वयंसेवक और स्वयंसेविका दल में भरती करने के लिए प्रेरित करते हैं, कारखानों और सभाओं में भिन्न-भिन्न विषयों पर बातचीत करते हैं, ऐतिहासिक और पुरातत्त्व संबंधी स्थानों की यात्रा करते हैं आदि, आदि। किंतु कम्युनिस्टों ने यह बात मेरे सामने चुपके से स्वीकार की है कि सोवियत रूस में राजनीतिक हलचल नहीं के बराबर है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को यह महसूस होता रहता है कि वह तो केवल दूसरों के इशारों पर नाच रहा है और 'प्रवदा' में प्रकाशित सम्पादकीय टिप्पणियों को बिना अपना मत या व्यक्तित्व प्रगट किये ज्यों-का-त्यों दुहरा रहा है।

सोवियत जनता के जीवन में कुछ और रोमांच की बातें भी हैं—जैसे, स्टालिनग्राड की विजय का रोमांच, लेनिनग्राड निवासियों के वीरतापूर्ण संग्राम का रोमांच, हिटलर पर विजय पाने का रोमांच आदि। ये उनकी सामाजिक ध्येय और राजनीतिक उद्देश्य संबंधी दिलचस्पियां नहीं हैं, ये उनकी शारीरिक अनुभूतियां हैं; उनकी भूमि, नदी और नगर सम्बन्धी दिलचस्पियां हैं। इनसे हमें पता चलता है कि बोलशेविक क्रांति का क्या हुआ। यह क्रांति राष्ट्रीय इसलिए बनी कि इसे राजनीतिक नहीं रहने दिया गया। राजनीति जनता के लिए नहीं थी। उसका प्रभाव हमारी आदि भावनाओं पर अधिक पड़ने लगा और नये समाज के आदर्श पर कम। जारों और जारशाही जनरलों ने सुधारकों, क्रांतिकारियों और समाज-शास्त्रियों को पकड़कर परदे के पीछे डाल दिया। पीटर महान् कार्लमार्क्स पर छा गए। स्टालिन ने देखा कि रूसियों में अपनी पितृभूमि के लिए पीट्रियन भावनाएँ जाग्रत करना जितना सरल है उतना एक नई अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक प्रणाली के लिए मार्क्सियन भावना जाग्रत करना नहीं।

चूँकि स्टालिन सोवियत जनता को काफी अन्न, वस्त्र और शरण देने में असमर्थ थे और वह उसे सरकारी मामलों में कुछ कहने-सुनने का अधिकार नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे राष्ट्रीयता दी। जो धर्म चाहते थे उन्हें स्टालिन ने धर्म भी दिया। कुछ अल्पसंख्यकों को, जिनकी स्वामि-भक्ति वह खरीदना चाहते थे, उन्होंने पदार्थिक ऐश्वर्य और सामाजिक सुविधाओं की अफीम खिलाई।

फिर भी अभी रूस में राष्ट्रीय धन पर सरकार का ही अधिकार है।

वहाँ अनिवार्यता भी अक्षुण्ण है। यह अनिवार्यता व्यक्ति की अपनी नहीं, बल्कि उससे ऊपर की है। रूस का साधारण जन एक हेतु का साधन मात्र है। वह हेतु रूस की शक्तिशाली राज-सत्ता है।

शरीर समाजवाद का है, किंतु उसमें अब जीव नहीं रहा, क्योंकि उसमें अब आजादी और अन्तर्राष्ट्रीयता नहीं रही।

जनतन्त्र-विहीन समाजवाद तो राज-अधिनायकता है। किसी एक राष्ट्र का समाजवाद, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीयता नहीं होती, राष्ट्रीय समाजवाद है। वह हिटलरवाद नहीं है। प्रत्येक देश का राष्ट्रीय समाजवाद अपने-अपने ढंग का है।

रूस राष्ट्रीय समाजवाद के प्रतिवादों के पक में फँस गया है। स्टालिन ने अपने को इसी द्विविधा से बचाये रखने का प्रयत्न किया है। सन् १९३६ के विधान का निर्माण कर उन्होंने जनतन्त्र की स्थापना करनी चाही; किंतु वह सफल नहीं हो सके। क्योंकि वह अधिनायकत्व की भावना को दबाने और गुप्त पुलिस को हटाने को तैयार नहीं थे। स्टालिन के तानाशाह बनने के बाद से रूस में हर साल जनतन्त्र कम होता जा रहा है। सम्भवतः स्टालिन सोचते हैं कि रूस की सीमाओं को बढ़ाकर या रूसी प्रभाव-क्षेत्र में अधिकाधिक देशों को मिलाकर वह अन्तर्राष्ट्रीयता स्थापित कर रहे हैं। किंतु छोटे-छोटे देशों को दास बनाना, सयुक्त राष्ट्रीय संधि में विशेष मताधिकार पर बल देना और तीन बड़े राष्ट्रों द्वारा आधिपत्य को नीति का अनुकरण किया जाना अन्तर्राष्ट्रीयता नहीं है, वह अन्तर्राष्ट्रीयता से भी बढ-चढकर है—वह साम्राज्यवाद है।

राष्ट्रीय तानाशाही की अधीनता में अन्तर्राष्ट्रीयता और जनतन्त्र नहीं फल-फूल सकते। अतः स्टालिन की अधीनता में समाजवाद नहीं पनप सकता। रूसी समाजवाद का तो नाम-ही-नाम है। वह निर्जीव है। प्राण उसमें से निकल चुके हैं। इसका कारण यह है कि वह अपने उन शिकारों के बोझ से दब गया जो या तो गोली से उड़ा दिये गए थे या अब भी कन्सेनट्रेशन कैम्पों (बंदीगृहों) में पड़े सड़ रहे हैं।

: १७ :

लास्की-शास्त्र

ब्रिटेन में मजदूरदली नेता और प्रकाशक हेराल्ड जे० लास्की मार्क्स के भौतिकवाद की दलदल में फँस गए हैं। इसलिए वह रूस को समझने में असमर्थ हैं। लास्की के विचार से, व्यक्तिगत व्यवसायी और व्यक्तिगत स्वतंत्र बाजार के उन्मूलन से ही समाजवादी सतयुग आजाता है। यह भयंकर भूल है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना समाजवाद सम्भव नहीं है। पूँजीवादी गोपण को मिटा देने के बाद भी आर्थिक दासता और राज्य के राजनीतिक शासन की गुजाइश रह जाती है।

लास्की का ख्याल है कि उत्पात्ति के साधनों पर राज्य का स्वामित्व हो जाने से और राज्य द्वारा आर्थिक योजना बनाने और कार्यान्वित करने से इस बुराई से मुक्त हो गया है। लेकिन यदि राज्य का स्वामित्व आतंकपूर्ण हो तो वह अच्छा नहीं रहता।

लास्की मनुष्य को भूल जाते हैं। सोवियत् मशीनों के सगठन की प्रशंसा करने की धुन में वह सोवियत्-सभ के मनुष्यों के सगठन की उपेक्षा कर देते हैं।

पूँजीवाद को न मानने वाले शिक्षित लोगों में पूँजीवाद का नाश करने वाली प्रत्येक चीज को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं, लास्की सबसे कुशाग्र बुद्धि हैं। ३ दिसम्बर १९४५ को न्यूयार्क में "नेशन" पत्र द्वारा आयोजित एक भोज में लास्की ने कहा था—“यह बात ध्यान देने योग्य है कि केवल रूस की नई दुनिया में व्यवसायी आदमी का महत्त्व नहीं रहा है।” यह सत्य है, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। कितने ही दूसरे लोगों का भी वहाँ कोई महत्त्व नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ केवल एक आदमी, एक तानाशाह ही सब बातों में महत्त्वपूर्ण होता है।

दुबले-पतले और तीखी जुवान वाले लास्की अपने-आपको 'निर्दोष विद्वान्' कहते हैं। उनकी लेखनी प्रस्तर है, जिससे लेखकों के हृदयों में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। वे उसका अनुकरण करने में केवल अपनी कमियाँ प्रकट करके रहें

जाते हैं। वह सुखपूर्वक कार्यक्रम तैयार करते हैं और सुगमता पूर्वक अपने विरोधियों को नष्ट कर देते हैं। मैंने लास्की को फेब्रियन सोसायटी में एक बहुत ही अच्छी तरह से तैयार किया हुआ पांडित्यपूर्ण व्याख्यान देते हुए सुना है और मैंने मजदूरों की चुनाव सम्बन्धी एक सभा में उन्हें अपनी मनोरंजक बातों द्वारा अपने श्रोताओं को हँसाते हुए भी देखा है। लेकिन हेरॉल्ड जे० लास्की के कम-से-कम दो रूप हैं और उन दोनों में आपस में कोई मेल नहीं बैठता। लास्की का दृष्टा रूप वस्तु को यथार्थ रूप में देखता है; किन्तु उसका विश्वास-कर्ता रूप प्रतिभापूर्ण तर्क करता हुआ लास्की के दृष्टा रूप से कहता है कि जो कुछ वह देखता है वह यथार्थ नहीं है।

सन् १९४३ में लास्की ने 'हमारे जमाने की क्रान्तियों पर विचार' नाम की एक जोरदार पुस्तक लिखी थी। इसमें सोवियत रूस की तानाशाही की भयकरताओं और स्टालिन के आतंक की पर्यालोचना कई पृष्ठों में की गई है। सन् १९४४ में उन्होंने 'धर्म, तर्क और सभ्यता' नाम की एक दूसरी पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने 'रूसी विचारों को ससार का रक्षक धर्म' बताया जो कभी ईसाइयत का स्थान ग्रहण कर लेगा।

मैंने 'धर्म, तर्क और सभ्यता' की आलोचना अगस्त १९४४ के 'कॉमन सेन्स' पत्र में की थी। आलोचना का शीर्षक था—'लास्की को इससे अधिक जानना चाहिए।' सम्पादक ने उसकी एक प्रति डाक से लास्की के पास इंग्लैंड भेज दी और उनसे उसका प्रत्युत्तर माँगा था। लास्की ने उत्तर में लिखा—“इस सम्बन्ध में लुई फिशर ने मेरे ऊपर जो चोट की है, उसे मैं उनके साथ अपनी मित्रता के नाते बिना किसी आपत्ति के नम्रता पूर्वक स्वीकार किये लेता हूँ।”

मैं हेरॉल्ड लास्की के साथ अपनी मित्रता को बहुमूल्य समझता हूँ और मैंने विश्वास है कि उस पर इस आलोचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मैंने पुस्तक की आलोचना में लिखा था—“प्रोफेसर लास्की ने एक समाजवादी विचारक के रूप में अपने जीवन की सबसे बड़ी बुनियादी गलती की है। उन्होंने ससार से अनुरोध किया है कि वह रूस के नए विचारों को स्वीकार कर ले, जब कि स्वयं रूस इन विचारों को छोड़ रहा है और पूँजीवादी जगत् के पुराने विचारों को अधिकाधिक स्वीकार करता जा रहा है।”

लास्की ने अपनी नई पुस्तक में कहा है—“नास्तिकता पर ईसाइयत की विजय प्राप्त होने से मनुष्य के विचारों को नई शक्ति मिली है। मैं नहीं समझता कि यदि कोई आदमी सावधानी से हमारे युग की स्थिति की जाँच करे, तो उसे लगातार यह खयाल न हो कि मनुष्य के विचारों को फिर नई

शक्ति देने के लिए फिर किसी धर्म की जरूरत है।" मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन चूँकि नया धर्म इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रत्येक आदमी को सावधानी से चुनाव करना चाहिए। लास्की ने स्वयं चेतावनी दी है कि नए धर्म का आधार राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। वह घोषित करते हैं—"राष्ट्रवाद के लिए नया उत्साह हमें सुगमता से उस मार्ग पर ले जा सकता है जिसके अंत में व्यापक सकट आता है। "नए रूसी विचारों के विरुद्ध, मेरी आपत्ति यही है कि उनकी गाड़ी को राजनीतिक तानाशाही आर्थिक राज्यसत्तावाद और रूसी राष्ट्रवाद के तीन घोड़े खींचते हैं।

लास्की ने साम्यवाद की कल्पना की तुलना ईसाई जगत् की वास्तविकताओं से की है। इसमें साम्यवाद की कल्पना श्रेष्ठ ठहरती है। उनको साम्यवाद की तुलना रूसी जगत् को वास्तविकताओं से भी करनी चाहिए थी।

मैंने लिखा था—'लास्की कहते हैं कि हमें नए धर्म की खोज में सोवियत् रूस जाना चाहिए, लेकिन स्टालिन ने, जिनकी जानकारी हमारे अंग्रेज मजदूरदली मित्र से अधिक है, कई वर्ष पहले यह दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अपना नया धर्म मध्ययुगीन रूस और जारकालीन अतीत से प्राप्त करेंगे। इसीलिए सोवियत्-सभ के नए नायक मध्यकालीन रूसी सरदार और पुजारी अलेक्जेंडर नेवस्की, अठारहवीं सदी के लुटेरे जनरल सूवोरोव, जारकालीन सरदार कुट्ज़ोव, जिन्होंने नैपोलियन को हराकर रूस में फ्रांसीसी क्रांति को घुसने नहीं दिया और एक शताब्दी तक रूस की उन्नति का मार्ग बन्द कर दिया और ऐसे ही दूसरे अत्यन्त प्राचीन और सड़े-गले व्यक्ति हैं जिनको लेनिन और दूसरे बोलशेविक गालियाँ दिया करते थे और उनका विरोध किया करते थे।

रूस का अतीत क्रान्तियों से पूर्ण है। लेकिन स्टालिन प्रतिगामी अतीत से ही प्रेरणा ग्रहण करते हैं। सोवियत्-सभ में सबसे ऊँचे सैनिक सम्मान का चिह्न 'सूवोरोव पदक' है। उसके बाद दूसरा स्थान 'कुट्ज़ोव पदक' का है। तीसरा पदक 'बोडमाल ख़मेलनित्ज़की पदक' है, जो अक्टूबर १९४३ से वितरित किया जाने लगा है। ख़मेलनित्ज़की एक यूक्रेनी नेता थे जिनका शिक्षण-मंगोलिया के जेसुइट स्कूल में हुआ था। वह सत्रहवीं शताब्दी में उत्पन्न हुए थे। वह पोलैण्ड निवासियों से लड़े थे और उन्होंने यहूदियों की हत्या की थी। इसीलिए सोवियत् पत्रों ने उस पर जोर दिया। वह स्वतंत्र यूक्रेन को जारशाही सरकार से संयुक्त करने के हिमायती थे।

लास्की की पुस्तक का विश्लेषण करते हुए मैंने आगे लिखा था—"रूस में इस समय जो साहित्य प्रकाशित हो रहा है उसमें स्लाव लोगों के एकी-

करण और राष्ट्रवाद की हिमायत की गई है। स्टालिन का नया धर्म यही है। इसके अतिरिक्त लास्की की दृष्टि इन हवाई किलो के बावजूद इतनी आगे बढ़ गई है कि उन्हें यह भी दिखाई नहीं देता कि सोवियत् राज्य की अधीनता में रूस में गिरजो को जो फिर स्वतंत्रता दी गई है, वह बालकान राज्यों के यूनानी कट्टर ईसाइयों का समर्थन प्राप्त करने या सोवियत् रूस के धार्मिक दलों को सतुष्ट करने की दृष्टि से ही नहीं दी गई है। यह इस बात की ओर संकेत है कि रूस में गम्भीर धार्मिक सकट पैदा हो गया है। स्टालिन की देख-रेख में क्रान्ति की ज्वाला इतनी ठंडी पड़ गई है कि उससे रूसी लोगों के हृदयों में कोई उत्साह पैदा नहीं होता।”

वास्तविक बात यह है कि ससार-व्यापी धर्म-सकट के इस समय में रूस में और भी बड़ा धर्म-सकट आ उपस्थित हुआ है। लास्की चाहे तो रूसी विचारों को ईसाइयत का स्थान ग्रहण करने वाली नई ‘कपोल-कल्पना’ या ‘नए विचार’ कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी पुस्तक के अधिकांश पाठक इसके सम्बन्ध में अनभिज्ञ हैं। और जो अज्ञात हैं उसे धार्मिक रूप देना सुगम होता है। लेकिन रूस के लोग अपने देश को जानते हैं, इसलिए वे जान जाते हैं कि स्टालिन गदले अतीत में से उनके लिए एक ‘कृत्रिम धर्म’ बना रहे है।

मैंने ‘कॉमन सेन्स’ में की गई आलोचना में शिकायत की थी—“लास्की ने कभी एक बार भी यह नहीं कहा कि स्टालिन ‘नए रूसी विचार’ की जगह नए धर्म की तलाश में है।” मैंने लिखा था—“लास्की ने जो कुछ कहा है उसके विरुद्ध वह एक ही दलील स्वीकार करते हैं और वह उनके कथन के विरुद्ध जाती है। वह स्वीकार करते हैं कि स्टालिन की सरकार ने ‘उन्मादपूर्ण निर्दयता के कार्य किये हैं।’ लेकिन उनका विश्वास है कि हत्याये, नजरबन्द-शिविर, विद्रोही तत्वों का उन्मूलन और मुकदमों में क्रान्ति की विजय को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक थे। यही उनकी सबसे बड़ी भूल है। मुझे कहना चाहिए कि मुझे इसमें सन्देह है कि लास्की सोवियत् इतिहास को भी समझते हैं या नहीं। क्रान्ति को सुदृढ़ करने के लिए आरम्भ में जो आतंक-जनक कार्य किये गए, मुझे उनसे कोई विरोध नहीं। मेरा विरोध तो स्टालिन के आतंककारी कार्यों से है जो उन्होंने रूस की वर्तमान क्रान्ति-विरोधी क्रान्ति की जड़ें मजबूत करने के लिए किये। विद्रोही तत्वों के उन्मूलन का रहस्य अब तक प्रकट हो जाना चाहिए था। स्टालिन ने क्रान्ति को समाप्त करने के लिए क्रान्तिकारियों को ही समाप्त कर दिया।”

लास्की ने युद्ध-काल में श्रीर स्टालिनग्राड की महान् विजय के मनो-वैज्ञानिक भावावेश में लिखा था—“हिटलरवाद के विरुद्ध गत दो वर्ष की लड़ाई में रूसियों ने जो वीरता दिखाई है, उससे समस्त ससार के आम लोगो को यह विश्वास हो गया है कि सन् १९१७ की क्रांति में कोई जादू है जो उनकी अपनी समस्याओं पर भी लागू हो सकता है।” लेकिन ‘धर्म, तर्क और सभ्यता’ में दूसरी जगह लास्की अपना दोष आप बताते हैं। वह कहते हैं “हमें उन आदमियों से बड़ा खतरा है जो साहस को ‘विचार’ समझ लेते हैं।”

क्या स्टालिनग्राड में दिखाया गया साहस ? हाँ, अगाध साहस। उतना ही साहस जितना डन्कर्क में, अल-ग्रामीन में, तरावा में, इवोज़िमा में, वारमा में, और लदन एव कन्वेन्टरी की सड़को पर दिखाया गया। नाज़ी और जापानी भी उन्माद पूर्वक लड़े। इसलिए मैं नाज़ी जीवन या जापानी धर्म को स्वाकार नहीं करता। आधुनिक मानव यदि अपने विचार युद्ध-भूमि में से ग्रहण करेगा तो वह नष्ट हो जायगा। किस युद्ध-भूमि में से ? ब्रिटेन और अमेरिका भी तो लड़ाई में विजयी हुए हैं।

स्टालिनग्राड में रूसियों की जीत इसलिए हुई कि एक ऐसे स्थान में जहाँ जर्मनी को सबसे अधिक दूर चलकर सामान ले जाना पड़ता था किंतु रूसियों की रक्षित जन-शक्ति जिसके निकटतम थी, स्टालिन उस स्थान की रक्षा के लिए सैनिकों का बलिदान करने के लिए तैयार होगए। यह लड़ाई शायद द्वितीय विश्व-युद्ध की निर्णायक लड़ाई थी। स्टालिन के दृढ़ निश्चय और लाल सेना की वीरता की जितनी प्रशंसा कवि और इतिहासकार करें, उतने के वह अधिकारी हैं। लेकिन स्टालिनग्राड में तो शक्ति का चमत्कार दिखाया गया था। इससे रूसी विचारों की उत्कृष्टता उससे अधिक सिद्ध नहीं होती जितनी ब्रिटेन और अमेरिका के उड़ाको, पनडुब्बी-चालको, छाता-सैनिकों, ग्राम स्टाफ के अफसरों, वैज्ञानिकों, और कारखानों के गौरवपूर्ण कार्यों से अंग्रेजों और अमेरिकियों के विचारों की उत्कृष्टता सिद्ध होती है। तोपों की गूँज और बमों के विस्फोट की अपेक्षा एक शांतिपूर्ण और छोटी आवाज़ में विचार के मिलने की अधिक सम्भावना होती है।

स्टालिनग्राड और कई दूसरे स्थानों में लड़ाई में जो बहुत और आश्चर्यजनक वीरता दिखाई गई वह केवल यह बताती है कि मानव-पशु जीवन-कला की अपेक्षा मरण-कला में अधिक निपुण है। उस सभ्यता में कोई-न-कोई दोष है जिसका अच्छा-से-अच्छा स्वरूप इस प्रकार की जाने वाली नर-हत्या है।

लास्की के विविध विषयों के विचार पृथक्-पृथक् कोष्ठों में बन्द मालूम होते हैं, जिससे उनमें पारस्परिक सम्पर्क न पैदा हो जाय। उनका सबसे बड़ी कठिनाई यही है। लास्की ने ईसाइयों के इतिहास का उल्लेख करते हुए लिखा है—“मेरे विचार से अत्याचारों के परिणाम-स्वरूप अत्याचारी में निर्दयता और अभिमान उत्पन्न होता है और अत्याचार-पीडित में मक्कारी और दास-भावना।” यह रूस की स्थिति का यथार्थ-चित्रण है, लेकिन लास्की इसे स्वीकार ही नहीं करते।

लास्की ने रूसी जीवन को समझने में इसलिए भूल की कि रूस में क्रान्ति के परिणाम-स्वरूप नया राज्य और नया मनुष्य उत्पन्न हो गया है।

अगस्त १९४४ में लास्की की पुस्तक के सम्बन्ध में विचार करते हुए मैंने लिखा था—“रूसी राज्य उसी प्रकार शक्ति-सन्तुलन की राजनीति में रत है जिस प्रकार कई राज्य पहले इस प्रयत्न में रत रहे हैं और इस समय भी रत हैं। मुझे रूस की वैदेशिक नीति में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जिसे हम ‘रूस के विचारों की उत्पत्ति’ कह सकें। उसका मूल मन्तव्य अपने राष्ट्र का लाभ है। रूसी सरकार ने फाशिस्टों, तानाशाही राज्यों, राज्य-सत्तावादियों प्रतिगामियों, परिवर्तनवादियों और जनतन्त्रवादियों सभी से मित्रतापूर्ण शर्तों के साथ सहयोग किया है।” रूस में यद्यपि आर्थिक साधनों पर राज्य का अधिकार है, तथापि इससे साम्राज्यवाद के प्रसार में कोई बाधा नहीं आई है।

इसा प्रकार रूस में आर्थिक साधनों पर राज्य का अधिकार होने पर भी वहाँ कोई समाजवादी व्यक्ति नहीं पैदा हुआ है और न कोई नई समाजवादी नैतिकता ही बनी है। लास्की का विश्वास है कि “सोवियतों की छत्र-छाया में वह व्यक्तिगत पूर्णता की भावना पैदा होती है जो किसी दूसरी प्रणाली में रहते हुए नहीं पैदा होती।” वह कहते हैं कि रूस में क्रान्ति के बाद “मनुष्य के सहज गौरव” पर जोर दिया गया है। बोलशेविकों के रूस में सत्तार में अन्य देशों की अपेक्षा “अधिक नर और नारियों को आत्म-विकास का अधिक अवसर प्राप्त है।”

मैं लास्की से पूछता हूँ कि जहाँ भय है वहाँ गौरव कैसा ? स्वतन्त्रता के बिना व्यक्तिगत पूर्णता कैसे सम्भव है ? रूस में धन्धों में व्यस्त लोगों को आत्मोन्नति का खूब अवसर प्राप्त है। कथित “निम्न-वर्गों” में लोगों, अल्प-नरक जातियों के सदस्यों को (जो कभी पीडित थे) और स्त्रियों को क्रान्ति के कारण नए और बहुत अवसर प्राप्त हुए हैं। रूस की विकासोन्मुख अर्थ-योजना के कारण लोगों को धंधा पाने और शिक्षा-सम्बन्धी उन्नति करने की सम्भा-

बनाए बहुत बढ गई है। इससे अन्ततोगत्वा रूसी लोगो के रहन-महन का वर्तमान नीचा दर्जा भी ऊँचा होगा ही।

इन स्थितियों से जो रूसी नागरिक और विदेशी लोग बहक जाते हैं, उन्हें मैं समझता हूँ, क्योंकि स्वयं मैं भी कई वर्षों तक इसी प्रकार भ्रम का शिकार रहा हूँ। रूस की बढ़ती हुई उत्पत्ति के आकड़ों और रूसी उद्योगों के विकास को देखकर मुझमें उत्साह पैदा हो जाता था। शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं की वृद्धि और पुस्तकों एवं समाचार-पत्रों के प्रचार की मैं प्रशंसा करता था। अल्पसंख्यक जातियों, स्त्रियों, औपनिवेशिक देशों, साम्राज्यवाद, सामूहिक सुरक्षा और कुत्सित आन्दोलन के रूप में आरम्भ होने पर फाशिज्म के बारे में रूस की जो नीति थी उसने मुझे सोवियत्-संघ का कट्टर समर्थक बना दिया था। सोवियत्-शासन के मित्र के रूप में मैंने बहुत समय तक बहुत कुछ किया है।

मैंने सोवियत्-संघ के प्रति अपना रुख क्यों बदला ?

मैंने सोवियत् रूस के प्रति अपने रुख में इसलिये परिवर्तन किया कि रूस खुद बदल गया था। मेरे विरोध का कोई व्यक्तिगत, गोपनीय या मेरे धन्ये से सम्बन्धित कारण न था। स्टालिन के रूस की नई नीतियों और नई अवस्थाओं की मेरे ऊपर प्रतिक्रिया हुई थी। रूसी राष्ट्रवाद, अमानुषिक शुद्धीकरण, बढ़ती हुई असमानता, नई अमीरी हुकूमतें, मानवीय स्वभाव के प्रति बढ़ती हुई घृणा (जिसका एक फल सोवियत् नाजी सचि के रूप में सामने आया था) और अपनी सब बुराइयों सहित वैयक्तिक तानाशाही—इन सबकी प्रतिक्रिया मुझमें प्रकट हो रही थी।

मैं रूस की राष्ट्रवादी, साम्राज्यवादी और अप्रजातंत्री नीतियों के कारण सोवियत् सरकार का विरोधी बना। खास तौर से रूस के नए राष्ट्रवाद की मैं उच्च-स्वर से निन्दा करता हूँ। रूस की अन्तर्राष्ट्रीयता मेरे लिए सबसे बड़ा आर्काषण थी। मैं चौदह वर्षों तक सोवियत्-संघ में रहा। इन दिनों मुझे उस देश की भूमि, नदियों, पत्थरों और वृक्षों में कभी दिलचस्पी नहीं हुई। रूस में जो भारी परिवर्तन हो रहे थे, वे उस देश के लिए और अन्य देशों के लिए लाभप्रद हो सकते थे, इसलिए मुझे रूस में दिलचस्पी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रूस में अन्तर्राष्ट्रीय भावना बढ़ रही थी उसमें मुझे बहुत दिलचस्पी थी, क्योंकि मेरे खयाल में राष्ट्रवाद सबसे बड़ी बुराई है। वह मानव जाति के लिए भारी अभिशाप और लड़ाइयों का मुख्य कारण सिद्ध हुआ है। रूस ने राष्ट्रवाद को फिर स्वीकार कर लिया, यह मेरे जीवन की सबसे दुःखपूर्ण घटना है। मैं

सोवियत्-सघ से उसकी अन्तर्राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद के विरोध, और जनतन्त्री उद्देश्यो के कारण बड़ी आशाये बाधे बैठा था ।

जब मैं इन बातों को अस्वीकार करता हूँ तो क्या मैं चुप बैठ रहा हूँ ? तानाशाही की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वह आलोचना को सहन नहीं कर सकती । आलोचना ही जनतन्त्रीयता है । जो जनतन्त्रवादी यह आग्रह करते हैं कि सोवियत्-सरकार को आलोचना से मुक्त कर दिया जाय वे तानाशाही के हित-साधन में लगे हुए हैं । ऐसे युग में जब सरकारें सर्वत्र ही भूले करती हैं और मनुष्यों के लिए विपदाएं खड़ी कर देती हैं, किसी सरकार को आलोचना से बरी कर देना हानिकर है । जो लोग यह कहते हैं, क्या वे सोवियत्-सरकार के अतिरिक्त किसी दूसरी सरकार पर अपने आक्रमण बन्द कर देंगे । कुछ लोगों की दृष्टि में बेकिन, ट्रूमैन, डिगाल, पोप और चांग-काई-शेक की आलोचना पूर्णतः उचित है । स्टालिन की आलोचना साम्यवादियों के लिए हितकर है । रूस में स्टालिन की आलोचना बिल्कुल नहीं होती । तानाशाही के विदेशी समर्थक, जो यह बात पसंद करते हैं, रूस के बाहर भी स्टालिन की आलोचना को निषिद्ध करना चाहते हैं । आलोचना से बचने का सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि उन अवस्थाओं को हटाया जाय या उनमें सुधार किया जाय जिनके कारण यह आलोचना करना उचित है । आलोचना को दबाना इसका इलाज नहीं है ।

मैंने 'नेशन' के लेखदाता-संपादक का कार्य इसलिए छोड़ दिया था, कि यह पत्र रूस के सम्बन्ध में कुछ कहता ही न था, जब तक कि उसके सामने कुछ बात उसके अनुकूल कहने के लिए न हो । इसके परिणाम-स्वरूप संसार के सबसे बड़े चुनौती देने वाले देश की कितनी ही घटनाओं के सम्बन्ध में उसका मुँह बन्द रहता था ।

राष्ट्रों की मित्रता वास्तविक तथ्य को दबाने से कायम नहीं रहती । असत्यो के बदले खरीदी हुई मित्रता नाजुक होती है और वह थोड़ा-सा जोर पड़ते ही टूट जाती है ।

मैं यह आशा नहीं करता कि मेरी सरकार पूर्ण ही होगी । प्रत्येक व्यक्ति किसी सामाजिक संगठन या सरकार से जो सम्बन्ध रखता है वह अच्छाई और बुराई के अनुपात से निश्चित होता है । यदि उसमें अच्छाई बुराई से अधिक है, या अधिक हानि की सम्भावना होती है, तो वह उसके पक्ष में हो जाता है । यदि बुराई अच्छाई से बहुत अधिक हो जाती है और वह अच्छाई की भी हत्या करने पर उतारू हो जाती है, तो वह उसके विपक्ष में हो जाता है ।

जो लोग जनतन्त्री देशों में रहते हैं उनके सामने जब सोवियत् रूस की अवस्थाएं प्रस्तुत की जाती हैं तो इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह सामने आती है कि वे प्रायः यह अनुभव नहीं कर पाते कि तानाशाही किस हद तक बुरी हो सकती है। उदाहरण के लिए कुछ प्रतिगामी अमेरिकन यह आरोप करते हैं कि फ्रैन्कलिन डी० रूजवेल्ट तानाशाह थे, और उद्योगों की नई व्यवस्था (न्यू-डील) के सम्बन्ध में उन्होंने मनमानी से काम लिया था। जो आदमी किसी तानाशाही शासन में रहा है, उसको इससे हँसी आयेगी। इसका अर्थ तो यह है कि इस प्रकार का दोष लगाने वाले यही नहीं जानते कि तानाशाही कैसी होती है। इसी प्रकार यह कहा गया है कि चांग-काई-शेक तानाशाह हैं। मैंने स्वयं उनकी प्रतिगामी नीतियों के कारण उनकी आलोचना की है। लेकिन कुछ समय पूर्व कुनमिंग के कुछ अध्यापकों ने चांग-काई-शेक को एक पत्र भेजा था। एक अध्यापक ने इस पत्र को १८ दिसम्बर १९४५ के 'न्यूयार्क हेराल्ड ट्रिब्यून' में छपावा दिया। पत्र में कहा गया था—“एक दलीय तानाशाही का अन्त करना आवश्यक है।” इसके अतिरिक्त उन्होंने लिखा था—“एक व्यक्ति के हाथों में सत्ता का केन्द्रीकरण अब समाप्त हो जाना चाहिए।” जो भी रूस की स्थितियों से परिचित है वह यह जानता है कि रूस में यह बात अकल्पनीय है। कोई भी प्रोफेसर या दूसरा आदमी जब तक आत्म-हत्या न करना चाहे, तब तक ऐसे शब्द किसी कागज के टुकड़े पर नहीं लिख सकता, उनको स्टालिन के पास भेजने का खयाल नहीं कर सकता और न किसी दूसरे देश के लिए डाक में छोड़ने का साहस कर सकता है।

रूस की गुप्त पुलिस के आतंक से मैं सदा ही घृणा करता था, लेकिन पहले मुझे आशा थी कि यह कम हो जायेगा।

दूसरे मैं इसकी तुलना उसकी सामाजिक और आर्थिक सफलताओं से करता था। कुछ समय बाद मैंने देखा कि यह आतंक प्रतिवर्ष अधिकाधिक निर्दयतापूर्ण होता जाता है। क्रांति ने अपने शत्रुओं को चौपट करने के बाद अपने निर्माताओं और अपनी सन्तानों को ही खाना शुरू कर दिया था। मुझे यह भी दिखाई देने लगा कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता के अभाव में बोलशेविज्म के कितने ही लाभों का वास्तविक मूल्य जाता रहा था।

उदाहरण के लिए अल्पसंख्यक जातियों को दी गई स्वतन्त्रता को ले लें। शाब्दिक दृष्टि से देखने से जार्जिया, यूक्रेन और सोवियत्-संघ में सम्मिलित दूसरे छोटे राष्ट्रों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वे चाहें तो सोवियत्-संघ से अलग हो सकते हैं। लेकिन वस्तुतः उन्हें ऐसा नहीं करने दिया

जाता। शाब्दिक दृष्टि से उनको राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन वास्तविक रूप में उनके साम्यवादी, जिनका उन पर प्रभुत्व है, रूसी सरकार की आज्ञाओं से संचालित होते हैं। वास्तव में सन् १९४१ से रूसी सरकार ने कई जातीय जनतंत्रों को दबाया है और उनकी खुदमुख्तारी छीन ली है। इसके लिए कोई सरकारी घोषणा नहीं की गई। यह तभी मालूम हुआ जब मत-दाता-क्षेत्रों की सूची प्रकाशित की गई। यह सोवियत-विधान को भंग करके किया गया। लेकिन सांस्कृतिक मामलों में रूसी सरकार अल्पसंख्यक जातियों को अपनी रूचियों और इच्छाओं के अनुसार चलने देती है, सिवा इसके कि इन लोगों को अभी रूसी इतिहास और रूसी भाषा सिखाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है और अभी हाल के वर्षों में प्रकाशित रूसी पुस्तकों के अनुसार रूसी सरकार ने कुछ अल्पसंख्यक जातियों, जैसे तातारों और स्लाव नस्ल से भिन्न नस्लों के लोगों में, बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को कुचलने का प्रयत्न भी किया है।

अल्पसंख्यक जातियों के साथ जातीय पक्षपात करना सभ्यता और शिष्टता के विरुद्ध है। फिर भी बोली बोलने वाले दलों को सांस्कृतिक स्वतंत्रता मिली हुई है, चाहे व्यक्तियों को भले ही रक्तों भर भी स्वतंत्रता न हो। सोवियत-संघ के अन्तर्गत आर्मेनियन जाति को स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन वहां के किसी भी निवासी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। उजबक, यूक्रेनी और ताजिक भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित हैं। इस सम्बन्ध में सबकी एक-सी दशा है।

उजबक, यूक्रेनियों या रूसियों के अत्याचार से पीड़ित नहीं हैं। लेकिन गुप्त पुलिस उसको किसी भी क्षण बिना कुछ पूछ-ताछ किये गिरफ्तार कर सकती है और मुकदमा चलाये बिना निर्वासित कर सकती है। वह साम्यवाद-विरोधी को इसी प्रकार मत नहीं दे सकता, जिस प्रकार एक अमेरिकन पूंजीवाद के विरोधी को मत दे सकता है। वह सरकार या उसके नेताओं की राजनीति की आलोचना नहीं कर सकता। यदि करना है तो उसे निजी रूप से गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उसको सहमत होना और आज्ञा पालन करना होता है, यदि वह असहमत भी हो तो भी वह कहेगा यही, कि वह सहमत है। वह इसी में बुद्धिमानी समझता है।

जहां तक सब जातियों का सवाल है सोवियत शासन सभ्य है लेकिन जहां सब लोगों का सवाल है, वहां वह असभ्य है। विज्ञान के प्रति सोवियत सरकार का नया ही रुख है। वह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बहुत-सी सहा-

यता और कई ठोस सुविधाएँ देती हैं। किन्तु विज्ञान के स्वतंत्र होने पर भी वैज्ञानिक वहाँ स्वतंत्र नहीं है। वैज्ञानिकों पर सोवियत्-संघ के उच्च-वर्गों का शासन है। रूसी वैज्ञानिक विदेशी वैज्ञानिकों से स्वतंत्रतापूर्वक पत्र-व्यवहार नहीं कर सकते। इस बात की व्यवस्था गुप्त पुलिस की मार्फत होनी आवश्यक है। रूसी वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेसों में नहीं जाते। यदि उन्हें विदेश जाने की जरूरत हो तो भी वे विदेश नहीं जा सकते। सोवियत्-संघ का भौतिक विज्ञान-शास्त्री, वनस्पति-शास्त्री, गणित-शास्त्री, तत्त्व-वेत्ता और इतिहासकार अवश्य ही सावधान रहता है कि उसका निष्कर्ष मार्क्सवाद और भौतिकवाद के वर्तमान ग्रंथों से विपरीत न हो। क्योंकि वह जानता है कि उसके कितने ही साथियों की निन्दा की जा चुकी है और कितने ही साथी क्रांति-विरोधी कहकर दंडित किये जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने विरोधी विचार प्रकट किये थे। कितने ही रूसी वैज्ञानिक सफाये के शिकार हो चुके हैं।

प्रो० लास्की के मित्र प्रमुख अंग्रेज वैज्ञानिक जूलियन हक्सले सन् १९-४५ में रूस गये थे। 'नेचर' पत्र में उन्होंने लिखा था— "रूसी विज्ञान की कुछ शाखाओं में वैज्ञानिक राष्ट्रवाद की कुछ भावना दिखाई देती है जो लोग विरोध करते हैं वे बरखास्त कर दिये जाते हैं।"

प्रो० पीटर कपीत्सा एक महान् भौतिक विज्ञान-वेत्ता हैं। सन् १९२२ में जब रूस के कुछ लोग बाहर जा सकते थे, कपीत्सा रूस से इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में चले आये। सन् १९२६ में प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक लार्ड रदरफोर्ड ने कैम्ब्रिज में खास तौर से एक रसायनशाला बनाई जहाँ कपीत्सा चुम्बकीय सुरंगों और इससे मिलते-जुलते विषयों पर खोज कर सकें। सन् १९-३५ में वह रूस गये। सोवियत् सरकार ने उनकी उनकी इच्छा के विपरीत वही रोक लिया और उसने ब्रिटिश सरकार, लार्ड रदरफोर्ड और दूसरे लोगों के विरोध-प्रकाश की कोई परवाह नहीं की। इस पर लन्दन-स्थित रूसी राजदूत ने एक वक्तव्य दिया; जिसमें कहा गया था कि सोवियत्-संघ में विज्ञान का साधारण विकास हो रहा है और वैज्ञानिकों की बहुत अधिक कमी है। उसको ध्यान में रखते हुए रूस के लिए विदेशों में काम करने वाले अपने वैज्ञानिकों का उपयोग करना आवश्यक कहा गया है। उसमें यह भी कहा गया था कि प्रो० कपीत्सा अच्छी जगह रखे गए हैं और उनको अच्छा वेतन दिया जा रहा है। यह निस्संदेह सत्य है, लेकिन कपीत्सा, जो सम्भवतः अणु का रहस्य खोल सकते हैं, स्वतंत्र नहीं हैं।

इन्हीं महीनों में अमेरिका और इंग्लैंड के घाघे रूसी बहानेबाजों ने

जनता को यह समझाने का प्रयत्न किया है कि जनतन्त्री, पाश्चात्य देशीय और रूसी कल्पनाओं में गहरा अन्तर है। उन्होंने यह भी कहा कि सोवियत्-सघ के नागरिक स्वतन्त्र हैं, यद्यपि उनकी स्वतन्त्रता भिन्न प्रकार की है। इस बकवास पर बहुत कम रूसी नागरिक चुप रह सकेंगे। रूसी नागरिक दो तरह के हैं; एक वे जो जानते हैं कि वे स्वतन्त्र नहीं हैं और इससे उनको दुःख भी होता है; दूसरे वे जो जानते तो हैं, लेकिन पगवाह नहीं करते। क्योंकि उनकी स्वतन्त्रता की आवश्यकता और उसके लिए उनकी रुचि बदल गई है।

जिनकी आयु सन् १९२७ में सोलह वर्ष से अधिक थी, उन्हें इस बारे में साम्यवादी दल में जो खुला विचार हुआ था, उसका स्मरण होगा। कितने ही कार्यकर्ताओं को स्मरण है कि वे पहले सामूहिक बातचीत कर सकते थे; लेकिन अब नहीं कर सकते। पारिवारिक घर में रहने वाला प्रत्येक आदमी जानता है कि ३ बजे प्रातः काल ही रूसी गुप्त पुलिस आती है और परिवार के एक दो सदस्यों को ले जाती है। जब दिन में निश्चित समय पर अरबत स्ट्रीट से सब लोगों को हटा दिया जाता है तो पैदल चलने वाले जान जाते हैं कि स्टालिन की मोटर यहाँ होकर गुजरने वाली है। वे आश्चर्य के साथ सोचते हैं कि यदि वे मार्ग के एक ओर खड़े हो जाय और उसे देखते रहे तो इससे क्या नुकसान हो जायगा? जब रूसी खुफिया पुलिस के आदमी उस मार्ग के दोनों ओर, जिस पर स्टालिन अपनी पत्नी के शव के पीछे-पीछे जाने वाले थे, घरों को देखने गए तो लोगों ने यह अनुभव किया कि उनका विश्वास नहीं किया गया।

यदि रूसी नागरिकों का यह खयाल हो कि वे स्वतन्त्र हैं तो वे इतनी कानाफूसी न करें। वे अपनी गर्दनो को पीछे की ओर मोड़-मोड़ कर यह न देखें कि कहीं उनकी बात कोई सुन तो नहीं रहा है। वे अपने एक पुराने मित्र से केवल इसीलिए सम्बन्ध न तोड़ ले, कि उसका एक सम्बन्धी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोवियत्-सघ के लोग इस पुलिस-राज के अभ्यस्त हो गए हैं और कुछ समय बाद वे यह सब कार्य इतना यत्नवत् करने लगते हैं कि उसको करते समय उन्हें उसका भान ही नहीं होता।

सोवियत् पत्रों में जनतन्त्री देशों की हडतालों की खबरें छपती हैं। सोवियत् मजदूर जानते हैं कि वे हडताल नहीं कर सकते, यद्यपि कभी-कभी करना भी चाहते हैं। इसका प्रमाण यह है कि जब सन् १९३५ में स्टारबनोव ने उत्पादन-वृद्धि का आन्दोलन उठाया और मजदूरों या खनकों के कार्य की मात्रा बढ़ा दी, तो इस आन्दोलन में कुछ मजदूर मार दिये गए या पीटे गए।

रूसी अखबारों ने इन घटनाओं और मज्जाओं की खबरें भी छपीं।

सोवियत्-सभ के नागरिक जानते हैं कि एकदलीय चुनाव में उनके मतों का कोई महत्व नहीं है। जो लोग भोले-भाले हैं—जैसी मेरी नीकरानी—वे पूछ बैठते हैं कि केवल एक उम्मीदवार के सूचक मत-पत्र को नरने का क्या प्रयोजन है। रूस में अब अधिकांश लोग कोई पूछ-ताछ ही नहीं करते। वे जो कुछ उनसे करने की आशा की जाती है वही करते चले जाते हैं।

सोवियत्-सभ के निवासी अश्वत होने पर भी मूर्ख नहीं हैं। वे जानते हैं कि वे तानाशाही हुकूमत में रहते हैं।

रूसी गुप्त पुलिस द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारियों के प्रति रूस की जनता जो भावना दिखाती है, वह सोवियत् जीवन की सबसे आश्चर्यजनक बातों में से एक है। किसी के बंदी बनाये जाने पर रूसी जनता में साधारणतः यह प्रतिक्रिया नहीं होती कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपराधी है; बल्कि यह कि वह अभाग है। अधिकांश सोवियत् नागरिक गुप्त रूसी पुलिस के जाल में फँसने वाले व्यक्तियों के इतने निकट सम्पर्क में रहते हैं कि उन्हें यह बात आसानी से मालूम हो जाती है कि उनकी गिरफ्तारी सफाये के उद्देश्य से की जाती है और उसका उनके निजी दुराचरण से कोई सम्बन्ध नहीं होता। इन गिरफ्तारियों के कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे निजी द्वेष की पूर्ति के लिए दोषी ठहराना या किसी राजद्रोही के साथ जीवन पर्यन्त मैत्री करना आदि।

अलेक्जेंडर अफीनोगेनाव रूस के एक बड़े ही सफल नवयुवक नाटक-कार थे। उनके खेल मास्को के कला-भवन और दूसरे उम्दा थियेट्रो में खेले गए थे। अन्य कलाकारों और लेखकों की भांति वह भी रूसी गुप्त पुलिस के प्रधान अधिकारी, जेनरिख यगोडा के यहाँ जाया करते थे। जेनरिख अपने को कलाओं का संरक्षक समझा करते थे। असल में अफीनोगेनाव-परिवार यगोडा को बहुत ही प्रिय था और उसे मास्को के उस सुन्दर मकान का हिस्सा मिला हुआ था जिसमें गुप्त पुलिस के अफसर रहा करते थे। किंतु यगोडा गिरफ्तार कर लिये गए और उन पर यह मुकदमा चलाया गया कि रूसी नेताओं को राज-द्रोह के अपराध में पकड़ते और गोली से उड़ाते समय उन्होंने राज-द्रोहात्मक कार्य किये थे। यगोडा पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मौत की सजा दी गई। यगोडा के गिरफ्तार कर लिये जाने पर अफीनोगेनाव से कमरा छीन लिया गया और वह कम्युनिस्ट दल से निकाल बाहर किये गए। इसके बाद सभी छोटे आलोचक अफीनोगेनाव पर टूट पड़े और कहने लगे कि उनके नाटक कभी भी अच्छे नहीं हुए। थियेट्रो ने इन्हें खेलना बंद कर

दिया। साहित्य-सभाओं में अफीनोगेनाव पर “क्रान्ति विरोधी प्रवृत्तियों” और बोलशेविक-विरोधी विचारों का दोषारोपण किया जाने लगा। ऐसा मालूम हुआ कि सदा की भाँति गिरफ्तारी के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है किन्तु एकाएक अफीनोगेनाव को फिर पूर्व-सम्मान प्राप्त होगया और जिन छोटे आलोचकों ने उस पर थूका था वे हाँ फिर से उसकी प्रशंसा करने लगे। अधिकांश लोगो ने सोचा कि यह बात स्टालिन के निजी हस्तक्षेप के कारण हुई है। बात यह थी कि वर्तमान शताब्दी के द्वितीय शतक में अफीनोगेनाव ने रूसी जीवन के पाखण्ड पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम उन्होंने “भूठ” (दी लाई) रखा था। एक दिन उनके पास स्टालिन के दफ्तर से बुलावा आया। पुस्तक की प्रतिलिपि स्टालिन के पास पढ़ने के लिए भेजी गई थी। स्टालिन ने अफीनोगेनाव से कहा कि नाटक है तो अच्छा किन्तु यह रंगमंच पर खेला नहीं जाना चाहिए। स्टालिन ने अफीनोगेनाव पर नाटक को रंगमंच से हटा लेने के लिए जोर दिया और अफीनोगेनाव ने ऐसा ही किया।

राजनीतिक सम्मान पुनः प्राप्त करने के बाद एक दिन अफीनोगेनाव मुझे और मेरी पत्नी मारकूशा को अपनी फोर्ड मोटर गाड़ी में बैठकर अपने गाँव वाले बगले में ले गये। मैं उनके पास आगे की सीट पर बैठा और बातचीत के दौरान मैं बोला—“शूरा, तुम जानते हो कि तुम पर जितने भी दोषारोपण किये गए थे वे सब असत्य थे। क्या इसका यह मतलब नहीं हुआ कि अगर तुम दूसरे पर भी ऐसे ही दोषारोपण की बातें सुनोगे तो तुम्हें यह खयाल होगा कि वे भूठ हैं।”

मेरी ओर घूमकर अफीनोगेनाव मुसकराये। वह मुझसे सहमत थे। युद्ध के दिनों में जर्मनी ने मास्को पर बम-वर्षा की तो अफीनोगेनाव भी उनकी भेंट हुए।

लास्की ने क्या कहा था? दण्ड देने से “दण्डित व्यक्ति के हृदय में पाखण्ड और दासता की भावना उत्पन्न हो जाती है।” साथ-ही-साथ, इससे दण्डित व्यक्तियों और दण्ड का समाचार सुनने वालों में चिड़चिड़ापन भी उत्पन्न हो जाता है। रूसी नागरिक दण्ड को अपराध से संबंधित नहीं समझते। वे उसे दण्ड देने वाले के किसी राजनीतिक आयोजन का अंग मानते हैं। बोलशेविक क्रान्ति के परिणामस्वरूप लोगो में कानून के प्रति भय तो अवश्य बढ़ गया है किन्तु उसके प्रति सम्मान नहीं बढ़ा है। कानून के प्रति सम्मान न होने का कारण यह है कि सोवियत-संघ में वस्तुतः कोई कानून है ही नहीं। तानाशाही खुद कानून है। पहले कानूनों की रत्ती भर भी चिंता न कर वह

कानून बनाती-बिगाड़ती और उनमें परिवर्तन भी करती है, जिससे प्रमाणित होता है कि वह स्वयं कानून का आदर नहीं करती। रूस में कानून से भय मानने का अर्थ है कि उन लोगों का भय मानना जो स्वयं कानून हैं; कानून तो उसी समय रह सकता है जब सरकार उसका पालन करे और उसी दशा में जनता से भी उसके पालन किये जाने की आशा की जा सकती है।

मन् १९३६ के स्टालिन-विधान की धारा १२१ में लिखा हुआ है—
 “सोवियत् यूनियन के निवासियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिकार की रक्षा के लिए प्रारम्भिक शिक्षा व्यापक और अनिवार्य बना दी गई है, प्राइमरी और उच्च दोनों ही प्रकार की शिक्षाएं नि शुल्क कर दी गई हैं और विश्वविद्यालयों के अधिकांश विद्यार्थियों के लिए सरकारी वजीफों की व्यवस्था कर दी गई है।”

बड़ी सुन्दर घोषणा है यह। किन्तु २ अक्टूबर १९४० को रूसी सरकार ने एक नया आदेश घोषित कर उच्च श्रेणी के हाई स्कूलों, कालेजों, विश्व-विद्यालयों और उच्च यांत्रिक स्कूलों में नि शुल्क शिक्षा बढ़ कर दी। साथ-ही-साथ, वजीफों और छात्र-वृत्तियां आदि भी खत्म कर दी गईं।

विधान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जनता से सलाह नहीं ली गई। सरकार ने विधान की नितान्त उपेक्षा की और उसके विपरीत कार्य किया। किसी ने विरोध का एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाला। ऐसा करने का किसे साहस होता? उस विरोध को छापता कौन? सरकारी प्रेस?

रूसी सरकार के इस अवैधानिक कार्य से मजदूरों और किसानों के लड़कों के लिए हाई स्कूलों और कालेजों में पढ़ना अधिक कठिन हो गया और इसके फलस्वरूप धनियों के लड़के-लड़कियों के लिए जगहें खाली हो गईं। स्टालिन उच्च-वर्ग के व्यक्तियों की एक पीढ़ी तैयार कर रहे थे।

विधान की धारा १२१ के रद्द किये जाने के अगले ही दिन रूसी सरकार ने कारखानों और रेलों के आस-पास हाई-स्कूलों को उच्च श्रेणी के टेक्नीकल स्कूलों के बनाये जाने की आज्ञा दी। ताकि उनमें वे ६ हजार विद्यार्थी भरती किये जा सकें जो फीस सम्बन्धी आदेश के कारण हाई-स्कूलों और कालेजों में पढ़ने का खर्च बरदाश्त नहीं कर सकते थे।

इस प्रकार उच्च-वर्ग के लड़के-लड़कियों को उनके भावी जीवन—इन्जीनियर, प्रोफेसर, व्यवसायी, वैज्ञानिक आदि बनने—के मार्ग पर डाल दिया गया। इसके विपरीत मजदूरों और किसानों के लड़के-लड़कियों को मिस्त्री, कारीगर, ट्रैक्ट-चालक और रेलवेमैन आदि की शिक्षा प्राप्त करने में लगा दिया गया।

फरवरी १९४४ में जब कि विधान की इस प्रकार बलात् उपेक्षा करने के फलस्वरूप उच्चवर्गीय नवयुवको-नवयुवतियों का विश्वविद्यालयों में प्रवेश हो गया और निम्न कोटि के नवयुवको-नवयुवतियों को उद्योगों और कृषि की द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में अपना भविष्य सीमित दिखाई देने लगा तो तानाशाह सरकार ने एकाएक और बिना कोई कारण बताये ही धारा १२१ को पुन लागू कर दिया । और इसके साथ-ही-साथ उसने कालेजों की शिक्षा को नि शुल्क घोषित कर दिया और छात्रवृत्तियाँ भी पुन आरम्भ कर दी ।

इस घटना से पता चलता है कि सरकार सर्वोच्च कानून का किस प्रकार पालन करती है, तानाशाही राज्य-व्यवस्था में शिक्षा का कितना आदर किया जाता है और नेता जनता के साथ कैसा व्यवहार करते हैं । नेता वहमी होते हैं, जनता भी वहम और उदासीनता का कवच पहनना सीख जाती है । इस-लिए यदि घटना-चक्र पर अपना कोई प्रभाव नहीं तो आप व्यर्थ ही क्यों चिन्ता करते हैं ?

मेक्सिको नगर में एक स्वागत-सभा में भाषण देते हुए रूसी राजदूत कान्सटेन्टाइन ग्रोमास्की ने, जो मास्को के मेरे पुराने मित्र थे और जिनकी एक विमान-दुर्घटना में मृत्यु हो गई, रूस की शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं के विस्तार पर बातचीत की ।

“क्या मैं पूछ सकती हूँ कि इस आश्चर्यजनक शिक्षा से लाभ क्या, जब आपके देश में लोगों को मत-प्रकाश की भी आजादी नहीं ?” एक महिला ने पूछा ।

“श्रीमती जी, मैं इस प्रश्न को एक प्रतिगामी प्रश्न समझता हूँ और इसका उत्तर देने से इकार करता हूँ”, ग्रोमास्की ने उत्तर दिया । यह बात एमिली वॉरेट ब्लैनचर्ड ने ‘सटर्डे ईवनिंग पोस्ट’ के २३ दिसम्बर १९४४ के अंक में एक लेख में बताई । ग्रोमास्की का उत्तर उन्होंने स्वयं अपने कानों से सुना था ।

आजकल हम जिसे पसन्द नहीं करते, वही हमारे लिए “प्रतिगामी” हो जाता है । असल में हम उसे “फाशिस्ट” कह बैठते हैं । किन्तु महिला के प्रश्न करने पर भी कूटनीतिज्ञ ग्रोमास्की का उत्तर न देना एक विचारणीय बात है । निस्सन्देह साक्षरता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । किन्तु विचार-शक्ति और कला की उत्पत्ति में “स्वतंत्रता” का उतना योग नहीं जितना “साक्षरता” का । सन् १९३६ के विधान में लिखे होने के बावजूद रूसी नागरिकों को मत-प्रकाश या सभा-समाज करने की आजादी नहीं है, सिवा उस आजादी के जो सरकार उन्हें किसी विशेष उद्देश्य से देना चाहती है ।

६ दिसम्बर १९३६ को रूस के ३० नेताओं ने क्रेमलिन में बैठकर गम्भीरतापूर्वक नये विधान पर हस्ताक्षर किये। इनमें स्टालिन, मोलोटोव, वोरोशिलाव और लिटविनाव भी थे। सन् १९३६ तक हस्ताक्षर करने वालों में से १५ व्यक्तियों का बिना किसी मुकदमे के सफाया कर दिया गया। इनमें दूर पूरब की रूसी सेना के कमांडर मार्शल ब्लूशर, सर्वोच्च राजनीतिक सभ्यता के सदस्य कोस्सियोर, उस सभ्यता के डिप्टी मेम्बर रड्जुटाक, यूक्रेन के कम्युनिस्ट दल के नेता पोस्टोशेव, गुप्त पुलिस के प्रधान अधिकारी येज़ोव, जो यगोडा के उत्तराधिकारी बने थे, और पश्चिमी साइबेरिया के कम्युनिस्ट दल के प्रधान ईशे भी थे। यही वह व्यवहार था जो स्टालिन ने रूस के मन्त्रियों के साथ किया। इस बात की कोई घोषणा नहीं की गई कि इन लोगों का सफाया कर दिया गया है, न उनके सफाये का कोई कारण ही बताया गया। वस, वह अदृश्य भर हो गए और उसके बाद दिखाई नहीं दिये।

चिरस्थायी, कठोर और व्यापक तानाशाही विवेक-शक्ति को प्रोत्साहन नहीं देती क्योंकि उसे वहाँ खतरनाक समझती है। साथ-ही-साथ वह राजनीतिक साहस को भी मृत्यु का संकेत समझकर प्रोत्साहन नहीं देती और लोगों की चिन्तन-प्रवृत्ति को दबाती है क्योंकि उसके विचारानुसार इसकी आवश्यकता उच्च-वर्ग के कुछ इने-गिने व्यक्तियों को ही होती है। अन्य सब लोग तो उनके ही विचारों को दुहराते हैं। रूसी शिक्षा का उद्देश्य कार्य है; चिन्तन नहीं।

बोलशेविज्म के संस्थापकों की यह भय पहले से ही था कि समाजवाद के अन्तर्गत राज्य-सत्ता नष्ट हो जायगी। किंतु उनकी आशा के बिल्कुल विपरीत, रूस से समाजवाद ही उड़ गया है। वहाँ के लोगों में अब राजनीति के प्रति दिलचस्पी न रह गई, न न्याय, नैतिकता और चिन्तन की ही कोई चिन्ता रह गई।

यही वह रूस है, जिसके प्रति लास्की हमसे नया विश्वास उत्पन्न करने को कहते हैं।

हैरॉल्ड जे० लास्की को और उनके साथ-ही-साथ उनके रूस सम्बन्धी विचार से सहमत होने वाले व्यक्तियों को इस समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। रूस की नई पीढ़ी के अधिकांश व्यक्ति, जिनमें तीस वर्ष तक की आयु वाले सभी लोग शामिल हैं, पूर्णतः भौतिकवादी हैं। चूँकि उनके पूर्वज सुअरों के बाड़ों के पास रहते थे और अशिक्षित थे और वे स्वयं शिक्षक, सैनिक-अफसर आदि बन सकते हैं और उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा का विश्वास है, इसलिए वे रूसी शासन को अच्छा समझते हैं। और आज़ादी? "आज़ादी किसे

कहते हैं ?" वे उत्तर देते हैं—“क्या पूजीवादी देशों में आजादी है ? अगले साल हमें खेती के लिए एक और ट्रैक्टर और जूतों के लिए कुछ और चमड़ा मिल जायगा ?” इस तरह की बातें रूस में कई आदमियों से हुईं ।

ह्लो० कावेरीन के सन् १९३१ के “अज्ञात कलाकार” नामक एक रूसी उपन्यास में एक नायक ने कहा है—“सच्चरित्रता ! मुझे तो इस शब्द के सम्बन्ध में सोचने तक की फुर्सत नहीं । मैं काम में लगा हुआ हूँ । मैं समाजवाद का निर्माण कर रहा हूँ । किन्तु यदि मुझसे कोई पूछे कि तुम सच्चरित्रता को अधिक पसन्द करते हो या पतलून को तो मैं उत्तर दूँगा—पतलून को ।” इस कलाकार को रूस की भावी प्रवृत्ति का काफी पहले से ही आभास हो गया था । कावेरीन से बहुत पीछे मैं भी यह समझा कि तानाशाही राज्य-सत्ता आदर्शवाद की हत्या कर देती है ।

रूस की वर्तमान जीवन प्रणाली में भौतिक पदार्थों पर ही ध्यान केन्द्रित होता है । ये पदार्थ अधिकांश रूसियों के लिए आज भी दुर्लभ हैं और सदा ही दुर्लभ रहे हैं । इन्हें प्राप्त करना और पेशेवर उन्नति की अधिकाधिक सम्भावनाओं से भरे हुए आरामदेह जीवन की आशा ही मनुष्य के समस्त प्रयासों का लक्ष्य होता है । यदि तानाशाही राज्य-व्यवस्था से इस उद्देश्य की पूर्ति की आशा हो सकती है तो वह अनिन्द्य है, चाहे उसकी कार्य-प्रणाली कितनी ही अनैतिक, अजनतन्त्री और सांस्कृतिक तथा चरित्र सम्बन्धी विचारों के लिए विनाशकारी क्यों न हो ।

यही आजकल रूस की प्रधान भावना है ।

कहा जा सकता है कि रूसियों के जीवन-मान में काफी उन्नति करने से स्थिति में परिवर्तन आजायगा । किन्तु वह उन्नति अभी सालों दूर है । तब तक नागरिक अधिकारों का दमन, व्यापक हत्या-काण्ड, बड़े-बड़े कान्सेन्ट्रेशन कैंम्प, सर्वसत्तावादी नीरस प्रचार और ऐसी ही दूसरी तानाशाही युक्तियों को, जो कि जनता के लिए अधिक भण्डारों, स्कूलों, पुस्तकों, वच्चों और शस्त्रों की व्यवस्था करने के बहाने से प्रचलित हैं—एक ऐसी महान् दार्शनिकता का रूप दिया गया है कि जिसके प्रलोभन को पश्चिमी देशों के उदार दल वाले और समाज-शास्त्री भी नहीं रोक सकते । इसके अलावा, तानाशाहों द्वारा स्वयं जनता को इस बात का विश्वास दिलाया जा रहा है कि उन्हें सब प्रकार की स्वतन्त्रताएँ प्राप्त हैं । ये स्वतन्त्रताएँ भावी भौतिक लाभों की तुलना में कम महत्वपूर्ण हैं और पूजीवादी देशों में भी किसी को स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं है । जिस तरह आजादी भोगकर ही आजादी के प्रयोग की योग्यता सीखी जाती है उसी प्रकार

आजानी के अधिक दिनों तक प्रयोग में न आने में उसे भोगने की इच्छा कुठित हो जाती है। सन् १९१७ के महीनों को छोड़कर रूस में कभी नागरिक स्वतन्त्रता नहीं रही, इसलिए अविकाश वृत्ति नागरिकों को यह पता ही नहीं कि यह स्वतन्त्रता कितनी सुखकर होती है।

रूस के अनेक नागरिकों में वह मानसिक क्षमता ही नहीं जिसकी महत्ता से वे स्वतन्त्रता को समझ सकें। पल्लवक के 'माशा स्काट' में रूस के सम्बन्ध में बातचीत नामक लेख में श्रीमती स्काट, जो पहले रूस के एक कारखाने में काम करती थी और जिनका अमेरिकन लेखक जान स्काट में विवाह होगया है, पल्लवक से कहती है—“मैं आपको यह बात देना चाहती हूँ कि आप जनता को शिक्षित बनाने का जो ढंग प्रयोग में लाते हैं उसे मैं अच्छा नहीं मानती। उदाहरण के लिए हमारे देश रूस में आप यह बात कही नहीं पा सकते कि दो भिन्न-भिन्न समाचार-पत्रों के दो भिन्न-भिन्न मत हों। अर्थात् ऐसा कभी नहीं होता कि किसी बात को एक आदमी तो ठीक बताये और दूसरा उसी को गलत कहे। जनता कैसे जान सकती है कि इनमें से सत्य कौन-सा है ?”

माशा स्काट और उसकी पीढ़ी के लोगो ने, जो कि रूस की नई पीढ़ी है, सत्य बताने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर ही निर्भर रहना सीखा है। यह काम उनके लिए रूसी सरकार करती है।

मेरा बड़ा लडका जार्ज २१ वर्ष की उम्र में अमेरिकन सेना में कप्तान था। युद्ध के दिनों में वह एक साल तक सोवियत-यूक्रेन-पोलरवाँ के अमेरिकन हवाई अड्डे पर तैनात रहा। उन दिनों में रूस में विदेशी सवाददाता की हैसियत से काम करता था। उसे वहाँ बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ और वह रूसी भाषा बहुत अच्छी तरह बोलता है। सन् १९४४ के शरत्-काल में पोलटावा के अड्डे पर काम करने वाले अमेरिकनो ने राष्ट्रपति के चुनाव में अपने मत दिये। ऐसा करने से पहले उनमें उम्मीदवारों की वैयक्तिक योग्यता के सम्बन्ध में स्वभावतः बड़ा वाद-विवाद हुआ। उनके साथ काम करने वाले रूसियों ने इस असाधारण राजनीतिक हलचल को देखा और पूछा कि बात क्या है।

जार्ज ने कहा—“हर चौथे साल हम अपने राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इस साल जनतंत्र की ओर से रूजवेल्ट खड़े हैं और वही इस समय राष्ट्रपति भी हैं, रिपब्लिकन दल की ओर से डेवे खड़े हैं और हमें इन दोनों में से किसी एक को मत देना है।”

“मैं कुछ नहीं समझा” रूसी सेना के एक लेफ्टीनेन्ट ने कहा, “आपका

कहने का मतलब यह है कि रूजवेल्ट जनतन्त्रवादी है और वह कई वर्षों से राष्ट्रपति है और फिर भी अमेरिकन सेना में रिपब्लिकन है ?”

यदि रूजवेल्ट की जगह पर स्टालिन होते तो वह निस्संदेह इन रिपब्लिकनों का अन्त कर देते ।

क्या लास्की ने रूस के नूतन निवासी की मानसिक प्रवृत्ति का निकटवर्ती रूप देखा है ? तानाशाही का अर्थ केवल बन्दीगृहों और फासियों से नहीं है । तानाशाही शरीर का बध करने से भी अधिक भयकर काम करती है । वह जीवित बचे हुए व्यक्तियों के मस्तिष्क और सकल्प को भी मार देती है ।

स्वेच्छाचारी तानाशाही का इस आधार पर समर्थन करना कि उससे सबको नौकरी मिल जाती है और जनता को उत्तमतर जीवन व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होता है, केवल रूस में ही सीमित नहीं रह गया है । अब यह एक विश्व-व्यापी समस्या बन गई है, आधुनिक पुरुष के सामने शायद यह सबसे बड़ी समस्या है । यदि तानाशाही राज्य-व्यवस्था द्वारा हम बहुलता और सुरक्षा की ओर बढ़ सकते हैं तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, और लैटिन अमेरिका के डेढ़ खरब निवासी, जो शतकों से दरिद्रता की यत्रणा भोगते आये हैं—रूसी जीवन-प्रणाली और साम्राज्य-विस्तार के समर्थक बनाये जा सकते हैं । किन्तु रूस के अनुभव से यह बात सिद्ध नहीं हुई है । इसी तरह यदि रूस शांति की गारण्टी है—जैसा कि सीधे-सादे, अज्ञानी और कुटिल कवि कहते हैं, किन्तु जिसे रूस के आक्रमणकारी कार्य द्वारा प्रमाणित नहीं करते—तो क्यों न जनतन्त्र मिटा दिया जाय और सभी जगह स्टालिनवाद स्वीकार कर लिया जाय ।

आगामी दस वर्षों में एशिया में एक खरब निवासियों और सम्भवतः यूरोप के भी करोड़ों व्यक्तियों को रूसी या अमेरिकन जीवन-प्रणाली में से किसी एक को चुनना होगा । कुछ अमेरिकन विद्वान् उन्हें रूसी जीवन-प्रणाली स्वीकार करने को कह रहे हैं । लास्की ने उन्हीं के सुर-मे-सुर मिलाया है ।

लास्कीवादियों पर बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारी है । जनतन्त्र द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद भी मरा नहीं, किन्तु जब तक सोवियत् रूस की सारी बातें पूरी तरह से खोलकर नहीं कह दी जायगी तब तक इस बात की सम्भावना नहीं कि जनतन्त्र उस बौद्धिक गृह-युद्ध में जीवित बच सकेगा जो इन सभ्य जनतन्त्री देशों में होता है । भगड़े की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उदार-दल वाले जहाँ एक ओर भिन्न-भिन्न देशों के अत्याचारों के विरुद्ध एक आन्दोलन-सा उठा रहे हैं वहाँ वे उस रूसी शासन-प्रणाली का भी समर्थन कर रहे हैं जहाँ क्रूरतापूर्ण मृत्यु-दण्ड, देश-निकाता, निजी स्वतन्त्रता और कलाकारों, लेखकों आदि

की आजादा का दमन एक दैनिक घटना है। उन बातों का एक कारण यह भी है कि लोगो को आशा है कि रूसी जीवन-प्रणाली आधुनिक ससार की आर्थिक समस्याओं को हल कर देगी।

अब तक यह बात सबको मालूम होजानी चाहिए थी कि प्राइवेट व्यवसायियों और व्यवसायों का अन्त करने से रूस में सतयुग नहीं आ पाया है। पूँजीपति को गद्दी से उतारकर उसके स्थान पर एक ऐसे अत्याचारी को बैठाने से जिसके हाथों में सर्वसत्ताधारा राज्य और साथ-ही-साथ समस्त पूँजीपतियों की शक्ति भी है, हम शिष्टता, बहुलता या शांति की ओर अग्रसर नहीं हो सकते। निश्चय ही इनका मार्ग कोई और है।

through a revolution
A revolution in the
of the world. Certainly
was very far from
there is a great deal
A lot of things
out a plan
happening and there
the matter comes
to the fore. The
cut through the
water. The
Then, the

जोसेफ स्टालिन

एक दिन मारकूशा ने आकर मुझे अचम्भे में डाल दिया। यद्यपि १९४४ में “माई लाइव्म इन रश” लिखने के बाद अब वह रूस के सम्बन्ध में एक उपन्यास लिख रही है फिर भी उसे मेरे छान-बीन के काम में हाथ बटाने की फुर्सत मिल जाती है। अचानक पुस्तकालय में उसकी नजर मेरे एक लेख पर पड़ गई, जो मैंने १९२५ में “करेंट हिस्ट्री” के जून वाले अंक में लिखा था। मैंने इस लेख को उतनी ही दिलचस्पी के साथ पढ़ा, जितनी से किसी ऐसे पुराने पत्र अथवा डायरी को पढ़ा जाता है, जिसमें किसी व्यक्ति के बीते हुए जीवन की भूली हुई बातों पर प्रकाश पड़ता हो।

लेख में स्टालिन के सम्बन्ध में निम्न वाक्य थे—“जिनोवीन से अधिक योग्य तथा शक्तिशाली स्टालिन है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का सेक्रेटरी है। १९२४ में लेनिन की मृत्यु के बाद रूस के शासन की वागडोर जिनोवीव, कामेनीव और स्टालिन की जिस त्रिमूर्ति के हाथों में आई, उसमें सबसे शक्तिशाली स्टालिन ही है। उसका जन्म जुगोशिविली में हुआ और पादरी बनने की शिक्षा पाई। फिर क्रान्तिकारी कार्रवाइयों के कारण वह पांच बार गिरफ्तार हुआ और पाचो बार साइबेरिया भेज दिया गया और पाचो ही बार वहां से भाग निकला। ऐसा स्टालिन, स्वभाव से चुप रहने वाला और शक्की मिजाज का व्यक्ति है। वही बोलशेविक सत्ता के भीतर छिपी रहस्यपूर्ण शक्ति है। वह एक अच्छा संगठन-कर्त्ता तथा विवाद-पटु व्यक्ति है। बदला लेने में वह बड़ा निर्दय तथा घृणित है। वह न तो किसी का माफ करना ही जानता है और न उसकी दृष्टि में सरल व्यवहार का कोई मूल्य है। वह एक प्रकार से बोलशेविक क्रान्ति का मूर्तिमान प्रतीक है—भावना-हीन, लौह-सकलपी, कठोर, अपने उद्देश्य के मार्ग में किसी बाधा को सहन न करने वाला और अतः करण जैसी किसी वस्तु में रहित। जो थोड़े शब्द उसके होठों से निकलते हैं उनसे मानो शक्ति चूती रहती है। उसका दफ्तर, जहां वह रात-दिन बैठा रहता है, शक्ति का महान्

बोत है। जिस प्रकार पावर-हाउस से त्रिजली की लहर निकलती है उसी तरह उसके दपतर से निकली हुई विद्युत्-लहर से पार्टी का कार्य निरंतर चलता है। वह पार्टी का सेक्रेटरी और इसीलिए प्रबान व्यवस्थापक है।

“लेनिन स्टालिन पर विश्वास करता है, पर स्टालिन किसी पर विश्वास नहीं करता” ये शब्द हैं, जो रूस में स्टालिन के सम्बन्ध में लोग कहते हैं। यह बात सच हो या नहीं, पर इससे पता चलता है कि स्टालिन के सम्बन्ध में लोगों का क्या मत है। इसका चित्र अपनी कहानी अलग कहता है। स्टालिन की आखों के चारों तरफ पड़ो हुई सिफुडने तथा भुरिया उमकी चतुराई तथा चालाकी को प्रकट करती है।”

अब दुनिया स्टालिन के बारे में पहले से बहुत अधिक जान गई है, क्योंकि अब वह मसार का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हो चुका है। उसके इतना प्रभावशाली होने का कारण यह नहीं है कि उसका देश मसार में सबसे शक्तिशाली है, बल्कि यह कि वह उसकी शक्ति का पूरा-पूरा उपयोग करता है।

स्टालिन शक्तिशाली व्यक्ति है। वह शक्ति प्राप्त करने और उसे बनाये रखने के तरीकों को खूब जानता है। देश के भीतर उसे शक्ति की जल्द-तरत यी और वह उसने प्राप्त कर ली। विदेश में शक्ति प्राप्त करने की उसकी इच्छा हुई और उसे पाने के उपाय करते उसे देर न लगी।

स्टालिन का असली नाम जोसेफ विसारियोनोविच जुगोशिविली है। उस का जन्म १८७९ में एक मोची के घर हुआ, जिसे शराब पीने का शौक था। माता कुछ धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उसने उसे पाठशाला भेजा, पर वह शाला से निकाल दिया गया।

“स्टालिन” का अर्थ है इसपात। इसपात की शलाखे या तो सीधी और मजबूत होती हैं और या उन्हें नाजुक स्प्रिंग अथवा घुमावदार स्क्रू का रूप दिया जा सकता है। स्टालिन का व्यक्तित्व जिस इसपात से बना है, वह जहाँ एक तरफ सख्त और कड़ा है वहाँ दूसरी तरफ नर्म और लचीला भी है। बटूक या रिवा-त्वर का घोड़ा दवाने में उसे ज़रा भी देर नहीं लगती, किन्तु वह अनन्त काल तक अवसर की प्रतीक्षा भी कर सकता है। अन्य लोग जल्दबाजी में असफल कार्य करने की गलती कर सकते हैं, किन्तु स्टालिन धैर्यपूर्वक मौका देखते रहना पसंद करता है। वह पक्का काम करने वाला, मेहनती और ह्छा है। अपने आगे आत्म-समर्पण करने वाले को वह भरपूर इनाम देता है, किन्तु विरोध करने वाले को कभी माफ नहीं करता। उसे कभी कोई बात नहीं भूलती।

सोवियत्-नेता अपने सस्मरण नहीं लिखते। हम स्टालिन के सम्बन्ध में

उसके भाषणों और लेखों के आधार पर तो मत बनाते ही हैं, किन्तु उसके व्यक्तित्व तथा विशेषताओं का सबसे अधिक ज्ञान आज के रूस को देखने से होता है, क्योंकि १९२६ से अब तक स्टालिन सोवियत् रूस को अपनी ही प्रतिमूर्ति बनाने की चेष्टा करता रहा है। सोवियत् रूस के सम्बन्ध में कुछ जानने से स्टालिन के सम्बन्ध में जानकारी अपने-आप हो जाती है और स्टालिन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने से सोवियत् रूस के सम्बन्ध में हमें अनायास ही बहुत कुछ मालूम हो जाता है।

यूरोप में मित्रराष्ट्रों की विजय के कुछ ही दिन बाद जनरल ड्वाइट आइजनहोवर ने लाल सेना के सुप्रसिद्ध सेनापति, मास्को के वीर और बर्लिन के विजेता, मार्शल जुकोव को फ्राकफर्ट में दावत दी थी। दोनों सेनापतियों में जो वार्ता हुई उसे नीचे दिया जाता है। यह वार्ता “न्यूयार्क हेरल्ड ट्रिब्यून” के १८ जून १९४५ वाले अंक में और फिर अमरीकी सेना के सरकारी विवरणों में प्रकाशित हुई थी।

जुकोव—“हमारे अधिकार में रासायनिक तेल की कुछ ऐसी मशीनें हैं, जो हमें अपने कब्जे में आये क्षेत्र में मिली हैं। हमने उनकी मरम्मत कर ली है, पर चला नहीं पाये हैं। शायद अपने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसी ही मशीनों को चलाना शुरू कर दिया है। क्या मैं अपने कुछ कारीगरों को भेजू, जो देख लें कि आपकी मशीनें कैसे चल रही हैं?”

आइजनहोवर—“जरूर, भेज दीजिए। हम उन्हें मशीनें चलाना सिखा देंगे।”

जुकोव—(चकित होकर) “तो क्या आपको अपनी सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी?”

आइजनहोवर—“नहीं, बिल्कुल नहीं। आप भेज दीजिये।”

जुकोव को आश्चर्य इसलिए हुआ था कि गुप्तचर पुलिस अथवा स्टालिन से पूछे बिना वह स्वयं ऐसा कभी न कर पाता। बड़े-मे-बड़े सोवियत् अफसर को किसी विषय में निर्णय करने का अधिकार नहीं होता—उसे तो केवल आदेश का पालन करना होता है। यही सोवियत् शासन-प्रणाली है, जिसका स्टालिन ने निर्माण किया है।

यह एक ऐसी बात है, जो हम रूस और स्टालिन के सम्बन्ध में जानते हैं।

अक्टूबर १९४४ के “रीडर्स डाइजेस्ट” में अमरीकी चेम्बर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष एरिफ ए० जॉन्सन का “जोसेफ स्टालिन ने मेरी वार्ता”

शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ था। जॉन्सन मुझे बता चुके हैं कि लेख में जो बातचीत दी हुई है, वह स्टालिन के कार्यालय द्वारा दिये गए विवरण से ज्यों-की-त्यों ली गई है।

एरिक जॉन्सन साइबेरिया के भ्रमण को निकला था। उसने स्टालिन से कहा — “मैं अपने साथ चार अमरीकी पत्र-प्रतिनिधि यूरोप ले जाने की अनुमति चाहता हूँ।”

“जल्द, क्यों नहीं?” स्टालिन ने कहा।

“तो इसका मतलब है कि मैं ले जाऊँ?”

“अवश्य, ही।”

“धन्यवाद, मार्शल स्टालिन” जॉन्सन बोला—“पर क्या मोलोटोव स्वीकार करेंगे? देखिये, अभी तक उसके कार्यालय (विदेश विभाग) ने मेरा अनुरोध स्वीकार नहीं किया है।”

“इस समय मोलोटोव मेरी ओर देख रहा था”—जॉन्सन लिखता है—एकाएक उसने स्टालिन की ओर दृष्टि फेरी और जल्दी से बोल उठा, “मैं मार्शल स्टालिन के फैसले को हमेशा स्वीकार करता हूँ?”

मार्शल ने अपना सिर एक तरफ को फेरा और खीसें निकाल दी—“मि० जॉन्सन, सचमुच आपका यह खयाल नहीं हो सकता कि मोलोटोव का मुझसे मतभेद होगा।”

यह है स्टालिन का व्यक्तित्व, स्टालिन की तानाशाही और आज का रूस।

सोवियत् रूस के रक्षा-मन्त्री मार्शल वोरोशिलोव से मैंने तथा यूनाइटेड प्रेस के प्रतिनिधि फ्रेडरिक कुट्ट ने भेंट की थी। भेंट का जो विवरण श्री कुट्ट ने तैयार किया उसका विदेश भेजे जाने से पहले सेसर किया जाना जरूरी था। वोरोशिलोव में उसका सेसर खुद करने की हिम्मत न थी। इसलिए वह उसे स्टालिन के पास ले गया।

पहले तो तानाशाह स्टालिन अपने सहकारियों को कोई महत्वपूर्ण निश्चय करने से रोक देता है। कुछ दिन यह परिस्थिति रहने के बाद वे खुद ही कोई निश्चय करना नहीं चाहते। इसी में रक्षा है और यही आसान है। सोवियत् अफसरो की विशेषता अपनी जिम्मेदारी ऊपर वाले अधिकारी के सिर टाल देना है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सोवियत् प्रतिनिधि जो देरी किया करते हैं उसकी वजह भी यही है कि वोट देने या प्रश्न का उत्तर देने से पहले उन्हें क्रेमलिन (रूसी सरकार का कार्यालय) से पूछ-ताछ करनी पड़ती है। जिस

प्रकार एरिक जॉन्सन के सामने स्टालिन द्वारा अपमानित किये जाने पर मोलो-टोव ने अपने को “शक्तिहीन” अनुभव किया था उसी प्रकार सभी सोवियत् अधिकारी पहले अपने को “शक्तिहीन” अनुभव करते हैं और फिर वास्तव में “शक्तिहीन” बन जाते हैं और इस स्थिति से स्टालिन खूब प्रसन्न होता है।

इसी नीति के परिणामस्वरूप सोवियत्-नाजी-संघर्ष के सम्बन्ध में प्रत्येक रूसी नागरिक स्टालिन को ही प्रधानता देता है। जब लाल सेना पीछे हट रही थी उस समय स्टालिन के नाम का सोवियत् पत्रों तथा रेडियो से प्रायः लोप हो गया था। रूसी तानाशाह मनोविज्ञान का अच्छा पंडित है। जिस समय रूसी जनता पराजय की आशंका से चिन्तित थी उस समय स्टालिन नहीं चाहता था कि लोग उसके सम्बन्ध में कुछ भी सोचें। परन्तु जब युद्ध का पासा लालसेना के पक्ष में पलटने लगा तो स्टालिन का नाम फिर सुनाई देने लगा और विजयों का श्रेय भी उसी को दिया जाने लगा।

कुशल प्रचारकों द्वारा स्टालिन के सम्बन्ध में जिन जनश्रुतियों को जन्म दिया गया है उन्होंने रूसी तानाशाह को ससार और इतिहास का सबसे महान् सेनापति बना दिया है। इसमें सत्य का अंश कहा तक है, मैं नहीं बता सकता और न स्टालिन के निकट-सम्पर्क में रहने वाले चंद आदमियों को छोड़कर दूसरा ही कोई बता सकता है। मास्को वाशिगटन, लंदन अथवा पेरिस नहीं है, जहाँ गुप्त-से-गुप्त बातें भी जल्दी या देर में प्रकट हो जाती हैं। कौन कह सकता है कि स्टालिन ने रण-नीति की योजनाएँ स्वयं तैयार की थीं या किसी सेनापति अथवा सेनापतियों द्वारा तैयार योजनाओं पर केवल सही कर दी थी ?

चर्चिल के निजी चिकित्सक लार्ड मोरन का कहना है कि स्टालिन के मन की बात का पता लगाना सहल नहीं है। चर्चिल ने लार्ड मोरन से स्वयं यह बात कही थी। ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ने, जिसे भूतपूर्व इंग्लैंड का सबसे प्रमुख वार्तालाप-प्रिय व्यक्ति कहा जा सकता है, लार्ड मोरन से कहा था कि मैं भारी-भरकम हजवेट को तो अपनी बातों में घसीट लेता हूँ किन्तु काकेशियन पर्वत का वह स्व-निर्मित व्यक्ति, स्टालिन मौन ही बनाये रहता है।

स्टालिन ने स्वाभाविकता को शून्य तक घटा दिया है। उनके कार्य, शब्द, संकेत, मौन तथा अनुपस्थितियाँ सब राजधानी से तैयार की गई योजना के अंग होते हैं। जब स्टालिन सोवियत्-भाजों कानून पर हस्ताक्षर होते समय मुसकराया था तो उसमें हिटलर के लिए एक संदेश छिपा था।

स्टालिन नहीं चाहता था कि चर्चिल उनके मन की बात जानें।

१९३६ तक चोटी के बोलशेविक स्टालिन को “खोज़वेन” या “प्रधान”

कहते थे। अचानक सकेत मिलने पर उन्होंने उसे "स्टारिक" अथवा "वृद्ध पुरुष" कहना शुरू कर दिया, जिसे रूसी भाषा में प्रेमपूर्ण सम्बोधन माना जाता है। तानाशाही शासन में सब बातें—यहाँ तक कि प्यार के सम्बोधन भी—तय की जाती हैं और आदेशों द्वारा उनका प्रयोग कराया जाता है।

सोवियत् प्रचारको ने स्टालिन को जनता के दिल में कील की तरह ठोक-ठोक कर घुसा देने में कुछ भी उठा नहीं रखा है।

१९४५ में स्टालिन को इवेत रुस के २५, ४७, ३६० निवासियों के हस्ताक्षरों से एक अभिनन्दन-पत्र भेंट किया गया था। १८ नवम्बर १९४५ के दिन जोसेफ बार्निन ने मास्को से "न्यूयाक हेरल्ड ट्रिब्यून" को कजाक सोवियत् प्रजातंत्र का २५ वां वार्षिकोत्सव मनाये जाने के सम्बन्ध में एक समाचार भेजा था। इस समाचार में २५,००,००० कजाक नागरिकों के हस्ताक्षरों से स्टालिन के नाम एक पत्र प्रकाशित करने का उल्लेख था। कजाक प्रजातंत्र मध्य एशिया में थोड़ी आबादी वाला प्रदेश है, जिसकी औसत जनसंख्या प्रति-वर्ग किलोमीटर ४ व्यक्ति है। युद्ध से उनके देश के ऐसे भाग में कर्मचारियों को इन पत्रों के लिए हस्ताक्षर प्राप्त करने में कितना परेशान होना पड़ा होगा और इसके लिए कितनी शक्ति, समय और धन की बर्बादी हुई होगी—यह क्या स्टालिन से छिपा होगा? फिर भी ऐसे पत्रों की संख्या रुस में बढ़ती ही जाती है।

६ अप्रैल १९४६ को जनरल फ्रांको के आगे ७,००,००० हस्ताक्षरों की ५० जिल्दे यह प्रमाणित करने के लिए पेश की गई थी कि स्पेनवासी अभी तक उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। मजदूर-विभाग के मंत्री गिरोन ने जिल्दे पेश करते हुए कहा था—“केवल आप ही एक ऐसे स्पेनियाई हैं, जिनका अनुसरण करने के लिए हम हर एक का और हर तरह के विरोध का सामना करने को तैयार हैं।”

जनता से यत्नपूर्वक जो प्रशंसा प्राप्त की जाती है, वह ऐसा करने वालों की आँखों में चकाचौध नहीं पैदा कर सकती। इसका उद्देश्य केवल जनसाधारण तथा विदेशियों को मूर्ख बनाने का होता है। ऐसे कार्य अनेक बार होने का, असाधारण प्रभाव पड़ता है।

“हमारा प्यारा पिता, मित्र और शिक्षक, हमारा गौरव, हमारा अभिमान महान् स्टालिन”—ये शब्द मास्को के एक दैनिक पत्र “ट्रुड” ने १९३९ में अपने २६ जनवरी वाले अंक में लिखे थे। ऐसे ही शब्द सोवियत् रुस के अन्य किसी भी प्रकाशन में मिल सकते हैं। मास्को की “बोलशेविक” पत्रिका

में १९४५ में अपने जुलाई वाले अंक में सोवियत् इतिहास, दर्शन तथा न्याय-शास्त्र सम्बन्धी एक गम्भीर लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें स्टालिन को “युग का सबसे महान् वैज्ञानिक” कहा गया था। स्टालिन की प्रतिमा बहुमुखी है और उसी की कृपा से अनेक देन प्राप्त हुई है—इस आशय के एक-से-एक बढ़कर तारीफ के पुल बांधे जाते हैं और सोवियत् पत्रों तथा पत्रिकाओं में इसके लिए होड़-सी लगी रहती है।

एकतन्त्रीय तानाशाही का “फ्यूहरर” वाला सिद्धांत बोलशेविकों ने हिटलर से कहीं पहले ही स्वीकार कर लिया था। अब से कितने ही साल पहले जब वह प्रकट हुआ था तभी से मैं उससे घृणा करने लगा था। यद्यपि सोवियत् विदेश-विभाग मास्को में रहने वाले पत्रकारों द्वारा स्टालिन की कटु आलोचना पसंद नहीं करता, फिर भी मैंने १९३० में “नेशन” के अगस्त वाले अंक में इस बात की निंदा की थी कि स्टालिन की निजी तारीफें इस अस-भावित ढंग से क्यों प्रकाशित होने दी जाती हैं। मैंने लिखा था—“स्टालिन चिकनी-चुपड़ी बातों, थोथी चापलूसी तथा अरुचिकर प्रशंसा का लक्ष्य बन गया है। लेनिन ने कभी भी ऐसी बातें अपने समय में न होने दी थी और वह जितना लोकप्रिय था उतना होने की स्टालिन कभी आशा नहीं कर सकता .. ऐसा करना न तो बोलशेविकों को ही शोभा देता है और न इसमें राजनीतिक बुद्धिमत्ता ही है। यदि स्टालिन इस सबके लिए जिम्मेदार नहीं है तो वह कम-से-कम उसे सहन तो करता है। वह सकेत मात्र से इसका खात्मा कर सकता है।”

सच तो यह है कि स्टालिन को यह सब पसंद था और अब भी है। उसने इसे प्रोत्साहन भी दिया है। जैसे-जैसे साल गुजरते गये हैं यह प्रचार अधिकाधिक अरुचिकर और भद्दा रूप ग्रहण करता गया है। स्टालिन के नाम पर आठ शहरों का नामकरण किया गया है—स्टालिनग्राड, स्टालिनो गोर्म्क, स्टालिनाबाद, स्टालिन, स्टालिनो, स्टालिनिर, स्टालिनिसी, और स्टालिनोल। इनके अतिरिक्त, असंख्य गावों, कारखानों, सामूहिक खेतों तथा विद्यालयों के नाम भी स्टालिन पर रखे गए हैं। पूर्वी देशों की भाँति देवताओं की तरह पूजे जाने से स्टालिन की “पिता” बनने की भ्रूख शान्त होती है। साथ ही यह एक ऐसा साधन है, जिसके द्वारा एक डिक्टेटर जनता का प्रेम प्राप्त करता है और उसे अपनी आज्ञा मानने के लिए बाध्य करता है। शायद स्टालिन सोचता है कि सोवियत् रूस जैसा कष्ट पीड़ित राष्ट्र, जो धर्म की सुविधा से वंचित है, अपने कष्टों की जड़ इस सरकार का केवल उसी हालत में अधिक नमयंक

हो सकता है जब कि सरकार का प्रधान उसका “पिता” हो। सावियत् नागरिकों द्वारा क्रेमलिन में बन्द “पिता” के प्रति प्रेम का कोई सबूत मुझे अभी तक नहीं मिला है। लेनिन को देशवासी प्रेम पूर्वक “इलिच” कहते थे। भूतपूर्व रक्षा-मंत्री मार्शल वोरोशिलोव से जिन साधारण लोगो तथा बालकों का प्रेम था वे उसे “मिलम” कहते थे। वोरोशिलावस्क नामक जो नगर उसके नाम पर रमाया गया था, उसका नाम हाल ही में स्टेवरोपोल कर दिया गया है। परन्तु स्टालिन, प्रत्येक प्रयत्न के बावजूद, स्टालिन—इमपात ही बना हुआ है। लोग उसके काम करने के प्रभावपूर्ण ढंग पर मुग्ध हैं। परन्तु वह ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसे कोई भी प्रेम करेगा। उसमें स्पन्दन का अभाव है। उसका चेहरा देखने से पता चलता है कि बाहर से जो कुछ आता है उसमें समा ही जाता है, कुछ भीतर से बाहर नहीं जाता। हिटलर ने लाखों प्राणियों को अपने भावावेश से आकर्षित कर लिया था। चर्चिल ने इंग्लैंड को तथा उसकी सीमा के बाहर के भी कितने ही लोगो को मोह लिया था। रूजवेल्ट की मधुर आवाज़ तथा व्यवहार की मृदुता तथा सरलता ने उसके मित्रों की सत्या वड़ाई और उसे सफल बनाया। परन्तु स्टालिन में आकर्षण, सम्मोहन-शक्ति और व्यवहार की मृदुता अथवा सरलता का पूर्ण अभाव है! एक बार मुझे मुलाकात के समय उसके पास सवा छ घंटे बैठने का मौका मिला। सब कुछ मिलाने पर मुझे उसमें शान्त शक्ति, दृढ़ सकल्प, चेतना युक्त निर्देशन तथा एक लक्ष्य के पीछे समस्त प्रयत्नों को केन्द्रीय करने के गुण ही दिखाई दिये। दुनिया में अन्य नेताओं ने जो अधिकार सार्वजनिक आकर्षण के बल पर प्राप्त किया वही स्टालिन ने ऊपर बताई विशेषताओं के साथ राजनीतिक कौशल तथा उच्चकोटि की संगठन-शक्ति द्वारा पाया है। और इस अधिकार तथा शक्ति को पिछले बीस वर्षों से जो वह बनाये हुए है, यह भी कुछ कम बड़ी मौलिक अथवा राजनीतिक सफलता नहीं है। ऐसा करने में स्टालिन को जहाँ एक तरफ उन असह्य समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जो दूसरी सरकारों के सामने उठती हैं, वहाँ दूसरी तरफ उसे उन सस्थाओं को निर्बल करना पड़ा है और उन व्यक्तियों को नष्ट करना पड़ा है, जो तानाशाह के इरादों की आलोचना करते उसे चुनौती देते अथवा उसमें बाधा डालते।

स्टालिन के संगठन का सिद्धान्त रणनीति से मिलता-जुलता है। वह जहाँ अपनी शक्ति बढ़ाने की चेष्टा करता है वहाँ विरोधी की शक्ति को कुचल डालने के लिए भी सचेष्ट रहता है। वह इस सिद्धान्त को सोवियत् रूस के घरेलू मामलों तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में समान रूप से काम में लाता है। इन

दानो ही क्षेत्रों में उसने विरोधियों में फूट पैदा करने, उन्हें अस्त-व्यस्त कर देने, और उनकी शक्ति को प्रभावहीन कर देने की विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है।

स्टालिन ने सोवियत प्रणाली का संगठन जिस ढंग से किया है उसमें विरोध की सम्भावना नगण्य रह गई है। देश में किसानों की ही संख्या अधिक है। ये सरकारी खेतों पर मिल-जुल कर काम करते हैं। भूमि, मशीनों तथा कृषि के औजारों पर सरकार का अधिकार है और वही फसल की खरीदार है। इन किसानों को वर्गों के रूप में संगठित होने की स्वतन्त्रता नहीं है। इस प्रकार किसानों में न तो राजनीतिक एकता है और न आर्थिक शक्ति ही। श्रमजीवियों की मालिक स्वयं सरकार है और ये श्रमजीवी हड़ताल करने को स्वतंत्र नहीं हैं। जिस प्रकार अन्य देशों में मजदूर सभाएं मालिकों के सामने अपनी मांग रख सकती हैं उस प्रकार रूसी मजदूर सभाएं नहीं रख सकती। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वहां मजदूर-सभाएं हैं ही नहीं। यही नहीं, सरकार के लाखों कर्मचारियों तथा सरकारी कारखानों के लाखों मैनेजरो के पास अपने डिक्टेटर की प्रभुता को रोकने अथवा उसका विरोध करने का भी कोई माधन नहीं है। यह ठीक है कि कर्मचारीवर्ग के सहयोग के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। परन्तु रूस में काम न करने वाले को भोजन नहीं मिलता और इस किसी बात पर आपत्ति करने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उच्च अधिकारीवर्ग स्थिति को बनाये रखने में और भी सहायक है। किसी अफसर को कहीं भी भेजा जा सकता है और जेल का द्वार भी उसके लिए सदा खुला रहता है। मोलोटोव से लेकर छोटे-से-छोटा कर्मचारी अपील का अवसर दिये बिना सदा के लिए मार्ग से हटाया जा सकता है। नौकरशाही कारखानों की एक आवश्यक कल है, किन्तु यह कल जिस विजली से चلتی है वह उसे तानाशाह से प्राप्त होती है। कम्युनिस्ट दल भी स्टालिन से स्वतंत्र होकर उस के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकती। पहले यह दल ही राजनीतिक शक्ति का स्रोत मानी जाती थी, किन्तु उसके नेताओं का एक एक करके सफाया कर दिया गया और जो बच गए हैं वे इतने भयभीत हैं कि चू भी नहीं कर सकते। कम्युनिस्ट दल के बाहर राजनीतिक कार्य है हा नहीं और दल के भीतर स्मशानवत् शान्ति है। कोई भी व्यक्ति प्रतिवाद अथवा विरोध करने को स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि मनुष्य स्वतन्त्र तभी रह सकता है जब कि गुप्तचर पुलिस से बचा रह सके। ऐसी स्वतन्त्रता भी क्या स्वतंत्रता है !

इसलिए कहा जा सकता है कि स्टालिन के ह्म ने विरोध प्रकट करने

के साधन का अभाव है। समाचार पत्रों, पार्टियों, मजदूर सभाओं, खेत-सभाओं तथा सरकारी दफ्तरो के हाथ में जो शक्ति होनी चाहिए थी उस पर तानाशाह ने अधिकार कर लिया है। ऐसी स्थिति में सार्वजनिक असंतोष इन साधनों द्वारा प्रकट नहीं हो सकता। लोग दगा मचा सकते हैं अथवा भारत की तरह अहिंसात्मक असहयोग कर सकते हैं, यह तभी सम्भव है जब पुलिस में अव्यवस्था फैल जाय। किन्तु ऐसा हो नहीं सकता। आगपू ने सोवियत् जनता को आज्ञा-पालन खूब सिखा दिया है और उससे आत्म-विश्वास छीन लिया है।

काकेशस-स्थित जाजिया जैसा कोई प्रजातन्त्र मास्को की तानाशाही के विरुद्ध विद्रोह करना चाहे तो केवल उसी अवस्था में कर सकता है, जब इस प्रकार के विद्रोह को स्थानीय अधिकारियों का समर्थन प्राप्त हो सके। परन्तु सोवियत् प्रजातन्त्र सभ्य की सभी सरकारों में ऐसे रूसी कर्मचारी तथा कम्युनिस्ट भरे पड़े हैं, जिन्हें शीघ्र क्रेमलिन से आदेश प्राप्त होते हैं। इसलिए लालसेना की सहायता के बिना कोई विद्रोह सफल नहीं हो सकता।

इस तरह प्रकट हो चुका है कि लालसेना और गुप्तचर पुलिस ही दो ऐसी शक्तियाँ हैं, जो स्टालिन की शक्ति के विरुद्ध सिर उठा सकती हैं। स्टालिन दोनों ही से किस तरह पेश आता है इससे उनकी प्रतिभा तथा प्रभुत्व के कारणों पर प्रकाश पड़ता है।

सोवियत् रूस की गुप्तचर पुलिस का पूरा नाम “पीपल्स कमिसरियेट आफ इंटर्नल अफेयर्स” है, किन्तु लोग उसे “आगपू” ही कहते हैं। इस सगठन के गुप्तचर प्रत्येक शहर, गावों, कारखानों और दफ्तरो में फैले हुए हैं। रूस की सबसे भव्य कतिपय इमारतों में इस सगठन के केन्द्र हैं, जिनके साथ ही जेल भी होते हैं। ‘आगपू’ अपनी शक्ति छिपाने का प्रयत्न नहीं करता। उसके कार्य अवश्य गुप्त रखे जाते हैं, किन्तु उनका अस्तित्व गुप्त नहीं है।

आगपू कितने ही आर्थिक कार्य भी करता है। मैंने दासों के श्रम द्वारा आगपू को नहरें अथवा रेल तैयार करते देखा है, इस कार्य के लिए उसकी बाकायदा प्रशंसा हो चुकी है। आगपू के अपने सशस्त्र फौजी दस्ते हैं। वह सीमा पर अपने पहरेदार रखती है। उसके अपने यातायात साधन हैं और कुछ महत्वपूर्ण इमारतों पर उसका कब्जा है।

मैं आगपू के अफसरों से मिल चुका हूँ। इनमें कुछ पुरुष थे और कुछ महिलाएँ। कुछ वरदी पहने थे और कुछ सादे वस्त्रों में थे। कुछ सोवियत् रूस में मिले थे और कुछ विदेशों के सोवियत् दूतावासों में रहकर अपने तथा विदेशी कूटनीतिज्ञों के कार्यों पर नज़र रखने के लिए नियुक्त थे। कुछ आदर्शवादी थे

और उनका विश्वास था कि उनका कार्य कुछ अप्रिय अवश्य है किन्तु साथ ही आवश्यक है। कुछ अधिकार तथा विलासितापूर्ण सुविधाओं के लिए अपने पदों पर काम कर रहे थे। परन्तु सभी मेहनती, गुप्त कार्य करने वाले तथा भय-व्रस्त थे। उनके भय-व्रस्त होने का कारण यह है कि आगपू का दण्ड जितना भयानक अपने अपराधी सदस्यों के प्रति होता है उतना अन्य किसी के प्रति नहीं। सभी में मिलकर काम करने की भावना की प्रधानता रहती है। प्रत्येक सदस्य अपने कार्य का अभिमान करता है। सब में अपने काम के लिए “कला कला के लिए” जैसी भावना रहती है। ‘आगपू’ एक ऐसे प्राचीन सगठन की तरह है, जिसके सदस्य मौन रखने के लिए शपथ लिये रहते हैं, जो अपने कार्य के लिए सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहते हैं, जो सभी विशेष पद तथा सुविधाओं का उपभोग करते हैं और जो सब-के-सब असफलता को बुरा मानते हैं।

आगपू स्टालिन का आध्यात्मिक शिशु है।

कुछ वर्ष तक आगपू वाले अपनी शक्ति, अपनी सख्या, अपने महत्त्वपूर्ण कार्य तथा तानाशाह के लिए अपने असाधारण महत्त्व को देखकर अनुभव करने लगे थे कि भीतरी मामलों में वे बिल्कुल स्वतन्त्र हैं। इसके अतिरिक्त, आगपू को उन सभी उपायों की भी जानकारी होती है, जिनके द्वारा तानाशाह अपनी शक्ति बढ़ाता है और अपने विरोधियों का अन्त करता है। इस विशेष स्थिति के कारण यह भ्रम होना स्वाभाविक था कि रूस की शासन-व्यवस्था में उसका सबसे महत्त्वपूर्ण स्थान है।

१९३१ में आगपू ने स्टालिन को चुनौती दी। उस समय मैंने “नेशन” में इसका विवरण प्रकाशित कराया था और फिर १९३३ में तत्सम्बन्धी याद की घटनाओं पर प्रकाश डाला था। दोनों ही लेख मास्को से लिखे गए थे।

मैंने १९३३ में “नेशन” में लिखा था—“दो वर्ष पूर्व आकुलोव आगपू का उपप्रधान नियुक्त किया गया था। उस समय सगठन का कार्य-वाहक प्रधान यागोदा था, जिसके दावों की नई नियुक्ति द्वारा उपेक्षा की गई थी। सगठन के स्थायी अफसरो तथा आकुलोव में संघर्ष हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप आकुलोव को डोनेज के कोयला-क्षेत्र में एक छोटे से पद पर बदल दिया गया।”

यागोदा कितने ही वर्ष तक आगपू का प्रधान था और उसने आकुलोव के साथ काम करने से इकार कर दिया। तब स्टालिन को विवश होकर आकुलोव को हटा कर प्रधान के पद पर यागोदा को नियुक्त करना पड़ा। इस प्रकार पहले संघर्ष में स्टालिन को आगपू के विरुद्ध मुट्ठी खानी पड़ी।

पर स्टालिन सहज में हार खाने वाला व्यक्ति नहीं है। अपने स्वभाव के अनुसार कुछ दिन ठहरकर उसने दूसरा प्रयत्न किया। दूसरी बार उसने आकुलोव को आगपू के भीतर न रखकर उसके ऊपर नियुक्त किया।

मैंने “नेशन” में लिखा था—“आकुतोव एक पुराना बोलशेविक तथा लेनिन के साधियों में से था। स्टालिन ने उसे सोवियन्-सभ का अटार्नी-जनरल नियुक्त कर दिया। यह एक नया पद है” इस पद का सबसे आश्चर्यपूर्ण कार्य आगपू के कार्या पर दृष्टि रखना भी है। अटार्नी-जनरल के कार्यों में एक इस बात की देख-रेख करना भी है कि आगपू के कार्य कहा तक कानूनन जायज होते हैं।

इससे बोलशेविक आतंक में कुछ कमी हुई। कई सोवियत् नागरिकों को, जिन्हें यागोदा ने गिरफ्तार किया था, आकुलोव ने छोड़ दिया। आकुलोव मरों को कब्र से निकालकर जिला तो नहीं सकता था, परन्तु जिन लोगों को गलत जुर्म लगाकर जेल में डाल दिया गया था उन्हें उमन छुड़ा दिया। १९३३ के उत्तरार्द्ध में तथा १९३४ के सम्पूर्ण वर्ष में वातावरण की गम्भीरता कम हुई। सोवियत् इतिहास में पहली बार वह स्थिति आई कि गुप्तचर पुलिस उच्च अधिकारियों से परामर्श लिये बिना किसी उड़े इजीनियर अथवा लाल सेना के अफसर को गिरफ्तार नहीं कर सकती थी।

जनवरी १९३४ में आगपू के कुछ न्याय सम्बन्धी अधिकार सोवियत् अदालतों के सुपुर्द कर दिये गए और आगपू का नाम “कमिसरियेट आफ इटर्नल अफेयर्स” रखा गया। परन्तु सात महीने तक कमिसरियेट के प्रधान कमिसार का पद खाली रहा, जो एक असाधारण बात थी। स्टालिन यागोदा की नियुक्ति का विरोध कर रहा था। अन्त में जुलाई १९३४ में यागोदा कमिसार बन ही गया। यद्यपि यागोदा के अधिकार कुछ कम कर दिये गए फिर भी विजय उसी की हुई।

दिसम्बर १९३४ में सेर्जी किरोव की हत्या होने पर, जो एक प्रमुख बोलशेविक नेता होने के अतिरिक्त लेनिनग्राड का राजनीतिक प्रधान भी था, प्राण-दण्ड तथा निर्वासन का ताता लग गया। किन्तु इवर कुछ समय से शासन में उदारता का जो पुट आने लगा था उसमें इन सजाओं से कोई बाधा न पड़ी। १९३६ में नवीन विधान जारी करने की घोषणा कर दी गई।

जहाँ एक तरफ विधान तैयार किया जा रहा था वहाँ मास्को में मुकदमों तथा विरोधियों के दमन द्वारा उस विधान की भावना का गला घोटा जाने लगा। हजारों उच्च सोवियत् अफसरों को, जिनमें से सकड़ों के नाम में अपनी पुस्तक

“मैन एंड पालिटिक्स” में गिना चुका हूँ, गोली मार दी गई अथवा देश-निकाला दे दिया गया।

सोवियत्-विधान को जितना माना गया है उससे कहीं अधिक उसकी अवज्ञा हुई है। कुछ लोग कागज पर लिखे को ही यथार्थ मानते हैं। परन्तु स्टालिन की अधीनता में तैयार किये गए विधान में दी गई नागरिक स्वतन्त्रता का सोवियत् रूस के वास्तविक जीवन में कहीं भी स्थान नहीं है। लोगो ने सोचा कि उन्हें नागरिक स्वतन्त्रता मिलने जा रही है और वे बड़े खुश हुए। उनकी खुशी से प्रकट होता था कि लोग स्वतन्त्रता पाने के लिए लालायित हैं और उसके अभाव का अनुभव करते हैं। सम्भवतः इसीलिए सोवियत् रूस के नेताओं ने विधान की उपेक्षा की है। जनता ने नेताओं की आशा से कहीं अधिक गम्भीरता पूर्वक विधान को ग्रहण किया। पागपू ने गुप्त रिपोर्टें पेश करके स्टालिन को राष्ट्र की भावना से अवगत कराकर यह विश्वास दिलाया कि स्वतन्त्रता उसकी तानाशाही को खतरे में डाल देगी। सच तो यह है कि मुकदमों तथा दमन ने जिस आतंक की सृष्टि कर दी थी उसने विधान की यथार्थता को नष्ट कर दिया था। १९३४ में आतंक घटने, १९३५ में विधान के निर्माण और १९३६ में उसकी घोषणा के उपरान्त फिर मुकदमों चलाये जाने से मैं स्तब्ध रह गया। इन मुकदमों के बीच केवल कुछ प्रमुख व्यक्तियों को ही प्राण-दंड नहीं दिया गया, बल्कि स्वयं लोकतन्त्रवाद का गला घोट दिया गया।

१९३६ और १९३७ में न्याय का नाटक गुप्तचर पुलिस के प्रधान जेन-रिच यागोदा द्वारा खेला गया था। परन्तु २ मार्च १९३८ को यागोदा स्वयं अपराधी से कटहरे में खड़ा हुआ और १३ मार्च को अदालत ने इस नाट्य, दुबले तथा हिटलरी मूछ वाले व्यक्ति को प्राणदंड का आदेश सुना दिया। इस तरह स्टालिन ने उस व्यक्ति का अंत किया, जिसने उसकी अवज्ञा की थी।

यागोदा का उत्तराधिकारी येजोव पांच फुट लम्बा था। उसने दमन-चक्र तेजी से घुमाया, किन्तु स्टालिन ने उसी का दमन कर दिया। येजोव का उत्तराधिकारी लेवरेरी वेरिया स्टालिन की तरह जाजियन था। वह नाटा तथा धूर्त था। मैं उससे १९२४ में टिफलिस में मिला था, जब वह जाजिया की गुप्तचर पुलिस का प्रधान था। उसने जाजिया के मेसैविको का दमन किया था। उसकी उन्नति मुख्यतः स्टालिन के कारण हुई। वेरिया की अधीनता में पागपू तानाशाह का आज्ञाकारी अनुचर बन गया। अटार्नी-जनरल को इन दिनों जितकुल भुजा दिया गया।

१४ जनवरी १९४६ के दिन कर्नल-जनरल सेर्जी एन० कुल्नोव ने वेरिया का स्थान ग्रहण किया। गुप्तचर पुलिस का प्रधान सोवियत् रूस में स्टालिन के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। स्टालिन सोचता है कि गुप्तचर पुलिस के प्रधान के पद पर अधिक दिन रहने वाला व्यक्ति स्वयं महत्त्वाकांक्षी तथा खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए विचारों में ज़रा-सी आज़ादी आते ही स्टालिन उसे अपने पद से हटा देता है। अस्तु, आगपू स्टालिन का विश्वासपात्र साधन है।

स्टालिन को लाल सेना का नियंत्रण करने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। सेनापति, सैन्य-विशेषज्ञ तथा सेनाएँ उन लोकतन्त्री शासन-प्रणालियों की राजनीति में भाग लेती रही हैं, जहाँ जनता के अधिकारों की रक्षा की बात प्रधान मानी जाती है और जहाँ सेना के प्रभुत्व से बचे रहने के आदेशों को माना जा चुका है। लोकतन्त्री देशों ने सेना के प्रभुत्व से बचने के लिए कतिपय उपाय कर रखे हैं—चुनावों में किसी बाहरी प्रभाव को न पड़ने दिया जाय और उनमें किसी प्रकार की जोर-जबर्दस्ती न हो, कितने ही अधिकारियों की चुनाव द्वारा नियुक्ति की जाय, सेना के लिए खर्च की मज़ूरी पार्लमेंट ही करे, और समाचार-पत्र विधान के प्रति अवज्ञा को प्रकट करने के लिए स्वतंत्र रहे। परन्तु तानाशाही में इन सुविधाओं का अभाव होता है। यदि तानाशाही बहुमत का निर्णय मानने को तैयार हो तो फिर उसे तानाशाही कौन कहेगा? जनता का समर्थन प्राप्त न होने के कारण ही तानाशाही को लोकतन्त्री सत्ता की अपेक्षा सेना पर अधिक निर्भर रहना पड़ता है। इससे सेना का महत्त्व बढ़ जाता है। युद्ध से पूर्व जापान में सेना का ही शासन था। हिटलर को अपने सेनापतियों पर सदा कड़ी दृष्टि रखनी पड़ती थी। सेनापति हिटलर का आदेश मानते थे। अन्य कितने ही विशेषज्ञों के निर्णय के विरुद्ध उन्होंने सेना को युद्ध में फसा दिया था, किन्तु कितने ही सेनापतियों ने हिटलर का साथ नहीं दिया और अन्त में उसे मार डालने का षड्यंत्र भी किया। मुसोलिनी को भी सेना के साथ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। स्पेन, आर्जेन्टाइना तथा अन्य देशों में तानाशाहियों को सदा सेना से भयभीत होकर रहना पड़ता है।

फिर रूस में तो लोकप्रिय होने के कारण सेना का और भी अधिक महत्त्व है। यह वास्तव में जनता की सेना है और जनता उसे चाहती भी है। सोवियत् तानाशाही तो एक भावनाहीन शस्त्र है और स्टालिन, मोलोटोव,

जेनोव, एड्रीयेव या मालेनकाव में से कोई भी सोवियत् नेता जन-साधारण के सम्पर्क में भी नहीं आ पाया है। इसके विपरीत, लाल सेना भावना पर आधारित है। उसके मार्शल तथा जनरल, तुखाचेवस्की, तिमोशेको, जुकोव तथा अन्य सेनापति अपने समय में जनता के बड़े प्रेम-पात्र रहे हैं।

लाल सेना के सम्बन्ध में स्टालिन की कठिनाई पर प्रकाश डालने के लिए दो सेनापतियों—जनरल बोरिस एम० शेपोशनिकोव और मार्शल माइकल एन० तुखाचेवस्की से सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं का उल्लेख कर देना अस-
गत न होगा।

शेपोशनिकोव का जन्म १८८२ में हुआ था और वह ज़ार की सेना में एक कर्नल था। उसने सैनिक कार्य पेशे के रूप में ग्रहण किया था और राज-नीति में उसे दिलचस्पी न थी। पहले वह कम्युनिस्ट दल में शामिल नहीं हुआ था, किन्तु १९३० में अपने उच्च-पद के कारण उसके लिए ऐसा करना आवश्यक हो गया।

जारशाही के हजारों दूसरे अफसरों की तरह वह लालसेना में इसलिए भरती हुआ था कि एक देशभक्त के रूप में देश की रक्षा करते हुए शत्रु से लड़ सके।

तुखाचेवस्की का जन्म १८९३ में हुआ था। वह नई पीढ़ी का था। वह ज़ार की सेना में लेफ्टिनेंट था और १९१८ में कम्युनिस्ट दल में शामिल हो गया था। उन दिनों दल में सम्मिलित होना बड़ी जिम्मेदारी और खतरे का काम था। २७ वर्ष की अवस्था में तुखाचेवस्की ने पोलैंड के भीतर वारसा के द्वार तक लालसेना की विजय-यात्रा का नेतृत्व किया। यूरोप में उसे "प्राधुनिक नेपोलियन" का नाम दिया गया। परन्तु तुखाचेवस्की पहले दर्जे का सेनापति होने के साथ-ही-साथ राजनीतिक दृष्टि से विचारशील भी था। लाल सेना के युवा कम्युनिस्ट-अफसर उसे अपना नेता मानते थे।

क्रमशः लालसेना में दो दल हो गए। एक में राजनीति में दिलचस्पी न रखने वाले पुराने सैन्य विशेषज्ञ थे, जिनका नेता शेपोशनिकोव था। दूसरे दल में तुखाचेवस्की जैसे युवा कम्युनिस्ट अफसर थे। दोनों दलों में प्रति-स्पर्धा बढ़ी, जिसमें स्टालिन ने शेपोशनिकोव का पक्ष लिया।

१९३६ में शेपोशनिकोव को लालसेना का चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ नियुक्त किया गया। परन्तु तुखाचेवस्की के अनुयायी-अफसरों के विरोध करने पर उसे वोल्गा जिले में एक छोटे पद पर बदल दिया गया। साथ ही तुखाचेवस्की को चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ बना दिया गया।

१९३७ में तुखाचेवस्की को भी हटाकर वोल्गा जिले में एक छोटे पद पर बदल दिया गया और उसके स्थान पर फिर शेपोशनिकोव को चीफ आफ स्टाफ नियुक्त किया गया ।

उसी वर्ष १२ जून को तुखाचेवस्की तथा आठ सर्वोच्च जनरलो और मार्शल को पदच्युत करने के अभियोग में, जो प्रमाणित न हो सका था, प्राण-दण्ड दे दिया गया । ११ मई के जिस आदेश के द्वारा तुखाचेवस्की को वोल्गा जिले में भेजा गया था उसी आदेश के द्वारा सेना के साथ राजनीतिक कमिसार रखने की प्रथा फिर जारी कर दी गई । कमिसार गैरसैनिक अफसर होते थे । सेना के अधिकार उनके तथा सैन्य अफसरों के बीच बंटे थे—यहां तक कि कभी-कभी वे सेना के अफसरों के आदेशों को रद्द भी कर देते थे । 'प्रवदा' के शब्दों में कमिसार "सेना में कम्युनिस्ट दल की आखें और कान" थे । वास्तव में दल और आगपू का उद्देश्य तुखाचेवस्की के मृत्यु-दण्ड के बाद उनके अनुयायी-अफसरों पर कड़ी नजर रखने का था ।

सेना के अफसर कमिसार रखे जाने के विरुद्ध थे और वे शेपोशनिकोव को भी नहीं चाहते थे । १० अगस्त १९४० को शेपोशनिकोव को चीफ आफ स्टाफ के पद से अलग कर दिया गया । १२ अगस्त को कमिसार नियुक्त करने की प्रथा भी तोड़ दी गई ।

कमिसार शेपोशनिकोव के साथ आये थे और उसी के साथ गये ।

जुलाई १९४१ में जब कि लालसेना जर्मनों से मार खाकर पीछे हट रही थी और अफसरों का प्रभाव घट रहा था, कमिसारों को फिर रखा गया । १ नवम्बर १९४१ में, जब जर्मन-सेना मास्को के द्वार पर पहुंच गई थी, शेपोशनिकोव को फिर चीफ आफ स्टाफ बनाया गया ।

स्टालिन की चालों में कोई नवीन सूझ-बूझ नहीं दिखाई देती, किन्तु बार-बार दोहराये जाने के कारण उनका चमत्कार बढ़ जाता है । इसी तरह स्टालिन के युद्धकालीन भाषणों तथा युद्ध-आदेशों में जो दृष्टिकोण ग्रहण किया गया था उसमें भी कोई विशेषता नहीं थी । अपनी युद्ध-समीक्षाओं में उसने एक विषय को सदा एक ही प्रकार उपस्थित किया है । यही कारण है कि वे हमें स्कूली बालकों को पढ़ाये जाने वाले सक्षिप्त विवरणों से अधिक और कुछ नहीं जान पड़ती । उन समीक्षाओं में नवीन विचार-धारा अथवा साहसपूर्ण विश्लेषण का अभाव ही रहता है । इस पिष्टपेषण में ही उसकी शक्ति छिपी हुई है । स्टालिन में बौद्धिक-ज्ञान अधिक न होने के कारण उसकी ध्वनि में अहम्भ्यता या घमंड का लेश नहीं रहता । दूसरे व्यक्ति द्वारा यह कह सकने की सम्भावना

कि स्टालिन यह पहले कह अथवा कर चुका है, तानाशाह को कभी परेशान नहीं करती और न ऐसा खयाल ही कभी उसके मन में उठता है। एक बात के बार-बार दुहराने से स्टालिन की इस कमजोरी पर प्रकाश भले ही पड़ता हो, किन्तु उसका शिकार जो भी कोई बनता है उस की सुध-बुध जाती रहती है।

स्टालिन ने यागोदा को गुप्तचर पुलिस विभाग में आगे बढ़ने से दो बार रोका। सेना में राजनीतिक विचार वाले अफसरों की रोक-थाम के लिए स्टालिन ने कमिमारो को तीन बार रखा। एक ही कार्य वह एक ही ढंग से कितनी ही बार करता है।

१० अक्टूबर, १९४२ को स्टालिन ने कमिसारों को एक बार फिर हटाया और सेना-नायकों के हाथ में पूरे अधिकार सौंप दिये। इससे उनके अधिकारों पर तहरीरी छाप लग गई। स्टालिन ने सेना में जिस विशेष वर्ग को जन्म दिया था उसके आगे युद्ध-परिस्थिति के कारण स्वयं उसी को सिर झुकाना पड़ा। जर्मनी के साथ युद्ध के मध्य में वह उसका दमन नहीं कर सकता था।

यद्यपि स्टालिन अफसरों के आगे झुक गया था फिर भी वह अन्य उपाय करने से चूका नहीं। वह सेनापतियों को अक्सर बदल दिया करता और छोटे अफसरों का समर्थन पाने की चेष्टा करने लगा। यह खयाल करके सैनिक अपने सेनापतियों के प्रभाव में रहते ही हैं, स्टालिन ने गैर-सैनिक कम्युनिस्ट नेताओं को सेना में उच्च-पद देना आरम्भ कर दिया। एंड्री ए० जेनाव को कर्नल-जनरल तथा यूक्रेन की कम्युनिस्ट दल के नेता एन० खुश्चेव को लेफ्टीनेन्ट जनरल का पद दे दिया गया। उसने इस बात की विशेष सावधानी रखी कि कोई प्रथम श्रेणी का सेनापति सर्वोच्च पोलिटव्यूरो में न आने पाय। परन्तु आगपू का प्रधान उसमें उप-सदस्य के रूप में रख लिया गया। यद्यपि वह एक भी मोर्चे पर नहीं लड़ा था, फिर भी उसे मार्शल का पद देकर सर्वोच्च सेनापतियों के समकक्ष बना दिया गया। स्टालिन नहीं चाहता था कि लाल सेना आगपू से बढ जाय। स्टालिन ने स्वयं अपने को प्रधान सेनापति के पद से विभूषित किया।

वाल्टर केर रुस के सम्बन्ध में ऐसी छोटी-छोटी बातों का उल्लेख करने के लिए प्रसिद्ध है, जिनसे महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश पड़ता है। १९४२ में उसने 'न्यूयार्क हेरल्ड ट्रिब्यून' के १८ नवम्बर वाले अंक में मास्को से भेजा हुआ अपना एक लेख प्रकाशित कराया था। इसमें उसने लिखा था कि नोवोवित् पोलो में जरा साविपत्-सच के १० गैर-सैनिक नेताओं के नामों का अक्षर

उल्लेख होता है, वहा सेना के सर्वोच्च सेनापतियों, जैसे जनरल जुकोव, मार्शल तिमोशेंको, मार्शल शेपोशनिकोव और मार्शल बुडेनी की कभी भी चर्चा नहीं रहती। बात यह है कि स्टालिन सेनापतियों को अधिक लोकप्रिय नहीं होने देना चाहता और न वह यही चाहता है कि उन्हें विजयों के लिए अधिक श्रेय मिले।

राजनीति का चतुर कलाकार स्टालिन अनेक कठिनाइयों के बावजूद युद्धकाल में सेना पर अधिकार बनाये रख सका है। शान्ति से तो तानाशाह का कार्य और भी सरल हो जाता है।

परन्तु स्टालिन रूसी सैन्यवाद का विकास रोक नहीं सका है और न इसका कोई प्रमाण है कि वह उसे रोकना चाहता था। कितने ही रूसी कूटनीतिज्ञ हमें सैनिक वर्तियों में दिखाई देते हैं। कितने ही एडमिरल और जनरल कूटनीतिक पदों पर काम कर रहे हैं। १९४० में ३० अगस्त को 'प्रवदा' न लिखा था "सेनानायक का पेशा देश में सबसे सम्मानपूर्ण माना जाता है।" यवको को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सोवियत् स्कूलों में सह-शिक्षा को जो बढ़ाकर दिया गया है उसका कारण यह है कि लड़कों की सैन्य-शिक्षा स्कूलों में आरम्भ हो जाती है और ऐसी परिस्थिति में लड़कियों के स्कूलों का अलग होना ही उचित है। जनरल जॉन आर० डीन का, जो मास्को में अमरीकी सेना के प्रतिनिधि थे, कहना है कि लालसेना की शान्तिकालीन सख्या ४०,००,००० निर्धारित की गई है, किन्तु देश की आर्थिक अवस्था देखते हुए यह सख्या अधिक है। इतनी विशाल स्थल-सेना बनाये रखने और नौ सेना का स्टालिन के आदेशों के अनुसार विस्तार करने का मतलब यह होगा कि विशेष सुविधाओं का उपभोग करने वाले तथा राजनीतिक आकांक्षाएँ रखने वाले अनेक अफसर देश भर में फैले रहेंगे। इसका यह भी मतलब होगा कि सोवियत् प्रचारकों को रूसी जनता से यह कहने का अवसर मिल जायगा कि देश को विदेशी शत्रुओं से खतरा है और इसलिए लोगों को चाहिए कि राष्ट्र की शक्तिशाली बनाने के लिए कोई प्रयत्न बाकी न छोड़ें। इस प्रकार रूस में घबराहट तथा थकान का वातावरण बना ही रहेगा।

१८१३ में रूस की एक जारशाही सेना ने पेरिस में प्रवेश किया था। उस समय रूसी अफसरों तथा सैनिकों ने यूरोप देखा था। उसे देखकर अपने देश की पिछड़ी हुई अवस्था निर्धनता तथा अत्याचारों के प्रति उनकी आँखें खुल गईं। १८२५ में फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा पाकर कुछ रूसी अफसरों ने प्रसिद्ध डिसेम्ब्रिस्ट-क्रान्ति कर डाली। विद्रोह असफल रहा, किन्तु जनता के

मस्तिष्क से उसकी स्मृति कभी नहीं मिटी ।

अब एक दूसरी रूसी सेना यूरोप देख चुकी है । यद्यपि यह वम-वर्षा से ध्वस्त, भूखा, फटे हाल, सुस्त, सकट-ग्रस्त, दुखी तथा दुविधा में पड़ा यूरोप था, फिर भी रूसी सैनिकों तथा अफसरों को वह अपनी मातृभूमि से अधिक सुखद, अधिक प्रगतिशील तथा अधिक स्वाधीन लगा । रूसी अधिकारियों ने इसे देखा और वे कुछ चिन्तित हो उठे । सितम्बर १९४४ में एक दिन “प्रवदा” ने एक छ कालम का लेख प्रकाशित किया, जो लालसेना के साथ बुखारेस्ट जाने वाले विशेष युद्ध-सवाददाता की कलम से लिखा गया था । इसमें रूसी सैनिक से अनुरोध किया गया था कि उसे इस “बेढगे प्रकाश” से चकाचौंध में न आना चाहिए । १९४५ के अक्टूबर मास में रूसी उपन्यासकार सिमोनेव ने इस विषय को लालसेना के मुखपत्र “रेड स्टार” में दुबारा उठाते हुए रूसी सैनिक से अनुरोध किया कि विलासितापूर्ण नागरिक जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा देश के लिए त्याग करना कहीं उत्तम है । इस अनुरोध का प्रभाव न पड़ने का अनुमान करके सिमोनेव ने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में सोवियत नागरिकों के लिए अधिक उत्तम सामग्री जुटाई जायगी ।

यूरोप की अवस्था देखने से लालसेना की जो आखे खुली हैं उसके परिणामस्वरूप अब वह जनता की आर्थिक अवस्था में सुधार के लिए जोर डालेगी । रूस की मौजूदा हालत ऐसी नहीं । ऐसी अवस्था में जनता के रहन-सहन के दर्जे में उसी हालत में सुधार किया जा सकता है, जब कि लालसेना के लिए आवश्यक व्यवसायों तथा धनराशि की दिशा बदल दी जाय, यह स्टालिन के लिए सबसे ताजी समस्या है ।

कल्पना कीजिये कि स्टालिन की मृत्यु हो जाती है । इस प्रश्न पर समस्त लोकतंत्रीय ससार में विवाद हो चुका है । किसी एक व्यक्ति की सम्भावित मृत्यु के सम्बन्ध में शायद ही कभी इतनी बहस छिड़ी हो—उससे शायद ही कभी इतनी आशाएँ की गई हो । क्या स्टालिन की मृत्यु के बाद लालसेना अधिकार ग्रहण कर लेगी ? क्या वह उसके उत्तराधिकारी का चुनाव करेगी, इन प्रश्नों का उत्तर “न” ही हो सकता है ।

किसी भी व्यक्ति के साथ उसके कार्यों का अंत नहीं हो जाता । वह अपनी विरासत छोड़ जाता है और स्टालिन की विरासत तो सचमुच बहुत ही बड़ी है । उसके बीस वर्ष के शासन के परिणाम को तुरत भिटाया नहीं जा सकता । विशेषकर इस हालत में और भी जब कि उसके कार्यों ने भौगोलिक, मानविक तथा संस्थाओं का रूप-धारण कर लिया हो । स्टालिन ने मानचित्र ही

बदल दिया है। यह मानचित्र अभी बना हुआ है। उसने मस्तिष्क को पुनः स्कार किया है। यह भी आसानी से नहीं बदला जा सकता। उसने निजी पूजावाद को नष्ट करके उसका स्थान राज्य को दिया। इस मौजूदा हालात में तबदीली करने का शायद ही कोई नेता साहस करेगा।

स्टालिन के मरने पर सोवियत प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की कोई आशा नहीं है। लेनिन के मरने पर रूस में न्यायमान लड़ाईयाँ छिड़ गईं। ये काफी अरसे तक चली और पहले दर्जे के सभी बोलशेविक नेताओं ने उसमें भाग लिया। परन्तु बोलशेविक सत्ता के लिए कमी भी खतरा नहीं उपस्थित हुआ। देश भर में इस समस्या को लेकर बहस छिड़ गई। नेता तथा साधारण लोग खुलकर तर्क-वितर्क करने लगे। ग्राज दल क्रेमलिन (सोवियत सरकार) के कार्यों की साधन बन गई है। उनकी आत्मा मर चुकी है।

स्टालिन की मृत्यु पर उसके इर्द-गिर्द रहने वाले नेताओं की मडली के बाहर राजनीतिक संघर्ष होने की सम्भावना नहीं है। यदि स्टालिन ने अपना उत्तराधिकारी चुना, जैसा कि मुझे आशा है वह करेगा, तो उसके फैसले को केवल आगपू ही बदल सकता है, सेना नहीं।

आगपू लालसेना की अपेक्षा छोटा है और इसमें सैनिक भी कम हैं। फिर भी राजनीतिक शक्ति उसके हाथ में अधिक है। स्टालिन और उसका आगपू सदा लालसेना को मुह की खिला सकते हैं, जिस तरह हिटलर और हिमलर मिलकर राजनीतिक संघर्ष में जर्मन-सेना को परास्त कर सकते थे। यही कारण था कि स्टालिन तुखाचेवस्की तथा लालसेना के प्रमुख सेनापतियों को मृत्यु के घाट उतार सका था। इस सगीत घटना को सोवियत इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना कह सकते हैं, किन्तु इसमें आवश्यकता केवल यही पड़ी कि आगपू के सैनिकों ने सूचा में निशान लगे ६ जनरलों तथा मार्शलों के मकान घेर लिये। यदि जनरल षड्यंत्र कर रहे थे तो उन्हें अपने सैनिकों के बाच रहना चाहिए था और गिरफ्तार किये जाते समय लड़ना चाहिए था। परन्तु सम्भवतः ये लोग सोते हुए मिले और आगपू के सैनिकों ने उन्हें जगाया। सेनापतियों में से एक, जनरल गमानिक बोलशेविक गृह-युद्ध में बड़ी वीरता से लड़ा था और सेना में राजनीतिक शिक्षा का डाइरेक्टर था। उसके सम्बन्ध में प्रकाशित सरकारी समाचार में कहा गया था कि गुप्तचर पुलिस के बुलाने पर उसने आत्म-हत्या कर ली। अन्य जनरल भी जानते थे कि उनके आगे दो ही मार्ग हैं, एक तो यह कि अपने रिवाल्वर से मुंह में गोली मारकर मर जाय और दूसरा यह कि आगपू के रिवाल्वर से पीछे गर्दन में गोली खाकर मरें।

खयाल से कि मृत्यु जितनी देर के लिए टले, अच्छा है—इन लोगो ने आगपू के ही हाथो मरना उत्तम समझा ।

स्पष्ट है कि डिक्टेटर की स्थिति सेना की तुलना में अधिक लाभपूर्ण है । सेना का कोई वर्ग सत्ता प्राप्त करने के लिए या तो गुप्त षड्यंत्र कर सकता है और या तानाशाही पर दबाव डाल सकता है किन्तु दबाव डालन पर गुप्तचर पुलिस असतुष्ट व्यक्तियों का सफाया करके तानाशाह के रास्ते का काटा दूर कर सकती है ।

ऐसी अवस्था में लालसेना के असतुष्ट व्यक्तियों के आगे दो ही रास्ते हैं—सशस्त्र विद्रोह अथवा मौन आज्ञा-पालन । चंद अफसर स्टालिन या उसके उत्तराधिकारी के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं या एक ही अफसर तानाशाह की हत्या की चेष्टा कर सकता है, परन्तु स्टालिन की खूब देख-रेख की जाती है । स्टालिन के सामने उपस्थित होने से पूर्व लाल-सेना के जलरल तक को तलाशी देनी पड़ता है । इसलिए किसी एक व्यक्ति द्वारा हत्या होने की सम्भावना कम है, यद्यपि उसे असमय नहीं कहा जा सकता । साथ ही यह भी मानी हुई बात है कि हत्यारो या षड्यंत्र-समिति के सदस्यों को अपने उद्देश्य में सफलता मिले या नहीं, किन्तु वे अपने-अपने परिवारो, मित्रो, सहयोगियो तथा जान-पहचान वालो तक के प्राणो को सकट में डाल देंगे । विद्रोह के लिए अखिल राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ेगी । इतना ही नहीं, षड्यंत्रकारियों को विभिन्न क्षेत्रों के सेनापतियों में सलाह लेनी पड़ेगी ।

लाल सेना का एक जनरल षड्यंत्र की बात सेना के अपने किसी मित्र से कर सकता है । वे दोनों एक तीलरे व्यक्ति से बातें कर सकते हैं । परन्तु यदि वे तीनों किसी चौथे या पाचवें आदमी से बात करे तो उसके मन में सहसा प्रश्न उठेगा—“क्या ये मेरी परीक्षा कर रहे हैं ? क्या ये आगपू के लिए पता लगाना चाहते हैं कि मैं कितना राजभक्त हूँ । यदि मैं उनकी शिकायत नहीं करता तो ये मेरी शिकायत कर देंगे ।” इसलिए अपनी हिफाजत के खयाल से वह उनकी शिकायत पुलिस से कर देगा । इसके अतिरिक्त, प्रत्येक दफ्तर और रेजिमेंट में गुप्तचर पुलिस के भेदिये रहते हैं, जो अधिकारियों के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्र का भडाफोड करने को उत्सुक रहते हैं । इस प्रकार रूस में शक्ति की कुंजी आगपू के हाथ में है । सोवियत् सघ से सशस्त्र विद्रोह भी बड़ी भारी बाजी लगाने के समान है । उच्च आदर्शवादी या दुस्साहसी लोग ही ऐसा कर सकते हैं और यह प्राय निश्चित है कि वे असफल होंगे ।

आगपू का लाल सेना के ऊपर जो अधिकार है उनसे दोनों में दुर्भावना

वनी रहती है। कहीं-कहीं एक ही प्रकार के कार्य करने के कारण उनके मध्य शत्रुता बढ़ गई है। आगपू और लाल सेना दोनों के गुप्तचर विदेशों में काम करते हैं। सोवियत् सीमा पर आगपू का पहरा है। इससे कुछ पीछे लाल सेना की चौकियां हैं। जिन सरकारों के विभाग अधिक-से-अधिक सहयोग पूर्वक काम करते हैं उनमें भी कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विवाद उठ खड़े होते हैं। सेना में आगपू के विरुद्ध जो असंतोष है उसका एक कारण यह भी है कि वह सेना में अपने गुप्तचर रखता है और सेना के अफसरों को गिरफ्तार कर सकता है।

यह भविष्यवाणी करना मूर्खता होगी कि स्टालिन से कम चतुर तानाशाह आगपू अथवा सेना पर नियन्त्रण रखने में समर्थ न हो सकेगा। गुप्तचर पुलिस तानाशाह के सामने पड़्यत्र अथवा शत्रु का पता लगा कर अपना महत्व सिद्ध कर सकती है। सेना विदेश में युद्ध छेड़ कर स्वदेश में अपनी राजनीतिक शक्ति बदल सकती है।

लालसेना के आगपू विरोधी होने के कारण कुछ लोगों ने आशा की है कि लाल सेना रूस को अधिक लोकतन्त्री बना सकेगी, क्योंकि आगपू पर विजय वास्तव में उसके आतंकवादी उपायों तथा व्यक्तिगत जीवन पर आक्रमण करने के असीम अधिकारों पर विजय प्राप्त करने के समान होगा। अब तक इसका कोई भी लक्षण प्रकट नहीं हुआ है कि लालसेना अथवा अन्य कोई संगठन सोवियत् रूस में लोकतन्त्र की वृद्धि करेगा। मैं चाहता हूँ कि रूस के समाचार पत्र इस दिशा में कुछ करें। इस सम्बन्ध में कोई लक्षण देख कर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। रूस में लोकतन्त्र की स्थापना होने से सोवियत् राष्ट्र और हमारा यह ससार खतरे से अधिक खाली हो जायगा।

रूसी अधिकारियों ने जो यह नीति ग्रहण की है कि वहाँ पहले ही लोकतन्त्र है, इससे स्टालिन के बाद भी लोकतन्त्र स्थापित होने की आशा क्षीण हो गई है। बोलशेविक शासन के शुरू के दिनों में लोकतन्त्र को ध्येय बताया जाता था, किन्तु स्वतन्त्रता की मात्रा कम हो जाने के बावजूद अब सरकार कहती है कि रूस में लोकतन्त्र पहले ही से मौजूद है। यदि स्वाधीनता के अभाव को सरकारी तौर पर स्वाधीनता बताया जा रहा है तो स्वाधीनता के लिए आन्दोलन को कैसे सहन किया जा सकेगा? उसे तो स्वाधीनता पर हमला ही बताया जायगा।

मास्को के "न्यूटाइम्स" ने जनवरी, १९४६ में कहा था कि रूमानिया तथा बल्गारिया की पश्चिमी लोकतन्त्र के निगूढ़ सिद्धान्तों से रक्षा होनी चाहिए। उस का यह भी कहना था कि आजकल ये देश ठोस रूसी लोकतन्त्र का उपभोग कर रहे हैं, किन्तु मि० बेविन उस पर पश्चिमी ढंग का लोकतन्त्र

लादना चाहते हैं। पश्चिमी लोकतन्त्र के सिद्धान्त निगूढ़ हो सकते हैं, किन्तु वे निगूढ़ केवल उन्हीं के लिए हैं, जो उनका उपभोग नहीं करते। उनमें जा भी कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। परन्तु स्टालिन ने अब तक जिस प्रकार स्वतन्त्र चुनावों, स्वतन्त्र सभाओं, स्वतन्त्र मजदूर सभाओं, स्वतन्त्र अदालतों, स्वतन्त्र भाषणों और स्वतन्त्र समाचार पत्रों के अभिशाप से रूस को बचाया है उसी तरह इन बुराइयों से वह रूमानिया और बल्गारिया की भी रक्षा करना चाहता है। स्टालिन राज्य के हाथ में पूरा अधिकार देना चाहता है।

एक ऐसा राज्य, जो व्यक्ति को न तो राजनीतिक अधिकार देता है और न उसके सुख सुविधा के सामान ही जुटा पाता है, आखिर उसे क्या देता है? उसने सावियत् नागरिक को राष्ट्रीयता दी है। उसने नागरिक की छाती पर पदक लगाये हैं, उसे मूर्ति दी है कि कहीं वह मूर्ति-भजक न बन जाय। राज्य ने अधिक सतान उत्पन्न करने तथा निर्धनों के लिए तलाक की सुविधाएँ उपजव्व न करने के सदिग्ध तरीकों द्वारा पारिवारिक बंधनों को अधिक दृढ़ बनाने की चेष्टा की है। उसने सरकार की सामाजिक सफलताओं का डका पीटा है और पश्चिमा देशों के “पू जीवादी गुलामों” द्वारा सहन किये जाने वाले कष्टों से उनकी तुलना की है। उस राज्य ने अपने नागरिकों को त्योहारों के रूप में सर्कस, कार्नीवाल, हवाई तमाशे और साइबेरिया के आरपार होनेवाली उड़ानें दी हैं और समाचारपत्रों ने इनकी प्रशंसा में धूम मचा दी है और अपने आवे कालम भर दिये हैं, जैसे अन्य किसी देश ने कभी ऐसी उड़ानें, ऐसी परेडे और ऐसे तमाशे कभी देखे ही न हो।

सभी देशों के तानाशाहों ने अपने यहां के लोगों का ध्यान बटाने के लिए तरह-तरह के तरीकों से काम लिया है, किन्तु स्टालिन ने तो उसे ललित-कला का रूप दे दिया है।

कभी-कभी जनता का ध्यान उसके कठोर जीवन से हटाने के लिए कूट-नीतिक तथा सैनिक विजयों का आसरा लिया जाता है। नाज़ियों, इटालियन फाशिस्टों और जापानी सेनावादियों को अपनी जनता पर नियंत्रण रखने के लिए विदेशों में विजय पाने की जरूरत हुई थी। उन्होंने युद्ध का एक दिन के रूप में स्वागत किया था। १९३४ में मुसोलिनी ने लिखा था—“केवल युद्ध ही मनुष्य की शक्ति का प्रदर्शन चरम सीमा पर पहुंचाता है और जो राष्ट्र उसका सामना खुलकर करता है उस पर वह श्रेष्ठता की छाप लगा देता है।” स्टालिन ने ऐसी मूर्ततापूर्ण बात कभी नहीं कही है और न वालशेविकों ने कभी उसका प्रचार ही किया है।

दार्शनिकों ने कुछ राष्ट्रों की आक्रामक प्रवृत्तियों की जिम्मेदारी उनके दार्शनिकों पर आदी है। मनोविज्ञान के पंडितों ने इन प्रवृत्तियों का कारण राष्ट्रीय आघात, मानसिक अव्यवस्था या वर्चस्व अवस्था को बताया है। मूल कारण जो भी हो, हाल के इतिहास में पता चलता है कि यदि अधिकार तानाशाहियों के हाथ में न हो तो इन प्रवृत्तियों के रहते हुए भी युद्ध नहीं छिड़ते। सोवियत रूस ने दार्शनिक न रहने पर भी हमला किया है।

दूसरा महायुद्ध छेड़ने की जिम्मेदारी तानाशाहियों पर है और लोकतंत्रों ने खुशामद करके तथा तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण करके उसमें तानाशाहियों की सहायता की है। तुष्टीकरण का मतलब है शक्ति का परित्याग; और वह बुद्धि के परित्याग का परिणाम है। हिटलर के शुरू के दिनों से ही भौतिक शक्ति अधिक होने पर भी लोकतंत्र तानाशाहियों के आक्रमण से भयभीत होकर पीछे ही हटते रहे हैं।

जहां तक हिटलर, मुसोलिनी और हिरोहितो का सम्बन्ध है, लोकतंत्रों की पृष्ठगति भौतिक थी, वे बड़े, हम पीछे हटे। इस तरह हमने तानाशाहों की शक्ति उनके देशों में बढ़ा दी। उनका घृणा हमारे प्रति बढ़ गई। वे सोचने लगे कि वे दुनिया का जीत सकते हैं।

जहां तक स्टालिन का सम्बन्ध है, पश्चिमी महाशक्तियों की पृष्ठगति भौतिक ही नहीं, आध्यात्मिक भी है। हम उसके सामने झुकते ही नहीं, हम उसका मान भी बढ़ाते हैं। यह हमारे युग की सबसे चकित करने वाली बात है।

रूस के इस पुत्र स्टालिन ने अपने महाद्वीप पर जादू कर रखा है और यूरोप पर भी प्रभाव जमा दिया है। रूस तथा साम्यवाद के मित्रों द्वारा उसका प्रभाव अमरीका के प्रत्येक कोने में फैल गया है। अन्य किसी एक व्यक्ति का (पोप को छोड़कर--और इसलिए उन दोनों की शत्रुता भी है) ससार के इतने अधिक व्यक्तियों के जीवनो पर ऐसा प्रभाव नहीं है।

स्टालिन का इतना अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव उसकी अपनी योग्यता, उसके देश की शक्ति तथा सफलताओं तथा पश्चिमी ससार के बौद्धिक दिवालियेपन और राजनीतिक अव्यवस्था के कारण है। पूंजीवाद को स्वयं अपने ही पर विश्वास नहीं है। अपनी कमियों के कारण वह अपने बुद्धिवादियों पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। लोकतंत्रवाद अनिश्चित तथा अरक्षित है। स्टालिन पश्चिम की भीतरी नैतिक कमजोरी को जान गया है और इसी आधार पर वह अपनी विदेश-नीति की रूपरेखा निर्धारित करता है।

: १६ :

रूज़वेल्ट, चर्चिल और स्टालिन के शान्ति-प्रयत्न

आखिर युद्ध-नेता ही सुलह करने वाले बने । अभी लड़ाई चल ही रही थी कि उन्होंने शांति के प्रयत्न आरम्भ कर दिये ।

जिन शांति सम्मेलनों को वास्तविक महत्व का कहा जा सकता है उनमें पहला तेहरान (दिसम्बर, १९४३) में, दूसरा क्रीमिया (फरवरी, १९४५) में और तीसरा पोर्ट्सडम (जुलाई-अगस्त १९४५) में हुआ था । युद्ध के दौरान में और उनके बाद रूज़वेल्ट, चर्चिल तथा स्टालिन की अन्य जितनी भी बैठकें हुईं, उनमें तेहरान और माल्टा वाली बातचीत में तैयार की-हुई योजना को ही आगे बढ़ाया गया था ।

साधारण तौर पर होता यह है कि पहले युद्ध में विजय प्राप्त कर ली जाती है और फिर कहीं शांति की रूप-रेखा तैयार की जाती है । शायद रूज़वेल्ट और चर्चिल भी यही करते । अमरीकी सरकार के प्रधान अधिकारी कार्टेरा हल ने १८ नवम्बर १९४३ के दिन कांग्रेस को बतलाया था कि अमरीकी सरकार युद्ध समाप्त होने से पूर्व सीमा सम्बन्धी कोई विवाद न उठाना चाहेगी । परन्तु इसमें रूस को कोई लाभ न था । शान्तिकालीन व्यवस्था का निर्माण वे देश नहीं किया करते, जिन्होंने विजय प्राप्त करने में सबसे अधिक हाथ डाला हो बल्कि वे देश करते हैं जिनमें युद्ध समाप्त होने के उपरान्त सबसे अधिक शक्ति बची रहती है । स्टालिन जानता था कि जन तथा धन के नाश के कारण रूस कमजोर हो जायगा । वह यह भी अनुभव करता था कि जब तक युद्ध के लिए रूस की सहायता का महत्व रहेगा तभी तक वह अन्य मित्रराष्ट्रों को अपनी बात मानने के लिए विवश कर सकता है, किन्तु युद्ध समाप्त होने पर उसे यह लाभ न रह जायगा ।

मान लीजिये कि किसी काम में तीन व्यक्ति हिस्सेदार हैं, और वे तीनों मिल कर ही उस काम को कर सकते हैं । यदि ऐसी व्यवस्था में उनमें से एक हिस्सेदार कोई मांग उपस्थित करे तो अन्य दो हिस्सेदारों को उसकी वही मांग

पूरी करनी पड़ेगी। तेहरान और माल्टा में स्टालिन की यही चाल थी।

परन्तु इंग्लैंड और अमरीका भी तो युद्ध में हिस्सेदार थे। वे रूस पर जोर क्यों न डाल सके ?

स्टालिन जानता था कि अमरीका और इंग्लैंड हिटलर या जापान से मुलह नहीं कर सकते। परन्तु रूजवेल्ट और चर्चिल को स्टालिन के प्रति उतना विश्वास न था। शान्ति सम्बन्धी व्यवस्था का निर्माण करते समय स्टालिन को यह सबसे बड़ा लाभ प्राप्त था।

अगस्त, १९३९ की सोवियत् नाजी-सन्धि ससार के कूटनीतिक क्षेत्र पर अपनी स्थायी छाप छोड़ गई थी। इस से प्रकट हो गया कि नाजियों का कट्टर विरोधी और मिलजुल कर आक्रमणकारी का सामना करने की नीति का पक्षपाती सोवियत् रूस भी ज़रूरत पड़ने पर नाज़ी जर्मनी के साथ मैत्री और तटस्थता की सधि कर सकता है। रूजवेल्ट और चर्चिल को यह आशका निरंतर बनी हुई थी कि कहीं फिर रूस शत्रुओं से सधि न कर ले।

कासब्लाका (जनवरी, १९४३) में रूजवेल्ट और चर्चिल ने अपनी प्रमिद्ध घोषणा की थी, जिसमें शत्रु से बिना किसी शर्त के आत्म-समर्पण करने को कहा गया था। उस घोषणा में ब्रिटेन और अमरीका ने मिलकर स्पष्ट कर दिया था कि शत्रु के पूर्ण पराजित होने तक वे मुलह न करेंगे। यह घोषणा नारमडी में मित्रराष्ट्रीय सेना उतरने से १८ महीने पूर्व की गई थी। उस समय तक अमरीकी सेना केवल उत्तरी अफ्रीका में ही अपने पैर जमा पाई थी। इस घोषणा का हिटलर की नीति पर तो क्या प्रभाव पड़ता, बल्कि इससे हिटलर और जर्मनों के लड़ते रहने के सकल्प में वृद्धि होने की ही सम्भावना थी। इसलिए कहा जा सकता है कि यह घोषणा कम-से-कम जर्मनी के लिए नहीं थी। साथ ही वह अमराकनों का जोश बढ़ाने के लिए भी नहीं थी, क्योंकि जब उन्होंने युद्ध में भाग लेने का निश्चय कर लिया था तो उसे समाप्त करते ही रूजवेल्ट और चर्चिल ने बिना किसी शर्त के आत्म-समर्पण करने के लिए शत्रु से जो कहा था उसका उद्देश्य यही था कि स्टालिन भी वैसी ही घोषणा करे। परन्तु स्टालिन के लिए ऐसा करना मूर्खता होती। रूजवेल्ट और चर्चिल ने कासब्लाका में जो कुछ किया उससे स्टालिन के इरादों के सम्बन्ध में उनके सदेह पर प्रकाश पड़ गया। यह स्टालिन भी ताड़ गया और उसने स्थिति से लाभ उठाने का निश्चय कर लिया। स्टालिन ने शत्रु को आत्म-समर्पण के लिए कहने के स्थान पर उससे बिल्कुल उलटा ही कार्य किया। उसने १ मई, १९४२ को जर्मन सेना तथा जर्मन राष्ट्र के नाम एक अपील निकाली। उस अपील में उसने कहा—“जर्मन सेना को

अपना तथा अन्य राष्ट्रों का खून बहाने के लिए इसलिए नहीं कहा जाता कि इससे जर्मनी का कोई लाभ होगा, बल्कि इसलिए कि जर्मन महाजनो तथा धना-धीशों की तिजोरिया भर सके .. जर्मन राष्ट्र को यह अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि उसने अपने-आपको जिस स्थिति में फसा लिया है उससे मुक्ति प्राप्त करने का उसके लिए एक ही उपाय है और वह यह कि हिटलर तथा गोइरिंग जैसे लुटेरों के चंगुल से जर्मनी को छुटकारा दिलावे. . . . हम दूसरे देशों की भूमि पर अधिकार नहीं करना चाहते और न अन्य राष्ट्रों पर विजय पाना ही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट तथा सम्मानपूर्ण है। हम अपनी सोवियत भूमि को जर्मन फाशिस्ट-पशुओं से आजाद करना चाहते हैं।”

७ नवम्बर, १९४२ को स्टालिन ने अधिक स्पष्ट शब्दों में कहा—
“हमारा उद्देश्य जर्मनी का नाश करना नहीं है, हमारा उद्देश्य जर्मनी की सेना को भी नष्ट करना नहीं है, क्योंकि रूस की तरह जर्मनी की सेना का विनाश केवल असम्भव ही नहीं वरन् भविष्य को देखते हुए अवाञ्छनीय भी है।”

दूसरे शब्दों में, स्टालिन ने कहा था, जर्मन सेनापतियों को हिटलर के हाथ से शक्ति छीन कर रूस से सधि कर लेनी चाहिए।

चर्चिल ने मास्को पहुँच कर स्टालिन से कहा था कि अभी अंग्रेजों के लिए पश्चिमी यूरोप में फौजे उतार कर दूसरा मोर्चा खोलना सम्भव नहीं है। फिर भी दूसरे मोर्चे के लिए चिल्ल-पो मचती रही। रूसी तथा रूसियों के विदेशी हिमायती निरन्तर यही माग करते रहे। रूस के लिए ऐसा करना स्वाभाविक था। उस समय उसके आगे जीवन-मरण का प्रश्न उपस्थित था। इसी अवस्था में नाजी सैनिकों के दूसरे युद्धक्षेत्र में भेजे जाने के रूप में सहायता प्राप्त करने की रूस की माग बिल्कुल वाजिब थी परन्तु स्टालिन को दूसरे मोर्चे वाली योजना की सूचना दे दी गई थी। ऐसी अवस्था में दूसरे मोर्चे के आन्दोलन से यही मतलब लगाया जा सकता था कि उस समय रूस अपने मित्रों से नाखुश था और उनसे अधिक सहायता चाहता था। इससे यह भी ध्वनि निजलनी थी कि मित्र-देशों से सहायता न मिलने पर वह जर्मनी से अलग सधि करके भी अपने कष्टों का अन्त कर सकता था।

१९४३ की ग्रीष्म ऋतु में स्टालिन के इरादों के सम्बन्ध में लंदन तथा वाशिंगटन के हलकों की धबराहट अपनी चरम-सीमा पर पहुँच गई। १२ जुलाई, १९४३ को सोवियत तत्त्वावधान में स्वाधीन जर्मनी की राष्ट्रीय समिति स्थापित की गई। उसमें रूस में रहने वाले कुछ जर्मन कम्युनिस्ट, तथा कुछ बाकी युद्धबंदी थे। इन युद्धबंदियों में कुछ जर्मन अफसर और कुछ जर्मन-नामन

भी थे, जिन्हें इस विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जेल से मुक्त किया गया था। समिति ने १० जुलाई को एक घोषणा-पत्र तैयार किया था, जिसकी लाखों प्रतियां लालमेना के वायुयानों ने जर्मन मोर्चा पर बरसाईं थीं और फिर उसे मास्को के “प्रवक्ता” पत्र में भी प्रकाशित किया गया।

घोषणा-पत्र में हिटलरी-सत्ता के स्थान पर एक “वास्तविक-जर्मन राष्ट्रीय सरकार” की स्थापना का अनुरोध किया गया था। उसमें आगे कहा गया था — “यह सरकार युद्ध-कार्य तुरंत बन्द कर देगी, जर्मन मेना को जर्मन सीमा पर वापस बूला लेगी और जीते हुए स्थानों से अधिकार छोड़कर सुनह की बात शुरू कर देगी। इस प्रकार यह शांति प्राप्त करेगी और एक बार फिर जर्मनी को अन्य राष्ट्रों के समकक्ष स्थान दिलायेगी।

“सुलह की बातें” “जर्मनी को अन्य राष्ट्रों के समकक्ष स्थान” यह बिना किसी शर्त के आत्म-समर्पण तो नहीं है।

इस सबको हम हिटलर तथा जर्मन-मेना के बीच फूट डालने के प्रयत्न कह सकते हैं। परन्तु इसका रुजवेल्ट और चर्चिल ने यह मतलब नहीं लगाया। ३१ अगस्त १९४३ को चर्चिल ने क्वीविक में एक भाषण दिया, जिसमें यद्यपि स्टालिन तथा रूस के प्रति सम्मान प्रकट किया गया था किन्तु साथ ही दूसरे मोर्चे की मांग के सम्बन्ध में कटु विचार प्रकट किये गए थे। चर्चिल ने कहा था—“एक समय था जब फ्रांस में हमारा बड़ा अच्छा मोर्चा बना हुआ था, किन्तु हिटलर की सेना की केन्द्रित शक्ति के कारण उसकी ध्वजिया उड़ गई। अपना मोर्चा नष्ट करा देना आसान है, किन्तु उसे फिर से बनाना कठिन है।” इस प्रकार चर्चिल ने परोक्ष रूप से सोवियत्-नाजी संधि के सम्बन्ध में स्टालिन की नीति की कड़ी आलोचना की थी और विचार प्रकट किया था कि यदि रूस अपनी पहली नीति पर कायम रहता तो फ्रांस की रक्षा हो सकती थी। रूस के साथ समझौता होने के कारण ही जर्मनी फ्रांस के विरुद्ध अपनी सारी शक्ति युद्ध में भौक सका था।

इन शब्दों में चर्चिल ने रूस के प्रति अपना असंतोष प्रकट किया। इस से भी अधिक अचम्भे में डालने वाला वक्तव्य उसी वर्ष हैरी हॉपकिन्स ने दिया। रुजवेल्ट के इस राजनीतिक सलाहकार ने “अमरीकन मैगजीन” में लिखा था—“यदि हम रूस से हाथ धो बैठे तो मेरा विश्वास है कि हम युद्ध हारेगें नहीं।” उस समय लालसेना स्टालिनग्राड ले चुकी थी और एक दूसरे मोर्चे पर भी जर्मनों को पीछे हटा रही थी। अब हिटलर के आघातों से रूस की कमर टूट जाने का कोई सवाल न था। उन दिनों पश्चिमी राष्ट्रों की रूस

से हाथ धो बैठने की सम्भावना स्टालिन द्वारा जर्मनी से पृथक् संधि करने की प्रवस्था ही में उठती थी।

१९ जनवरी, १९४४ को कार्डेल हल ने मुझे बताया था कि पिछले वर्ष वह विदेश मंत्रियों के प्रथम सम्मेलन में भाग लेने के लिए मास्को क्यों गया था। उसने कहा था—“वाशिंगटन, लंदन और चुगकिंग में रूस तथा जर्मनी के मध्य पृथक् संधि होने की जो अफवाहें उड़ रही थी, मैं उनकी असलियत का पता लगाना चाहता था। इस सम्बन्ध में हम बिल्कुल अधिकार में थे।”

अमरीकी तथा ब्रिटिश सरकारें इस बात के लिए चिन्तित थी कि कहीं स्टालिन हमारे गुट से अलग न हो जाय। दिसम्बर, १९४३ में अमरीका तथा ब्रिटेन की नीतियों के भीतर तेहरान में यही भावना काम कर रही थी। इससे स्टालिन को बड़ी अनुकूल परिस्थिति मिली। पोलिश भूमि और अन्य जिस भी रियायत की मांग स्टालिन की तरफ से की गई उसके पीछे यह धमकी भी थी कि यदि इन मांगों को अस्वीकार किया गया तो हिटलर के पतन के बाद रूस जर्मनी से संधि कर लेगा।

तेहरान सम्मेलन में स्टालिन की पूर्ण विजय हुई। यही कारण था कि विदेशी कम्युनिस्टों—विशेषकर वाउडर के नेतृत्व में अमरीकी कम्युनिस्ट दल ने तेहरान वाली शर्तों को अपना नारा बना लिया। परन्तु सोवियत् अधिकारियों ने अनुभव किया कि तेहरान सम्मेलन से रूस की भावी नीति स्पष्ट हो गई है, जो ठीक नहीं हुआ। स्टालिन दूसरे पर प्रकट नहीं होने देना चाहता था कि उसकी मशा क्या है। इसलिए १७ जनवरी, १९४४ को “प्रवदा” के काहिरा रियत सवाददाता ने (बाद में प्रकट हुआ कि काहिरा में इस पत्र का तब कोई भी सवाददाता न था) यह विवरण प्रकाशित कराया कि दो “प्रमुख अंग्रेज” नाजो विदेशमंत्री रिबनट्राप से पृथक् संधि की बातें चला रहे हैं। “प्रवदा” के इस “निज सवाददाता” ने लिखा था कि उसे यह खबर प्लाना तथा प्लाव स्त्री से मिली है और रिबनट्राप से बातें “आइवीरियन प्रायद्वीप” पर चल रही हैं।

प्रत्येक लक्षण से प्रकट होता था कि बात बिल्कुल मनघड़त है। सारा-रणतौर पर “प्रवदा” ऐसे मनघड़त समाचार नहीं छापता, किन्तु इस बार ऐसा विशेष उद्देश्य से किया गया था। अमरीकी तथा ब्रिटिश पत्रों ने इस सवाद को पहले पृष्ठ पर दिया था। महत्व इस अफवाह का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि “प्रवदा” ने उसे प्रकाशित किया था।

“प्रवदा” का यह सनसनीपूर्ण समाचार जिन दिन अमरीका में प्रकाशित हुआ उस दिन में वाशिंगटन में ही था। नूजे ब्रिटिश राजदूत जार्ज हेन्ना-पेन्स के साथ अकेले चाय पीने का भी अवसर मिला था। जार्ज हेन्नापेन्स ने

मुझे देखते ही कहा—“जरा बताइये तो, रूसी चाहते क्या हैं ? वे ब्रिटिश सरकार पर जर्मनी के साथ पृथक् संधि करने का आरोप क्यों कर रहे हैं ?” उन नोदिमैं सैक्रेटरी कार्डेल हल, अडर-सेक्रेटरी स्टेटिनस, असिस्टेंट सेक्रेटरी एडाल्फ ए० वर्ले आदि जिस भी अमरीका या ब्रिटिश राजनीतिज्ञ से मिला, प्रत्येक ने मुझ से यही प्रश्न किया । वे सभी दुविधा में पड़े थे ।

मेरे विचार में “प्रवदा” में प्रकाशित समाचार का उद्देश्य यही दुविधा उत्पन्न करना था । कूटनातिज्ञ कहते थे—“अग्रेजों द्वारा जर्मनी से पृथक् संधि की वार्ता का समाचार छाप कर कही सोवियत् रूस जर्मनी के साथ ऐसी ही वार्ता का सूत्रपात करने का बहाना तो नहीं खोज रहा ।” वस, तेहरान सम्मेलन के बाद रूस के प्रति विश्वास की जो भावना जमी थी, वह लोप हो गई । हमारे कूटनीतिज्ञ दात पीसने लगे । रूस को फिर मनाना पड़ेगा । उसका किसी प्रकार विरोध न होना चाहिए । ऐसे वातावरण में रूजवेल्ट और चर्चिल से प्राप्त रियायतों को हजम करके स्टालिन नई मांगें पेश कर सकता था । इसी कारण उधार-पट्टा-प्रणाली के अन्तर्गत अमरीका से जितनी सामग्री की आशा स्टालिन को थी, उससे कुछ अधिक प्राप्त हुई ।

१९४३ में जब रूस ने लड़ाइयाँ जीतनी आरम्भ कर दी तो पृथक् सोवियत्-जर्मन संधि की आशका और भी बढ़ गई । परिणाम यह हुआ कि स्टालिन ने तेहरान में इंग्लैंड और अमरीका से मनचाही शर्तें प्राप्त करली । बाद में लालसेना पूर्वी और मध्य यूरोप में आगे बढ़ने लगी और रूस वहाँ के छोटे देशों पर हावी हो गया । इससे “तीन बड़ों” के सम्बन्धों में एक नया अध्याय आरम्भ हुआ । रूस की एकांगी नीति तथा उसकी लोलुपता को कम करने के लिए अमरीका और ब्रिटेन को माल्टा में सोवियत् सरकार की इच्छाओं के आगे और भी झुक जाना पड़ा ।

युद्धकाल में लोकतन्त्री सरकारों को जनता का उत्साह बनाये रखने की आवश्यकता जान पड़ती थी । जनता चाहती थी कि सब कुछ ठीक चलता रहे और राजनीतिक नेताओं ने उसे यही विश्वास दिलाने का प्रयत्न भी किया । इसीलिए मित्रराष्ट्रों के प्रत्येक सम्मेलन को विजय तथा “युद्धोत्तर स्वर्ण” की ओर ले जाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम बताया जाता था । रूजवेल्ट और चर्चिल समझीते तथा प्रगति की जोरदार घोषणा किये बिना तेहरान या माल्टा से रवाना न होना चाहते थे । और स्टालिन प्रत्येक समझीते पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसकी कीमत वसूल कर लेता था ।

परन्तु दूसरा मार्ग ही और क्या था ? क्या रूजवेल्ट और चर्चिल के लिए उचित था कि रूस को नाराज करके उसे जर्मनी से पृथक् संधि कर लेने

देते ? इसका मतलब यह होता कि युद्ध अधिक काल तक चलता और ब्रिटिश, अमरीका तथा अन्य देशों के सैनिकों का मृत्यु-संख्या कहीं अधिक बढ़ जाती । हेंरी हार्पकिन्स के आशावाद के बावजूद, रूस का साथ छूटने पर पश्चिमी मित्रराष्ट्र शायद युद्ध में हार जाते । स्टालिन ने पोलैंड में जो कुछ मांगा था वह न दिये जाने पर वह शायद जर्मनी से समझौता करके प्राप्त कर लेता । १९३६ में उसने ऐसा किया ही था और वह सम्भवतः सोचता कि तब की अपेक्षा अब परिस्थिति कहीं उसके अनुकूल है ।

सचमुच जिम्मेदारी महान् थी । मैं जब कभी भी युद्ध के दिनों में होने वाले शान्ति के प्रयत्नों के सम्बन्ध में मित्र राष्ट्रीय अधिकारियों से बातें करता था तो वे सदा इसी प्रश्न को दुहरा देते थे—“और मान लीजिये कि रूस युद्ध से पृथक् हो जाय ?” एक बार मैं पोलैंड तथा वाटिक राज्यो के सम्बन्ध में रूस की चालों के विषय में सेक्रेटरी हल से बातें कर रहा था । वह बोला—“यदि आप रूस से ये रियायतें लेना चाहते हैं तो आपको अमरीकी सेना और जमी बड़े अपने साथ मास्को ले जाना पड़ेगा ।” उसके इस कथन का तात्पर्य दूसरे शब्दों में यह था कि स्टालिन केवल ऐसे साधनों तथा उपायों के प्रयोग से ही बात मान सकता था, जो अमरीका और ब्रिटेन काम में नहीं लाना चाहते थे ।

साधारण नागरिक अपनी सरकारों की आलोचना कर सकता है । परन्तु नागरिक जिस नीति का समर्थन करना चाहता है उसके अनुसार काम करने पर तो एक लाख युवकों की जाने जाने की सम्भावना होती ? रूजवेल्ट, हार्पकिन्स और चर्चिल ने रियायत पर रियायत देकर स्टालिन की जो इतनी खुशामद की तो इसका कारण यह था कि युद्ध के परिणाम के सम्बन्ध में सन्देह उठ खड़ा हुआ था । परन्तु वास्तव में ऐसा होना नहीं चाहिए था । जर्मनी से रूस की पृथक् संधि होने की कोई सम्भावना नहीं थी । सच तो यह है कि ऐसा होना बिल्कुल असम्भव था । यह होता भी कैसे ? यदि जर्मनी मुनह का प्रस्ताव करता तो उससे प्रकट हो जाता कि अब जर्मनी में खड़े होने की शक्ति नहीं रह गई है और फिर उस अवस्था में स्टालिन के लिए वह प्रस्ताव स्वीकार करना मूर्खता होती । इसी प्रकार रूस की तरफ से मुनह के प्रस्ताव को जर्मनी में कमजोरी का लक्षण माना जाना और उस हाथ में जर्मनी हम को कुचल डालने के लिए अपने प्रयत्नों में दुगुनी गति लाना आरम्भ करना ।

दूसरी ओर स्टालिन-हिटलर-मवि के मर्म में दुर्निष्ठता बाधा थी, और, जैसा कि १९४४ तथा १९४५ के जर्मनी के इतिहास की देखने में स्पष्ट

हो जाता है कि हिटलर को अप्रदस्थ नहीं किया जा सकता था। मास्का में स्वाधीन जर्मन समिति की स्थापना तथा जर्मन-सेना के लिए स्टालिन के सकेतो का कुछ भी महत्त्व न था, क्योंकि आत्म-हत्या के दिन तक हिटलर अपने पद पर बना था।

इसके अतिरिक्त, युद्ध-काल में जर्मनी और यूरोप की बहुत-सी भूमि हड़प जाने के लिए रूसी अधिकारियों की लिप्सा बलवती हो उठी थी। यदि रूस की जर्मनी से पृथक् संधि हो जाती तो उसकी ये आकांक्षाएँ कभी पूरी न हो सकती थी। यह सुलह एक समझौता होती, जिससे रूसियों के इरादों का सीमित होना भी स्वाभाविक ही था। पृथक्संधि करने की अवस्था में हम अपने विस्तार की जितनी आशा कर सकता था उससे कहीं अधिक विस्तृत साम्राज्य रूस का आजकल है। कम-से-कम इस इरादे के कारण रूस पृथक् संधि कभी न करता।

१९४३ से कुछ महीने पूर्व ही वह काल था जब हिटलर रूस को कुचल डालने की अपनी शक्ति के सम्बन्ध में सन्देह कर सकता था। इसके बाद ही स्टालिन विश्वास करने लगा था कि वह जर्मनों को रूस के बाहर निकाल सकता है। यही काल था जिसमें रूस और जर्मनी के मध्य पृथक् संधि की बात सोची जा सकती थी। परन्तु हिटलर का हठ पहली बाधा थी और हिटलर के सम्बन्ध में स्टालिन का अनुभव दूसरी।

भविष्य कुहरे से भरे आकाश की तरह है। वायुयान के चालक के समान राजनीतिज्ञ अपने अनुमानों के आधार पर उड़ता है। वह भविष्य की ओर अपने यंत्रों के द्वारा इंगित दिशा में बढ़ता है और ये यंत्र हैं राजनीतिज्ञ का अपना ज्ञान, निर्णय करने की उसकी योग्यता, उसकी सूझ-बूझ और शत्रु के सम्बन्ध में उसका अध्ययन। रूस-जर्मन-संधि होने की सम्भावना इतनी कम थी और ब्रिटेन तथा अमरीका के पास रूस को प्रभावित करने के साधन (उधार पट्टा सामग्री, बढ़ती हुई सैन्य-शक्ति इत्यादि) इतने जोरदार थे कि यह तो कहा ही जा सकता है कि रुजवेल्ट और चर्चिल ने तेहरान और माल्टा में जैसा पूर्ण आत्म-समर्पण स्टालिन के आगे किया था, कम-से-कम वैसा तो न करना चाहिए था। अगस्त १९४५ में पोद्सडम सम्मेलन के समय तो उनके आत्म-समर्पण करने का और भी कम कारण था, क्योंकि तब तक जर्मनी घुटने टेक चुका था और जापान पर भी परमाणु-बम डाले जाने वाले थे। सब तो यह है कि वार्ता के मध्य स्टालिन के मुकाबले में ब्रिटिश तथा अमरीकी प्रतिनिधियों ने अपेक्षाकृत कम कौशल का परिचय दिया।

राष्ट्रपति रुजवेल्ट, सेक्रेटरी हल और अडर-सेक्रेटरी सुमनरवेल्स ने बाल्टिक देशों पर रूस के अधिकृत होने का जोरदार विरोध किया। स्टालिन ने पोलैंड की समस्या का जो युद्धकालीन हल बताया, उस पर भी रुजवेल्ट और चर्चिल ने स्टालिन के आगे घुटने टेक दिये। ऐसा उन्होंने विवश होने पर ही किया था। उन्हें स्टालिन के पृथक् संधि करने का भय तब तक किये हुए था।

परिणाम यह हुआ कि युद्धकालीन सम्मेलनों के निर्णय इस आधार पर नहीं किये गए कि न्यायपूर्ण क्या है अथवा युद्ध के बाद ससार को सुखी बनाने के लिए क्या होना चाहिए, बल्कि ये निर्णय तो जल्दबाजी में और लेन-देन की भावना में किये गए। लेन-देन में पश्चिमी शक्तियों को जितना मिला उससे कहीं अधिक उन्होंने दिया और रूस ने केवल लिया ही, दिया कुछ भी नहीं।

स्टालिन की योजना सदा के समान पुरानी नीति का पृष्ठ-पेषण मात्र थी? पूर्वी पोलैंड पर अधिकार होने से रूस की सीमा चेकोस्लोवाकिया से मिल जायगी। बाल्टिक राज्यों और पूर्वी प्रशा पर कब्जा होने से रूस का सीमा जर्मनी से मिल जायगी। कार्पेथो-रूस (रुथेनिया) पर अधिकार होने से रूस की सीमा हंगरी से मिल जायगी। ईरानी अजरबैजान पर अधिकार होने या उसके चंगुल में फस जाने से रूस की सीमा तुर्की से मिल जायगी।

दूसरे महायुद्ध से पूर्व सोवियत-संघ की सीमा चेकोस्लोवाकिया, या जर्मनी या हंगरी, या नार्वे की सीमाओं से नहीं मिली हुई थी। अब उसकी सीमा इन देशों की सीमाओं से मिली हुई है और इसलिए उन पर रूस का प्रभाव भी बढ़ गया है।

रूस द्वारा आधे जर्मनी, आस्ट्रिया, और हंगरी पर कब्जा जमाने से यूरोप भर में उसकी शक्ति बढ़ जानी स्वाभाविक थी। रूमानिया और बल्गारिया पर रूस का अधिकार होने तथा यूगोस्लाविया में मार्शल टिटो के हाथ में शासन-सूत्र चले जाने से इटली, यूनान, तुर्की तथा भूमध्य सागर में भी रूस का प्रभाव बढ़ गया।

स्टालिन ने चीन तथा अन्य एशियाई देशों पर भी अपना प्रभाव बढ़ाया।

जिस तरह भारत में ब्रिटेन की स्थिति का सम्बन्ध हिंद एशिया, फिनलैंड, यूनान तथा इटली की घटनाओं से है उसी प्रकार फिनलैंड में इन के उद्देश्यों का स्पष्टीकरण रूस द्वारा ईरान में किये गए कामों द्वारा होता है। जर्मन शक्ति का विस्तार वस्तुतः बर्लिन तक है। रूमानिया पर अधिकार दरे दानिशन तक पहुँचने का एक साधन माना है।

स्टालिन का स्वप्न एक महान् रूसी साम्राज्य की स्थापना थी, जो जर्मन और जापानी शक्तियों के रिक्त-स्थान की पूर्ति कर सके। स्टालिन को अपने उद्देश्य की सिद्धि का भरोसा इसलिए प्रोर भी था कि उसके पयाल में युद्ध के बाद इंग्लैंड और फ्रान्स की शक्ति में कभी होगी।

स्टालिन के इस युग में आइवन भयानक, पीटर महान्, कैथराइन महान्, तथा अन्य ऐसे सभी जागे और रूसी सेनापतियों की प्रशंसा करके उन्हें आकाश पर चढ़ा दिया गया है, जिन्होंने अपने समय में रूसी साम्राज्य का विस्तार किया था। ये सभी अपने समय में प्रजा-पीडक शासक थे और रूसी प्रजा के प्रति उनके अत्याचारों की कोई सीमा न थी। अब स्टालिन भी हमें नासकों के पुराने आदर्शों पर चल रहा है।

इस प्रकार युद्ध-काल में और उसके बाद सोवियत् कम शान्ति-संस्थापन की दृष्टि से मुख्य समस्या बना रहा। अन्य दो समस्याएँ यह उठीं कि ब्रिटेन ने अपना साम्राज्य समाप्त करने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई और अमरीका भी साम्राज्य की इच्छा करने लगा।

युद्ध-काल में सोवियत् अधिकारियों ने अपने साम्राज्य-विस्तार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए ब्रिटिश तथा अमरीकी साम्राज्यवादों को स्वीकार कर लिया। रूस चाहता था कि लूट का माल ब्रिटेन, अमरीका और रूस मिलकर बांट ले और ये तीनों महाशक्तियाँ मिलकर दुनिया का बंटवारा कर लें। इन परिस्थितियों में विदेशी कम्युनिस्टों का साम्राज्यवाद के प्रति विरोध घट गया। तेहरान-सम्मेलन के उपरान्त वे कहने लगे कि साम्राज्यवाद जैसी कोई चीज अब रही ही नहीं, परन्तु युद्ध के बाद रूसी साम्राज्यवाद ने इंग्लैंड और अमरीका के प्रति अधिक विरोधी रुख धारण कर लिया।

अपना कोई भी निर्णय कार्यान्वित करने से पूर्व तेहरान और मास्को के सम्मेलनों में यह निश्चय स्वीकार कर लिया गया कि तीन महाशक्तियों के प्रतिनिधि के रूप में “तीन बड़े” पोलैंड जैसे कमजोर देशों के भाग्य का निर्णय उन की अनुपस्थिति में भी कर सकते हैं। बुरी राष्ट्रों के विरुद्ध बीस से अधिक देशों ने संग्राम में भाग लिया था। परन्तु शान्ति की व्यवस्था का निर्णय तीन ही ने किया। मित्रराष्ट्रों के हिसाब का यह एक नमूना है। छोटे देशों की सरकारों ने कितना ही प्रयत्न और विद्रोह किया, परन्तु वे शान्ति का निर्माण करने के अधिकार की “तीन बड़ों” के चंगुल से रक्षा न कर सकी।

विजय प्राप्त करने में इन तीनों महाशक्तियों का हाथ सबसे अधिक था। परन्तु इसका यह मतलब तो नहीं है कि बुद्धि या विचारशीलता भी केवल

उन्हीं के हिस्से में आई हैं। परन्तु निर्णय करने का एकाधिकार जमा लेने के कारण उनकी स्वार्थ-परता तथा बदर-बाद करने की मनोवृत्ति को फलने-फूलने का खूब अवसर मिल गया है। शक्तिशाली व्यक्ति अथवा देश को किसी समस्या का पहले निर्णय करने का अधिकार देने पर न्याय अथवा लोकतन्त्रवाद का गला घुट जाता है। प्रत्येक प्रजातन्त्र राज्य में इने-गिने व्यक्तियों की शक्ति का नियन्त्रण जन-साधारण की वोटों द्वारा और केन्द्रित आर्थिक शक्ति का नियन्त्रण निर्वाचकों की राजनीतिक शक्ति द्वारा किया जाता है। परन्तु "तीन बड़ों" ने असह्य "छोटों" को "परामर्श" अथवा "विवाद" कर सकने से अधिक और कुछ भी अधिकार नहीं दिया। और "तीन बड़ों" में भी एक अन्य दो के निश्चयों को अस्वीकार कर सकता था। इस प्रकार एक ही महाशक्ति ससार भर की जनता पर अपनी इच्छा लाद सकती थी। यह राष्ट्रीयता का अंतिम ध्येय और अन्तराष्ट्रीयता की न्यूनतम विशेषता है।

'तीन बड़ों' के प्रभुत्व से मुक्ति पाने का एक-मात्र उपाय ससार भर के लिए ऐसी शासन-व्यवस्था करना है, जिसे तीनों महाशक्तियाँ स्वीकार कर लें। इससे दुनिया को एक ही हुकूमत के अधीन करने की कठिनाइयों पर प्रकाश पड़ता है। परन्तु तेहरान, माल्टा अथवा पोट्सडम में यह समस्या उठाई ही नहीं गई।

दूसरा महायुद्ध भूमि के बटवारे के प्रश्न को लेकर नहीं हुआ था। यह तो हमारी सभ्यता की व्याधि के परिणाम स्वरूप हुआ था। १९४३ में 'माग्ना-ग्र' नामक एक पुस्तक में मैंने लिखा था—“यह युद्ध या तो एक नतीजा ससार को जन्म देगा और या एक नये विश्व-युद्ध को।” जिन लोगों ने शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न किया था उन्हें सबसे पहले यह जानना चाहिए था कि व्याधि क्या है, और फिर उसके उपचार का प्रयत्न करना चाहिए था, परन्तु उन्हें इसके लिए समय ही न था। आधुनिक राजनीतिज्ञ इतनी तेजी से काम करते हैं कि उन्हें यह विचार करने के लिए ठहरने का भी समय नहीं मिलता कि वे जा कहा रहे हैं। रुजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ससार के सबसे व्यस्त व्यक्ति थे और वे समस्त मानव-समाज के भाग्य का निबटारा करने के लिए पाँच दिन तक बात-चीत करने रहे। उनका पहला काम युद्ध में विजय प्राप्त करना था। इस विचार को ध्यान में रखकर उन्होंने तैनात बाले चली और यही ध्यान में रखकर उन्होंने तुर्क के प्रयत्न दिये। तेहरान, माल्टा तथा पोट्सडम में शक्ति की जिन व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय किया गया था उसका उद्देश्य तीसरे महायुद्ध में दबने के लिए शान्ति

स्थापित करना न होकर दूसरे महायुद्ध में विजय प्राप्त करना था। युद्ध में भाग लेने वाले मित्रराष्ट्र खुश रहें—इसका यह एक प्रयत्न-मात्र था। उदार-पट्टा प्रणाली के अनुसार रूस को सामान देने या फास पर हमले की योजना तैयार करने के ही समान यह भी एक सैनिक कार्यवाई थी।

१४ अगस्त १९४१ को रुजवेल्ट और चर्चिल ने अपना अटलांटिक घोषणा-पत्र निकाला था और १ जनवरी १९४२ को सोवियत् सरकार ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये थे। अधिकार पत्र में कुछ कमियाँ थीं, फिर भी उसे शान्ति-स्थापना करते समय आदर्श लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता था। यही अधिकार-पत्र तेहरान में एक रद्दी कागज-जैमा हो गया। माल्टा में उस कागज को जला दिया गया।

अटलांटिक अधिकार-पत्र की पहली शर्त यह है—“हमारे देशों का उद्देश्य भूमि प्राप्त करने या दूसरे किसी इरादे से हमला करने का नहीं है।” दूसरी शर्त में कहा गया है—“हम ऐसा कोई प्रादेशिक परिवर्तन नहीं होने देना चाहते जिसे करते समय उस प्रदेश की जनता का मत न जान लिया गया हो।”

रुजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने तेहरान और माल्टा में पोलैंड तथा जर्मनी के सम्बन्ध में जो निर्णय किये थे, उनमें इन दोनों शर्तों को बुरी तरह भग किया गया था। अपने शब्दों की अवज्ञा करके उन्होंने वास्तव में शान्ति की ही अवज्ञा की थी।

१९३९ में सोवियत् सरकार द्वारा पूर्वी पोलैंड पर अधिकार कर चुकने के बाद वहाँ “सर्वसाधारण” का मत लिया गया और ९० प्रतिशत मतदाताओं ने रूस के ही पक्ष में अपना निर्णय दिया था। परन्तु यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि मत लिये जाने से पूर्व १०,००,००० से अधिक व्यक्तियों का निर्वासन साइबेरिया और तुर्किस्तान को किया जा चुका था। सोवियत् कांग्रेस ने अपने उच्च आदर्शवाद के काल में १८ नवम्बर १९१८ को एक प्रस्ताव पास करके मत प्रकट किया था कि “यदि एक राष्ट्र पर दूसरे का अधिकार हो और यदि एक अधीन राष्ट्र को—ऐसी अवस्था में जब कि अधिकारी राष्ट्र की सेना हटा ली गई हो और कोई दबाव न डाला गया हो—अपनी शासन-प्रणाली का निर्णय करने का अधिकार नहीं दिया जाता तो यही कहा जायगा कि दूसरे राष्ट्र का सम्बन्ध उस पर कब्ज़ा जमाना और वहाँ विदेशी शासन स्थापित करना है और इसे एक अपराध माना जायगा।”

इस प्रकार स्वयं सोवियत कांग्रेस के ही शब्दों में स्टालिन का पूर्वी पोलैंड पर अधिकार जमाना अपराध था।

कार्ल मार्क्स यूरोप की राजनीतिक समस्याओं पर अधिकार-पूर्वक विचार प्रकट किया करता था, १६ अगस्त १८८४ को उसने कहा था—“लोकतन्त्रवादी जर्मनी की स्थापना की पहली शर्त लोकतन्त्रवादी पोलैंड को जन्म देना है... यह समस्या केवल कागज पर स्वतन्त्र पोलैंड कायम करने की नहीं है, बल्कि सुदृढ़ आधार पर एक राज्य स्थापित करने की है, जो अपना पृथक् और वास्तविक अस्तित्व बनाये रख सके। पोलैंड को कम-से-कम वह भूमि तो अवश्य मिलनी चाहिए जो उसके पास १७७२ में थी।” निश्चय ही तब पोलैंड के पास १९३९ की तुलना में कहीं अधिक भूमि थी। क्या क्रेमलिन में मार्क्स का अध्ययन कोई नहीं करता ?

रूस ने हिटलर के साथ सितम्बर १९३९ में की गई संधि के अनुसार पूर्वी पोलैंड पर अधिकार कर लिया था। ३० जुलाई १९४१ को रूस ने पोलैंड के साथ लंदन में एक संधि की, जिसके अनुसार निश्चय किया गया कि सितम्बर १९३९ वाली संधि द्वारा पोलैंड में जो प्रादेशिक परिवर्तन हुए थे, उन्हें रद्द समझा जाय। दूसरे शब्दों में हिटलर की महायत्ना में स्टालिन को पोलैंड में जो भूमि प्राप्त हुई थी उस पर रूस का अधिकार नहीं रह गया। लालसेना की उपस्थिति में पोलैंड में सर्व-साधारण का जो मत लिया गया था, उसे भी अमान्य ठहरा दिया गया। इस तरह वह भूमि फिर पोलैंड को मिल गई।

इतना सब हो चुकने और रूस के अटलांटिक अधिकार-पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने के बावजूद और लालसेना द्वारा पूर्वी पोलैंड को जर्मनी में जीतने से पहले ही, रूजवेल्ट और चर्चिल ने वह रूस को दे दिया। यह एक उमड़झोल थी। यह सब उन्होंने पोलैंड की जनता का मत जाने बिना ही किया। ऐसा करते समय उन्होंने सिर्फ स्टालिन से सलाह ली थी। स्वयं पोलैंड के मन्त्रिमंडल में फैमला महत्वपूर्ण अवश्य है, किन्तु इस कार्रवाई का और भी अधिक महत्व है। इससे यह कुटिलतापूर्ण तथा घृणित सिद्धान्त कायम होगया कि जब ‘तीन बड़ों’ में बातचीत हो तो सिद्धान्तों का कुछ भी महत्व नहीं रहता।

इसके उपरान्त, जैसा कि स्वाभाविक ही था, नोबिसन् सरकार और कम्युनिस्ट दल के प्रचारकों तथा अन्य देशों के कम्युनिस्टों ने एक स्वर में गोर मचाना आरम्भ कर दिया कि रूस द्वारा पश्चिम में वर्जित व्यक्ति नरुगेनेड की भूमि पर अधिकार करना उचित ही है। यह हमारे युग की एक नई नई दुष्ट बात है कि लोकतन्त्री देशों के कितने ही लोग इस गुन-गार में प्रभावित होकर

सोचने लगे कि रूस का दावा न्यायपूर्ण है।

प्रचारको ने कहा कि कर्जन-पक्ति तक पोलैंड पर रूस का अधिकार था। यह प्रसत्य है। जिस प्रदेश के सम्बन्ध में दावा किया गया था, उसका एक बहुत बड़ा तथा समृद्धिशाली भाग पूर्वी गेलीशिया कभी भी जारशाही रूस के कब्जे में न था।

इस प्रदेश का केवल एक भाग जारो के कब्जे में था। यह भाग जारो को कैसे मिला? बोलशेविक सत्ता का जन्मदाता लेनिन इस सम्बन्ध में लिख चुका है। मई १९०७ में प्रकाशित 'युद्ध और क्रान्ति' नामक पुस्तक में उसने पोलैंड तथा लटाविया के एक प्रांत कोरलैंड के बटवारे का जिक्र किया है। यह बटवारा जारशाही रूस, जर्मनी तथा आस्ट्रो हंगेरियन राज्य के बीच हुआ था। लेनिन लिखता है—'कोरलैंड तथा पोलैंड की बदर-बाट तीन ताजधारी लुटेरों के बीच हो चुकी है। वे लगभग १०० साल तक उनके टुकड़े किये रहे और उनसे अपने पेट भरते रहे। सबसे बड़ा टुकड़ा रूसी लुटेरे के हाथ लगा, क्योंकि तब वह सबसे बलवान था।'

बोलशेविक स्टालिन ने अपने दावे का आधार जार का इस लूट को बनाया है। जब स्टालिन जारो से प्रेरणा लेने लगा है तो उससे और आशा ही क्या की जा सकती है?

लेनिन द्वारा स्टालिन के कार्यों की निन्दा का एक और नमूना लीजिये। एक समय था जब अलेक्जेंडर पहला और नेपोलिपन पोलैंड का सौदा किया करते थे। एक समय जारो ने भी पोलैंड का सौदा किया था। क्या हम जारो की यही चाले काम में लाते रहेंगे। यह तो अंतर्राष्ट्रीयता को तिलाजलि देना होगा। यह तो 'बहुत बुरे प्रकार की देशभक्ति है।' यह स्टालिन की साम्राज्यवादी देशभक्ति है।

यह सिद्धान्त कि किसी देश को वह प्रदेश मिलना चाहिए, जो कभी उसके अधिकार में था—कार्यान्वित नहीं हो सकता। यदि इस सिद्धान्त को माना जाय तो दुनिया एक पागलखाना बन जायगी। इस सिद्धान्त के अनुसार इंग्लैंड वर्जीनिया, बोस्टन तथा फ्रांस के एक भाग को ले लेगा, रोम लंदन पर अधिकार जमाएगा, न्यूयार्क डचो के कब्जे में चला जायगा, फ्रांसीसी न्यूग्रालियन्स ले लेंगे, मिन्न, फिलस्तीन, सोवियत् यूक्रेन, बल्गारिया, और रूमानिया तुर्कों के हाथ में चले जायगे, स्वीडन को रूस का एक बड़ा हिस्सा मिल जायगा, कैलिफोर्निया स्पेन के पास चला जायगा, इटली हिंदचीन ले लेगा, ईरान भारत का एक हिस्सा ले लेगा, यूनान भी भारत के उसी हिस्से के लिए दावा उप-

स्थित करेगा और फिर यह व्यापार अनन्त काल तक अशान्ति का कारण बन जायगा ।

प्रचारको की दलील है कि १९२० में कमजोर होने के कारण रूस को यह प्रदेश पोलैंड को देने के लिए विवश होना पड़ा था; यह सच नहीं है । उस समय सोवियत् सत्ता का सूत्र लेनिन के हाथों में था । वह अपने कार्यों का निरपेक्ष भाव से विश्लेषण करने के लिए प्रसिद्ध रहा है । उसने २० नवम्बर १९२० को मास्को में कहा था—“लाल सेना ने जो विजय प्राप्त की है उसका महत्त्व वारसा की क्षणिक हार के बावजूद भी असाधारण है क्योंकि उसके कारण पोलैंड युद्ध जारी रखने में असमर्थ हो गया था । पोलैंड की साधारण अवस्था ऐसी अस्थिर हो चुकी थी कि उसके द्वारा युद्ध जारी रखने का कोई प्रश्न उठता ही न था ।” यह कथन ऐतिहासिक तथ्य पर प्रकाश डालता है । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि गक्तिशाली पोलैंड ने अशक्त रूस में वह प्रदेश छीन लिया । सच तो यह है कि १९२१ की सधि-वार्ता के बाद पोलैंड ने जितनी भूमि मांगी थी उससे कहीं अधिक लेनिन ने उसे स्वेच्छापूर्वक दे दी, क्योंकि लेनिन कर्जन पवित्र-प्रदेश के निवासियों को सोवियत् रूस में सम्मिलित नहीं करना चाहता था । उनमें से कितने ही रोमन कैथोलिक थे और लेनिन अपने वहाँ एक नई समस्या को नहीं उठाना चाहता था—वह रूस तथा पोलैंड के मध्य एक धार्मिक सीमा बनाना चाहता था । जो वह बना भी सका ।

यदि रूस द्वारा कमजोरी की हालत में पोलैंड को भूमि देने की बात सच भी हो, फिर भी उस प्रदेश का परित्याग ग्यामान्स्न या न ही गयी जायगी । यदि कमजोरी की हालत में त्यागे गए प्रदेशों को ऐसा करने वाले देश शक्तिशाली होकर फिर प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे तो ग्याम और स्थिरता कभी कायम न हो सकेगी । यदि जर्मनी, जापान और इटली भविष्य में अपने छिने हुए प्रदेशों को प्राप्त करने की चेष्टा करे तो क्या होगा ?

प्रचारको की दूसरी दलील है कि कर्जन प्रदेश के अधिकांश निवासी रूसी, श्वेत रूसी या यूक्रेनियन हैं । ग्रास्ट्रूपा तथा स्टेटनलैंड के भी अधिकांश निवासी जर्मन थे । फिर हमने हिटलर द्वारा उन्हें हडप जाने का समर्थन क्यों नहीं किया ? जबरन कब्जा करने की सफाई में कुछ भी नहीं कहा जा सकता । यदि वहाँ रूसियों का बहुमत था तो सोवियन् अधिकारियों ने लाल सेना तथा आगपू के हटने पर स्वतंत्र चुनाव का निर्णय मानने में इत्तफाक क्यों कर दिया ?

प्रचारको की तीसरी दलील है कि पूर्वी पोलैंड पिछली सोवियत सरकार की अपेक्षा रूसी सरकार के शान्त ने अच्छा रहेगा । परन्तु यह किसे मालूम है ?

और अच्छा होने का फैसला कौन करेगा ? क्या वारसा में नई और रूसी शासकों के अनुकूल सरकार नहीं है और क्या उन्हीं प्रचारकों के मतानुसार उसका शासन पिछली सरकार से उत्तम नहीं है ? फिर उसे पूर्वी पोलैंड पर राज क्यों नहीं करने दिया जाता ?

यह बहाना कि पोलैंड, बाल्टिक देशों या बाल्कन राष्ट्रों को रूस के प्रभुत्व से अथवा उसमें मिलने में लाभ पहुंचेगा—वास्तव में साम्राज्यवादियों की ग्रह-भावना है। यह तो ब्रिटेन तथा मुसोलिनी के तर्कों के समान है कि भारत में श्वेत जाति की विशेष जिम्मेदारी है, और इटली ने अवीसीनिया पर उसे गुलामी से छुड़ाने के लिए आक्रमण किया था। दक्षिण अमरीका के देशों पर मयुक्त राष्ट्र का अधिकार होने पर उनके रहन-सहन के मान, उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनकी यातायात व्यवस्था और राजनीतिक स्थिति में उन्नति होगी। तो क्या मयुक्त राष्ट्र को उनपर कब्जा कर लेना चाहिए ?

फ़िनलैंड, एस्थोनिया, लटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ईरान और तुर्की में १९३९ से ही रूस के कार्यों के सम्बन्ध में सोवियत् सरकार और उसके हिमायती जो बहाना बनाया करते थे उनका उत्तर रूस के भूतपूर्व विदेश-मन्त्री लिटविनोव एक सम्झौते द्वारा पहले ही दे चुके हैं। इस सम्झौते पर सोवियत् रूस ने अफगानिस्तान, फ़िनलैंड, एस्थोनिया, लटविया, लिथुआनिया, ईरान, पोलैंड, रूमानिया, युगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया और तुर्की के साथ १९३० में हस्ताक्षर किये थे। सम्झौते में आक्रमण क्या होता है, इसकी व्याख्या की गई थी। सम्झौते में कहा गया था—“राजनीतिक, सैनिक अथवा आर्थिक—किसी भी कारण को आक्रमण के लिए उचित ठहराने का हेतु नहीं कहा जा सकता।” इसका कारण यह है कि यदि एक महाशक्ति आक्रमण करती है या अपने साम्राज्य के विस्तार की चेष्टा करती है तो दूसरी महाशक्तियों का सदेह बढ़ता है और उनसे उसका झगड़ा बढ़ता है। परिणाम यह होता है कि उन अन्य महाशक्तियों को बदले की कार्रवाई करनी पड़ती है। इसी प्रकार युद्ध छिड़ जाते हैं, दूसरा महायुद्ध भी इसी तरह छिड़ा था।

परन्तु आश्चर्य की बात है कि हिटलर, मुसोलिनी और हिरोहितो के आक्रमण के परिणामस्वरूप होने वाले युद्ध के बीच में ही रुजवेल्ट और चर्चिल ने तेहरान और माल्टा में रूस के नए आक्रमणों को स्वीकृति दे दी।

२२ दिसम्बर, १९२० को लेनिन ने एक सम्मेलन में कहा—“आप जानते हैं कि पश्चिमी सीमा पर स्थित कितने ही ऐसे देशों से हमारी संधि हो गई है, जो पहले रूसी साम्राज्य के अंग थे। सोवियत् सरकार की आधारभूत

नीति के अनुसार इन देशों की स्वतन्त्रता तथा स्वाधीन-सत्ता को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया गया है।”

अब स्टालिन ने इन देशों की स्वाधीनता का अतः करके सोवियत्-नीति के “आधारभूत सिद्धांतों” का गला घोट दिया है। मैं सोवियत् रूस की विदेश-नीति के सम्बन्ध में १९३० में दो ग्रंथ लिख चुका हूँ। मैं कितने ही वर्ष तक सोवियत् रूस की विदेश-नीति के लिए उत्तरदायी राजनीतिज्ञों के निकट-सम्पर्क में रह चुका हूँ। मैं इस सम्बन्ध के सभी महत्वपूर्ण ग्रंथों तथा अन्य सामग्री का अध्ययन कर चुका हूँ। १९२० से १९३९ तक किमो सोवियत् राजनीतिज्ञ अथवा ग्रंथ द्वारा फ़िन्लैंड या पोलैंड को स्पर्श करने वाली रूस की सीमा की आलोचना नहीं की गई थी। और न वाल्टिक देशों की स्वाधीनता को ही अनुचित बताया गया था। सोवियत् सरकार इन सभी देशों की स्वाधीनता स्वीकार करती थी और उन सबसे उसके व्यावहारिक तथा राजनीतिक सम्बन्ध कायम थे। यदि इन देशों की सीमाओं से सोवियत् अधिकारी अन्तुष्ट थे तो वे बेसराविया प्रदेश की तरह उनकी स्थिति से भी असंतोष प्रकट कर सकते थे। बेसराविया प्रदेश रूमानिया ने १९१९ में हड़प लिया था, किन्तु सोवियत् अधिकारियों ने सिद्धान्त रूप से बेसराविया को सोवियत् रूस के ही अन्तर्गत माना था और तब भी वे उसे रूस के अंतर्गत दिखाया करते थे। परन्तु सोवियत् अधिकारियों ने पोलैंड के वर्जन पवित वाले प्रदेश, फ़िन्लैंड के किसी प्रदेश अथवा वाल्टिक राज्यों के सम्बन्ध में कभी ऐसा नहीं किया था। उन्होंने इसके लिए बना समय बर्बाद किया, जब उन पर अधिकार करने की शान्ति सोवियत् सरकार में था गई। साथ ही उनके हिमयनियों ने भी लोकतन्त्रवादी देशों की अशांति के प्रसंग में शांति के लिए शार मचाना आरम्भ कर दिया। अब उन्हें संकल्पना में मिला गई है। दुनिया में जो इतनी बुराई फैली हुई है उसका दोष निश्चय बुरा शांति करने वालों पर ही नहीं है, बल्कि दोष उन अच्छे आदमियों का भी है जो बुरे काम करने वालों की खुशामद करने और उन्हें खुश करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं।

सोवियत् रूस के राष्ट्राति माइकेल बोर्जनिन ने ताजिकिस्तान के आक्रमण की निन्दा करते हुए प्रशा के फ़ेडरिक टिनीन के निम्न शब्दों का उद्धरण दिया था, जो स्वयं सोवियत् आक्रमणों पर भी लागू होता है— “जब आपकी कोई किसी प्रदेश पर हमला है, और साथ ही उसके साथ संबंधित होता है तो उस पर उचित अधिकार अमा तीजिण।” यहाँ एक बार आपका ध्यान होना चाहिए कि आपका भ्रष्ट करने वाले अन्तु से निश्चय रूप से निश्चय है कि उस प्रदेश पर अधिकार करने के लिए उचित था।”

राजनीति के विकास विचार्यों सोवियत् रूस की विदेश नीति के सम्बन्ध में ईरान और पोलैंड में उसके रूप को देखकर अपने विचार स्थिर करते हैं। इसी प्रकार अमरीकी विदेशनीति को चीन में उसके रूप को देखकर समझा जाता है। किसी देश की विदेशनीति को समझने का अधिक उत्तम तराका उद्गम स्थान में ही उसके अध्ययन करने का है। ऐसा करने पर ही हम जान सकते हैं कि किसी देश की विदेशनीति उसके भीतर कितने ही व्यक्तियों के पारस्परिक सपनों, आर्थिक दवावों, राजनीतिक स्वार्थों इत्यादि का परिणाम है। यदि देश प्रजातन्त्र है तो उसकी विदेश-नीति पर उस नीति की रूपरेखा तैयार करनेवाले राजनीतिक दलों के सपनों का भी प्रभाव पड़ेगा। यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अमरीका की सरकार ने राजतन्त्री स्पेन के लिए शस्त्रों के निर्यात पर जो रोक लगाई थी उसका कारण स्पेन की कोई तात्कालीन समस्या न थी। बात यह थी कि रूजवेल्ट की राजतन्त्रवादियों ने सहानुभूति थी और वह जनरल फ्रांको की विजय नहीं चाहता था। हथियारों के निर्यात पर रोक कैथोलिकों तथा ब्रिटेन के दवाव और तटस्थता नीति के हिमायतियों के भय से लगाई गई थी। ऐसे ही अन्य कितने ही निर्णयों को उदाहरण के रूप में उपस्थित किया जा सकता है।

पोलैंड के सम्बन्ध में रूस के इरादों की छानबीन करते हुए हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहां सोवियत् विदेशनीति के सब रहस्यों को गुप्त रखा जाता है। पूर्वी पोलैंड में लाखों यूक्रेनियन हैं। इसलिए पूर्वी पोलैंड पर अधिकार करके सोवियत् अधिकारियों का उद्देश्य सोवियत् यूक्रेन के निवासियों को खुश करना था। दूसरी तरफ इसका उद्देश्य रूस के उन राष्ट्रवादियों को खुश करना भी था, जो अपने देश की सीमा का विस्तार रूसी साम्राज्य का जारशाही सीमा तक या उनसे भी आगे करना चाहते थे। युद्ध के दिनों में सोवियत् सरकार ने क्रान्ति की सामाजिक, राजनीतिक अथवा आर्थिक सफलताओं पर जोर नहीं दिया, बल्कि इस बात पर कि क्रान्ति के कारण ही देश की रक्षा हो गई। २१ जनवरी, १९४४ को एक सोवियत् नेता मि० ए० ए० शेरवाकोव ने कहा कि—“जारशाही रूस ऐसे मार्ग पर अगसर हो रहा था, जिसका अंत अनिवार्य रूप से स्वाधीनता के नाश से होता। बोलशेविक दल ने देश को इस लाछना से बचा लिया।” राष्ट्रवादियों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कम्युनिस्टों के पास इससे अच्छा तर्क और क्या हो सकता था। देश के बाहर के प्रदेश पर अधिकार करना राष्ट्रवादी को आश्वस्त करने के लिए सब से बड़ा तर्क है।

यूरोप में जर्मनी १। केन्द्रीय स्थिति का ज्ञान बोल्शेविकों को बहुत दिनों से था। जर्मनी का भाग्य-सूत्र अपने हाथ में लेने के लिए स्टालिन ने अपने कार्य-क्रम में निम्न बातों को सम्मिलित किया था। पोलैंड के आधे पूर्वी भाग पर रूस का अधिकार, पोलैंड की इस हानि की पूर्ति के लिए अपर साइ-लेशिया, पेसीएनिया, और पूर्वी प्रशा में कुछ बड़े-बड़े जर्मन प्रदेशों को पोलैंड के सिपुर्द करना, पूर्वी प्रशा के एक बड़े भाग पर, जिसमें कोनिग्सबर्ग का नगर भी सम्मिलित था, रूस का अधिकार, जर्मनी द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए दी जाने वाली रकम के बहुत बड़े भाग के लिए रूस की तरफ से माँग उपस्थित करना, युद्ध के उपरान्त आधे जर्मनी पर लालमेना का अधिकार रहे और शेष आधे जर्मनी पर अमरीका, इंग्लैंड और फ्रान्स अधिकार करें और बर्लिन पर रूसी मेनाए ही अधिकार करें, जिससे उनकी धाक जम जाय।

रुजवेल्ट और चर्चिल ने स्टालिन की ये सभी बातें तेहरान और मास्को में स्वीकार कर ली थी।

कर्जन पक्षित से पूर्व के प्रदेश ने हाथ धो बैठने के कारण पोलैंड कमजोर हो गया। उधर जर्मनी के कितने ही उद्योग-प्रधान प्रदेश मिलने में पोलैंड के आगे अनेक टेक्निकल, आर्थिक, राजनीतिक और नैतिक समस्याएँ उठ खड़ी हुईं। इनके निवटारे के लिए वह रूस पर निर्भर हो गया। इन बातों ने जर्मनी को पराजित करने के समय पोलैंड में उपस्थित रहने या भी लालमेना के कारण नई पाकिस्तान सरकार स्टालिन की कठपुतली हो गई। पोलैंड को भीमा रूप से दूर कर जर्मन सीमा से मिली हुई है। जर्मनी पर प्रतिगार रक्त के लिए रक्त का पोलैंड पर अधिकार रखना आवश्यक है। इसलिए स्टालिन ने पोलैंड के प्रति जो व्यवहार किया है वह जर्मनी के प्रति करने वाले जर्मनी की नीति का अंग है। इसी प्रकार स्टालिन की जर्मनी के प्रति करने वाले नीति की नीति का अंग है। जिन महाशक्ति का जर्मनी पर अन्तर्गत होने की सम्स्त यूरोप पर नियन्त्रण करेगी।

का भी यूरोप अथवा एशिया में एक भी प्रदेश नहीं मिला। यह कोई शिकायत नहीं है, बल्कि एक तथ्य का उल्लेख है। यह मान लिया गया था कि रूस तथा इंग्लैंड के यूरोप में अलग-अलग प्रभाव-क्षेत्र रहेगे। रूस तथा अमरीका के प्रभाव-क्षेत्र एशिया में होंगे। और इंग्लैंड ने एशिया में अपना साम्राज्य बनाये रखा।

“तीन बड़ों” द्वारा पदान की हुई गारंति यही थी। पहले उन्होंने दूसरे देशों के प्रदेशों पर अधिकार जमाने की स्वीकृति दे दी और फिर मित्रान्तों का प्रश्न उठाया। पहले उन्होंने प्रभाव क्षेत्र निर्धारित कर दिये और इसके उपरान्त उगमगती हुई नौव पर मयुक्त राष्ट्र सत्र का भवन खड़ा किया। यह भी एक ऐसा मध्य या हि उससे अधिक अपूर्ण सत्र की कल्पना नहीं की जा सकती।

राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने आशा की थी कि पहले महायुद्ध के बाद हुई संधि की बुराई को राष्ट्रसंघ दूर कर देगा। राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने यही विश्वास सयुक्त राष्ट्र के सम्बन्ध में किया।

१९४४ में डम्बर्टन ओक्स नामक स्थान पर अमरीकी, ब्रिटिश, रूसी और चीनी प्रतिनिधियों ने उस मसविदे का अधिकांश भाग तैयार किया था, जिसे बाद में सान-फ्रांसिस्को अधिकारपत्र का नाम दिया गया था। परन्तु उन के बीच एक बड़ा भारी मतभेद “नकारात्मक मत” के सम्बन्ध में रह गया था।

इसलिए इस प्रश्न को माल्टा में “तीन बड़ों” द्वारा निवटारे के लिए छोड़ दिया गया था। अधिकारपत्र की सबसे बड़ी विशेषता रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन का यह निर्णय ही है। सयुक्त राष्ट्र का मुख्य कार्य आक्रमण रोकना तथा शान्ति बनाये रखना है, किन्तु इस निर्णय ने इस कार्य के लिए सयुक्तराष्ट्र को विल्कुल प्रभावहीन कर दिया।

सयुक्तराष्ट्र की परिषद् में सभी सदस्य-राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है, किन्तु वह आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध कोई प्रभावपूर्ण कार्रवाई नहीं कर सकती। केवल ११ सदस्य-राष्ट्रों की सुरक्षा-समिति ही सयुक्तराष्ट्र की तरफ से शान्ति-भंग करने वाले राष्ट्र के विरुद्ध कोई निर्णय कर सकती है। और इस समिति में, जैसा कि माल्टा के निर्णय और सानफ्रांसिस्को अधिकार-पत्र द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है, “पांच बड़ों” यानी अमरीका, सोवियत रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन में से कोई एक आक्रमणकारी के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई को रोक सकता है, चाहे आक्रमणकारी वह स्वयं ही क्यों न हो। महाशक्तियों के “नकारात्मक मत” प्रदान करने के अधिकार का यही मतलब है।

ऐसी अवस्था में संयुक्तराष्ट्र आक्रमण अथवा युद्ध को कैसे रोक सकता है।

स्टालिन ने माल्टा में 'नकारात्मक मत' के लिए हठ किया था। सोवियत् राजनीतिज्ञ अभी तक इसकी सफाई में आलोचकों को उत्तर दिया करते हैं। स्वयं रुजवेल्ट ने अनुभव किया था कि 'नकारात्मक मत' प्रदान करने के अधिकार के बिना राष्ट्रवादी सदस्य मानफ्रांसिस्को अधिकार-पत्र को शायद अमरीकी सीनेट में न पास होने देते। चीन ने खुलकर 'नकारात्मक मत' का विरोध किया था, ब्रिटेन ने इसके सम्बन्ध में तटस्थता का रुख ग्रहण किया था।

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पीटर फ्रेजर ने 'नकारात्मक मत' को "अधिकार-पत्र पर "एक धक्का" कहा है। सचमुच ही यह बहुत बड़ा और काला धक्का है।

इस नकारात्मक मत के द्वारा एक ही देश संयुक्तराष्ट्र अधिकार-पत्र के संशोधन में स्थायी अड़गा लगा सकता है।

यही है युद्ध-काल में निर्मित शान्ति की व्यवस्था।

पहले महायुद्ध में एक तो रूस पराजित हुआ था और दूसरे विजयी मित्रराष्ट्र बोलशेविकों के विरुद्ध थे। इसलिए उन्हें (रूस का) शान्ति-सम्मेलन में स्थान नहीं दिया गया। १९१९ में शान्ति की जिस व्यवस्था का निर्माण किया गया था उसमें जर्मनी, बल्गारिया, तुर्की और मुग़ल आस्ट्रो-हंगेरियन साम्राज्य को अपराधी माना गया था। अब रूस ने केवल दूसरे महायुद्ध में ही विजय नहीं प्राप्त की है प्रत्युत उसने पहला महायुद्ध भी जीता है, इसलिए अब उसे भी कुछ प्राप्त हुआ है वह पहले आस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य, बल्गारिया और आर्मेनिया जर्मनी था। तुर्की अपवाद है।

अमरीका दोनों ही महायुद्धों में विजयी हुआ। पहले महायुद्ध में अमरीका इंग्लैंड और फ्रांस पर जर्मनी की विजय न होने देने के लिए सम्मिलित हुआ था। इस उद्देश्य की सिद्धि होने पर अमरीका अपने घर वापस चला गया। उसे लाभ उठाने अथवा अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की उच्छा न थी। यूरोप की चिन्ता से मुक्त होकर वह अपने आनन्द-प्रमोद में फिर से डूब जाना चाहता था। दूसरे महायुद्ध में अमरीका इंग्लैंड और फ्रांस पर जर्मनी की और सम्पूर्ण चीन पर जापान की विजय न होने देने के लिए सम्मिलित हुआ था। इस उद्देश्य की भी सिद्धि हो गई, पर अगली बार अमरीका घर वापस नहीं गया।

भाग—३

दोहरी अस्वीकृति

दाहरी अस्वीकृति

मैं जब भारत में अंग्रेजों से बात करते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद की निन्दा करता था तो वे कहते थे—“और अमरीका वाले हृदयियों के प्रति जो व्यवहार करते हैं उनके सम्बन्ध में आपका क्या कहना है ?”

मैं उत्तर देता था—“मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जिस प्रकार निन्दा करता हूँ उसी प्रकार अमरीकी श्वेतांगों द्वारा हृदयियों के विरुद्ध भद-भाव की नीति की भी निन्दा करता हूँ।”

मैं दोनों ही की निन्दा करने वाला हूँ।

मैं पोलैंड के जमींदारों और वक्ता की कठपुतली राजा—दोनों ही को ना-पसंद करता हूँ। जर्मनों द्वारा किये गए अत्याचारों और उन पर होने वाले अत्याचारों दोनों ही का मैं निन्दक हूँ। मैं तो अत्याचार-मात्र का निन्दक हूँ।

यदि आप एक बुरी बात को अस्वीकार कर देंगे और उसी के समान तथा वैसी ही एक अन्य बुराई का स्वीकार कर देंगे तो आप अपना एक सिद्धान्त की हत्या करके अच्छी बात के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। हो सकता है कि जिस आप कम बड़ी बुराई स्वीकार देंगे उस पर अधिक बड़ी बुराई निकले। इससे अच्छा तो यह है कि आप बड़ी बुराई को स्वीकार करें और मानव-समाज का उपकार करने का प्रयत्न करें।

कम बड़ी बुराई का सिद्धान्त हमारी सभ्यता के लिए एक बड़ा उपकार है। इसका अन्तर व्यावहारिक राजनीति पर भी पड़ता है।

चर्चिल इस नीति के अन्तर्गत ही काम करते हैं। वे अमरीका की संधि की हिमायत करते हैं। स्टालिन के साथ भी वे इस नीति का अनुसरण करते हैं। वे अमरीका और स्टालिन के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं। वे अमरीका और स्टालिन के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं। वे अमरीका और स्टालिन के बीच के अन्तर को दूर करने के लिए प्रयत्न करते हैं।

यदि आप इस नीति को अपना लेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं।

करता है। दूसरा आदमा रूस का हिमायती है। वह कहता है—“ठीक है, किन्तु आप भारत तथा हिंद एशिया में अंग्रेजों के सम्बन्ध में क्या कहते हैं ?”

मे रूस और ब्रिटेन दोनों ही के साम्राज्यवाद को प्रस्वीकार करता हूँ।

एक दूसरी बातचीत का नमूना तीजिए। एक साहब कहते हैं—“अगर हम क्यूराइल द्वीप या पोर्ट आर्थर मांगता हैं तो क्या बुरा करता है ? क्या अमरीकी ग्रीकीनावा तथा प्रशान्त के अन्य टापू नहीं माग रहे ?”

दोनों ही बुरे हैं। दोनों ही मूर्ख हैं। द्वीप, जड़े या प्रदेश प्राप्त कर लेने से ही रक्षा नहीं हो जाती।

साम्राज्यवाद अच्छा है या बुरा। यदि वह इंग्लैंड के लिए अच्छा है तो रूस, अमरीका, फ्रांस और हालैंड के लिए भी अच्छा होगा। यदि साम्राज्यवाद बुरा है तो वह आपके राष्ट्र के लिए भी बुरा होगा। जिस देश से आपको नफरत है उसकी बुराई को आप बड़ाकर बताते हैं और जिस देश के प्रति आपका प्रेम है उसकी बुराई को आप प्रशंसा करते हैं तो आप निश्चय ही एकांगी देशभक्त हैं।

“न्यूयार्क पोस्ट” में कंडेल फोस ने बर्लिन में एक वृद्धिया से अपनी मुलाकात का विवरण बताया है। वृद्धिया बोली—“रूसी आदमी नहीं राक्षस हैं। उन्हें मनुष्य के प्राणों और उसकी चीजों का कुछ भी ख्याल नहीं रहता। वे लोगों को सड़क से पकड़ लेते हैं और फिर उनके बारे में कभी कोई बात नहीं सुनाई देती। रूसी अधिकृत प्रदेश में मेरी बहन के मकान के सामने रूसी पुलिस ने जेल खोला है। मेरी बहन अच्छे कपड़े पहने हुए स्त्री-पुरुषों को दरवाजे के भीतर घसीटे जाते देखती है और रात को उनका आर्तनाद सुनाई पड़ता है। इस तरह की एशियाई अव्यवस्था की रोक-थाम होनी चाहिए।”

श्री फोस ने इस सम्बन्ध में लिखा है कि रूसी अधिकृत क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है उसके लिए पहले की परम्परा मौजूद है। परन्तु प्रश्न यह है कि यदि एक अत्याचार दूसरे अत्याचार की परम्परा के आधार पर किया जाय तो इस ससार का क्या होगा ?

सितम्बर १९४५ में “तान वड़ो” का जो सम्मेलन लंदन में हुआ था उसमें अमरीका के प्रधान अधिकारी वर्न्स ने रूमानिया तथा बल्गारिया में स्वतन्त्र चुनाव करने की माग की थी। तब कुछ आलोचकों ने कहा था—“मि० वर्न्स बाल्कन देशों में स्वतन्त्र चुनाव की माग क्यों करते हैं, जब उनके अपने प्रान्त दक्षिणी कैरोलिना में ही स्वतन्त्र चुनाव की सुविधा नहीं है।”

मुझे वर्न्स द्वारा रूमानिया और बल्गारिया में स्वतन्त्र चुनाव की माग

करने पर कुछ भी आपत्ति नहीं है। इससे दक्षिण केरोलिना में स्वतन्त्र चुनाव की मांग पेश करने का रास्ता साफ हो जाता है।

केथोलिक लोग स्टालिन की नित्य ही आलोचना करते हैं। परन्तु जब रूसी पाप की राजनीति की आलोचना करते हैं तो वे नाराज होते हैं। कम्युनिस्ट चीन में स्वतन्त्रता को कम करने के लिए चांग-काई-शेक की निन्दा करते हैं। परन्तु रूस में सोवियत सरकार ने स्वतन्त्रता का जो पूर्ण अपहरण कर लिया है, इससे उनके कान पर जूँ भी नहीं रेंगती।

सिद्धान्तों के परित्याग तथा कायरता के कारण हमारी सभ्यता सकट में पड़ गई है, जायद निर्दोष सरकार तो कोई हुई ही नहीं, मेरा देश गलती कर सकती है, चाहे वह मेरा देश ही क्यों न हो। यदि मेरी सरकार तानाशाही होती तो मैं उसे भी उलटने का प्रयत्न करता।

जिस प्रकार अन्य देश द्वारा किये किसी दुष्कर्म में मैं घृणा करता हूँ उसी प्रकार अपने देश के कुकृत्य से भी मैं घृणा करता हूँ। दोहरी अस्वीकृति के लिए मनुष्य को तटस्थ होंकर विचार करना चाहिए और तटस्थ होकर ही अपना मत स्थिर करना चाहिए।

कुछ लोगो में अपनी मातृभूमि के प्रति धार्मिक भावना होती है। कुछ लोगो का किसी विदेश के प्रति धार्मिक भाव रहता है। दुनिया की घटनाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण पर जब इस धार्मिक भावना का प्रभाव पड़ता है तभी वे सत्य की बातें चढ़ा देते हैं। वे अपने को भ्रम में डालते हैं। वे राष्ट्रों के दृष्टिकोण से विचार करते हैं और उसी दृष्टिकोण के आधार पर अपना मत स्थिर करते हैं।

आवश्यकता का हम अनुभव करने लगते हैं। १९३० में अत्यधिक आशावाद दूसरे महायुद्ध का एक कारण था। जनता के मन में भ्रम पैदा हो गया था कि परिस्थिति उतनी गम्भीर नहीं है, जितनी बताई जाती है। वह मोचती थी कि किसी-न-किसी तरह परिस्थिति में सुधार हो जायगा और हिटलर भी क्रमशः रास्ते पर आ जायगा। उस समय निराशा अथवा घबराहट होती तो कदाचित् दूसरा महायुद्ध न छिड़ता। इस प्रकार निराशावाद कभी-कभी उपयोगी होता है। अब भी दोहरी अस्वीकृति के दृष्टि-कोण से हमें इर्द-गिर्द फैले हुए मकड़ों का बोध हो सकता है।

अधिकांश व्यक्ति, कभी-कभी बिना जाने हुए ही, दोहरी अस्वीकृति से बचना चाहते हैं। दोहरी अस्वीकृति की प्रवृत्ति में उनके लिए सिद्धान्त पर जम जाना आवश्यक हो जाता है। परन्तु सिद्धान्त पर जमना कितने व्यक्तियों की अर्च्छा लगता है?

कुछ अमरीकी, जो रूस की तारीफ के पुल बाधा करते हैं, इसका कारण है। अमरीकी-प्रणाली की बुराइयों के कारण वे उसे अस्वीकार कर देते हैं। तब वे एक दूसरी—रूसी-प्रणाली को स्वीकार करते हैं। यदि उनसे कहा जाय कि रूसी प्रणाली में भी बुराईयाँ हैं तो उन्हें प्रसन्नता नहीं होती। ऐसा कहने से उनका नैतिक आधार जाता रहता है।

किसी ऐसी अर्च्छाई को स्वीकार कर लेना, जिससे आपका परिचय नहीं है, अथवा निकट की किसी भी परिस्थिति को स्वीकार कर लेना, क्योंकि दूसरी परिस्थिति का ज्ञान नहीं है, कमजोरी प्रकट करता है। बोलशेविज्म में जो भी बुराई है, उसे मैं नहीं मानता। इसी प्रकार पूँजीवाद की बुराई भी मुझे मान्य नहीं है। मैं तो कोई ऐसी वस्तु चाहता हूँ, जो इन दोनों से बढकर हो।

दोहरी अस्वीकृति नकारात्मक अस्वीकृति नहीं होती। यह एक क्रिया-त्मक सिद्धान्त है, जो मौजूदा हालत में परिवर्तन चाहता है। वह उज्ज्वल भविष्य की तरफ अग्रसर होने का हामी है।

अज्ञात समुद्रों में बढने वालों को ही नये महाद्वीपों या नई दुनिया का पता लगता है। नई दुनिया की जरूरत है। यह नई दुनिया कहा है? यह उज्ज्वल भविष्य किस दिशा में बढने से प्राप्त हो सकता है? नई दुनिया या उज्ज्वल भविष्य का दिखाई देना आसान नहीं है। यह हमें पुरातनवादियों से नहीं प्राप्त हो सकता। यह तो हमें सुधारवादियों या निश्चित कार्यक्रम रखने वाले ऐसे असंतुष्ट व्यक्तियों द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, जिनमें कल्पना है, जो सकुचित पथ पर बहादुरी से आगे बढना जानते हैं और जो दोनों मार्गों के विरोधियों की गोलियों को सहने के लिए तत्पर रहते हैं।

: २१ :

एक भारी संकट

हममे से प्रत्येक व्यक्ति विद्रोही होता है। यह विद्रोह एक रात, एक दिन, एक वर्ष या जीवन भर रह सकता है। यह भी सम्भव है कि विद्रोह का अंत किशोरावस्था के साथ ही हो जाय अथवा उसका प्रारम्भ उस समय हो जब वृद्धावस्था आने वाली हो। यह विद्रोह किसी काम की दकान से, शत्रुओं से घिरे रहने पर या जीवन में दिखाई देने वाले पाखंडों के प्रति हो सकता है। निर्धनता, अधिकार, धन, स्त्री-पुरुष के यौन सम्बन्धों पर लगे प्रतिबन्धों अथवा माता-पिता के शासन के विरुद्ध यह विद्रोह उठ सकता है। मुख्य बात यह है कि हम सभी में कम या अधिक विद्रोह की मात्रा रहती है।

एक कम्युनिस्ट आत्म-हत्या कर लेता है, या केथोलिक हो जाता है या नाज़ी बन जाता है। जो भी जीवन वे चिन्ता रहे होते हैं उनके प्रति यह विद्रोह है। वे विद्रोही हैं और मौजूदा जीवन उन्हें नहीं मुहताता इसलिए उसका परित्याग कर रहे हैं।

हिटलर से पूर्व जर्मनी में कितने ही यहूदी कम्युनिस्ट बने और फिर यहूदी धर्म में प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार उन्होंने परीक्षा रूप में जर्मनी के प्रति अपनी विद्रोह की भावना प्रकट की।

अमरीका, इंग्लैंड और फ्रांस में ऐसे कितने ही लोग हैं, जिन्होंने पहले कम्युनिस्ट दल से सम्बन्ध तोड़ दिया था और अब फिर उसी में सम्मिलित हो गये हैं। वे दूसरा मार्ग योजना चाहते थे, पर वह उन्हें मिला नहीं।

कम्युनिस्टों का डाकूतन और रूस की सत्ता में विश्वास है। उनकी भी नींव मार्क्स के सिद्धान्त है और पार्टी उनका संगठन है। कम्युनिज्म और केथोलोसिज्म के सिद्धान्तों में आकाश-पाताग का अन्तर है, किन्तु मानसिक दृष्टि से एक को छोड़कर दूसरे में जाना एक पग प्राण बढ़ाने से अधिक महत्त्व का नहीं है।

इस युग के सबसे बड़े राजनीतिक विद्रोही कम्युनिस्ट अथवा फाशिस्ट रहे हैं। कम्युनिस्ट पूँजीवादी सत्ता का परित्याग करते हैं। वे रूस का पक्ष ग्रहण करते हैं, जिसे वे परित्याग पूँजीवादी नमार का शत्रु समझते हैं। कम्युनिस्टों का विचार है कि पूँजीवाद में मुधार असम्भव है। वे क्रान्तिवादी हैं। वे पूर्ण परिवर्तन के हामी हैं। इस परिवर्तन के लिए वे रूस को एक साधन मानते हैं। वे सघर्ष इसलिए करते हैं कि उन्हें और रूस का परिवर्तन करने के लिए शक्ति प्राप्त हो सके। कम्युनिस्ट दल सुधार का साधन नहीं है, वह तो शक्ति प्राप्त करने का साधन है।

कम्युनिज्म और फाशिज्म की सबसे उल्लेखनीय विशेषता यह है कि सभी वर्गों, दलों तथा व्यक्तियों के हाथ से शक्ति छिनकर राज्य में केन्द्रित हो जाती है, राज्य इतना शक्तिशाली हो जाता है कि व्यक्ति में विद्रोह करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। इस प्रकार विद्रोह का अन्त विद्रोह को असम्भव कर देने के रूप में होता है।

सोवियत रूस में स्त्री और पुरुष कम्युनिस्ट दल में अपने विश्वास और परम्परा के कारण ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक तथा आर्थिक कारणों से भी सम्मिलित होते हैं। इसके विपरीत, रूस के बाहर लोग कम्युनिस्ट दल में अपने विद्रोही विचारों के कारण सम्मिलित होते हैं। वे सत्ता की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं। कम्युनिस्ट दल क्रियाशील है। वह अपने सदस्यों

ने अनुशासन, सचाई और सेवा-भावना की आज्ञा रखती है। दल की कारण से कम्युनिस्टों को काम तथा साहचर्य प्राप्त होता है। कुछ अमीर आदमियों, जैसे विरासत में भारी सम्पत्ति प्राप्त करने वाले और हॉलीवुड के लेखकों के अंत-करण को कम्युनिस्ट दल में सम्मिलित होने में जाति मिलती है। अन्य लोग कम्युनिस्ट इसलिए होते हैं कि वे एकाकी, निराश, कार्य करने को उत्सुक अथवा समाज में असंतुष्ट हैं। कम्युनिस्ट बनने में दोस्त मिलते हैं, पार्टियों में जाने का अवसर मिलता है, और संचित ज्ञान को व्यय करने का रास्ता निकलता है।

औसत कम्युनिस्ट एक अग्रगत फाशिस्ट की अपेक्षा अधिक सरल और सच्चा होता है। फाशिज्म ऐसे लोगों को आकर्षित करता रहा है और अब भी करता है, जिनकी अपराधी मनोवृत्ति है, जो समाज में निहाले हुए हैं और जिन्हें हिंसा से प्रेम है। फाशिस्टों में ऐसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति भी पाए जा सकते हैं, जो अपने उद्देश्य की निष्ठा के लिए बदमाशों का समर्थन प्राप्त करते हैं। इसके सिवा फाशिस्टों में ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है, जिनमें घृणा भरी हुई है और जिन्हें मरने-मारने में ही आनंद आता है।

सुना था ।" पुस्तक के ब्रिटिश संस्करण में "या ट्राट्स्की" शब्दों को निकाल दिया गया था । एक अन्य स्थान पर मैंने लिखा था कि "मैं रूस विरोधी नहीं हूँ, मैं स्टालिन-विरोधी हूँ ।" इन शब्दों को भी निकाल दिया गया था । एक अन्य स्थान पर मैंने लिखा था—“जब से मैं भारत आया हूँ और यहाँ जिन लोगों में मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है उनमें से प्रत्येक पाचवें आदमी ने मुझे कहा है कि वह जेल जा चुका है । मैं रूस और जर्मनी में भी रह चुका हूँ । उन देशों में ऐसा कोई व्यक्ति शायद ही मिले, जो जेल जा चुका हो । वहाँ जेल जाने वाले जेल में ही रह जाते हैं ।” यहाँ भी रूस का उल्लेख निकाल दिया गया था । इसी प्रकार एक अन्य स्थान से भी रूस-विरोधी तथा स्टालिन-विरोधी अंग को निकाल दिया गया था ।

निश्चय ही यह काट-छाट किमी कम्युनिस्ट ने या कम्युनिस्टों से महानु-भूति रखने वाले व्यक्ति ने की थी । उसकी दृष्टि में अमरीका या ब्रिटेन की नीति की आलोचना करने में कोई हर्ज नहीं है, परन्तु स्टालिन और उनकी नीति पर किसी तरह आँच न आनी चाहिए ।

हमारी सभ्यता की एक बहुत बड़ी विशेषता का यह एक साधारण-सा उदाहरण है । यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है । यह तानाशाही पाखंड का ही एक अंग है । मास्को के मुकदमों में यही प्रवृत्ति दिखाई दी थी । अब भी यह हमें सोवियत प्रकाशनों, कम्युनिस्टों की विदेशी पत्रिकाओं तथा उनके तर्कों में मिलती है । यदि एक कम्युनिस्ट किसी लेखक के अप्रिय शब्दों को दवा देने के लिए तत्पर रहता है तो वह स्वयं लिखते या बोलते समय उतनी ही ईमान-दारी या सचाई का परिचय क्यों नहीं देता ? तानाशाही के अन्य हिमायतियों की तरह कम्युनिस्ट भी सत्य की रक्षा का विशेष ध्यान नहीं रखते ।

एलीनर रूजवेल्ट ने २२ जून, १९४५ को लिखा था—“कम्युनिस्टों के अपने दल के सदस्य होने अथवा उनके उद्देश्यों पर मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है । कितने ही वर्षों से वे मिथ्यावाद के सिद्धान्त का प्रचार करते रहे हैं । उन्होंने यह भी प्रचार किया है कि दल के प्रति अपने कर्तव्य का पालन और दल के नेताओं के आदेशों को मानना सर्वोपरि बात है और वह भी ऐसी दशा में जब कि दल के नेताओं तथा अमरीका के स्वार्थ सदा एक जैसे नहीं होते । मैं अमरीकी कम्युनिस्टों के धोखे को देख चुकी हूँ । इसलिए मैं कभी उन पर निश्वास नहीं कर सकता ।”

यदि आपको उन पर विश्वास नहीं है तो आप उनके साथ काम भी नहीं कर सकते ।

मिथ्या बातों का प्रचार कम्युनिस्टों के सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं है। सत्य की रक्षा की कम्युनिस्ट खिल्ली उड़ाते हैं। लिखने और बोलने को वे अपने उद्देश्य की सिद्धि का साधन मात्र मानते हैं और यही करते भी हैं। छोटे-से-छोटे और बड़े-से-बड़े असत्य का प्रयोग करने से वे नहीं चूकते। चरित्र की हत्या करने और दुमरे को बदनाम करने को भी वे उद्देश्य-सिद्धि का उत्तम साधन मानते हैं।

यह दूसरे को बदनाम करने का युग है। तर्क के अभाव में तानाशाहिया कीचड़ उछालती हैं। “प्रतिक्रियावादी”, “ट्राट्स्की का अनुयायी”, “फाशिस्ट” आदि कहकर किसी को बदनाम करना सर्वसाधारण के मस्तिष्क पर अधिकार करने का सबसे सहज तरीका है।

शब्दों का गलत प्रयोग करके किसी को बदनाम करना आजकल की सबसे बड़ी बुराई है। गोइवत्स पश्चिमी राष्ट्रों को “अमीर पूजीवादियों की यहूदी लोकतन्त्रवादी सत्ताएँ” कहा करता था। कम्युनिस्ट पहले नाजियों को “समाजवादी फाशिस्ट” कहा करते थे और फिर उन्हीं में उन्होंने समझौता कर लिया था। आजकल कम्युनिस्ट लोग प्रत्येक कम्युनिस्ट बात को “लोक-तन्त्रीय” और “फाशिस्ट-विरोधी” कहते हैं और प्रत्येक लोकतन्त्रीय तथा उदार वस्तु को कम्युनिस्ट-विरोधी तथा प्रतिक्रियावादी बनाने में। इसी प्रकार रिडेल के कट्टरपथी प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिन्हें वे नहीं समझ सकते, कम्युनिस्ट कहते हैं।

ये पत्रिकाएँ और संगठन कभी रूस के सम्बन्ध में सत्य बात नहीं कहेंगे। वे इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका तथा अन्य देशों की बड़ी उत्साह से निन्दा करते हैं पर वे रूस की आलोचना कभी नहीं करते। यद्यपि यह सरासर झूठ का प्रचार है, फिर भी कम्युनिस्ट-दलों की तरफ लोग आकर्षित होते हैं।

ऐसा करने वालों के इरादे अलग-अलग होते हैं। कुछ अधिक बड़ी फौजों का समर्थन चाहते हैं। कुछ इस धमकी से प्रभावित होते हैं कि यदि अमुक बात का समर्थन नहीं किया गया तो उनका जीवन नीरस और गुप्त कर दिया जायगा। अन्य लोग इसलिए सम्मिलित होते हैं कि प्रकाश में आने वाले दूसरे कितने ही लोग कम्युनिस्टों की हा-मे-हा मिलाते हैं और वे स्वयं भी उन्हीं के समान प्रकाश में आने को उत्सुक हैं। कुछ लोग केवल हलचलों, डिनरों, सम्मेलनों तथा विभिन्न कारंवाइयों में शरीक होना चाहते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि दुनिया में चारों तरफ घुराई-ही-घुराई है, पर ऐसे विरले ही हैं जो उस घुराई से लाहा लेते हैं। स्वाधीनता और सुख का प्रसार करने वाली एक प्रणाली के लोप होने का सकट केवल इसीलिए बढ़ गया है कि कुछ लोग और अधिक स्वाधीनता तथा सुख चाहते हैं। परन्तु इस सकट से प्रणाली के समर्थकों को स्वाधीनता और सुख के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए प्रेरणा नहीं प्राप्त होती। इससे केवल प्रणाली के शत्रुओं को ही बल प्राप्त होता है, जो अधिक स्वाधीनता तथा अधिक सुख की मृग-मरीचिका दिखाकर स्वाधीनता का पूरी तरह गला घोटकर ही दम लेंगे।

ब्रिटेन में मजदूर-दल के शक्तिशाली होने के कारण वहाँ कम्युनिस्ट-दल की शक्ति अधिक नहीं है। युद्ध से पूर्व आस्ट्रिया में कम्युनिस्टों का बल बहुत कम था, क्योंकि समाजवादी-प्रजातन्त्र दल वालों के सिद्धांतों का आकर्षण अधिक था और उनकी राजनीतिक शक्ति भी अधिक थी। १९३६ से पूर्व स्पेन में कम्युनिस्टों को अधिक अनुयायी नहीं मिले, क्योंकि समाजवादियों तथा सिडो-कलिस्टों—मजदूर-सघों के हाथों में विभाजन एवं उत्पादन सौंपने के समर्थकों का दल—ने विद्रोह का झंडा फहरा रखा था। भारत में कम्युनिस्टों को अधिक समर्थक नहीं प्राप्त होते, क्योंकि वहाँ गांधी और नेहरू के नेतृत्व में साम्राज्यवाद के विरुद्ध मोर्चा लेने वाली प्रमुख सस्था कांग्रेस है।

ब्रिटेन के मजदूर-दल, आस्ट्रिया के समाजवादी दल और स्पेन के समाजवादी दल ने जहाँ एक ओर पीछे धकेलने वाले कट्टर पथियों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया वहाँ दूसरी ओर तानाशाही कम्युनिस्ट के भी पैर नहीं जमने दिये। इस प्रकार दोहरी अस्वीकृति जहाँ प्रभावपूर्ण होती है वहाँ असत्य

के आघार पर कार्य करने वाले पाखंडी विद्रोहियों की दाल नहीं गलने पाती ।

लोकतत्रवादी सत्ता में जितनी ही कम कमजोरियां होगी उतनी ही कम सम्भावना उस पर आक्रमणों की होगी । लोकतत्रवादी सत्ता में जितनी अधिक उन्नति होगी उतनी ही वह आलोचकों द्वारा की गई निन्दा को कम पमद करेगी, यदि लोकतत्रवादी सत्ता निष्क्रिय होने लगेगी तो अन्य ऐसे लोगों को दोष नहीं दिया जा सकता, जो उसके स्थान पर अधिकार करना चाहते हैं ।

यदि लोकतत्रवाद को नष्ट नहीं होना है तो उसे स्वयं अपने रक्षक खोज निकालने पड़ेंगे ।

लोकतत्रवाद के शत्रु उसे नष्ट करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने उसे चुनौती दी है । कम्युनिस्टों या फासिस्टों का लोकतत्रवाद में विश्वास नहीं है, फिर भी वे अपने को लोकतत्रवादी कहते हैं । फासिस्ट लोकतत्रवादियों में सम्मिलित होने के वाद भीतर से उसकी जड़ें नष्ट करना चाहते हैं । इसमें लोकतत्रवादी शक्तिशाली होती है और फासिज्म का वन बढ़ता है । यूरोप के कई देशों में कम्युनिस्टों के कारण फासिज्म की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ । जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी ने हिटलर को बड़ी सहायता मिली थी । अमेरिका के ट्रेड यूनियन आन्दोलन की एकता और जड़ों के हटाने का कारण कम्युनिस्ट ही हैं ।

यदि लोकतत्रवाद में अपने पुनर्निर्माण के लिए नाश, धोखे और कत्तिया की कमी है तो यह उसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल है । यदि नाश, धोखे और कत्तिया में नाश, दमन अथवा जातीय भेद-भाव बना हुआ है तो लोकतत्रवाद के लिए एक भारी सकट है ।

: २२ :

दूसरे महायुद्ध के बाद

छोटे राष्ट्रों पर महाशक्तियाँ छा गई हैं। पृथ्वी के बटवारे के प्रश्न पर महाशक्तियों में समझौता नहीं हो पा रहा है। अन्तर्राष्ट्रीयता के आवरण के पीछे आक्रामक राष्ट्रीय प्रवृत्तियाँ छिपी हुई हैं। साम्राज्यवादी लूट-मार के लिए "रक्षा" का बहाना बनाया जाता है। आर्थिक युद्ध छिड़ जाते हैं। उपनिवेशों की विद्रोही जनता का क्रूरता से दमन किया जाता है। जिन करोड़ों प्राणियों ने कष्ट में युद्ध के दिन गुजारे थे अब वही प्रतिहिमापूर्ण शान्ति की यातनाएँ भुगत रहे हैं। न्याय तथा जनता के हितों का गला घोट कर शक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। कहीं-कहीं इन्हें रोकने की शक्ति सरकारों में नहीं है और कहीं सरकारों के ही आगे जनता का बस नहीं चलता। नेता सत्य पर पर्दा डालने के लिए प्रयत्नशील हैं, क्योंकि सत्य प्रकट होने पर उनकी नेतागिरी सकट में पड़ जायगी। सरकारी अफसरों ने झूठी आशा फैला रखी है। अधिकारीवर्ग अनिश्चित नीति का सहारा पकड़े हुए है और सोचते हैं कि कदाचित् उसी पर चलने से सफलता मिल जाय। समस्याओं का समझदारी से निवटारा हो सकने में जनता का कुछ भी विश्वास नहीं रह गया है। यह सब प्रवृत्तियाँ हमारे लिए नई नहीं हैं। इन्हें हम पहले भी देख चुके हैं। ससार में युद्ध अभी जारी है।

सबसे अधिक चिन्ता में डालने वाली बात तो वर्तमान अवस्था की पिछली कुछ उन परिस्थितियों से समानता है, जिन के कारण युद्ध छिड़ चुके हैं।

कोई भी ईमानदार व्यक्ति नहीं कह सकता कि जिन परिस्थितियों के कारण दूसरा महायुद्ध हुआ वे युद्ध में बरते गए अथवा शान्ति के लिए काम में लाये गए तरीकों के कारण मिट सकी है। युद्ध जिस उद्देश्य से लड़ा जाता है उसके सिद्ध हुए बिना वह समाप्त नहीं होता। इसीलिए कहा जा सकता है कि अभी दूसरा महायुद्ध समाप्त नहीं हुआ है। वर्तमान शान्ति की शान्ति नहीं कहा जा सकता। सच तो यह है कि दुनिया में अभी तक संघर्ष चल रहा है।

हिटलर, मुसोलिनी और जापानी युद्ध-नेता अब नहीं रहे । जर्मनी, इंग्लैंड और जापान की युद्ध-कालीन सरकारों का भी नाम-निशान बाकी नहीं है बड़ी सफलताएँ हैं और इन्हें प्राप्त करने के लिए असंख्य प्राणी अपनी जानें भुनका चुके हैं और कितने ही व्यक्ति अपने अंग अपना स्वास्थ्य और अपना मान-सम्मान गंति गवा चुके हैं । परन्तु यदि हम अधिक सुन्दर मसार का निर्माण कर सकते तो ये सफलताएँ और भी अधिक उपयोगी सिद्ध होतीं । परन्तु अब तो न के कारण कितनी ही को अपनी राष्ट्रीय स्वार्थपरता की प्यास बुझाने, प्रदेशों को छीना-भूषटी करने, अन्यायपूर्ण एकांगी कार्य करने और पिछली सवियों के भग करने का अवसर मिल गया है ।

इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में हमें एकता की तरफ अग्रसर होने वाले किसी मिद्धान्त किसी नैतिक आदर्श, कार्य करने के किसी नयुक्त कार्यक्रम, किसी समान लक्ष्य और किसी स्पष्ट उद्देश्य का भी अभाव दिखाई देता है ।

हिटलर, मुसोलिनी और जापानी युद्ध-नेता अब नहीं हैं । परन्तु क्या आशिर्वाद का अन्त हो गया ? क्या नानाजाही मर चुकी ?

युद्ध पाँच वर्षों में कुछ अधिक चला । इनमें कितने ही देश समाप्त हो गए । किन्तु जिन लोगों को युद्ध के सम्मान और मजदूरी के बीच रहना पड़ रहा उन्हें भी युद्ध एक साधारण घटना के ही समान जान पड़ रहा है, लोगों के सके बाद जो कुछ देखने में आ रहा है वह बहुत कुछ उन लोगों की तुलना वाली बातों के ही समान है ।

प्राप्त करने वाला चाहे बढमाश ही हो—राजा वही होता है। विजेता के पीछे जाना ही पड़ेगा—चाहे वह कैदखाने को ही ले जाय। झूठ और वेईमानी से काम भले ही लेना पड़े—शक्ति जरूर प्राप्त करनी चाहिए। कम्युनिस्ट तथा फाशिस्टों का यही विचार है। “शक्ति मिलने पर हम वैसे ही भीषण अत्याचार दूसरों पर करेंगे, जो वे हमारे साथ कर चुके हैं।” यह नया मित्रान्त है। तानाशाहियों ने प्रतिरोध के कानून को स्वीकार कर लिया है।

शक्ति के पुजारियों के लिए नैतिकता एक बेहूदा शब्द है। वे कहते हैं—“आदर्शवाद—परमाणु-युग में ? क्या पागल हो गए हो ?”

उनके विचार हैं, ‘गांधी स्वप्नदृष्टा है, गेहलू इस दुनिया का नहीं है। उनमें धोखा देने की शक्ति नहीं है। वे जो सोचते हैं वही कह देते हैं—यहाँ तक कि अपने सम्बन्ध में भी। उनका वाकित में विश्वास है।’

तानाशाही शक्ति के पूजक हैं—उमी रक्ति के, जो मनुष्य को गुलामी की बेड़ी में जकड़ लेती है और अन्त में उसे नष्ट कर देती है। फाशिस्ट विदेश-मंत्री सिग्रानो की जो डायरी प्रकाशित हुई है उसे पढ़ने से प्रकट होता है कि मुसोलिनी की दृष्टि में मनुष्य के प्राणों का क्या मूल्य था। इटली के पास खाना, कच्चे माल और धन की बेहद कमी थी, किन्तु मुसोलिनी यही चाहता था कि हिटलर उम के अपर्याप्त शस्त्रास्त्र से सुसज्जित इटालियन सिपाहियों का रूस के विरुद्ध अधिक-से-अधिक प्रयोग करे, ताकि उसे भी रूस का विजेता बनने का श्रेय मिले। हताहत होने वाले तथा अपग व्यक्तियों की कोई गिनती न थी—“जो मरता है उस मरने दो” “इटली” और ‘राष्ट्र’ का सम्बन्ध मुसोलिनी की दृष्टि में उस देश में रहने वाले व्यक्तियों से कुछ भी न था। देश की शक्ति क्षीण हो चली थी, पर मुसोलिनी नवीन प्रदेश पर आधिपत्य होने की आशा में खुश था। वह कमजोर और बोदे आदिमियों के देश की शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। सभी तानाशाहों की यही मनोवृत्ति होती है। शक्ति के भंडार को भरने की उनकी लिप्सा का कहीं भी अन्त नहीं होता।

यह तानाशाही युग है। इसका आरम्भ १९३९ से पहले हो चुका था। परन्तु युद्ध से इसका अन्त नहीं हुआ है। युद्ध इसलिए लड़ा गया था कि जिस प्रकार तानाशाहियों में केवल पशु-बल से निर्णय होते हैं उसी प्रकार ससार में भी पशु-बल के द्वारा फैसले न होने लगे। युद्ध में प्रमुख फाशिस्ट शक्तियाँ नष्ट हो गईं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पशु-बल का अब भी बोल-वाला है।

न्याय की पुष्टि के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु न्याय के बिना जब बल का प्रयोग किया जाता है तो वह तानाशाही का रूप धारण कर

ज्ञेता है। विचारहीन बल नास्तिकवाद है। बल का बल के लिए प्रयोग फाशिज्म है। बल द्वारा शासन लोकतन्त्रवाद के लिए सबसे बड़ा सकट है।

यदि लोकतन्त्रवादी राष्ट्र १९३६ अथवा १९३७ में अथवा १९३८ में ही सत्तर्क होते तो दूसरे महायुद्ध को रोका जा सकता था। इसके विपरीत 'मफल सम्मेलनो' के समाचार प्रकाशित करके लोकतन्त्रवादी राष्ट्रों की जनता को निश्चित कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, बल्कि उनमें यह धारणा भी उत्पन्न की जाती थी कि यदि वे कुछ न करेंगे—यदि वे मचूरिया, अवीमोनिया और स्पेन में तटस्थ बने रहेंगे तो सर्वत्र ज़ान्ति का साम्राज्य रहेगा। परन्तु हुआ यह कि युद्ध छिड़ गया।

अपने अस्तित्व के लिए सकट उपस्थित हो उठने पर भी लोकतन्त्रवादी राष्ट्र इतने बेखबर क्यों रहते हैं? वे दूर बने रहने, विरोधी राष्ट्रों को मना-कर खुश करने या चुपचाप हाथ-पर-हाथ घरे बैठे रहने की नीति का क्यों अनुसरण करते हैं?

आधुनिक लोकतन्त्रवाद निर्दिष्ट ध्येय की प्राप्ति के लिए कोई पान्दोलन न होकर रहन-सहन का एक खाम तरीका है। राष्ट्र अपने अस्तित्व की रक्षा और दौलत या दूसरे प्रलोभनों की प्राप्ति के लिए जो सपर्प करते हैं लोकतन्त्रवाद उन सघर्षों से विश्राम की अवस्था है।

आधुनिक सभ्यता मनुष्य के कुदृष्ट होने के स्वभाव को दबा देती है। शायद इसी तरह वह चारों तरफ फैली हुई पुरातनता के प्रति धर्म-धर्म का रक्षण करने के मानसिक दास से बच जाता है। ईसाई धर्म के लिए धर्म का अर्थ आज के कष्टों के बदले में भविष्य में सुख और शान्ति का दावा करना है। धर्म-वाद प्रत्येक मनुष्य की समस्या को अलग-अलग रूप में दूर करने का प्रयत्न करता है।

प्राप्त करने वाला चाहे वदमाश ही हो—राजा वही होता है। विजेता के पीछे जाना ही पड़ेगा—चाहे वह कैदखाने को ही ले जाय। झूठ और बेईमानी से काम भले ही लेना पड़े—शक्ति जरूर प्राप्त करनी चाहिए। कम्युनिस्ट तथा फाशिस्टो का यही विचार है। “शक्ति मिलने पर हम वैसे ही भीषण अत्याचार दूसरों पर करेंगे, जो वे हमारे साथ कर चुके हैं।” यह नया सिद्धान्त है। तानाशाहियों ने प्रतिरोध के कानून को स्वीकार कर लिया है।

शक्ति के पुजारियों के लिए नैतिकता एक बेहदा शब्द है। वे कहते हैं—“आदर्शवाद—परमाणु-युग में ? क्या पागल हो गए हो ?”

उनके विचार हैं, “गांधी स्वप्नदृष्टा है, गेहलू इस दुनिया का नहीं है। उनमें धोखा देने की शक्ति नहीं है। वे जो सोचते हैं वही कह देते हैं—यहां तक कि अपने सम्बन्ध में भी। उनका व्यवित में विश्वास है।”

तानाशाही शक्ति के पूजक है—उसी शक्ति के, जो मनुष्य को गुलामी की बेड़ी में जकड़ लेती है और अन्त में उसे नष्ट कर देती है। फाशिस्ट विदेश-मनी सिग्रानो की जो डायरी प्रकाशित हुई है उसे पढ़ने से प्रकट होता है कि मुसोलिनी की दृष्टि में मनुष्य के प्राणों का क्या मूल्य था। इटली के पास खाद्य, कच्चे माल और धन की बेहद कमी थी, किन्तु मुसोलिनी यही चाहता था कि हिटलर उस के अपर्याप्त शस्त्रास्त्र से सुसज्जित इटालियन सिपाहियों का रूस के विरुद्ध अधिक-से-अधिक प्रयोग करे, ताकि उसे भी रूस का विजेता बनने का श्रेय मिले। हताहत होने वाले तथा अपग व्यक्तियों की कोई गिनती न थी—“जो मरता है उस मरने दो” “इटली” और ‘राष्ट्र’ का सम्बन्ध मुसोलिनी की दृष्टि में उस देश में रहने वाले व्यक्तियों से कुछ भी न था। देश की शक्ति क्षीण हो चली थी, पर मुसोलिनी नवीन प्रदेश पर आधिपत्य होने की आशा में खुश था। वह कमजोर और बोदे आदमियों के देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। सभी तानाशाहों की यही मनोवृत्ति होती है। शक्ति के भंडार को भरने की उनकी लिप्सा का कहीं भी अन्त नहीं होता।

यह तानाशाही युग है। इसका आरम्भ १९३९ से पहले हो चुका था। परन्तु युद्ध से इसका अन्त नहीं हुआ है। युद्ध इसलिए लड़ा गया था कि जिस प्रकार तानाशाहियों में केवल पशु-बल से निर्णय होते हैं उसी प्रकार ससार में भी पशु-बल के द्वारा फैसले न होने लगे। युद्ध में प्रमुख फाशिस्ट शक्तियाँ नष्ट हो गईं, किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पशु-बल का अब भी बोल-वाला है।

न्याय की पुष्टि के लिए बल की आवश्यकता पड़ती है, परन्तु न्याय के बिना जब बल का प्रयोग किया जाता है तो वह तानाशाही का रूप धारण कर

लेता है। विचारहीन बल नास्तिकवाद है। बल का बल के लिए प्रयोग फाशिज्म है। बल द्वारा शासन लोकतन्त्रवाद के लिए सबसे बड़ा सकट है।

यदि लोकतन्त्रवादी राष्ट्र १९३६ अथवा १९३७ में अथवा १९३८ में ही सतर्क होते तो दूसरे महायुद्ध को रोका जा सकता था। इसके विपरीत 'सफल सम्मेलनों' के समाचार प्रकाशित करके लोकतन्त्रवादी राष्ट्रों की जनता को निश्चिन्त कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, बल्कि उनमें यह धारणा भी उत्पन्न की जाती थी कि यदि वे कुछ न करेंगे—यदि वे मचूरिया, अवीसीनिया और स्पेन में तटस्थ बने रहेंगे तो सर्वत्र शान्ति का साम्राज्य रहेगा। परन्तु हुआ यह कि युद्ध छिड़ गया।

अपने अस्तित्व के लिए सकट उपस्थित हो उठने पर भी लोकतन्त्रवादी राष्ट्र इतने बेखबर क्यों रहते हैं? वे दूर बने रहने, विरोधी राष्ट्रों को मना-कर खुश करने या चुपचाप हाथ-पर-हाथ घरे बैठे रहने की नीति का क्यों अनुसरण करते हैं?

आधुनिक लोकतन्त्रवाद निर्दिष्ट ध्येय की प्राप्ति के लिए कोई आन्दोलन न होकर रहन-सहन का एक खास तरीका है। राष्ट्र अपने अस्तित्व की रक्षा और दौलत या दूमरे प्रलोभनों की प्राप्ति के लिए जो सघर्ष करते हैं लोकतन्त्रवाद उन सघर्षों से विश्राम की अवस्था है।

आधुनिक सभ्यता मनुष्य के क्रुद्ध होने के स्वभाव को दबा देती है। शायद इसी तरह वह चारों तरफ फैली हुई बुराइयों के प्रति निरन्तर कोप करने के मानसिक त्रास से बच जाता है। ईश्वर पर विश्वास रखने अथवा भ्राज के कष्टों के बदले में भविष्य में सुख और शान्ति उपभोग करने के सच्चे वाग दिलाकर धर्म मनुष्य की विरोधी-भावना को शान्त कर देता है। व्यक्तिवाद प्रत्येक मनुष्य की समस्या को अलग-अलग हल करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है।

तानाशाही जनता को लडने के लिए सदा कटिबद्ध रखती है। तानाशाही शासक अपनी प्रजा को युद्ध के लिए तैयार रहने के आदेश देने रहते हैं। इसके विपरीत लोकतन्त्रवाद सामूहिक जियाहीनता की ओर ले जाता है।

लोकतन्त्रवादी समाज की आखें खोलने के लिए पर्वहार्वर के आक्रमण, अथवा सितम्बर १९३९ में इंग्लैंड के लिए उपस्थित होने वाले सन्ट जेन किसी सकट अथवा घोर आर्थिक मन्दी की आदरशक्ती नहीं है। लोकतन्त्रवादी जनता अपनी इच्छा से प्रेरित होकर कोई नया शासन ही नहीं करती है। लोकतन्त्रवादी राष्ट्र को किनी जर्म के लिए उसका एक विशेष वर्ग—जैसे

मजदूर दल, कोई जातीय अल्पसंख्यक समुदाय अथवा पूंजीपतियों का कोई एक गुट विवश करता है और इसमें सकल होने के लिए उसे समाज के अधिकांश भाग का सुस्ती और उदासीनता पर विजय पानी होती है ।

सार्वजनिक प्रश्नों पर जनता के बीच जो मतभेद होते हैं उनसे लोकतन्त्री सरकारों को कुछ न करने का बहाना मिल जाता है और कभी-कभी तो इन मतभेदों के कारण सरकारें सचमुच ही कोई कार्रवाई नहीं करने पाती ।

लोकतन्त्रवाद का कार्य अल्पसंख्यकों से बहुसंख्यकों की, बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों की और एक अल्पसंख्यक समुदाय की दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय से रक्षा करना होता है । इससे उसमें निष्क्रियता आ जाती है । लोकतन्त्रवाद में विरोधी शक्तियों की रोक-थाम और संतुलन होता रहता है । निष्क्रियता इस रोक-थाम से और भी बढ़ जाती है ।

लोकतन्त्रवाद की प्रवृत्ति समाज को उसकी छोटी-से-छोटी इकाइयाँ—व्यक्तियों और परिवारों में बांट देती है । इस प्रकार लोकतन्त्रवाद विघटन को प्रोत्साहन देता है और विघटित होने पर वह अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है । ट्रेड यूनियन, पूंजीपतियों के संघ तथा अन्य दल और संस्थाएँ अपनी रक्षा तथा दूसरों पर हमले करती हैं, किंतु सम्पूर्ण राष्ट्र एक इकाई के रूप में कुछ नहीं कर पाता ।

लोकतन्त्री सरकारें कभी कोई निर्णय नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी सम्पूर्ण शक्ति राष्ट्र के भीतर की विरोधी शक्तियों की रोक-थाम और उनके मध्य संतुलन स्थापित करने में ही खर्च हो जाती है ।

राजनीति और विज्ञान की एक जैसी उन्नति न होने से समाज बड़ी दुविधा में पड़ जाता है । मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क जिस सर्वोत्तम तरीके को निकालने की क्षमता रखते हैं उससे परमाणु-बम का आविष्कार होता है । परन्तु शान्ति-काल में परमाणु-बम के नियंत्रण का निर्णय समाज के सबसे बुद्धिमान् व्यक्तियों के हाथ में नहीं दिया जाता । इस सम्बन्ध में जो फैसला होता है वह असंख्य स्वार्थों की खींच-तान तथा अनेक आशकाओं, प्रलोभनों, दवावों और आशाओं के घात-प्रतिघात का परिणाम है । विज्ञान का बस चलता तो निर्धनता, साम्राज्यों और पिछड़े हुए मजहबों का नाम-निशान न जाने कब का मिट गया होता, परन्तु राजनीति अभी तक इन पुरानी और बेकार बातों को कायम रखे हुए है । राजनीति शरीर की विपरीत गथियों को काटकर निकाल देने से घबराती है ।

दल के सबसे योग्य व्यक्ति को चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाना

जरूरा नहीं है, बल्कि उम्मीदवार उस व्यक्ति को बनाया जाता है, जिसे सबसे अधिक वोट मिलने की सम्भावना होती है। सर्वोत्तम विचार की विजय नहीं होती, बल्कि उस विचार की होती है, जिसे जनता का समर्थन सबसे अधिक प्राप्त होता है।

लोकतन्त्रवाद क्रियाशील तथा कार्यक्षम सरकार से घबराता है कि कहीं वह स्वाधीनता पर ही कुठाराघात न करने लगे। और जब किसी सरकार को चुस्ती और लापरवाही की आदत पड़ जाती है तो जरूरत के समय भी वह कार्य नहीं कर पाती।

इस तथ्य को समझने से स्पष्ट हो जाता है कि आक्रमणशील ताना-शाहियों का सामना होने पर लोकतन्त्रवादी राष्ट्र पीछे क्यों हटते गये। इससे घरेलू समस्याएँ हल करने में लोकतन्त्रवादी राष्ट्रों की असमर्थता और उनके कारणों पर भी प्रकाश पड़ता है।

युद्ध से लोकतन्त्रवादी राष्ट्रों की गुप्त शक्तियाँ सामने आ जाती हैं। सकट उनकी आँखें खोल देता है। वे अपनी शक्ति संग्रह करने लगती हैं और अन्त में युद्ध में जीत जाती हैं। परन्तु राजनीति का अभिशाप और शक्ति का विघटन फिर उन पर अधिकार जमा लेता है।

दूसरे महायुद्ध के बाद ससार को अनेकों महान् समस्याओं का हल करना है। यदि सकट से बचना है तो लोकतन्त्रवादी देश उन समस्याओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। यातायात के साधनों की गति बढ़ाने के कारण भू-मंडल पहले-से छोटा हो गया है। युद्ध के बाद महाशक्तियों की मग्या में भी कमी हुई है। ससार के एक भाग में सकट उपस्थित होने से अनेक देशों पर उसका प्रसर पड़ेगा और यदि उसे दूर न किया गया तो इस सकट के असर की मात्रा भी अधिक होगी। राजनीतिक वार्ताएँ अब मज्जाक न रह जायँगी, वे जीवन-मरण और राष्ट्रों के अस्तित्व का निपटारा करेगी। लापरवाही, दूर रहने की मनोवृत्ति, सरल आशावाद और टालमटोल की नीति का परिणाम तीसरा महायुद्ध हो सकता है।

इसी प्रकार घरेलू समस्याओं ने अधिक महत्त्वपूर्ण रूप धारण कर लिया है। ससार के स्त्री-पुरुष अधिक उत्तम जीवन की माँग करने लगे हैं। काम प्राप्त करना मनुष्य का आवश्यक अधिकार समझा जाने लगा है। युद्ध के समय लोकतन्त्रवादी देशों में कोई बेकार न था, क्योंकि लड़ाई के कारण वस्तुओं की माँग बढ़ी हुई थी। अब शान्तिजालीन रचनात्मक उद्देश्यों के लिए ही नागरिक पूरे काम की माँग करने लगे हैं। परन्तु गैर-मरजारी उद्योगों द्वारा सभी को

लगातार काम देना असम्भव है। यही कारण है कि गैर सरकारी उद्योग जिन गतिवियों को सुलझाने में असमर्थ रहे हैं उन्हें सुलझाने की आशा सरकारों से की जा रही है।

इस प्रकार गैर सरकारी उद्योगों का प्रभुत्व घटने लगा है। यहां तक कि निजी कारबारों को भी सार्वजनिक दृष्टिकोण से देखा जाने लगा है। ब्रिटिश औद्योगिक संघ के अध्यक्ष सर क्लाइव वेल्च ने ३० नवम्बर १९४५ को माचेस्टर में भाषण देते हुए कहा था—“हम मानते हैं कि उद्योग-धंधों का नियंत्रण उनके मालिकों की ही एक-मात्र इच्छा की वस्तु नहीं है।” जनता के हितों का ध्यान रखते हुए उद्योगपतियों के अधिकार में कमी की जाती है। जिस प्रकार किसी घर के मालिक को राष्ट्रीय महत्त्व की अपनी किसी कलाकृति को नष्ट करने का अधिकार नहीं है उसी प्रकार कारखानेदार को अपने कर्मचारियों को थोड़ा वेतन देकर अथवा तैयार माल का अधिक मूल्य लेकर समाज को हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है। मानव अधिकारों के इस नये दृष्टिकोण ने साम्प्रतिक अधिकारों की पुरानी धारणा में क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया है।

परन्तु नये दृष्टिकोण ने नये संकटों को भी जन्म दिया है। यदि राष्ट्र के प्रतिनिधि के रूप में सरकार के कार्यक्षेत्र में विस्तार हो जाता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है और तब इस देख-रेख की आवश्यकता उठ खड़ी होती है कि कहीं सरकार समाज पर अत्यधिक प्रभुत्व तो नहीं प्राप्त कर लेती। आधुनिक तानाशाहियों का इतिहास देखने से पता चलता है कि किस प्रकार व्यक्तियों तथा दलों के हाथों से शक्ति पहले सरकारों के हाथों में आई और फिर ये सरकारें जनता के नियंत्रण के बाहर हो गईं। प्रत्येक लोकतन्त्रवादी राष्ट्र को तानाशाही का खतरा रहता है।

बेकारी, अभाव और भेद-भाव आधुनिक लोकतन्त्रवाद की कठिनाइयां हैं, जो तानाशाही के हिमायतियों का बल बढ़ाती हैं। इसके विपरीत, व्यापक अधिकारों वाली ऐसी सरकार, जो सभी आर्थिक तथा राजनीतिक समस्याओं को हल करने का बीड़ा उठाती हो, तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करती है।

तानाशाही में स्वतन्त्रता का अभाव होता है और वेतन कम होते हैं, किन्तु काम प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। पुराने पूँजीवादी लोकतन्त्रीय राष्ट्रों में स्वतन्त्रता तो रहती है, किन्तु काम का अभाव रहता है और जिन्हें काम मिला हुआ है वह आगे बना रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोकतन्त्रवाद की मुख्य समस्या राजनीतिक स्वतन्त्रता बनाये हुए आर्थिक सुरक्षा तथा समृद्धि में वृद्धिकरना है। इस विषय में सफलता प्राप्त करने पर ही लोकतन्त्रवाद

तानाशाही पर विजय प्राप्त कर सकता है ।

लोकतन्त्रवाद की सरकार की उपेक्षा, जिसमें अधिकांश समस्याएँ बिना हल की हुई रह जाती हैं और सरकार के कार्यक्षेत्र के अत्यधिक विस्तार के, जिससे सबको काम तो मिल जाता है पर स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है, बीच का मार्ग खोज निकालना है ।

अमरीका ससार का सबसे समृद्धिशाली तथा शक्तिशाली राष्ट्र है । वह अत्यल्प शासन तथा अत्यधिक शासन के मध्य का सुविधापूर्ण मार्ग कुछ समय तक ग्रहण कर सकता है । अधिक-से-अधिक अमरीका “नई योजना” जैसे किसी कार्यक्रम का अनुसरण कर सकता है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत “टेनीसी वेली प्रॉजैक्ट” जैसे सरकारी उद्योग भी सम्मिलित किये जा सकते हैं । अमरीका में पहले तो सरकारी निमंत्रण थोड़ा रहे, किन्तु उसमें क्रमशः वृद्धि होती रहनी चाहिए । सरकार को अपनी याजना बनाने, निरोक्षण करने तथा मालिकों और मजदूरों के झगड़ों में पचायत द्वारा फैसला कराने के कार्य में वृद्धि करनी चाहिए । उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं की सहयोग समितियों की स्थापना भी एक अच्छी बात रहेगी । यदि इस साधारण उन्नति का कट्टर पूँजीवादियों ने विरोध किया तो अमरीकी समाज विचित्र स्थिति में हो जायगा और कट्टर-पक्षियों का वामपक्षियों से संघर्ष छिड़ जायगा ।

परन्तु यूरोप में लोगों को पूँजीवादी लोकतन्त्रवाद और कम्युनिस्ट तानाशाही के मध्य चुनाव नहीं करना है । हिटलर के हाथों में मत्ता मुरतत जर्मन पूँजीपतियों और ज़मींदारों ने ही तैयारी की और उसे गैर-जर्मन प्रतिक्रियावादी वर्ग कम्युनिज्म के विरुद्ध सबसे बड़ी शक्ति मानने लगे थे । इस से यूरोप में पूँजीवाद का जनाजा ही उठ गया । इस यूरोप के सामने दो मार्ग हैं । पहला है समाजवाद—पूँजीवाद और लोकतन्त्रवाद के साथ, जिसे समाजवादी लोकतन्त्रवाद कहा जा सकता है । दूसरा मार्ग है समाजवाद—पूँजीवाद तथा लोकतन्त्रवाद के बिना, जो बालशेविज्म है ।

इसी प्रकार ससार के आर्थिक पुनर्निर्माण में एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमरीका और आस्ट्रेलिया की उद्योग और कृषि की दृष्टि से पिछड़ी हुई सरकारें भी बहुत कुछ भाग ले सकती हैं । भारत के करोड़ों व्ययमायी ने मुझे बताया कि वह भी समाजवादी हैं । बम्बई के कृषिपटु प्रमुख पूँजीपतियों ने इस बात के प्रमुख भारतीय उद्योगपति श्री जे० आर० डी० ताना के नेतृत्व में औद्योगिक उन्नति की एक १५ वर्षीय योजना बनाई है, जिसकी सफलता सरकारी सहयोग पर निर्भर है । इसमें प्रष्ट होता है कि नवीन विचारधारा किन

दिशा की ओर बढ़ रही है। पूँजीपतियों ने स्वीकार किया है कि राज्य की सहायता के बिना वे कुछ करने में असमर्थ हैं। भारतीय पूँजीपतियों ने अमरीकी पूँजीपतियों से भी सहायता की आशा की है। इस प्रकार नई आर्थिक व्यवस्था बहुत कुछ मिश्रित-सी होती जान पड़ती है।

युद्ध ने समाजवाद का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। पहले महायुद्ध में विदेशी सरकारों को अमरीकी बैंकों से ऋण मिले थे। दूसरे महायुद्ध में उन्हें अमरीकी सरकार की माफ़त उधार-पट्टा प्रणाली के अन्तर्गत माल उधार मिला है। यह अमरीका की सघ सरकार ही थी जिसने १९४१ में युद्ध-उद्देश्य से प्रेरित होकर औद्योगिक विस्तार का आयोजन किया, उसमें धन लगाया और उसके मंचालन का प्रबन्ध किया। सरकारी सहायता के बिना युद्धोत्पादन का कार्य असम्भव था। अत्र शान्ति के समय भी लोकतन्त्रवादी राष्ट्रों को उतने ही विशाल कार्य को अपने हाथों में लेना है।

इस तरह स्पष्ट है कि आर्थिक क्षेत्र से सरकारों को अपदस्थ नहीं किया जा सकता। कट्टरपथी चंचल मान चुका है कि ससार में समाजवाद की तरफ जो एक लहर बह चली है—वह निश्चित रूप से एक स्थायी विचार-धारा है।

सोवियत रूस के अतिरिक्त, जहाँ गैर सरकारी पूँजी पर प्रतिबन्ध है, अन्य देशों में यह प्रश्न नहीं है कि गैर-सरकारी उद्योग कायम रहे अथवा नहीं? वहाँ तो प्रश्न यह है कि उद्योगों में कितना हिस्सा सरकार का रहे और कितना अन्य लोगों का और इस प्रश्न पर राष्ट्र के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाय। दूसरे शब्दों में समाजवाद का मिश्रण किस सीमा तक पूँजीवाद के साथ वाञ्छनीय है। महत्त्व अनुपात को निर्धारित करने का है। अनुपात इस दृष्टि से निर्धारित किया जाय कि एक तरफ तो किसी काम का अभाव न रहे—सबकी समृद्धि बढ़े और दूसरी तरफ स्वतन्त्रता में कमी न हो। युद्ध के बाद इस प्रयोग पर ही लोकतन्त्रवाद का भविष्य निर्भर है। इस प्रयोग का उद्देश्य मनुष्य को स्वतन्त्र तथा सुखी बनाना है।

युद्ध के बाद सामाजिक प्रयोगशाला में सबसे पहले ब्रिटेन ने प्रवेश किया, जो लोकतन्त्रवादी सत्ताओं में सबसे परिपक्व है।

ऐसा बिरला ही भाग्यवान् राष्ट्र होगा, जिसे अपने पसन्द की सरकार मिली हो। स्पेन फ्रांको, हिटलर तथा मुसोलिनी से जूझता रहा, किंतु रहना पड़ा उसे फ्रांको के ही शासन में। फिर भी कभी-कभी, और विशेषकर प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी देशों में जनता ऐसे निर्णय कर डालती है, जो वास्तव में

राष्ट्रीय हितों के अनुकूल होते हैं। एक ऐसा ही निर्णय जुलाई, १९४५ के आम चुनाव में ब्रिटेन के मजदूर-दल की विजय थी। पार्लामेंट में मजदूर सदस्यों को भारी बहुमत में भेजकर निर्वाचकों ने आर्थिक-क्षेत्र में राष्ट्रीयकरण की नीति का और वैदेशिक क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीयता की नीति पर चलने का फैसला दे दिया था।

ब्रिटेन की औद्योगिक व्यवस्था पुरानी पड़ गई है। उसमें सुधार करने के लिए राष्ट्रीयकरण परम आवश्यक है। १९४१ में मैं ब्रिटिश कारखानों की कुछ ऐसी मशीनों को देख चुका हूँ, जो बहुत पुरानी चाल की थीं। ब्रिटेन में साधारण वस्तुओं के उत्पादन की कुछ आधुनिक मशीनें अवश्य हैं, किंतु आम-तौर पर यह कहा जा सकता है कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के संयुक्त प्रभाव के कारण ब्रिटेन औद्योगिक उन्नति के विषय में कुछ पिछड़ा हुआ ही रहा है।

ब्रिटेन की विदेश-नीति में अन्तर्राष्ट्रीयता की आवश्यकता स्पष्ट है। अब राष्ट्रीयता की नीति का, जिसमें कमजोर राष्ट्रों को जबरन अपने अवीन रखा जाता है, उसके लिए कुछ भी महत्त्व नहीं है। अब उसे रुस और कहीं-कहीं अमेरिका का सामना करना है।

परन्तु कभी-कभी उपयोगिता न रहते हुए भी पुरानी नीति का अनुसरण मुस्ती, पहले की आदत और नवीनता से भय के कारण होता रहता है। कभी-कभी अस्थायी अफसर पुरानी नीति के पोषक बन जाते हैं और निर्वाचित मंत्रियों की अपेक्षा उनकी अधिक चलती है। परन्तु यदि दुर्गुण अपने पुराने साम्राज्यवाद को त्याग दे और शक्ति-मनुष्य तथा पूंजीवादी नीति को तिला-जलि दे सके तो पहले यूरोप और बाद में एशिया उसने नौकर ग्रहण करने को कह सकते हैं।

ब्रिटिश जनता ने इसीलिए मजदूर-सरकार के हावों में शासन-मंत्र सौंपा है। मजदूर-दल के राजनीतिज्ञ भी ब्रिटेन के इस अवसर से अनपरिचित नहीं हैं। यह समय ही बतायेगा कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञ इस अवसर से लाभ उठा पाते हैं अथवा नहीं?

यूरोप की सबसे बड़ी तीन शक्तियाँ ब्रिटेन, रुस और फ्रांस हैं। भू-शक्ति और क्षत-विक्षत यूरोप पर, जो युद्ध की विनीमिका के बावजूद भी मध्य से महान् सांस्कृतिक केन्द्र है, प्रभाव जमाने के लिए इन तीनों के ही बीच स्पर्धा होनी है।

ब्रिटेन सामाजिक लोकतन्त्रवाद का नवीन सिद्धान्त लेकर आगे बढ़ रहा है। रुस बोल्शेविज्म—रहन-सहन के सोवियन्त तरीके जो केन्द्र सरकार द्वारा

है। अपरिवर्तनवादी कैथोलिक, अपरिवर्तनवादी पूंजीपति राजतंत्रों के हिमायती और फाशिस्ट इन दोनों ही विचार-धाराओं के विरुद्ध है। ब्रिटेन, रूस और पोप के इस त्रिकोण के प्रति अमेरिका के सम्बन्धों का अभावधारण महत्त्व है।

१९४४ में स्टालिन ने धार्मिक समस्याओं के सम्बन्ध में एक पत्र पोप को लिखा था। स्टालिन ने पोप के प्रति मैत्री का हाथ बढ़ाया था। यहाँ तक कि उसने रूस के पुराने यूनानी सम्प्रदाय और रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय दोनों को मिला देने तक का प्रस्ताव किया था।

स्टालिन की चिन्ता पोलैंड के सम्बन्ध में थी। जर्मनी जाने के लिए पोलैंड रूस के पुल के समान है और जर्मनी यूरोप का हृदय—उसका केन्द्रस्थल है। पोलैंड रामन कैथोलिकों का देश है। स्टालिन जानता था कि पोलो पर आधिपत्य जमाने में उसे विशेष कठिनाई होगी। वह यह भी जानता था कि पोल लोग दीर्घकाल तक उसका सक्रिय विरोध करते रह सकते हैं। इसीलिए स्टालिन पोप की सहायता का इच्छुक था। पोप और स्टालिन का समझौता होने पर पोलैंड में रूस की कठिनाइयाँ दूर हो सकती थीं।

अमेरिका में बसे हुए एक कैथोलिक पादरी फादर ओरेलेमनस्की ने १९४४ में स्टालिन से मिलने के उपरान्त एक वक्तव्य निकाला था कि पोलैंड के रोमन कैथोलिकों को रूस किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचाना चाहता। परन्तु पोप ने इस सम्बन्ध में कुछ भी कहना ठीक न समझा। जब पोप ने स्टालिन के पत्र का उत्तर बहुत समय तक न दिया तो राष्ट्रपति रुजवेल्ट ने इसमें कुछ दिलचस्पी ली। एक अमरीकी नेता एडवर्ड जे० फिलन कई बार रोम और मास्को गया। वह माल्टा-सम्मेलन में भी उपस्थित था। परन्तु समझौते का यह प्रयत्न भी निष्फल हुआ और पोप ने स्टालिन का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उसी दिन से सोवियत पत्रों तथा रूस के हिमायतियों ने सभी जगह रोमन कैथोलिकों के विरुद्ध विष-वमन करना आरम्भ कर दिया।

स्टालिन और पोप दोनों अपने-अपने क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीयता हामी हैं, किन्तु उनके आदर्श तथा राजनीति परस्पर टकराती हैं। दूसरे महायुद्ध से यूरोप में कैथोलिकों का प्रभाव घट गया। कैथोलिकों का मुख्य देश इटली हार गया। जर्मनी में भी कैथोलिकों की सख्या अधिक है, किन्तु दूसरे महायुद्ध के बाद उसकी कोई राजनीतिक स्थिति नहीं रही। दो अन्य कैथोलिक देश स्पेन और पुर्तगाल अभी तक फाशिस्ट हैं। इसलिए उनका भी कोई प्रश्न नहीं उठता। फ्रांस पहले प्रथम कोटि की शक्ति था, किन्तु अब दूसरी कोटि में आ गया है। पोलैंड, जो पोप की राजनीतिक व्यवस्था का एक आधार-स्तम्भ था, रूस के प्रभाव में हो गया।

है। इसलिए पोप ने अब अमरीकी देशों की ओर दृष्टि फेरी है। इसका यह मतलब नहीं कि पोप ने यूरोप में हार मान ली है, बल्कि इसके विपरीत, वह अमरीका को भी इस संधर्ष में घसीटने की चेष्टा कर सकता है।

संसार के अपरिवर्तनवादी रूस तथा ब्रिटेन के विरुद्ध पोप को अपना मित्र मानते हैं। परन्तु फ्रांस और इटली में कैथोलिक वर्ग प्रगतिशील है और नई विचार-धाराओं से प्रभावित हो चुके हैं। वे ब्रिटेन से मैत्री कर सकते हैं।

ब्रिटेन और रूस एक संधर्ष में व्यस्त हैं। दोनों के घात-प्रतिघातों की गूँज यूरोप और एशिया में सुनाई देने लगी है। दूसरे महायुद्ध के बाद यह एक और निर्णयात्मक संधर्ष चल रहा है।

वाल्टर लिपमान प्रभाव-क्षेत्रों के बटवारे और 'तीन बड़ों' के प्रभुत्व के विरुद्ध नहीं है। उसका कहना है कि ब्रिटेन और रूस में भगड़ा होने की सम्भावना नहीं है, क्योंकि जहाँ ब्रिटेन ह्वेल अर्थात् सबसे महान् जल-शक्ति है वहाँ रूस हाथी अर्थात् सबसे बड़ी स्थल-शक्ति है, परन्तु, एशिया में इंग्लैंड बहुत बड़ी स्थल-शक्ति है और उधर रूस महान् जमीन बेड़े का निर्माण कर रहा है। वह अटलांटिक की तरफ क्रमशः बढ़ रहा है। स्टालिन की आँखें प्रशान्त, बाल्टिक सागर, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर की तरफ लगी हुई हैं।

इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि 'ह्वेल' 'हाथी' के जगत में घुस सकती है या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या ब्रिटिश 'सिंह' नती 'रीछ' के साथ निर्वह कर सकेगा? 'सिंह' चाहे 'रीछ' के साथ विश्राम करना भले ही मजूर कर ले, पर रूसी 'रीछ' स्फूर्ति से भरा हुआ है और एक जगह से दूसरी जगह धूमना ही पसंद करता है। कम-से-कम वह बड़बड़े 'सिंह' के साथ रहना अभी पसंद नहीं करेगा, जो निर्बल हो चुका है और जिसकी गर्जन अपनी एशियावासी प्रजा के चीत्कारों और चुनौतियों में विलीन हो जाती है।

अपनी एक पिछली पुस्तक लिखते समय मुझे आर्ज चिचरिन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जो १९१८ से १९३० तक रूस का विदेश-मंत्री था। चिचरिन की अफगानिस्तान और ईरान में विशेष तथा पूर्व में साधारण दिलचस्पी थी। उसने कहा था कि बाकू एशिया की तरफ निर्देश करने वाली एक ग्रन्थी है। एशिया और जर्मनी में दिलचस्पी अधिक होने के कारण उसका ब्रिटेन से मैत्री बनाये रखने में अधिक विश्वास न था। चिचरिन कम्युनिस्ट पक्ष का सदस्य अवश्य था, किन्तु ज़ारों के विदेश-सम्बन्ध में काम कर चुकने के कारण उसका भुकाव पिछली परम्परा कायम रखने की तरफ ही अधिक था।

परन्तु मैक्सिम लिटविनोव मुझे बताया करता था कि सोवियत् सरकार के लिए ब्रिटेन से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। मध्य-पूर्व के अर्द्ध-औपनिवेशिक देशों के लिए रूस को ब्रिटेन से अपने सम्बन्ध नहीं बिगाड़ने चाहिए। लिटविनोव चिचरिन का सहकारी था और बाद में वह भी विदेश-मंत्री हुआ। चिचरिन और लिटविनोव में विदेशी नीति के इस पहलू को लेकर लगातार संघर्ष चला करता था। स्टालिन ने जब चिचरिन की नीति स्वीकार कर ली तो लिटविनोव को अलग कर दिया गया। लिटविनोव को १९-३९ के मई महीने में निकाला गया था, जब रूस ने आक्रमणकारी नीति का श्रीगणेश किया था। लिटविनोव का विस्तार करने की नवीन सोवियत् नीति में विश्वास नहीं है और इसीलिए वह उस पर अमल नहीं करना चाहता।

१९३६ में अवीसीनिया के युद्ध के समय में पेरिस में था। मुझे एक फ्रांसीसी पत्र में यह पढ़कर आश्चर्य हुआ कि अवीसीनिया का पेरिस-स्थित राजदूत रूसी भाषा बोलता है। मुझे ज्ञात हुआ कि बोलशेविक क्रान्ति से पूर्व हब्शी सरदारों के लड़के जारों के निमंत्रण पर सैनिक-शिक्षा प्राप्त करने के लिए सेंट पीटर्सबर्ग जाते थे। उन दिनों अवीसीनिया ब्रिटेन के प्रभाव में था।

अवीसीनिया के ईसाई मोनोफिस्टिक सम्प्रदाय के हैं अर्थात् वे ईसा के मानवीय रूप को न मानकर केवल ईश्वरीय रूप को ही स्वीकार करते हैं। आर्मीनियन ईसाई भी इसी सम्प्रदाय के हैं और उनका प्रधान केन्द्र रूसी आर्मीनिया में है। रूसी अधिकारी आर्मीनियन ईसाइयों का उपयोग अवीसीनिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए करते रहे हैं।

ज़ारशाही रूस की नीति ब्रिटेन के प्रभाव-क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की रही है। आज भी जहाँ ब्रिटेन का प्रभाव है वही रूस उपस्थित होकर हस्तक्षेप करने का चेष्टा करता है।

१९४४ में मिस्री सरकार ने सोवियत् सरकार से राजनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये। यह कार्य वहाँ के प्रतिक्रियावादी ज़मींदारों को बुरा लगा, जो मिस्री किसानों पर अपने अत्याचारों के कारण प्रसिद्ध हैं। तब रूस ने एक चाल चली। उसका जो राजदूत काहिरा आया उसके साथ सेक्रेटरियों का बड़ा स्टाफ भी था और ये सब-के-सब मुसलमान थे (रूस में लाखों मुसलमान हैं)। इन मुसलिम सेक्रेटरियों का पहला काम शाह फरूक के आगे सलाम करने आना और शुक्रवार की नमाज के समय उपस्थित रह सकने की अनुमति प्राप्त करना था। दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य यह था कि रूस की मित्त से- सहानुभूति है और वह उसकी भावनाओं का आदर करता है।

सोवियत् आसक फिलस्तीन तथा अरब राज्यों में भी दिलचस्पी लेने लगे हैं। कारण सिर्फ यह है कि यह ब्रिटेन का प्रभाव-क्षेत्र है। सोवियत् सरकार का कहना है कि अरबों तथा अन्य पूर्वी राष्ट्रों के मध्य वह अंग्रेजों का स्थान ग्रहण करने को तैयार है। सोवियत् मुसलमान, सोवियत् आर्मीनियन, सोवियत् यूनानी स्लान ब्रिटिश देशों में और उनके इर्द-गिर्द रुस के प्रति सद्भावना उत्पन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति इन प्रदेशों में जो कटुता की भावना है, उसे बढ़ाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है।

रुस के इरादों का अलग-अलग मतलब लगाया जा सकता है। सवाल यह नहीं है कि दरें दानियाल में रुसियों के अड्डे प्राप्त करने, ईरान में रुसियों के घुस जाने, यूनान में उनका प्रभाव बढ़ाने, डोडेकोनीज द्वीपों पर उनका नियंत्रण होने और ट्रिपोलीटानिया के उपनिवेश में उनके पैर जम जाने से ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा उपस्थित होता है और मिन्य तथा भारत के लिए ब्रिटेन का मार्ग कट जाता है। यदि रुस को रक्षा के लिए उत्तरी अफ्रीका चाहिए तो ब्रिटेन दरें दानियाल और अमरीका पोलैंड की माँग अपनी रक्षा के लिए कर सकते हैं। इस तरह तो सम्पूर्ण भूमंडल पर अधिकार जमाये बिना रक्षा की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो सकती।

ब्रिटिश साम्राज्य के भग होने पर मुझे तनिक भी आपत्ति नहीं। परन्तु अगर ऐसा रुस के दबाव से होता है तो ये उपनिवेश रुस के अधिकार में चले जायेंगे और फिर एक मात्र बचे हुए महान् राष्ट्र अमरीका को विशाल रुसी साम्राज्य से टक्कर लेनी पड़ेगी।

ब्रिटेन द्वारा उपनिवेशों को आजादी देना अच्छा है। यदि मजबूत राष्ट्रों का संगठन उनकी रक्षा करता रहे तो ये उपनिवेश जमा उगानि करके अन्तर्राष्ट्रीय ईर्ष्या के लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ और भी बन सकते हैं। परन्तु यदि अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्द्धा के परिणामस्वरूप ये ब्रिटेन के प्रभुत्व से मुक्त होते हैं तो अनिवार्य रूप से सोवियत् तानाशाही के उदर में समा जायेंगे। एक साम्राज्यवादी शाक्ति की साम्राज्य-विरोधी नीति भी अन्ततः साम्राज्यवाद ही होती है।

मध्य एशिया और निकट पूर्व के देश ब्रिटिश तथा रुसी साम्राज्यों की इस कलमकश को चुपचाप खड़े होकर देखने नहीं रह सकते। वे भी पट्टियों में शामिल होंगे और कभी एक महाशक्ति न हो और कभी दूसरा महाशक्ति का साथ देकर अपने स्वार्थ-साधन का प्रयत्न करेंगे उन्होंने ऐसा करना प्रारम्भ भी कर दिया है।

रुस और ब्रिटेन के साम्राज्यों के पारस्परिक संबंधों के बीच पराधीन

राष्ट्रो के इस स्वाधीनता-प्रयत्न का विशेषमहत्त्व है। जब तक इंग्लैंड अपने साम्राज्य को भगनहा करता तब तक इस प्रयत्न से रूस का ही लाभ होगा। एशियाई राष्ट्र प्रत्येक सम्भव तरीके से स्वाधीनता प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। ब्रिटेन की अधीनता में रहने वाला अशान्त और विद्रोही भारत साम्राज्यवादी शक्ति से लड़ने के लिए रूस को बुला सकता है। परन्तु स्वतंत्र भारत इसी प्रभुत्व का कट्टर विरोधी होगा और वह सोवियत् आक्रमण से रक्षा के उद्देश्य से विश्व-संगठन कायम करने के लिए ब्रिटेन अथवा अमेरिका से नेतृत्व ग्रहण करने के लिए कह सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्य-विस्तार के इच्छुक रूस के पदार्पण से पश्चिमी साम्राज्यवाद की समस्या का हर पहलू बदल जाता है। इस अवस्था में रूस रंगीन जातियों का हिमायती और उनका नेता बनकर सबकी आंखों में धूल भीक सकता है।

१९४६ के आरम्भ में रूस के सहकारी विदेश-मंत्री एड्री विशिंस्की की इंडोनेशिया के प्रश्न पर ब्रिटिश विदेश-मंत्री वेविन से जो झड़प हुई थी उसमें मि० विशिंस्की की इस बात में कुछ भी दिलचस्पी नहीं थी कि मित्रराष्ट्रीय संगठन का निर्णय क्या होता है, या वेविन का कहना क्या है अथवा ब्रिटिश और अमरीकी पक्ष इस भाषण का कैसा मजाक कर सकते हैं। उनकी दिलचस्पी सिर्फ इसी बात में थी कि पश्चिमी साम्राज्यवाद की सम्मिलित सेना के दमन का शिकार होने वाले उपनिवेशवासियों की हिमायत लेने वाले के रूप में समस्त दक्षिण-पूर्वी एशिया में उसका स्वागत किया जायगा।

अब किया क्या जाय ? एशिया के लोगो को स्वाधीनता मिलनी चाहिए ताकि कोई उनसे अनुचित लाभ न उठा सके। इसके उपरान्त इन लोगो को स्वतंत्रता की रक्षा और आर्थिक उन्नति करने के लिए जिस सहायता की आवश्यकता हो वह मित्र-देशों द्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था से मिले।

प्रत्येक असंतुष्ट एशियावासी पश्चिमी देशों—विशेषकर इंग्लैंड और अमरीका के विरुद्ध रूस के समर्थकों की सख्या बढ़ाता है। पश्चिम को और कुछ नहीं तो केवल इसलिए साम्राज्यवाद को त्याग देना चाहिए कि वह उसके नैतिक और आर्थिक स्वार्थों के लिए हानिकर है। यदि पश्चिमी महाशक्तियों ने इस तथ्य को हृदयगम करके उसके अनुसार कार्य नहीं किया तो रूस के दवाव के कारण उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा।

सोवियत् सरकार के पक्ष में दूसरा लाभ सप्ताह भर में कम्युनिस्ट दलों का फैला होना है। मई १९४३ में तीसरी अन्तर्राष्ट्रीय या कॉमिंटर्न भग होने की

घोषणा की गई। परन्तु इस बात का कोई सबूत नहीं है कि विभिन्न देशों का कम्युनिस्ट दल, जिनका प्रतिनिधित्व कामिटर्न करनी थी, सोवियत्-सरकार के आदेश के बिना स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करते रहे हैं। आज तक किसी भी कम्युनिस्ट दल ने सोवियत्-सरकार के किसी कार्य को न तो आलोचना की है और न उससे कोई मतभेद ही प्रकट किया है। सभी दल सोवियत्-सरकार के कार्यों का समर्थन ही करते रहे हैं। रुस के सम्बन्ध में स्वतंत्र निर्णय का एक उदाहरण भी सोवियत् सरकार के प्रभाव से स्वनन्त्र होने का प्रमाण माना जा सकता था, किंतु ऐसा एक भी उदाहरण अब तक देखने में नहीं आया है।

कभी-कभी किसी कम्युनिस्ट दल द्वारा गैर-कम्युनिस्ट कार्यक्रमों और विचारों का समर्थन इस बात का सबूत मान लिया जाता है कि दल वास्तव में कम्युनिस्ट नहीं है और न वह सोवियत् सरकार के इशारे पर ही नाचता है। यह तर्क असंगत है। वास्तव में रुस केवल नाम का ही कम्युनिस्ट है। चीनी कम्युनिस्टों द्वारा तम्रम विचारों के सुधारों का समर्थन करना आश्चर्य की बात नहीं है। उनकी परीक्षा तो इसी तरह हो सकती है कि क्या कभी उन्होंने अथवा अन्य देशों के कम्युनिस्टों ने सोवियत् सरकार की नीति की निन्दा की है या उससे सहयोग करने से कभी इन्कार किया है।

सोवियत् सरकार ने अप्रैल १९४१ को संधि द्वारा मचूरिया को जापान के संरक्षण में एक राज्य स्वीकार कर लिया था। क्या किसी भी चीनी के लिए इस प्रकार की संधि का समर्थन करना उचित हो सकता था? परन्तु चीनी कम्युनिस्ट दल के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से पूरी घोषणा किया। तत्संगत बात तो यह थी कि १९४३ में कामिटर्न ने अपने इस परिणामस्वरूप चीनी कम्युनिस्टों की सोवियत्-सरकार के प्रति नीति में परिवर्तन हो जाना चाहिए था। परन्तु परिवर्तन हुआ नहीं, क्योंकि कामिटर्न का बोझा जाना आसन्निक न था।

दूसरा महायुद्ध छिड़ने पर भारत के सभी राजनीतिज्ञ दोनों युद्ध का विरोध किया, क्योंकि युद्ध का समर्थन परोक्ष रूप में ब्रिटेन का समर्थन करने के समान था। जब रुस पर हमला हुआ तो भारतीय कम्युनिस्ट दल युद्ध का समर्थन करने लगा और उसने ब्रिटिश सरकार को अपना सहयोग दिया। इस प्रकार भारतीय कम्युनिस्टों के लिए रुस ने 'हेनो' का प्रत्यय बदलने लगाना था। कामिटर्न ने भी भारत की भारतीय कम्युनिस्ट दल में परिवर्तन रहे और अंत में रुस ने सहायता पहुंचाई।

राज्यपति रुस के दलों को सहायता देने के लिए रुस के दलों

राष्ट्रो के इस स्वाधीनता-प्रयत्न का विशेषमहत्त्व है। जब तक इंग्लैंड अपने साम्राज्य को भगनहा करता तब तक इस प्रयत्न से रूस का ही लाभ होगा। एशियाई राष्ट्र प्रत्येक सम्भव तरीके से स्वाधीनता प्राप्त करने को प्रयत्न करेंगे। ब्रिटेन की अधीनता में रहने वाला अशान्त और विद्रोही भारत साम्राज्यवादी शक्ति से लड़ने के लिए रूस को बुला सकता है। परन्तु स्वतंत्र भारत इसी प्रभुत्व को कट्टर विरोधी होगा और वह सोवियत् आक्रमण से रक्षा के उद्देश्य से विस्व-संगठन कायम करने के लिए ब्रिटेन अथवा अमेरिका से नेतृत्व ग्रहण करने के लिए कह सकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में साम्राज्य-विस्तार के इच्छुक रूस के पदार्पण से पश्चिमी साम्राज्यवाद की समस्या का हर पहलू बदल जाता है। इस अवस्था में रूस रगीन जातियों का हिमायती और उनका नेता बनकर सबकी आँखों में बूल भोंक सकता है।

१९४६ के आरम्भ में रूस के सहकारी विदेश-मंत्री एड्री विशिंस्की की इडोनेशिया के प्रश्न पर ब्रिटिश विदेश-मंत्री बेविन से जो झड़प हुई थी उसमें मि० विशिंस्की की इस बात में कुछ भी दिलचस्पी न थी कि मित्रराष्ट्रीय संगठन का निर्णय क्या होता है, या बेविन का कहना क्या है अथवा ब्रिटिश और अमरीकी पत्र इस भाषण का कैसा मजाक कर सकते हैं। उसकी दिलचस्पी सिर्फ इसी बात में थी कि पश्चिमी साम्राज्यवाद की सम्मिलित सेना के दमन का शिकार होने वाले उपनिवेशवासियों की हिमायत लेने वाले के रूप में समस्त दक्षिण-पूर्वी एशिया में उसका स्वागत किया जायगा।

अब किया क्या जाय ? एशिया के लोगों को स्वाधीनता मिलनी चाहिए ताकि कोई उनसे अनुचित लाभ न उठा सके। इसके उपरान्त इन लोगों को स्वतंत्रता की रक्षा और आर्थिक उन्नति करने के लिए जिस सहायता की आवश्यकता हो वह मित्र-देशों द्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था से मिले।

प्रत्येक असंतुष्ट एशियावासी पश्चिमी देशों—विशेषकर इंग्लैंड और अमरीका के विरुद्ध रूस के समर्थकों की सहायता बढ़ाता है। पश्चिम को और कुछ नहीं तो केवल इसलिए साम्राज्यवाद को त्याग देना चाहिए कि वह उसके नैतिक और आर्थिक स्वार्थों के लिए हानिकर है। यदि पश्चिमी महाशक्तियों ने इस तथ्य को हृदयगम करके उसके अनुसार कार्य नहीं किया तो रूस के दबाव के कारण उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा।

सोवियत् सरकार के पक्ष में हमारा लाभ सप्ताह भर में कम्युनिस्ट दलों का फैला होना है। मई १९४३ में तीसरी अंतर्राष्ट्रीय या कार्मिटेर्न भग होने की

घोषणा की गई। परन्तु इस बात का कोई सबूत नहीं है कि विभिन्न देशों का कम्युनिस्ट दल, जिनका प्रतिनिधित्व कार्मिटर्न करती थी, सोवियत्-सरकार के आदेश के बिना स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करते रहे हैं। आज तक किसी भी कम्युनिस्ट दल ने सोवियत्-सरकार के किसी कार्य की न तो आलोचना की है और न उससे कोई मतभेद ही प्रकट किया है। सभी दल सोवियत्-सरकार के कार्यों का समर्थन ही करते रहे हैं। रूस के सम्बन्ध में स्वतंत्र निर्णय का एक उदाहरण भी सोवियत् सरकार के प्रभाव से स्वनन्त्र होने का प्रमाण माना जा सकता था, किंतु ऐसा एक भी उदाहरण अब तक देखने में नहीं आया है।

कभी-कभी किसी कम्युनिस्ट दल द्वारा गैर-कम्युनिस्ट कार्यक्रमों और विचारों का समर्थन इस बात का सबूत मान लिया जाता है कि दल वास्तव में कम्युनिस्ट नहीं है और न वह सोवियत् सरकार के इशारे पर ही नाचता है। यह तर्क असंगत है। वास्तव में रूस केवल नाम का ही कम्युनिस्ट है। चीनी कम्युनिस्टों द्वारा नरम विचारों के सुधारों का समर्थन करना आश्चर्य की बात नहीं है। उनकी परीक्षा तो इसी तरह हो सकती है कि क्या कभी उन्होंने अथवा अन्य देशों के कम्युनिस्टों ने सोवियत् सरकार की नीति की निन्दा की है या उससे सहयोग करने से कभी इन्कार किया है।

सोवियत् सरकार ने अप्रैल १९४१ की संधि द्वारा मचूरिया को जापान के मरक्षण में एक राज्य स्वीकार कर लिया था। क्या किसी भी चीनी के लिए इस प्रकार की संधि का समर्थन करना उचित हो सकता था? परन्तु चीनी कम्युनिस्ट दल के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से यही घोषित किया। तर्क-संगत बात तो यह थी कि १९४३ में कार्मिटर्न भग होने के परिणामस्वरूप चीनी कम्युनिस्टों की सोवियत्-सरकार के प्रति नीति में परिवर्तन हो जाना चाहिए था। परन्तु परिवर्तन हुआ नहीं, क्योंकि कार्मिटर्न का तोड़ा जाना वास्तविक न था।

दूसरा महायुद्ध छिड़ने पर भारत के सभी राजनीतिक दलों ने युद्ध का विरोध किया, क्योंकि युद्ध का समर्थन परोक्ष रूप से ब्रिटेन का समर्थन करने के समान था। जब रूस पर हमला हुआ तो भारतीय कम्युनिस्ट दल युद्ध का समर्थन करने लगा और उसने ब्रिटिश सरकार को अपना सहयोग दिया। इस प्रकार भारतीय कम्युनिस्टों के लिए रूस के हितों का प्रश्न सबसे प्रधान था। कार्मिटर्न भग होने के बाद भी भारतीय कम्युनिस्ट रूस से चिपके रहे और उन्होंने युद्ध में सहायता पहुंचाई।

इटालियन कम्युनिस्टों को साधारणतः मुनोलिनी के चीफ आफ-स्टाफ

मार्शल वेडोग्लियो के विरुद्ध होना चाहिए था। परन्तु सोवियत्-सरकार द्वारा वेडोग्लियो-मन्त्रिमंडल स्वीकार कर लेने पर इटली के कम्युनिस्ट भी उस समय समर्थन करने लगे और उसमें सम्मिलित होना मजबूर कर लिया। साधारण तौर पर अन्य इटालियन नागरिकों की तरह उन्हें ट्रीस्ट मार्शल टिटो के सुपुर्न करने के विरुद्ध होना चाहिए, किन्तु यह विचार करके कि ट्रीस्ट टिटो के हाथ में जायेगा, तो वे सोवियतों से यूगोस्लाविया में कम्युनिस्टों का प्रभाव बढ़ जायगा और इसका प्रभाव एड्रियाटिक सागर तक पहुँच जायगा, इटली के कम्युनिस्टों ने अपने देश के हिस्से के विरुद्ध टिटो के पक्ष का समर्थन किया।

दूसरे महायुद्ध के बाद जर्मनी से जो भूमि छीनी गई है उसका जर्मन कम्युनिस्टों को खेद है। उन्होंने जर्मनी से राइनलैंड और रूर छीने जाने का विरोध किया है। परन्तु उन्हीं जर्मन कम्युनिस्टों ने पोलैंड की भूमि इसी प्रकार मिलाये जाने का समर्थन किया है।

सोवियत्-सरकार की नीति में जब भी परिवर्तन हुए हैं उन्हें सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट दलों ने प्रसन्नतापूर्वक सिर-माये पर लिया है। इसलिए कहा जा सकता है कि सोवियत्-सरकार तथा विदेशी कम्युनिस्ट दलों के कथन तथा कार्य में तनिक भी अंतर नहीं देखने में आता और वे अब भी परस्पर सम्बद्ध हैं।

तब कॉमिटर्न को भग करने से तात्पर्य क्या था ? इस ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से जो पीछे कदम हटाया है—यह उसी नीति का पूर्व लक्षण था। ऐसा करने से सत्तारूढ़ के कम्युनिस्ट दलों के जिम्मे एक नया कार्य सौंपा गया था।

राजनीति के क्षेत्र में स्टालिन एक कारवारी आदमी हैं। साधारण व्यापारी की तरह वह वहीं में अपने हानि-लाभ का लेखा लिख लेता है और वहाँ में उसकी समीक्षा करता रहता है। चीनी कम्युनिस्टों के पास एक विशाल सेना है और वे एक विस्तृत भूखंड पर शासन करते रहे हैं, किन्तु एक बार वे मार्शल चांग-काई-शेक की विदेश-नीति में परिवर्तन करने में सफल नहीं हो सके। १९३३ से पूर्व जर्मन कम्युनिस्टों का बहुत जोर था और चुनाव में उनका ६०,००,००० से अधिक मत प्राप्त हो चुके थे। परन्तु वे न तो हिटलर के हाथ में सत्ता जाने से रोक सके और न बाद में ही उसे अपदस्थ कर सके। कम्युनिस्टों ने इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका में स्पेन के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने में अवसर सफल हुए, किन्तु वे स्पेन के प्रति उन देशों की विदेश-नीति में कोई रूढ़िवाद बदल न करा सके। कहीं भी कम्युनिस्टों ने विदेशी सरकारों की नीतियों का निर्णयात्मक ढंग से प्रभावित नहीं किया।

कारण स्पष्ट था और स्टालिन भी उसे ताड़ गया। कम्युनिस्ट विशाल सार्वजनिक प्रदर्शन कर सकते थे, वे किसी सगठन पर कब्जा कर सकते थे और वे जोरदार प्रचार भी कर सकते थे। परन्तु विदेशी कम्युनिस्टों के इन कार्यों से सोवियत् सरकार को कभी भी अधिक लाभ नहीं हुआ, क्योंकि ये सब विरोधी पक्ष में रहने वाले दल के कार्य थे। ये कार्य वे ऐसे क्षेत्र में रहकर कर रहे थे, जिसमें शक्ति का अभाव होता था और शक्ति के बिना वे रूसी सरकार की कुछ ठोस सहायता करने में असमर्थ थे।

कॉमिटर्न को भग करके स्टालिन ने विदेशी कम्युनिस्ट दलों को अधिकार ग्रहण करने की सुविधा दे दी।

१९४३ से पूर्व रूस के बाहर ऐसी सरकार, जिसमें कम्युनिस्ट थे, केवल स्पेन की ही सरकार थी। १९४३ के बाद कम्युनिस्ट दलों के निर्बल सगठनों ने भी, जहाँ सम्भव हो सका है, शक्ति ग्रहण की है।

इससे कम्युनिस्टों के हाल के कार्यों पर प्रकाश पड़ता है और भविष्य की झलक मिलती है।

अब स्टालिन और कम्युनिस्ट दल स्तीफे देकर अपने यहाँ की सरकारों का पतन करा सकती है। इसी कारण, इटली और फ्रांस की सरकारें रूस के विरुद्ध नीति ग्रहण करने के लिए स्वतन्त्र नहीं रह गई हैं। यही कारण है कि फ्रांस पश्चिमी राष्ट्रों के गुट में सम्मिलित होने में असमर्थ है। फ्रांसीसी कम्युनिस्ट दल और दूसरे शब्दों में सोवियत् सरकार इसके विरुद्ध है।

इस प्रकार विदेशी सरकारों में कम्युनिस्टों की उपस्थिति होने पर वे सोवियन् सरकार के विरुद्ध कुछ कह या कर पाएंगी। सिर्फ विरोध करने की अपेक्षा स्टालिन के लिए इस नीति का कहीं अधिक महत्व है। स्टालिन के लिए कौंसिल चैम्बरों के भीतर अपने प्रतिनिधियों को मत प्रदान करने के लिए भेजना अधिक लाभकर है, वनिस्वत इसके कि वे उसके बाहर रहकर नारे लगाते रहे। समय पड़ने पर कम्युनिस्ट दोनों ही कार्य कर सकते हैं।

कॉमिटर्न भग होने के बाद अन्य देशों में काम करने वाले कम्युनिस्ट-दलों ने जो नीति ग्रहण की है उसमें समाजवाद के सिद्धांतों की तुलना में शक्ति-ग्रहण करने और रूस के राष्ट्रीय साधनों की पूर्ति का अधिक महत्व है, यही कारण है कि भारतीय कम्युनिस्टों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का साथ दिया था। चीना कम्युनिस्ट उस चांग-काई-शेक से सहयोग करने को तैयार हो गए थे, जिसकी वे पहले फाशिस्ट कहकर निंदा किया करते थे। रूमानिया के कम्युनिस्टों ने हिटलर का साथ देने वाले राजा माइकेल के साथ और यूरोप के एक

सबसे बड़े प्रतिक्रियावादी रूपानिया के विदेश-मंत्री जार्ज तातरस्कू के साथ सहयोग किया था। अब कम्युनिस्ट वामपक्षी नहीं है—अब उन्हें केवल रूसी साम्राज्यवाद के एजेंट कहा जा सकता है।

अमेरिका जैसे देश में जहाँ राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित होने की शक्ति कम्युनिस्टों में नहीं है वहाँ उन्होंने नई नीति का अनुसरण करना आरम्भ कर दिया है। वे मंत्रियों, कांग्रेस के सदस्यों, पूँजीवादी समाचार पत्रों, रेडियो-स्टेशनों, ट्रेड यूनियनों इत्यादि में प्रभाव जमाने की चेष्टा करते हैं। मजदूर-दलों तथा वामपक्षियों में घुमकर उन पर रज्जा करने की चेष्टा की जाती है। अन्य प्रभावशाली सस्याओं पर भी प्रभाव जमाने का प्रयत्न किया जाता है।

इस नीति का कम-से-कम इतना प्रभाव तो होता ही है कि सोवियत् सरकार की आलोचना इन दलों तथा सस्याओं में बढ़ हो जाती है। वे दल ब्रिटिश सरकार तथा अपनी सरकार की तो आलोचना करते हैं, किंतु सोवियत् सरकार के विरुद्ध अगुली तक नहीं उठाई जाती।

यदि अन्य सस्याओं पर प्रभाव जमाने में सफलता नहीं मिलती तो कम्युनिस्ट दल पूँजीवाद को बुरा-भला कहकर जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने लगता है।

इस प्रकार स्टालिन ने एक गहरी चाल चलकर अपना उल्लू सावा है। कमिटेन को भग कर दिया गया है। यद्यपि विदेशी कम्युनिस्ट दलों का अब सोवियत् सरकार से सम्बन्ध नहीं रह गया है फिर भी उसके लिए उनकी उपयोगिता कहीं अधिक बढ़ गई है। अब रूस को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कम्युनिस्ट दलों द्वारा पहले से कहीं अधिक सहायता मिल सकती है।

युद्ध में सोवियत् रूस को हिटलर को पराजित करने का जो श्रेय प्राप्त हुआ है उसके कारण यूरोप और एशिया के कम्युनिस्ट दलों का कार्य और सरल हो गया है। कम्युनिस्ट और उनके समर्थक रूस के युद्ध-प्रयत्न को ही प्रधान महत्त्व देते रहे हैं। लड़ाई जीतने में ब्रिटेन, अमरीका, चीन तथा अन्य राष्ट्रों ने जो भाग लिया है उनका और उधार पट्टा सहायता का महत्त्व कम्युनिस्ट घटाकर बताते हैं। यूरोप तथा एशिया के देश रूस की सैनिक शक्ति से बड़े प्रभावित हुए हैं और एक सीमा तक उसके प्रशंसक बन गए हैं।

जो देश रूस के सम्पर्क में नहीं आये हैं उनमें यह प्रशंसात्मक भावना अभी तक बनी हुई है। प्रशंसकों में इंग्लैंड, अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका आदि मुख्य हैं। परन्तु केन्द्रीय और पूर्वी यूरोप की जनता की

आखो का पर्दा हट गया है, क्योंकि उसने रूसी सैनिकों को हाथघड़ी चुराते देखा है।

यूरोप लाल सेना के पुराने ढग के साज-सामान को देख चुका है। वह उसकी घोड़े से चलने वाली गाड़ियों और सैनिकों के फटे पुराने कपड़ों को भी देख चुका है।

कोई भी राष्ट्र विदेशी विजेता का स्वागत नहीं करता, किन्तु लाल सेना को मध्य यूरोप में सम्मान की दृष्टि से न देखे जाने का एक और भी कारण है। यूरोप का यह भाग युद्ध के कारण पहले ही तबाह हो चुका था। फिर भी लाल सेना जो अमरीकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी सेनाओं की सम्मिलित शक्ति से अधिक थी, उसी ध्वस्त यूरोप पर अपना निर्वाह करती थी। इसके विपरीत, अमरीकी सेना अपना ही नहीं बल्कि जर्मनों और आस्ट्रियनो तक के लिए अपने देश से भोजन लाती थी। वस मध्य तथा पूर्वी यूरोप के लोगों ने अनुमान लगा लिया कि रूसियों की तुलना में अमरीकी, ब्रिटिश तथा फ्रांसीसियों का रहन-सहन कितना ऊँचा है।

यूरोप वालों ने लाल सेना को देखकर एक और बात मालूम की। पोलैंड और बाल्टिक देशों के निर्वासित लोग ही नहीं, वरन् रूसी नागरिक भी युद्ध समाप्त होने पर रूस को वापस नहीं जाना चाहते थे। अमरीकी, ब्रिटिश तथा फ्रांसीसी सैनिक स्वदेश जाने का अवसर मिलने पर खुशी से पागल-से हो जाते थे, किन्तु रूसी सैनिक अपने प्रचारकों द्वारा चित्रित उस “मजदूरों के स्वर्ग” को लौटने से बचने के लिए कोई प्रयत्न बाकी नहीं छोड़ते थे। माल्टा सम्मेलन में स्टालिन ने सभी रूसी नागरिकों के रूस लौटाने की माँग की थी, जिसे रुजवेल्ट और चर्चिल ने स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार अनिच्छुक रूसियों को स्वदेश वापस जाना पड़ा था। कुछ को जबरन भेजा गया था और कुछ ने विरोध में आत्म-हत्याएँ तक कर ली थी। इसका कुछ-न-कुछ कारण अवश्य था।

लाल सेना के कुछ कार्यों ने यूरोप की जनता को आश्चर्य में डाल दिया। वहाँ के कम्युनिस्ट, समाजवादी तथा अन्य प्रगतिशील वर्ग लाल सेना के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। बर्लिन की श्रमजीवी वस्तियों तथा अन्य नगरों में खिडकियों तथा छज्जों पर लाल झंडे लगाये गए थे। यह भय से प्रेरित होकर नहीं किया गया था, जैसा कि ऐसे अवसरों पर बहुधा हुआ करता है। यह वास्तव में उन लाल सेना के वीरों के स्वागत की तैयारी थी, जो जर्मन नागरिकों को नाज़ियों से मुक्त करने आ रहे थे। परन्तु लाल सेना ने जिस प्रकार अमरीकी के मुहल्लों को तबाह किया उसी प्रकार श्रमजीवियों की वस्तियों में

भी लूट-मार और बलात्कारों का बाजार गरम किया। वर्गवाद तथा अन्तर्राष्ट्रीयता की शिक्षा का स्थान रूस की राष्ट्रीय भावना ने ग्रहण कर लिया था।

इसके अतिरिक्त रूसी सैनिकों ने चोर बाजार से भी खूब जेबें भरी। अन्य देशों के सैनिकों ने भी यही सब किया, किन्तु माल-असबाब के लिए रूसियों की भूख सबसे अधिक बढ़ी हुई थी। इससे यूरोप के उन आदर्शवादियों की आंखें खुल गईं, जो लालसेना में रूस के उस समाजवादी समाज की बानगी देखने की आशा करते थे, उसी समाज की, जो पूँजीवाद को मिटाकर एक "नवीन मनुष्य" की सृष्टि करने का दावा करता आया है।

इसके कुछ ही समय बाद यूरोप ने देखा कि उसके कारखानों, इकानों, खेतों और घरों का सामान ट्रेनों पर लद-लद कर रुम को जा रहा है। भूतपूर्व जन्तु-देशों की ही नहीं, बल्कि पोलैंड, चीन, चेकोस्लोवाकिया और चीन जैसे मित्रदेशों तक की सामग्री का अपहरण किया गया। आस्ट्रिया में रूसियों ने उस सम्पत्ति को हथिया लिया, जो नाजियों ने यहूदियों तथा अपने अन्य जन्तुओं में लूटी थी।

पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रumanिया, बल्गारिया, और युगोस्लाविया में लालसेना के अफसरो ने स्थानीय सेनाएँ तैयार कर लीं। आगपू के भेदियों का जाल सभी जगह फैल गया। रूसी प्रभाव-क्षेत्र की स्थानीय सरकारों के साथ किये समझौतों द्वारा वहाँ की आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। प्रत्येक देश में या तो कम्युनिस्ट दल के हाथ में बाकायदा शक्ति आ गई और या वह परदे के पीछे रहकर कार्रवाई करने लगा।

ऐसा जान पड़ता था जैसे कि आधे यूरोप को, जिसमें लगभग १५ करोड़ प्राणी रहते हैं, रूस ने खरीद लिया है। इस परिस्थिति में सघर्ष बढ़ने की सम्भावना थी और सोवियत् सरकार ने उससे सामना करने की तैयारी भी कर ली।

पहली बात तो उसने यह की कि जर्मनों के रूसी क्षेत्र का सम्बन्ध बाहर से तोड़ दिया। बाद में किसी चुने हुए पत्र-प्रतिनिधि अथवा प्रतिनिधियों को निर्दिष्ट क्षेत्रों में घुमाया गया। विदेशी राजनीतिक अथवा सैनिक प्रतिनिधियों पर रोक लगा दी गई और पत्र-प्रतिनिधियों के विदेशों को जाने वाले तारों पर कड़ा सेसर लगा दिया गया। जिन सरकारों को अपने प्रतिनिधियों से रिपोर्ट मिलती थी वे सोवियत् सरकार की नाराजी के भय से उन्हें दवा देती थी। सरकारें एक दूसरी से अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने की फिक्र में सत्य और न्याय का गला घोटने से नहीं चूकती।

यदि कभी कोई बात निकल पड़ती थी तो उससे दुनिया में एक हंगामा उठ खड़ा होता था। लोगो को खयाल नहीं रहता कि रूस से समाचार बाहर नहीं आने पाते। जब यूनान अथवा इडोनेशिया में कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो समाचारपत्र और रेडियो इसकी खबरे खूब विस्तार से देते हैं। परन्तु जब युगोस्लाविया, पोलैंड अथवा उत्तरी ईरान के सम्बन्ध में कोई असाधारण घटना हो जाती है तो सब चुप रहते हैं। परिणाम यह होता है कि जहाँ यूनान अथवा इडोनेशिया की खबरों का, जिन्हें प्राप्त करने में पत्र-प्रतिनिधियों को कोई कठिनाई नहीं होती, जनता के मस्तिष्क और अंतःकरण पर गहरा प्रभाव होता है वहाँ रूसी प्रभाव-क्षेत्र की परिस्थिति के सम्बन्ध में जनता अज्ञान में रह जाती है। इस अज्ञान को कम्युनिस्ट प्रचारक इस तरह और भी गहरा बना देते हैं कि वे जनता का ध्यान उन देशों से हटाकर, जहाँ रूस की गलती होती है, उन देशों की ओर ले जाते हैं जहाँ ब्रिटेन और अमेरिका की गलती होती है। यही कारण था कि एक समय जहाँ दुनिया का ध्यान सभी तरफ से खिंचकर स्पेन और अर्जेन्टाइना की ओर केन्द्रित हो गया था। वहाँ एशिया तथा यूरोप में रूसी साम्राज्यवादियों की करतूतों का उसे कुछ भी पता न था।

रूसियों का यह पर्दा इतना गहरा है कि उसे भेदकर प्रकाश को एक भी किरण भीतर नहीं पहुँच पाती। इसी पर्दे के पीछे रहकर सोवियत अधिकारी और उनके सहायक उन लोगो का नाम-निशान मिटा रहे हैं, जो तानाशाही और विदेशी शासन के विरुद्ध सिर उठाने की हिम्मत करते हैं। पोलिश अथवा युगोस्लाव सरकारों की सेनाओं तथा उनके तथाकथित शत्रुओं के मध्य होने वाली घमासान लड़ाइयों के समाचार कभी-कभी इस काले पर्दे को फाड़कर निकल पड़ते हैं और कभी-कभी पोलिश अधिकारों द्वारा की जाने वाली हत्याओं की सख्या इतनी अधिक बढ़ जाती है कि अन्य देशों की सरकारों को उसका विरोध करना पड़ता है।

फिर भी लोकतन्त्रवादियों, कम्युनिस्ट-विरोधियों, प्रतिक्रियावादियों और समाजवादियों का सफाया करने की कार्रवाई अबाध रूप से जारी है। अग्रे यूरोप से ऐसे लोगो का नाम-निशान मिटाया जा रहा है, जो पश्चिमी देशों में स्वाधीनता और उन्नति के आन्दोलनों का नेतृत्व करते हैं। पहले तो नाज़ियों ने यूरोप के बुद्धिवादियों तथा निरकुश-शासन-विरोधियों पर सितमड़ाये और जो इस दमन से बच रहे उनका सफाया अब बोलशेविक कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर कम्युनिस्टों ने फ़िन्लैंड से लेकर अल्बानिया तक सभी देशों के गृह-विभागों में रूस में शिक्षा प्राप्त भूतपूर्व कॉमिटर्न कर्मचारियों को मंत्री

बनवा दिया है ताकि गुप्तचर पुलिस का विभाग उन्हीं के नियंत्रण में रहे और उनके द्वारा वे अपनी मनमानी करने में सफल हो सकें।

रूस की तरह रूसी प्रभाव-क्षेत्र में भी कम्युनिस्टों ने पुलिस शक्ति को हथियाने के अतिरिक्त प्रचार द्वारा भी अपना बल बढ़ाया है। कभी-कभी प्रचार पुलिस से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध होता है। वीरो के शरीर तलवारों का सामना कर सकते हैं, किन्तु अधिकांश व्यक्तियों के मस्तिष्क निरंतर किये जाने वाले, एकांगी प्रचार के अनिवार्य प्रभाव से नहीं बच सकते।

रूसी प्रभाव क्षेत्र में सोवियत् सरकार की नीति क्या है? प्रश्न उठता है कि रूस राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण कर रहा है या वह पहले सम्पूर्ण यूरोप को और फिर समस्त एशिया को कम्युनिस्ट बनाने का पड़्यत्र रच रहा है?

इस प्रश्न का उत्तर है कि स्टालिन जैसा कूटनीतिज्ञ सदा एक ही नीति का अनुसरण नहीं करता। एक तो वह स्वभाव से ही परिवर्तनशील है और दूसरे लोगों की आँखों में धूल झाँकने के लिए भी नीति में परिवर्तन किया करता है। एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह कितने ही उपायों को ग्रहण करता है। यदि ये उपाय या साधन परस्पर विरोधी हैं तो और भी अच्छा है। इससे विरोधी विचार वालों का समर्थन प्राप्त हो जाता है और आलोचक दुविधा में पड़ जाते हैं।

सोवियत् सरकार स्लाव जाति वालों से कहती है कि रूस बड़े भाई की तरह उनकी जर्मनों से रक्षा करेगा। सोवियत् प्रचारक नित्य ही इस विरोध को बढ़ाने की चेष्टा करते रहते हैं। इसमें सदेह नहीं कि चेकोस्लोवाक, बल्गेरियन, युगोस्लाव और कितने ही पोल हिटलर से मुक्ति दिलाने के लिए रूसियों के कृतज्ञ हैं। यद्यपि जर्मनों का पतन हो गया है फिर भी उनके फिर से उठ खड़े होने का भय बना हुआ है और इसमें रूसियों का लाभ है। अधिक-से-अधिक यही कहा जा सकता है कि उनके फिर से जर्मनों के चंगुल में फसने की सम्भावना है। यह तो सम्भावना ही है, किन्तु रूसियों का प्रभुत्व तो अभी है—आज की यथार्थता है।

परन्तु फिन्लैंड, बाल्टिक देश, रूमानिया, हंगरी, आस्ट्रिया और अल्बानिया के निवासी तो स्लाव नहीं हैं। पोल स्लाव हैं, किन्तु वे सदा से रूसियों के कट्टर शत्रु रहे हैं। पोल स्लाव और कैथोलिक दोनों ही हैं। इसलिए सभी देशों के स्लावों की एकता का आन्दोलन पूर्वीय यूरोप के टुकड़े-टुकड़े करके ही रहेगा।

स्लावों की एकता के इस आन्दोलन को रूसी पादरियों का समर्थन प्राप्त है। अखिल जर्मन एकता की तरह यह भी एक जातीय और प्रतिक्रियावादी आन्दोलन है। पूर्वयि यूरोप के उदारपथी और समाजवादी इससे घृणा करते हैं। यहूदी भी इसके विरोधी हैं।

अखिल स्लाववाद का परिणाम यह होगा कि पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया वल्गारिया और युगोस्लाविया स्लाव-रूस के उदर में समा जायगे और उनके पृथक् अस्तित्व का सदा के लिए अंत हो जायगा।

स्लाव देशों के भय को दूर करने के लिए रूस ने एक और चाल चली। फरवरी १९४४ में जब लालसेना एस्थोनिया होती हुई पोलैंड की तरफ बढ़ रही थी, सोवियत-संघ के भीतर के सोलहों प्रजातन्त्रों को पृथक् सेनाएँ रखने और विदेशी सम्बन्धों में स्वतन्त्र होने का अधिकार दे दिया गया। इसी आधार पर स्टालिन ने माल्टा में रुजवेल्ट और चर्चिल को यूक्रेन तथा श्वेत रूस के प्रजातन्त्रों को स्वतन्त्र मानने और संयुक्त राष्ट्र में उन्हें अपने पृथक् प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्रदान करने के लिए मजबूर कर दिया। परन्तु वस्तुस्थिति क्या है ?

यूक्रेन, श्वेतरूस, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया अथवा युगोस्लाविया के जो प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में रूस के पक्ष में मत दिया करते हैं उन्हें स्वतन्त्र रूप से कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। सोवियत प्रभाव-क्षेत्र का जो भी अधिकारी सोवियत सरकार का आदेश मानने से इकार करता है उसे रूसी अधिकारी अथवा कम्युनिस्ट अपदस्थ कर देते हैं।

सोवियत सरकार जानती है कि ऐसी परिस्थिति से सम्बन्धित देशों में रूस के विरुद्ध असंतोष बढ़ता है और पश्चिमी राष्ट्रों के प्रति सहानुभूति में वृद्धि होती है। इस सम्भावना का निराकरण करने के लिए कम्युनिस्ट उन देशों के राष्ट्रीय आन्दोलनों में उत्साहपूर्वक सम्मिलित हो जाते हैं। १९४६ में चेकोस्लोवाकिया का दौरा समाप्त करने के उपरान्त मारिस हिडस को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ की प्रत्येक जर्मन वस्तु का बहिष्कार करने में कम्युनिस्ट सबसे आगे हैं—यहाँ तक कि वे वीथोवन और शिलर तक के विरुद्ध हैं। वे प्रत्येक जर्मन को, चाहे वह मजदूर हो अथवा पूँजीपति, सुडेटनलैंड से निकाल बाहर करने के लिए कटिबद्ध हैं। जर्मनी में कम्युनिस्ट जर्मन राष्ट्रीयता के पुजारी हैं। उधर फ्रांसीसी कम्युनिस्ट जर्मनी के विरुद्ध आन्दोलन करते हैं।

यूरोप में शान्ति की स्थापना का क्या यही तरीका है कि चेको में जर्मन-विरोधी भावना की, जर्मनों में जर्मन राष्ट्रीयता की और फ्रांसीसियों में फ्रांसीसी राष्ट्रीयता

की वृद्धि की जाय ? इसी यह चाल इसलिए चल रहे हैं कि जिससे प्रत्येक देश की राष्ट्रीय शक्ति पर वे अधिकार जमा सके और उसे रूस का विरोधी होने में रोक सके । टिटो के ट्रीस्ट पर अधिकार जमाने का समर्थन करने के कारण जब इटली के कम्युनिस्ट दल के अनुयायियों की सन्ध्या घटने लगी तो उसे अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा, क्योंकि सोवियत् सरकार के लिए ट्रीस्ट के प्रश्न पर इटालियन कम्युनिस्टों की सहायता प्राप्त करने की अपेक्षा इटली में एक शक्तिशाली कम्युनिस्ट दल बनाये रखना कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण था ।

रूस ने यूरोप में जिन देशों से उनके प्रदेश छीने हैं उन्हें उनके विर-वाञ्छित अन्य प्रदेश दिलाकर सन्तुष्ट करने का प्रयत्न भी वह करता है । पोलैंड को एक बड़ा जर्मन-प्रदेश देकर खुश किया गया है । युगोस्लाविया यूनानी मेसी-डोनिया और ट्रीस्ट माग रहा है । बल्गारिया टर्की के प्रदेश हड़प जाना चाहता है । नक्शे के इस काया-पलट से रूस का प्रभाव बढ़ना अनिवार्य है । ऐसा करके रूस विभिन्न देशों की भूमि-विस्तार की आकांक्षा को तुष्ट करने का भी ढोंग करता है । तब नया प्रदेश प्राप्त करने वाले राष्ट्र भूल जाते हैं कि रूस उनसे कुछ छीन भी चुका है । इसके प्रतिरिक्त, सीमा सम्बन्धी झगड़ों के कारण प्रत्येक वात्कान राष्ट्र रूस का समर्थन पाने के लिए उनकी खुशामद करने को बाध्य हो जाता है । अतः इसका परिणाम यह होगा कि जहाँ एक तरफ रूस के प्रभुत्व तथा प्रभाव में वृद्धि होगी वहाँ दूसरी तरफ यूरोप तथा निकटपूर्व में त्यागी अशान्ति का बीजारोपण हो जायगा ।

तानाशाहियों की उन्नति के लिए विदेशी नीति की सफलता आवश्यक है । धुरी राष्ट्रों की शक्ति इसी प्रकार बढ़ी थी । हिटलर ने तो इसे सिद्धान्त का रूप दे दिया था । अमरीकी सरकार के हाथ लगे एक गुप्त कागज को देखने से पता चलता है कि जनरल फ्रांको के विदेश-मंत्री मि० सुनेर का बर्लिन में स्वागत करते हुए नाजी डिक्टेटर ने कहा था—“स्पेन को घरेलू क्षेत्र में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनका अतः विदेशी नीति की सफलता से एक दिन में हो सकता है । इतिहास का यही अनुभव है ।”

आर्थिक कठिनाइयों तथा सार्वजनिक असंतोष का सामना करने के लिए तानाशाहियाँ राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहन देती हैं । राष्ट्रीय भावना से अन्य देशों पर आक्रमण करने की प्रवृत्ति को प्रश्रय मिलता है । अन्तर्राष्ट्रीय उत्तेजना का वातावरण उत्पन्न होते ही तानाशाही सरकार जनता से सहायता और समर्थन की अपील करती है और देश की शक्ति बढ़ाने के लिए लोगों से त्याग करने का अनुरोध करती है ।

तानाशाही सरकार अपनी सत्ता कायम रखने और कठिनाइयों को दूर करने के लिए देशभक्ति का राग अलापने लगती है और लोगों को भोजन के स्थान पर बढ़क देती है। तानाशाहियों ने शत्रुओं का खूब विज्ञापन किया है। वे डिक्टेटरो के सबसे बड़े सहायक हैं।

एक डिक्टेटर दूसरे की नकल करता है। मुसोलिनी ने अपने मास्को के दूतावास को आदेश दे रखा था कि स्टालिन के तौर-तरीकों की सूचना उसे नियमित रूप से मिलती रहनी चाहिए। जिस प्रकार इटालियन गला फाड़-फाड़ कर "ड्यूस ! ड्यूस !" चिल्लाते थे और स्पेन के फाशिस्ट "फ्राको ! फ्राको" के नारे लगाते थे उसी प्रकार युगोस्लाविया की जनता अब "टिटो ! टिटो" चिल्लाने लगी है। यह तानाशाह आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में सोवियत रूस का अनुकरण कर रहा है।

तानाशाहियाँ नये देशों में अपने ही यहाँ की प्रणाली जारी कर देती हैं। स्टालिन ९ फरवरी १९४६ को अपने एक भाषण में कह भी चुका है कि सोवियत प्रणाली अन्य सभी प्रणालियों की तुलना में उत्तम है। ऐसी दशा में स्टालिन के लिए अपने प्रभुत्व में आने वाले नये देशों में सोवियत-व्यवस्था कायम करना बिलकुल स्वाभाविक है।

परन्तु सोवियत प्रणाली तुरंत जारी नहीं की जा सकती। किसी देश में वह कितनी शीघ्रता से जारी की जा सकती है यह उस देश की जनता की प्रवृत्तियों तथा राजनीति पर निर्भर रहता है। और ये विभिन्न देशों में विभिन्न होती हैं।

टिटो की शिक्षा-दीक्षा मास्को में हुई थी। उसने युगोस्लाविया में एक दल का शासन स्थापित किया है। वहाँ की पुलिस सर्वशक्तिमान् है और उसका संगठन आगपू के ढंग पर हुआ है। माल्टा में स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट के मध्य हुए सम्झौते के अनुसार टिटो ने अपनी सरकार में राजनीतिक विरोधियों को स्थान तो दिया, किन्तु कुछ ही दिन बाद उन्हें निकाल भी दिया।

अट्वानिया का तानाशाह होक्सा टिटो के पद-चिह्नों का अनुसरण कर रहा है। ऐसा करने में उसे टिटो से सहायता मिलती है।

रेडेस्कू के रूमानियन मन्त्रि-मंडल का पतन सहकारी सोवियत विदेश-मन्त्री एड्रीविशिस्की के हस्तक्षेप से हुआ था, जो विशेष रूप से इसीलिए बुखारेस्ट गया था। फिर विशिस्की ने एक नया मन्त्रि-मंडल स्थापित किया। इसमें जूलियस मेनोयू के किसान-दल को सम्मिलित नहीं किया गया, क्योंकि वह रूस तथा कम्युनिस्टों का विरोधी था। यह रूमानिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल था।

बल्गारिया की सरकार में 'फादरलैड फ्रंट' नामक दल का प्रभुत्व है। इस दल का नेता जार्ज डिमीट्रोव है, जिसे रीखटाग अग्नि-कांड के मामले में स्याति मिल चुकी है। वह कामिटर्न का अधिकारी भी रह चुका है।

आस्ट्रिया तथा हंगरी में लालमेना के प्रवेश के समय वहां के मन्त्रिमंडलों में कम्युनिस्टों की प्रधानता थी, किन्तु जनसाधारण की कम्युनिस्टों से कोई सहानुभूति न थी।

पोलिश सरकार की स्थापना पहले मास्को में हुई थी। कुछ दिन लुवलिन रहने के बाद अंत में वह वारसा आ गई। सरकार में कम्युनिस्टों की प्रधानता थी। पहले उसने किसान दल के नेता मिकोलाजेव्स्की को नहीं लिया गया था, जो एक समय निर्वासित पोलिश सरकार का प्रधानमंत्री रह चुका था। बाद में पश्चिमी राष्ट्रों के जोर देने पर उसे वारसा में स्थापित सरकार में सम्मिलित कर लिया गया। यह व्यक्ति राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से पोलिश नेताओं में सबसे बड़का है, किन्तु राजनीतिक शक्ति उसके हाथों में अधिक नहीं है।

फिन्लैंड की सरकार पर कम्युनिस्ट जबरन थोपे गए। इस सरकार को युद्ध के लिए रूस को हरजाना देना पड़ा। सोवियत सरकार के आदेश से रूस से युद्ध छेड़ने के प्रपराध में कितने ही फिनिश अफसरो को दंड दिया गया। परन्तु सोवियत प्रभाव-क्षेत्र के अधिकांश देशों की तुलना में फिन्लैंड को अधिक स्वाधीनता का उपभोग करने दिया गया।

एस्थोनिया, लटविया और लिथुआनिया के मन्त्रिमंडलों का संगठन विशुद्ध सोवियत ढंग पर किया गया है।

रूस के प्रभाव-क्षेत्र में जितने भी राष्ट्र हैं उनमें सबसे अधिक स्वतंत्रता तथा लोकतंत्रवाद चेकोस्लोवाकिया को प्राप्त है। परन्तु वहां भी कम्युनिस्ट अपनी सख्या से कहीं अधिक प्रभाव रखते हैं।

जर्मनी के रूसी क्षेत्र में स्थानीय शासन कम्युनिस्टों के ही हाथों में है और इन सब-के-सब कम्युनिस्टों को मास्को में शिक्षा मिल चुकी है।

स्टालिन का पहला कार्य नये रूसी साम्राज्य में कम्युनिस्टों को भेजना था। इससे स्टालिन को शक्ति प्राप्त होती है और बाद में शक्ति बढ़ने पर कम्युनिस्ट अपने सिद्धान्तों को कार्यान्वित भी कर सकते हैं।

ये कम्युनिस्ट अथवा कम्युनिस्ट प्रधान सरकारें इन देशों की जनता की विचार-धारा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। इसका कोई भी सबूत नहीं है कि उनकी जनता समाजवाद में विश्वास करने लगी है। जहां भी स्वतन्त्र चुनाव

हुए—जैसे आस्ट्रिया और हंगरी में—वही कम्युनिस्टों की शक्ति सबसे कम दिखाई पड़ी। इन चुनावों में एक प्रकार से रूस के विरुद्ध स्पष्ट मत प्रकट किया गया। यद्यपि जनता ने अपने यहां के कम्युनिस्टों के विरुद्ध मत दिये, किन्तु ऐसा करके उसने रूस के प्रभुत्व के विरुद्ध अपना निर्णय दिया। फिर भी लाल-सेना अपना नियंत्रण उन देशों में बनाये रही। हंगरी के चुनाव में कम्युनिस्टों को केवल थोड़े-से मत मिले थे, किन्तु सोवियत सरकार के प्रभाव से उन्हें मंत्रिमंडल में सबसे महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो गए।

रूस के प्रभाव क्षेत्र में कम्युनिस्टों को बहुमत प्राप्त न था, फिर भी उनको अथवा उनसे प्रभावित सरकारों को तानाशाही उपायो, गुप्त पुलिसों तथा रूसी सगिनो के जोर से कायम रखा गया।

इस प्रकार सोवियत रूस की शक्ति बढ़ने से ससार में तानाशाही के क्षेत्र का विस्तार हो गया है। तानाशाही का प्रथम कार्य उन लोगों को गोली मारना, कैद करना, निर्वासित करना अथवा उन्हें अपने दमन के शिकजे में कसना होता है, जो आदर्श सम्बन्धी, राष्ट्रीय, धार्मिक, राजनीतिक, वर्गीय, आर्थिक अथवा अन्य किसी भी कारण से उसे अपदस्थ करने की चेष्टा कर सकते हैं। तानाशाही के विरुद्ध संघर्ष जारी है और रहेगा, किन्तु मध्य तथा पूर्वी यूरोप भर में सोवियत-सरकार की सर्वोपरि शक्ति राजनीतिक स्वाधीनता का गला घोट सकती है।

परन्तु तुरत सवाल उठाया जा सकता है कि मध्य तथा पूर्वी यूरोप में स्वाधीनता कभी रही भी है? वहां तो सदा से ही सामतवाद का दौर-दौरा रहा है।

इस प्रकार की बात अज्ञान अथवा बौद्धिक खोखलेपन के कारण कही जाती है। युद्ध से पूर्व वहां स्वाधीनता अपूर्ण थी। निर्धनता के कारण लोग लोकतन्त्रवाद का विकास नहीं कर पाए थे। इन देशों में सर्वत्र ही जातीय शत्रुता, घूमखोरी, राजनीतिज्ञों की अकुशलता, पुलिस के अत्याचार, जमींदारों, अमीरों और राजाओं का बोल-वाला था। परन्तु इन सभी में, जहां, आज कम्युनिस्ट शासन करते हैं, पहले विरोधी दल थे। हंगरी का समाजवादी दल नाजी-विरोधी था और भूमि-प्रणाली में सुधार का पक्षपाती था। कुछ देशों में विरोधी दल के हाथ में कुछ भी शक्ति न थी और उसे दमन का शिकार बनना पड़ता था। परन्तु कम-से-कम वह पार्लमेंट में चित्तपोषण कर अपना पक्ष तो उपस्थित कर ही सकता था। इस सभी देशों में विरोधी दल के पत्र थे, जो सरकार की आलोचना करने से नहीं चूकते थे। मजदूर सभाएं थी और हड़तालें

की जा सकती थी। लोग देश के बाहर जा सकते थे और बाहर से देश में वापस आ सकते थे। विदेशी लोग सम्पूर्ण प्रदेश में खुशी में घूम-फिर सकते थे। विदेशी पत्र और पुस्तकें अभाव रूप से आ सकती थी। नागरिक विदेशी रेडियो सुन सकते थे।

युद्ध से पूर्व पोलैंड, टमोनिया तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देशों की सरकारों की में अक्सर आलोचना किया करता था। निश्चय ही प्रगतिशील और समाजवादी वर्गों की इच्छा यही थी कि युद्ध के उपरान्त पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतन्त्रवाद का अधिक विकास हो, न कि यह कि वे स्टालिनवाद के शिकार बन बैठें।

उन लोकतन्त्रवादियों तथा उदार राजनीतिज्ञों की बात मेरी समझ में नहीं आती, जो लोकतन्त्रवाद के दमन से खुश हैं और लोकतन्त्रवादियों के विनाश का प्रतिवाद नहीं करते।

अन्य कितने ही लोगों की तरह मैं भी भारतीय स्वाधीनता का समर्थन रहा हूँ। साम्राज्यवाद एक प्रकार की तानाशाही है और मैं उससे घृणा करता हूँ। हिन्दुस्तान की अंग्रेजी हुकूमत ऐसे हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिन्होंने कोई नियम भंग नहीं किया है और उन्हें बरसों तक जेल में रखती है। अनेक बार गिरफ्तार व्यक्तियों पर मुरुदमे तक नहीं चलाये जाते। ब्रिटेन के जगी वायुयानों ने आसमान से हिन्दुस्तान के गांवों पर मशीनगनों द्वारा गोलियों की वर्षा की है। ये कार्य १९४२ के राजनीतिक उपद्रवों के समय हुए हैं। परन्तु साधारण वर्षों में भारतीय समाचारपत्र और राजनीतिक दल अंग्रेजों की नीति तथा अंग्रेजों के अफसरों के विरुद्ध ज़्वाली ज़िहाद-सा जारी रखते हैं। सरकार का विरोध करने के लिए सगठन होने दिया जाता है। यह एक पराधीन देश की स्वतन्त्रता है। स्थिति असंतोषजनक है, किन्तु यह एक ऐसी स्वाधीनता है, जिसका रूस अथवा रूसी प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में अभाव है। रूसी जहाँ भी जाते हैं, अपनी प्रणाली को साथ ले जाते हैं। उनके साथ जो सबसे प्रधान वस्तु अन्य देशों में पहुँचती है, वह दमन है। रूस इस बात की शक्ती बघारता है कि उसने मध्य तथा पूर्वी यूरोप से सामन्तवाद की जड़ें खोद दी हैं। परन्तु साथ ही उसने एक ऐसी राजनीतिक तथा बौद्धिक गुलामी को जन्म दिया है, जो कम-से-कम उतनी ही बुरी है।

परन्तु स्टालिन ने अपनी दूरदर्शिता के कारण यह अवश्य अनुभव किया है कि यदि कम्युनिस्ट लोग स्थानीय जनता का समर्थन नहीं प्राप्त करते तो आगे जाकर एक दिन रूसियों के लिए अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्र में बने रहना

असम्भव हो जायगा। यही कारण है कि उन्होंने मध्य तथा पूर्वी यूरोप में बड़े व्यवसायो का राष्ट्रीयकरण और बड़ी जमीदारियों का वटवारा आरम्भ कर दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि जहाँ एकतरफ पूँजीपतियों और जमींदारों के हाथों से आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति जाती रही है, वहाँ दूसरीतरफ जिन किसानों और मजदूरों को जमीनें मिली हैं वे रूसियों का आभार मानने लगे हैं।

यूरोप के बहुत से भागों में निर्धन किसानों के हित-साधन के लिए भूमि-प्रणाली के सुधार और वहाँ के अमीर और विलासी जमींदारों के खात्मे की बहुत अधिक आवश्यकता थी। परन्तु रूसियों ने भूमि-प्रणाली का जो सुधार किया उसका लोगो ने बहुत ही अतिरजित वर्णन किया है। इनमें से कुछ तो मेरे मित्रों ने ही उन देशों के सम्बन्ध में 'दि नेशन' में लेख लिखे हैं, जिनका उन्हें ज्ञान नहीं है। बोलशेविक क्रांति से प्रेरणा प्राप्त करके फिन्लैंड, तीनो बाल्टिक राज्य, पोलैंड, रूमानिया, बल्गारिया, युगोस्लाविया और चेकोस्लोवाकिया में भूमि-प्रणाली का सुधार पहले ही हो चुका था—यह सुधार होथी के हंगरी और जर्मनी में नहीं हुआ था। भूमि-प्रणाली में सुधार न होना भी लोकतन्त्रवादी जर्मनी के पतन का एक कारण था।

फिन्लैंड, बाल्टिक राज्य, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया ऐसे छोटे किसानों के राज्य हैं, जो खेतों के स्वयं स्वामी हैं। कुछ जमींदारियां रह गईं, किन्तु देश की आर्थिक व्यवस्था में उनका कुछ भी महत्त्व नहीं रह गया। रूमानिया और पोलैंड में बची हुई जमींदारियों की संख्या अधिक थी। किन्तु इस पोलैंड में भी कर्जान पद्धति से पूर्व, अर्थात् पोलैंड के रूस द्वारा लिये गए भाग में, युद्ध से पूर्व ही ८० प्रतिशत भाग किसानों के बीच विभाजित किया जा चुका था।

किसी देश में लालसेना के पदार्पण करते ही स्थानीय परिस्थितियों का ध्यान रखे बिना ही भूमि-प्रणाली में सुधार का कार्य आरम्भ कर दिया जाता है। पोलैंड, रूमानिया और हंगरी में इसका तात्कालिक परिणाम खाद्य की कमी तथा जनता के कष्टों की वृद्धि के रूप में दिखाई दिया। जिस प्रकार रूस में मिली-जुली खेती की प्रणाली शुरू करते समय सोवियत अधिकारियों ने जनता के कष्टों की तरफ ध्यान नहीं दिया, वही अन्य देशों में हुआ।

पोलैंड में जिन किसानों को भूमि-प्रणाली के सुधार से लाभ हुआ उन्हें अधिक-से-अधिक ८ एकड़ और कुछ को इतनी कम कि ५ एकड़ भूमि मिली। इसका परिणाम यह होगा कि वे अपनी माली हालत कभी सुधार न सकेंगे और या हताश होकर उन्हें पूर्वी जर्मनी के हाल में प्राप्त प्रान्तों में चले जाना पड़ेगा।

रूस की दुहाई देने वाली लेखिका अन्ना लुइसी स्ट्रॉंग ने ३ फरवरी

१९४५ के “नेशन” में पोलैंड की भूमि-प्रणाली के सुधार के सम्बन्ध में लिखा था—“इस प्रकार ९ लाख एकड़ भूमि को, जिस पर पहले १०००५ परिवारों का अधिकार था, १ लाख परिवारों के बीच बांट दिया गया।” पर इससे प्रत्येक परिवार के हिस्से में ८ एकड़ भूमि ही आती है।

५ दिसम्बर १९३५ को पोलिश ग्रंथ-मंत्री क्वीग्रारकोवस्की ने देश का पार्लमेन्ट को बताया था कि जिन किसानों के पास २५ एकड़ भूमि है वे औसतन ८ डालर वार्षिक कमाते हैं। परन्तु उन्हें उन किसानों की तुलना में लक्ष-पति कहा जा सकता है, जिनके पास केवल १० या १२ करोड़ भूमि है। इनका अनुपात कुल जनसंख्या में ३१ प्रतिशत है। अन्य ३४ प्रतिशत किसानों के पास इससे छोटे खेत हैं। १ करोड़ के लगभग किसानों का देश के आर्थिक जीवन में कुछ स्थान ही नहीं है, क्योंकि उनके पास ८ एकड़ या इससे कुछ ही अधिक भूमि है। उन्हें इतनी कम आय होती है कि वे शहर का कोई भी सामान नहीं खरीद सकते।

फिर युद्ध के मध्य ही भूमि-प्रणाली में सुधार की क्या आवश्यकता उत्पन्न हो गई। अन्ना लुइसी स्ट्राग ने इसके कई कारण बताये हैं। उसने लिखा था—“भूमि-प्रणाली में सुधार से पोलिश सेना के लिए केवल जवान ही अधिक संख्या में नहीं मिलते हैं बल्कि इससे लाखों पोलिश किसानों में पूर्वी प्रशा तथा बोमेरानियन प्रदेशों को प्राप्त करने की इच्छा में भी वृद्धि होती है, क्योंकि इन नये प्रदेशों के मिलने पर ही प्रत्येक किसान को १२ एकड़ भूमि मिल सकती है।” आठ एकड़ भूमि मिलने पर प्रत्येक पोलिश किसान १२ एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिए जर्मनी से लड़ने को तैयार हो जाता है।

निर्धन देशों में थोड़ी भूमि पर खेती को प्रोत्साहन देने से न तो किसानों का रहन-सहन ऊँचा हो सकता है और न देश की आर्थिक उन्नति ही सम्भव है।

मध्य और पूर्वी यूरोप में स्टालिन ने भूमि-प्रणाली में सुधार की जा चाल चली है उससे इस विस्तृत भू-खंड की आर्थिक समस्या हल नहीं हो सकती। मुख्य समस्या उद्योग-धंधों तथा पूँजी का अभाव है। इस क्षेत्र में रूस विवश है। रूस अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्र के तैयार माल की ऐसी बड़ी मंडी बन सकता है, जिसकी माँग शायद ही कभी पूरी हो सके। रूस उन देशों के कारखानों के लिए कुछ कच्चा माल दे सकता है; जिस तरह उसने पोलैंड को कपास दी भी है। परन्तु कितने ही वर्षों तक—शायद १५ वर्ष तक—रूस को अपने ही यहाँ भोजन, निवास-स्थान, कपड़ा, मशीनी औजार तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करना है। इसलिए वह अन्य देशों को ये चीजें दे नहीं सकता। उसे तो अन्य देशों से माल मगाने की ही ज़रूरत पड़ेगी। वह आस्ट्रिया,

हंगरी, रूमानिया और पोलैंड से तेल, रूमानिया से अनाज, हंगरी से मांस और चेकोस्लोवाकिया से साधारण उपयोग में आने वाली वस्तुएँ लेगा।

इस प्रकार स्पष्ट है कि रूस के प्रभुत्व में रहने वाले देशों को अमरीका और ब्रिटेन की आर्थिक सहायता पर निर्भर रहना पड़ेगा। इस सहायता के बिना न तो उनकी आर्थिक अवस्था में सुधार हो सकता है और न राजनीतिक स्थिरता हो सकती है। अमेरिका और इंग्लैंड का रूसी क्षेत्र में प्रवेश इन देशों से सोवियत सरकार की सधि के परिणामस्वरूप ही हो सकता है।

रूस न तो मध्य तथा पूर्वी यूरोप की आर्थिक समस्या का हल कर सकता है और न राष्ट्रीयता के सवाल का ही। हिटलर के सकुचित जातिवाद, रूस की नीति और अखिल स्लाववाद के परिणामस्वरूप प्रायः प्रत्येक देश में राष्ट्रीयता की लहर जगी हुई है। इस क्षेत्र में चेक सबसे सुसंस्कृत हैं और ये अपने प्रदेश से जर्मनों तथा हंगेरियनों को निकाल रहे हैं। चेकोस्लाविया और पोलैंड के सीमा सम्बन्धी झगड़े अभी बने हुए हैं। धुरी राष्ट्रों ने हंगेरियनों को ट्रान्सिल्वानिया प्रदेश देकर अपनी तरफ फोड़ा था। बाद में वही प्रदेश रूमानिया को देकर स्टालिन ने रूमानियनों को अपनी तरफ से लड़ने को राजी कर लिया, परन्तु ट्रान्सिल्वानिया में हंगेरियन और रूमानियन दोनों ही हैं, इसलिए नई व्यवस्था में हंगेरियन असंतुष्ट हैं। युद्ध के दिनों में युगोस्लाविया में क्रोटो ने सरवो की सामूहिक हत्या की थी। टिटो ने “न्यूयार्क फ्रीवर्ल्ड” पत्रिका के एक विशेष लेख में लिखा था—“जर्मनों के उकसाने पर क्रोटो ने लाखों सरवो को मौत के घाट उतार दिया था। उधर मिहैलोविच के चेटनिकों ने जर्मनों तथा इटालियनों द्वारा भडकाये जाने पर लाखों क्रोटो का यही हाल किया था..... हमने चेटनिकों, और चेटनिकी सरवो को यह विश्वास दिलाने में कोई प्रयत्न वाकी नहीं छोड़ा कि सभी क्रोट वदमाश नहीं होते।” प्रश्न यह है कि सरवो को विश्वास हुआ या नहीं? सरवो ने क्रोटों को क्षमा नहीं किया। क्रोट होने के कारण टिटो से और उसके हिमायती रूस तक से सरव नाराज है। युगोस्लाविया में सरवो का अनुपात जनसंख्या में आधा है। इसी प्रकार क्रोटो द्वारा सरवो को माफ किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है। सरवो के विरुद्ध क्रोटो की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए रूस युगोस्लाविया से बल्गारिया और भेसीडोनिया को मिलाकर एक सघ कायम करना चाहता है। इस सघ में सरवो की सत्ता अपने विरोधियों की अपेक्षा कम रह जायगी। परन्तु इससे राष्ट्रीय कठिनाइयों का अंत नहीं होगा, इनसे तो संघर्ष तथा दमन का ही द्वार खुलेगा।

सीमाओं के उलट-फेर, विशाल जन-समूहों के निर्वासन अथवा अन्य किसी

भी तरीके से राष्ट्रों अथवा उपराष्ट्रों की ये समस्याएँ हल नहीं हो सकती। इन्हें हल करने का एक-मात्र उपाय अन्तर्राष्ट्रीयता है। परन्तु सोवियत् सरकार राष्ट्रीयता के पथ पर अग्रसर हो रही है और दूसरों से भी ऐसा ही करने को कह रही है। इसलिए मध्य तथा पूर्वी यूरोप के राष्ट्रों के लिए तीन ही रास्ते हैं—(१) राष्ट्रीय कटुता और सघर्ष जारी रहे, या (२) यूरोपीय राष्ट्रों को मिलाकर एक संयुक्त सघर्ष की स्थापना हो अथवा (३) ये राष्ट्र सोवियत् मंच में सम्मिलित कर लिये जाय।

पूर्वी यूरोप, जर्मनी और एशिया में सोवियत् सरकार को एक ऐसा दल चाहिए, जो उसके अपने स्वार्थ को इन क्षेत्रों में अग्रसर कर सके। कम्युनिस्ट दल इस कार्य में असफल रहा है, क्योंकि उसके प्रनुयायियों की मर्यादित नहीं रही है। सोवियत् अधिकारियों ने परिस्थिति का सामना करने के लिए तरह-तरह के उपाय किये हैं। बल्गारिया में राष्ट्रवादियों को फुसलाने के लिए उन्होंने “फादरलैंड-फूट” खोला है। ईरान में उन्होंने डेमोक्रेटिक (लोकतंत्री) दल को जन्म दिया है। एक अन्य देश में उन्होंने पीपल्स (जनता का) दल स्थापित किया है।

इस तरह स्पष्ट है कि सोवियत् सरकार की चाल कम्युनिस्ट दलों को यूरोप के अन्य लोकप्रिय लोकतन्त्रवादी अथवा समाजवादी दलों में मिला देने की है। उसे आशा है कि सहायता करने पर कम्युनिस्ट अधिक लोकप्रिय दलों पर अधिकार जमा सकेंगे और इस प्रकार रूस को अपने स्वार्थ-साधन का अवसर मिल सकेगा।

कम्युनिस्टों और समाजवादियों का झगडा आज का नहीं है। यह उस समय का है, जब स्वयं रूस में ही दो दल थे। एक था बोलशेविकों का, जो हिंसा द्वारा निम्नवर्ग की सत्ता स्थापित करना चाहते थे। दूसरा दल था मेशेविकों का, जो समाजवाद-युक्त लोकतन्त्रवाद के समर्थक थे और हिंसा के विरोधी थे। जर्मनी में इसी झगड़े के कारण मजदूरों में फूट पड़ गई और हिटलर के लिए रास्ता साफ हो गया। कभी-कभी कम्युनिस्ट पार्लमेन्ट में नाज़ियों का भी समर्थन करते थे। उनका खयाल था कि वे इसी प्रकार अपनी शक्ति में वृद्धि कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने सामाजिक लोकतन्त्रवादियों का विरोध किया। इससे नाज़ियों को लाभ हुआ और उन्होंने दोनों ही का खात्मा कर दिया।

जर्मनी के सामाजिक लोकतन्त्रवादी नरम विचारों के थे। १९१८ में उन्हें देश की सामाजिक व्यवस्था बदलने और सैनिक वर्ग तथा पूँजीपतियों के निराकरण करने का अवसर मिला। परन्तु उन्होंने आधारभूत सुधार करने का साहस

कभी नहीं किया। अतः मे शक्ति उनके शत्रुओं के हाथ में चली गई।

इस प्रकार जर्मनी के दोनों ही श्रमजीवी दलों ने अपने कर्तव्य का ठीक तरह पालन नहीं किया।

१९३५ में नाजियों की शक्ति से भयभीत होकर सोवियत् सरकार लोकतन्त्रवादी देशों से मैत्री बढ़ाने की आवश्यकता का अनुभव करने लगी और उसने अन्य देशों के कम्युनिस्टों को सामाजिक लोकतन्त्रवादियों से सम्पर्क बढ़ाने का आदेश दिया। तब कम्युनिस्टों ने उन्हीं सामाजिक लोकतन्त्रवादियों के साथ काम करना स्वीकार किया, जिन्हें पहले वे "सामाजिक फाशिस्ट" कहते थे।

स्पेन में केटेलोनिया के सामाजिक लोकतन्त्रवादियों और कम्युनिस्टों ने मिलकर एक गुट बनाया और यह गुट कार्मिटरन में सम्मिलित हो गया। स्पेन के समाजवादी तथा कम्युनिस्ट युवक-संगठनों ने मिलकर एक संयुक्त संस्था बनाई और इसने क्रमशः विशुद्ध कम्युनिस्ट दल का रूप ग्रहण कर लिया।

सोवियत्-सरकार यही तो चाहती थी। कार्मिटरन के नेता डिमिट्रोव ने मुझे मई, १९३८ में बताया कि वह प्रत्येक देश में कम्युनिस्ट और समाजवादी दलों की एकता चाहता है। उसने यह भी कहा कि अन्त में यह समाजवादी-कम्युनिस्ट संगठन कार्मिटरन का स्थान ग्रहण कर लेगा।

इस प्रकार कार्मिटरन भग किये जाने का विचार डिमिट्रोव के मस्तिष्क में १९३८ में ही था। उसका यह भी खयाल था कि इस संयुक्त संगठन में कम्युनिस्टों का प्रभुत्व रहेगा। अब सोवियत् सरकार तथा कम्युनिस्टों की यही नीति है।

यूरोप के कम्युनिस्ट दलों ने सामाजिक लोकतन्त्रवादी शक्तियों से एकता स्थापित करने के लिए कोई भी प्रयत्न शेष नहीं छोड़ा है। इससे उस दल के पृथक् अस्तित्व का अंत हो जायगा, जिसे श्रमजीवियों का समर्थन कम्युनिस्टों की अपेक्षा अधिक मात्रा में मिलता रहा है। इससे कम्युनिस्टों को श्रमजीवियों के संयुक्त संगठन को चलाने का अवसर मिल जायगा। कितने ही देशों में ऐसी पार्टी या तो सरकार बनाकर शासन करेगी और या सरकार पर निर्णयात्मक प्रभाव डालेगी।

जर्मनी के रूसी क्षेत्र और बर्लिन में लालसेना के अफसरों ने सामाजिक लोकतन्त्रवादियों को कम्युनिस्टों से मिलकर कार्य करने का आदेश दे दिया है। अधिकांश सामाजिक लोकतन्त्रवादी इस आदर्श को मान लेते हैं और जो नहीं मानते उन्हें साइबेरिया भेज दिया जाता है। अन्य कुछ अमरीकी तथा ब्रिटिश सेना की सहायता से पश्चिमी जर्मनी को भाग गए हैं।

सोवियत् सरकार को विश्वास है कि यदि श्रमजीवियों के एक-मात्र सगठन में और मजदूर सभाओं में कम्युनिस्टों का बोल-वाला बना रहे तो रूस स्थानीय राजनीतियों की मदद से अपने प्रभाव-क्षेत्र के शासन का संचालन कर सकता है। इस हालत में लालसेना का अधिकार भी स्थानीय जनता को कम खलेगा। यदि जर्मनी के अमरीकी, ब्रिटिश और फ्रांसीसी क्षेत्रों में भी समाजवादियों का जोर बना रह सके तो कम्युनिस्ट और समाजवादियों का मास्को से नियंत्रित संयुक्त दल जर्मनी भर में रूस की सत्ता स्थापित कर सकता है। इस प्रकार सोवियत्-सरकार ने “जर्मनी का क्या होगा?” प्रश्न का उत्तर दिया है।

जहां तक पूंजीवाद और फाशिज्म के विरोध का सम्बन्ध है, समाजवादियों और कम्युनिस्टों में कोई मतभेद नहीं हो सकता। परन्तु लोकतन्त्रवाद के विषय में उनका सैद्धान्तिक मतभेद है। यह उनके मध्य एक गहरी खाई है। समाजवादी लोग ऐसा समाजवाद चाहते हैं, जो लोकतन्त्रवाद के साथ हो। और कम्युनिस्ट? उनके लक्ष्य की व्याख्या प्रसिद्ध जर्मन कम्युनिस्ट-नेता विल्हेम लापीक अपने २१ फरवरी, १९४६ के उस भाषण में कर चुका है, जो उसने समाजवादियों तथा कम्युनिस्टों की एकता के समर्थन में बर्लिन में हुए एक प्रदर्शन के अवसर पर दिया था। उसने कहा था—“हमारा लक्ष्य सदा वही सच्चा समाजवाद रहेगा, जिसकी सफलता सोवियत् रूस में दिखाई देती है।”

कम्युनिस्टों की मातृभूमि रूस है। इसीलिए जर्मन के सामाजिक लोकतन्त्रवादियों ने खुले शब्दों में जर्मन कम्युनिस्टों से प्रश्न किया है कि उनका दल रूसी है या जर्मन? एक तरफ कम्युनिस्टों का रूसी सरकार से गहरा सम्बन्ध बना हुआ है और दूसरी तरफ समाजवादी लोकतन्त्रवाद की ओर झुके हुए हैं। इन विरोधी प्रवृत्तियों के कारण ही श्रमजीवियों के संयुक्त सगठन का काम रुका हुआ है। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक प्रतिक्रिया, राजतन्त्रवाद, पादरियों की गुलामी और फाशिज्म का पूर्ण रूप से विनाश नहीं हो सकता।

कुछ समाजवादियों का कम्युनिस्टों से मिलने की ओर झुकाव रहा है। रूसियों के प्रभाव-क्षेत्र के बाहर के देशों में यह प्रवृत्ति सोवियत् सरकार के दबाव के कारण नहीं है। वहां यह प्रवृत्ति मुख्यतः अपरिवर्तनवादियों का बल बढ़ने के कारण उत्पन्न होती है। जब अपरिवर्तनवादियों के हाथ में शक्ति चली जाती है या जाने लगती है तो वामपक्षी अपने मतभेद भूलकर एकता के सूत्र में बंधने लगते हैं।

यही कारण है कि मजदूर-दल द्वारा चर्चिल को पराजित करने से स्टालिन

प्रसन्न नहीं हुआ। चर्चिल के कट्टरपथीपन और नरेशों से सहानुभूति के कारण स्टालिन अपनी शक्ति बढ़ने की आशा कर सकता था। चर्चिल के हाथ में शक्ति बनी रहने की अवस्था में ही कम्युनिस्ट लोग श्रमजीवियों, समाजवादियों और उदारपथियों से एकता की अपील कर सकते थे। परन्तु हुआ यह कि ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार स्थापित होते ही लास्की ने यूरोप के अन्य देशों के समाजवादियों को कम्युनिस्टों से न मिलने की सलाह दी। समाजवादियों में कम्युनिस्टों के प्रति घृणा की भावना पहले ही थी, लास्की की सलाह से वह और भी पुष्ट हो गई। परन्तु भविष्य में कम्युनिस्ट दल समाजवादियों के आक्रमण से मुक्त केवल उसी अवस्था में रह सकता है जब कि यूरोप रूढ़िवादियों से मुक्त रहे। मध्यमश्रेणी तथा पेशेवर लोगों को युद्ध-काल में बहुत कष्ट मिला है और राजनीति में उनकी दिलचस्पी भी बहुत कुछ घट गई है। युद्ध से पूर्व फ्रांस में और हिटलर से पूर्व जर्मनी में समाजवादी लोग रूढ़िवादियों का बल बढ़ने पर मध्यम श्रेणी तथा उदारपथियों की तरफ झुकते थे। इधर उदारपथियों की शक्ति घटने पर समाजवादी दल रूढ़िवादियों से लोहा लेने के लिए अब केवल कम्युनिस्टों के समर्थन पर ही निर्भर रह सकता है।

इस प्रकार रूढ़िवादियों का बल बढ़ने पर समाजवादियों और कम्युनिस्टों की एकता को प्रोत्साहन मिलता है। इससे पश्चिम के लोकतन्त्री राष्ट्रों का बल घटता है और सोवियत सरकार को प्रसन्नता होती है। फाशिस्टों, प्रतिक्रियावादियों और राजतन्त्रवादियों की शक्ति घटने पर समाजवादी वर्ग कम्युनिस्टों को घटा बताने में समर्थ हो जाते हैं। तब वे कम्युनिस्ट तानाशाही से अपना बचाव कर सकते हैं।

इसलिए ब्रिटेन की मजदूर सरकार को समाजवादियों के सम्मेलनों में लास्की जैसे वक्ताओं को भेजकर ही सन्तुष्ट न हो जाना चाहिए। उसे यूरोप में उदार तथा लोकतन्त्रीय प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए। स्पेन में फ्रांको, पुर्तगाल में सालाजार, हंगरी में राजतन्त्रवादी, आस्ट्रिया में जमींदार, जर्मनी में उद्योगपति और इटली के बचे-खुचे फाशिस्ट—ये सब समाजवादियों में कम्युनिस्टों की ओर झुकने की प्रवृत्ति उत्पन्न करते हैं।

प्रश्न उठता है कि कम्युनिस्ट लोग समाजवादियों का कार्यक्रम क्यों नहीं स्वीकार करते? कारण यह है कि कम्युनिस्ट दल में अनुशासन कड़ा है और उसका मुख्य कर्तव्य रूस के हितों को अग्रसर करना है; यदि कम्युनिस्ट दल का कोई नेता एक नीति ग्रहण करता है और मास्को से आदेश मिलने पर उसमें परिवर्तन करने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है तो उसे “पूँजी-

वादियों का गुलाम" कहकर बदनाम किया जाता है। कम्युनिस्ट-नेता में विचार-स्वातंत्र्य की भावना जहाँ एक बार देखी गई, वस उसे "ट्राट्स्की का अनुयायी" या "फाशिस्ट" कहा गया। इसलिए कोई भी कम्युनिस्ट दल सोवियत् सरकार की नीति के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। जब कम्युनिस्ट "लोकतन्त्रवाद" की बातें करते हैं तो उनका मतलब "सोवियत् लोकतन्त्रवाद" से होता है, जिसके आवश्यक अंग गुप्त पुलिस, एक ही दल और एक ही डिक्टेटर हैं। कम्युनिस्ट को "तानाशाही लोकतन्त्रवादी" कहा जा सकता है।

यदि कम्युनिस्टों को सामाजिक-लोकतन्त्रवादियों का सहयोग प्राप्त हो गया तो यूरोप से लोकतन्त्रवाद और ब्रिटेन के प्रभाव का खात्मा हो जायगा और रूस के प्रभुत्व की पुष्टि हो जायगी। हिटलर के साथ केवल पशु-बल या। स्टालिन को राजनीति का भी बल प्राप्त है।

रूसी और ब्रिटिश साम्राज्य का पुराना मघर्ष अब नये सिरे से शुरू हो गया है और उसके विस्तार में वृद्धि भी हो गई है। पहले वह एशिया तथा पूर्वी यूरोप तक ही सीमित था। अब वह यूरोप के प्रत्येक कोने और एशिया के सभी भागों में फैल गया है। ससार के अधिक दूर के भागों तक उसका प्रभाव फैला हुआ है। नये हथियारों को काम में लाया जा रहा है। जारों के शस्त्रागार में अखिल स्लाववाद, ईसाइयों का यूनानी सम्प्रदाय, कूटनीतिज्ञ, गुप्तचर और सेना के शस्त्रास्त्र थे। बोलशेविकों के पास ये सब तो हैं ही, किन्तु इनके अतिरिक्त सभी देशों में उनके क्रियाशील राजनीतिक दल फैले हुए हैं, कम्युनिज्म का आकर्षक सिद्धान्त साम्राज्य-विरोधी नारा है। जहाँ जारों ने सेनाओं के जोर से दो बार भारत को विजय करने का असफल प्रयत्न किया, वहाँ सोवियत् सरकार ने समस्त उपनिवेशों की जनता से अपनी पराधीनता की जजीरे तोड़ फेंकने की अपील की है।

इसके अतिरिक्त, १९वीं शताब्दी की अपेक्षा ब्रिटेन कमजोर और रूस शक्तिशाली होगया है। तेहरान और बाल्टा में शान्ति की जो व्यवस्था स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट ने मिलकर तैयार की थी उसके परिणामस्वरूप रूस की भारी विजय हुई है और उसे लगभग आधे यूरोप पर अधिकार प्राप्त हो गया है। अंग्रेजों का कहना है कि शेष यूरोप को मिलाकर एक पश्चिमी राष्ट्रों का गुट बनाया जाय और रूसी प्रभाव-क्षेत्र के जवाब में ब्रिटेन अथवा ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही मिलकर उसका नेतृत्व करें।

प्रश्न है कि क्या इस प्रकार का कोई गुट बनाया जा सकता है? रूस के प्रभाव-क्षेत्र से बाहर के राष्ट्रों पर एक बार दृष्टिपात तो कीजिये।

नार्वे, स्वीडेन और डेनमार्क सदा से यूरोप की राजनीति से तटस्थ रहते आये हैं। स्कैंडेनेविया प्रायद्वीप से बाहर के राष्ट्रों से संधि करना अथवा उनसे मिलकर गुट बनाना उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, नार्वे, स्वीडेन और डेनमार्क रूस के पड़ोसी हैं। ऐसी अवस्था में वे पश्चिमी राष्ट्रों के किसी ऐसे गुट में कैसे सम्मिलित हो सकते हैं, जिसका रुख रूस-विरोधी हो।

हालैंड और बेल्जियम पश्चिमी राष्ट्रों के गुट में शरीक हो सकते हैं। किन्तु फ्रांस में जब तक कम्युनिस्टों की वर्तमान शक्ति बनी हुई है तब तक वह ऐसा नहीं कर सकता। यदि स्पेन और पुर्तगाल में लोकतन्त्रवादी शासन कायम हो जाय तो वे ऐसा कर सकते हैं। इटली का निर्णय भी एक सीमा तक वहाँ के कम्युनिस्टों पर निर्भर है। स्विटजरलैंड पक्का तटस्थतावादी है। यद्यपि उसकी सहायुभूति ब्रिटेन के साथ है, फिर भी वह किसी गुट में शामिल नहीं हो सकता। यूनान में फूट फैली हुई है। उसका सम्बन्ध ब्रिटेन के साथ हो जाने पर दक्षिण-पक्षियों और वामपक्षियों में विरोध बढ़ेगा और युगोस्लाविया तथा बल्गारिया के बीच कटुता बढ़ेगी। इसलिए यूनान भी गुट में सम्मिलित होने से हिचकिचाएगा। तुर्की का एक भाग यूरोप में है और दूसरा एशिया में है। निस्सन्देह उसे ब्रिटेन से बहुत कुछ आशा है, किन्तु वह रूस के आक्रमण की आशंका से भयभीत है। ऐसी अवस्था में रूस से सुलह होने की आशा जब तक बनी रहेगी तब तक वह ब्रिटेन के साथ किसी पश्चिमी गुट में नहीं शामिल होगा।

जर्मनी को छोड़कर यूरोप के शेष देशों का यह हाल है।

दूसरे महायुद्ध में असह्य जर्मनों ने पशुओं तथा राक्षसों का-सा व्यवहार किया है। यदि मानव जाति के विरुद्ध जर्मनों के अपराधों की सूची तैयार की जाय तो जर्मनी की समस्त भूमि एक विशाल काले घव्व से ढक जायगी। जर्मनी के युद्ध सम्बन्धी तथा उससे पूर्व के अपराधों को किसी प्रकार क्षम्य नहीं कहा जा सकता। इन सब अपराधों के लिए क्या जर्मनी को कुछ दण्ड न मिलेगा? पराजय और उसके परिणाम ही जर्मनी के लिए दण्ड है। जर्मनी के विरुद्ध ससार के असतोष का सरलता से अन्त नहीं हो सकता। परन्तु यदि वास्तव में देखा जाय तो जर्मन जो कुछ कर चुके हैं उसका पर्याप्त दण्ड देना सम्भव ही नहीं है क्योंकि पहले की जो भी कार्रवाई की जायगी उससे जर्मनी के भीतर के निर्दोष जर्मन और बाहर के निर्दोष जर्मन ऐसे दब जायगे कि ससार को उन्नति में बाधा पड़ने लगेगी। एक बात और भी महत्वपूर्ण है। यदि जर्मनी को उसके अपराधों के लिए दण्ड दिया जाय तो दण्ड देने वालों का नैतिक अध-पतन हो जायगा। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बुराई का बदला भलाई

से देना पड़ेगा, चाहे जिनके प्रति भलाई की जाय वे इसके योग्य न भी हो

हमारी सम्भ्यता किधर जा रही है ? यूरोप को देखिये या एशिया को—अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, रूसी, आर्जेन्टाईनी, स्पेनवासी या चीनी किसी को भी देखिये, हमारे ऊपर बबरता उसी प्रकार छाती जा रही है, जिस प्रकार फ्रांसी पाने वाले व्यक्ति के मस्तक पर कनटोप आ जाता है, परन्तु हमें फ्रांसी नहीं लगाई जाती। हम कनटोप लगाये निरुद्देश्य फिर रहे हैं। हमारी सम्भ्यता क्षत-विक्षत होने जा रही है। प्रतिहिंसा के इस कुचक्र का कहीं तो अन्त होना ही चाहिए। प्रश्न यह नहीं है कि जर्मन अच्छे व्यवहार के योग्य हैं या नहीं ? तथ्य की बात तो यह है कि हमें केवल अच्छा व्यवहार करना चाहिए।

१८ जून १९४५ को पत्र-प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में भाषण करते हुए जनरल आइजन होवर ने कहा था “घृणा अथवा हिंसा द्वारा आप शान्ति का निर्माण नहीं कर सकते।” ये शब्द एक ईसाई के मुह से निकले थे।

१९४२ में जब मैं महात्मा गांधी के साथ ठहरा हुआ था तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था . “आपके राष्ट्रपति चार स्वाधीनताओं की बात कहते हैं। क्या इनमें स्वतन्त्र होने की स्वाधीनता भी सम्मिलित है ?”

“युद्ध के बाद दुनिया में सुधार होगा”—मैंने उत्तर दिया।

गांधीजी ने मुझसे दृष्टि मिलाते हुए कहा—“आपको इसमें कोई शक तो नहीं है ?”

मैंने उत्तर दिया—“मुझे आशा है।”

गांधीजी बोले—“यदि आप मुझे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप दुनिया में शान्ति की स्थापना करने में समर्थ हो सकेंगे तो मेरे विचार में इसके लिए इंग्लैंड और अमेरिका में अभी से हृदय-परिवर्तन होना आवश्यक है।” ये शब्द भी एक ईसाई के हैं—ऐसे ईसाई के, जो हिन्दू हैं।

कुछ समय पहले एक पादरी की पत्नी ने मुझसे पूछा था कि शान्ति की स्थापना के लिए पादरी क्या कर सकते हैं। मैंने जवाब दिया—“उन्हे ईसाइयों को ईसाई बनाना चाहिए।”

मैं अनेक देशों का भ्रमण कर चुका हूँ। मैं ऐसे हिन्दुओं से मिल चुका हूँ, जो ईसाई थे; और ऐसे यहूदियों से भी, जो ईसाई थे। मैं ऐसे प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों से भी मिल चुका हूँ, जो ईसाई थे। परन्तु ईसाई देश मैंने आज तक नहीं देखा।

शान्ति उतनी ही अच्छी होगी, जितने अच्छे वे लोग होंगे, जो उसका निर्माण करने जा रहे हैं।

जर्मनो, जापानियों और इटालियनो ने जो युद्ध छेड़ा उसमें उन्हें अंग्रेजों, फ्रांसीसियों, रूसियों, अमरीकियों तथा अन्य लोगों की मदद मिली थी। म्यूनिख की संधि में भाग लेने वाले सभी युद्ध-अपराधी थे। सोवियत-नाज़ी संधि करने वाले भी युद्ध-अपराधी थे। कौन कहता है कि यूरोप में युद्ध-अपराधी केवल जर्मन ही थे ?

सभी जर्मनो को युद्ध-अपराधी नहीं कहा जा सकता। मैं कुछ ऐसे जर्मनो को जानता हूँ, जो उन लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक नाज़ी-विरोधी हैं, जो कहा करते हैं कि सभी जर्मन नाज़ी हैं। १९४५ में नूरेम्बर्ग में जर्मन युद्ध-अपराधियों के मामले पर विचार करते हुए जस्टिस राबर्ट जेकसन ने कहा था, “हमारा इरादा समस्त जर्मन राष्ट्र पर अपराध लगाने का नहीं है। हम यह भी जानते हैं कि नाज़ी-दन को बहुमत के आधार पर शक्ति नहीं प्राप्त हुई थी। यह भी हमें अज्ञात नहीं है कि उसे उग्र नाज़ी क्रांतिकारियों तथा जर्मन सेना-वादियों की दुरभिसंधि के कारण अधिकार प्राप्त हुआ था। यह एक ऐतिहासिक सत्य है।”

यह कहना कि नाज़ियों के हाथ में अधिकार जनता की सहमति के बिना नहीं रह सकता था, तानाशाही के सबसे कठोर सत्य की उपेक्षा करना होगा। वह कठोर सत्य यह है कि तानाशाही का शासन जनता की स्वीकृति पर आधारित नहीं होता। हिटलर द्वारा समस्त जर्मन जनता का समर्थन प्राप्त करने की बात मैं किसी तरह नहीं मान सकता। उसने बहुत से जर्मनो का समर्थन प्राप्त कर लिया था। जिन जर्मनो ने हिटलर का समर्थन नहीं किया उन्हें भी अपना सहयोग प्रदान करना पड़ा। क्योंकि ऐसा न करने पर या तो उन्हें मौत का शिकार बनना पड़ता और या जेलों में जीवन व्यतीत करना पड़ता।

जर्मनी अथवा जापान के विरुद्ध हम चाहे जितना कड़ा व्यवहार करें— इसमें शान्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरे महायुद्ध—परमाणु युद्ध—की चर्चा चल पड़ी है। परन्तु यह युद्ध जर्मनी, जापान या इटली नहीं छेड़ेंगे। वे इच्छा रखते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते।

युद्ध और फाशिज्म केवल जर्मनी तक सीमित नहीं है। ये तो ससार भर की व्याधियाँ हैं। भूगोल, रक्त और जाति की सीमाओं से वे परे हैं।

निर्धनता, कष्ट, दमन और भेद-भाव विश्वव्यापी हैं। इन्हीं के कारण युद्ध होते हैं।

राष्ट्रवाद युद्ध छेड़ता है।

तानाशाह युद्ध छेड़ते हैं।

लोकतन्त्रवादी देश युद्ध को रोकने की चेष्टा करते हैं, किन्तु लोकतन्त्र-वाद सर्वत्र नहीं है।

जर्मनी के लोकतन्त्रवादी सकोची, सुधारवादी और अहिंसक थे। जर्मनी के सामंतों, पूँजीपतियों और सेनावादियों के हाथों में अभी तक शक्ति बनी हुई थी। जर्मन लोकतन्त्रवादियों पर अंगुली उठाने वाले अन्य देशों के लोकतन्त्रवादियों को ही ज़रा देख लें। स्पेन के लोकतन्त्रवादियों की लोकतन्त्रवाद में वास्तविक आस्था है और जर्मनी का जोर भी वहाँ अधिक नहीं है। १९३१ से १९३६ तक स्पेन में सेनावादी, जमींदार, फाशिस और राजतन्त्रवादी प्रजातन्त्र का गला घोटने की तैयारी कर रहे थे, किन्तु वहाँ के लोकतन्त्रवादियों ने क्या किया? फ्रांस में लोकतन्त्रवाद का जोर था और फ्रांसीसी बड़ी गम्भीरता से उसके पक्ष में अपने मत प्रदान करते थे। १९३६ से पूर्व लोकतन्त्रवाद के जिन विरोधियों ने अनेक पड़्यत्रों में भाग लिया था क्या फ्रांसीसियों ने उन्हें देश-निकाला दिया?

अमरीका के प्रगतिशील, उदार तथा लोकतन्त्रवादी दलों को ही लीजिये। क्या वे स्वतन्त्रता के घरेलू दुश्मनों, हठिगियों से घृणा करने वालों और यहूदियों, श्रमजीवियों तथा सुधारों के विरोधियों का खात्मा कर सके हैं? यदि जर्मनों का दोष देते हैं तो अपने को भी दोष दीजिये।

कहा जाता है कि जब फ्रांस, पोलैंड, युगोस्लाविया, इटली और यूनान में गुप्त नाज़ी-विरोधी सस्थाएँ काम कर सकती थीं तो जर्मनी में क्यों नहीं, परन्तु यह कहना कहा तक उचित है? युद्ध से पहले ही जर्मन नज़रबंद कैम्प भर चुके थे। वे उन नाज़ी-विरोधी जर्मनों से भरे हुए थे, जिन्होंने अपने प्राणों को वास्तव में सकट में डाला था और उनमें कितने ही उनसे हाथ भी धो बैठे थे। नाज़ी-अधिकृत देशों में गुप्त संगठनों के अधिक विशाल और शक्तिशाली होने का कारण यही था कि अभी उनमें नाज़ियों का दमन-चक्र पूरी तरह घूम नहीं पाया था और दूसरे विदेशी विजेताओं से मुक्ति पाने का विचार भी राष्ट्रीयता की भावना को उकसाकर गुप्त संगठनों का बल बड़ा रहा था।

लोकतन्त्रवादी देशों के उन नागरिकों को, जो मृत्यु का सामना न करने के लिए जर्मनों की निन्दा करते हैं, स्वयं अपने से ही प्रश्न करना चाहिए कि अपने यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक बुराइयों को दूर करने के लिए वे स्वयं कितना खतरा उठाते हैं। अधिक-से-अधिक इसके लिए वे अपना कुछ समय अथवा धन खर्च कर देते हैं। क्या उपर्युक्त बुराइयों को दूर

करने के लिए वे अपने पेशे, परिवार, सामाजिक सम्बन्ध, नौकरी और प्राणों की बलि चढ़ा सकते हैं ?

स्पेन और रूस के कितने नागरिक अपने तानाशाहों से लड़ते हैं ?

१८ अक्टूबर १९४३ को न्यूयार्क में मि० सुमनर वेल्स ने कहा था—
‘हम एक सड़े-गले और बुरे ससार में रहते आये हैं और रह रहे हैं। जर्मनों की बुराई उस बुराई का अधिक कलुषित अंश थी, किन्तु वह कुल बुराई न थी। कुछ-न-कुछ बुराई प्रत्येक देश के हिस्से में आती है।’

जापानियों की युद्ध से पूर्व की और युद्ध-काल की अपराध-सूची लम्बी है। यह कौन कह सकता है कि वह जर्मनों से अधिक लम्बी और बुरी है या नहीं ? फिर भी जापानियों के प्रति जर्मनों से भिन्न व्यवहार हुआ है। जनरल डगलस मैकार्थर की स्वीकृति से वहाँ जैसी प्रगतिशील सामाजिक क्रान्ति हुई है उससे अमरीकी प्रतिक्रियावादी तो आश्चर्य में पड़ जायेंगे। लोकतन्त्रवाद के विरुद्ध विद्रोह करने वाले जापानियों को राजनीतिक जीवन में भाग लेने से वंचित कर दिया गया है। भूमि-प्रणाली के सुधार का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। समाचारपत्रों की स्वाधीनता को प्रोत्साहन दिया गया है। राजनीतिक दलों का जीवन भी स्वच्छन्द हो गया है। केन्द्रीय सरकार बनी हुई है, किन्तु सम्राट् के निरकुश अधिकारों का अन्त कर दिया गया है। सम्राट् को उसकी धार्मिक महानता तथा मर्यादा से वंचित कर दिया गया है। यह सब बिना किसी रक्त-पात अथवा संघर्ष के हो सका है। जनता लोकतन्त्रवाद के लिए उत्सुक है। लोगों में विदेशियों के विरुद्ध कटुता की भावना भी नहीं है।

जापानियों के साथ जैसा व्यवहार हुआ है उसे करते समय यह नहीं सोचा गया कि क्या वे इसके योग्य हैं। कहा जाता है कि ऐसा होने का कारण यही है कि जापान के प्रति नीति-निर्धारित करने की जिम्मेदारी केवल अमराका के कंधों पर थी।

१९४६ में जर्मनी का प्रधान यूहर्दी धर्मोपदेशक डा० वीक अमेरिका का भ्रमण कर रहा था। वह जर्मनी में सहस्रो यूहूदियों को निर्दयतापूर्वक मारे जाते देख चुका था और स्वयं भी एक नज़रबन्द कैम्प में रह चुका था। उससे जब प्रश्न किया गया कि क्या भविष्य में जर्मनी लोकतन्त्रवादी बन सकता है तो उसने उत्तर दिया—“अवश्य, जर्मनी लोकतन्त्रवादी बन सकता है, किन्तु सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि मित्रराष्ट्र जर्मनी में रचनात्मक शक्तियों को प्रोत्साहन देने में वहाँ तक सफल होते हैं।” डा० वीक ने कहा कि जर्मनों से हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। यह ठीक है कि मुख्य जिम्मेदारी स्वयं जर्मनों

की है, किन्तु जर्मनी सत्कार का ही एक हिस्सा है और और सत्कार में होने के कारण हमें जर्मनी के साथ रहना ही पड़ेगा ।

जर्मनी के प्रति जो व्यवहार किया गया है वह उसके अपराधों के दंड की अपेक्षा जर्मनी के नियंत्रण के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस की स्पर्धा का परिणाम अधिक है ।

जर्मनी यूरोपीय समस्या का केन्द्र-बिंदु है । रूस ने आरम्भ में ही पूर्वी प्रशा के एक भाग पर अधिकार कर लिया । जर्मनी के पश्चिम भाग को, जिसमें साइलीशिया, पोमेरानिया तथा पूर्वी प्रशा का शेष भाग है, रूस ने पोलैंड को देकर अपने प्रभुत्व में कर लिया । जर्मनी के इस भाग की समुचित व्यवस्था पोलैंड कारीगरो तथा अन्य साधनों के अभाव में स्वयं नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त, जर्मनी का एक-तिहाई भाग रूसी प्रबंध में है । एक-तिहाई से कुछ कम अमेरिका के हिस्से में आया है । शेष में ब्रिटेन और फ्रांस के हिस्से हैं । यदि इन महाशक्तियों में आपसी होड़ इसी तरह चलती रही तो जर्मनी में प्राप्त स्थिति का उपयोग प्रत्येक महाशक्ति प्रतिस्पर्धी के विरुद्ध करने का प्रयत्न करेगी ।

जर्मनी में, चीन में और सभी जगह रूस की नीति अपने नियंत्रण के प्रदेश की शक्ति बढ़ाना और अपने नियंत्रण से बाहर के प्रदेश की टुकड़े-टुकड़े करके कमजोर करने की है ।

रूस जर्मनी को कृषि-प्रधान देश बनाने की नीति पर अपने क्षेत्र में अमल नहीं कर रहा है । परन्तु अन्य क्षेत्रों में कम्युनिस्ट और उनके हिमायती जर्मन कारखानों को तोड़ने और वहां के उद्योगों को नष्ट करने पर जोर दे रहे हैं । युद्ध के कारण जो तबाही हुई है और विजेताओं ने जिस पूर्णता से अधिकार कर रखा है उसे देखते हुए जर्मनी से निकट भविष्य में युद्ध छेड़ने की आशा नहीं की जा सकती । जर्मनी केवल उसी हालत में युद्ध छेड़ सकता है जब कि अमेरिका, इंग्लैंड और रूस ऐसा चाहेंगे । जर्मनी को चाहे जितना निरस्त्र किया जाय—उसके उद्योग-धंधों को चाहे जितनी पूर्णता से क्यों न नष्ट किया जाय; विजेता-शक्तियां जब चाहे इस प्रवृत्ति को उलट सकती हैं । जर्मनों ने शस्त्रीकरण का कार्यक्रम रूस की सहायता से १९२२ में आरम्भ किया था और १९३२ तक गुप्त रूप से सोवियत भूमि में वह युद्ध-सामग्री तैयार करता रहा, जिसे तैयार करने पर वार्साई की संधि द्वारा उसे रोक दिया गया था । इस की पुनरावृत्ति किसी भी समय इसी प्रकार अथवा अन्य किसी प्रकार हो सकती है ।

युद्ध में पराजित होने के कारण जर्मनी दूसरों की नीतियों का शिकार बना हुआ है। स्वयं उस पर नीति निर्धारित करने की जिम्मेदारी नहीं है। अब वह युद्ध नहीं छेड़ सकता। परन्तु उसके लिए युद्ध छिड़ सकता है।

यूरोप में युद्ध सबसे शक्तिशाली देश ने ही छेड़ा है। पहले रोम ने, फिर स्पेन ने, फिर फ्रांस ने और फिर जर्मनी ने युद्ध छेड़े। कारण स्पष्ट हैं। सबसे शक्तिशाली देश को ही युद्ध में विजय पाने की आशा हो सकती है।

अमेरिका और सोवियत् रूस

ह्वशी-नेता वाल्टर ह्वाइट, जो काला (ग्रादिम) जातियों के मुद्धार के लिए स्थापित राष्ट्रीय सघ के सेक्रेटरी थे, अगमर प्रेसीडेण्ट रूजवेल्ट से मिलने ह्वाइट हाउस जाया करते थे। रूजवेल्ट के मरने के कुछ ही दिनों बाद वह ट्रुमन से मिलने ह्वाइट हाउस गये। ट्रुमन के कमरे में प्रवेश करते हुए ट्रुमन ने उनसे कहा—“मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि यह कैसी अजीब बात है कि आज इस कमरे में प्रेसीडेण्ट नहीं बैठे हैं।”

कुछ समय बाद, दो लेखकों के साथ बात-चात के दौरान में प्रेसीडेण्ट ट्रुमन ने कहा—“मैं इस पद के लिए इच्छुक नहीं था और न इसके लिए इच्छुक ही हूँ।”

ट्रुमन अमेरिकन व्यक्तित्व के प्रतीक है। बडप्पन का बोझ उन पर लादा गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में अपनी स्थिति के कारण अमेरिका को जो कार्य करने पड़ रहे हैं उनके लिए वह इच्छुक नहीं है। विदेशों में लड़ने के लिए भेजे गए अमेरिकन सैनिकों को वापस बुला लेने के लिए अमेरिका में इतनी अनवरत, इतनी व्यापक और इससे शीघ्र सफलता प्राप्त करने वाली माग पहले कभी नहीं हुई थी। अमेरिकावासी यही चाहते थे कि विदेशों में भेजे गए उनके सैनिक स्वदेश लौट आयें। अमेरिकावासी साम्राज्यवादी नहीं हैं। एक अमेरिकन टैंक्सों को वफादारी के साथ अदा करता किंतु उनसे नफरत करता है। भारी किस्म के जगी-जहाजों के निर्माण और नौकरशाही के लिए होने वाले खर्चों को घटाने के लिए की जाने वाली माग से बढ़कर लोकप्रिय कोई दूसरी माग नहीं है और साथ ही जनरलों और फौजी सरदारों जैसे अलोकप्रिय कोई दूसरे व्यक्ति भी नहीं। सारे अमेरिका में सैनिकवाद-विरोधी भावना की ही सबसे अधिक प्रधानता है। अमेरिका के बड़े-बड़े जनरल और फौजी सरदार अपने अड़े बनाने के लिए द्वीप, विशाल नौ-सेना, हवाई-सेना, और फौज सगठित

करना चाहते हैं। कुछ लोग अरब के तैल-क्षेत्र प्राप्त करना चाहते हैं।” उनके अनुयायियों में बहुत से “राष्ट्रवादी” और “देशभक्त” हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वे उनके लिए शक्तिशाली-साधन हैं। कभी-कभी कुछ इने-गिने व्यक्तियों की इच्छाओं के सामने, जिनके हाथों में शासन की बाग्डोर है, करोड़ों जनता की इच्छाएँ कम प्रभावपूर्ण साबित होती हैं।

ओकीनावा, सेईपान और ट्रुक में जापानियों के विरुद्ध मोर्चे-बन्दी करने की कोई जरूरत नहीं। जापान में अमेरिका एक नया कानून बना सकता है और उसे अमल में लाने के लिए वह जर्मनों को मजबूर भी कर सकता है। इस दृष्टि से जापान में अमेरिका को अपनी सारी सेनाएँ मौजूद रखने की कोई बात ही नहीं रह जाती। फिर भी सैनिकवादी अब यह दलील पेश करेंगे कि प्रशान्त महासागर के द्वीप, आइसलैंड या ग्रीनलैंड और एल्युशियम द्वीप-पुंज अपने अधिकार में रखना और अपेक्षाकृत बड़े पैमाने पर शस्त्रीकरण करना रूस के विरुद्ध रक्षात्मक कार्रवाई के ही रूप में है। ससार की घटनाओं के लिहाज से मुमकिन है कि इस दलील पर जनता की सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया हो।

अमेरिका में जाति-भेद और रंग-भेद की भावना रही है। इस तरह की जाति-भेद या रंग-भेद सम्बन्धी अमहिष्णुता को न तो जन-तन्त्रात्मक कहा जा सकता है और न उदारतापूर्ण या मानवोचित ही। फिर भी अमेरिका प्रतिहिंसा या वैर-साधन में तत्पर रहने वाला राष्ट्र नहीं है। जनता के दबाव के कारण और खास करके ग़दरियों की ओर से दबाव डाले जाने के कारण फरवरी १९४६ में सघ-सरकार ने स्वेच्छापूर्वक संगठित समितियों की ओर से जर्मनों के लिए सहायता के रूप में जहाजों से सामग्रियाँ भेजे जाने की अनुमति दे दी थी। जापान के सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की गई है उस पर औसत अमेरिकन प्रसन्नता प्रकट करता है। क्योंकि यह कठोर न होकर कम खर्च वाली और वास्तविक ही है। अमेरिकन रूसियों की कद्र करते और उनके साथ मैत्रीभाव रखते हैं। चीनियों के साथ परम्परा से उनका मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहा है। उनके लिए यह सोचना कठिन ही है कि इटालियन उनके शत्रु थे।

चाहे यह उनका आदर्शवाद हो या धर्म या चाहे इतने शान-शौकत के साथ रहने की वजह से यह उनकी अपराध की आत्म-स्वीकृति की भावना हो, किसी को कष्ट भोगते देखकर अमेरिकावासियों में उसकी प्रतिक्रिया होती है। वे भूखों को भोजन देना चाहेंगे। उनका यही आदर्शवाद आक्रमण-कारियों, अत्याचारियों और तानाशाहों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन्हें मजबूर कर देता है।

अमेरिकन उन लोगों का पक्ष लेना चाहते हैं जिनका पल्लव कमजोर पड़ रहा हो। अमेरिकावासी आजादी को जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। वे यही चाहते हैं कि सत्तार उन्हें अच्छी निगाह से देखे। एक नये और पहले की अपेक्षा उत्तम सत्तार के निर्माण के लिए अमेरिकावासी एक अच्छे प्रस्तावन हैं।

लेकिन अमेरिकन डम बात में डरते हैं कि कहीं वे 'शोषण करने का नर्तक' न बन जाय। उनकी अनुभवहीनता और बेवकूफी में कोई बेजा फायदा उठावे, इनके वे विरोधी हैं। वे इस बात में डरते हैं कि कहीं चुन्ती-दुश्मनी के लिहाज में पुगने देश उनसे बाजी न मार ले जाय। दूसरों की बात पर विचार करते समय अपने ही काम से सरोकार रखना वे अधिक पसन्द करते हैं। वे मुग-नाथनों से सम्पन्न जीवन यापन करने में ही मग्न रहते हैं। वे जानते हैं कि हम अणु-बम, असाधारण कोटि के हवाई किनो, गति-मूलक राजनीति तथा अनेकानेक समस्याओं के युग में रह रहे हैं।

इस प्रकार अमेरिकन मस्तिष्क अनगणित या परस्पर-विरोधी विचारों का एक पुंज है। अभी तक अमेरिका अपनी युद्धोत्तर समस्याओं को हल करने के प्रयत्न में लगा हुआ है। वह सत्तार के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र की हैमियत से अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने में अभ्यस्त नहीं हो सका है। अमेरिका एक बालक के समान है जिसका हाथ एक शक्तिशाली इज्जत के बालक पर है, जिसके द्वारा कोई भी अनहोनी बात हो सकती है।

१६ अप्रैल १९४५ को प्रेसीडेंट ट्रूमन ने कांग्रेस को सबसे पहला सन्देश देते हुए कहा था—“आज ऐसे सत्तार में जब कि दूरी का महत्त्व अधिकाधिक घटता जा रहा है, भौगोलिक अवरोधों से सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिश करना व्यर्थ ही है। वास्तविक सुरक्षा एक मात्र न्याय और कानून में ही निहित है।” कितनी अच्छी बात उन्होंने कही थी। इसी प्रकार २८ अक्टूबर १९४५ को उन्होंने कहा था, “हम सत्तार के किसी भी भाग में अपने लिए एक इंच भी भूमि प्राप्त करने के लिए लालायित नहीं हैं।” और उन्होंने अपने इस वाक्य की पूर्ति इन शब्दों में की थी, “अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक अड़्डे कायम करने के सिवाय हम किसी दूसरे राष्ट्र के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए उत्सुक नहीं हैं।” ट्रूमन सुरक्षा के विचार से अड़्डे कायम करने के लिए द्वीप प्राप्त करना चाहते हैं, हालांकि कांग्रेस से वह कहते हैं, “वास्तविक सुरक्षा एक मात्र न्याय और कानून में ही निहित है।”

एक दिन तो ट्रूमन कानून की बात-चलाते हैं और दूसरे दिन अड़्डे के लिए द्वीप प्राप्त करने या युद्ध की बात चलाते हैं—इसका क्या कारण? इसका कारण यही है कि कानून को अमल में लाने के साधन के बिना कोई कानून

टिक नहीं सकता। किन्तु महान् राष्ट्रों पर कानून लाद ही कौन सकता है ? किसी राष्ट्र पर कानून लादने का अन्तिम उपाय, और अधिकांश मामलों में एक मात्र उपाय, यही है कि उसके विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी जाय।

एक ऐसे ससार में, जिसने अणु को खण्डित किया है और साम्राज्यवाद की सीमाओं को छिन्न-भिन्न कर दिया है, अमेरिका परस्पर-विरोधी विचार-धाराओं में फस गया है। ससार के सभी राष्ट्र अभी परस्पर-विरोधी विचार-धारा में फसे हुए हैं। यह परस्पर-विरोधी विचार-धारा मानव-जाति का गला घोट सकती है।

कुछ लोगों का आग्रह है कि रूस को अपना प्रसार करने से रोक दिया जाय। लेकिन मान लीजिए कि वह नहीं चाहता कि उसे कोई रोकें। तो क्या इसके मानी यही है कि ससार में एक तीसरे महासमर—प्रथम अणु-युद्ध का श्रीगणेश हो ? ससार के प्रत्येक राष्ट्र की भाति और खास करके प्रत्येक शक्तिशाली राष्ट्र की भाति रूस का अपना एक अलग कानून है।

इस प्रकार रूस की समस्या ससार में राष्ट्रीयता की समस्या बन जाती है—ऐसे ससार में जो या तो अन्तर्राष्ट्रीयता स्थापित करेगा या एक दूसरे अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध में फम जायगा।

यहां पर प्रश्न यह उठता है कि तीसरा विश्व-व्यापी युद्ध कैसे हो सकता है ? इसका सूत्रपात कैसे हो सकता है ?

सानफ्रान्सिस्को सम्मेलन (१९४५) शुरू होने के कुछ ही पहले एथोनी एडिन ने, जो उस समय ब्रिटेन के विदेश-मंत्री थे, ग्लासगो में भाषण देते हुए कहा था—“जैसा कि पिछले कुछ वर्षों के इतिहास से प्रकट है, हमने हमेशा, इसी बात की कोशिश की है कि यूरोप पर किसी एक राष्ट्र का प्रभुत्व न कायम होने पाये, हालांकि हमारे इस प्रयत्न में कभी-कभी सिथिलता भी हुई है। हमने अपने लिए कभी ऐसी स्थिति प्राप्त करने की कोशिश नहीं की है, और न किसी दूसरे राष्ट्र को ही ऐसी स्थिति प्राप्त होने दी है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो स्वतः हमारी स्वतंत्रता शीघ्र ही यूरोप के दूसरे राष्ट्रों की स्वाधीनता के साथ-साथ छिन जायगी। इसी उद्देश्य को लेकर हमने दो महायुद्ध लड़े हैं।”

इसी उद्देश्य को लेकर अमेरिका ने भी दो विश्व-व्यापी युद्ध लड़े हैं।

यूरोप पर किसी एक राष्ट्र का प्रभुत्व कायम होने देने के लिए पहला और दूसरा महायुद्ध लड़ने के बाद अब इंग्लैंड और अमेरिका इस बात के लिए उत्सुक हैं कि यूरोप पर रूस का प्रभुत्व कायम न होने दिया जाय। अगर

रूस यूरोप पर अकुश कायम कर लेने में सफल हुआ तो वह एशिया पर भी अपना सिक्का जमा लेगा। यूरोप की समस्या और एशिया की समस्या दोनों मिलकर यूरोप-एशिया की समस्या में परिणत होगई है।

यूरोप या एशिया में रूसियों का प्रभाव न होने पाए यह अमेरिका का कार्य है और उन्हीं कारणों से यह ब्रिटेन का भी।

यूरोप या एशिया के छोटे-छोटे या कमजोर राष्ट्रों या यदि रूसों आक्रमण होता है तो उसने ब्रिटेन और अमेरिका यह समझ सकते हैं कि यह सप्ताह की १०॥ खरब जनता पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए उठाया जाने वाला रूिनियों का पहला कदम है, और इसलिए यह सप्ताह के अन्य देशों के लिए एक भारी खतरे के रूप में है।

हिटलर या जापानियों के आक्रमण से इसी बात का खतरा पैदा हो गया था जो दूसरे महायुद्ध का कारण बना।

हिटलर की दलील थी कि उसने आत्म-रक्षा के लिए युद्ध छेड़ा है। आक्रमण करने का दोष तो उसने वास्तव में पोलो के मध्ये मड़ा। जर्मनी की इस दलील पर सप्ताह हसने लगा और उसे युद्ध में उतरना पड़ा। पिछले कुछ वर्षों में बोलशेविकों ने आक्रमण करने के इस नाज़ी तौर-तरीके को अद्वितीय किया है। क्या यह सच नहीं है कि १९३९ में स्टालिन और मोलोटोव ने आक्रमण के लिए ब्रिटेन और फ्रांस को दोषी बताया था? क्या विदेशों में रहने वाले कम्युनिस्ट तथा अनभिज्ञ और कम्युनिस्टों के साथ के यात्रा करने वाले अन्य सभी यात्री यही बकवाद नहीं करते थे?

अक्सर तानाशाह लोग बेतुकी बातें मुंह से निकालने के दोषी पाये जाते हैं, लेकिन वे खुद इस तरह की बेतुकी या थोथी बातों को सच समझते या उनका यकीन करते हों, ऐसी बात नहीं, बल्कि वे यही आशा करते हैं कि दूसरे लोग उनका बातों को सच मान लेंगे।

किसी देश पर होने वाला आक्रमण चाहे जितना भी प्रच्छन्न हो, उसे छिपाने के लिए चाहे जितनी भी बहानेबाजी की जाय, लेकिन वह एक तीसरे महायुद्ध का सूचक बन सकता है।

द्वितीय महायुद्ध की पहली चिनगारी १८ सितम्बर १९३१ को भड़की थी, जब कि जापानियों ने मुकुडेन को हड़प लिया था। लेकिन बहुत लोग युद्ध के इस विस्फोट की आवाज़ केवल तभी सुन सके जब कि कोई दस साल बाद ७ सितम्बर १९४१ को पर्ल बन्दरगाह में वह पुनः प्रतिध्वनित हुआ।

जाहिरा तौर पर बहुत बुद्धिमान् समझे जाने वाले अनेक अमेरिकनो के

मेने लेख पढे है और उनके भाषण भी सुने है । उनका कहना है—“अमेरिका और रूस एक दूसरे से बहुत ही दूरी पर है । प्रदेशो के सम्बन्ध मे, इन दोनों मे कोई मतभेद नही है और वे एक दूसरे से लडने क्यों जाय ?”

अमेरिका का तो जर्मनी से भी कोई प्रादेशिक मतभेद नही था । फिर भी अमेरिका को जर्मनी से दो-दो लडाइया लडनी पडी । और उसे यह दोनों लडाइया यूरोप पर किसी एक राष्ट्र का आधिपत्य न स्थापित होने के ही उद्देश्य से लडनी पडी । जो लोग केवल इस बात से सन्तुष्ट है कि सोवियत् रूस और संयुक्तराज्य अमेरिका के बीच कोई प्रादेशिक मतभेद नही है वे भौगोलिक स्थिति पर बहुत अधिक और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत कम ध्यान देते है ।

युद्ध उस हालत मे नही छिडता जब कि कोई बडा राष्ट्र किसी बडे राष्ट्र पर हमला करता है । प्रथम और द्वितीय महासमर तभी आरम्भ हुआ जब कि बडे राष्ट्रों ने छोटे राष्ट्रों पर हमला किया । एवीसीनिया, स्पेन, मचूरिया, आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, अल्बानिया, और पोलैंड पर ही आक्रमण होने पर ओहिमो, लिवरपूल, और लेनिनग्राड से नौजवानो को युद्ध-प्रयाण करना पडा और ससार के सभी भागो मे उनकी कब्रें बनी । छोटे-छोटे राष्ट्रों पर होने वाला आक्रमण ही हमारी आपदाओं की जड होता है ।

क्या रूस आक्रमणकारी राष्ट्र रहा है ?

आक्रमण की सोवियत् परिभाषा, जिसका मसविदा तात्कालीन सोवियत् वदेशिक मन्त्री मैक्सिम लिटविनोव ने तैयार किया था, लाजवाब है । इस रूसी परिभाषा का स्वरूप उस घोषणा-पत्र में सम्मिलित है जिस पर लडन-सम्मेलन मे, जो कि आक्रमण की परिभाषा निश्चय करने के लिए आयोजित किया गया था, ४ जुलाई १९३३ को सोवियत् रूस और रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, टर्की और लिथुआनिया के प्रतिनिधियो ने और बाद में पोलैंड, ईरान, अफगानिस्तान, फिन्लैंड, इस्थोनिया और लैटविया के प्रतिनिधियो ने भी हस्ताक्षर किये थे ।

उस घोषणा की धारा (२) मे कहा गया है, “आक्रमणकारी वह राष्ट्र समझा जायगा जो निम्नलिखित कार्य पहले करेगा

१ किसी दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना ।

२ युद्ध-घोषणा किये या न किये बिना ही किसी दूसरे राष्ट्र के प्रदेश पर अपनी शस्त्र-सेनाओं के साथ आक्रमण कर देना ।

३. युद्ध-घोषणा किये या न किये बिना ही किसी दूसरे राष्ट्र के

प्रदेश, जहाँ जा या वागुयानो पर अपनी जल, थल या हवाई-सेनाओं द्वारा आक्रमण करना।

४ किसी दूसरे राष्ट्र के समुद्र-तटों अथवा बन्दरगाहों की नाकेबन्दी करना।

५ अपने प्रदेश में उन सशस्त्र दलों को सहायता पहुँचाना जिन्होंने किसी दूसरे राष्ट्र पर हमला कर दिया हो।”

इस घोषणा-पत्र का “परिशिष्ट” और भी रोचक या दिलचस्प है और वह चाहे घोषणा-पत्र से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा है, “इस घोषणा की धारा (२) के अन्तर्गत कोई भी आक्रमणात्मक कार्य अन्य बातों के अलावा निम्नांकित आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता

“(अ) किसी राष्ट्र की आन्तरिक अवस्था। उदाहरण के लिए उसकी राजनीतिक, आर्थिक अथवा सामाजिक व्यवस्था, हड़तानों, क्रांतियों प्रति-क्रान्तियों अथवा गृह-युद्धों के कारण वहाँ की शासन-व्यवस्था में उत्पन्न हुई कथित खराबियाँ या उथल-पुथल।” आक्रमण की इस सरकारी सोवियत् परिभाषा के अनुसार सोवियत् रूस, फिन्लैंड, पोलैंड, लैटविया, लियुथानिया, इस्थोनिया और ईरान में, जो सब-के-सब उस घोषणा-पत्र के हस्ताक्षर-कर्ता थे, रूस ही आक्रमणकारी रहा है।

ऐसी हालत में तीन बड़े राष्ट्र-नायकों में एकता स्थापित होने की आशा दुरीशा मात्र है, जब कि उनमें से एक अपना प्रसार कर रहा है। रूसियों के आक्रमण और प्रसारण को देखकर ब्रिटेन और अमेरिका सतर्क हो गए हैं। एकता और आक्रमण में कोई मेल नहीं। एकता और प्रसारण यह दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं।

इसी प्रकार एक ओर तो अमेरिकन सोवियत् मैत्री के लिए और दूसरी ओर इस मैत्री में खिचाव-तनाव पैदा करने वाले रूसी प्रसारण को माफ कर देने के लिए दलील पेश करना व्यर्थ है।

दिसम्बर १९४१ में जब पोलिश प्रधान मन्त्री जनरल सिकोरस्की मास्को पहुँचे थे, तो स्टालिन ने पहले पोलैंड से पोलिश-प्रदेश के लिए माग की। १९४३ में रूसियों ने अंग्रेजों को सूचित किया कि वे बाल्टिक प्रदेशों को रूस में मिला लेना चाहते हैं। रूस ने १९४३ में चेकोस्लोवाक प्रदेश के लिए माग की। रूसियों की इस शक्ति-वृद्धि की पुष्टि दिसम्बर १९४३ में तेहरान-सम्मेलन में और फिर फरवरी १९४५ में याल्टा-सम्मेलन में रूजवेल्ट और स्टालिन ने की थी। यह बात तब की है जब कि युद्ध-कालीन तीनों मित्र-राष्ट्रों (रूस,

ब्रिटेन और अमेरिका) में कोई गहरी तनातनी या संघर्ष नहीं हुआ था। यह हिरोशिमा पर अणु-बम गिराये जाने के पहले की बात है। उस समय तो ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका की सरकार बड़ी सक्रियता पूर्वक और जोरों के साथ रूस की सहायता पहुंचाने में लगी थी और उसके साथ बहुत ही मैत्री-भाव रखती थी। इसलिए स्टालिन के प्रसारण और शक्ति-विस्तार होने का कारण अणु-बम या रूस के प्रति ऐंग्लो-अमेरिकन वैमनस्य नहीं बताया जा सकता।

हमने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में कानून का एक विशिष्ट स्वरूप प्रस्तुत करने के इरादे से द्वितीय महासमर में पदार्पण किया था। क्योंकि जहां तक कानून है वही तक शान्ति है। किन्तु संधियों का अतिक्रमण अराजकता है, विदेशों में बहा की जनता की इच्छाओं के विरुद्ध सेनाएं रखना अराजकता है, रियायतें या सुविधाएं प्राप्त करने के लिए छोटे-छोटे राष्ट्रों पर दबाव डालना अराजकता है—सहा माने में अराजकता, जिसके कारण १९३६ में महायुद्ध छिड़ा। कानून तोड़ने वाला आक्रमणकारी राष्ट्र अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा का अपहरण कर लेता है, लेकिन ज्यादातर अन्त में अपने ही को मुसीबत में फसा लेता है।

‘सोवियत इन वर्ल्ड अफेयर्स’ नामक पुस्तक में मैंने इसका विस्तार-पूर्वक वर्णन किया है कि पूंजीवादी देशों से बोलशेविक रूस का क्या सम्बन्ध रहा है। सोवियत राष्ट्र सच को वर्षों तक अनावश्यक सशस्त्र हस्तक्षेप, आर्थिक बहिष्कार और आर्थिक प्रतिबन्ध का शिकार बनना पड़ा था और उसके साथ कूटनीतिक सम्बन्ध नहीं स्थापित किया गया था। विदेशों में रहने वाले उसके दूतों की हत्याएं हुईं और सोवियत दूतावासों पर हमले हुए थे।

वह एक और ही युग था। यह युग तब तक रहा जब तक कि रूस अपेक्षाकृत कमजोर और कम्युनिस्ट मनोवृत्ति धारण किये था—जब तक कि वह भयभीत और अनाक्रमणकारी था। अब रूस शक्तिशाली और राष्ट्रवादी बन गया है। अब रूस ने आक्रमण का रुख धारण कर लिया है। अब यह एक विलकुल नया युग है। अगर रूस भयभीत होना तो वह आक्रमणकारी रुख धारण न करता।

नाज़ी लोग लोकतन्त्रवादी राष्ट्रों को समझ नहीं सके थे। वे लोकतन्त्रवादी राष्ट्रों से नफरत करते थे और उनके संकल्प को तुच्छ समझते थे। स्टालिन ने इस तरह का व्यवहार किया है जिससे ऐसा जान पड़ता है कि वह भी नाज़ियों के-से विचार रखने है। वह अपने तर्क मचाई के साथ कह सकते हैं—‘नहरान

और याल्टा सम्मेलनो में रूजवेल्ट और चर्चिल ने हमें वही दिया था जो कि हम जर्मनी, पोलैण्ड, बालकान प्रदेशों, मचूरिया, कोरिया, म्यूराइल द्वीप-पुन और साखालिन में प्राप्त करना चाहते थे। उस समय पूर्वी प्रशा का कुछ हिस्सा रूस में मिला दिया जाना उन्होंने मजूर कर लिया था लेकिन इसे वे अन्तिम रूप से स्वीकार कर लेते इसके पूर्व ही मैंने दर असल उन भागों को सोवियत रूस में मिला लिया और उन्होंने उस पर कोई आपत्ति नहीं प्रकट की। इसके बाद रूमानिया, आस्ट्रिया, पोलैण्ड, और बल्गारिया में मैंने अपनी इच्छा के अनुसार एकांगी सरकारें कायम कर लीं। मेरा यह कार्य याल्टा-सम्मेलन के विरुद्ध ही हुआ था (याल्टा-सम्मेलन में यह सम्मेलन हुआ था कि यूरोप के किसी देश में या घुरोराष्ट्रों के भूतपूर्व पिट्ठू देशों में अस्थायी सरकार कायम करने में तीनों मित्रराष्ट्रों की सरकारें महायत्ना प्रदान करेंगी और यह कि इस प्रकार की अस्थायी सरकारों का निर्माण तत्सम्बन्धी देशों की जनता के सारे लाकतत्रवादी दलों के प्रतिनिधियों को चुनकर किया जायगा) और ट्रूमन, वायर्नेन, एटली और बेविन इस बात को जानते हैं और उन्होंने ऐसा कहा भी है लेकिन इस बारे में कुछ किया नहीं है। सच तो यह है कि अमेरिका ने अपने यहां के लोकमत के दबाव की वजह से और वहां पर मेरी कम्युनिस्ट-दल की भी मदद से, यूरोप में अपनी अधिकांश सेनाएं वापस बुला ली हैं। पोड्सडम सम्मेलन के समय मैंने इस्तम्बूल पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए टर्की से कांस और अर्दाहान प्रान्त ले लेने की भी मांग की थी जो कि 'दर्रे-दानियाल के जल-डमरू मध्य के भीतर एक दुर्ग है।' अमेरिका और ब्रिटेन उक्त जलडमरूमध्य का मार्ग खुला रख छोड़ने के लिए राजी होगा और यह एक अच्छी बात भी थी। लेकिन उस दुर्ग के अपने अधिकार में आ जाने पर हम उस मार्ग को बन्द कर सकते हैं। आश्चर्य है कि यह तमाम बातें इतनी खामोशी के साथ स्वीकार कर ली गईं। ये लोग बहुत सक्रिय नहीं जान पड़ते। इंग्लैण्ड को अपने साम्राज्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अरब विद्रोह कर रहे हैं। चीन में फूट पैदा हो गई है। अमेरिका में कम्युनिस्ट-दल और उसके "मोर्चे" ने जनता को उलझन में डाल देने और उदार-वादियों तथा मजदूरों की कार्रवाई को निष्क्रिय बना देने का अच्छा काम किया है। जर्मन कम्युनिस्ट-दल सारे जर्मनी पर अपना दबदबा कायम कर लेने की कोशिश कर रहा है। फ्रेंच कम्युनिस्ट-दल की वजह से फ्रांस कोई निर्णयात्मक कार्रवाई करने में असमर्थ है। यूरोप और एशियावासी भूखो मर रहे हैं। मैंने एक महान् शक्ति-शाली रूसी साम्राज्य का निर्माण किया है। जब उन्होंने इतनी बड़ी बात मजूर कर ली तो क्या वे इस भुनगे के लिए कोई आपत्ति प्रकट करेंगे? मैं देखंगा

कि जब मैं ईरान और टर्की की ओर मुखातिब होता हू तो वे क्या करते हैं ?”

इस तरह के मनोभाव, कठोर राष्ट्रीयता, और तानाशाही राष्ट्र के भीतर आम तौर पर पाई जाने वाली तनातनी के फलस्वरूप युद्ध छिड़ सकता है। इन्हीं कारणों से दूसरा महायुद्ध हुआ था।

इन परिस्थितियों में कुछ अमेरिकनो और अंग्रेजों का कहना है कि अमेरिका को अणु-बम बनाना बन्द कर देना चाहिए। फिर क्यों न टी० एन० टी० बम, असाधारण कोटि के हवाई किले और भारी किस्म के युद्ध-पोतों का बनाना भी बन्द कर दिया जाय ? क्यों न निःशस्त्रीकरण किया जाय ? निःशस्त्रीकरण के लिए राष्ट्र तैयार क्यों नहीं हैं ? इसका कारण यही है कि वे आपस में संघर्ष होने की सम्भावना देखते हैं।

मान लीजिए अमेरिका ने अणु-बम बनाना बन्द कर दिया। फिर क्या इस बात की कोई गारन्टी है कि रूस अणु-बम न बनाएगा ? क्या रूस अपने सारे देश के कारखानों और वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की विजली के स्टेशनों, विजली की लाइनों की पूरी-पूरी जाच करने देगा ? यह सवाल मास्को से करना चाहिए। रूस एक पुलिस-राज्य है। वर्षों से सोवियत् नागरिकों को अपने देश के ही भीतर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पासपोर्ट लेना पड़ता है और पुलिस में अपना नाम दर्ज कराना पड़ता है। रूस पहुँचने वाले विदेशियों पर वहाँ की पुलिस कड़ी निगाह रखती है, जैसा कि वहाँ पर विदेशी पत्रकारों के सम्बन्ध में होता है। भले ही वे सिर्फ दृश्य का अवलोकन करने, वहाँ की कुछ साधारण जनता से बातचीत करने और जानकारी हासिल करने के इरादे से किसी छोटे-मोटे प्रान्तीय नगर में जाना चाहते हों। क्या मास्को के अधिकारी विदेशी विशेषज्ञों को अपने यहाँ के कल-कारखानों की इम बात का पता लगाने के लिए पूरी तौर से छान-बीन करने देंगे कि कहीं उनमें अणु-बम तो नहीं तैयार किये जा रहे हैं ? क्या वे इस बात को स्वीकार करेंगे कि अणु-बम पर नियंत्रण स्थापित करने वाली अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्र सस्था का रूस में यूरेनियम की खानों और रूसी आणुविक कारखानों पर अधिकार हो और उसे उन खानों तथा कारखानों को संचालित करने का अधिकार मिले ? सोवियत्-प्रणाली की कुछ भी जानकारी रखने वाले व्यक्तियों के लिए यह बात सर्वथा अकल्पनीय ही है। युद्ध के दिनों में जब अमेरिका रूस को उधार-पट्टा कानून के अन्तर्गत ८० खरब डालर की युद्ध-सामग्रियाँ पहुँचा रहा था उन दिनों भी अमेरिकन अफसरों को सिवाय थोड़ी देर के लिए सरसरी तौर पर निगाह डालने के, मोर्चों पर या सोवियत् फैक्टोरियों में जाने की इजाजत नहीं दी गई थी।

कुछ लोगो का कहना है कि रूस को अणु-बम दे दिया जाय । रूस अणु-बम लेकर क्या करेगा ? क्या वह जर्मनी या जापान के विरुद्ध इसका प्रयोग करेगा ? इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जर्मनी और जापान को कुचल दिया गया है और उन पर कब्जा कर लिया गया है । क्या वह संयुक्तराज्य अमेरिका और ब्रिटन के विरुद्ध इसे काम में लायेगा ? यह तो उसे अणु-बम देने का कोई उचित कारण नहीं जान पड़ता । तो क्या वह डराने-बमकाने के उद्देश्य से किसी छोटे देश के विरुद्ध इसे इस्तेमाल करेगा ? यह भी तो उसे अणु-बम देने का कोई उचित कारण नहीं प्रतीत होता ।

उनका कहना है, "लेकिन रूस किसी-न किसी तरह अणु-बम प्राप्त कर लेगा और इस बीच अणु-बम पर ब्रिटन और अमेरिका के एकाधिकार ने मास्को में सन्देह पैदा कर दिया है और दो दुनिया के बीच मतभेद की खाई और चौड़ी कर दी है ।" शायद रूस के पास अणु-बम है, या शायद वह इसे प्राप्त कर लेगा । अणु-शक्ति की शोध करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक और हेरॉल्ड जे० यूरे ने १९४६ के आरम्भ में कहा था कि मुमकिन है कि ३ मास के भीतर रूसी अणु-बम तैयार करने लग जाय । अन्य अधिकारी व्यक्तियों का ह्याल है कि रूस को अणु-बम तैयार करने में शायद ५ से १० साल तक का समय लगेगा । लेकिन मान लीजिए कि रूस २ साल या १ साल या ६ महीने के ही भीतर अणु-बम बनाने लगे । यूरोप और एशिया का नक्शा रोजाना नया बन रहा है । और यदि रूस के पास अणु-बम हैं तो यह नक्शा यूरोप और एशिया को हानि पहुंचाकर ही बनेगा । यदि रूस के हाथ में अणु-बम आगया तो यूरोप और एशिया के छोटे-छोटे देश इस समय जितने आतंकित हो रहे हैं उससे भी अधिक आतंकित हो उठेंगे । ब्रिटन और अमेरिका को, जो पहले से ही रूस को तुष्ट कर रहे हैं, उसे और भी तुष्ट करना पड़ जायगा । रूस को अणु-बम देने पर हम इसी अर्थ में युद्ध से बचे रहेंगे, जैसा कि तुष्टीकरण से राष्ट्र कुछ समय के लिए हमेशा युद्ध से बच जाया करते हैं । लेकिन तुष्टीकरण के बाद जो युद्ध शुरू होता है वह निकृष्ट ही होता है ।

रूस को अणु-बम का रहस्य बता देने से क्या हमारे प्रति उसके सन्देह दूर हो जायगे ?

यह कहना ग़लत है कि अमेरिका के पास अणु-बम है—ऐसा मैंने कहा है । मेरी इस बात पर सुनने वालों को विस्मय हुआ है । माना कि अमेरिका के पास अणु-बम है लेकिन उसका उपयोग अमेरिका किन परिस्थितियों में करेगा ?

प्रशान्त महासागर स्थित अमेरिका जहाजी बेड़े के प्रधान एडमिरल

चेस्टर निमिट्ज के सम्मान में वाशिंगटन में दी गई एक दावत के अवसर उन्होंने एक बहुत ही आश्चर्यजनक भाषण दिया था। उन्होंने कहा था, “जापान पर विजय अणु-बम की वजह से नहीं प्राप्त हुई। सच तो यह है कि हिरोशिमा के साथ ससार में अणु-युग आरम्भ होने की घोषणा होने और उस युद्ध में रूस के पदार्पण करने के पूर्व ही जापान मधि-प्रस्ताव कर चुका था। लेकिन यदि सर्वथा सैनिक दृष्टि से यह कहा जाय कि जापान को हराने में अणु-बम ने कोई निर्णयात्मक कार्य नहीं किया तो उसका मतलब यह नहीं कि इस नये अस्त्र का भयानक सहायकारिता को कम बताने की चेष्टा की जा रही है।”

यदि यह बात सच है—और निमिट्ज को यह मालूम होना चाहिए—तो हिरोशिमा पर अणु-बम का गिराया जाना और फिर नागासाकी पर दूसरा अणु-बम प्रहार करना निश्चय इस दूसरे महायुद्ध में हुआ सबसे भारी अत्याचार है, बावजूद इसके कि शायद अणु-बम प्रहार से जापान-विरोधी संघर्ष जल्द समाप्त हो जाने में सहायता मिली।

जो भी हो, सच तो यह है कि ऐसा ख्याल भी नहीं किया जा सकता कि शान्ति-काल में अमेरिका मेक्सिको या अर्जन्टाइना, फ्रान्स या ब्रिटेन पर अणु-बम से इसलिए प्रहार करने जायगा, कि वह अपने शिकार बने राष्ट्र से कुछ हड़प कर लेने की इच्छा रखता है। इस बात की कल्पना उस समय तक नहीं की जा सकती जब तक कि अमेरिका एक लोकतन्त्रवादी राष्ट्र है और जब तक अमेरिकन लोक-मत शक्तिशाली, आलोचक एवं स्वतन्त्र सत्ता बनाये हुए है।

अणु-बम के विरुद्ध एक रक्षा-क्वच है—और वह है लोकतन्त्रवाद। स्टालिन को मालूम है कि संयुक्त-राज्य अमेरिका किसी देश के विरुद्ध आक्रमण के उद्देश्य से अणु-बम का प्रयोग न करेगा। उसे शायद इस बात की उम्मीद है कि यदि किसी देश पर कोई आक्रमणकारी हमला करता है तो उसकी रक्षा करने के लिए भी अणु-बम का इस्तेमाल करने से वह हिचकेगा।

अमेरिकन समाचार पत्रों में मुझे इस आशय के कई लेख या वक्तव्य पढ़ने को मिले हैं कि सोवियत् अधिकारी हमारी नीयत पर सन्देह करते या अमेरिका से भय खाते हैं। लेकिन उनके इस कथन की सचाई का उनके लेखों या वक्तव्यों में कोई सबूत मुझे देखने को नहीं मिला है। वेशक, एक सोवियत् रूस के हिमायती अमेरिकन लेखक जॉसफ वार्नेस ने, रूस की यात्रा समाप्त करके वापस लौटने के कुछ ही दिनों बाद न्यूयार्क में १५ दिसम्बर १९४५ को उनके सम्मान में दी गई एक दावत में भाषण करते हुए कहा था कि मुझे वहाँ के

लोगों में 'उड़्डता और शैली बघारने की भावना' फैलने की मिली है।

रूस न कोई सन्देह रखता है, न उसे कोई डर है। इसके दो स्पष्ट कारण हैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन हो रहा है और वह अपनी रक्षात्मक कार्रवाइयों में लगा है। और अमेरिका ?—वह तो युद्ध में विजय प्राप्त कर लेने के बाद बेमरम्भे-बूभे मानसिक और सैनिक विसंगठन करने में व्यस्त है। ब्रिटेन और अमेरिका के अलावा समार में कोई तीसरा राष्ट्र है ही नहीं जो रूस पर हमला कर सके—जर्मनी या जापान, ईरान या फिन्लैंड, चीन या फ्रांस, कोई भी नहीं ! ब्रिटेन की कमजोरी और अमेरिका का साम्राज्यवादी सैनिक विसंगठन—इन दोनों बातों से स्टालिन की हिम्मत बढ़ी है। ताकतवर शक्ति की कद्र करता है।

रूस जिस तरह का कार्य करता है उसका असली कारण यह नहीं कि वह किसी से डरता है, बल्कि यह कि उसे किसी का डर ही नहीं रह गया है, और उसे इस बात का इतमीनान हो गया है कि उस पर कोई हमला नहीं कर सकता।

ज्या आप कहेंगे कि मेरा यह विचार रूस की निस्वत गौर ईमानदारी से भरा हुआ, अमेरिका के बारे में बहुत उदारतापूर्ण और ब्रिटेन के सम्बन्ध में जरूरत से ज्यादा मैत्री-सूचक है ?

मैं अपना कोई विचार प्रकट करने में बड़ी सावधानी और सयम से काम लेता हूँ। मैंने अमेरिका या ब्रिटिश-सरकारों के कार्यों की आलोचना या निन्दा करने में कभी कोई सकोच नहीं किया है। स्वतंत्रता, प्रगति, शान्ति और मानव-जाति की सुख-समृद्धि का मैं उपासक हूँ। जब मुझे ऐसा लगता है कि इन बातों में कोई दखल देना या बाधा डालना चाहता है, तभी मैं बोलता हूँ। मेरा यह विश्वास नहीं कि किसी की आलोचना करने के कारण युद्ध छिड़ते हैं, बल्कि इसके खिलाफ मेरी राय में आलोचना न होने पर ही युद्ध छिड़ सकता है। खतरो को चिकनी-चुपड़ी बातें करके कम बताने या गलतियाँ करने से युद्ध शायद जल्द छिड़ जाने की सम्भावना रहती है। हिटलर ने अपनी सेनाएँ हमला करने के लिए इस वजह से जर्मनी नहीं रवाना की थी, क्योंकि उनके खिलाफ किसी ने कोई भाषण दिया था या कोई पुस्तक लिखी थी। स्टालिन उस समय सैन्य-संचालन का आदेश नहीं करते जब कोई ऐसा वक्तव्य या पुस्तक पढ़ते हैं, जिसमें सोवियत् राष्ट्र-संघ की घोर निन्दा की गई होती है। बल्कि इस तरह से की गई निन्दा या आलोचना का जवाब वह कड़ी निन्दा या आलोचना में ही देते हैं।

नाजी जर्मनी के विरुद्ध चर्चिल के आग उगलने पर भी हिटलर ने

१९३९ में इंग्लैंड पर हमला नहीं किया, उसने बहुत खामोश रहने वाले शांति-प्रिय राष्ट्र पोलैंड को अपना शिकार बनाया और ब्रिटेन को लड़ाई से बचाना चाहा। २३ अगस्त १९३९ से २२ जून १९४१ तक सोवियत् रूस के अधिकारी-गण न केवल जर्मनी की आलोचना करने से अपने को रोकते रहे बल्कि वे जर्मनी की खुशामद-दरामद करते रहे और जर्मनी ने रूस पर धावा बोल दिया।

प्रतिक्रियावादी अमेरिकन समाचार-पत्र सच रेडियो-टिप्पणी-कर्ता, सम्पादकीय लेखक, और अमेरिकन कांग्रेस के सदस्यो से जो, रूस के खिलाफ लगातार जिहाद शुरू कर रहे हैं, मुझे नफरत है। लेकिन यह कहना गलत है कि इन सबकी बातों से युद्ध के जल्द छिड़ने में सहायता मिलती है— ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता कि तटस्थतावादियों के प्रचार के ही फलस्वरूप पलं बन्दरगाह पर एकाएक जापानियों के युद्ध शुरू हो जाने के पूर्व तक अमेरिका युद्ध से तटस्थ ही बना रहा।

प्रोपेगण्डा मनोभावों को परिपक्व बना सकता या मनोभावों के परिपक्व होने में विलम्ब लगा सकता है। लेकिन युद्ध जल्द छिड़ने में ठोस फीजी कार्र-वाइयो, सेनाओं के संचालन, नगरों पर बम-वर्षा और आक्रमण से अधिक सहायता मिलती है।

क्या ब्रिटिश सरकार या अमेरिका ने कोई ऐसी बात की है जिससे सोवियत् रूस को आशंका या व्यग्रता प्रकट करने की कोई जरूरत जान पड़ती हो !

अमेरिकन सरकार की इस बात के लिए आलोचना की गई है कि आर्जन्टाइना की तानाशाही के विरुद्ध और फ्रैंको के विरुद्ध हस्तक्षेप करने में उसने उदासीनता दिखाई है। फ्रैंको के विरुद्ध लड़ाई में मैं सक्रियतापूर्वक लगा रहा हूँ और मैं तानाशाही से नफरत करता हूँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस सिद्धान्त के आधार पर शान्ति-स्थापित करना ससार के लिए खतरनाक होगा कि बड़े राष्ट्रों को इस बात का अधिकार है कि वे दूसरे राष्ट्रों के मामले में, जिनसे वे युद्ध की स्थिति में नहीं हैं, दखल दें। अगर आज कोई लिबरल (उदार) सरकार तानाशाही का तस्ता उलट देने के लिए हस्तक्षेप करती है तो हो सकता है कि कल कोई प्रतिक्रियावादी सरकार लोकतंत्री शासन को उलट देने के लिए हस्तक्षेप करे। पहले मामले में हस्तक्षेप का उद्देश्य ईमानदारी के साथ फाशिस्ट-विरोधी हो सकता है और दूसरे में वह साम्राज्य-वादी।

किसी विदेशी राष्ट्र के हस्तक्षेप करने पर जनता को देशभक्ति सवधी

कारणों से वहाँ के तानाशाह की छत्र-छाया में एकत्र होने का अवसर प्राप्त हो जाता है, भले ही वह वर्ण सम्बन्धी तथा आर्थिक कारणा से उसका विरोध ही क्यों न करती हो।

यह एक उल्लेखनीय बात है कि जो लोग सोवियत् हस्तक्षेप और आक्रमण के हामी हैं (समर्थन करते हैं) वही स्पेन और आर्जेन्टाइना के मामले में अमेरिकन हस्तक्षेप के लिए सबसे ऊँची आवाज उठा रहे थे। लेकिन अगर अमेरिका ने दक्षिणी अमेरिका के मामले में दखल दिया होता तो वह यूरोप और एशिया के मामलों में रूसियों के दखल देने का विरोध कैसे कर सकता था ?

किसी शान्तिपूर्ण राष्ट्र के मामले में दखल देना केवल उभी हालत में ग्राह्य हो सकता है जब कि किसी प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय मस्या द्वारा—जो कि किसी ऐसे एक या दो राष्ट्रों के दबाव में पड़कर कार्य न करती हो जिन्हें उस मस्या की ओर से उस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए चूने जाने की सम्भावना हो—स्वेच्छापूर्वक किये गए निर्णय के ही अनुसार ऐसा किया जाय।

लेकिन सच तो यह है कि यदि अंग्रेज और अमेरिकन आर्जेन्टाइना और स्पेन में तानाशाही की बड़े जोर-शोर से निन्दा करते हैं तब भी वे उनके मामले में कोई दखल नहीं देते तो इससे रूस को और भी निश्चित हो जाना चाहिए। क्योंकि इससे यह प्रकट हो जाता है कि जब लोकतन्त्रवादी राष्ट्र कमजोर राष्ट्रों के खिलाफ—जो उनका बहुत कम प्रतिरोध कर सकते हैं—दखल देने में इतनी हिचकिचाहट दिखा रहे हैं तो साफ जाहिर है कि वे रूस जैसे शक्तिशाली राष्ट्र पर हमला करने में कितनी अधिक हिचकिचाहट दिखाएंगे।

इण्डोनेशिया में ब्रिटेन ने जो कार्य किये उनकी निन्दा करने का मैं एक उचित आधार देखता हूँ। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में ब्रिटेन का यह कार्य एक पतनोन्मुख राष्ट्र को अपने से भी जर्जरित साम्राज्य को सहायता पहुँचाने के प्रयत्न के समान था। और रूस को शायद उच्च और ब्रिटिश साम्राज्यशाही की स्थिति और भी चकनाचूर होते देखकर, जैसा कि जावा की रक्त-रजक घटनाओं से जाहिर होता है, सन्तोष ही हुआ होगा। इसमें कोई शक नहीं कि अगर कोई उपनिवेश पश्चिमी साम्राज्यवादियों की हुकूमत में बसने से इन्कार करता है तो इस बात से रूस के लिए कोई खतरा पैदा न होगा।

ग्रीस में ब्रिटिश सरकार के कार्यों की आलोचना की गई है। यह एक जटिल और उलझन-ग्रस्त स्थिति थी। क्योंकि दूसरे कई देशों, दुखी और क्षुधात देशों की भाँति ग्रीस के घरेलू मामले विदेशी राष्ट्रों के खींचतान के

बजाय उसकी अन्दरूनी कशमकश के ही प्रतीक है ।

अमरीकन पत्र 'न्यूयार्क हेराल्ड ट्रिब्यून' के ६ मार्च १९४६ के अंक में सुमनर वेल्स ने लिखा : "यह बड़े दुःख की बात है कि नाजियों के पजे से छुटकारा मिलने के बाद ग्रीस को सोवियत और ब्रिटिश स्वार्थों के सघर्ष का अड्डा बन जाना पड़ा है । इससे ग्रीस में गृह-युद्ध छिड़ने में प्रोत्साहन मिला है ।... निकट भविष्य में सोवियत रूस, जो कि उस क्षेत्र में अपना शक्ति-विस्तार करने पर तुला हुआ है और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच, जिन्होंने भूमध्य सागर, स्वेज नहर, के मार्ग को यातायात के लिए सभी देशों के वास्ते खुला रखने का संकल्प कर लिया है, होने वाले सघर्ष का केन्द्र-स्थल बन रहा है ।

अगर ग्रीस में कम्युनिस्ट दल या वाम-पक्षी दल का दबदबा कायम हो जाता है और अगर रूस उत्तरी अफ्रीका के ट्रिपोलीटानिया को अपने संरक्षण में कर लेने में सफल हो गया, तो उसके फलस्वरूप टर्की का आधा हिस्सा घिर जायगा, रूसी शान्ति के सामने ग्रीस बहुत पीछे पड़ जायगा और निकट भविष्य में ब्रिटेन की सारी स्थिति खतरे में पड़ जायगी ।

चर्चिल ने ग्रीस के राजतन्त्रवादियों को प्रोत्साहित करने की गलती की । लेकिन फिर भी चर्चिल के बारे में कोई आश्चर्य करने की बात नहीं, ऐसी गलतियाँ वह पहले बहुत कर चुके हैं । लेकिन इसके पूर्व ब्रिटेन की टोरी (कट्टरपथी) सरकार ग्रीस में जो बीड़ा उठा चुकी थी उससे अब मजदूर सरकार पीछे कैसे हट सकती थी । दक्षिणी यूरोप में ब्रिटेन के बचे-खुचे आधारभूत केन्द्र-स्थलों में से एक स्थल रूसियों के हाथ पड़ जाने से बचा लेने के लिए कोशिश करने पर उसे मजबूर हो जाना पड़ा । ग्रीस में भीतर से वामपक्षीय दल और कम्युनिस्टों के आन्दोलन और बाहर से डोडिकनीज द्वीप पुंज ग्रीस को लौटा दिये जाने के प्रश्न पर सोवियत रूस का रुख और ग्रीक प्रदेश प्राप्त करने के लिए अल्बानिया और युगोस्लाविया की मांग के रूप में रूस उस (ग्रीस) पर अपना प्रभुत्व कायम कर लेने का प्रयत्न करता है, जब कि ब्रिटेन उसके विरुद्ध प्रभावहीन अस्त्रों से लड़ रहा है ।

रूस और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच सघर्ष के केन्द्र-स्थल जर्मनी और चीन हैं । ये दोनों राष्ट्र और ग्रीस तथा इटली तब तक सुख, शान्ति और समृद्धि प्राप्त न कर सकेंगे जब तक कि रूस इंग्लैंड तथा अमेरिका के सघर्ष का निपटारा नहीं हो जाता । आज इनमें हर एक पराजित घुरी-राष्ट्रों, छोटे-छोटे तटस्थ राष्ट्रों, चीन या उसके कुछ भाग की जनता को अपनी तरफ खींच लेने की कोशिश कर रहा है ।

उनका यह कार्य एक बहुत ही रहस्यपूर्ण और गैर ईमानदारी के साथ किये जाने वाले प्रचार की आउ मे हो रहा है। अपने यहां के कम्युनिस्टों के मन के मुताबिक अमेरिकन और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा जर्मनी में नाजियों का निराकरण नहीं किया जाता तो उस पर वे बड़ा हंगामा मचाते हैं। जब जर्लिन का कम्युनिस्ट दैनिक पत्र यह प्रस्ताव करता है कि 'छोटे नाजियों' को कम्युनिस्ट दल में शामिल होने की इजाजत मिलनी चाहिए और जब उसके कुछ ही दिनों बाद चोटी का जर्मन कम्युनिस्ट विलहेमपीक नाजियों से 'जन सत्तात्मक और फाशिस्ट-विरोधी जर्मनी का मुनिश्चित रूप में निर्माण किये जाने में' सहायता पहुंचाने के लिए अनुरोध करना है तो इस पर निराकरण सम्बन्धी—अमेरिकन और ब्रिटिश कार्रवाइयों के आलोचक चुप्पी साध लेते हैं—और वे कुछ नहीं कहते। अगर अधिकृत जर्मनी के पश्चिमी क्षेत्रों के जर्मन-औद्योगिकों को अपना कार-बार शुरू करने की इजाजत दे दी जाती है तो उसका मतलब फौरन यह लगाया जाता है कि यह रूस के खिलाफ युद्ध की तैयारी हो रही है। लेकिन जब जर्मनी के रूसी क्षेत्र में जर्मन-उद्योग-वधे अपने काम में फिर लग जाते हैं तो उसे बुद्धिमत्तापूर्ण राजनीति समझा जाता है।

महत्त्व तो इस बात का है कि जर्मन-उद्योग-वधों का संचालन कौन करता है। जर्मन औद्योगिकों के ही कारण हिटलर और युद्ध का प्रादुर्भाव हुआ। जर्मन औद्योगिकों और पूंजीवाद पश्चिमी राष्ट्रों के बीच एक स्वाभाविक और कभी-कभी अधिक गठबन्धन होता है। औद्योगिकों के अन्तर्राष्ट्रीय गठबन्धन और घरेलू कार्यों की कड़ाई के साथ जाँच होनी चाहिए और उस पर प्रतिरोध लगा देना चाहिए। फिर भी, अंग्रेजों की यह दलील बेबुनियाद नहीं है कि जर्मन-फैक्टरियों के उत्पादन पर रोक लग जाने से बेकारी और अशान्ति उत्पन्न होगी, लोग भूखी मरने लगेंगे। फलतः पश्चिमी राष्ट्रों के लिए नई कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जायगी और कम्युनिस्टों को अपने प्रभाव का प्रसार करने के नये अवसर प्राप्त हो जायेंगे। सम्भवतः इस कठिनाई से बचाव का यही उपाय है कि जर्मनी के उद्योग-वधे चालू तो किये जायें किन्तु उनके संचालक जर्मन औद्योगिक न हों।

लेकिन जर्मनी की परिस्थिति के सम्बन्ध में सबसे उल्लेखनीय बात तो यह है कि जर्मनी का आधा भाग या तो रूस या पोलैंड में मिला लिया गया है या वह रूसी अधिकार में आ गया है। जर्मनी का यह क्षेत्र रूसियों के पजे में आ गया है और उस पर से पश्चिमी राष्ट्रों का प्रभाव हमेशा के लिए उठ गया

हैं। जर्मनी के बाकी आधे भाग में जर्मन कम्युनिस्ट और कतिपय सोवियत समर्थक अमेरिकन, ब्रिटिश और फ्रेंच ट्रेड यूनियन के सदस्य रूसियों के हितों का प्रसार कर रहे हैं और ब्रिटेन तथा अमेरिका के हितों की जड़ खोद रहे हैं।

जर्मनी का पूर्वी अर्धभाग तानाशाही शिकजे में पड़ गया है। हिटलर के बनाये नज़रबन्द कैम्प फिर खुल गए हैं और वहाँ पर रूसी भंडे फहरा रहे हैं। जर्मनी के पश्चिमी अर्धभाग में लोकतन्त्रवाद की आवाज़ अब तक बहुत धीमी पड़ी हुई है। फिर भी वहाँ पर स्वतन्त्र भावना, स्वतन्त्र ट्रेड यूनियन, स्वतन्त्र राजनीतिक दल और स्वतन्त्र व्यक्ति बने रह सकते हैं।

रूस और पश्चिमी राष्ट्रों का सम्बन्ध इस प्रकार बिगड़ जाने का अर्थ यह है कि जर्मनी दो भागों में विभाजित हो जायगा।

जापान और चीन में सोवियत सरकार की राजनीतिक अधिकार सन्तुष्टी शिकायत बाजिव है। जापान अमेरिकन अधिकृत प्रदेश है। कम्युनिस्ट-विरोधी चांग-काई-शेक के शासन में संयुक्त चीन अमेरिकन प्रभाव-क्षेत्र में निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा।

यह दलील पेश की जा सकती है कि 'अमेरिकन सशस्त्र सेनाओं ने जापान को हराया है।' यह सच है। लेकिन सोवियत सशस्त्र सेनाओं ने हिटलर को बाल्टिक प्रदेशों, पोलैण्ड, रूमानिया, बल्गारिया, युगोस्लाविया और हंगरी से भगाया और जर्मनी में हिटलर को कुचलने में अधिकांश खून बहाया, लेकिन तब भी उन प्रदेशों में रूस को सबसे प्रमुख स्थिति प्राप्त होने पर अमेरिका आपत्ति प्रकट करता है।

पहले कौन पैदा हुआ—मुर्गी या अण्डा? इस तरह की बहस हमेशा दिलचस्प लेकिन ज्यादातर व्यर्थ हुआ करती है। टोकियो की खाड़ी में अमेरिकन सेनाओं के उतरने और जापान को चीन से भगा दिये जाने के बहुत पहले से सोवियत रूस ने बाल्टिक क्षेत्र, पोलैण्ड, बाल्टिक प्रदेश, और मंचूरिया के लिए अपने दावे को दाँव पर लगा दिया था। रूस यह कह सकता है कि जापान और चीन में अमेरिकनों के क्या इरादे हैं इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। चर्चिल ने तो कहा ही था कि ब्रिटेन अपने साम्राज्य को छिन्न-भिन्न न होने देगा। फिर क्यों न रूस अपना साम्राज्य कायम कर लेना चाहे?

मेरी निजी राय तो यह है कि ब्रिटेन को अपना साम्राज्य खत्म कर देना चाहिए। फिर न रूस साम्राज्य प्राप्त करेगा और न अमेरिका साम्राज्य प्राप्त करने की अभिलाषा रखेगा। और तब युद्ध और युद्ध का खतरा मिट जायगा।

ब्रिटेन का साम्राज्यवाद तत्त्व हो रहा है। अमेरिकन साम्राज्यवाद पूर्णरूप से विकसित नहीं हुआ है। इसी साम्राज्यवाद गतिशील, प्रसरणशील है और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वह एक तुपार-नद की भाँति जिन प्रदेशों पर फैलता जा रहा है वहाँ भी जनता का क्या भविष्य होगा। ईरान, मचूरिया को लूट-खसोट, पोलैंड के प्रदेशों का रूस में मिला लिया जाना, चेकोस्लोवाकिया, जापान, और जर्मनी तथा यूरोप में कायम की गई दमनकारी सोवियत् कठपुतली सरकारें, यह सब इसी बात के सबूत हैं।

अमेरिका या ब्रिटेन ने यूरोप में किसी प्रदेश को हड़प लिया हो, या किसी देश को लूटा-खसोटा हो, किसी देश में पहले तो सरकार कायम की हो और बाद में उस सरकार में कोई तबदीली करने से निर्वाचकों को मना कर दिया हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

अमेरिका के पास एक शक्तिशाली हवाई सेना और नौसेना है और वह अपने अड्डे कायम करने के लिए और अधिक द्रोण प्राप्त कर लेने की कोशिश में है। रूस ने कई लाख सशस्त्र सैनिकों को तैयार कर रखा है, वह पहले से बड़ी नौसेना का निर्माण कर रहा है और गस्त्रास्त्र तैयार करने वाले कारखानों का उत्पादन बढ़ा रहा है। सच तो यह है कि १९३६ से रूस ने एक विस्तृत साम्राज्य कायम कर लिया है और उसका फैलाव अब तक जारी है, और इस साम्राज्य के भीतर स्वतंत्रता मर चुकी है।

इसका कोई सबूत नहीं दिया जा सकता कि अमेरिका या ब्रिटेन रूस पर आक्रमण करने का इरादा रखते हैं। यह साबित नहीं किया जा सकता कि रूस अमेरिका या ब्रिटेन पर हमला करने का कोई इरादा रखता है। लेकिन यह साफ ज़ाहिर है कि रूस का विस्तार ससार की एक महान् समस्या है—और इस विस्तार का परिणाम युद्ध होता है।

जर्मनी और जापान पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद कई महीनों तक असह्य अमेरिकन, अंग्रेजों तथा अन्य लोगों के मस्तिष्क को जो सन्देह वेचैन बना रहा था उसका लाभ उन्होंने रूसियों को उठाने दिया। वे केवल यही आशा कर सकते थे कि पोलैंड, बाल्कान प्रदेशों, आस्ट्रिया, जर्मनी और एशिया में रूसियों की कार्रवाइयाँ केवल अस्थायी तौर पर हो रही हैं। वे अपनी ज़बान वन्द किये चुपचाप देखते रहे। भारी-से-भारी अनिष्ट की आशंका रखते हुए भी वे रूस की सराहना करते रहे।

तेहरान, याल्टा, पोर्ट्सडम आदि युद्ध के दौरान में हुए सभी सम्मेलनों में रूस का एक वोट ब्रिटेन और अमेरिका के दो वोटों के मुकाबले में

अधिक महत्व रखता था। रूस को नाराज नहीं किया जा सकता था। इसलिए रूस ने जो भी चाहा ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने सद्बिवेक के विरुद्ध उसे वही प्रदान किया।

युद्ध-काल से शान्ति-काल की कूटनीति के क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए यह आवश्यक था कि समझौते के लिए किये जाने वाले प्रयत्न के स्वरूप में आधार-भूत परिवर्तन कर दिया जाय। इसके अनुसार युद्ध के बाद लन्दन में हुए प्रथम सम्मेलन में, जो कि सितम्बर १९४५ में हुआ था, अमेरिकन वैदेशिक मंत्री वायर्नेस और ब्रिटिश विदेश-मन्त्री बेविन ने मोलोटोव को शान्तिकालीन गणित के लिए एक पाठ सिखाने का प्रयत्न किया। एक बराबर होता है एक के; एक दो से अधिक के बराबर नहीं होता। मोलोटोव ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। तीनों विदेश-मंत्रियों के बीच का यह मतभेद इतना बड़ा हुआ था कि वे इस बात पर भी सहमत नहीं हुए कि इस सम्मेलन के सम्बन्ध में इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी जाय कि तीनों विदेश-मंत्रियों में कोई समझौता नहीं हो सका। इसी प्रकार मोलोटोव ने शान्ति-सम्मेलन में फ्रांस और चीन को शामिल करने से इकार कर दिया। मोलोटोव चाहते थे कि शान्ति-सम्मेलन में तीनों बड़े राष्ट्रों का ही बोल-वाला हो और तीनों बड़े राष्ट्रों में वह आशा रखते थे कि युद्ध-काल की गणित की उलटवासी के अनुसार—अर्थात् एक बराबर होता है दो से अधिक के—रूस का ही बोल-वाला होगा।

प्रकट रूप से रूस का यह इरादा देखकर कि वह ससार के मामले में निर्णायक का स्थान ग्रहण करना चाहता है, पश्चिमी राष्ट्र और चीन घबरा उठे। फिर भी रूस के साथ उनका सम्बन्ध इतना सकट-ग्रस्त और पहले से ही नाजुक हो चुका था कि उसके द्वारे में व्यर्थ की निराशावादिता प्रकट करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वायर्नेस ने एक बार फिर कोशिश करने का निश्चय किया। दिसम्बर १९४५ में मास्को में तीनों विदेश-मंत्रियों का एक सम्मेलन फिर हुआ। ईरान और टर्की के ज्वलन्त प्रश्न चुपचाप टाल दिये गए। उस सम्मेलन में सरकारी तौर से जितने भी प्रश्नों पर विचार हुआ उनमें से प्रत्येक प्रश्न पर मोलोटोव विजयी हुए।

सथम और आशावादिता ने सन्देह को अब भी ठिकने नहीं दिया। फरवरी १९४६ में पहली बार लन्दन में नयुन राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। ग्रीस और युगोस्लाविया के प्रश्न पर बेविन की बिश्निन्स्की से जोरों की भडप हुई। लेकिन रूस ने ईरान के प्रश्न पर, जहाँ पर उसके कामरेडों (साथियों) ने स्टालिन के जन्म-स्थान सोवियत आज़िया के निम्नस्थ प्रदेश, अज़रबैजान

ब्रिटेन का साम्राज्यवाद खत्म हो रहा है। अमेरिकन साम्राज्यवाद पूर्णरूप से विकसित नहीं हुआ है। रूसी साम्राज्यवाद गतिशील, प्रसरणशील है और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वह एक तुपार-नद की भाँति जिन प्रदेशों पर फैलता जा रहा है वहाँ भी जनता का क्या भविष्य होगा। ईरान, मंचूरिया की लूट-खसोट, पोलैंड के प्रदेशों का रूस में मिला लिया जाना, चेकोस्लोवाकिया, जापान, और जर्मनी तथा यूरोप में कायम की गई दमनकारी सोवियत् कठपुतली सरकारें, यह सब इसी बात के सबूत हैं।

अमेरिका या ब्रिटेन ने यूरोप में किसी प्रदेश को हड़प लिया हो, या किसी देश को लूटा-खसोटा हो, किसी देश में पहले तो सरकार कायम की हो और बाद में उस सरकार में कोई तबदीली करने से निर्वाचकों को मना कर दिया हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता।

अमेरिका के पास एक शक्तिशाली हवाई सेना और नौसेना है और वह अपने शत्रु कायम करने के लिए और अधिक द्रोण प्राप्त कर लेने की कोशिश में है। रूस ने कई लाख सशस्त्र सैनिकों को तैयार कर रखा है, वह पहले से बड़ी नौसेना का निर्माण कर रहा है और शस्त्रास्त्र तैयार करने वाले कारखानों का उत्पादन बढ़ा रहा है। सच तो यह है कि १९३६ से रूस ने एक विस्तृत साम्राज्य कायम कर लिया है और उसका फैलाव अब तक जारी है, और इस साम्राज्य के भीतर स्वतंत्रता मर चुकी है।

इसका कोई सबूत नहीं दिया जा सकता कि अमेरिका या ब्रिटेन रूस पर आक्रमण करने का इरादा रखते हैं। यह साबित नहीं किया जा सकता कि रूस अमेरिका या ब्रिटेन पर हमला करने का कोई इरादा रखता है। लेकिन यह साफ ज़ाहिर है कि रूस का विस्तार ससार की एक महान् समस्या है—और इस विस्तार का परिणाम युद्ध होता है।

जर्मनी और जापान पर विजय प्राप्त कर लेने के बाद कई महीनों तक असंख्य अमेरिकन, अंग्रेजों तथा अन्य लोगों के मस्तिष्क को जो सन्देह वेचैन बना रहा था उसका लाभ उन्होंने रूसियों को उठाने दिया। वे केवल यही आशा कर सकते थे कि पोलैंड, बाल्कन प्रदेशों, आस्ट्रिया, जर्मनी और एशिया में रूसियों की कार्रवाइयाँ केवल अस्थायी तौर पर हो रही हैं। वे अपनी जवान वन्द किये चुपचाप देखते रहे। भारी-से-भारी अनिष्ट की आशंका रखते हुए भी वे रूस की सराहना करते रहे।

तेहरान, याल्टा, पोट्सडम आदि युद्ध के दौरान में हुए सभी सम्मेलनों में रूस का एक वोट ब्रिटेन और अमेरिका के दो वोटों के मुकाबले में

अधिक महत्व रखता था। रूस को नाराज नहीं किया जा सकता था। इसलिए रूस ने जो भी चाहा ब्रिटेन और अमेरिका ने अपने सद्बिवेक के विरुद्ध उसे वही प्रदान किया।

युद्ध-काल से शान्ति-काल की कूटनीति के क्षेत्र में पदार्पण करने के लिए यह आवश्यक था कि समझौते के लिए किये जाने वाले प्रयत्न के स्वरूप में आधार-भूत परिवर्तन कर दिया जाय। इसके अनुसार युद्ध के बाद लन्दन में हुए प्रथम सम्मेलन में, जो कि सितम्बर १९४५ में हुआ था, अमेरिकन वैदेशिक मंत्री वायर्नेस और ब्रिटिश विदेश-मन्त्री बेविन ने मोलोटोव को शान्तिकालीन गणित के लिए एक पाठ सिखाने का प्रयत्न किया। एक बराबर होता है एक के। एक दो से अधिक के बराबर नहीं होता। मोलोटोव ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। तीनों विदेश-मंत्रियों के बीच का यह मतभेद इतना बड़ा हुआ था कि वे इस बात पर भी सहमत नहीं हुए कि इस सम्मेलन के सम्बन्ध में इस आशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी जाय कि तीनों विदेश-मंत्रियों में कोई समझौता नहीं हो सका। इसी प्रकार मोलोटोव ने शान्ति-सम्मेलन में फ्रांस और चीन को शामिल करने से इकार कर दिया। मोलोटोव चाहते थे कि शान्ति-सम्मेलन में तीनों बड़े राष्ट्रों का ही बोल-वाला हो और तीनों बड़े राष्ट्रों में वह आशा रखते थे कि युद्ध-काल की गणित की उलटवासी के अनुसार—अर्थात् एक बराबर होता है दो से अधिक के—रूस का ही बोल-वाला होगा।

प्रकट रूप से रूस का यह डरावा देखकर कि वह ससार के मामले में निर्णायक का स्थान ग्रहण करना चाहता है, पश्चिमी राष्ट्र और चीन घबरा उठे। फिर भी रूस के साथ उनका सम्बन्ध इतना सकल-ग्रस्त और पहले से ही नाजुक हो चुका था कि उसके बारे में व्यर्थ की निराशावादिता प्रकट करने की कोई गुजाइश नहीं थी। वायर्नेस ने एक बार फिर कोशिश करने का निश्चय किया। दिसम्बर १९४५ में मास्को में तीनों विदेश-मंत्रियों का एक सम्मेलन फिर हुआ। ईरान और टर्की के ज्वलन्त प्रश्न चुपचाप टाल दिये गए। उस सम्मेलन में सरकारी तौर से जितने भी प्रश्नों पर विचार हुआ उनमें से प्रत्येक प्रश्न पर मोलोटोव विजयी हुए।

सयम और आशावादिता ने सन्देह को अब भी टिकने नहीं दिया। फरवरी १९४६ में पहली बार लन्दन में सयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। ग्रीस और युगोस्लाविया के प्रश्न पर बेविन की विशिष्टी से जोरो की भड़प हुई। लेकिन रूस ने ईरान के प्रश्न पर, जहाँ पर उसके कामरेडों (साथियों) ने, स्टालिन के जन्म-स्थान सोवियत जाजिया के निम्नस्थ प्रदेश, अज़रबैजान

मे एक 'स्वतन्त्र' सरकार कायम कर ली थी, वार्ता चलाने से इन्कार कर दिया। वह प्रदेश रूसी फौजों के कब्जे में था। इसके पहले रूस ने उत्तरी ईरान में तेल के सम्बन्ध में सुविधाओं की माग की थी, जिसे ईरान सरकार ने ठुकरा दिया था।

इस घटना के फलस्वरूप ब्रिटेन और रूस तथा अमेरिका और रूस में पारस्परिक सम्बन्धों में एक सकट-ग्रस्त स्थिति उत्पन्न होगई। लन्दन-सम्मेलन से, जिसमें उन्होंने अमेरिकन प्रतिनिधि की हैसियत से भाग लिया था, लौटने पर सीनेटर आर्थर एच० वेण्डेनबर्ग ने सीनेट में एक लम्बा भाषण दिया था जिस पर बाद में विस्तृत रूप से टीका-टिप्पणियां हुईं। उस भाषण में उन्होंने प्रश्न किया था, "रूस अब किस बात के लिए कटिबद्ध है?" आपने कहा, "सोवियत् रूस आज ससार की सबसे बड़ी पहेली है।" इसके अलावा अमेरिकन वैदेशिक मंत्री वायर्नेस ने भी उसी सम्मेलन में एक लम्बे भाषण में अपनी व्यग्रता प्रकट की। उन्होंने रूस के 'आक्रमण' का उल्लेख किया और कहा कि ससार की परिस्थिति 'निश्चित या भय से रहित' नहीं है। उसी दिन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के एक दूसरे अमेरिकन प्रतिनिधि जान फॉस्टर डुलेस ने, जो कई बार डिमोक्रेटिक (लोकतन्त्री) सरकार के सलाहकार रह चुके थे, फिलेडेल्फिया में वैदेशिक नीति सम्बन्धी सभ की बैठक में कहा, "सोवियत् रूस के साथ मिल-जुलकर काम करना बड़ा मुश्किल जान पड़ता है, क्योंकि ऐसा लगता है, कि सोवियत् रूस सहयोग करना नहीं चाहता।"

समाचार पत्रों के स्थायी स्तम्भों के लेखक, टिप्पणीकार, सम्पादक अमेरीका और यूरोप तथा अन्य भागों की जनता सम्भावित सकट-ग्रस्त परिस्थिति की आशंका प्रकट करने लगी। हर-एक यही पूछता, "रूस की वास्तव क्या किया जाय?"

ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री की हैसियत से ५ वर्षों तक महान् परिश्रम करने के उपरान्त चर्चिल, चित्रकार, उन दिनों फ्लोरिडा में विश्राम कर रहे थे। उन्होंने प्रेसीडेंट ट्रूमन के साथ एक छोटे से कस्बे फुल्टन, (मिस्स्यूरी) की यात्रा की। व्यग्र ससार उनसे कुछ सुनने के लिए उत्सुक हो उठा। ट्रूमन ने चर्चिल का परिचय कराया और कहा, "मे जानता हू कि अपने भाषण में चर्चिल कोई रचनात्मक बात कहेंगे।" उनको यह बात इसलिए मालूम थी क्योंकि वह जानते थे कि चर्चिल का क्या भाषण होगा। और यही बात वायर्नेस को भी मालूम थी।

चर्चिल ने श्रोताओं को सावधान किया, "समय बहुत कम है। रोग

का इलाज करने से यह बेहतर है कि रोग होने ही न दिया जाय ।”

उन्होंने आगे कहा, “सयुक्त राष्ट्रों की विजय से अभी-अभी जो प्रकाश फैल उठा था उस पर एक काली छाया पड़ गई है । निकट भविष्य में सोवियन् रूस और उसका कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रीय सगठन क्या करना चाहता है अथवा उसके विस्तार या लोगों को कम्युनिज्म की दीक्षा देने की प्रवृत्ति की कोई सीमा है या नहीं, यह कोई नहीं जानता ।”

चर्चिल के ये शब्द बहुत गम्भीर थे । चर्चिल ने कहा—“मेरा यह यकीन नहीं है कि सोवियत् रूस युद्ध चाहता है । वह केवल युद्ध के परिणामों से लाभ उठाने, अपनी शक्ति और अपने सिद्धान्तों का अनिर्दिष्ट विस्तार करने की अभिलाषा रखता है ।

चर्चिल ने प्रस्ताव किया, “अंग्रेजी भाषा-भाषी जनता का एक सघ स्थापित होना चाहिए । ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, और साम्राज्य तथा सयुक्त राज्य अमेरिका के बीच विशेष सम्बन्ध स्थापित होने चाहिए ।”

‘विरादराना सघ’ की व्याख्या करते हुए चर्चिल ने कहा, “इसके लिए हमारे फौजी सलाहकारों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध बने रहने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप प्रच्छन्न खतरो का समान रूप से अध्ययन किया जाय, शस्त्र और सैनिक निर्देश के माध्यम एक से हो, और टेकनिकल कालेजों में अफसरों और केडेटों का परस्पर आदान-प्रदान हो । इस सगठन के साथ ही पारस्परिक सुरक्षा के लिए प्राप्त हुई मौजूदा सुविधाएँ बनी रहे और सारे ससार में किसी भी देश के अधिकार में रहने वाले नौ-सैनिक और हवाई अड्डों का सयुक्त रूप से प्रयोग किया जाय । . हम पहले से ही बहुत से द्वीपों का सयुक्त रूप से उपभोग करते हैं, और निकट भविष्य में हमें इसके लिए और भी द्वीप प्राप्त हो सकते हैं ।... इस प्रकार चाहे जो भी हो, हमारे लिए अपने को सुरक्षित रखने का यही एक मात्र उपाय है । . ”

चर्चिल का यह प्रस्ताव बहुत कुछ सैनिक-सचि का-सा जान पड़ता है ।

स्टालिन ने पत्र-प्रतिनिधियों के साथ हुई एक मुलाक़ात में—जो कि एक बहुत ही असाधारण-सी बात थी—चर्चिल और उनके प्रस्ताव तथा ब्रिटिश मजदूर सरकार की बुरी तरह आलोचना की । सोवियन् समाचार-पत्रों ने चर्चिल की रोषपूर्ण आलोचना की । अमेरिका ने चर्चिल के भाषण की भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया हुई । किसी ने तो उनके इस विश्लेषण को और प्रस्तावित मति को पसन्द किया, तो दूसरों ने, जिनमें मैं भी शामिल था, यह महसूस किया कि जहाँ चर्चिल ने वर्तमान समय की ज्वलन्त समस्या की ओर हमारा ध्यान आँक़र

सत्कार्य किया है, वहा उनका यह प्रस्ताव खेदजनक और अपर्याप्त है।

ससार की शान्ति इस बात पर निर्भर करती है कि सभी मजदूरो को इतनी मजदूरी पर, जिससे उनका जीवन-निर्वाह हो सके, बराबर काम मिलता रहे। सभी कृषको को जीविकोपार्जन के लिए भूमि प्राप्त हो, सभी जाति और वर्ग के लोगो को स्वतन्त्रता मिले और सभी देश और उपनिवेश आजाद हो जाय। सधियो से ये परिणाम नही निकलते।

यह साधारण मानव का युग नही है। यह वह युग है जिसमे साधारण मनुष्य लगातार मागे करने लगा है। अगर उसे पूरा-पूरा काम नही मिलता, अगर उसे पूरा-पूरा भोजन, शिक्षा, सुरक्षा और अवसर नही मिलता और यदि वह भेद-भाव का शिकार बनने से छुटकारा नही पा जाता तो वह समष्टिवादियो का सहज ही शिकार बन सकता है, जो यह सब चीजें प्रदान करने का वचन देते है और जो इसके बदले में अपना वादा पूरा करने के पहले ही उसकी आजादी छीन लेते है। लोकतन्त्रवाद को नष्ट कर देने के लिए कम्युनिस्ट लोग लोकतन्त्रवादी ससार की इन सारी अपूर्णताओ से लाभ उठाएंगे। यन्त्र-तन्त्र और विशेषतः दक्षिणी अमेरिका मे फाशिस्ट लोग उसी रण-नीति से काम लेंगे।

मास्को के हाथ में एक ऐसा आइना है जो उन लोगो के सकट को, जो उस आइने में देखना पसन्द करते हैं, अक्सर बहुत बढ़ाकर प्रतिबिम्बित करता है। इसके विरुद्ध कोई सधि या शान्ति प्राप्त करने की अन्य दूसरी राजनीतिक व्यवस्था उनके लिए शक्तिहीन है।

चर्चिल का प्रस्ताव उन्नीसवीं सदी का प्रस्ताव है जो शक्ति प्राप्त करने के लिए किया गया है। रूसियो की चुनौती के कुछ पहलुओ का सामना करने के लिए यह पर्याप्त हो सकता है। इससे या तो सोवियत् रूस की सैनिक चाल को रोक दिया जा सकता है या उस स्थिति का मुकाबला करने का यह एक सभावित साधन बन सकता है। लेकिन रूस महज एक राष्ट्र नही और ना ही वह महज पीटर महान् है। वह तो मार्क्स के विकृत और अस्वीकृत रूप द्वारा सज्जित पीटर है। किन्तु फिर भी मार्क्स का यह रूप उन बातों के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक है जो कि अपरिवर्तन की स्थिति मे पड़ी रहकर जीर्ण-शीर्ण हो गई है।

चर्चिल पीटर के साथ उतने ही कौशल से लड़ सकता है, जितने कौशल से वह हिटलर से भिड़ा है। किन्तु मार्क्स के विरुद्ध लड़ने के लिए उसके पास कोई शस्त्र नही है। वास्तव मे इसमे सदेह करने का कारण नही है कि आज चर्चिल ने हिटलर पर अन्तिम रूप से विजय पा ली है। हिटलर ने भी

अमेरिका और सोवियत रूस
सारे ससार को चुनौती दी थी। यदि यूरोप रोग से जर्जरित न हुआ होता तो
हिटलर के फौलादी सैन्यदल और उसके गोताखोर वम-वर्षक यूरोप को इतनी
शीघ्रता से ध्वस्त न कर सकते थे। इसी प्रकार एशिया के उपनिवेशों—जावा,
बर्मा, और चीन की दुखी जनता भी जापानियों के आक्रमण का मार्ग प्रशस्त
करने में सहायक हुई। हिटलर और जापान की अन्तिम पराजय के लिए यह
आवश्यक है कि एक अपेक्षाकृत उत्तम ससार और मानव जाति का साथ में
ढाला जाय—उसका निर्माण किया जाय। अगर ऐसा नहीं होता तो हिटलर और
जापानी सैनिक महाप्रभुओं का स्थान स्टालिन ग्रहण कर लेंगे।

हिटलर, मुसोलिनी और हिरोहितो ने लोकतन्त्रवादी ससार को चुनौती
दी थी। हमने उनका सिर कुचल दिया। अब रूस लोकतन्त्री सरकारों को
चुनौती दे रहा है। लोकतन्त्रवाद को दी जाने वाली यह सबसे भारी चुनौती
है। यह हमारे लिए सुधार करने या मिट जाने की चुनौती है।

इसमें कोई शक नहीं कि चुनौती दिये जाने वाले राष्ट्र की अपेक्षा चुनौत
देने वाले राष्ट्र के लिए सुधार करने की अधिक गुंजाइश है। चुनौती देने वाले
राष्ट्र की प्रजा किसी बाहरी राष्ट्र की चुनौती को सुन नहीं सकती, वह फौलादी
घरे के अन्दर बन्द रहनी है। चुनौती देने वाला राष्ट्र इसलिए चुनौती नहीं देता
कि वह श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि हमने नृटियाँ और खामियाँ हैं।

रूस रहे या न रहे लेकिन भारत में लोग भूतों मरेगे, चीन में असन्तोष
होगा, ग्रीस में तनातनी, इटली में प्रजातन्त्रवाद और स्पेन में फाशिज्म-विरोधी
भावना फैलेगी ही। सोवियत सरकार अपने को महज समस्त विरोधियों का
प्रवक्ता या सरदार बना लेती है। वह उनको संगठित करती और उनका शोषण
करती है।

रूस का रोकने के लिए ब्रिटिश-अमेरिकन सैनिक संधि के प्रस्ताव का प्रश्न
उठाया जाता है, लेकिन इस प्रकार का प्रस्ताव रूस को अपनी सीमाओं के या
अपने क्षेत्र के बाहर अंतर फैलाने से किस प्रकार रोक सकता है? क्या रूस को
इस तरह की कार्रवाई करने से रोक देने का उपाय यही है कि सोवियत प्रदेश
पर हमला किया जाय और सोवियत सरकार को नष्ट कर दिया जाय? अगर
इस तरह का हमला हो तो कितने लाख प्राणों की आहुति दी पड़ेगी? और
यदि हमला सफल भी हो जाय तो क्या लोकतन्त्रवाद में जो धुन लग रहा है
उसका निराकरण हो जायगा? हो सक्ता है कि इसका शायद बिलकुल हा
विपरीत प्रभाव हो।

चर्चित इस समस्या पर सैनिक और दूतनीतिक दृष्टिकोण से विचार

है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि-कोण से नहीं। लेकिन यह मुख्यतः सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ही है।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति विभिन्न देशों की सरकारों के बीच सम्बन्ध बनाने तक ही सीमित होती थी। यही वैदेशिक नीति कहलाती थी। अब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया है, जिस पर भी बहुत कम सरकारों देशी विभागों ने इस बात को महसूस किया है। कूटनीति जनता की ओर से आच्छादित हो उठी है। अमेरिका या चीन से सम्बन्ध एक मात्र सरकार के प्रधान, उसके विदेश-मंत्री और विदेशी व्यापारियों से ही बन गया है। इन सबके ऊपर अमेरिका का चीन से सम्बन्ध अनिवार्य रूप से भूमि-मुद्धार और औद्योगीकरण से होगा। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की से सम्बन्ध स्थापित होना इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ पर 'कारवायों' को अपने में मिला लेने और उनको हड़प कर जाने के म्युनिस्टों के जो प्रयत्न हो रहे हैं उनसे वे अपने को बचा सकते हैं या ब्रिटेन से अमेरिका का सम्बन्ध स्थापित होने का प्रश्न समाजवाद, नी स्वतंत्रता और माल पर लगने वाली चुनौती पर निर्भर करता है।

यही वजह है कि कूटनीतिज्ञों का अब पहले का-सो कोई खात जामा नहीं हो रहा है। कूटनीति को अब अवश्य ही कूटनीतिक 'कारवायों,' पत्रों 'वार्ताओं' और सरकारी पत्रों के उच्च-शिखर से नीचे उतरकर की जाँपड़ियों, फैक्टरियों, और राजनीतिक दलों से अपना सम्बन्ध ढूँढ़ेगा। कूटनीति को अब अवश्य ही मध्य-वर्ग के लोगों की वैराग्य-भावना छोड़ मनुष्यों का महत्वाकांक्षाओं के सवाल को हल करना होगा। क्योंकि बातें अनुचित लाभ उठाने के लिए तानाशाही का होसला बढ़ाने की हैं।

अमेरिका और ब्रिटेन की विदेशी नीतियाँ विस्तृत आधार पर अवलम्बित हुईं तक पहुँचने वाली होनी चाहिए और उनका सम्बन्ध मानव-जीवन का चाहिए। केवल तभी वे उस चुनौती का सामना कर सकेंगे जो कि नई दी है।

विषय रूस के विस्तार को देखकर संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन रें अपनी क्षत फौजी-शक्ति को पुनः संगठित करने लगी है और सम्भव हो सका है उनका संगठन इकट्ठा किया जाने लगा है। रूस और पश्चिमी राष्ट्रों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी जिसका स्वरूप एंग्लो-अमेरिकन संधि, यदि सन्धि के नाम से नहीं तो व्याव-

हारिक रूप में, अवश्य हो जायगी।

लेकिन यदि ब्रिटेन और अमेरिका इस प्रकार की सधि करके ही रह गए तो वे रूस की चुनौती का सामना न कर सकेंगे। रूस ससार के प्रत्येक देश में फूट पैदा करने की कोशिश करेगा। उस अवस्था में गरीबी और लोकतन्त्रवाद की आधार-मूलक समस्याएँ हल न होगी। इसके विपरीत जनता को शस्त्रीकरण के भारी बजट से पिस जाना पड़ेगा और आजादी का दम घुटने लगेगा।

भौगोलिक दृष्टि से यह दुनिया एक है, लेकिन राजनीतिक और सैद्धान्तिक दृष्टि से यह एक दुनिया एक न रहकर दो दुनियाँ हो गई है। और शायद तीन दुनियाँ—रूस, इंग्लैंड और अमेरिका और बाकी वह दुनियाँ जहाँ इन तीनों राष्ट्रों में संघर्ष होगा।

वैदेशिक और घरेलू कण्ठमर्श के वर्तमान युग में यूरोप या एशिया का शायद ही कोई राष्ट्र अकेला रहकर टिक सके। इन सभी देशों में और यहाँ तक कि उन देशों में भी, जहाँ पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से सोवियत् रूस का प्रभुत्व कायम हो गया है, दो दुनियाँ अपनी सर्वोच्च सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रही हैं।

ब्रिटिश अमेरिकन दुनियाँ में कम्युनिस्ट 'दरारें' आ गई हैं। पश्चिमी दुनियाँ का प्रवेश रूसियों के उम्र क्षेत्र में हो गया है, जहाँ जनता आजादी के लिए आतुर हो उठी है और वह उस अनवरत तनातनी की स्थिति से छुटकारा पा जाना चाहती है जो कि किसी एक दल की स्वेच्छाचारिता के रूप में प्रकट होती है।

इन दोनों दुनियाँ के बीच का मोर्चा एक सीध में नहीं है। कहीं-कहीं पर दोनों एक दूसरे को ढके हुए हैं। फ्रांस दो दुनियाँ है। जर्मनी दो दुनियाँ है। जहाँ पर स्वास्थ्य तो है पर अधिक शक्ति नहीं है, जैसे स्कैंडिनेविया का क्षेत्र। वहाँ पर एक दुनियाँ के विरुद्ध दूसरी दुनियाँ को सन्तुलित करने का—दोनों दुनियाँ से फायदा उठाने का और उनमें भी किसी एक का भिन्न न बनने का प्रयत्न किया जायगा।

यह मोर्चा लम्बा है और लड़ाई लम्बी होगी। लड़ाई के क्षेत्र बदलते रहेंगे। बीच-बीच में खामोशी छा जाय करेगी। विराम संधियों पर हस्ताक्षर होंगे। युद्ध-बन्धियों का आदान-प्रदान होगा।

संधियों से काम न चलेगा। पहले महायुद्ध ने दूसरे महायुद्ध का मार्ग अपना तमनात्मक संधियों, शान्ति-सम्मेलनों, शान्ति दानों रखने के लिए गम्भीरता

पूर्वक किये जाने वाले वादों और शान्ति से होने वाले लाभों के आकर्षक उल्लेखों से प्रशस्त हुआ था ।

युद्ध राष्ट्रों से सम्बन्धित है । और इसलिए स्वभावतः राष्ट्रों के बीच संधियों, समझौतों, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्ततोगत्वा विश्व-सरकार के निर्माण द्वारा ही युद्ध का निराकरण हो सकता है ।

नाजी जर्मनी के मुकाबले में पोलैण्ड की कमजोरी ही युद्ध का तात्कालिक कारण बनी थी । यदि पोलैण्ड को एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सहायता प्राप्त हुई होती और यदि हिटलर को यह मालूम हो जाता कि अगर उसने पोलैण्ड पर (या अन्य किसी राष्ट्र पर) हमला किया तो वह पोलैण्ड की रक्षा के लिए बढ़ेगा तो संभवतः युद्ध रोका जा सकता था ।

लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना ससार की परिस्थिति को जरूरत से ज्यादा सरल बना देना है । सच बात तो यह है कि पोलैण्ड को किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता प्राप्त नहीं थी और उस समय वह इस तरह की कोई सहायता प्राप्त भी नहीं कर सकता था क्योंकि उस समय का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एंग्लो-फ्रेच गुट और सोवियत् रूस के बीच मतभेद होने और अमेरिका के तटस्थ रहने के कारण शक्तिहीन हो गया था ।

पहले की अपेक्षा आज परिस्थिति अच्छी है क्योंकि आज सामूहिक सुरक्षा प्राप्त हो सकती है ।

किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ाना चाहे वहाँ शायद राष्ट्रों का कोई भी गुट उसे रोक नहीं सकता । लेकिन इस बात की सम्भावना नहीं है कि अमेरिका शक्ति-विस्तार के लिए युद्ध करने जायगा । और इंग्लैंड को कोई आक्रमणात्मक कार्रवाई करने से रोका जा सकता है ।

यदि प्रत्यक्ष रूप से या एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के जरिये ब्रिटेन और अमेरिका फौरन कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध हो जाय तो रूस को भी, कम-से-कम अगले कुछ वर्षों के लिए रोका जा सकता है । क्योंकि नाज़ियों को हराने में रूस को जो रक्त बहाना पड़ा है उससे वह कमजोर हो गया है । सोवियत् सरकार कोई बड़ी लड़ाई लड़ना नहीं चाहती । और अगर उसे यह मालूम हो जाय कि सामूहिक सुरक्षा की दृष्टि से अन्य बड़े राष्ट्रों के हस्तक्षेप करने के फलस्वरूप यह लड़ाई भारी युद्ध में बदल जायगी, तो वह (सोवियत् रूस) अपेक्षाकृत छोटी लड़ाई लड़ने से भी बचने की पूरी तौर से कोशिश करेगा ।

यदि सोवियत् रूस की प्रादेशिक विस्तार की नीति इस हद तक न पहुँच जाय कि वह असह्य जान पड़ने लगे, तो यह मानी हुई बात है कि अगले

अमेरिका और सोवियत रूस

१ या ६ वर्षों के लिए तीनों बड़े राष्ट्रों के सामने वास्तविक समस्या विश्व-व्यापी युद्ध की न होगी, बल्कि वह अपने प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार करने के इरादे से बड़े राष्ट्रों द्वारा कमजोर राष्ट्रों को हड़प कर लेने, उनमें घुस जाने और उनको दबा दिये जाने की ही होगी। और यही समस्या उन राष्ट्रों को, जो अपने क्षेत्र का विस्तार करने की लालसा नहीं रखते, एक खतरे के रूप में दिखाई देने लगेंगी और तब मुमकिन है कि यही राष्ट्रों के बीच प्रथम आणुविक-संघर्ष का कारण बन जाय।

बहुत सम्भव है कि एग्लो-अमेरिकन सन्धि रूस को किसी दूसरे राष्ट्र पर हमला करने से रोक दे। उस रूस पर यही प्रभाव एक ऐसा सयुक्तराष्ट्र-संघ भी डाल सकता है, जिसके निर्णय को रद्द कर देने का अधिकार किसी राष्ट्र को न प्राप्त हो। लेकिन प्रश्न यह है कि इस प्रकार की सन्धि या सयुक्तराष्ट्र-संघ सोवियत रूस को विदेशी राष्ट्रों के भीतर सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को भंग कर देने से कैसे रोक सकता है ?

अगर कोई राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र के मुकाबले में कमजोर पड़ता है, इस स्थिति का मुकाबला सामूहिक सुरक्षा के निमित्त संगठित अन्तर्राष्ट्रीय संस्थ के सहयोग द्वारा किया जा सकता है। लेकिन राष्ट्रों की आन्तरिक (घरेलू) राजनीतिक और आर्थिक विकास सम्बन्धी असमानता को, जो एक ओर तो किसी राष्ट्र को अपना विस्तार करने के लिए लालायित करती और दूसरी ओर किसी दूसरे राष्ट्र को इस तरह के विस्तार का मुकाबला करने में असमर्थ बना देती है, शक्ति-प्रयोग द्वारा किसी भी हालत में दूर नहीं किया जा सकता। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और शान्ति का अन्तिम सूत्र सधियाँ या संगठन नहीं, बल्कि राष्ट्रों की घरेलू नीति और राष्ट्रीय सरकारों का सामाजिक स्वरूप ही है।

मान लीजिए, अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य कई छोटे-छोटे राष्ट्र विश्व-सरकार का संगठन करने के लिए तैयार हो गए और उसके नेतृत्व में रहने लगे, लेकिन रूस ने उसका समर्थन करने से इसलिए इन्कार कर दिया कि वह किसी प्रजावादी सरकार का प्रग बनना नहीं चाहता या उसने यह सोचा कि अगर वह इस तरह की सरकार में शामिल होता है तो उसे उस सरकार ने बहुतम के सामने नुरी तरह नीचा देखना पड़ेगा, तो उस हासन में क्या किया जा सकता है ?

गैर-सोवियत राष्ट्रों के विश्व सरकार में शामिल होने के लिए तैयार होते ही (और यह बात जितनी जल्दी है उनी ही अच्छी होगी) उन्हें करना

यह चाहिए कि वे फौरन रूस को इस बात पर राजी करने की पूरी तौर से कोशिश करे कि विश्व-सरकार के सगठन के कार्य में वह भी हाथ बटाए, और इसके साथ-ही-साथ इस बात का भी प्रयत्न होना चाहिए कि इस विश्व-सरकार के अन्तर्गत प्रत्येक राष्ट्र को स्वेच्छानुसार अपना व्यक्तित्व प्रकट करने के लिए विस्तृत रूप से स्वतन्त्रता दी जाय । अगर सोवियत् रूस विश्व-सरकार में शामिल न होकर उससे अलग रहना ही पसन्द करे तो उस पर कोई जोर या दबाव न डाला जाय या इसके लिए उसे दण्ड देने की कोई कार्रवाई न की जाय । गैर-सोवियत् राष्ट्र उस हालत में विश्व-सरकार के केवल ५ भाग को ही सगठित करे, पर साथ ही रूस के लिए उसका दरवाजा बराबर खुला रख छोड़ें ।

सम्भव है कि कुछ लोग फिलहाल इस तरह की विश्व-सरकार का सगठन हो जाने के विरुद्ध राय दे और यह दलील पेश कर कि अगर अभी ऐसा हुआ तो सोवियत् रूस तथा ससार के अन्य राष्ट्रों के बीच एक खाई खुद जायगी । लेकिन विश्व-सरकार सगठित न करने से भी तो यह खाई दूर नहीं हो सकती । बल्कि यह तो सिर्फ उस खाई पर परदा डालना ही होगा । क्योंकि उनके बीच यह खाई पहले से ही मौजूद है । यदि यह दुनिया एक ही दुनिया होती तो उसकी घोषणा खुशी के साथ कर सकते थे । लेकिन चूँकि दो दुनिया हैं इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम इस असलियत को स्वीकार कर लें ।

यदि उस समय तक, जब तक कि रूस उसमें शामिल नहीं होता, विश्व-सरकार सगठित करने से इन्कार किया जाता है तो इसका मतलब यही होगा कि रूस को गैर-सोवियत् राष्ट्रों में असीम काल तक फूट पैदा करने दिया जाय जिससे कि वे रूसियों के दबाव का विरोध न कर सके । ऐसी हालत में जबकि एक दुनिया दूसरी दुनिया की जड़ खोद रही हो और इसके साथ-ही-साथ स्वयं अपने प्रभाव-क्षेत्र को सुदृढ़ बनाती और उसका विस्तार करती जा रही हो, उस हालत में बजाय इसके कि लोकतन्त्रवादी एकता की भ्रान्त धारणा की—इस तरह की भ्रान्त धारणा बोलशेविकों में नहीं है—‘दोनों दुनिया’ के लिए यह कहीं बेहतर होगा कि वे आपस के इस विभेद को स्वीकार कर ले ।

काश, एक ही दुनिया होती—एक शानदार दुनिया । लेकिन आखे बंद कर लेने से ही तो ऐसा नहीं हो जाता । एक ही दुनिया—यह एक महान् लक्ष्य है । और विल्की—जिसने मानव जाति को यह नारा दिया—एक महान् पुण्य था । लेकिन वास्तव में यह दुनिया एक ही दुनिया नहीं है ।

ससार को दो भागों में बांट देने पर उन दोनों भागों में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित होने की सम्भावना नहीं हो, सकती—ऐसा नहीं कहा जा सकता। व्यापार, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान और यात्राएँ—यह सब बातें सफलतापूर्वक चलाई जा सकती हैं। दो देशों के बीच की प्रतिद्वन्द्विता बहुत लम्बे समय तक अहिंसात्मक बनी रह सकती है।

इस प्रतिद्वन्द्विता का क्या स्वरूप है ? क्या यह सच है कि दुनिया आधी गुलाम और आधी आज़ाद नहीं रह सकती ? क्या यह सच है कि बोलशेविक नेताओं को डर है कि अगर ससार को वैयक्तिक स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो उस हालत में सोवियत्-सरकार—जिसने स्वयं एक बहुत बड़े पूँजीवाद का रूप धारण कर लिया है—का यह आत्याचार अनिश्चित काल तक टिका न रह सकेगा ? क्या यह सच है कि ससार के पूँजीवादी राष्ट्रों को भय है कि मास्को से आदेश प्राप्त करने वाले कम्युनिस्ट और आमूल परिवर्तनवादी उनका खात्मा कर देंगे ?

इस प्रतिद्वन्द्विता का चाहे जो भी कारण हो और चाहे वह जितने भी समय तक और चाहे जितनी भी गम्भीरता के साथ चलती रहे, इसका मुकाबला पूँजीवादी राष्ट्र केवल एक ही नीति द्वारा कर सकते हैं। अर्थात् वे खुद रहने के लिए अपने घर को पहले से आकर्षक और आरामदेह बनाएँ। अगर वे यह कहते हैं—‘हम इस घर में कई पुस्तकें से रह रहे हैं। यह घर हमारे बाप दादों को पसन्द था, इसलिए हमारे लड़के-लड़कियों, हमारे मेहमानों और हमारे नौकरों को भी इसे पसन्द करना पड़ेगा,’ तो उनके नौकर उस घर को त्याग देंगे, उनकी नई सन्तानें उस घर को छोड़कर चल देंगी।

यदि रूढ़िवादियों, प्रतिक्रियावादियों और मौजूदा स्थिति को ज्यों की-त्यों बनी रहने देने के समर्थकों की, जो कि घर में कोई मरम्मत, आधुनिक ढंग से सुधार, और नई बातों का विरोध करते हैं, जीत हुई तो नई सन्तानें उस घर में टिक न सकेगी, वे अपने रहने के लिए किसी दूसरे घर की तलाश करने निकलेगी।

धुरी-राष्ट्रों के शिकार बनने वाले राष्ट्रों की कमजोरी और हमला होने पर उनकी सहायता करने के प्रति शान्तिप्रिय राष्ट्रों की उदासीनता—इन्हीं दो बातों से धुरी-राष्ट्र आक्रमण, युद्ध और संहार करने के लिए प्रोत्साहित हुए थे।

सोवियत् सरकार का ख्याल है कि जहाँ अन्य राष्ट्रों की अमकनता मिली वहाँ उसे सफलता मिल सकती है। क्योंकि वह पूँजीवादी राष्ट्रों की एक दूसरी कमजोरी से लाभ उठा सकती है। और वह कमजोरी है अन्य राष्ट्रों

द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, और आर्थिक समस्याओं का निराकरण न करना ।

यदि रूस चीन, भूमध्यसागर, उत्तरी अफ्रीका, ट्रीस्ट, ग्रीस और अपने कम्युनिस्ट दलों के जरिए प्रत्येक पूँजीवादी राष्ट्र तक पहुँचता है, तो उसका यह प्रसार न केवल साम्राज्यवादी गर्व से बल्कि सैद्धान्तिक विश्वास से भी अनुप्राणित है । सोवियत् रूस का यह भारी आक्रमण कमजोर राष्ट्रों की अरक्षित अवस्था, बड़े देशों की तुष्टीकरण की भावना और इन सबसे बढ़कर स्वतः सोवियत् राष्ट्र के भीतर फैली हुई अगान्ति और असन्तोष से गान्ति प्राप्त करता है । किसी राष्ट्र के आक्रमणकारी बनने का कारण भी वही है जो किसी व्यक्ति के आक्रमणकारी बनने का—अर्थात् भीतर से मानसिक गुत्थियाँ और बाहर से उपयुक्त लक्ष्य और अक्सर इसके लिए इन दोनों कारणों में से केवल एक ही आक्रमण के लिए पर्याप्त होता है ।

लोकतन्त्रवादी राष्ट्र अपना माल दूसरे देशों में भेजते हैं और वे अपने विचार भी दूसरे देशों में पहुँचाने के लिए तैयार हैं । वे तानाशाही से आजादी को पसन्द करते हैं । बहुत से प्रजातन्त्रवादी राष्ट्रों को यकीन हो गया है कि पूँजीवाद सर्वोत्तम है । लेकिन लोकतन्त्रवादी राष्ट्र लम्बे अरसे से निष्क्रिय नहीं बन रहे हैं । शायद उन्हें अपने में विश्वास नहीं रह गया है । शायद वे अपने विचारों को बलपूर्वक दूसरों पर लादने में विश्वास नहीं करते । वे वास्तव में अपने पूँजीवाद को समाजवाद में मिला रहे हैं, जिससे प्रकट होता है कि वे किसी दूसरी बात को आजमाने के लिए उद्यत हैं ।

दूसरी ओर बोलशेविकों को यकीन हो गया है कि उन्होंने जिस रास्ते को अख्तियार किया है वह ठीक है और उनकी प्रणाली सर्वोत्तम है । उन्होंने इस बात को साबित नहीं किया है, लेकिन बड़े जोर-शोर से यह दावा करते हैं ।

स्टालिन के आदर्शवादी आक्रमण का सूत्रपात इस निश्चय की भावना से हुआ है कि वह इसमें विजय प्राप्त कर सकता है ।

स्टालिन का यह विश्वास उन गड्ढों के भीतर के रक्षकों की, जिन पर वह हमला करने की आशा रखता है, बेवकूफी से और भी दृढ़ बन गया है । वे अपने किले की चहार-दीवारी में कुछ और ईंटें जोड़ देते हैं और रक्षा के लिए उसके चारों तरफ तैयार की गई खाई को और चौड़ी बना देते हैं । स्टालिन यह देखकर मुसकराने लगता है वह सोचते हैं—'इस किले की चहार-दीवारी के भीतर हमारे बहुत से मित्र हैं । चर्चिल जैसे व्यक्तियों के कारण हर रोज हमारे नए-नए दोस्त बनते जा रहे हैं । इस के भीतर रहने वाले दूसरे लोग या तो आक्रमण का मुकाबला करने से

अत्यधिक उदासीन या ऊबे हुए या इतने शक्ति-क्षीण हो रहे हैं कि वे लड़ ही नहीं सकते ।'

सधि-प्रस्ताव को सुनकर मास्को को गुस्सा आता है । 'ठोस बातों' के साथ ठोस कार्य ही सोवियत् सरकार को प्रभावित कर सकता है । लेकिन जब अमेरिका और ब्रिटेन सारे ससार में स्वातंत्र्य आन्दोलनों और सामाजिक लोक-सत्ता का समर्थन करने लगेंगे तभी स्टालिन को विश्वास होगा कि अब हम यह समझ गए हैं कि उसके क्या इरादे हैं और अब हम रचनात्मक और प्रगतिशील कार्रवाइयाँ करने और उसके आक्रमण को रोक देने के लिए तैयार हो गए हैं ।

बचिल के एग्लो-अमेरिकन समझौते के प्रस्ताव की अपेक्षा ब्रिटिश मजदूर-सरकार की एशिया के उपनिवेशों की आजादी की योजनाओं से सोवियत् सरकार को अधिक घबराहट होती है । पश्चिमी राष्ट्र निकट-पूर्व के सामन्त-शाही नरेशों का समर्थन करना बन्द करके वहाँ के गरीब किसानों का समर्थन करने लग जाय और तब मास्को को मालूम हो जायगा कि दरअसल कोई महत्वपूर्ण बात हुई है । चीन की मध्य सरकार अपने यहाँ भूमि-सुधार करे और तब स्टालिन कहने लगेगा — "वह चीन में एकता स्थापित कर रही है और मुझे चीन से बढ़ेड़ रही है ।" गरीब जाति के लोग इस बात का निर्विवाद प्रमाण देना चाहते हैं कि 'नहने काली जातियों के प्रति एक नया और सम्मानपूर्ण रुख धारण किया है, और तब मास्को को महसूस होने लगगा कि उसे लाग्यो शक्तिशाली राजनीतिक रणरङ्ग से हाथ धोना पड़ रहा है । लोकतन्त्रवादी राष्ट्रों को यहूदी विरोधी आन्दोलन का विरोध करना चाहिए और तभी समीक्षक इस निर्णय पर पहुँचेंगे कि लोकतन्त्रवादी राष्ट्र फाशिरट-विरोधी हैं । इंग्लैंड और अमेरिका यूरोप में सामाजिक परिवर्तनकारी शक्तियों से मंत्री स्थापित कर लें, तो यूरोप यह देखेगा कि उसमें साम्राज्यवादी स्ताव फाशिरट से लड़ने की ताकत आ गई है । अंग्रेज और अमेरिकन फाशिवादिओं से नफरत करने लग जाय, तो वह देखेंगे कि लाग्यो की तादाद में स्टो, पादरी प्रतिष्ठानादियों, सत्तावादियों, आर्थिक सत्तावादियों और मैनिस-वादिओं से नफरत करने लग जाय, तो वह देखेंगे कि लाग्यो की तादाद में फाल, हालैंड और पुर्तगाल प्रादेशिक तेल सम्बन्धी और व्यापारिक साम्राज्यवाद का स्थाप दे, उन्हें किनी अन्य साम्राज्यवाद का मार्ग अवरोध कर देने की एक नई नैतिक शक्ति प्राप्त हो जायगी । पश्चिमी राष्ट्र कमजोर देशों के नामों से अन्तराष्ट्रीय दबल देना बन्द कर दें, फिर उन्हें सोवियत् रुस के हस्तक्षेप को रोक देने का सुत्रान्तर प्राप्त हो जायगा । पूर्वी उपनिवेशों के प्रवक्ता न केवल

बाहरी संरक्षण से आज़ादी के लिए, बल्कि भीतर से सामाजिक न्याय के लिए जिहाद शुरू करें। तब वे पूर्ण स्वतंत्र होने की आशा कर सकते हैं।

यही वे अस्त्र है जिनसे लोकतंत्री राष्ट्रों पर होने वाले रूसी हमले को रोका जा सकता है। यह रूस के साथ सैद्धान्तिक प्रतिद्वन्द्विता है। रूस से लड़ने के बजाय यही एक दूसरा तरीका है। अगर लोकतंत्रवादी राष्ट्र इसमें विजयी हुए तो युद्ध न होगा—संसार में कभी युद्ध न छिड़ेगा। संसार में एक विश्व-सरकार कायम होगी जिसमें अन्ततोगत्वा रूस भी शामिल हो जायगा। लेकिन अगर रूस की जीत हुई तो लोकतन्त्रवाद का नाम निशान न रह जायगा।

इसमें शक नहीं कुछ लोग कहेंगे कि रूस के साथ यह सैद्धान्तिक प्रतिद्वन्द्विता का प्रस्ताव “सोवियत् विरोधी” है, और वह रूस तथा संसार के बाकी राष्ट्रों के बीच खाई उत्पन्न कर देगा और युद्ध को अनिवार्य बना देगा। लेकिन मैं इससे बिल्कुल विपरीत बात को सच समझता हूँ। इस समय सोवियत् रूस गैर-सोवियत् राष्ट्रों के विरुद्ध सयुक्त प्रादेशिक सैद्धान्तिक आक्रमण आरम्भ करने में व्यस्त है। उसे न रोकने का मतलब रूस को उस हद तक अपना विस्तार करने में सहायता पहुँचानी होगी, जहाँ पर दोनों पश्चिमी राष्ट्रों चौंककर बल-प्रयोग द्वारा रूस को आगे बढ़ने से रोक देना होगा।

रूसी समस्या सुलझाने के तीन उपाय हैं—(१) रूस से अभी लड़ा जाय। मैं उसका जोरदार विरोध करता हूँ। (२) रूस को तुष्ट किया जाय। तुष्टीकरण में हमेशा यह बात शामिल रहती है कि आप जो कुछ कर रहे हैं वह तुष्टीकरण नहीं बल्कि रूस से मैत्री बनाये रखने का यही एक मात्र उपाय है। मैं इसे अस्वीकार करता हूँ क्योंकि इससे बहुत से देशों की स्वतन्त्रता मिट जायगी और इसका परिणाम युद्ध होगा। (३) रूस के प्रादेशिक विस्तार को एक प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा और उसके मार्ग में पड़ने वाले देशों में सन्तोष और एकता की भावना को बढ़ाकर सोवियत् रूस के विस्तार को रोक दिया जाय। मैं इसका अनुमोदन करता हूँ। इसका विरोध वही लोग करेंगे जो रूस के विस्तार को रोकना नहीं चाहते।

रूस के साथ सैद्धान्तिक जागरूक प्रतिद्वन्द्विता पर आधारित वैदेशिक नीति से संसार में शान्ति स्थापित होने की सम्भावना बढ़ेगी, उदारवादियों के बीच तानाशाही विचार-धारा का समावेश होना रुक जायगा, लोकतन्त्रवाद की सुरक्षा होगी, रहन-सहन का मान बढ़ेगा और स्वतंत्र संसार का नैतिक विकास

होगा, जिसकी बड़ी आवश्यकता है। रूस से सैद्धान्तिक प्रतिद्वन्द्विता के बचाव का दूसरा उपाय यही है कि रूस से अपनी पराजय पूरी तौर से स्वीकार कर ली जाय।

लेकिन वंदेशिक नीति किसी विदेश मंत्री की सनक या मनमानी योजना नहीं है। स्वतः अपने घर में अमेरिका का जो रूप है, उसी के अनुसार वह विदेशों में भी आचरण करता है। यही बात इंग्लैंड तथा अन्य राष्ट्रों के बारे में भी सच साबित होती है।

‘क्या हमारे नेता इतने महान् तथा बुद्धिमान् हैं कि वे एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रगतिशील नीति कार्यान्वित कर सकें?’ यह प्रश्न बहुत से नागरिकों को परेशान करना रहता है। इसका उत्तर यही है कि एक लोकतन्त्रवादी राष्ट्र के नेता अनिवार्यतः अपने देश की जनता से, जिनका वे नेतृत्व करते हैं, बहुत बड़े नहीं होते और न वे जनता की अपेक्षा बहुत तेजी के साथ कदम ही बढ़ा सकते हैं।

उन सभाओं में जिनमें मैं इस बात का आग्रह करता हूँ कि संयुक्तराष्ट्र-संघ के अन्तर्गत राष्ट्रों के विशेषाधिकार को उड़ा देना चाहिए, अथवा मजदूर विरोधी कानून को रद्द कर देना चाहिए, मुझसे पूछा गया है, “क्या हमें अपने कांग्रेस सदस्यों के पास तार भेजने चाहिए?” मैं कहता हूँ, “अवश्य, आप अपने कांग्रेस-सदस्यों के पास तार भेजें। लेकिन दूसरी बार कांग्रेस के लिए ऐसे प्रतिनिधि चुनें जिन्हें तार देने की जरूरत ही न हो।”

वंदेशिक नीति और प्रत्येक नीति निर्धारित करने वाले स्वी-पुरुष, वे व्यक्ति हैं जो व्यवस्थापिका सभाओं में और सरकारी दफ्तरो में बैठते हैं। उनका चुनाव होता है अथवा उन्हें उन लोगों की इच्छा, दवाव और दलीलो को स्वीकार करना पड़ता है जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार वंदेशिक नीति वोट पड़ने के बक्स से निर्धारित होती है, वंदेशिक नीति तथा शान्ति उस प्रत्येक नगर और गांव में निमित्त होती है जहाँ निर्वाचक लोग स्वतन्त्रता पूर्वक और ईमानदारी के साथ वोट देने जाते हैं।

दान अथवा प्रत्येक सद्गुण की भांति शान्ति नवम् पहले अपने घर से ही शुरू होती है। साधारण जनता ससार के सारे देशों की साधारण जनता को हित-कामना करती है। शीमन आदमी शान्ति के लिए बहुत कुछ त्याग करेगा। यह माल पर चूगी बसूल करने की इच्छा रखने वाले कारपोरेट्स, और सुविधाएँ प्राप्त करने की इच्छा रखने वाली समितियों के हितों के मुकाबले में शान्ति को बहुत उच्च दृष्टि से देखना है। सामान्य रूप से सामान्य

तो सैनिकवादी है, न साम्राज्यवादी ।

लेकिन साधारण जनता की मनोभावनाओं, विचारों और हितों की देश के राजनीतिक जीवन में पूरी-पूरी झलक देखने की नहीं मिलती । सुधारक, आदर्शवादी, पादरी नेता, सामाजिक कार्यकर्ता, अन्तर्गठवादी, महिला निर्वाचकों के सघ, ट्रेड यूनियन तथा विभिन्न प्रकार के सदुद्देश्यों को लेकर स्थापित की गई अनेकानेक सुधार-समितियाँ लगानार राजनीतिज्ञों के ही पीछे पीछे लगी रहती हैं । क्या यह अच्छा न होता कि वे स्वयं राजनीति में पदार्पण करती ? लोकतन्त्रवादी देशों के सार्वजनिक जीवन में अधिकतर नैराश्य का कारण वह खाई होती है, जो दो बातों के बीच पाई जाती है कि बहुत से लोग क्या चाहते या क्या लक्ष्य रखते और उनकी प्राप्ति के लिए वे क्या प्रयत्न करते हैं ।

राजनीति को एक 'खेल' समझा जाता था । राजनीति उन लोगों से वास्ता रखती थी जो सड़कें माफ कराते, कूड़ा-कंकड़ जमा कराते और पुलिस इन्स्पेक्टर को नियुक्त करते थे । लेकिन अब राजनीति जीवन का ताना-बाना बन गई है । अब वह इसका फैसला करने वाली है कि वमों से मर मिटने के बजाय मानव जाति को सन्तुष्ट, बेकारी से मुक्त, सुखी और जीवित रहना है ।

अपेक्षाकृत एक उत्तम संसार के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि संसार की जनता न केवल अवसर आने पर वोट देकर वल्कि उस चुनाव के लिए प्रतिद्वन्द्वी उम्मीदवार भी खड़ा करके अपने देश के राजनीतिक मामलों में पहले से अधिक सक्रियता पूर्वक भाग ले । यह कार्य दल के कार्यकर्ताओं और पेशेवर संरक्षकों के ऊपर हार्गिज न छोड़ना चाहिए ।

श्रीसत नागरिक युद्ध या शान्ति के लिए, आजादी या तानाशाही के लिए, अमीरी या गरीबी के लिए कुछ-न-कुछ करना हा चाहता है । वह उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और खपत के रूप में कुछ-न-कुछ करता हा है । अपने व्यक्तिगत आचरण द्वारा वह कुछ सहायता ही पहुँचाता है । लेकिन अब उसे राजनीतिक इकाई के रूप में इससे कुछ और अधिक करना पड़ेगा ।

जिन लोगों को इस बात का पूर्वाभास मिल गया था कि एक महान् नई दुनिया (अमेरिका) का अभ्युदय होने वाला है वह अपने नौजवानों को वहाँ जाने और लाभ उठाने की नैक सलाह देते थे । इसी प्रकार आज प्रत्येक युवक-युवती और प्रौढ़ स्त्री-पुरुषों के लिए जो एक नए, महान् और स्वतंत्र संसार के निर्माण का स्वप्न देखते हैं, यही नारा होना चाहिए कि 'राजनीति को अपनाओ—उसे ग्रहण करो ।'

अपेक्षाकृत उत्तम अमेरिका, उत्तम इंग्लैंड, उत्तम फ्रांस, उत्तम जर्मनी,

उत्तम रूस, उत्तम भारत को अपेक्षाकृत उत्तम समार के निर्माण के लिए पारस्परिक सहयोग द्वारा कार्य करना होगा। आज आदी और शान्ति की समस्या किमी करामात ने—जादू ने—हल नहीं की जा सकती। इसके लिए प्रत्येक परिवार, प्रत्येक जाति, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक राष्ट्र में खून का पसीना बनाने की जरूरत है।

अपेक्षाकृत उत्तम ससारमें सभी आजाद होंगे, अपने विकास के लिए सभी को अवसर प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त बेकारी के जुए से मुक्ति, अन्तर्वेदना से पूर्ण भेदभाव से छुटकारा, अभाव की पीड़ा से आज़ादी, अरक्षा और भय से स्वतंत्रता, अत्यधिक शासन-नियंत्रण और अत्यधिक सम्पत्ति के प्रपीड़न से मुक्ति, और काबू में न लाए जा सकनेवाले राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभुओं से छुटकारा मिल जायगा। और तब हर-एक को कुछ सीखने का, कुछ बढ़ने का और अन्यो की सेवा करते हुए अपनेपन को जान लेने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार की दुनिया में मानव और मानवों में जो शांति होगी, वही राष्ट्रों की शांति होगी।

